भारतीय रिज़र्व बैंक

बुलेटिन

सितंबर 2024

खंड 79 अंक 9

अध्यक्ष
माइकल देवब्रत पात्र

संपादक समिति
मनीष कपूर
अजीत आर जोशी
रेखा मिश्र
प्रज्ञा दास
सुनिल कुमार
स्नेहल हेरवाडकर
पंकज कुमार
वी. धन्या
श्वेता कुमारी
अनिर्बन सान्याल
सुजाता कुंडू

संपादक
जी. वी. नथनएल

भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन संपादकीय समिति के
निर्देशन में आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा
मासिक आधार पर प्रकाशित की जाती है।
इसमें व्यक्त व्याख्याओं और विचारों के लिए
बैंक का केंद्रीय निदेशक मंडल उत्तरदायी नहीं है।
हस्ताक्षरित आलेखों में व्यक्त विचारों के लिए
लेखक स्वयं उत्तरदायी हैं।

© भारतीय रिज़र्व बैंक 2024

सर्वाधिकार सुरक्षित।
सामग्री के पुनः उत्पादन की अनुमति है,
बशर्ते स्रोत का उल्लेख किया जाए।

बुलेटिन की सदस्यता के लिए कृपया 'हाल के प्रकाशन' खंड देखें।

भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन को
https://bulletin.rbi.org.in पर देखा जा सकता है।

विषय-वस्तु

भाषण

वैश्विक वित्तीय स्थिरता: जोखिम और अवसर
श्री शक्तिकान्त दास 01

भारत एक महत्वपूर्ण मोड़ पर : कुछ विचार
श्री शक्तिकान्त दास 07

ग्लोबल फिनटेक फेस्ट (जीएफएफ) 2024 में संबोधन
श्री शक्तिकान्त दास 13

इंडिया@100 के लिए फिनटेक नवोन्मेष: भारत के वित्तीय परिदृश्य के भविष्य को आकार देना
श्री शक्तिकान्त दास 15

आरबीआई@90 वैश्विक सम्मेलन में उद्घाटन भाषण
श्री शक्तिकान्त दास 21

भारत की आकांक्षाओं का वित्तपोषण
माइकल देवब्रत पात्र 27

आधारभूत संरचना के लिए वित्तपोषण में आनेवाली चुनौतियों का प्रबंधन: एनएबीएफआईडी के लिए आगे की राह
श्री एम. राजेश्वर राव 33

जमा बीमा: बदलते समय के साथ तालमेल बनाए रखना
श्री एम राजेश्वर राव 39

धारणीय कृषि के लिए वित्तपोषण
श्री स्वामीनाथन जे. 45

वित्तीय परिदृश्य में परिवर्तन: आर्थिक स्थिरता के लिए समुत्थानशीलता का निर्माण
श्री स्वामीनाथन जे. 51

स्थानिक से वैश्विक: एमएसएमई के विकास में वित्तीय क्षेत्र की भूमिका
श्री स्वामीनाथन जे. 55

आलेख

अर्थव्यवस्था की स्थिति 59

भारतीय राज्यों के व्यापार चक्र का समन्वय 109

प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र ऋण : भारतीय अनुभव 125

गहन विश्लेषण: हाल के समय में एनबीएफसी क्षेत्र की समीक्षा 135

वर्तमान सांख्यिकी **149**

हाल के प्रकाशन **203**

भाषण

वैश्विक वित्तीय स्थिरता: जोखिम और अवसर
श्री शक्तिकान्त दास

भारत एक महत्वपूर्ण मोड़ पर : कुछ विचार
श्री शक्तिकान्त दास

ग्लोबल फिनटेक फेस्ट (जीएफएफ) 2024 में संबोधन
श्री शक्तिकान्त दास

इंडिया@100 के लिए फिनटेक नवोन्मेष: भारत के वित्तीय परिदृश्य के भविष्य को आकार देना
श्री शक्तिकान्त दास

आरबीआई@90 वैश्विक सम्मेलन में उद्घाटन भाषण
श्री शक्तिकान्त दास

भारत की आकांक्षाओं का वित्तपोषण
माइकल देवब्रत पात्र

आधारभूत संरचना के लिए वित्तपोषण में आनेवाली चुनौतियों का प्रबंधन: एनएबीएफआईडी के लिए आगे की राह
श्री एम. राजेश्वर राव

जमा बीमा: बदलते समय के साथ तालमेल बनाए रखना
श्री एम राजेश्वर राव

धारणीय कृषि के लिए वित्तपोषण
श्री स्वामीनाथन जे.

वित्तीय परिदृश्य में परिवर्तन: आर्थिक स्थिरता के लिए समुत्थानशीलता का निर्माण
श्री स्वामीनाथन जे.

स्थानिक से वैश्विक: एमएसएमई के विकास में वित्तीय क्षेत्र की भूमिका
श्री स्वामीनाथन जे.

*वैश्विक वित्तीय स्थिरता: जोखिम और अवसर**

श्री शक्तिकान्त दास

मुझे 'ब्रेट्टन वुड्स कमिटीज़ फ्यूचर ऑफ फाइनान्स फोरम' के तीसरे वार्षिक सम्मेलन में भाग लेते हुए खुशी हो रही है। यह सम्मेलन सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों, बहुपक्षीय संस्थानों और थिंक टैंकों के नेताओं और विशेषज्ञों को वित्तीय क्षेत्र में उभरते मुद्दों, प्रवृत्तियों और प्रौद्योगिकियों पर विचार-विमर्श करने के लिए एक साथ लाता है। यह व्यापक विचार-विमर्श निर्णय प्रक्रिया को समृद्ध कर सकता है और अवसरों का लाभ उठाने, जोखिमों का प्रबंधन करने और भविष्य के लिए सुदृढ़ता निर्माण की रणनीतियों को तैयार करने में मदद कर सकता है। इस पृष्ठभूमि के साथ, मैं वैश्विक वित्तीय स्थिरता परिदृश्य और वर्तमान व्यापक आर्थिक वातावरण से परे उभरते जोखिम संतुलन और अवसरों पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करूंगा।

I. वर्तमान परिस्थितियाँ

वैश्विक वित्तीय प्रणाली ने हाल की अवधि में उच्च प्रभाव वाले कई आघातों का सामना करने में उल्लेखनीय लचीलापन प्रदर्शित किया है। जबकि वैश्विक आर्थिक गतिविधि और व्यापार ने बड़े पैमाने पर प्रतिकूल जोखिमों को झेला है, अवस्फीति का अंतिम स्तर चुनौतीपूर्ण साबित हुआ, जिससे वित्तीय स्थिरता के जोखिम बढ़ रहे हैं। जैसे-जैसे मौद्रिक नीतियों की भविष्य की दिशा के बारे में बाजार की उम्मीदें केंद्रीय बैंकों के नीति मार्गदर्शन के साथ परिवर्तित होती जाएंगी, हार्ड लैंडिंग की संभावनाएँ कम होती जाएंगी। यह अधिकांश पूर्वानुमानों में परिलक्षित होता है, जो इंगित करते हैं कि अंतरराष्ट्रीय आर्थिक और वित्तीय वातावरण में निरंतर अनिश्चितताओं के बावजूद निकट-अवधि की संभावनाओं में सुधार हो रहा है। वित्तीय मध्यस्थों के मजबूत तुलनपत्र और सहायक मदें, और यहां तक कि सक्रिय सूक्ष्म और मैक्रोप्रूडेंशियल नीति प्रतिक्रियाओं द्वारा समष्टि-वित्तीय स्वास्थ्य मजबूत हुआ है। तथापि, हाल ही में, देशों के बीच मौद्रिक नीति विचलन के परिणाम सामने आने लगे हैं और विशेष रूप से वित्तीय बाजारों में अस्थिरता और असामान्य बिकवाली हुई है। वैश्विक स्तर पर हाल ही में हुई अभूतपूर्व आईटी कटौती के चलते, इन घटनाक्रमों ने दिखाया कि वित्तीय प्रणाली के जोखिम वैश्विक स्तर पर कैसे पहुंच सकते हैं। कभी-कभी यह बहुत तेज़ी से होता है, जैसा कि 2023 की शुरुआत में कुछ बैंकों में हुआ। इन तथ्यों ने एक बार फिर संकट की तैयारी और मजबूत व्यापार निरंतरता योजनाओं (बीसीपी) के महत्व को सामने ला दिया है।

नेल्सन मंडेला की कही बात का मैं उल्लेख करता हूँ: "एक बड़ी पहाड़ी पर चढ़ने के बाद, केवल यही दिखाई देता है कि चढ़ने के लिए और भी कई पहाड़ियाँ हैं।" जबकि निकट-अवधि के कई जोखिम कम हुए दिखाई देते हैं, व्यापक दृष्टिकोण से देखें तो वैश्विक वित्तीय प्रणाली को बढ़ी हुई अनिश्चितता का सामना करना पड़ रहा है। इनमें से कुछ जोखिमों को हम पहचानते हैं और उनसे निपटना भी जानते हैं, लेकिन दूसरे कुछ ऐसे जोखिम हैं जो अभी उभर रहे हैं या पृष्ठभूमि में छिपे हुए हैं। जैसे-जैसे दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में समष्टि आर्थिक स्थितियाँ बदलती जा रही हैं और नीतिगत प्रतिक्रियाएँ तेजी से असंगत होती जा रही हैं, उन्नत और उभरती अर्थव्यवस्थाओं में समान रूप से इसका प्रभाव प्रसार बढ़ रहा है।

इस अत्यधिक अनिश्चित परिदृश्य में, नीति निर्माताओं और वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों को आर्थिक गतिविधियों और **वित्तीय क्षेत्र को अप्रत्याशित झटकों से बचाने के लिए नए सिरे से काम करना होगा। वित्तीय क्षेत्र में एक सुदृढ़ और मज़बूत तथा सुसज्जित विनियामक ढांचा समय से आगे रहने और जोखिमों को कम करने के लिए आवश्यक है। समष्टि आर्थिक नीति निर्माताओं और अन्य हितधारकों को भी भविष्य में आने वाले कठिन मोड़ों और संकटों से पार होने के लिए एक दूरदर्शी दृष्टिकोण अपनाने में तेज़ी दिखानी चाहिए। टिकाऊ व्यवसाय मॉडल को अपनाना और प्रौद्योगिकीय प्रगति की पूरी क्षमता का विवेकपूर्ण तरीके से दोहन करना इस दृष्टिकोण की सफलता की आधारशिला होगी।**

* 13 सितंबर 2024 को सिंगापुर में ब्रेटन वुड्स समिति द्वारा आयोजित फ्यूचर ऑफ फाइनेंस फोरम 2024 में भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकान्त दास द्वारा दिया गया मुख्य भाषण।

II. समष्टि आर्थिक संभावनाएं

2024 की पहली छमाही में वैश्विक आर्थिक गतिविधि के सुदृढ़ीकरण ने वित्तीय बाजारों द्वारा नीति पथों के पुनर्मूल्यांकन को प्रेरित किया। तदनुसार, संभाव्य जोखिमों में बेहतर संतुलन उभरने लगा। अर्थव्यवस्थाओं में आउटपुट दिशा विचलन कम होने लगे। चक्रीय प्रभाव भी कम होने लगे। हालांकि वैश्विक संवृद्धि स्थिर प्रतीत होती है, वर्ष की दूसरी छमाही में यह ऐतिहासिक मानकों[1] के अनुसार धीमी बनी हुई है, और विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग है। कुछ उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) ने सुदृढ़ता और अनुकूलनशीलता जारी रखी है, जबकि अन्य - ज़्यादातर कम आय वाले देश (एलआईसी) - अभी भी कमज़ोर स्थिति में हैं। कुछ उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (एई) को भी मंदी का जोखिम है।

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने जुलाई 2024 के अपने हाल के विश्व आर्थिक दृष्टिकोण में वैश्विक अर्थव्यवस्था[2] के संबंध में नपे-तुले रूप में आशावादी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। उसके विचार में गतिविधि की गति में भिन्नता के कारण अर्थव्यवस्थाओं में विचलन कम हो रहा है, जबकि विश्व व्यापार मजबूत हो रहा है। 2024-25 में वैश्विक व्यापार में वृद्धि वैश्विक वृद्धि की गति के अनुरूप रहने की उम्मीद है, जिससे मध्यम अवधि में व्यापार-जीडीपी अनुपात स्थिर रहेगा। लेकिन, साथ ही बढ़ती शिपिंग लागत और लॉजिस्टिक्स व्यवधानों के साथ-साथ सीमा पार व्यापार प्रतिबंध बढ़ गए हैं। **कुल मिलाकर, भावी संभावनाओं की तुलना में जोखिमों को संतुलित माना जा रहा है, लेकिन निकट अवधि में, उनका पलड़ा भारी रहेगा। अब मैं वैश्विक स्तर पर व्यापक आर्थिक संभावना के लिए कुछ प्रमुख जोखिमों पर बात करना चाहूंगा।**

पहली बात तो यह है कि वैश्विक स्तर पर कीमतों में वृद्धि (अवस्फीति) की गति धीमी हो रही है, जिससे मौद्रिक नीति में ढील देने में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। मुद्रास्फीति की निरंतरता, विशेष रूप से सेवा क्षेत्र में, एक बड़ा जोखिम है। मजदूरी में वृद्धि और सीमित उत्पादकता, इन दोनों के भी जुड़ने से ये कारक वित्तीय मध्यस्थ संस्थाओं के तुलनपत्रों को मान्य और अमान्य मूल्यांकन घाटे के जोखिम में डाल रहे हैं। मुद्रास्फीति के बने रहने से मूल्य स्थिरता बहाल होने में देरी हो सकती है, जिससे बाह्य, राजकोषीय और वित्तीय जोखिमों में वृद्धि होती है। ऐसे परिदृश्य में केंद्रीय बैंकों द्वारा मौद्रिक नीति का प्रबंधन विवेकपूर्ण ढंग से किया जाना चाहिए, और आपूर्ति पक्ष के उपायों के लिए सरकार को सक्रिय होना चाहिए।

दूसरा, वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में ऋण का स्तर अब तक का सर्वोच्च है। अंतरराष्ट्रीय वित्त संस्थान के 2024 के अनुमानों के अनुसार यह 315 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर या वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 333 प्रतिशत के स्तर पर पहुँच गया है। इस अत्यधिक ऋण का बोझ अधिक समय तक बने रहने से ईएमई के लिए बड़ा जोखिम उत्पन्न होता है। विशेष रूप से निम्न आय और कुछ मध्यम आय वाले देश बहुत असुरक्षित हैं। अत्यधिक ऋण और उच्च ब्याज दर, दोनों के एक साथ रहने से सरकारी और निजी क्षेत्र के तुलनपत्र पर प्रतिकूल असर पड़ेगा जिससे वित्तीय अस्थिरता का दुष्चक्र बढ़ सकता है। राजकोषीय घाटे या ऋण मात्रा में शुद्ध वृद्धि महामारी-पूर्व स्तरों से अधिक है। राजकोषीय मदों में सुधार की बहुत कम गुंजाइश है, क्योंकि 2024 में कई सारे चुनाव हैं, और इसके अलावा 88 अर्थव्यवस्थाएं भी चुनाव चक्रों से गुजर रही हैं। कहने की जरूरत नहीं है कि राजकोषीय समेकन 'अवस्फीति के अंतिम चरण' को प्राप्त करने के लिए पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए, इस तरह का समेकन उनकी रेटिंग में सुधार करके पूंजी बहिर्वाह की घटनाओं और गंभीरता को भी कम कर सकता है।

तीसरा, बढ़ते और लगातार बने रहे भू-राजनीतिक जोखिम निवेशकों की जोखिम से बचने की प्रवृत्ति को और बढ़ा सकते हैं, जिससे सुरक्षा को प्राथमिकता देना और आस्तियों की कीमतों में अस्थिरता बढ़ सकती है। ऐसी स्थिति से पीड़ित देशों को अपने स्वयं के सुरक्षा उपाय करने होंगे और उचित नीति पहलों के माध्यम से अपनी सुदृढ़ता को बढ़ाना होगा।

चौथा, व्यापार संबंधी नीति में असाधारण रूप से अत्यधिक अनिश्चितता आने से बचाव वृत्ति और एकतरफा व्यापार नीतियों से जुड़े जोखिम बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली को कमजोर कर सकते

[1] 2024 और 2025 में वैश्विक वृद्धि का आईएमएफ का क्रमशः अनुमान जो ऐतिहासिक (2000-19) वार्षिक औसत 3.8 प्रतिशत से कम है।

[2] 2024 के लिए वैश्विक संवृद्धि का पूर्वानुमान आईएमएफ के अप्रैल 2024 के 3.2 प्रतिशत के आकलन पर बनाए रखा गया, जबकि 2025 के लिए इसे 10 आधार अंकों से बढ़ाकर 3.3 प्रतिशत कर दिया गया।

हैं। ऐसा परिदृश्य लंबे समय तक के लिए आर्थिक विखंडन और वैश्विक संवृद्धि को सीमित बनाए रख सकता है। बहुपक्षीय व्यापार का पुनरुद्धार और समन्वित नीति कार्रवाई इस स्थिति की तीव्रता को कम कर सकती है।

पांचवां, जलवायु परिवर्तन के परिणामस्वरूप प्रतिकूल मौसम की स्थिति संवृद्धि और मुद्रास्फीति दोनों के पथदिशाओं (ट्राजेक्ट्री) में काफी अनिश्चितता पैदा कर रही है। व्यापार प्रकृति में परिवर्तन किए जाने तथा स्वावलंबन नीतियां जलवायु परिवर्तन जैसी वैश्विक चुनौतियों से निपटने की क्षमता कमजोर कर सकती हैं। राष्ट्रों द्वारा की गई जलवायु प्रतिबद्धताओं को व्यापक रूप से स्वीकृत सामूहिक दृष्टिकोण सिद्धांत से लेकिन आवश्यकतानुसार अलग-अलग स्वरूप में पालन करते हुए पूरा किया जाना चाहिए।

ये सभी जोखिम तेजी से एक दूसरे से जुड़ते जा रहे हैं। किसी भी जोखिम के स्वरूप में हुआ परिवर्तन आमतौर पर दूसरों से संबंधित अपेक्षाओं को बदल देता है। इसलिए, नीति प्राधिकारियों और केंद्रीय बैंकों के लिए समय की यह मांग है कि वे चुस्त रहें और जोखिमों पर काबू पाने के लिए उचित दूरदर्शी उपाय और संरचनात्मक परिवर्तन करें।

III. वैश्विक वित्तीय स्थिरता जोखिम

मैं अब कुछ वैश्विक वित्तीय स्थिरता से जुड़े जोखिमों को रेखांकित करना चाहूंगा। पहली बात यह कि वैश्विक वित्तीय बाजारों ने हाल के महीनों में सुदृढ़ता दिखाई है। इसके अलावा इक्विटी और बॉन्ड प्रतिफल में तेजी आई है, अधिकांश क्षेत्र में अस्थिरता कम रही है, और कॉरपोरेट बॉन्ड स्प्रेड कम हो रहे हैं। लेकिन तुलनात्मक रूप से अधिक जोखिम वाली आस्तियों की कीमतों में तेज वृद्धि हुई है। हालाँकि शेयरों को मजबूत आय का समर्थन मिला, कॉरपोरेट स्प्रेड का कम होना कॉरपोरेट चूक[3] के बढ़ते प्रकरणों का असर है। वर्तमान परिदृश्य पिछले मौद्रिक नीति के सख़्त चक्रों से भी भिन्न है। उस समय बाजारों ने जोखिम-मुक्त भावनाएँ प्रदर्शित की थीं और जोखिम वाली आस्तियों की कीमतों में गिरावट आई थी। वर्तमान में मूल्यांकन जिस सीमा तक बढ़ा हुआ है, उससे आकस्मिक आघात का दबाव बढ़ सकता है जो बिकवाली और सामूहिक भावना के प्रभावों के माध्यम से वित्तीय बाजार क्षेत्र में संक्रामक रूप से फैलता है।

दूसरा, संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएस) में उच्च ब्याज दरों की बाजार अपेक्षाओं के साथ-साथ अन्य कारकों ने अमेरिकी डॉलर को मजबूत रखा है। वैश्विक स्तर पर सामान्य रूप से जोखिम लेने और जोखिम टालने (जनरलाइज्ड ग्लोबल रिस्क ऑन रिस्क ऑफ) जैसे वातावरण ने कई उभरते बाजारों के लिए पूंजी प्रवाह की अस्थिरता को बढ़ा दिया था[4]। इसके अलावा, मजबूत यूएसडी के कारण ईएमई का ऋण संबंधी भार और मुद्रास्फीतिक दबाव बढ़ा है। यह परिदृश्य किस हद तक प्रभावित होगा यह इस बात पर निर्भर करेगा कि यूएस फेड के नीतिगत आंकड़े और उसका समय क्या होगा, जिसके बारे में उसके द्वारा हाल ही में घोषणा की गई थी।

तीसरा, वित्तीय मध्यस्थता में गैर-बैंक संस्थानों का प्रसार उनके आकार, जटिलता और घरेलू तथा वैश्विक वित्तीय प्रणालियों के साथ उनके परस्पर जुड़ाव के कारण वित्तीय स्थिरता के लिए जोखिम पैदा कर सकता है। पिछले कुछ वर्षों में कुछ उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की एनबीएफआई में कई कमजोरियाँ उभरी हैं, जिनकी कई अवसरों पर बाज़ार बाधित[5] होने में भूमिका रही है। इन संस्थाओं के छिपे सौदे और चलनिधि बेमेल आघातों को बढ़ा सकते हैं और वित्तीय प्रणाली में तनाव बढ़ा सकते हैं।

चौथा, पिछले दस वर्षों में निजी ऋण[6] में चार गुना वृद्धि हुई है। यह अब मध्यम-बाजार की फर्मों के लिए कॉरपोरेट वित्तपोषण का एक प्रमुख स्रोत है, जिनकी आय कम या नकारात्मक है, जिन पर अत्यधिक ऋण है, और उच्च गुणवत्ता वाले संपार्श्विक की कमी है। इस प्रकार का आस्ति वर्ग बढ़ने से, तथा बड़े सौदों पर निवेश बैंकों के साथ प्रतिस्पर्धा तेज होने से, आपूर्ति-मांग संबंध का स्वरूप

[3] जुलाई 2024 तक वैश्विक कॉरपोरेट डिफ़ॉल्ट का योग 87 था, जो इसके पांच साल के औसत से अधिक है। जुलाई में डिफॉल्ट में से दो तिहाई डिफॉल्ट संकटग्रस्त एक्सचेंजों के कारण हुए और ये 2009 के बाद से अपने उच्चतम स्तर पर हैं। इसके अलावा, इन डिफॉल्ट में सर्वाधिक हिस्सा मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र तथा उपभोक्ता उत्पाद क्षेत्र का था- 'डिफॉल्ट, ट्रांजिशन, एंड रिकवरी: डिस्ट्रेस्ड एक्सचेंजेस रीच्ड देअर हाइएस्ट लेवल सिंस 2009' , एस एंड पी ग्लोबल, 15 अगस्त, 2024।

[4] वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट: दी लास्ट माइल: फाइनान्शियल वल्नराबिलीटिज़ एंड रिस्क्स, अप्रैल 2024, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष।

[5] ऑस्ट्रेलिया में गैर-बैंक वित्तीय मध्यस्थता से वित्तीय स्थिरता जोखिम। बुलेटिन - अप्रैल 2024; रिज़र्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया।

[6] सार्वजनिक प्रतिभूतियों या वाणिज्यिक बैंकों के दायरे से बाहर द्विपक्षीय समझौतों या छोटे "क्लब सौदों" के माध्यम से प्रदान किया गया गैर-बैंक कॉरपोरेट ऋण। इस परिभाषा में बैंक ऋण, व्यापक सिंडिकेट ऋण और कॉरपोरेट बॉन्ड जैसी सार्वजनिक रूप से कारोबार की जाने वाली आस्तियों के माध्यम से प्रदान की गई फंडिंग शामिल नहीं है। (वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, आईएमएफ, अप्रैल 2024)।

बदल सकता है जिसके परिणामस्वरूप हामीदारी के मानक निकृष्ट हो सकते हैं। इससे ऋण में घाटा होने की संभावना बढ़ सकती है और मौजूदा जोखिम प्रबंधन मॉडल बेअसर हो सकते हैं। निजी ऋण में हो रही तीव्र वृद्धि, बैंकों और एनबीएफआई के साथ उनका बढ़ता संबंध, और पारदर्शिता की कमी ऐसी कमजोरियाँ पैदा करती हैं जो प्रणाली को प्रभावित कर सकती हैं। दुनियाभर के विनियामकों को इन घटनाक्रमों पर करीब से नज़र डालने और आवश्यक सुरक्षा उपाय करने की ज़रूरत है।

पाँचवाँ, वैश्विक वाणिज्यिक स्थावर संपत्ति (सीआरई) क्षेत्र में तनाव पर बारीकी से नज़र रखने की ज़रूरत है[7]। बैंकों की ऋण बहियों में अपेक्षाकृत उच्च सीआरई कवरेज अनुपात के कारण अपेक्षित और अप्रत्याशित सीआरई घाटे के प्रति वे अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। इसके अलावा, बड़े सीआरई ऋण देने वाले बैंकों के लिए चलनिधि की कमी हो सकती है, क्योंकि शॉर्ट सेलर उन्हें निशाना बना सकते हैं जिससे निवेशकों का विश्वास और कम हो सकता है। जैसा कि मैंने पहले कहा था, सतर्क रहना और समय से पहले दूरदर्शी विनियामक उपाय करना बैंक तुलनपत्र और प्रणालीगत स्थिरता के जोखिमों को कम कर सकता है।

IV. लंबे समय तक अधिक ब्याज दरों का बना रहना

मौद्रिक नीति के साथ वित्तीय स्थितियों की परस्पर क्रिया वित्तीय स्थिरता के लिए भारी जोखिम प्रस्तुत कर सकती है। पिछले कुछ वर्षों में दुनिया भर में समान रूप से की गई मौद्रिक नीति सख्ती 2024 में धीरे-धीरे मौद्रिक नीति विचलन का मार्ग प्रशस्त कर रही है। हालांकि कुछ केंद्रीय बैंकों ने मंदी की चिंताओं के कारण दरों में कटौती का रास्ता अपनाना शुरू कर दिया है[8], फिर भी कई अभी भी प्रतिबंधात्मक रुख बनाए हुए हैं और मुद्रास्फीति की निरंतरता को निर्णायक रूप से कम करने के लिए नीति दरों में कटौती की नहीं सोच रहे हैं। 'लंबे समय तक उच्च' ब्याज दर के माहौल ने वित्तीय स्थिरता जोखिम को बढ़ाया है, जो कुछ उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में मार्च 2023 में देखा गया। सख्त वित्तीय स्थितियों ने इन क्षेत्राधिकारों में बैंकों के तुलनपत्रों को प्रभावित किया है। दरों में कटौती की बाजार उम्मीदें अब गति पकड़ रही हैं, खासकर यूएस फेड से नीतिगत बदलाव के संकेतों के बाद। लेकिन 'लंबे समय तक उच्च' ब्याज दर परिदृश्य से प्रतिकूल प्रसार-प्रभाव एक आकस्मिक जोखिम बना हुआ है। दूसरी ओर ऐसे केंद्रीय बैंक हैं जो स्वाभाविक और उचित रूप से अपने देशों में मुद्रास्फीति पर पूरी तरह से लगाम लगने से पहले नीति में समय से पहले ढील देने के खिलाफ़ हैं। इन देशों के केंद्रीय बैंकों को अपने घरेलू मुद्रास्फीति-संवृद्धि संतुलन पर नज़र रखने और नीतिगत विकल्प चुनने की ज़रूरत है।

V. भू-राजनीतिक जोखिम

भू-राजनीतिक जोखिमों का फिर से उभरना और उनका बने रहना वित्तीय स्थिरता के लिए उच्च जोखिम पैदा करता है क्योंकि उनके फैलने की गति बहुत तेज़ होती है और उनसे वित्तीय क्षेत्र को कई प्रकार के जोखिम हो सकते हैं। भू-राजनीतिक जोखिम न केवल युद्ध, आतंकवादी हमलों, व्यापार विवादों और राजनीतिक गतिरोधों के रूप में उत्पन्न हो सकते हैं, बल्कि आपूर्ति श्रृंखला तनाव, प्रौद्योगिकी अवरोध, साइबर हमलों और वित्तीय नियंत्रणों के माध्यम से भी उत्पन्न हो सकते हैं।

भू-राजनीतिक जोखिम सूचकांक[9] में 2024 में व्यापार और वित्तीय प्रतिबंधों के कारण तेजी से वृद्धि हुई है, जिसने कई दशकों के वैश्विक आर्थिक एकीकरण से प्राप्त लाभों को उलट दिया है[10]। भू-राजनीतिक जोखिम पूंजी प्रवाह और आस्तियों की कीमतों में अत्यधिक अस्थिरता पैदा कर रहे हैं। वे पड़ोसी या संघर्षों में सीधे शामिल न होने वाले देशों को भी प्रभावित कर रहे हैं। इन घटनाक्रमों के परिणामस्वरूप अक्सर अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली पर दबाव पड़ता है, जिससे वैश्विक भुगतान प्रणालियों की दक्षता कम हो जाती है। भले ही हमें बढ़ते वित्तीय एकीकरण से कई लाभ हो रहे हों, लेकिन यह स्पष्ट है कि भू-राजनीतिक घटनाओं से होने वाले संक्रमण के जोखिमों को अब अनदेखा नहीं किया जा सकता है, खासकर विदेशी मुद्रा, इक्विटी और ऋण बाजारों के साथ-साथ बैंकिंग प्रणाली में लेनदेन के संदर्भ में[11]।

[7] आईएमएफ के अनुसार, पिछले वर्ष के दौरान वैश्विक स्तर पर वास्तविक रूप से सीआरई की कीमतों में 12 प्रतिशत की गिरावट आई है, साथ ही यह क्षेत्र हाई वेकेन्सी दर और बढ़ती वित्तपोषण लागतों के प्रति भी संवेदनशील बना हुआ है।

[8] बैंक ऑफ कनाडा, बैंक ऑफ जापान, यूरोपीय सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ इंग्लैंड।

[9] कॅलडारा, डारियो और इएकोविएलो, मॅटेओ (2022), "मेजरिंग जिओपॉलिटिकल रिस्क", अमेरिकन इकॉनोमिक रिव्यू, खंड 112, संख्या 4, अप्रैल, पृष्ठ 1194 1225।

[10] वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, आरबीआई; जून 2024।

[11] न्गुयेनहु, टी., और ओर्सल, डी. के. (2024)। जिओपॉलिटिकल रिस्क्स एंड फिनान्शियल स्ट्रेस इन इमर्जिंग इकॉनोमीज़। दी वर्ल्ड इकॉनोमी, 47, 217–237।

भू-आर्थिक विखंडन मध्यम अवधि में वैश्विक संवृद्धि की संभावनाओं पर भारी पड़ रहा है। इससे उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के बेहतर जीवन स्तर की ओर पहुंचने में देरी हो सकती है। इसके अलावा, अतीत में भू-राजनीतिक तनावों ने आम तौर पर कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव और आपूर्ति स्थिति में व्यवधान उत्पन्न किया। इन नकारात्मक अनुभवों के चलते ऐसी स्थितियां वास्तविक अर्थव्यवस्था और वित्तीय प्रणाली पर दबाव को बढ़ाते हैं। हालांकि ऐसे जोखिमों से पूरी तरह से बचना संभव नहीं है, फिर भी व्यवस्थित निगरानी, सुरक्षा उपाय करने, आकस्मिक योजनाओं को तैयार करने और बहुपक्षीय सहयोग बढ़ाते हुए उनसे निपटना महत्वपूर्ण है।

VI. अवसर

जब हम इन जोखिमों और चुनौतियों से निपट रहे हैं, तो हमें यह भी स्वीकार करना होगा कि हमारे सामने बहुत बड़े अवसर भी हैं। मौजूदा चुनौतियों से आर्थिक लचीलेपन और मजबूत वैश्विक दृष्टिकोण के रास्ते खुलते हैं, यदि मिलजुल कर और रणनीतिक तरीके से उससे निपटा जाए। मैं इनमें से कुछ अवसरों पर प्रकाश डालना चाहूंगा।

(i) सॉफ्ट लैंडिंग की प्रबल संभावना के साथ भावी मौद्रिक नीति की दिशा यह आशा प्रदान करती है कि वैश्विक मुद्रास्फीति निरंतर नीचे की ओर जा सकती है। इससे सौम्य इनपुट लागत और श्रम बाजार के पुनरुद्धार के माहौल में संवृद्धि की नींव को मजबूत करने के लिए अवसर प्राप्त होगा। विशेष रूप से उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं के लिए यह संभावना निवेश को आकर्षित करने और टिकाऊ संवृद्धि को गति देने की क्षमता का दोहन करने के लिए मजबूत राजकोषीय, मौद्रिक और वित्तीय नीति ढांचे पर पूंजी लगाने के अवसर प्रदान करती है। यह उत्पाद-बाज़ार और कच्ची सामग्री-बाजार (प्रोडक्ट एंड फैक्टर मार्केट), दोनों में बेहतर संरचनात्मक सुधारों के चलते महामारी के बाद के लाभ को समेकित करने का भी उपयुक्त समय है।

(ii) भू-राजनीतिक वातावरण में अनिश्चितता के बावजूद, नवीनतम अनुमानों से यह संकेत मिलता है कि विश्व व्यापार में बदलाव आ रहा है[12]। यह आर्थिक विस्तार के लिए एक और ऊर्जा का माध्यम है। व्यापार नीति की अनिश्चितताओं को अधिक सशक्त तरीके से और समन्वय के साथ सुलझाने से वैश्विक समृद्धि को मजबूत करने का अवसर प्राप्त होगा।

(iii) वैश्विक संवृद्धि के सफर में वित्त की भूमिका को स्वीकार करना महत्वपूर्ण है, खासकर भारत जैसे उभरते बाजारों के लिए[13]। उपभोक्ता हितों की रक्षा को ध्यान में रखते हुए वित्तीय बाजारों के विस्तार, पहुंच और दक्षता को बढ़ाने के लिए यह एक उपयुक्त समय है। एक दूरदर्शी दृष्टिकोण के लिए विनियामक सैंडबॉक्स विकसित करना, नवोन्मेषकों के साथ सहयोग को बढ़ावा देना और विवेक तथा स्थिरता के साथ समझौता किए बिना नए खिलाड़ियों को विनियामक ढांचे में शामिल करना आवश्यक होगा।

(iv) डिजिटलीकरण की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण रही है। इससे सशक्तीकरण, उद्यमशील नवाचार, उत्पादकता को बढ़ावा मिलता है और आर्थिक परिदृश्य में अपरिवर्तनीय बदलाव लाने में मदद करता है। डिजिटलीकरण में वित्तीय समावेशन, वित्त के औपचारिकीकरण और सीमा पार भुगतान प्रणालियों में वृद्धि लाने की क्षमता है।

(v) जलवायु परिवर्तन हमें नवाचार के लिए एक और महत्वपूर्ण अवसर देता है। नई जलवायु प्रौद्योगिकियों की खोज और उनका उपयोग ऊर्जा स्वतंत्रता को बढ़ावा देने में सहायक हो सकता है, जो खासकर विकासशील देशों के लिए महत्वपूर्ण है। ग्रीन बॉन्ड जारी करने जैसे जलवायु-अनुकूल वित्तीय समाधान भी निजी क्षेत्र की भागीदारी और सहभागिता के लिए अवसर प्रदान करते हैं।

[12] डब्ल्यूटीओ गुड्स ट्रेड बैरोमीटर का वर्तमान मूल्य, जो व्यापारिक कारोबार की मात्रा के प्रक्षेपवक्र का एक प्रारंभिक संकेतक है, 103 पर है - जो तिमाही कारोबार मात्रा सूचकांक और 100 के बेसलाइन वैल्यू, दोनों से ऊपर है।

[13] संसाधनों के कुशल आवंटन और अर्थव्यवस्था की विकास क्षमता के दोहन के लिए अच्छी तरह से विकसित एक वित्तीय क्षेत्र का होना एक पूर्व शर्त है। इसके लिए, वित्तपोषण, बचत और निवेश प्रवृत्तियों तथा यहां तक कि जनसांख्यिकीय परिवर्तनों के नए स्रोतों के माध्यम से वित्तीय प्रणाली की गतिशील प्रकृति को समझना महत्वपूर्ण है।

(vi) वैश्विक आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने, संवृद्धि को बढ़ावा देने और प्रणालीगत जोखिमों को कम करने के लिए अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक और वित्तीय प्रणाली में सुधार करना महत्वपूर्ण है। मौजूदा प्रणाली ने दशकों से आर्थिक विस्तार को आधार दिया है लेकिन वह असंतुलन और अक्षमताओं की बढ़ती चुनौती का सामना कर रही है, जिसमें वैश्विक व्यापार और वित्त में कुछ मुद्राओं का प्रभुत्व होना भी शामिल है। सुधार कार्यों में वैश्विक वित्तीय अभिशासन में उभरती अर्थव्यवस्थाओं को अधिक से अधिक शामिल करने के लिए वैश्विक वित्तीय असंतुलनों को संबोधित करने की क्षमता होनी चाहिए और साथ ही वैश्विक वित्तीय सुरक्षा जाल (ग्लोबल फिनान्शियल सेफ्टी नेट, जीएफएसएन) को मजबूत करने पर भी ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

VII. निष्कर्ष

निष्कर्ष के साथ अब मैं इस अस्थिर और अत्यधिक अनिश्चित अंतरराष्ट्रीय वातावरण में भारत की संभावनाओं पर संक्षेप में बात करना चाहूँगा। भारतीय अर्थव्यवस्था कोविड-19 महामारी के कारण हुए गंभीर संकुचन से उबर गई है और 2021-24 के दौरान औसत वास्तविक जीडीपी वृद्धि 8 प्रतिशत से अधिक रही। 2024-25 के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने वास्तविक जीडीपी वृद्धि 7.2 प्रतिशत अनुमानित की है और इस पूर्वानुमान में समान रूप से संतुलित जोखिमों को विचार में लिया गया है। संवृद्धि का यह परिदृष्य भारत की व्यापक रूप से अंतर्निहित आधारभूत मजबूती को दर्शाता है, जिसमें घरेलू घटक, अर्थात निजी खपत और निवेश, एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा, संवृद्धि के दिशापथ (ट्राजेक्ट्री) को समष्टि आर्थिक और वित्तीय स्थिरता के वातावरण का आधार प्राप्त है। मुद्रास्फीति अप्रैल 2022 के अपने चरम स्तर 7.8 प्रतिशत से कम होकर 4 प्रतिशत के लक्ष्य के आसपास +/- 2 प्रतिशत के सहनीय दायरे में है, लेकिन हमें अभी भी कुछ दूरी तय करनी है और हट कर किसी अन्य विचार का जोखिम नहीं उठा सकते। रिज़र्व बैंक के अनुमान बताते हैं कि मुद्रास्फीति 2023-24 के 5.4 प्रतिशत से घटकर 2024-25 में 4.5 प्रतिशत और 2025-26 में 4.1 प्रतिशत हो सकती है। इस बीच, राजकोषीय समेकन जारी है और मध्यम अवधि के लिए लोक ऋण का स्तर घट रहा है। कॉरपोरेट प्रदर्शन में जोरदार सुधार हुआ है, जिससे ऋणभार में कमी और लाभप्रदता में मजबूत वृद्धि हुई है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय मध्यस्थों के तुलनपत्र भी मजबूत हुए हैं[14]। हमारे दबाव परीक्षणों से पता चलता है कि ये वित्तीय मध्यस्थ संस्थाएं गंभीर दबाव परिदृश्यों के तहत भी विनियामक पूंजी और चलनिधि आवश्यकताओं को बनाए रखने में सक्षम होंगी।

वैश्विक प्रगति के बारे में भारत का दृष्टिकोण अंतरराष्ट्रीय सहयोग पर जोर देता है जो जन-विशिष्ट, महत्वाकांक्षी, कार्रवाई-उन्मुख और निर्णायक है। 2023 में भारत की जी20 प्रेसीडेंसी और उसके बाद उसका निरंतर योगदान भारत के इस दृष्टिकोण को दर्शाता है कि दुनिया एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य है। इन प्राथमिकताओं में 21वीं सदी की साझा वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने के लिए बहुपक्षीय विकास बैंकों (एमडीबी) को मजबूत करना; डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के माध्यम से वित्तीय समावेशन और उत्पादकता लाभ प्राप्त करना; निम्न और मध्यम आय वाले देशों के लिए ऋण समाधान; और भविष्य के शहरों को वित्तपोषित करना, आदि शामिल हैं।

अंत में मैं यह कहना चाहूंगा कि भारत दुनिया की बेहतरी के लिए आने वाले दशकों में वैश्विक व्यवस्था को फिर से आकार देने के लिए प्रतिबद्ध है। अब समय आ गया है कि सभी लोग पूरी मानव जाति के लिए 'एक भविष्य' के लिए काम करें।

---

[14] (i) बैंकों का सकल गैर-निष्पादित आस्ति (जीएनपीए) अनुपात जून 2024 के अंत में 2.7 प्रतिशत था, जो मार्च 2011 के अंत के बाद सबसे कम था। वार्षिक स्लिपेज अनुपात, जो मानक अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में नए एनपीए अभिवृद्धि को मापता है, लगातार घटता रहा और जून 2024 के अंत में 1.3 प्रतिशत पर पहुंचा। प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर) में सुधार जारी रहा और वह जून 2024 के अंत तक 76.5 प्रतिशत पर पहुँच गया। पूंजी बनाम जोखिम-भारित आस्ति अनुपात (सीआरएआर) जून 2024 के अंत में 16.8 प्रतिशत रहा, जो विनियामक सीमा से बहुत अधिक है। वार्षिक लाभप्रदता संकेतक, अर्थात् आस्तियों पर प्रतिफल (आरओए) और इक्विटी पर प्रतिफल (आरओई) जून 2024 के अंत में क्रमशः 1.4 प्रतिशत और 14.5 प्रतिशत रहा, जो निरंतर सुधार दर्शाता है। (ii) जून 2024 के अंत में एनबीएफसी का जीएनपीए अनुपात 2.8 प्रतिशत था, जो मार्च 2021 के अंत के बाद सबसे कम है। इसी तरह, जून 2024 के अंत में एनएनपीए अनुपात में सुधार होकर वह 1.0 प्रतिशत हो गया। वार्षिक स्लिपेज अनुपात, जो मानक अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में नए एनपीए अभिवृद्धि को मापता है, लगातार घटते हुए जून 2024 के अंत में 2.6 प्रतिशत पर पहुंचा। प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर) में सुधार जारी रहा और जून 2024 के अंत तक वह 61.5 प्रतिशत पर पहुंच गया। पूंजी बनाम जोखिम-भारित आस्ति अनुपात (सीआरएआर) जून 2024 के अंत में 26.6 प्रतिशत रहा, जो विनियामक सीमा से काफी ऊपर है। वार्षिक लाभप्रदता संकेतक, अर्थात् आस्तियों पर प्रतिफल (आरओए) और इक्विटी पर प्रतिफल (आरओई) जून 2024 के अंत में क्रमशः 3.2 प्रतिशत और 11.6 प्रतिशत रहा, जो निरंतर सुधार दर्शाता है।

*भारत एक महत्वपूर्ण मोड़ पर : कुछ विचार**

श्री शक्तिकान्त दास

मुझे एफआईबीएसी वार्षिक सम्मेलन में पुन: आकर खुशी हो रही है। यह सम्मेलन विशेष है क्योंकि यह उद्योग जगत के नेताओं, वित्तीय क्षेत्र के खिलाड़ियों और विनियामकों को वर्तमान के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच पर लाता है। मैं इस वार्षिक सम्मेलन के आयोजन के लिए फिक्की और आईबीए को बधाई देता हूँ।

भारतीय अर्थव्यवस्था अब एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों और बाजारों में बड़े पैमाने पर बदलाव हो रहे हैं और देश महत्वपूर्ण परिवर्तन के लिए तैयार है। एक उन्नत अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में हमारा देश कई कारकों के अनूठे मिश्रण से ताकत हासिल कर रहा है। इसकी आबादी युवा और गतिशील है, अर्थव्यवस्था सुदृढ़ और विविधतापूर्ण है, लोकतंत्र मजबूत है और इसके पास उद्यमिता और नवाचार की समृद्ध परंपरा है।

इस पृष्ठभूमि में मैंने "भारत एक महत्वपूर्ण मोड़ पर: कुछ विचार" विषय को चुना है। मैं चार मुद्दों पर बात करूंगा। सबसे पहले, मैं भारत की विकास संभावनाओं और उस दृष्टिकोण पर बात करूँगा जिसका हमें आगे बढ़ने के लिए पालन करने की आवश्यकता है। दूसरा, मैं मुद्रास्फीति और मौद्रिक नीति में हाल के घटनाक्रमों पर विस्तार से चर्चा करूंगा। तीसरा, मैं हमारे वित्तीय क्षेत्र को मजबूत बनाने से संबंधित कुछ मुद्दों पर प्रकाश डालना चाहूंगा और अंत में मैं वित्तीय क्षेत्र से जो अपेक्षाएं हैं उन्हें बताना चाहूंगा।

I. विकास की संभावनाएँ

भारतीय अर्थव्यवस्था ने कोविड-19 के कारण हुए संकुचन के बाद मजबूती से वापसी की है और पिछले तीन वर्षों के दौरान संवृद्धि 8.3 प्रतिशत की प्रभावशाली वार्षिक औसत दर से बढ़ रही है। चालू वित्त वर्ष के लिए, रिज़र्व बैंक ने 7.2 प्रतिशत की संवृद्धि दर का अनुमान लगाया है। आईएमएफ ने भी निजी खपत, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर संभावनाओं का हवाला देते हुए भारत की जीडीपी वृद्धि को संशोधित कर 7.0 प्रतिशत कर दिया है। दो दिन पहले, विश्व बैंक ने भी 2024-25 के लिए भारत के संवृद्धि पूर्वानुमान को बढ़ाकर 7.0 प्रतिशत कर दिया है।

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) ने 2024-25 की पहली तिमाही में भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान 6.7 प्रतिशत रखा है। पिछली तिमाही से संवृद्धि नरम रहने और पहली तिमाही में हमारे अनुमान से कम होने के बावजूद, आकंड़ों से पता चलता है कि बुनियादी विकास के चालक गति पकड़ रहे हैं। इससे हम यह कह सकते हैं कि **भारतीय विकास की गाथा बरकरार है**।

निजी खपत, जिसका कुल मांग में प्रमुख स्थान है और सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 56 प्रतिशत की हिस्सेदारी है, में वृद्धि 7.4 प्रतिशत पर पहुंच गई जबकि पिछले वर्ष की दूसरी छमाही में 4 प्रतिशत की कमजोर वृद्धि थी। इससे ग्रामीण मांग के पूर्ववत होने की पुष्टि होती है। संवृद्धि का दूसरा महत्वपूर्ण चालक, अर्थात निवेश, जो सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 35 प्रतिशत है, अपनी हालिया गति को बनाए रखते हुए 7.5 प्रतिशत की दर से बढ़ा। इस प्रकार, सकल घरेलू उत्पाद का 90 प्रतिशत से अधिक अंश मजबूत गति से बढ़ा और वास्तव में 7 प्रतिशत से ऊपर रहा जबकि हेडलाइन आंकड़ा कम रहा। इसका कारण संभवत: केंद्र और राज्यों में लोकसभा चुनाव का होना हो सकता है जिसके कारण सरकारी व्यय में कमी रही। सरकारी उपभोग व्यय को छोड़ दें तो सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि 7.4 प्रतिशत रही।

आपूर्ति पक्ष देखें तो कृषि क्षेत्र में पहली तिमाही में मामूली अर्थात 2 प्रतिशत की वृद्धि रही लेकिन मानसून की अच्छी प्रगति, खरीफ की बेहतर बुवाई और रबी फसलों के लिए अच्छी नमी की स्थिति को देखते हुए आगे चलकर इसके बेहतर प्रदर्शन की संभावना है। उद्योग और सेवाओं ने पहली तिमाही में क्रमशः 7.4 प्रतिशत और 7.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की, जो आर्थिक गतिविधि में निरंतर मजबूती दर्शाती है। निर्माण गतिविधि 10.5 प्रतिशत की दर से मजबूत रही।[1]

* भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकान्त दास द्वारा फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) और भारतीय बैंक संघ (आईबीए) द्वारा संयुक्त रूप से 5 सितंबर 2024 को मुंबई में आयोजित वार्षिक एफआईबीएसी 2024 सम्मेलन में दिया गया उद्घाटन भाषण।

[1] 2023-24 के दौरान 9.9 प्रतिशत की वृद्धि के बाद, 2024-25 की पहली तिमाही में निर्माण गतिविधि 10.5 प्रतिशत की तीव्र गति से बढ़ती रही।

आरबीआई के नवीनतम आंकड़ों[2] के अनुसार कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए बैंक ऋण मजबूत रहा और इसमें 18.1 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि हुई। जुलाई 2024 में उद्योग क्षेत्र को दिए गए ऋण में 10.2 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि हुई, जबकि जुलाई 2023 में वह 4.6 प्रतिशत थी। उद्योगक्षेत्र के भीतर, एमएसएमई ऋण में भी 14.4 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि हुई। रसायन और रासायनिक उत्पाद; खाद्य प्रसंस्करण; पेट्रोलियम, कोयला उत्पाद और परमाणु ईंधन; और बुनियादी ढाँचा जैसे उद्योगों को दिया गया बैंक ऋण जुलाई 2024 में काफी मजबूत रहा है। उद्योगक्षेत्र को बढ़ा हुआ ऋण प्रवाह और अब तक का सबसे उच्च क्षमता उपयोग निवेश चक्र में वृद्धि की ओर इशारा करता है, जैसा कि एनएसओ आंकड़ों से परिलक्षित होता है।

यह स्पष्ट है कि भारत निरंतर विकास पथ पर है। संवृद्धि के दो मुख्य चालक – खपत और निवेश मांग, दोनों एक साथ बढ़ रहे हैं। केंद्र और राज्यों का सरकारी व्यय वर्ष की शेष तिमाहियों में बजट अनुमानों के अनुरूप गति पकड़ने की संभावना है। बैंकों और कॉरपोरेट्स की मजबूत बैलेंस शीट ने निजी पूंजीगत व्यय को और अधिक समर्थन देने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाई हैं। 2024-25 की पहली तिमाही में कॉरपोरेट मुनाफे (निवल) में 14.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।[3] सरकारी पूंजीगत व्यय मजबूत बना हुआ है। कुल मिलाकर, 2024-25 के लिए जीडीपी वृद्धि का रिज़र्व बैंक का 7.2 प्रतिशत का अनुमान समुचित प्रतीत होता है।

मध्यम से दीर्घावधि में विकास की संभावनाओं के संबंध में ऐसा महसूस होता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था परिवर्तनकारी बदलावों के मोड़ पर है। इस तथ्य से, कि वैश्विक विकास मामूली रहने और वैश्विक चुनौतियां बनी रहने के बावजूद विकास की प्रवृत्ति बढ़ रही है, यह संकेत मिलता है कि संरचनात्मक चालक भारत के व्यापक आर्थिक परिणामों में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। इन चालकों में शामिल हैं: मजबूत भौतिक अवसंरचना के निर्माण पर नीतिगत जोर; तेजी से बढ़ती हमारी डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना; विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार और प्रौद्योगिकीय प्रगति; तथा प्रमुख क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सुधार।

2047 तक उभरती अर्थव्यवस्था से उन्नत अर्थव्यवस्था में बदलने की आकांक्षा को साकार करने के लिए, **भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुआयामी और बहु-क्षेत्रीय दृष्टिकोण की आवश्यकता होगी**। हमारा ध्यान आपूर्ति और मांग, दोनों पक्षों से विकास के सभी चालकों को नियोजित करने पर होना चाहिए। आपूर्ति पक्ष की प्राथमिकता में कृषि, उद्योग और सेवाओं को शामिल किया जाना चाहिए। हमें इस तथ्य के प्रति सचेत रहना चाहिए कि भारत में कृषि में अपार संभावनाएं हैं। बागवानी, खाद्य तेल, डेयरी, पोल्ट्री, खाद्य प्रसंस्करण आदि में कृषि-वाणिज्यिक गतिविधियाँ महत्वपूर्ण क्षेत्र हो सकती हैं। हमारा दृष्टिकोण उत्पादकता के साथ-साथ अपने उत्पादन की गुणवत्ता को बढ़ाने का होना चाहिए ताकि हम अपनी घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करते हुए विश्व निर्यात में महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकें।

अधिक रोजगार पैदा करने में विनिर्माण क्षेत्र का संभाव्य योगदान महत्वपूर्ण होगा। 'मेक इन इंडिया', 'स्टार्ट अप इंडिया', 'एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी)' और 'उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई)' योजना जैसी पहलें विनिर्माण क्षेत्र को प्रतिस्पर्धात्मकता हासिल करने और तेजी से बढ़ने में मदद कर रही हैं। विशेष रूप से एमएसएमई क्षेत्र संवृद्धि और रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए बहुत आशाजनक है। कुल मिलाकर, विनिर्माण क्षेत्र को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए विशिष्ट क्षेत्रों में अग्रणी होना चाहिए।

सेवा क्षेत्र, जो पिछले कई दशकों से विकास का मुख्य आधार बना हुआ है, को उच्च मूल्य-वर्धित सेवाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए अवसरों के नए आयाम तलाशने चाहिए। इसके अलावा, उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता के लिए अनुसंधान और विकास पर अपेक्षित ध्यान दिया जाना भी महत्वपूर्ण है। अनुसंधान और विकास के लिए अधिक निधि आबंटन तथा सरकारी पहलों के साथ, निजी क्षेत्र भी इस क्षेत्र में सक्रिय भागीदार हो सकता है।

जैसा कि मैंने पहले कहा था, खपत जैसे प्रमुख मांग चालकों, निवेश और वस्तुओं तथा सेवा निर्यात की गति एक जैसी होनी चाहिए। घरेलू खपत अधिक होने से अर्थव्यवस्था को बाहरी अनिश्चितताओं से बचाने में मदद होगी। अर्थव्यवस्था के टिकाऊ विकास के लिए निवेश महत्वपूर्ण है और अनुकूल कारकों के वर्तमान संगम को देखते हुए निजी कॉरपोरेट क्षेत्र को बड़े पैमाने

---

[2] बैंक ऋण का क्षेत्रीय प्रयोग - जुलाई 2024 (आरबीआई द्वारा 30 अगस्त 2024 को जारी डेटा)।

[3] 2,934 सूचीबद्ध निजी गैर-वित्तीय कॉरपोरेट्स के निवल मुनाफे में 2024-25 की पहली तिमाही में 14.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि 2023-24 की चौथी तिमाही में यह 6.4 प्रतिशत थी। (2024-25 की पहली तिमाही के दौरान निजी कॉरपोरेट व्यवसाय क्षेत्र का प्रदर्शन, आरबीआई द्वारा 30 अगस्त, 2024 को जारी)।

पर आगे आने का समय है। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के साथ जुड़ते हुए बाहरी मांग की क्षमता का हमारे लाभ के लिए उपयोग किया जा सकता है।

अर्थव्यवस्था के व्यापक आधार वाले विकास को बढ़ावा देने और उसको गति देने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण के लिए **पिछले सुधारों के लाभों को संरक्षित करना और अधिक सुधारों के साथ भारत की सुधार यात्रा को गति देना भी आवश्यक होगा**। आर्थिक दृष्टिकोण से, ऐसे सुधार जिन्होंने बड़े परिवर्तन किए हैं और हमारी स्थिरता और विकास के प्रयासों को मजबूत किया है, उनमें शामिल हैं: (i) रुपये की प्रशासित विनिमय दर से बाजार निर्धारित व्यवस्था में परिवर्तन; (ii) रिज़र्व बैंक द्वारा बजट घाटे के वित्तपोषण के स्वचालित मुद्रीकरण को रोकना; (iii) राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएफ) अधिनियम बनाना; (iv) लचीले मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण ढांचे की शुरुआत; (v) दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) का अधिनियमन; और (vi) माल और सेवा कर (जीएसटी) का कार्यान्वयन। इन छह सुधारों में से प्रत्येक ने दीर्घकालिक सकारात्मक परिणाम दिए हैं। इन सुधारों को भूमि, श्रम और कृषि बाजारों में सुधारों द्वारा बढ़ाया जाना चाहिए। हालांकि हमने इन क्षेत्रों में कुछ प्रगति की है, अभी भी राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। कारोबार करने में सरलता बढ़ाने से, विशेष रूप से स्थानीय स्तर पर, हमारी प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा मिलेगा।

II. मुद्रास्फीति और मौद्रिक नीति

2022 की शुरुआत में यूक्रेन युद्ध छिड़ने के बाद खाद्य, कमोडिटी और ऊर्जा की कीमतों में उछाल आने के कारण मुद्रास्फीतिक दबाव में तीव्र वृद्धि हुई। प्रतिकूल घरेलू मौसम के सतत आघातों ने इसे और तीव्र कर दिया। रिज़र्व बैंक द्वारा उठाए गए निर्णायक कदमों, सरकार की ओर से आपूर्ति पक्ष के उपायों और अंतरराष्ट्रीय पण्य कीमतों में गिरावट के कारण 2023-24 की शुरुआत से मुद्रास्फीति में गिरावट आई। फिर भी, अस्थिर और उच्च खाद्य मुद्रास्फीति से अवस्फीति की गति अक्सर बाधित होती है। यह हेडलाइन मुद्रास्फीति है जो मायने रखती है। हेडलाइन मुद्रास्फीति में खाद्य मुद्रास्फीति का भार 46 प्रतिशत है जिसे लोग समझते हैं। मानसून के अच्छे रहने और खरीफ की अच्छी बुवाई से बेहतर फसल की संभावनाएँ बढ़ने से इस बात की अधिक आशा है कि वर्ष के दौरान खाद्य मुद्रास्फीति की स्थिति अधिक अनुकूल हो।

हमें इस बात पर नज़र रखनी होगी कि मुद्रास्फीति को प्रभावित करने वाली ताकतें कैसे काम करती हैं। मुद्रास्फीति और संवृद्धि के बीच संतुलन अच्छी तरह से बना हुआ है। हमें अवस्फीति के अंतिम पड़ाव को सफलतापूर्वक पार करना होगा, तथा लचीले मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण (एफआईटी) ढांचे की विश्वसनीयता को बनाए रखना होगा जो एक प्रमुख संरचनात्मक सुधार है। मौद्रिक नीति द्वारा टिकाऊ संवृद्धि के लिए किया जा सकने वाला सबसे अच्छा योगदान मूल्य स्थिरता को बनाए रखना है।

III. वित्तीय क्षेत्र - भविष्य के लिए नींव को मजबूत करना

भारत के वित्तीय क्षेत्र ने चुनौतियों और संकटों से पार पाने की अपनी क्षमता का समय-समय पर प्रदर्शन किया है। वित्तीय क्षेत्र ने कोविड-19 महामारी के दौरान और उसके बाद उल्लेखनीय सुदृढ़ता दिखाई। आज वित्तीय क्षेत्र के सभी प्रमुख संकेतक इसके मजबूत स्वास्थ्य को दर्शाते हैं[4]। यह सुदृढ़ता, अन्य ताकतों के साथ मिलकर भारत के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण प्रेरक शक्ति के रूप में कार्य कर सकती है।

इस परिवेश में, वित्तीय क्षेत्र को वित्तीय समावेशन अधिक गहरा करने, ऋण और अन्य वित्तीय उत्पादों तक पहुँच को व्यापक बनाने और समग्र समावेशी विकास का समर्थन करने की आवश्यकता है। उसे डिजिटल बैंकिंग में नवाचार को बढ़ावा देने, टिकाऊ वित्त को बढ़ावा देने और एक मजबूत वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र बनाने की भी आवश्यकता है जो उभरती चुनौतियों का सामना कर सके और विकास के दिशापथ को बेहतर बनाने में मदद कर सके।

[4] बैंकों का जीएनपीए अनुपात जून 2024 के अंत में 2.7 प्रतिशत था, जो मार्च 2011 के अंत के बाद से सबसे कम था। वार्षिक स्लिपेज अनुपात, जो मानक अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में नए एनपीए अभिवृद्धि को मापता है, जून 2024 के अंत में लगातार घटते हुए 1.3 प्रतिशत पर पहुंचा है। प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर) में सुधार जारी रहा और जून 2024 के अंत तक यह 76.5 प्रतिशत पर पहुंच गया। पूंजी तथा जोखिम-भारित आस्ति अनुपात (सीआरएआर) जून 2024 के अंत में 16.8 प्रतिशत रहा, जो विनियामक सीमा से काफी ऊपर है। वार्षिक लाभप्रदता संकेतक, अर्थात् आस्तियों पर प्रतिफल (आरओए) और इक्विटी पर प्रतिफल (आरओई) जून 2024 के अंत में क्रमशः 1.4 प्रतिशत और 14.2 प्रतिशत रहे, जो निरंतर सुधार दर्शाते हैं।

चूंकि वित्तीय क्षेत्र अब एक मजबूत स्थिति में है, इसलिए इस स्थिरता को सुरक्षित रखना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है, खासकर बढ़ी हुई वैश्विक अनिश्चितता के माहौल में। वित्तीय संस्थानों को अपने व्यवसाय मॉडल का लगातार मूल्यांकन और परिशोधन करना चाहिए, उभरते जोखिमों को पहचानना और उनसे निपटना चाहिए और हर नए अवसर का लाभ उठाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

अब समावेशी विकास के महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करते हैं। हालांकि जीडीपी और प्रति व्यक्ति जीडीपी जैसे आर्थिक विकास के पारंपरिक आंकड़े प्रगति के महत्वपूर्ण संकेतक हैं, किंतु वे अकेले किसी राष्ट्र के लिए वास्तव में विकसित होने के मतलब की पूरी तस्वीर नहीं दिखाते हैं।

भारत ने लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में उल्लेखनीय प्रगति[5] की है। एक सच्चे विकसित भारत को यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रत्येक नागरिक की, चाहे उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, वित्तीय सेवाओं तक पहुँच हो और उसके पास आवश्यक वित्तीय साक्षरता हो। वित्तीय क्षेत्र बैंकिंग, ऋण और बीमा तक पहुँच का विस्तार करके और डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म की शक्ति का उपयोग करके हाशिए पर खड़े वर्गों तक पहुँचकर समावेशी विकास को आगे बढ़ा सकता है।

प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (पीएसएल) कार्यक्रम वंचित वर्गों के संबंध में ऋण अंतराल को दूर करने में महत्वपूर्ण है। बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट (बीसी) की शुरुआत ने वित्तीय पहुँच को आगे बढ़ाया है। रिज़र्व बैंक द्वारा पेश किया गया वित्तीय समावेशन सूचकांक 2021 के 53.9 से बढ़कर 64.2 हो गया है, जो वित्तीय सेवाओं तक पहुँच प्रदान करने में की गई प्रगति को दर्शाता है। हालाँकि, इन सेवाओं के उपयोग और गुणवत्ता में सुधार के लिए अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है।

दो और प्रमुख चालकों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए: वित्तीय साक्षरता को बढ़ाना और प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना। रिज़र्व बैंक ने वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए स्व-संचालित और सहयोगी दोनों तरीकों को अपनाया है। हम मल्टीमीडिया जन जागरूकता अभियान और आउटरीच कार्यक्रम चलाते हैं और साथ ही लक्षित वित्तीय साक्षरता जागरूकता कार्यक्रम भी चलाते हैं। रिज़र्व बैंक ने अन्य वित्तीय विनियामकों के साथ सहयोग करते हुए वित्तीय साक्षरता प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केंद्र (एनसीएफई) की स्थापना में सहायता की है। बैंकों और गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से, देश के लगभग सभी ब्लॉकों को शामिल करते हुए 2,421 वित्तीय साक्षरता केंद्र भी स्थापित किए गए हैं।

प्रौद्योगिकी के मोर्चे पर रिज़र्व बैंक ने डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और नवाचार के विकास को सुगम बनाने के लिए कई उपाय किए हैं। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) ने डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। रेगुलेटरी सैंडबॉक्स और इनोवेशन हब जैसी अन्य पहलों ने हमारे फिनटेक इकोसिस्टम को समृद्ध करने के लिए एक मजबूत वातावरण को बढ़ावा दिया है। अबाधित ऋण के लिए रिज़र्व बैंक की पायलट परियोजना, अर्थात् एकीकृत ऋण इंटरफेस (यूएलआई) के एंड-टू-एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत से ऋण तक पहुंच में क्रांतिकारी बदलाव आने की उम्मीद है, विशेष रूप से किसानों और एमएसएमई के लिए।

IV. वित्तीय क्षेत्र से अपेक्षाएँ

वित्तीय स्थिरता और वित्तीय समावेशन की सुरक्षा के बारे में बात करने के बाद, मैं अब कुछ विशिष्ट क्षेत्रों पर प्रकाश डालना चाहूँगा जहाँ मेरा मानना है कि वित्तीय क्षेत्र भारत की विकास आकांक्षाओं में योगदान दे सकता है।

(ए) महिला श्रम भागीदारी में सुधार

भारत की महिला श्रम शक्ति भागीदारी वैश्विक औसत से कम है। यह अंतर लड़कियों की शिक्षा, कौशल विकास, कार्यस्थल सुरक्षा में सुधार और सामाजिक बाधाओं को दूर करने जैसी लक्षित पहलों की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करता है।

उद्यमिता आर्थिक सशक्तीकरण का एक महत्वपूर्ण घटक है। फिर भी भारत में, एमएसएमई के पांचवें हिस्से से कम महिलाओं के स्वामित्व में है। महिला उद्यमियों को अक्सर पूंजी तक सीमित पहुँच, प्रतिबंधात्मक सामाजिक मानदंड और किफायती वित्त तक

[5] नीति आयोग द्वारा जारी भारत में बहुआयामी गरीबी पर एक चर्चा पत्र के अनुसार, भारत में बहुआयामी गरीबी 2013-14 के 29.17 प्रतिशत से घटकर 2022-23 में 11.28 प्रतिशत हो गई, जबकि इस अवधि के दौरान लगभग 24.82 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले। 2005-06 से भारत में बहुआयामी गरीबी - एक चर्चा पत्र, प्रो. रमेश चंद और डॉ. योगेश सूरी, नीति आयोग, जनवरी 2024।

पहुँचने में कठिनाइयों सहित बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। वित्तीय क्षेत्र को सहायक नीतियों को लागू करके, अनुरूप वित्तीय उत्पाद बनाकर और वित्त तक बेहतर पहुँच प्रदान करने के लिए फिनटेक नवाचारों का लाभ उठाते हुए इस लैंगिक अंतर को पाटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। इसे दो मोर्चों पर आगे बढ़ाया जा सकता है - पहला, वित्तीय संस्थानों में महिलाओं को अधिक रोजगार के अवसर प्रदान करके; और दूसरा, सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के साथ-साथ महिलाओं द्वारा चालित व्यवसायों के अनुरूप बैंकों की अपनी योजनाओं के माध्यम से महिला उद्यमियों का समर्थन करके। बैंक सक्रिय रूप से बड़ी संख्या में महिला बीसी यानी 'बैंक साथी' या 'सखी' को शामिल करने पर भी विचार कर सकते हैं, खासकर एसएचजी सदस्यों में से।

(बी) *एमएसएमई का समर्थन*

हमारी बड़ी युवा आबादी को देखते हुए हमें रोजगार और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए एमएसएमई की क्षमता का पूरी तरह से दोहन करने की आवश्यकता है। उनके महत्व के बावजूद, कई एमएसएमई छोटे आकार के बने हुए हैं और विभिन्न चुनौतियों के कारण प्रभावी रूप से बड़े पैमाने पर नहीं बढ़ पा रहे हैं, जिसमें किफायती वित्त तक पहुंच भी एक बाधा है।

वित्तीय क्षेत्र एमएसएमई का समर्थन करने में सक्रिय भूमिका निभा सकता है। बैंक और वित्तीय संस्थान एमएसएमई की जरूरतों को पूरा करने वाले अनुरूप वित्तीय उत्पाद और सेवाएं विकसित कर सकते हैं। इसमें सुविधाजनक ऋण विकल्प प्रदान करना, कार्यशील पूंजी तक पहुंच में सुधार करना और एमएसएमई के विशिष्ट नकदी प्रवाह चक्रों और विकास चरणों को समायोजित करने वाली वित्तीय सहायता प्रदान करना शामिल है। यह एमएसएमई को विकसित करने, उनकी उत्पादकता बढ़ाने और रोजगार सृजन में अधिक महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए प्रेरित कर सकता है।

निष्कर्ष

निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था व्यापक आर्थिक और वित्तीय स्थिरता तथा अनुकूल संवृद्धि-मुद्रास्फीति संतुलन के साथ आगे बढ़ रही है। हाल के वर्षों में अपनाए गए नीति उपायों ने अर्थव्यवस्था के अंतर्निहित मूल तत्वों को मजबूत किया है और सुरक्षिततता को बढ़ाया है। खपत, जो हमारे विकास का मुख्य चालक रहा है, ने ग्रामीण मांग में सुधार के साथ गति पकड़ी है। निवेशकों का विश्वास सर्वकालिक उच्च स्तर पर है; बैंक और कॉरपोरेट के तुलनपत्र मजबूत हैं; और संरचनात्मक सुधार हमारे विकास की सीमा को आगे बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं।

हम एक गतिशील और अनिश्चित दुनिया में रह रहे हैं, और हमें सतर्क रहने और मजबूत सुरक्षा व्यवस्था बनाने की आवश्यकता है। नए अवसर हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। जब मैं हमारी युवा आबादी में उद्यमशीलता के उत्साह और प्रतिभा को देखता हूं, तो यह मुझे भारत की दीर्घकालिक विकास संभावनाओं के बारे में अधिक आश्वस्त करता है।

धन्यवाद। नमस्कार।

ग्लोबल फिनटेक फेस्ट (जीएफएफ) 2024 में संबोधन*

श्री शक्तिकान्त दास

माननीय प्रधानमंत्री महोदय, श्री कृष्ण गोपालकृष्णन, उद्योग जगत के अग्रणी सदस्य, जो प्रतिष्ठित प्रतिभागीगण, मीडिया के सदस्यगण, और देवियो और सज्जनो।

ग्लोबल फिनटेक फेस्ट (जीएफएफ) एक प्रमुख कार्यक्रम के रूप में उभरा है, जो भारतीय फिनटेक क्षेत्र में नवोन्मेषों, प्रौद्योगिकीय रूपांतरण और सहयोगात्मक भावना को प्रदर्शित करता है। कोविड-19 महामारी के बीच, वर्ष 2020 में लगभग 12,000 प्रतिभागियों के साथ वर्चुअल मोड में शुरू हुए जीएफएफ में, 2024 की स्थिति में अब तक 80,000 प्रतिभागी शामिल हो चुके हैं। यह न केवल इस आयोजन के बढ़ते दर्जे को दर्शाता है, बल्कि प्रौद्योगिकी-संचालित वित्तीय नवाचार में भारत की बढ़ती प्रधानता को भी दर्शाता है। जीएफएफ 2024 में माननीय प्रधानमंत्री की उपस्थिति हम सभी को एक फिनटेक पारितंत्र का निर्माण करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने के लिए प्रेरित करती है, एक ऐसा पारितंत्र जो वास्तव में भविष्य के लिए तैयार हो।

इस प्रयास में, हमारी प्राथमिकता एक ऐसा परिवेश बनाने की होनी चाहिए जहाँ वित्तीय सेवाएँ हमारे 1.4 अरब लोगों के जीवन में सहज रूप से एकीकृत हों। भारत अब एक परिवर्तन के मुहाने पर खड़ा है, जहाँ प्रत्येक नागरिक की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रौद्योगिकी एक महत्वपूर्ण साधन बनेगी।

फिनटेक पारितंत्र मोबाइल बैंकिंग से लेकर डिजिटल भुगतान, एआई-आधारित उधार देना और ब्लॉकचेन नवोन्मेषों तक, हमारी उभरती अर्थव्यवस्था की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लगातार विकसित हो रहा है। डिजिटल प्रौद्योगिकियां देश भर में वित्तीय समावेशन का विस्तार करने, दक्षता में सुधार लाने और तत्काल सेवाओं को सक्षम बनाने में सहायक रही हैं। डिजिटल भुगतान में आज भारत वैश्विक स्तर पर अगुवाई कर रहा है, यह उपलब्धि नवोन्मेष और प्रौद्योगिकीय उन्नति के साथ सक्रिय नीति निर्माण के संयोजन से हासिल की गई है।

नीति निर्माताओं, विनियामकों और नवप्रवर्तकों के बीच सहयोग भारत की फिनटेक यात्रा का निर्णायक तत्व है। हमारे फिनटेक क्षेत्र में सफलता की कहानियाँ यथा आधार, यूपीआई और डिजीलॉकर - ऐसे ही सहयोगात्मक प्रयासों का परिणाम हैं।

एकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क, यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस (यूएलआई), ओपन क्रेडिट इनेबलमेंट नेटवर्क (ओसीईएन) और कई अन्य पहलों के माध्यम से क्रेडिट तक पहुंच की नई परिभाषा गढ़े जाने की उम्मीद है, विशेषकर लघु व्यवसायों और व्यक्तियों के लिए। रिज़र्व बैंक के विनियामक ढांचों ने नए और नवोन्मेषी कारोबारों को व्यवस्थित तरीके से बढ़ने में मदद की है। ये विनियामकीय पहलें, विवेकपूर्ण तरीके से नवोन्मेष का समर्थन करने की हमारी प्रतिबद्धता दर्शाती है।

हमारा दृष्टिकोण सहयोगात्मक है। विशेषज्ञों और हितधारकों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के बाद अंततः विनियम जारी किए जाते हैं। जैसे कि मैंने दो दिन पहले इस मंच पर बात कही थी, पिछले एक वर्ष में, रिज़र्व बैंक के विभिन्न विभागों के अधिकारी और दल द्विपक्षीय रूप से लगभग 750 विचार-विमर्श सत्रों में शामिल हुए हैं और फिनटेक भागीदारों के साथ लगभग 50 संरचित बैठकें की हैं।

जैसे-जैसे हम वर्ष 2047 में भारत@100 की ओर आगे बढ़ते हैं, मैं इस जीएफएफ के प्रत्येक प्रतिभागी और अन्य लोग जो इसमें भाग नहीं ले सके, उनसे आग्रह करता हूं कि वे सपने देखना, नवोन्मेष करना और उम्मीद से अधिक कड़ी मेहनत करना जारी रखें।

धन्यवाद।

* दिनांक 30 अगस्त 2024 को मुंबई में भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकान्त दास द्वारा ग्लोबल फिनटेक फेस्ट (जीएफएफ) 2024 में संबोधन।

इंडिया@100 के लिए फिनटेक नवोन्मेष: भारत के वित्तीय परिदृश्य के भविष्य को आकार देना*

श्री शक्तिकान्त दास

ग्लोबल फिनटेक फेस्ट (जीएफएफ) के 5वें संस्करण में भाग लेकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। मैं इस वर्ष के जीएफएफ के लिए फिनटेक नवोन्मेषकों और कंपनियों, बैंकों, एनबीएफसी, विनियामकों और अन्य सहित फिनटेक पारितंत्र से विविध हितधारकों को एक साथ लाने के लिए आयोजकों - एनपीसीआई, पीसीआई और एफसीसी[1] को बधाई देना चाहता हूँ। यह कार्यक्रम न केवल फिनटेक उद्योग बल्कि विस्तृत प्रौद्योगिकी पारितंत्र के कैलेंडर में भी एक बहुप्रतीक्षित कार्यक्रम बन गया है।

जीएफएफ, विचारों के एक सच्चे मिश्रण का प्रतिनिधित्व करता है, जहां अभिनव अवधारणाएं और विविध दृष्टिकोण हमारे वित्तीय क्षेत्र के डिजिटल भविष्य को आकार देने की क्षमता के साथ एक साथ आते हैं। यह हमारे लक्ष्यों और रणनीतियों को संरेखित करने का एक अनूठा अवसर भी प्रदान करता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि फिनटेक पारितंत्र गतिशील और स्थायी रूप से विकसित होता रहे।

भारत अब एक तेजी से उभरती हुई आर्थिक शक्ति है, जिसकी तकनीक के प्रति जागरूक आबादी बढ़ती जा रही है। भारत के वित्तीय क्षेत्र में उल्लेखनीय परिवर्तन देखने को मिला है, जो अन्य कारकों के अलावा फिनटेक क्षेत्र द्वारा संचालित है। सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी[2] के अनुसार भारत में संस्थापित फिनटेक की संख्या लगभग ग्यारह हजार (11,000) है। इस क्षेत्र को केवल पिछले दो वर्षों में ही लगभग 6 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश प्राप्त हुआ है।

मैं आज अपने संबोधन में तीन प्रमुख पहलुओं पर प्रकाश डालना चाहता हूँ: (i) इंडिया@100 के लिए प्राथमिकताएं निर्धारित करना; (ii) भावी प्रौद्योगिकियां; और (iii) फिनटेक के लिए विनियामकीय संरचना।

I. इंडिया@100 के लिए प्राथमिकताएं निर्धारित करना

मैं महात्मा गांधी के कथन को उद्धृत करके शुरुआत करना चाहूंगा, जिन्होंने कहा था: "भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि हम वर्तमान में क्या करते हैं"। इसलिए, जैसे-जैसे हम 2047 में भारत की स्वतंत्रता की शताब्दी की ओर अपनी यात्रा पर आगे बढ़ रहे हैं, हमारे वित्तीय परिदृश्य, इसकी आवश्यकताओं और इसे आकार देने वाली प्रौद्योगिकियों के भविष्य पर विचार करना और कल्पना करना आवश्यक होगा।

यह यात्रा प्रौद्योगिकी, विनियमन, भू-राजनीति और सामाजिक अपेक्षाओं में गतिशील बदलावों द्वारा चिह्नित होगी। वित्तीय क्षेत्र तेजी से डिजिटलीकरण और नवाचार का अनुभव कर रहा है। जबकि हम सभी वित्तीय समावेशन को बढ़ाने, डिजिटल भुगतानों को अनुकूलित करने तथा ब्लॉकचेन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसी उभरती हुई प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने का प्रयास करते हैं, हम वैश्विक वित्तीय प्रणाली की अंतर्निहित अप्रत्याशितता और अंतर्संबद्धता का भी सामना करते हैं। इस माहौल में एक ऐसी मानसिकता विकसित करना जो कि व्यवधान का अनुमान लगा कर, विवेक के साथ बदलाव को अपनाती है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए, एक जैसी वित्तीय संस्थाओं और फिनटेक स्टार्टअप्स को तेजी से अनुकूलन करना चाहिए, नए अवसरों को भुनाने के लिए कुशल रणनीतियों और मजबूत ढांचों का लाभ उठाना चाहिए और संबद्ध जोखिमों को कम करना चाहिए।

भारत के वित्तीय पारितंत्र में हितधारकों - बैंक, गैर-बैंक, फिनटेक, विनियामक और सरकार - पर यह निर्भर करता है कि वे सुदृढ़ता बनाए रखते हुए नवाचार को बढ़ावा दें। जबकि फिनटेक पारितंत्र उपभोक्ताओं के लिए वित्त के अति-आवश्यक वैयक्तिकरण और संदर्भीकरण की शुरुआत कर रहा है, वृहत समाज की सेवा करने वाली वित्तीय प्रणाली का सृजन करने के लिए संदर्भ को व्यापक बनाने की आवश्यकता है। इन्हें प्राप्त करने के लिए, मैं भारत की वित्तीय प्रणाली के भविष्य के लिए निम्नलिखित पाँच नीतिगत प्राथमिकताएं प्रस्तावित करना चाहता हूँ।

प्राथमिकता 1: डिजिटल वित्तीय समावेशन

नीतिगत प्राथमिकता के रूप में, वित्तीय समावेशन को सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी को वित्तीय सेवाओं तक समुचित पहुँच मिले। रिज़र्व बैंक का वित्तीय समावेशन सूचकांक, जो वित्तीय समावेशन के स्तर को मापता है, मार्च 2021 के 53.9 से

* ग्लोबल फिनटेक फेस्ट, मुंबई में 28 अगस्त 2024 को भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकान्त दास द्वारा संबोधन।

[1] **एनपीसीआई** - भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम; **पीसीआई** - पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया; **एफसीसी** - फिनटेक कन्वर्जेंस काउंसिल।

[2] ट्रैक्स्न (Traxcn) डेटाबेस, फीड रिपोर्ट - फिनटेक - भारत - अप्रैल 2024।

बढ़कर मार्च 2024 में 64.2 हो गया। हम एक देश के रूप में, 5 किलोमीटर के दायरे में हर गाँव या पहाड़ी क्षेत्रों में 500 घरों की बस्ती तक बैंकिंग पहुँच सुनिश्चित करने में सफल रहे हैं। राष्ट्रीय मिशन के तहत 530 मिलियन जन धन बैंक खाते[3] खोले गए हैं, जिनमें से 66 प्रतिशत खाते ग्रामीण/अर्धशहरी केंद्रों में और 55 प्रतिशत महिला लाभार्थियों के लिए खोले गए हैं[4]।

वित्तीय समावेशन के विस्तार में यद्यपि महत्वपूर्ण प्रगति हुई है, लेकिन बदलते परिदृश्य में डिजिटल वित्तीय समावेशन[5] (डीएफआई) की ओर झुकाव, यानी वित्तीय रूप से वंचित और अल्प-सेवित आबादी के लिए सुरक्षित और डिजिटल रूप से सक्षम वित्तीय सेवाओं और उत्पादों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। डिजिटल वित्तीय समावेशन में मापनीयता और लागत-प्रभावशीलता के अनूठे लाभ हैं। तदनुसार, अगले दो दशक मुख्यतः विविध आवश्यकताओं को पूरा करने वाली सुलभ और प्रयोजन-विशिष्ट वित्तीय सेवाएँ प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के बारे में होंगे।

डिजिटल वित्तीय समावेशन के अनुसरण में, फिनटेक डिजिटल भुगतान समाधान, सूक्ष्म ऋण और किफायती बीमा के साथ पारंपरिक बैंकिंग में अंतर को पाटते हुए अभिनव और सुलभ वित्तीय सेवाएं प्रदान करने का प्रयास कर सकते हैं। वे मोबाइल बैंकिंग ऐप, डिजिटल वॉलेट और ऑनलाइन ऋण देने वाले प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से दूरदराज के क्षेत्रों में वित्तीय सेवाओं तक निर्बाध पहुंच को सक्षम बना सकते हैं, जिससे बेहतर और सुरक्षित ग्राहक अनुभव प्राप्त हो सके। डेटा एनालिटिक्स और एआई का उपयोग व्यक्ति-विशिष्ट और दक्ष वित्तीय समाधानों को और सक्षम बना सकता है।

प्राथमिकता 2: डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई)

दूसरी प्रमुख नीतिगत प्राथमिकता, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई) में और अधिक पैठ बनाने की होगी। डीपीआई जिसमें डिजिटल पहचान (आधार), सार्वभौमिक त्वरित खुदरा भुगतान (यूपीआई) और बिल भुगतान के लिए प्लेटफ़ॉर्म जैसे लक्षित भुगतान समाधान जैसे फ्रेमवर्क शामिल हैं, सामान्य रूप से वित्तीय प्रणाली के प्रभाव को बढ़ाएगा। वे अंतर-परिचालनीयता, पारदर्शिता और लागत प्रभावशीलता को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण साधन होंगे।

नए डीपीआई धोखाधड़ी, साइबर खतरों, डेटा गोपनीयता और अन्य चिंताओं जैसी उभरती चुनौतियों का समाधान कर सकते हैं। वे वित्तीय सेवाओं में सुरक्षा और दक्षता बढ़ाने के लिए ब्लॉकचेन और एआई जैसी उन्नत तकनीकों के एकीकरण का भी समर्थन कर सकते हैं। प्रौद्योगिकीय उन्नति का लाभ उठाने और वैश्विक वित्तीय परिदृश्य में प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त बनाए रखने के लिए निरंतर नवाचार महत्वपूर्ण है।

इस दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस (यूएलआई) पर रिज़र्व बैंक की प्रायोगिक परियोजना (पायलट) है, जिसे पूर्ववत पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म फॉर फ्रिक्शनलेस क्रेडिट (पीटीपीएफसी) के नाम से जाना जाता था। यूएलआई का उद्देश्य ऋणदात्री संस्थाओं को सहमति आधारित डेटा और संबंधित सेवाओं का लाभ उठाकर निर्बाध, एंड-टू-एंड डिजिटल ऋण प्रदान करने में सक्षम बनाना है। इस प्लेटफ़ॉर्म पर लगभग 50 प्रकार की डेटा सेवाएँ उपलब्ध हैं। बैंकों और एनबीएफसी के अलावा, अब हम नाबार्ड के माध्यम से सहकारी ऋण संस्थाओं जैसे अन्य ऋणदाताओं को शामिल करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। यूएलआई का विस्तृत प्रारंभ नियत समय में किया जाएगा। जैसा कि मैंने दो दिन पहले एक अन्य कार्यक्रम में कहा था, भारत की डीपीआई यात्रा में जेएएम[6]-यूपीआई-यूएलआई की 'नई त्रिमूर्ति', एक क्रांतिकारी कदम को चिह्नित करेगी।

प्राथमिकता 3: उपभोक्ता संरक्षण और साइबर सुरक्षा

वित्तीय प्रणाली में भरोसा बनाए रखने के लिए मज़बूत उपभोक्ता सुरक्षा सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। जैसे-जैसे उपभोक्ता डिजिटल वित्तीय सेवाओं पर अधिकाधिक भरोसा कर रहे हैं, व्यक्ति-विशिष्ट, दक्ष और निर्बाध अनुभव के लिए उनकी अपेक्षाएँ भी बढ़ रही हैं। अपविक्रय (मिससेलिंग) और धोखाधड़ी जैसे पारंपरिक जोखिमों के साथ-साथ, नवीन प्रौद्योगिकियों के

[3] ये खाते भारत सरकार की जन-धन योजना के अंतर्गत खोले गए बचत बैंक जमा खातों को संदर्भित करते हैं।

[4] https://pmjdy.gov.in/account (14 अगस्त 2024 तक का डेटा)

[5] परिभाषा वर्ष 2024-2026 के लिए जी20 वित्तीय समावेशन कार्य योजना (एफआईएपी) से ली गई।

[6] जेएएम से तात्पर्य है जन-धन बैंक खातों, आधार बायोमेट्रिक पहचान और मोबाइल नंबरों का एकीकरण। यह ढांचा प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण को सक्षम करके, बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच में सुधार करके और निर्बाध सेवा वितरण के लिए डिजिटल पहचान का लाभ उठाकर भारत में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

[7] आरबीआई@90 वैश्विक सम्मेलन में भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकान्त दास द्वारा "डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और उभरती हुई प्रौद्योगिकियाँ" पर उद्घाटन भाषण, 26 अगस्त 2024, बेंगलुरु।

आगमन के साथ डेटा गोपनीयता और सुरक्षा उल्लंघन जैसे उपभोक्ता जोखिमों की नई अभिव्यक्तियाँ सामने आयी हैं। इन चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान करने के लिए वास्तविक समय पर निगरानी और विनियामकीय अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना आवश्यक होगा।

भारत के उपभोक्ता संरक्षण परिदृश्य में डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (डीपीडीपी) अधिनियम, 2023 एक आधारशिला है। यह व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है। यह अधिनियम डेटा न्यूनीकरण और उद्देश्य सीमा के सिद्धांतों को सुनिश्चित करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि संगठन केवल आवश्यक जानकारी एकत्र करें और इसे आवश्यक अवधि के लिए केवल निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए उपयोग करें। यह व्यक्तियों को अपने डेटा को देखने, उसे सही करने और हटाने का अधिकार देता है, जिससे उपभोक्ताओं को अपनी व्यक्तिगत जानकारी पर अधिक नियंत्रण मिलता है। यह अधिनियम कारोबारों को सुदृढ़ डेटा सुरक्षा उपायों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिससे डिजिटल लेनदेन संबंधी विश्वास में अंततः वृद्धि होगी।

डिजिटल मार्केटप्लेस में भ्रामक बटन, गुप्त शुल्क और जारी रखने की बाध्यता जैसे डार्क पैटर्न बड़ी चिंता का विषय बन गए हैं। भारत सरकार द्वारा जारी डार्क पैटर्न की रोकथाम और विनियमन के लिए दिशा-निर्देश, 2023, कारोबारों में प्रौद्योगिकी के अनुचित उपयोग से उपभोक्ताओं को बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इन दिशानिर्देशों का उद्देश्य प्रतिबंधात्मक और भ्रामक प्रथाओं की पहचान करना, उन्हें प्रतिबंधित करना और दंडित करना है, ताकि उपभोक्ता सुविचारित विकल्प चुन सकें।

बैंकों और फिनटेक एनबीएफसी से उनकी तरफ से अपेक्षा की जाती है कि वे ग्राहक-केंद्रित दृष्टिकोण अपनाएं; मजबूत सुरक्षा उपायों को लागू करें; पारदर्शी वित्तीय उत्पाद पेश करें; और ऋण देने की उचित प्रथाओं को अपनाएं। एल्गोरिदम संबंधी निर्णय उचित और निष्पक्ष होने चाहिए और उनका ग्राहकों के प्रति समान व्यवहार होना चाहिए। प्रौद्योगिकी जोखिमों को कम करने के लिए, साइबर खतरों और तकनीकी विफलताओं से बचाव हेतु सुदृढ़ आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश और निरंतर निगरानी की आवश्यकता होती है। इन सिद्धांतों को अपनाकर, कारोबार उपभोक्ता विश्वास में वृद्धि ला सकते हैं, दीर्घकालिक संबंधों को बढ़ावा दे सकते हैं, अधिक सुरक्षित और विश्वसनीय वित्तीय पारितंत्र में योगदान दे सकते हैं, और अपनी स्वयं की दीर्घकालिक व्यवहार्यता सुनिश्चित कर सकते हैं।

इन उपायों के अलावा, साइबर सुरक्षा एक प्रणालीगत स्थिरता के दृष्टिकोण से भारत के डिजिटल वित्तीय पारितंत्र की सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में उभरती है। जैसे-जैसे वित्तीय लेन-देन ऑनलाइन होते जा रहे हैं, वैसे-वैसे संकटपूर्ण परिदृश्य में भी बढ़ोतरी हो रही है। सूचना प्रणालियों की सुदृढ़ता बढ़ाने के लिए, मानव संसाधन क्षमताओं में सुधार पर स्पष्ट ध्यान देने के साथ-साथ एआई-चालित खतरे का पता लगाने, विश्लेषण और न्यूनीकरण जैसी अत्याधुनिक तकनीकों में निवेश करना आवश्यक है। उपभोक्ताओं और कर्मचारियों के बीच साइबर सुरक्षा जागरूकता को बढ़ावा देना एक सुरक्षित डिजिटल अर्थव्यवस्था के निर्माण की दिशा में आवश्यक कदम है।

एक विनियामक के रूप में, मुझे रिज़र्व बैंक की ओर से इन पहलुओं पर जोर देना है, साथ ही नवोन्मेष को बढ़ावा देने के लिए अपनी निरंतर प्रतिबद्धता को दोहराना है।

प्राथमिकता 4: धारणीय वित्त

दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता के लिए धारणीय वृद्धि और पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। पर्यावरण संरक्षण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48-ए[8] में निहित है। वित्तीय क्षेत्र के दृष्टिकोण से, हमने रिज़र्व बैंक की हाल की पहलों जैसे भारत के सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क (2022) और ग्रीन डिपॉजिट की स्वीकृति के लिए फ्रेमवर्क (2023) के साथ धारणीयता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं। इन रूपरेखाओं से आशा है कि वे हरित परियोजनाओं के वित्तपोषण, सतत प्रथाओं को प्रोत्साहित करने और विकास की सामाजिक लागत को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

अपने लाभों के बावजूद, ग्रीन बॉन्ड और ग्रीन डिपॉजिट फ्रेमवर्क कई चुनौतियों का सामना करते हैं। इनमें स्केलेबिलिटी शामिल है, क्योंकि वृहत निर्गम और निवेशकों के विविध समूह को आकर्षित करने के लिए, ग्रीन बॉन्ड के लिए बाजार का काफी विस्तार करने की आवश्यकता है। इन ढांचों के माध्यम से वित्तपोषित हरित परियोजनाओं की प्रामाणिकता और प्रभाव

[8] राज्य, पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने तथा देश के वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा करने का प्रयास करेगा।

सुनिश्चित करने के लिए मजबूत निगरानी और रिपोर्टिंग तंत्र की आवश्यकता होती है। इन चुनौतियों पर काबू पाने में प्रौद्योगिकी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। उदाहरण के लिए, ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी ग्रीन बॉन्ड निर्गम में पारदर्शिता और मूल मार्ग का पता लगाने की क्षमता को बढ़ा सकती है तथा परियोजना के प्रभावों के अपरिवर्तनीय रिकॉर्ड प्रदान कर सकती है। कृत्रिम मेधा (एआई) और बिग डेटा एनालिटिक्स, बैंकों और निवेशकों को हरित निवेश से जुड़े पर्यावरणीय जोखिमों और अवसरों का आकलन करने में सक्षम बनाएँगे। ग्रीन बॉन्ड की ट्रेडिंग के लिए डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म और प्रभाव मापन साधन जैसे फिनटेक नवोन्मेष, प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित बना सकते हैं और विस्तृत निवेशक आधार को आकर्षित कर सकते हैं।

भविष्य की ओर बढ़ते हुए, अगले दो दशकों में फिनटेक संक्रमण वित्त, जलवायु वित्त और प्रकृति-आधारित समाधानों में और अधिक प्रगति लाने में सहायक होंगे। विनियामक ढाँचों को मजबूत बनाना, निवेशकों की जागरूकता बढ़ाना और सार्वजनिक-निजी भागीदारी को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण होगा। प्रौद्योगिकी की परिवर्तनकारी शक्ति का उपयोग करके और संधारणीय वित्त में नवाचार को बढ़ावा देकर, भारत एक सुदृढ़ और निम्न-कार्बन उत्सर्जन वाली अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में गति ला सकता है। हमें भावी पीढ़ियों के लिए धारणीय वृद्धि प्राप्त करने और पर्यावरण संरक्षण के लिए मिलकर काम करना होगा।

प्राथमिकता 5: वैश्विक एकीकरण और सहयोग

भारत ने आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अंतरराष्ट्रीय मंचों और द्विपक्षीय समझौतों में सक्रिय रूप से भाग लिया है। आगे चलकर, सीमा पार भुगतान प्रणालियों सहित वित्तीय इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाना, प्रमुख महत्वपूर्ण क्षेत्र होंगे। भारत अपनी तकनीकी प्रतिभा और विकसित फिनटेक पारितंत्र के साथ, डिजिटल नवोन्मेष और फिनटेक स्टार्टअप के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में काम करने की क्षमता रखता है। रणनीतिक साझेदारी का निर्माण और सुदृढ़ीकरण, अंतरराष्ट्रीय सहयोग के लिए हमारी प्रतिबद्धता को मजबूत करना, वित्तीय सेवाओं सहित विभिन्न क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्रों में उत्कृष्ट संस्थाओं को विकसित करना, वर्ष 2047 की ओर हमारी यात्रा के लिए सही गतिशक्ति होगी।

कई क्षेत्राधिकारों से हमें जो उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली है, उसके आधार पर अब हम यूपीआई और रुपे को सही मायने में वैश्विक बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। हमारी कार्यसूची में विदेशी क्षेत्रों में यूपीआई जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर का विनियोजन, अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक स्थानों पर यूपीआई ऐप के माध्यम से क्यूआर कोड-आधारित भुगतान स्वीकृति की सुविधा प्रदान करना तथा सीमा-पार धन विप्रेषण के लिए यूपीआई को अन्य देशों के फास्ट पेमेंट सिस्टम (एफपीएस) के साथ जोड़ना, सर्वोच्च स्थान पर है। इस दिशा में भूटान, नेपाल, श्रीलंका, सिंगापुर, यूएई, मॉरीशस, नामीबिया, पेरू, फ्रांस और कुछ अन्य देशों में पहले ही उल्लेखनीय प्रगति हो चुकी है[9]। ये प्रयास दुनिया भर में भारत की पहलों को अपनाने के लिए किए गए सहयोगात्मक प्रयासों को रेखांकित करते हैं। मैं अब तक की उपलब्धि के लिए एनपीसीआई और रिज़र्व बैंक में अपने सहयोगियों की सराहना करना चाहूंगा, लेकिन हमें इस राष्ट्रीय प्रयास में और अधिक योगदान करने का संकल्प लेना चाहिए।

भारत का सीबीडीसी अभी प्रायोगिक चरण में है, वह भी संभावित अंतरराष्ट्रीय सहयोग का एक और उदाहरण है। अब हम सीबीडीसी के माध्यम से बंटाई पर भूमिहीन किरायेदार किसानों को ऋण या सरकारी सहायता तथा किसानों को कार्बन क्रेडिट प्रदान करने के लिए प्रोग्रामेबिलिटी जैसी सुविधाओं का उपयोग कर रहे हैं। जबकि हमने यूपीआई जैसी त्वरित खुदरा भुगतान प्रणालियों के साथ सीबीडीसी की अंतर-परिचालनीयता का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया है, हमारा ऑफलाइन समाधानों पर अपने प्रयोग से लाभ उठाना जारी है। जैसे-जैसे हम प्रगति करते हैं, हमें अन्य देशों के साथ उनके सीबीडीसी प्रयासों में सहयोग करने में खुशी होगी।

II. भावी प्रौद्योगिकियाँ

भारत के वित्तीय परिदृश्य के भविष्य की ओर देखते हुए, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों का एकीकरण हमारे जीवन के विभिन्न

[9] उल्लेखनीय घटनाक्रमों में भूटान, फ्रांस, मॉरीशस, सिंगापुर, श्रीलंका, नेपाल और यूएई में यूपीआई क्यूआर कोड स्वीकृति शामिल है। इसी तरह, नेपाल, भूटान, सिंगापुर, मॉरीशस और यूएई में रुपे कार्ड की स्वीकृति है, इन देशों के कार्ड भारत में भी स्वीकार किए जाते हैं। सिंगापुर में पीयर-टू-पीयर विप्रेषण के लिए एफपीएस के साथ यूपीआई का एकीकरण और यूपीआई जैसे समाधानों को लागू करने के लिए यूएई, नेपाल, नामीबिया और पेरू में विनियामकों के साथ समझौते वैश्विक वित्तीय संपर्क स्थापित करने में अब तक की गई प्रगति को दर्शाते हैं।

पहलुओं में परिवर्तनकारी प्रगति का वादा करता है। कृत्रिम मेधा और मशीन लर्निंग (एआई/एमएल) अभूतपूर्व तरीके से वित्तीय सेवाओं में क्रांति लाने के लिए तैयार हैं। धोखाधड़ी का पता लगाने के लिए एआई एल्गोरिदम पहले से ही विनियोजित किए जा रहे हैं। मशीन लर्निंग मॉडल का क्रेडिट स्कोरिंग में तेजी से उपयोग किया जा रहा है, क्रेडिट योग्यता का आकलन करने और क्रेडिट तक पहुंच का विस्तार करने के लिए पूर्वानुमान विश्लेषण (प्रीडिक्टिव एनालिटिक्स) का लाभ उठाया जा रहा है। एआई-संचालित चैटबॉट और वर्चुअल असिस्टेंट, व्यक्ति-विशिष्ट सुझाव प्रदान करके, प्रश्नों का तुरंत समाधान करके और समग्र संतुष्टि में सुधार ला कर ग्राहक सेवा के अनुभव में लगातार परिवर्धन कर रहे हैं। जैसे-जैसे एआई और एमएल क्षमताएँ विकसित होती जा रही हैं, विनियामकीय अनुपालन, निवेश संबंधी परामर्शदात्री सेवाओं और एल्गोरिथम ट्रेडिंग में उनके संभावित अनुप्रयोगों से वित्तीय परिदृश्य के नए सिरे से परिभाषित होने की उम्मीद है।

साथ ही, हमें एआई से उत्पन्न होने वाले जोखिमों को भी पूरी तरह से समझना चाहिए और इसे संतुलित तरीके और जिम्मेदारी से अंगीकृत करना चाहिए। वित्तीय क्षेत्र के भागीदारों, केंद्रीय बैंकों और सरकारों को डेटा गोपनीयता, व्याख्या, जवाबदेही और पारदर्शिता से जुड़ी चिंताओं को ध्यान में रखते हुए, विश्वसनीय एआई के विकास को बढ़ावा देना चाहिए। एआई जैसी प्रौद्योगिकियों को नियंत्रित करने के लिए एक वांछनीय मॉडल क्या हो सकता है, यह संभवतः यहाँ एकत्रित विशेषज्ञों के बीच चर्चा का एक प्रमुख मुद्दा हो सकता है।

वित्तीय क्षेत्र के लिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) अवसरों की एक और सीमा का प्रतिनिधित्व करता है। सेंसर और कनेक्टिविटी क्षमताओं से लैस आईओटी डिवाइस, पहनने योग्य (वियरेबल्स) और स्मार्ट उपकरणों जैसी कनेक्टेड डिवाइस के माध्यम से निर्बाध लेनदेन को सक्षम करके, भुगतान पारितंत्र को नया रूप दे रहे हैं। इसके अलावा, आईओटी-संचालित डेटा एनालिटिक्स, बीमाकर्ताओं को नीति निर्णयकर्ताओं के व्यवहार और जोखिम प्रोफाइल के बारे में वास्तविक समय-आधारित जानकारी प्रदान करते हैं। वे व्यक्ति-विशिष्ट बीमा पेशकश और गतिशील मूल्य निर्धारण मॉडल की सुविधा प्रदान कर सकते हैं। आपूर्ति श्रृंखला वित्त और आस्तियों की ट्रैकिंग में आईओटी-सक्षम डिवाइसेज में संचालन को सुव्यवस्थित करने, पारदर्शिता बढ़ाने और जोखिमों को कम करने की क्षमता है। जैसे-जैसे आईओटी को अपनाया जाता है, फिनटेक नवोन्मेषकों और आईओटी डेवलपर्स के बीच सहयोग, इसकी पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए महत्वपूर्ण होगा।

क्वांटम कंप्यूटिंग एक गेम-चेंजिंग प्रौद्योगिकी के रूप में बहुत आशाजनक है, जिसका क्रिप्टोग्राफी, वित्तीय मॉडलिंग और जोखिम प्रबंधन पर गहन प्रभाव पड़ता है। इसकी बहुत तीव्र गति और पैमाने पर जटिल गणना करने की क्षमता, अवसर और चुनौतियाँ दोनों पेश करती है। क्रिप्टोग्राफी में, संवेदनशील वित्तीय डेटा को क्वांटम-सक्षम साइबर खतरों से बचाने के लिए क्वांटम-प्रतिरोधी एल्गोरिदम विकसित किए जा रहे हैं। वित्तीय मॉडलिंग में, क्वांटम कंप्यूटिंग के वृहत मात्रा में डेटा को संसाधित करने और जटिल परिदृश्यों का अनुकरण करने की क्षमता पोर्टफोलियो अनुकूलन, ट्रेडिंग रणनीतियों और जोखिम आकलन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने का वादा करती है। इसके अलावा, अनुकूलन समस्याओं को हल करने की क्वांटम कंप्यूटिंग की क्षमता तत्काल निर्णय लेने की प्रक्रियाओं को बढ़ा सकती है और जोखिम प्रबंधन में पूर्वानुमान विश्लेषण को बेहतर बना सकती है।

चूंकि ये भावी प्रौद्योगिकियां निरंतर विकसित हो रही हैं, इसलिए भारत के वित्तीय पारितंत्र में उनके एकीकरण के लिए अनुसंधान और विकास में रणनीतिक निवेश, विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग और नैतिक विनियोजन और संभावित जोखिमों के न्यूनीकरण को सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय विनियामक ढांचे की आवश्यकता होगी। रिज़र्व बैंक इन सभी मुद्दों के प्रति पूरी तरह सजग है और इन क्षेत्रों पर उचित ध्यान दे रहा है।

III. विनियामक संरचना

अंततः, मैं फिनटेक क्षेत्र के लिए विनियामकीय दृष्टिकोण पर बात करना चाहूंगा। फिनटेक क्षेत्र के सतत और व्यवस्थित विकास के लिए नवोन्मेष और विवेक के बीच उचित संतुलन होना आवश्यक है। हमारा प्रयास इस संवेदनशील संतुलन को प्राप्त करने के लिए सावधानीपूर्वक विनियम तैयार करना है, और साथ-ही-साथ विश्वास, सुरक्षा, पहुंच, जोखिम प्रबंधन और प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करना है।

इस संदर्भ में, मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श के बाद, हाल में कई विनियामकीय दिशा-

निर्देश जारी किए गए हैं। इनमें 'डिजिटल ऋण संबंधी दिशा-निर्देश' (सितंबर 2022); 'सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं की आउटसोर्सिंग पर मास्टर निदेश' (अप्रैल 2023); और 'गैर-बैंक भुगतान प्रणाली परिचालकों के लिए साइबर सुदृढ़ता और डिजिटल भुगतान सुरक्षा नियंत्रण पर मास्टर निदेश' (जुलाई 2024) शामिल हैं।

नवोन्मेष और विवेकपूर्ण विनियमन के बीच संतुलन बनाने के लिए एक मुख्य दृष्टिकोण में फिनटेक क्षेत्र के भीतर स्व-विनियमन शामिल है। स्व-विनियामक संगठन (एसआरओ), जिनमें उद्योग भागीदार शामिल हैं और जिन्हें इस क्षेत्र की विशिष्ट चुनौतियों और अवसरों की अच्छी समझ है, वे विनियामकों को ऐसे विनियमों पर उचित सुझाव देने की स्थिति में होंगे जो व्यावहारिक और प्रभावी, दोनों हों। इस दिशा में रिज़र्व बैंक द्वारा फिनटेक के लिए स्व-विनियामक संगठनों (एसआरओ-एफटी) की मान्यता के लिए एक रूपरेखा की घोषणा एक महत्वपूर्ण कदम है। यदि स्मरण करें, तो पिछले वर्ष के ग्लोबल फिनटेक फेस्ट (जीएफएफ) में मैंने जीएफएफ 2024 तक कम-से-कम एक फिनटेक क्षेत्र के स्व-विनियामक संगठन (एसआरओ) को विकसित होते देखने की हमारी इच्छा की घोषणा की थी। मुझे यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि जिन तीन उद्योग निकायों/संस्थाओं ने एसआरओ के रूप में मान्यता के लिए आवेदन किया है, उनमें से रिज़र्व बैंक ने एक संस्था को मान्यता प्रदान की है। शेष दो आवेदनों में से एक आवेदन को कतिपय आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद पुनः प्रस्तुत करने के प्रावधान के साथ वापस कर दिया गया है। तीसरा आवेदन जांच के अधीन है। नियमित परामर्श, फीडबैक तंत्र और नीति संवादों के माध्यम से, एसआरओ व्यापक संचार की सुविधा प्रदान करेंगे तथा फिनटेक को विनियामकीय अपेक्षाओं और प्राथमिकताओं के बारे में अवगत रहने में सक्षम बनाएंगे। पिछले एक वर्ष में फिनटेक के साथ हमारे जुड़ाव की गहराई को दर्शाने के लिए, मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि रिज़र्व बैंक के विभिन्न विभागों के अधिकारियों और दलों ने द्विपक्षीय रूप से लगभग 750 विचार-विमर्श किए हैं और फिनटेक भागीदारों के साथ लगभग 50 संरचित बैठकें की हैं। मैं एक गतिशील फिनटेक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए हमारी प्रतिबद्धता को दोहराता हूं।

निष्कर्ष

इंडिया@100 की ओर यात्रा अपार संभावनाओं और अवसरों से युक्त है। फिनटेक नवाचारों की परिवर्तनकारी शक्ति वित्तीय समावेशन, धारणीयता और उपभोक्ता संरक्षण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता के साथ मिलकर भविष्य के लिए एक मजबूत आधार तैयार करती है। उभरती प्रौद्योगिकियों का निर्बाध एकीकरण, वित्तीय परिदृश्य को और भी अधिक परिभाषित करेगा। आइए, हम सामूहिक परिदृष्टि और सहयोगी भावना के साथ इस गतिशील युग को अपनाएं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि भारत का वित्तीय पारितंत्र न केवल हमारे लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करे, बल्कि नवोन्मेष और वृद्धि के लिए एक वैश्विक मानदंड भी स्थापित करे।

धन्यवाद। नमस्कार।

आरबीआई@90 वैश्विक सम्मेलन में उद्घाटन भाषण*

श्री शक्तिकान्त दास

हम चालू वित्त वर्ष में भारतीय रिज़र्व बैंक की 90वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। 'डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और उभरती हुई प्रौद्योगिकी' पर यह वैश्विक सम्मेलन इस महत्वपूर्ण उपलब्धि को मनाने के लिए आयोजित किए जा रहे प्रमुख कार्यक्रमों में से एक है। सुंदर और जीवंत शहर बेंगलुरु में आयोजित इस सम्मेलन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए मुझे खुशी हो रही है। यह एक ऐसा है शहर जो कई वर्षों से भारत की प्रौद्योगिकी क्रांति में सबसे आगे रहा है। मैं दुनिया भर से हमारे साथ शामिल हुए सम्मानित प्रतिभागियों का भी विशेष स्वागत करता हूं। हमारे निमंत्रण को स्वीकार करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप वैश्विक सम्मेलन के दौरान विचार-विमर्श और बातचीत को समृद्ध और उपयोगी पाएंगे।

इस सम्मेलन का विषय - डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई) और उभरती हुई प्रौद्योगिकी- समयानुकूल और प्रासंगिक है। यह दुनिया की लगभग सभी अर्थव्यवस्थाओं की भविष्य की यात्रा को आकार देगा। पिछले दशक में पारंपरिक बैंकिंग प्रणाली में अभूतपूर्व प्रौद्योगिकीय परिवर्तन हुआ है। इस संबंध में सभी संकेत यह बताते हैं कि आने वाले वर्षों में यह प्रक्रिया और भी तीव्र होने की संभावना है। आज अपने संबोधन में, मैं भारत की डिजिटलीकरण प्रक्रिया में डीपीआई द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका और भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था में समावेशिता में इसके योगदान पर प्रकाश डालना चाहूँगा। भारत का अनुभव केंद्रीय बैंकों सहित सार्वजनिक प्राधिकरणों के लिए एक प्रभावी डिजिटलीकरण रणनीति प्रदान करता है। मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रणाली के कुछ प्रमुख मुद्दों और सीमा पार भुगतान में मुद्दों के समाधान में डीपीआई के उपयोग पर भी बात करूँगा।

डीपीआई का अर्थ और सकारात्मक प्रभाव

डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना से तात्पर्य ऐसी बुनियादी प्रौद्योगिकी प्रणालियों से है जो मुख्य रूप से सार्वजनिक क्षेत्र में बनाई जाती हैं, और उपयोगकर्ताओं और अन्य विकासकों के लिए खुले तौर पर उपलब्ध होती हैं। डीपीआई को आवश्यकता के अनुसार छोटा या बड़ा बनाया (स्केलेबल) जा सकता है, अत: वे उन प्रणालियों के लिए उपयोगी हो सकते हैं जो बड़ी जनसंख्या के लिए बनाई जानी हैं; वे इंटरऑपरेबल हैं, और नवाचारकर्ताओं के लिए सुलभ होने के कारण नवाचार को बढ़ावा देते हैं; और वे किफायती भी हैं। स्केलेबिलिटी, इंटरऑपरेबिलिटी और लागत दक्षता के ये तीन फायदे वित्तीय समावेशन को गति देने और भौतिक दूरी, दस्तावेज़ीकरण और लेन-देन की लागत जैसी पारंपरिक बाधाओं को दूर करके लोगों के जीवन को बदलने की क्षमता रखते हैं।

यह कहा जा सकता है कि डीपीआई ने भारत को एक दशक से भी कम समय में वित्तीय समावेशन के एक ऐसे स्तर को हासिल करने में सक्षम बनाया है जिसमें अन्यथा कई दशकों या उससे अधिक का समय लग सकता था। डीपीआई संव्यवहार लागत को कम करके, पहुँच को सर्वजन सुलभ बनाकर, अंतर-संचालन के माध्यम से प्रतिस्पर्धा बनाए रखकर और निजी पूंजी को आकर्षित करके बाजार नवाचार को बढ़ावा देता है। डीपीआई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय बुनियादी ढांचे को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने का मार्ग प्रदान करता है। संकट के समय में, जैसे कि कोविड-19 महामारी के दौरान, भारत और कुछ अन्य देशों ने टीकाकरण कार्यक्रमों और लक्षित अंतरण भुगतानों के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे का लाभ उठाया।

अन्य देशों में डीपीआई के उल्लेखनीय उदाहरणों में सत्यापन योग्य डिजिटल पहचान प्रणालियां शामिल हैं, जैसे कि कोलंबिया की सेडुला डिजिटल; नाइजीरिया की नेशनल आईडी या बैंक वेरिफिकेशन नंबर; फिलीपींस की फिलसिस्ट; रवांडा की राष्ट्रीय पहचान एजेंसी (एनआईडीए) द्वारा प्रबंधित डिजिटल पहचान प्रणाली; सऊदी अरब का नफाथ डिजिटल आईडेंटिटी मैनेजमेंट प्लैटफॉर्म; सिंगापुर का सिंगपास ; संयुक्त अरब अमीरात का यूएई-पास; और इसी प्रकार की अन्य प्रणालियां।

जी20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप (डीईडब्ल्यूजी) ने ग्लोबल डीपीआई रिपोजिटरी (जीडीपीआईआर) विकसित की है, जो एक व्यापक संसाधन केंद्र है, जो जी20 सदस्यों और अन्य भागीदार देशों से आवश्यक अनुभव और विशेषज्ञता को एकत्रित करता है। इसका प्राथमिक उद्देश्य डीपीआई के डिजाइन, निर्माण, परिनियोजन और अभिशासन के लिए आवश्यक विकल्पों और

* भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकान्त दास द्वारा “डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और उभरती हुई प्रौद्योगिकी” पर आरबीआई@90 वैश्विक सम्मेलन में उद्घाटन भाषण, 26 अगस्त, 2024, बेंगलुरु।

कार्यप्रणालियों में ज्ञान की कमी को पूरा करना है। 15 जुलाई 2024 को डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना पर भारत के जी20 टास्क फोर्स की अंतिम रिपोर्ट जारी की गई जिसने अन्य बातों के अलावा डीपीआई की परिभाषा और रूपरेखा को स्वीकार करने में योगदान दिया है। आगामी जी20 प्रेसीडेंसी के दौरान इसी कार्यसूची को कार्यान्वयन के लिए आगे बढ़ाया जाएगा।

डीपीआई के संबंध में भारत का अनुभव

अब मैं डीपीआई के संबंध में भारत के अनुभव की बात करना चाहूंगा। भारत की डीपीआई यात्रा एक अनूठा मॉडल है, जिसमें आधारभूत तकनीकी अवसंरचना का निर्माण, संचालन और प्रबंधन सार्वजनिक क्षेत्र में किया जाता है, जबकि निजी क्षेत्र अभिनव ग्राहक-उन्मुख सेवाएं बनाने के लिए डीपीआई का उपयोग करता है। सार्वजनिक क्षेत्र में डीपीआई विकसित करने का लाभ यह है कि आमतौर पर निजी क्षेत्र अनिश्चित प्रतिलाभ को देखते हुए अवसंरचना बनाने के लिए पूंजी निवेश के लिए इच्छुक नहीं होता। निजी तौर पर बनाई गई अवसंरचना सर्व जनों तक पहुंच या अंतर-संचालन के लिए भी अनुकूल नहीं हो सकती। भारत का अनूठा दृष्टिकोण ऐसी सेवाओं और उत्पादों को डिजाइन करने के लिए अनुकूल है जो खुले बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक हैं।

वित्त क्षेत्र में डिजिटल भुगतान, डिजिटल धन, डिजिटल पहचान और डिजिटल प्रक्रियाओं को सुविधाजनक बनाने वाली प्रणालियाँ डीपीआई के प्रमुख घटक हैं। भारत ने तीन महत्वपूर्ण आयामों - डिजिटल पहचान, बैंक खाते और प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान केंद्रित करके अपनी डीपीआई रणनीति को सावधानीपूर्वक तैयार किया है। भारत की बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली 'आधार', पहचान का एकल और पोर्टेबल प्रमाण है। भारत के निवासियों के लिए लगभग 1.4 बिलियन[1] आधार संख्याएँ तैयार की गई हैं जिसमें लगभग पूरी भारतीय आबादी शामिल है। इसी तरह, जन-धन खातों यानी बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट (बीएसबीडी)[2] खातों के माध्यम से बैंकिंग प्रणाली से वंचित वर्गों के लिए पहुँच को सक्षम किया गया है। जन-धन योजना के तहत लाभार्थियों के लिए आधे बिलियन से अधिक बैंक खाते खोले गए हैं।[3] प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के संबंध में किफायती मोबाइल फोन और इंटरनेट की उपलब्धता के माध्यम से बुनियादी कनेक्टिविटी सुनिश्चित की गई है। मई 2024 की स्थिति के अनुसार भारत में मोबाइल आधारित इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या लगभग 0.9 बिलियन है [4] जिसमें मोबाइल टेली-घनत्व 83 प्रतिशत है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी मोबाइल टेली-घनत्व लगभग 60 प्रतिशत है। जन-धन खातों, आधार और मोबाइल फोन की त्रयी, जिसे जेएएम ट्रिनिटी के नाम से जाना जाता है ने आधारभूत डीपीआई अवसंरचना प्रदान की है जिसका उपयोग कई मूल्य वर्धित सेवाओं के लिए किया जा रहा है। जेएएम ट्रिनिटी पहल के तहत 67 प्रतिशत से अधिक लाभार्थी ग्रामीण/अर्ध-शहरी क्षेत्रों से हैं और 55 प्रतिशत से अधिक महिलाएँ हैं। यह स्पष्ट रूप से समावेशन को बढ़ावा देने में डीपीआई की भूमिका को दर्शाता है।

भारत में डीपीआई का एक और उदाहरण अकाउंट एग्रीगेटर (एए) ढांचा है जो रिज़र्व बैंक की एक विनियामक पहल है। यह ढांचा ग्राहकों की वित्तीय जानकारी को उनकी सहमति के आधार पर पात्र वित्तीय प्रणाली प्रतिभागियों के बीच सुरक्षित, पारदर्शी और कुशल तरीके से साझा करने और एकत्र करने की सुविधा प्रदान करता है। यह एमएसएमई को न्यूनतम दस्तावेजीकरण के साथ ऋणदाताओं से नकदी प्रवाह-आधारित वित्तपोषण प्राप्त करने में सक्षम बनाता है।

पिछले कुछ वर्षों में भारतीय रिज़र्व बैंक ने 'इनफिनेट' बैंकिंग नेटवर्क, एसएफएमएस संदेश प्रणाली, आरटीजीएस और एनईएफटी भुगतान प्रणालियों जैसे डिजिटल बुनियादी ढांचे के निर्माण को समर्थन देते हुए देश में खुदरा और थोक भुगतान, दोनों के लिए मजबूत प्रणालियों के विकास की सुविधा प्रदान की है।[5] भारत में डिजिटल भुगतान का वर्तमान पारिस्थितिकी तंत्र व्यवसायों और व्यक्तियों के लिए बड़े और छोटे मूल्य, दोनों के धन के तत्काल या त्वरित अंतरण के लिए सरल, सुरक्षित और संरक्षित कई विकल्प प्रदान करता है।

1 https://uidai.gov.in/aadhaar_dashboard/

2 ऐसे बचत बैंक खातों में कोई न्यूनतम शेष राशि रखने की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे खातों में कुछ न्यूनतम सुविधाएं भी निःशुल्क दी जाती हैं।

3 https://pmjdy.gov.in/

4 https://www.trai.gov.in/release-publication/reports/telecom-subscriptions-reports.

5 **इनफिनेट** (भारतीय वित्तीय नेटवर्क): आरबीआई और वित्तीय संस्थानों से मिलकर बना एक सीमित उपयोगकर्ता समूह नेटवर्क। यह भारतीय बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र के लिए संचार का मुख्य आधार प्रदान करता है। **एसएफएमएस** (संरचित वित्तीय संदेश प्रणाली) एक सुरक्षित वित्तीय संदेश प्रणाली है जिसका उपयोग भारत में इंटर-बैंक और इंट्रा-बैंक संचार दोनों के लिए किया जाता है। **आरटीजीएस** (रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट) बड़े मूल्य के लेन-देन (₹2 लाख और उससे अधिक) के लिए एक चौबीसों घंटे उपलब्ध इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम है जिसमें लेनदेन को सकल आधार पर (अर्थात लेनदेन दर लेनदेन आधार पर) लगातार संसाधित किया जाता है। **एनईएफटी** (नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफर) एक चौबीसों घंटे उपलब्ध खुदरा इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम है जिसमें लेनदेन बैचों में संसाधित होते हैं।

अप्रैल 2016 में भारत में नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) द्वारा शुरू की गई एक वास्तविक समय भुगतान प्रणाली - यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस या यूपीआई ने भारत में खुदरा डिजिटल भुगतान के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एनपीसीआई की स्थापना रिज़र्व बैंक के मार्गदर्शन में बैंकों द्वारा की गई थी। हालाँकि यूपीआई प्लेटफ़ॉर्म पर शुरुआती भागीदार बैंक थे, लेकिन गैर-बैंक थर्ड पार्टी ऐप प्रदाता और क्यूआर कोड के उपयोग ने यूपीआई को लोकप्रिय बनाने में साथ दिया है। तब से यह एक मजबूत, लागत प्रभावी और पोर्टेबल खुदरा भुगतान प्रणाली के रूप में उभरा है और दुनिया भर में लगातार आकर्षण का विषय रहा है।

बैंकिंग सेवाओं के डिजीटलीकरण के प्रयासों को जारी रखते हुए पिछले साल हमने प्रौद्योगिकी प्लेटफ़ॉर्म का एक पायलट लॉन्च किया जो अवरोध-मुक्त ऋण वितरण की सुविधा देता है। इसके आगे हम इसे यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफ़ेस (यूएलआई) कहे जाने का प्रस्ताव करते हैं। यह प्लेटफ़ॉर्म कई डेटा सेवा प्रदाताओं से ऋणदाताओं तक विभिन्न राज्यों के भूमि रिकॉर्ड सहित डिजिटल जानकारी के निर्बाध और सहमति आधारित प्रवाह की सुविधा प्रदान करता है। इससे ऋण मूल्यांकन में लगने वाला समय कम हो जाता है, खासकर छोटे और ग्रामीण उधारकर्ताओं के मामले में। यूएलआई आर्किटेक्चर में सामान्य और मानकीकृत एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफ़ेस (एपीआई) हैं, जिन्हें विभिन्न स्रोतों से सूचना तक डिजिटल पहुँच सुनिश्चित करने के लिए 'प्लग एंड प्ले' स्वरूप के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह कई तकनीकी एकीकरणों की जटिलता को कम करता है। यह उधारकर्ताओं को अधिक दस्तावेज़ीकरण की आवश्यकता के बिना ऋण के निर्बाध वितरण तथा शीघ्रता से कार्य संपन्न करने में सक्षम बनाता है। संक्षेप में, ग्राहक के वित्तीय और गैर-वित्तीय डेटा तक पहुँच को डिजिटाइज़ करके, जो अन्यथा पेटियों में बंद रहता है, यूएलआई की मदद से विभिन्न क्षेत्रों में ऋण की बड़ी अपूरित मांग को पूरा किया जा सकता है, खासकर कृषि और एमएसएमई उधारकर्ताओं के लिए। पायलट प्रोजेक्ट से मिलने वाले अनुभव के आधार पर यूएलआई को जल्द ही पूरे देश में कार्यान्वित किया जाएगा। जिस तरह यूपीआई ने भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र को बदल दिया, उसी तरह हम उम्मीद करते हैं कि यूएलआई भारत में ऋण क्षेत्र को बदलने में भी ऐसी ही भूमिका निभाएगा। **जेएएफ-यूपीआई-यूएलआई की 'नई त्रयी' भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की यात्रा में एक क्रांतिकारी कदम होगी।**

सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी) ने हाल ही में दुनिया भर में नीतिगत चर्चाओं में अपना बड़ा स्थान बनाया है। भारत में, रिज़र्व बैंक ने 2022 के अंत में खुदरा और थोक, दोनों क्षेत्रों में सीबीडीसी पायलट कार्यान्वित किए। खुदरा पायलट में वर्तमान में 5 मिलियन से अधिक उपयोगकर्ता और 16 सहभागी बैंक हैं। हालांकि खुदरा पायलट भुगतान संबंधी प्रारंभिक उपयोग के मामले से शुरू हुआ था, वर्तमान में उसके संबंध में ऑफ़लाइन और प्रोग्रामेबिलिटी, दोनों कार्यों का भी परीक्षण किया जा रहा है। सीबीडीसी की प्रोग्रामेबिलिटी विशेषता लक्षित उपयोगकर्ता को धन वितरण सुनिश्चित करके वित्तीय समावेशन के लिए एक प्रमुख प्रवर्तक के रूप में काम कर सकती है। मैं इसे हाल ही में लॉन्च किए गए एक वास्तविक पायलट द्वारा स्पष्ट करता हूँ[6]। काश्तकार किसानों को अक्सर प्रारंभिक खरीद और कच्चे माल के लिए कृषि ऋण प्राप्त करने में कठिनाई होती है क्योंकि उनके पास बैंकों को प्रस्तुत करने के लिए भूमि का स्वामित्व नहीं होता है। तथापि, कृषि प्रारंभिक खरीद के संबंध में अंतिम उपयोग को प्रोग्राम करने से बैंकों को आश्वस्त होने में सहूलियत हो सकती है और इस प्रकार किसान की पहचान उसकी भूमि जोत के माध्यम से नहीं बल्कि वितरित किए जा रहे धन के अंतिम उपयोग के माध्यम से स्थापित हो सकती है। एक और अनोखा उपयोग मामला[7] है जिसमें किसानों को कार्बन क्रेडिट सृजन के लिए प्रोग्रामेबल सीबीडीसी के माध्यम से उद्देश्यपूर्ण धन प्राप्त होगा। नाम गुप्तता (एनोनिमिटी) और ऑफलाइन उपलब्धता जैसी सुविधाओं के परीक्षण के उद्देश्य से अन्य नए उपयोग मामलों को धीरे-धीरे शुरू करने का प्रस्ताव है।

इस बात को ध्यान में रखना जरूरी है कि उपयोगकर्ताओं, मौद्रिक नीति, वित्तीय प्रणाली और अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव की व्यापक समझ हासिल करने से पहले संपूर्ण प्रणाली स्तर पर सीबीडीसी को लागू करने में कोई जल्दबाजी नहीं की जानी चाहिए। पायलट परीक्षणों में उपयोगकर्ता डेटा सृजित करने से इस संबंध में समझ बन पाएगी। सीबीडीसी की वास्तविक शुरुआत धीरे-धीरे चरणबद्ध तरीके से की जा सकती है। निस्संदेह, सीबीडीसी में, घरेलू भुगतान और सीमा पार भुगतान, दोनों के लिए भविष्य की भुगतान प्रणालियों को आधार उपलब्ध कराने की क्षमता है।

6 यह पायलट परियोजना एसबीआई द्वारा 16 अगस्त 2024 को ओडिशा और आंध्र प्रदेश राज्यों में शुरू की गई।

7 इंडसइंड बैंक ने महाराष्ट्र में इसका परीक्षण किया।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डीपीआई

आज, चूंकि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) चैटबॉट, इंटेलिजेंट अलर्ट के लिए आंतरिक डेटा प्रोसेसिंग, धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन, क्रेडिट मॉडलिंग और अन्य प्रक्रियाओं जैसी सेवाओं के रूप में वित्तीय क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है, इस अत्याधुनिक तकनीक को एक मजबूत और जिम्मेदार डीपीआई के साथ जोड़ने से डीपीआई की क्षमता और दक्षता को और भी अधिक बढ़ाया जा सकता है। 'डीपीआई पर भारत के जी20 टास्क फोर्स की रिपोर्ट' में कहा गया है - एआई के साथ डीपीआई का जुड़ना हमें "डिजिटल पब्लिक इंटेलिजेंस" की एक नई दुनिया में ले जाएगा। वित्तीय सेवाओं को एआई के साथ जोड़ने से सभी हितधारकों के लिए महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त होंगे। एआई ग्राहकों के लिए अति-वैयक्तिकृत उत्पाद और तेज़, अधिक प्रासंगिक सेवाएं उपलब्ध करा सकता है। ऋणदाताओं जैसे वित्तीय संस्थानों को जोखिम और धोखाधड़ी प्रबंधन, सुव्यवस्थित संचालन और कम अनुपालन लागत के लिए इन उन्नत साधनों से लाभ मिलेगा। विनियामकों को बेहतर निगरानी और वास्तविक समय निगरानी करना संभव होगा, जिससे विनियामक प्रवर्तन और बाजार स्थिरता में सुधार होगा।

लेकिन ऐसी प्रगति गंभीर चुनौतियों के साथ आती है। व्यक्तिगत जानकारी के विशाल भंडार के साथ लेन-देन किए जाने से डेटा गोपनीयता की चिंताएँ उत्पन्न होती हैं। निष्पक्षता और पक्षपात की रोकथाम सुनिश्चित करने के लिए नैतिक एआई अभिशासन आवश्यक है। वित्तीय संस्थानों को यह सुनिश्चित करना होगा कि एआई मॉडल व्याख्या योग्य हों, अर्थात, उनमें यह समझाने की क्षमता हो कि जो भी परिणाम प्राप्त होते हैं वे किस कारण से उत्पन्न होते हैं। एआई तकनीक का गलत सूचना फैलाने के लिए भी दुरुपयोग किया जा सकता है जिससे संभावित रूप से डीपीआई के साथ-साथ अन्य डिजिटल प्रणाली को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है और व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। वे वित्तीय संस्थानों की प्रतिष्ठा और संचालन को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) जैसे अंतरराष्ट्रीय निकायों ने एआई को अभिशासित करने वाले मुख्य सिद्धांतों को रेखांकित किया है, जिसमें समावेशी विकास, विधिवत अभिशासन और मानवाधिकारों का सम्मान, पारदर्शिता और व्याख्या, मजबूती और सुरक्षा तथा जवाबदेही शामिल हैं। दिसंबर 2023 में, हिरोशिमा एआई प्रोसेस कॉम्प्रेहेन्सिव पॉलिसी फ्रेमवर्क स्थापित किया गया। इसमें मार्गदर्शक सिद्धांतों और आचार संहिता की एक सूची शामिल है जो एआई के जिम्मेदारीयुक्त विकास के लिए समन्वित वैश्विक दृष्टिकोण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

भारत 2024 के ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन एआई (जीपीएआई) का प्रमुख हिस्सा (लीड चेअर) है। 29 देशों के साथ इस बहु-हितधारक पहल का उद्देश्य अत्याधुनिक शोध का समर्थन करते हुए और लागू गतिविधियों को आगे बढ़ाकर एआई सिद्धांत और उसके कार्यान्वयन के बीच की खाई को पाटना है। भारत सरकार का इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण पहल कर रहा है, जैसे कि एआई रिसर्च एनालिटिक्स और नॉलेज डिसेमिनेशन प्लेटफॉर्म की स्थापना करना, जो भारत-विशिष्ट चुनौतियों और जटिल वास्तविक जीवन की समस्याओं से निपटने के लिए स्वदेशी एआई-सक्षम उत्पादों और समाधानों को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। ये पहलें न केवल एआई तकनीक की संभावनाओं का लाभ उठाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती हैं, बल्कि मजबूत अभिशासन भी सुनिश्चित करती हैं।

मुझे यह जानकर खुशी हुई कि इस सम्मेलन में पैनल चर्चा उभरती हुई प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित होगी। मुझे विश्वास है कि वे एआई जैसी प्रौद्योगिकियों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विचार करेंगे। नई प्रौद्योगिकियों की क्षमताओं का लाभ उठाने के लिए सक्रिय होना महत्वपूर्ण है, लेकिन साथ ही उससे जुड़े जोखिमों और चुनौतियों के बारे में भी पूरी तरह से सचेत रहना आवश्यक है। निम्नलिखित पहलुओं को ध्यान में रखना हितकर होगा:

i. एआई एक डेटा संचालित विज्ञान है। मॉडलों के प्रशिक्षण में उपयोग किए जा रहे डेटा की प्रामाणिकता, पूर्वाग्रहों की संभावना, डेटा गोपनीयता के मुद्दे की सावधानीपूर्वक जांच की जानी चाहिए।

ii. एआई में प्रक्रियाओं को सरल और कुशल बनाने की क्षमता है। यह काफी हद तक निर्णय लेने की प्रक्रिया का भी काम कर सकता है । लेकिन, जब विनियमित वित्तीय संस्थानों की बात आती है तो महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले क्षेत्रों, जैसे कि ऋण स्वीकृति में, एआई को सावधानीपूर्वक अपनाया जाना चाहिए। हालांकि एआई निश्चित रूप से प्रक्रिया में सहायता कर सकता है, उनका उपयोग करने वाले संस्थानों को मॉडलों की उचित समझ होनी चाहिए और परिणामों की जवाबदेही सुनिश्चित करनी चाहिए।

iii. एआई से होने वाले जोखिमों को समझने के बाद, वित्तीय संस्थानों द्वारा उत्तरदायित्व को स्पष्ट रूप से रेखांकित किया जाना चाहिए और एक संतुलित और जिम्मेदाराना तरीके से एआई को अपनाना सुनिश्चित करना चाहिए। केंद्रीय बैंकों और सरकारों को, अपनी ओर से, डेटा गोपनीयता, व्याख्यात्मकता, जवाबदेही और पारदर्शिता को इसके मूल में रखते हुए, विश्वसनीय एआई के विकास को बढ़ावा देना चाहिए।

डीपीआई और सीमापार भुगतान

जी-20 और भुगतान एवं बाजार अवसंरचना समिति (सीपीएमआई) जैसे अंतरराष्ट्रीय मानक निर्धारण निकायों सहित सभी बहुपक्षीय व्यवस्थाओं में एक महत्वपूर्ण कार्य सीमा पार भुगतान में दक्षता लाना है। विभिन्न देशों के बीच द्विपक्षीय और बहुपक्षीय व्यवस्थाओं संबंधी कई पहलें और प्रयोग पहले से ही चल रहे हैं। हालांकि थोक बाजारों के मामले में काफी दक्षता हासिल की गई है, खुदरा सीमा पार क्षेत्र अभी भी कई चुनौतियों से भरा हुआ है जिससे सीमा पार प्रेषण में लागत और देरी बढ़ती है। कहने की आवश्यकता नहीं कि आधुनिक प्रौद्योगिकी ऐसे समाधान प्रदान करती है जो इन अवरोधों को कम कर सकती है। विभिन्न देशों में फास्ट पेमेंट सिस्टम के उद्भव और सीबीडीसी के प्रयोग की संभावना से सीमा पार भुगतान में अधिक दक्षता लाने के लिए नई संभावनाएं खुल रही हैं। ऐसी पहलों में अधिकतम दक्षता लाभ तब प्राप्त होगा जब एक प्रमुख डिजाइन तत्व के रूप में अंतर-संचालन (इंटर ऑपरेबिलिटी) को सुनिश्चित किया जाएगा।

आदर्श रूप से, जबकि परंपरागत भुगतान प्रणाली और इसी तरह सीबीडीसी प्रणाली भी एक दूसरे से जुड़ने में सक्षम होनी चाहिए, एक देश की परंपरागत प्रणाली दूसरे देश की सीबीडीसी के साथ अंतर-संचालन योग्य होनी चाहिए। अंतर-संचालन के वास्तविक कार्यान्वयन में चुनौतियां होंगी और जिसमें कुछ समझौते करना शामिल हो सकता है। तकनीकी बाधाओं को समान (अंतरराष्ट्रीय) तकनीकी मानकों का उपयोग करके दूर किया जा सकता है। इसके अलावा, दीर्घकालिक स्थिरता के लिए अभिशासन संरचना या प्रबंधन ढांचे को भी अंतिम रूप देने की आवश्यकता होगी।

देशों के बीच सामंजस्य और अंतरसंचालनीयता प्राप्त करने की इस यात्रा में एक प्रमुख चुनौती यह हो सकती है कि देश अपनी आंतरिक सोच के अनुसार अपनी स्वयं की प्रणाली डिजाइन करना पसंद करें। हम एक ऐसा प्लग एंड प्ले सिस्टम विकसित करके इस चुनौती को दूर कर सकते हैं जो संबंधित देशों की संप्रभुता को बनाए रखते हुए उसकी प्रतिकृति बनाने की सुविधा देता हो। भारत ने इस दिशा में कुछ प्रगति की है और विभिन्न देशों के लाभ के लिए एक प्लग एंड प्ले सिस्टम विकसित करने में उसे प्रसन्नता होगी।

यूपीआई प्रणाली में सीमा पार प्रेषण के उपलब्ध माध्यमों के लिए एक सस्ता और तेज़ विकल्प बनने की क्षमता है। इसकी शुरुआत छोटे मूल्य के व्यक्तिगत प्रेषण से की जा सकती है क्योंकि इसे जल्दी से लागू किया जा सकता है।

निष्कर्ष

भारत विविधताओं से भरा एक विशाल देश है। भारत में कारगर समाधान को किसी अन्य देश की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप ढाला जा सकता है। तदनुसार, सम्मेलन के आयोजकों ने दूसरे दिन भारत के यूपीआई पर, विशेष रूप से अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों के लिए, एक गहन चर्चा सत्र आयोजित किया है। मैं सभी प्रतिनिधियों से अनुरोध करता हूं कि वे इसमें भाग लें और विभिन्न सत्रों से लाभ उठाएं तथा अपने अनुभव भी साझा करें, जिससे सभी को सीखने को मिल सके। मैं आपको सम्मेलन प्रदर्शनी में भी आमंत्रित करता हूं, जिसमें इस सम्मेलन से संबंधित भारत के कुछ नवाचारों को प्रदर्शित किया गया है।

जैसा कि आपको याद होगा, 2023 में भारत की जी-20 अध्यक्षता का विषय "एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य" था। यह भारत की इस विचार प्रक्रिया को रेखांकित करता है कि वह दुनिया और खुद को एक परिवार का हिस्सा मानता है जिसका साझा भविष्य है। भारतीय रिज़र्व बैंक की आरबीआई@100 की ओर यात्रा को हम काफी आशावादी रूप से देख रहे हैं। हम लगातार ऐसी नीतियों, दृष्टिकोणों, प्रणालियों और मंचों को तैयार करने में लगे हैं जो हमारे वित्तीय क्षेत्र को अधिक मजबूत, चुस्त और ग्राहक केंद्रित बनाएंगे। इन शब्दों के साथ मैं आप सभी के सुखद निवास और उपयोगी चर्चाओं की कामना करता हूँ। सम्मेलन की सफलता के लिए शुभकामनाएं।

धन्यवाद और नमस्कार।

भारत की आकांक्षाओं का वित्तपोषण

माइकल देवब्रत पात्र

नमस्कार! सुप्रभात,

आज यहाँ आकर मुझे गर्व महसूस हो रहा है। सीआईआई द्वारा आयोजित यह पहल - वित्त पोषण 3.0 पर शिखर सम्मेलन - शायद अपनी तरह की पहली पहल है और यह वर्तमान समय में महत्व रखती है, क्योंकि यह भारत के भविष्य की ओर छलांग लगाने वाले प्रकाश स्तंभ के रूप में अपनी स्थिति बना रही है। इसलिए, सबसे पहले, मैं 1895 से भारत के औद्योगिक और व्यावसायिक परिदृश्य को आकार देने में सीआईआई की भूमिका की भूरी-भूरी सराहना करना चाहूँगा, जो आज देश में सबसे अधिक दिखाई देने वाला व्यावसायिक संगठन है। यह उचित ही है कि मैं एक राष्ट्र के रूप में हमारी महत्वाकांक्षाओं और उन्हें साकार करने में वित्त की भूमिका पर विचार करके सीआईआई के असाधारण योगदान को अभिनंदन अर्पित करूँ।

II. भारत का एक आकांक्षापूर्ण दृष्टिकोण

राष्ट्र के भाव में स्पष्ट स्पंदन है। व्यापक रूप से ऐसा माना जा रहा है कि यह भारत की सदी है। प्रत्येक भारतीय के लिए दुनिया में सर्वोत्तम जीवन स्तर सुनिश्चित करने वाले मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए अवसर की एक खिड़की खुल गई है । शास्त्रीय अर्थशास्त्र की परंपरा में, यह माना जाता है कि उत्पादक कार्यबल ही मूल्य निर्माण का सच्चा स्रोत है; पूंजी केवल आयोजन कारक है, जो श्रम की उत्पादकता को बढ़ाती है और इसके विकास के लिए परिस्थितियां बनाती है। अर्थव्यवस्था के आपूर्ति पक्ष के उस शास्त्रीय अर्थ में, दुनिया का हर छठा कामकाजी व्यक्ति एक भारतीय है, जो दुनिया की सबसे युवा आबादी होने का लाभ उठा रहा है। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि भारत की कामकाजी आयु वाली आबादी प्रति वर्ष 9.7 मिलियन बढ़ेगी।[1] 2030 तक उक्त समूह के कुल आबादी का 68.9 प्रतिशत हो जाने की उम्मीद है।[2]

मांग पक्ष की ओर से, भारत इस बढ़ते कार्यबल को तीव्र गति से कौशल प्रदान करेगा, यह देखते हुए कि हम पहले से ही दुनिया में सबसे अधिक संख्या में एसटीईएम[3] स्नातक तैयार कर रहे हैं – हर साल 20 लाख से अधिक, जिनमें से 43 प्रतिशत महिलाएं हैं[4]। भारत डिजिटल क्रांति में भी सबसे आगे है, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग में और स्टार्ट-अप पारितंत्र में दुनिया के नेतृत्वकर्ताओं में से एक है। अनुमान बताते हैं कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) 2035 तक भारतीय अर्थव्यवस्था में लगभग 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान कर सकती है[5]। जैसे-जैसे वैश्विक विनिर्माण केंद्र और निर्यात महाशक्ति बनने की महत्वाकांक्षा साकार होती है, कार्यशील आयु वाली आबादी की रोजगार क्षमता बढ़ेगी और भारत में आय और समृद्धि बढ़ेगी। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) में अर्थशास्त्रियों ने दिखाया है कि जनसांख्यिकीय लाभांश का लाभ उठाने से अगले दो दशकों में भारत की प्रति व्यक्ति जीडीपी वृद्धि में प्रति वर्ष लगभग 2 प्रतिशत अंक की वृद्धि हो सकती है।[6] वास्तव में, हालिया शोध जनसांख्यिकी लाभांश, डिजिटल नवाचार और आर्थिक विकास के बीच संबंधों की पुष्टि करता है[7]। भारत के कामकाजी आयु अनुपात में वृद्धि के साथ जुड़ी उच्च बचत और निवेश दरों द्वारा समर्थित, आज के जीडीपी स्तरों और 2047 के बीच यात्रा करना संभव हो जाएगा, जैसा कि हाल ही में नीति आयोग[8] द्वारा परिकल्पित किया गया है और एक उन्नत अर्थव्यवस्था से जुड़े प्रति व्यक्ति आय स्तरों को पार करना संभव हो जाएगा। काल-चर दृष्टिकोण से, लगभग एक दशक के लिए गति का तीव्र होना आवश्यक है; उसके बाद, विशुद्ध गति भारत को कम विकास दर पर भी आगे बढ़ाएगी। इस रास्ते पर, हमें एक हरित, स्वच्छ और स्वस्थ राष्ट्र बनने की दिशा में आगे बढ़ते हुए, नवाचार ऊर्जा को उन्मुक्त करने के लिए विश्व स्तरीय

* 2024 को मुंबई, भारत में भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) द्वारा आयोजित वित्तीयन 3.0 शिखर सम्मेलन: विकसित भारत की तैयारी में भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के उप गवर्नर माइकल देवब्रत पात्र द्वारा दिया गया मुख्य भाषण । सुनील कुमार, स्नेहल एस हेरवाडकर, समीर रंजन बेहरा, धन्या वी, राजस सरौए, संभावी ढींगरा, गौतम से प्राप्त मूल्यवान टिप्पणियों और विनीत कुमार श्रीवास्तव से प्राप्त संपादकीय सहायता के लिए आभार।

[1] भारत सरकार, आर्थिक सर्वेक्षण, 2018-19, खंड 1, अध्याय 7।

[2] अन्र्स्ट एंड यंग, 2023, इंडिया@100: रीपिंग द डेमोग्राफिक डिविडेंड, 11 अप्रैल।

[3] विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (एसटीईएम)।

[4] भारत सरकार, अंतरिम केंद्रीय बजट, 2024-25।

[5] विदेश मंत्रालय, 2020, भारत ने बीएफएसआई क्षेत्र में एआई नवोन्मेष को बढ़ावा देने के लिए हब लॉन्च किया।

[6] अय्यर, एस. और मोदी , ए., 2011, जनसांख्यिकी लाभांश: भारतीय राज्यों से साक्ष्य, आईएमएफ वर्किंग पेपर डब्ल्यूपी/11/38।

[7] ज़मान, के.ए., यू. और सरकार, टी., 2021, जनसांख्यिकी लाभांश, डिजिटल नवोन्मेष और आर्थिक विकास: बांग्लादेश अनुभव, एशियाई विकास बैंक संस्थान वर्किंग पेपर 1237।

[8] आज की 3.36 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की जीडीपी से 2047 तक 30 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनना तथा प्रति व्यक्ति आय आज की 2,392 अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष से बढ़कर 18,000 अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष होना (नीति आयोग, 2047 के लिए विकसित भारत का विजन-एक दृष्टिकोण पत्र, 7 अगस्त, 2024)।

भौतिक अवसंरचना और अनुकूल वातावरण का निर्माण करने की आवश्यकता होगी। भारत मानवता के लिए एक न्यायसंगत, समावेशी और सुदृढ़ भविष्य प्राप्त करने के लिए विश्व व्यवस्था को नया रूप देने में भी योगदान देगा।

III. वित्त और विकास पर पुनर्विचार

'कल के भारत' के इस विजन को पूरा करने की कुंजी वित्त की भूमिका है। विकास और वित्त के बीच संबंधों पर वर्षों से एक जीवंत बहस चल रही है। अर्थशास्त्रियों ने तर्क दिया है कि यह या तो आपूर्ति चालित या मांग के अनुक्रम का अनुसरण करता है। पहली स्थिति में, वित्तीय क्षेत्र का विकास आर्थिक विकास से पहले होता है। उदाहरण के लिए, किसी देश के आर्थिक आकार के सापेक्ष वित्तीय क्षेत्र की गहराई या आकार को भविष्य के आर्थिक विकास, भौतिक पूंजी संचय और आर्थिक दक्षता में सुधार का एक मजबूत भविष्य वक्ता माना जाता है।[9] दूसरी स्थिति में, यह माना जाता है कि अर्थव्यवस्था का विकास होना चाहिए और फिर वित्तीय क्षेत्र को उसका अनुसरण करना चाहिए। साथ ही, यह मान्यता है कि यह संबंध सभी देशों और अवधियों में रैखिक नहीं हो सकता है। विकास के अपेक्षाकृत कम स्तरों पर, यह पारस्परिक रूप से सुदृढ़ अनुक्रम परिवर्तनकारी हो सकता है, लेकिन विकास के उच्च स्तरों पर कम प्रभावी हो सकता है।[10] अंतर्जात विकास सिद्धांत में प्रगति दोनों परिकल्पनाओं का समर्थन करती है, नवाचार और शिक्षा में निवेश को सुविधाजनक बनाने, लेनदेन लागत को कम करने और जोखिमों का प्रबंधन करने में वित्त और वित्तीय मध्यस्थों की भूमिका पर जोर देती है, जिससे विकास प्रक्रिया में तेजी आती है।[11]

वास्तविकता यह है कि दोनों धागे आपस में इस तरह से जुड़े हुए हैं कि उन्हें अलग करना मुश्किल है। जहाँ, एक अच्छी तरह से काम करने वाला वित्तीय क्षेत्र संसाधनों के कुशल आवंटन और अर्थव्यवस्था की विकास क्षमता के दोहन के लिए एक पूर्व शर्त है, वहीं, यह भी स्वयंसिद्ध है कि वित्तीय सेवाओं की मांग विकास और अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के औपचारिककरण पर निर्भर करती है। दूसरी ओर, व्यापार और वित्तीय चक्र एक दूसरे को पोषण, सुदृढ़ और प्रवर्धित करते हैं। इसमें आगे और पीछे भी होते हैं। अगस्त की शुरुआत में, हमने दुनिया भर के वित्तीय बाजारों में बेतहाशा गिरावट देखी – जो 1987 के काले सोमवार (ब्लैक मंडे) की याद दिलाता है - जब आने वाले डेटा को आसन्न मंदी के संकेत के रूप में पढ़ा गया, जिससे व्यापक रूप से बिकवाली हुई और बिकवाली जारी रखने (कैरी ट्रेड) की वैश्विक समाप्ति हुई। इसी तरह, यूक्रेन में युद्ध के मद्देनजर वैश्विक मुद्रास्फीति में उछाल ने मौद्रिक नीति और वित्तीय स्थितियों में एक समन्वित और आक्रामक कठोरता को बढ़ावा दिया, जिसके परिणामस्वरूप मार्च 2023 में कुछ क्षेत्राधिकारों में बैंक विफलताएं और जमा राशि में कमी आई।

IV. राष्ट्रीय लेखांकन में वित्त को स्थान देना

आय और व्यय के चक्रीय प्रवाह में जो अर्थव्यवस्था के कामकाज का वर्णन करता है, वस्तुओं, सेवाओं, मुआवज़ों और करों में लेन-देन बचत और निवेश के प्रवाह से मेल खाते हैं, जो उधार देने योग्य संसाधनों के अंतर-क्षेत्रीय हस्तांतरण का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत में, घरेलू क्षेत्र आमतौर पर अपने निवेश के सापेक्ष अधिशेष बचत उत्पन्न करता है जिसे वह अन्य क्षेत्रों को उधार देता है। हाल ही में, महामारी के दौरान संचित विवेकपूर्ण बचत को समाप्त करने के साथ-साथ वित्तीय आस्तियों से आवास जैसी भौतिक आस्तियों में बदलाव के रूप में चल रहे व्यावहारिक परिवर्तनों के कारण परिवारों की निवल वित्तीय बचत 2020-21 के स्तर से लगभग आधी हो गई है। आगे चलकर, बढ़ती आय से प्रेरित होकर, परिवार अपनी वित्तीय आस्तियों का फिर से निर्माण करेंगे - 2000 के दशक की शुरुआत से लेकर वैश्विक वित्तीय संकट तक यह सकल घरेलू उत्पाद का 15 प्रतिशत रहा था। यह प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है - परिवारों की वित्तीय आस्तियां 2011-17 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद के 10.6 प्रतिशत से बढ़कर 2017-23 (महामारी वर्ष को छोड़कर) के दौरान 11.5 प्रतिशत हो गई हैं। महामारी के बाद के वर्षों में उनकी भौतिक बचत भी सकल घरेलू उत्पाद के 12 प्रतिशत से अधिक हो गई है और आगे भी बढ़ सकती है – यह 2010-11 में सकल घरेलू उत्पाद

[9] किंग, आर.जी. और लेविन, आर. (1993). वित्त और विकास: शुम्पीटर सही हो सकते हैं. क्वार्टरली जर्नल ऑफ इकोनॉमिक्स 108(3), 717-737; लेविन, आर. और ज़र्वोस , एस. (1998). शेयर बाजार, बैंक और आर्थिक विकास. अमेरिकन इकोनॉमिक रिव्यू 88(3), 537-558.

[10] हुआंग, एच. और लिन, एस. (2009)। नॉन-लीनियर फाइनेंस-ग्रोथ नेक्सस। संक्रमण का अर्थशास्त्र 17(3), 439-466।

[11] लेविन, आर., (2004). वित्त और विकास: सिद्धांत और साक्ष्य, एनबीईआर वर्किंग पेपर नंबर 10766; रोमर, पीएम, (1990). अंतर्जात तकनीकी परिवर्तन, जर्नल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, 98(5, भाग 2), एस71-एस102.

के 16 प्रतिशत तक पहुंच गई थी। तदनुसार, आने वाले दशकों में परिवार शेष अर्थव्यवस्था के लिए शीर्ष निवल ऋणदाता बने रहेंगे। निजी कॉरपोरेट क्षेत्र ने शेष अर्थव्यवस्था से अपने निवल उधार को काफी कम कर दिया है[12], जो बढ़ती आंतरिक प्राप्ति और मंद क्षमता निर्माण के संयोजन को दर्शाता है। आगे देखते हुए, कैपेक्स चक्र में पुनरुद्धार के पीछे इसकी निवल उधारी आवश्यकता बढ़ने की संभावना है। इन वित्तपोषण आवश्यकताओं को बड़े पैमाने पर परिवारों और बाहरी संसाधनों द्वारा पूरा किया जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र की निवल बचत असमान रूप से कम हो रही है; भारत के भविष्य को आकार देने में राजकोषीय नीति के लिए परिकल्पित महत्वपूर्ण भूमिका के मद्देनजर यह क्षेत्र अर्थव्यवस्था में निवल उधारकर्ता बना रहेगा।

पूरे देश में घाटा है, तो वह बाकी दुनिया से उधार लेता है और विदेशी बचत का प्रवाह उसकी निवेश आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करता है। भारत के लिए, घरेलू बचत ने विकास की समग्र निवेश आवश्यकताओं को काफी हद तक वित्तपोषित किया है, जिसमें बाहरी वित्तपोषण ने एक पूरक भूमिका निभाई है, जैसा कि काफी हद तक मामूली चालू खाता घाटे में परिलक्षित होता है। जैसे-जैसे अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता बढ़ती है और विदेशी संसाधनों को अवशोषित करने की इसकी क्षमता बढ़ती है, बाहरी वित्तपोषण की मात्रा और इसकी संरचना में मौलिक बदलाव हो सकते हैं, लेकिन पिछले अनुभवों के आलोक में, बाहरी ऋण स्थिरता एक नीतिगत प्राथमिकता बनी रहेगी।

कार्यबल और उसकी मितव्ययिता और उत्पादकता सहित प्राकृतिक संपदा को देखते हुए, यह निवेश की दर है जो अर्थव्यवस्था के विकास पथ के साथ-साथ इसके संरचनात्मक बदलावों में महत्वपूर्ण मोड़ प्रदान करती है। जैसा कि पहले बताया गया है, अर्थव्यवस्था अपने दृष्टिकोण की खोज में आधुनिक होती जा रही है, बाजार वित्तपोषण के विस्तार और परिष्कार में वृद्धि होने की संभावना है। वित्तीय मध्यस्थता की संस्थागत संरचना विशेषज्ञता के क्षेत्रों का दोहन करते हुए और तकनीकी समाधानों का लाभ उठाते हुए अधिक विविध हो सकती है।

ऐतिहासिक रूप से, भारत में विकास में तेजी के चरणों के साथ-साथ सकल घरेलू निवेश दर भी बढ़ी है। विकास की समग्र दर के अलावा, वांछित निवेश दर का एक प्रमुख निर्धारक जीडीपी की एक इकाई का उत्पादन करने के लिए आवश्यक पूंजी की इकाइयों की संख्या के संदर्भ में पूंजी उपयोग की दक्षता है। यह वृद्धिशील पूंजी उत्पादन अनुपात (आईसीओआर) जितना कम होगा, पूंजी की उत्पादकता या पूंजी की सीमांत दक्षता उतनी ही अधिक होगी। अधिकांश विकसित देशों में आईसीओआर 3 के आसपास है। 2012-19 की अवधि में, भारत में आईसीओआर औसतन 5.0 था, लेकिन पिछले तीन वर्षों में यह 4.0 पर आ गया है। जैसे-जैसे ये दक्षता लाभ बढ़ते हैं, कार्यबल कौशल हासिल करता है और आर्थिक संरचना परिष्कार और तकनीकी प्रगति हासिल करती है, आईसीओआर को 3.5 से 4 की सीमा में परिकल्पित करना संभव है। तदनुसार, उच्च विकास के एक दशक में आवश्यक निवेश प्रति वर्ष सकल घरेलू उत्पाद के 33-38 प्रतिशत के दायरे में होगा। यह किसी भी तरह से असंभव नहीं है, अगर 2010-11 में हासिल की गई लगभग 39 प्रतिशत की ऊंचाई को संभावित माना जाए। जीडीपी के 32-36 प्रतिशत की सीमा में बचत दरों के साथ इस वांछित निवेश दर को वित्तपोषित करना संभव है, जो 2007-08 में हासिल की गई 37.8 प्रतिशत की ऊंचाई को देखते हुए फिर से प्राप्त करने योग्य है।[13] भविष्य की ओर देखते हुए, यह आकांक्षा सभी प्रमुख घटकों - बढ़ते कुशल कार्यबल के बल पर परिवार; विनिर्माण और निर्यात पर जोर से लाभान्वित होने वाले व्यवसाय; और वर्तमान मजबूती को जारी रखने वाली सरकारों के बीच बचत क्षमता में सुधार पर आधारित है। जैसा कि पहले कहा गया है, बाहरी वित्तपोषण का योगदान परिमाण और संरचना को बदल सकता है।

मैं आशा करता हूँ कि अपने शेष संबोधन में मैं भारत के आकांक्षात्मक लक्ष्यों में वित्त के विकासात्मक योगदान के कुछ रणनीतिक पहलुओं पर नजर डालने के लिए उपलब्ध अनुमानों का उपयोग कर सकूंगा।

V. अवसंरचना

अवसंरचना राष्ट्रीय उत्पादन क्षमता, सामाजिक कल्याण और आर्थिक विकास के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अवसंरचना पर खर्च पूंजीगत व्यय के वर्ष में 2.45 और अगले

[12] वर्ष 2007-08 में सकल घरेलू उत्पाद के 9 प्रतिशत से घटकर हाल ही में 1 प्रतिशत से भी कम हो गया है।

[13] नीति आयोग की नवंबर 2018 की "नया भारत @75 के लिए रणनीति" में भी इसी तरह की आकांक्षा व्यक्त की गई है।

वर्ष में 3.14 का जीडीपी गुणक उत्पन्न करता है।[14] सालाना जीडीपी के कम से कम 8-10 प्रतिशत की अवसंरचना में निवेश की आवश्यकता के साथ[15], भारत का अवसंरचना अंतर प्रति वर्ष जीडीपी का 4.1 प्रतिशत अनुमानित किया गया है, जो जलवायु आवश्यकताओं के लिए समायोजित होने पर 5.3 प्रतिशत हो जाता है।[16] 2024-30 की अवधि में, यह अनुमान लगाया गया है कि अवसंरचना में निवेश को 1.7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर (143 लाख करोड़ रुपये) तक बढ़ाना होगा, जिसमें लगभग 0.4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर हरित निवेश होगा।[17] भविष्य में निजी क्षेत्र अवसंरचना व्यय के, विशेष रूप से, ऊर्जा और परिवहन में, केंद्र में आ जाएगा। वित्तपोषण के स्रोत विविध होंगे, जिनमें घरेलू पूंजी बाजार में ऋण और इक्विटी जारी करने से लेकर बाह्य वाणिज्यिक उधार और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) तक शामिल होंगे।

VI. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) भारत की आर्थिक और सामाजिक प्रगति के लिए महत्वपूर्ण हैं - यह अनुमान लगाया गया है कि एमएसएमई क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 30 प्रतिशत, निर्यात का 45 प्रतिशत और व्यापार क्षेत्र में 62 प्रतिशत रोजगार प्रदान करता है।[18] आने वाले वर्षों में एमएसएमई की संख्या में वृद्धि होने की उम्मीद है। भारत के एमएसएमई की कुल वित्त मांग लगभग 1,955 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। इसमें से ऋण आधारित वित्त की मांग 1,544 बिलियन अमेरिकी डॉलर आंकी गई है,[19] जिनमें से आधी उन लोगों से आती है जो अनौपचारिक स्रोतों से या वित्तीय रूप से अलाभकारी उद्यमों से वित्तपोषण पसंद करते हैं। इससे 819 बिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण मांग बचती है, जिसमें से 289 अरब अमेरिकी डॉलर की मांग वर्तमान में बैंकों जैसे औपचारिक ऋणदाता द्वारा पूरी की जाती है। शेष 530 बिलियन अमेरिकी डॉलर की शेष मांग बैंकों, फिनटेक और एनबीएफसी के लिए एक विशाल बाजार बनाती है।

VII. कौशल विकास

भविष्य के लिए तैयार होने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता होगी, जिसमें तकनीकी परिवर्तन में तेजी के अनुरूप मानव संसाधनों को कुशल बनाना प्रमुख रूप से शामिल है। विश्व आर्थिक मंच के अनुसार, अगले पांच वर्षों में वैश्विक स्तर पर 44 प्रतिशत श्रमिकों के कौशल में व्यवधान आएगा।[20] भविष्य के कार्यबल को प्रभावी ढंग से कुशल बनाने के लिए, भारत को अगले 6 वर्षों में प्रति वर्ष लगभग 2-3 लाख करोड़ रुपये का निवेश करने की आवश्यकता है।[21] इसमें अवसंरचना, प्रशिक्षण केंद्र और निजी क्षेत्रों के साथ भागीदारी शामिल होगी।

कौशल आवश्यकताओं को वित्तपोषित करने में प्रदर्शन-आधारित निवेश साधनों जैसे कि पूर्व-सहमत सामाजिक परिणाम के साथ विकास कार्यक्रमों को वित्तपोषित करने के उद्देश्य से बांड, मजदूरी रोजगार की संभावनाओं को बढ़ाने वाले मोचनीय कौशल वाउचर, तकनीक-आधारित प्रशिक्षण प्लेटफार्मों, ई-लर्निंग स्टार्ट-अप और इस तरह के लिए निजी इक्विटी/उद्यम पूंजी निधि, सामाजिक विकास कार्यक्रमों और परियोजनाओं के रूप में बहुपक्षीय एजेंसियों, सामाजिक और निजी संगठनों से प्रत्यक्ष समर्थन; और कार्यशील पूंजी वित्तपोषण, प्रशिक्षुओं और सेवा प्रदाताओं को संस्थागत ऋण प्रदान करने के लिए बैंकों के साथ समझौतों में व्यापार प्राप्तियां छूट प्रणाली को जोड़ा जा सकता है।[22] केंद्रीय बजट 2024-25 ने श्रम बल को कुशल बनाने में निजी क्षेत्र की एक बड़ी भूमिका पर ज़ोर दिया है। अब तक केवल 36 प्रतिशत कंपनियां उद्यम-आधारित प्रशिक्षण आयोजित करती हैं।[23] शीर्ष 500 कंपनियों में युवाओं के लिए इंटर्नशिप के अवसरों की सुविधा के लिए बजट प्रस्ताव से उद्योगों की कौशल मांग को पूरा करने के साथ-साथ श्रम बल के लिए कौशल अवसर बढ़ सकते हैं।

---

[14] राज्यसभा में केंद्रीय बजट 2022-23 पर चर्चा, 11 फरवरी, 2022; बोस, एस. और भानुमूर्ति , एनआर, 2015, भारत के लिए राजकोषीय गुणक। मार्जिन: जर्नल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च 9(4), 379-401।

[15] आरबीआई के आंतरिक अनुमान।

[16] एशियाई विकास बैंक, 2017, एशिया की अवसंरचना संबंधी जरूरतों को पूरा करना, 1 फरवरी।

[17] क्रिसिल (2023)। वित्त वर्ष 2024 और 2030 के बीच भारत का अवसंरचना व्यय 2017-2023 की तुलना में दोगुना होकर ₹143 लाख करोड़ हो जाएगा। प्रेस विज्ञप्ति। 17 अक्टूबर।

[18] भारत सरकार, असंगठित क्षेत्र उद्यमों का वार्षिक सर्वेक्षण (एएसयूएसई), 2022-23; पीआईबी, 2023, देश के सकल घरेलू उत्पाद में एमएसएमई का योगदान, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय। 11 दिसंबर; मैकिन्से ग्लोबल इंस्टीट्यूट, 2024, छोटे व्यवसायों पर एक सूक्ष्म विश्लेषण: देश के अनुसार उत्पादकता अवसर, मई।

[19] एवेंडस , 2023, एमएसएमई ऋण: क्षमता को खोलना, सपनों को साकार करना, अप्रैल।

[20] विश्व आर्थिक मंच, 2023, नौकरियों का भविष्य रिपोर्ट, मई।

[21] आरबीआई के आंतरिक अनुमान।

[22] केपीएमजी-फिक्की, 2023, भारत में कौशल वित्तपोषण, सितंबर।

[23] अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, 2024, भारत की रोजगार रिपोर्ट 2024: युवा रोजगार, शिक्षा और कौशल।

VIII. जलवायु

जलवायु परिवर्तन के अनुकूल होने के लिए भारत के अद्यतन राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) को पूरा करने के लिए 2024-2030 की अवधि में ₹30 लाख करोड़ (यूएस$ 0.36 ट्रिलियन) के निवेश की आवश्यकता होगी।[24, 25] प्रति वर्ष 5 मिलियन मीट्रिक टन की उत्पादन क्षमता का लक्ष्य वाले भारत के 'राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन' में ₹19,744 करोड़ या 2.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रारंभिक परिव्यय शामिल होगा।[26] इसके अलावा, 2047 तक जीवाश्म ईंधन के आयात से मुक्त होने और 2070 तक निवल शून्य का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए 10.1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के वित्तपोषण की आवश्यकता होने का अनुमान है।[27]

हाल के अनुभव के आधार पर, सॉवरेन ग्रीन बॉण्ड (एसजीआरबी) का उपयोग ग्रीन परियोजनाओं को वित्तपोषित या पुनर्वित्तपोषित करने के लिए किया जा सकता है। एसजीआरबी वैश्विक रूप से गतिशील पर्यावरण, स्थिरता और अभिशासन (ईएसजी) निधियों को जुटाने के लिए निजी उद्यम द्वारा ग्रीन बॉण्ड के मूल्य निर्धारण के लिए एक बेंचमार्क भी प्रदान कर सकते हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण (पीएसएल) के तहत एक निश्चित सीमा तक अक्षय ऊर्जा क्षेत्र को शामिल करने और "हरित जमा की स्वीकृति के लिए रूपरेखा" से हरित गतिविधियों/परियोजनाओं के लिए बैंक निधीयन की सुविधा मिलने की उम्मीद है। इसके साथ ही, जलवायु से संबंधित वित्तीय जोखिमों पर आरबीआई का मसौदा प्रकटीकरण रूपरेखा अपर्याप्त जानकारी के कारण आस्तियों के गलत स्थान पर रखे जाने और पूंजी के गलत आवंटन को रोकने की दिशा में काम करेगा। अक्षय ऊर्जा क्षेत्र के लिए स्वचालित मार्ग के तहत 100 प्रतिशत एफडीआई और स्वचालित मार्ग के तहत हरित परियोजनाओं के लिए धन जुटाने वाली कंपनियों के लिए बाहरी वाणिज्यिक उधार के लिए शिथिल मानदंडों के साथ, एक बार हरित वर्गीकरण विकसित होने और वैश्विक मानकों के साथ संरेखित होने के बाद, घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों जलवायु वित्त का प्रवाह बढ़ने की उम्मीद है।

IX. डिजिटलीकरण

भारत में तेजी से डिजिटल बदलाव हो रहा है। बैंकिंग क्षेत्र में, डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म, मोबाइल बैंकिंग ऐप और ऑनलाइन सेवाएँ नकदी निर्भरता को कम कर रही हैं और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दे रही हैं। कई फिनटेक कंपनियाँ और डिजिटल लेंडिंग प्लेटफ़ॉर्म व्यक्तियों और व्यवसायों को त्वरित और परेशानी मुक्त ऋण प्रदान करते हैं, जो क्रेडिट योग्यता का आकलन करने के लिए डेटा एनालिटिक्स और एआई का उपयोग करते हैं।

एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) की सफलता एक गेम-चेंजर रही है, जो इसे वैश्विक स्तर पर सबसे तेजी से बढ़ते डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्मों में से एक बनाती है। अन्य विकासों में केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी) परियोजना या e₹ शामिल है, जिसमें न केवल भुगतान परिदृश्य, बल्कि व्यापक वित्तीय प्रणाली को बदलने की क्षमता है। डिजिटल सप्लाई चेन फाइनेंस (डीएससीएफ) एक और उभरता हुआ खंड है जो डिजिटल वित्तीय सेवाओं को आपूर्ति श्रृंखला में एकीकृत करने, सुगम लेनदेन की सुविधा, जोखिम को कम करने और समग्र दक्षता को बढ़ाने का प्रयास करता है। बीमा, पूंजी बाजार और ग्रामीण और शहरी कनेक्टिविटी और डिजिटल वित्तीय सेवाओं तक पहुंच के विस्तार में भी डिजिटल तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है।

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार, भारत 2025 तक 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की डिजिटल अर्थव्यवस्था बन सकता है, जिसमें डिजिटल वित्तपोषण की आवश्यकता सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 2.3 प्रतिशत होगी।[28] इस निकट-अवधि लक्ष्य से अनुमान लगाते हुए, 2047 में भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का आकार 5.4 से 6.9 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के बीच होगा, और डिजिटल बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण का अंतर 2047 तक लगभग 124-159 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच जाएगा।[29]

---

[24] पीआईबी, 2024: "भारत को अपने सीओपी जलवायु प्रतिज्ञाओं को पूरा करने के लिए वित्त वर्ष 2024-2030 के दौरान 30 लाख करोड़ रुपये के निवेश की आवश्यकता है", विश्व बैंक वेबिनार में आईआरईडीए के सीएमडी, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, 15 फरवरी।

[25] यह निवेश सौर फोटोवोल्टिक सेल, इलेक्ट्रोलाइजर, पवन ऊर्जा उपकरण, बैटरी ट्रांसमिशन और अपशिष्ट को ऊर्जा में रूपान्तरण के लिए विनिर्माण क्षमता में आवश्यक होगा।

[26] पीआईबी, 2023, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, 3 जनवरी।

[27] ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद (2021)। भारत के 2070 निवल शून्य लक्ष्य के लिए निवेश का आकार। 18 नवंबर।

[28] भारत को डिजिटल सेवाओं की बढ़ती मांग और बढ़ते ऑनलाइन ट्रैफ़िक का समर्थन करने के लिए भौतिक डिजिटल अवसंरचना में 2025 तक 23 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक के निवेश की आवश्यकता है (अर्नस्ट एंड यंग और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स एसोसिएशन (2022)। डिजिटल इंफ्रा कंपनी - अनलॉकिंग द टावर पावर। जनवरी)।

[29] आरबीआई के आंतरिक अनुमान।

निष्कर्ष

निष्कर्ष के तौर पर, भारत को अपनी आकांक्षाओं के अनुरूप वित्त की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने संस्थागत ढांचे में बदलाव की जरूरत होगी। भौतिक, सामाजिक और डिजिटल अवसंरचना, कौशल, हरित ऊर्जा, नवोन्मेषी विनिर्माण और एमएसएमई के वित्तपोषण पर जोर दिया जाएगा। इसके मूल में पर्याप्त द्वितीयक बाजार व्यापार चलनिधि और विस्तार के साथ एक मजबूत कॉरपोरेट बॉण्ड बाजार होना चाहिए। बाहरी वित्तपोषण निवेश को बढ़ावा देने और नई प्रौद्योगिकियों को लाने में तेजी से जीवंत भूमिका निभाएगा, बशर्ते बाहरी वित्तपोषण के संबंध में अवशोषण क्षमता निर्यात क्षमता को बढ़ाने और लएफडीआई को आकर्षित करने वाले सुधारों की खोज के साथ बढ़े। विकास के उच्च स्तर की भारत की खोज में, वित्तपोषण को एक सुविधाकर्ता के रूप में देखा जाना चाहिए, न कि एक अवरोधक के रूप में। जैसा कि केंद्रीय बैंकिंग के मूल सिद्धांत के प्रवर्तक वाल्टर बेजहोट ने अपने लोम्बार्ड स्ट्रीट में लिखा है, 'जितना कम पैसा बेकार पड़ा रहेगा, उतना ही अधिक लाभांश होगा'।[30] वित्त और विकास के बीच संबंधों पर जहां से मैंने शुरुआत की थी, वहीं पर लौटते हुए, मैं स्वर्गीय आनंद चंदावरकर को उद्धृत करने से बेहतर कुछ नहीं कर सकता, जो आरबीआई में अर्थशास्त्र के पेशे के साधकों की पवित्र परंपरा के सबसे अच्छे समर्थकों में से एक हैं[31]: “इस संबंध में बहस कि क्या वित्तीय मध्यस्थता और विकास एक "मांग-अनुसरण" या "आपूर्ति-अग्रणी" घटना है, तुलनात्मक रूप से इस प्रश्न का पूरक है: कि क्या (देशों) के पास उचित नीतियां अपनाने के लिए आवश्यक अंतर्दृष्टि और आर्थिक राजनीति है?"

धन्यवाद।

[30] बेजहोट, वाल्टर, 1873, लोम्बार्ड स्ट्रीट: ए डिस्क्रिप्शन ऑफ़ द मनी मार्केट, न्यूयॉर्क: स्क्रिब्नर, आर्म्सटॉग एंड कंपनी.

[31] चंदावरकर, ए., विकास के लिए वित्त कितना प्रासंगिक है?, आईएमएफ ई-लाइब्रेरी, https://www.elibrary.imf.org >article-A004-en. जगदीश भगवती ने आनंद चंदावरकर को “अपने आप में एक अलग श्रेणी का व्यक्ति, एक पुस्तक प्रेमी, एक बुद्धिजीवी, एक प्रतिभाशाली लेखक और एक बेहतरीन अर्थशास्त्री बताया, और यह सब बिना किसी अहंकार के और बहुत ही शालीनता और आकर्षण के साथ।”

*आधारभूत संरचना के लिए वित्तपोषण में आने वाली चुनौतियों का प्रबंधन: एनएबीएफआईडी के लिए आगे की राह**

श्री एम. राजेश्वर राव

विशिष्ट अतिथिगण, देवियो एवं सज्जनो,

आज यहां 'एनएबीएफआईडी के इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्क्लेव' में आना खुशी की बात है, जो भारत की आधारभूत संरचनागत यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रतिभागियों के साथ बातचीत करने का उत्कृष्ट अवसर प्रदान करता है।

आधारभूत संरचना को सुविधाओं और प्रणालियों के तंत्र के रूप में सोचा जा सकता है जो एक अर्थव्यवस्था को कुशलतापूर्वक कार्य करने में सक्षम बनाता है, जो बड़े पैमाने पर समाज के लिए इष्टतम परिणाम संभव कर सकता है। इसलिए, यह देश के आर्थिक विस्तार और समग्र विकास को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण मुख्य स्रोत है। यह उत्पादकता बढ़ाकर, निवेश आकर्षित करके, बाज़ारों का विस्तार करके और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करते हुए, एक समृद्ध और न्यायसंगत समाज की नींव रखता है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है और जैसे-जैसे यह वैश्विक आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभरने की महत्वाकांक्षी यात्रा पर अग्रसर है, ठोस और विश्वसनीय आधारभूत संरचना की भूमिका सर्वोपरि होती जा रही है। इसे स्वीकार करते हुए, भारत ने हाल के वर्षों के दौरान राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (एनआईपी), पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान, भारतमाला परियोजना और सागरमाला परियोजना जैसे नीतिगत उपायों के माध्यम से पर्याप्त आधारभूत संरचनागत निवेश किया है। इस वर्ष केंद्रीय बजट में पूंजीगत व्यय के लिए ₹11.11 लाख करोड़ का आवंटन, जो सकल घरेलू उत्पाद का 3.4 प्रतिशत है, इस प्रतिबद्धता को मजबूत करना चाहता है।

ऐतिहासिक रूप से, सार्वजनिक व्यय भारत में आधारभूत संरचना के विकास की आधारशिला रहा है। हालाँकि, उन सीमाओं को ध्यान में रखते हुए, जिन तक हम सार्वजनिक व्यय पर निर्भर रह सकते हैं, आधारभूत संरचना के विस्तार के लिए वित्तपोषण, औद्योगिक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने, विविध प्रतिभा आधार तक पहुंच व्यापक बनाने और संसाधनों के उपयोग को अनुकूलित करने में निजी क्षेत्र की भागीदारी महत्वपूर्ण हो जाती है। यह इस संदर्भ में है कि भारत में दीर्घकालिक आधारभूत संरचना के वित्तपोषण का समर्थन करने के लिए एक विशिष्ट जनादेश के साथ नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट (एनएबीएफआईडी) जैसी एक विशेष संस्था, निजी क्षेत्र की भागीदारी को उत्प्रेरित करने के लिए निधीयन अंतर को पाटने में एक परिवर्तनकारी भूमिका निभा सकती है। इस पृष्ठभूमि में, मैं सामान्य रूप से आधारभूत संरचना के वित्तपोषण में आनेवाली चुनौतियों और इन चुनौतियों पर नियंत्रण पाने में एनएबीएफआईडी द्वारा निभाई जा सकने वाली महत्वपूर्ण भूमिका पर संक्षेप में अपने विचार रखना चाहूंगा। मैं कुछ उभरते मुद्दों पर भी प्रकाश डालना चाहूंगा जिन पर एनएबीएफआईडी को अपने अधिदेश को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए ध्यान देना चाहिए।

विकास वित्त संस्थान

इस संदर्भ को स्पष्ट करने के लिए, मैं विकास वित्त संस्थानों (डीएफआई) की अवधारणा पर एक संक्षिप्त दृष्टिकोण के साझाकारण से शुरुआत करता हूं। द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद, जब युद्ध से तबाह राष्ट्र और नव स्वतंत्र देश तेजी से औद्योगिक विकास की राह पर चल पड़े, तो उन्हें तुरंत एहसास हुआ कि उस युग की वित्तीय प्रणालियाँ लंबी निर्माण अवधि वाली परियोजनाओं के वित्तपोषण से जुड़े मूल्य निर्धारण और प्रबंधन जोखिम के लिए आवश्यक कौशल से लैस नहीं थीं। इन कमियों को दूर करने के लिए, विकासात्मक प्रयासों के लिए वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता को पूरा करने हेतु सरकारों द्वारा दुनिया भर में विकास वित्त संस्थान (डीएफआई) स्थापित किए गए थे। इन संस्थानों को अपने घाटे को कम करने के लिए सरकारी समर्थन प्राप्त था और उन्हें बहुपक्षीय और द्विपक्षीय एजेंसियों से सस्ते फंड तक पहुंच प्राप्त थी जिसकी गारंटी सरकारों द्वारा दी जाती थी। हालाँकि, चूँकि बजटीय बाधाओं और बाजार दक्षता संबंधी मतों

---

* 12 सितंबर, 2024 को मुंबई में नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट (एनएबीएफआईडी) द्वारा आयोजित इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्क्लेव में उप गवर्नर श्री एम. राजेश्वर राव द्वारा मुख्य भाषण दिया गया। उषा जानकीरमन, अखिलेश गोखले और शशांक श्रीवास्तव द्वारा प्रदान किए गए इनपुट को कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार किया जाता है।

को देखते हुए सरकारों को अंततः उनका समर्थन करना मुश्किल हो गया, इसलिए इनमें से कई डीएफआई की पुन: स्थापना की गई।[1]

भारतीय डीएफआई की यात्रा

भारतीय डीएफआई ने भी अपने वैश्विक समकक्षों के समान रास्ता अपनाया। इसकी शुरुआत 1948 में राज्य वित्त निगमों (एसएफसी) के इको-सिस्टम के साथ आईएफसीआई की स्थापना से हुई, इसके बाद अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में विकास का समर्थन करने के लिए आईसीआईसीआई और आईडीबीआई जैसे अन्य ऋणदाता और पुनर्वित्त संस्थानों की स्थापना की गई। दीर्घकालिक औद्योगिक वित्त प्रदान करके, इन संगठनों ने चार दशकों से अधिक समय तक देश के भीतर पूंजी निर्माण को प्रोत्साहित करने और निवेश गतिविधियों का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालाँकि, वाणिज्यिक बैंकों से बढ़ती प्रतिस्पर्धा के साथ बढ़े हुए एनपीए ने डीएफआई को अपनी रणनीतियों को फिर से संरेखित करने के लिए मजबूर किया। चूँकि उन्हें अपना व्यवसाय मॉडल अव्यवहार्य लगा, इसलिए कुछ डीएफआई वाणिज्यिक बैंकों में परिवर्तित हो गए।

आधारभूत संरचना के वित्तपोषण में चुनौतियाँ

आधारभूत संरचना के वित्तपोषण के लिए आवश्यक विशिष्ट विशेषज्ञता वाली चुनौतियों का एक अनूठा समूह प्रस्तुत किया जाता है। सबसे पहले आधारभूत संरचना की परिभाषा पर ही आम सहमति बनाने की जरूरत है। रंगराजन आयोग (2001)[2] ने आधारभूत संरचना क्षेत्रों की प्राकृतिक एकाधिकार, उच्च डूब लागत, उत्पादन की गैर-व्यापारिकता, आबादी की सीमा तक खपत में गैर-प्रतिद्वंद्विता, मूल्य बहिष्कार की संभावना, और समाज पर बाहरी प्रभाव डालना जैसे छह विशेषताओं की पहचान की। इनमें से कुछ विशेषताएँ आधारभूत संरचना की प्रकृति के बजाय उसके वित्तपोषण की अंतर्निहित चुनौतियों से उत्पन्न होती हैं। लंबी निर्माण अवधि के साथ उच्च डूब लागत आधारभूत संरचना परियोजनाओं के वित्तपोषण को और अधिक जटिल बनाती है और आस्ति-देयता बेमेलता का कारण बनती है। अनुमोदन, मंजूरी में देरी, भूमि अधिग्रहण की चुनौतियाँ और समझौतों का उल्लंघन भी परियोजना वित्तपोषण के जोखिमों को बढ़ाता है और लागत में वृद्धि जैसे अन्य मुद्दों का कारण बनता है।

आधारभूत संरचना परियोजनाओं की परस्पर निर्भरता वित्तपोषण को और अधिक जटिल बना देती है, क्योंकि किसी आधारभूत संरचना परियोजना की वास्तविक क्षमता को उजागर करना अक्सर पूरक आधारभूत संरचना की उपलब्धता पर निर्भर होता है। यह अंतर्संबंध या अन्योन्याश्रय वित्तपोषण प्रक्रिया को जटिल बना सकता है, क्योंकि एक परियोजना में बाधाएं या देरी कारणात्मक प्रभावों का एक समूह शुरू कर सकती है, जिससे सभी परस्पर जुड़ी परियोजनाएं प्रभावित हो सकती हैं। नतीजतन, एक आधारभूत संरचना परियोजना का सफल समापन अक्सर सहक्रियात्मक आधारभूत संरचना, व्यापक योजना, सावधानीपूर्वक सिंक्रनाइज़ेशन और कुशल निष्पादन की उपलब्धता पर निर्भर करता है। यह आधारभूत संरचना के विकास के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण रखने की आवश्यकता को रेखांकित करता है, जहां परियोजनाओं को अलगाव में नहीं बल्कि एक परस्पर जुड़े मैट्रिक्स के घटकों के रूप में माना जाता है।

आधारभूत संरचना परियोजनाओं की लंबी कालावधि के लिए परियोजना के विभिन्न चरणों में विशेषज्ञता वाली विभिन्न वित्तीय संस्थाओं की भागीदारी की आवश्यकता होती है, जो इन संस्थाओं के बीच परियोजनाओं को पुनर्वित्त, स्थानांतरण और अधिग्रहण करके प्रक्रिया में सहायता करती हैं। तुलनात्मक रूप से अविकसित वित्तीय प्रणाली और आधारभूत संरचना क्षेत्र के लिए ऋण जुटाने वाले बाजार ने इस क्षेत्र को अपनी वित्तपोषण आवश्यकताओं के लिए बैंकों और एनबीएफसी पर निर्भर बना दिया था। हालाँकि, पिछले दशक में बैंकों में गैर-निष्पादित आस्तियों में हुई बढ़ोतरी और आधारभूत संरचना के वित्तपोषण में लगी प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण एनबीएफसी द्वारा ऋण चूक के कारण, आधारभूत संरचना के वित्तपोषण के प्रति इन वित्तीय मध्यस्थों की मांग कम हो गई। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) की बढ़ी हुई समुत्थानशीलता के साथ बैंकों के लिए गैर-निष्पादित आस्तियों (एनपीए) की हालिया गिरावट, इस क्षेत्र के लिए एक सकारात्मक बदलाव का संकेत देती है।

[1] उदाहरणों में चायना डेवलेपमेंट बैंक (सीडीबी), आफ्रिकन डेवलेपमेंट बैंक (एएफडीबी), अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (आईएफसी), कोरिया डेवलेपमेंट बैंक (केडीबी), ब्राजिलीयन राष्ट्रीय आर्थिक और सामाजिक डेवलेपमेंट बैंक (बीएनडीईएस), सिंगापुर डेवलेपमेंट बैंक (डीबीएस) शामिल हैं जिन्होंने अपने अधिदेश में औद्योगिक विकास से ध्यान हटाकर निजी क्षेत्र के विकास, क्षेत्रीय एकीकरण, वाणिज्यिक बैंकिंग को शामिल कर लिया है।

[2] जनवरी 2000 में सरकार द्वारा डॉ. सी. रंगराजन की अध्यक्षता में गठित एक आयोग ने देश में सांख्यिकीय प्रणाली और आधिकारिक सांख्यिकी के संपूर्ण दायरे की समीक्षा की। रिपोर्ट के हिस्से के रूप में, इसने अन्य क्षेत्रों से अलग आधारभूत संरचना की अपनी धारणा प्रस्तुत की। (https://www.mospi.gov.in/82-notion-infrastructure)

आधारभूत संरचना के वित्तपोषण के समर्थन में आरबीआई द्वारा उपाय

आर्थिक विकास के लिए आधारभूत संरचना के वित्तपोषण के महत्व को पहचानते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने विवेकपूर्ण नियमों के ढांचे के भीतर कई महत्वपूर्ण उपाय लागू किए हैं:

क. यदि आधारभूत संरचना परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त एक्सपोजर आवंटित किया जाता है, तो एनबीएफसी[3] को एकल उधारकर्ता के लिए निर्दिष्ट ऋण जोखिम सीमा को अतिरिक्त 5 प्रतिशत से बढ़ाने की अनुमति है।

ख. जबकि बैंकों को वर्तमान में यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि इक्विटी पूंजी के लिए प्रवर्तक का योगदान उनके अपने संसाधनों से आना चाहिए और उन्हें आम तौर पर अन्य कंपनियों के शेयर खरीदने के लिए अग्रिम प्रदान नहीं करना चाहिए, आधारभूत संरचना परियोजनाओं में प्रवर्तकों के शेयरों के अधिग्रहण के वित्तपोषण के लिए अपवाद बनाए गए हैं।

ग. बैंकों को बाजार से धन जुटाने के लिए दीर्घकालिक आधारभूत संरचना बांड जारी करने की भी अनुमति है। इस निधि को प्राथमिकता क्षेत्र ऋण आवश्यकताओं से छूट दी गई है और ये 2019 से सीआरआर/एसएलआर आवश्यकताओं के अधीन नहीं हैं।

घ. इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (इनविट्स) को बैंक द्वारा ऋण देने की अनुमति दी गई थी।

ड़. कॉरपोरेट्स/एसपीवी द्वारा निधीयन परियोजनाओं के लिए जारी किए गए बांड में निवेश करने के लिए लंबी अवधि के निधि प्रदाताओं को सक्षम करने की दृष्टि से, बैंकों को आंशिक क्रेडिट वृद्धि (पीसीई) की पेशकश करने की अनुमति है।

च. इसके अलावा, बैंक, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (एआईएफआई) और चुनिंदा एनबीएफसी[4] कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार के लिए बाजार-सक्षम नियामक ढांचे को स्थापित करने के आरबीआई के प्रयासों के हिस्से के रूप में क्रेडिट डेरिवेटिव में बाजार निर्माता के रूप में कार्य कर सकते हैं।

सरकार द्वारा किए गए प्रयासों और रिज़र्व बैंक द्वारा सक्षम विनियामक ढांचे के बावजूद, यह स्पष्ट है कि अगले कुछ दशकों में देश की आधारभूत संरचना की जरूरतों को पूरा करने के लिए और अधिक काम करने की जरूरत है क्योंकि हम 2047 तक एक विकसित अर्थव्यवस्था बनने की आकांक्षा की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। यहां एनएबीएफआईडी जैसी संस्था निस्संदेह महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

एनएबीएफआईडी की भूमिका और आगे की चुनौतियों से निपटना

नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट या एनएबीएफआईडी की स्थापना भारत में दीर्घकालिक गैर अवलंबन आधारभूत संरचना के वित्तपोषण का समर्थन करने के लिए की गई थी, जिसमें आधारभूत संरचना के वित्तपोषण के लिए आवश्यक बॉण्ड और डेरिवेटिव बाजारों का विकास भी शामिल था। मैं कुछ ऐसे क्षेत्रों पर प्रकाश डालना चाहूंगा जहां हमारा मानना है कि एनएबीएफआईडी को अपने अधिदेश को देखते हुए ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

इक्विटी संरचना और निधीयन

एनएबीएफआईडी ने वास्तविक वितरण में पर्याप्त वृद्धि के साथ-साथ पिछले वित्तीय वर्ष तक ₹1 लाख करोड़[5] से अधिक की मंजूरी देकर आशाजनक प्रगति की है। ₹20,000 करोड़ की प्रारंभिक पूंजी पूरक ₹5,000 करोड़[6] के अतिरिक्त अनुदान के साथ निकट अवधि में क्रेडिट बुक वृद्धि का समर्थन करेगी। इसके अलावा, जीवन बीमा कंपनियों, पेंशन फंड आदि जैसे बड़े संस्थागत निवेशकों के स्तर में वृद्धि, एनएबीएफआईडी के लिए

[3] एनबीएफसी-यूएल के बाहर की संस्थाओं के लिए, सभी एनबीएफसी (एनबीएफसी-आईएफसी के अलावा) की एक्सपोजर सीमा उनकी टियर-1 पूंजी का 25 प्रतिशत है, जबकि एनबीएफसी-आईएफसी की एक्सपोजर सीमा उनकी टियर-1 पूंजी का 30 प्रतिशत तक हो सकती है। एनबीएफसी-यूएल के लिए, एनएफबीसी (एनबीएफसी-आईएफसी के अलावा) और एनबीएफसी-आईएफसी के लिए एक्सपोजर को उनके पात्र पूंजी आधार के क्रमशः 20 प्रतिशत और 25 प्रतिशत पर सीमित रखा गया है।

[4] मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक (क्रेडिट डेरिवेटिव्स) दिशानिर्देश, 2022।

[5] एनएबीएफआईडी वार्षिक रिपोर्ट।

[6] स्रोत: माननीय वित्त मंत्री द्वारा एनएबीएफआईडी के कार्यनिष्पादन की समीक्षा पर दिनांक 29 फरवरी, 2024 की पीआईबी की प्रेस विज्ञप्ति।

उनकी वित्तीय जरूरतों के लिए विश्वसनीय दीर्घकालिक निधीयन को सुरक्षित करने का अवसर प्रस्तुत करती है, जो 'नैचरल फिट' की पेशकश करती है। नतीजतन, इसे एक मजबूत क्रेडिट रेटिंग के लिए भी प्रयास करना चाहिए जो भविष्य में निधीयन के घरेलू और वैश्विक दोनों स्रोतों का लाभ उठाने में मदद करेगी।

यह भी आवश्यक है कि मध्यावधि में, एक ऐसे व्यवसाय मॉडल के तहत आत्मनिर्भर संचालन की योजना बनाई जाए जो निरंतर सरकारी समर्थन या विनियामक व्यवस्था पर निर्भर न हो। हमारे युग की गतिशील प्रकृति के लिए सरकार द्वारा प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने वाले संस्थानों के लिए चुस्त रणनीतियों की आवश्यकता होती है, जिससे अर्थव्यवस्था की बदलती जरूरतों के अनुसार, अपनी रणनीतियों को मोड़ने के लिए आवश्यक लचीलेपन को बनाए रखते हुए, समग्र सरकारी प्रयासों को पूरक बनाया जा सके।

अनुशासन

इस संदर्भ में अनुशासन की भूमिका महत्वपूर्ण है। आरबीआई ने दीर्घकालिक स्थिरता और विकास के लिए वित्तीय संस्थानों के भीतर अनुशासन और आश्वासन कार्यों के महत्व को अधिकाधिक रेखांकित किया है। संस्थान के भविष्य के मार्ग का मार्गदर्शन करने और दीर्घकालिक संभावित संस्थागत निवेशकों को आकर्षित करने में बोर्ड की भूमिका महत्वपूर्ण है। एक स्वतंत्र, कुशल और पेशेवर प्रबंधन इसके लिए महत्वपूर्ण प्रवर्तक है। चूंकि एनएबीएफआईडी अभी भी अपने प्रारंभिक चरण में है, इसलिए मानव पूंजी विकास, संस्थागत मजबूती और सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने संबंधी ठोस प्रयासों के माध्यम से खुद को आवश्यक संसाधनों, कौशल और ज्ञान से लैस करने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। वित्तीय सेवा क्षेत्र में किसी भी अन्य इकाई की तरह, एनएबीएफआईडी को विशेष रूप से जोखिम प्रबंधन को समर्थ बनाने और आगे बढ़ने के लिए एक सशक्त जोखिम संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए मजबूत आश्वासन प्रणालियों की स्थापना पर ध्यान देना चाहिए।

परियोजना आकलन और मूल्यांकन में विशेषज्ञता और प्रतिष्ठा विकसित करना

जबकि एनएबीएफआईडी अधिनियम सर्वोत्तम प्रतिभा को आकर्षित करने और सर्वोत्तम विशेषज्ञता प्राप्त करने के लिए विभिन्न सक्षम सुविधाएँ प्रदान करता है, एनएबीएफआईडी को परियोजना आकलन विशेषज्ञता को शीघ्रता से विकसित करने और परियोजना चयन, आकलन और निगरानी के लिए बाजार में मानक स्थापित करने वाले अग्रणी के रूप में खुद को स्थापित करने की आवश्यकता होगी ताकि ऋणदाता और हितधारक निश्चिंत हो सके।

पिछली गलतियों से सीखना

शायद तत्कालीन डीएफआई में ऋण उपयोग की वितरण-पश्चात कडी निगरानी का अभाव एक प्रमुख डिजाइन विफलता थी, जिसके परिणामस्वरूप उप-इष्टतम परिणाम प्राप्त हुए[7]। पिछली घटनाओं से सीखने और व्यापक एवं लगातार सर्वेक्षणों और मूल्यांकनों के माध्यम से वित्त पोषित परियोजनाओं की चल रही निगरानी और मूल्यांकन के लिए समर्पित इकाइयों की स्थापना करने की आवश्यकता है, जो न केवल बाद के संवितरण के लिए गतिशील मूल्यांकन को सक्षम करेगी बल्कि यह भी सुनिश्चित करेगी कि वित्त और परियोजनाओं में ठोस प्रगति परस्परानुरूप है। इसके अलावा, अनुपयुक्त आस्तियों के परिसमापन और समाधान से निपटने के लिए आवश्यक तंत्र स्थापित किए जाने चाहिए और इस दिशा में आंतरिक रूप से पर्याप्त विशेषज्ञता का निर्माण किया जाना चाहिए।

अच्छी प्रथा के रूप में स्थायी वित्त

जलवायु जोखिमों के महत्व और आवश्यक न्यूनीकरण पर जोर देने के लिए, इससे अधिक प्रासंगिक समय नहीं हो सकता है। हम उन जोखिमों के गवाह हैं जो प्रत्यक्ष सामने हैं और अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित कर रहे हैं। ईएमडीई और विशेषकर भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती जलवायु परिवर्तन के मुद्दों से निपटने और एक स्थायी आर्थिक प्रणाली के निर्माण के लिए प्रौद्योगिकियों के विकास और आवश्यक आधारभूत संरचना के लिए पर्याप्त वित्तपोषण उपलब्ध कराना है। प्रौद्योगिकी और आधारभूत संरचना जलवायु परिवर्तन के खिलाफ अभियान चलाने और भविष्य में सतत विकास को बढ़ावा देने का आधार होगा। लो-कार्बन क्लाइमेट रेजिलिएंट (एलसीसीआर) आधारभूत संरचना आगे की राह है और दुनिया जलवायु संबंधी जोखिमों से निपटने के मामले में इसकी प्रतीक्षा कर रही है।

[7] स्रोत: ईएसी-पीएम वर्किंग पेपर श्रृंखला (ईएसी-पीएम-डब्ल्यूपी/08/2022) एनएबीएफआईडी – ए व्हेईकल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग: चुनौतियां और अवसर।

एनएबीएफआईडी जैसे विशिष्ट वित्तपोषण संस्थान इन परियोजनाओं के लिए सार्वजनिक और निजी धन के निवेश की सुविधा प्रदान करके अर्थव्यवस्था में जलवायु वित्त[8] और एलसीसीआर आधारभूत संरचना के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। विशेष रूप से, ये संस्थान रियायती और गैर-रियायती ऋण, इक्विटी निवेश, जलवायु-विशिष्ट निधि, सार्वजनिक-निजी भागीदारी, जोखिम-साझाकरण साधन, विशिष्ट अनुदान और सहायता तथा तकनीकी सहायता के माध्यम से पूंजी तक पहुंच प्रदान कर सकते हैं।

आधारभूत संरचना परियोजनाओं के पूरे कार्यकाल में प्रौद्योगिकी-सक्षम पारितंत्र का समर्थन करने की आवश्यकता को देखते हुए, विशिष्ट विशेषज्ञता विकसित करने और देश में स्थायी वित्त के पारितंत्र को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करने की भी आवश्यकता है। यह विशेष रूप से एलसीसीआर विकास को मुख्यधारा में लाने की दिशा में काम कर सकता है और देश को अपने प्रसार लक्ष्यों को पूरा करने में सक्षम बना सकता है। यह सहजीवी आधारभूत संरचना के विकास में भी सहायता कर सकता है जिसका जलवायु परिवर्तन को कम करने पर लाभकारी प्रभाव पड़ता है।

विकासात्मक भूमिका

मैं नए युग के डीएफआई के रूप में एनएबीएफआईडी की विकासात्मक भूमिका पर थोड़ा प्रकाश डालना चाहूँगा। अपने वित्तीय उद्देश्यों के अलावा, एनएबीएफआईडी कई महत्वपूर्ण विकासात्मक उद्देश्यों जैसे बांड बाजार विकास और बुनियादी परियोजनाओं के लिए तकनीकी सहायता/परामर्श सेवाओं के प्रावधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। यह बाजार निर्माता बनने और निवेशकों को पर्याप्त चलनिधि प्रदान करने का प्रयास कर सकता है। इसके अलावा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि पेंशन और बीमा फंड जैसे दीर्घकालिक निधियों के संरक्षकों को अपनी दीर्घकालिक देयताओं से मेल खाने के लिए इन्फ्रा-सेक्टर को ऋण देने में सुविधा मिलती है, यह रेटिंग अपग्रेड के माध्यम से आंशिक क्रेडिट वृद्धि प्रदान करने या फ़र्स्ट लॉस डिफ़ॉल्ट गारंटी प्रदान करने जैसे अभिनव समाधान पेश करने के बारे में सोच सकता है। यह बड़े ऋणों के लिए ऋण समूहन की सुविधा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है और क्रेडिट बाजारों के विकास में एसएलएमए का समर्थन करने में भी अग्रणी भूमिका अदा कर सकता है। जैसा कि एनएबीएफआईडी क्रेडिट मूल्यांकन के लिए अपना आंतरिक रेटिंग मॉडल विकसित करता है, यह बांड बाजार में अदला-बदली (सीडीएस) जैसे उत्पादों की पेशकश करने में भी सक्षम हो सकता है जो बॉन्ड मार्केट स्पेस में विश्वास लाने में काफी मदद करेगा।

निष्कर्ष

जैसे-जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था बढ़ती जा रही है, यह जरूरी है कि आधारभूत संरचना को इसके गुणक प्रभावों पर विचार करते हुए, क्षमता निर्माण, विकासात्मक परिणाम और सामाजिक कल्याण में आवश्यक ध्यान आकर्षित करने के लिए श्रम और पूंजी जैसे उत्पादन के कारक के रूप में देखा जाए। जैसे की ऐतिहासिक चुनौतियाँ और सबक बोधप्रद है, मुझे लगता है कि एनएबीएफआईडी के पास भारत के आधारभूत संरचना को आकार देने में परिवर्तनकारी भूमिका निभाने का एक अनूठा अवसर है। आगे की यात्रा के लिए वित्तीय विवेक, विकासात्मक प्रभाव और दीर्घकालिक दृष्टि के बीच एक नाजुक संतुलन की आवश्यकता है। नई पीढ़ी के डीएफआई के रूप में, एनएबीएफआईडी को नवोन्मेष को आगे बढ़ाने और यह सुनिश्चित करने में सबसे आगे रहने का प्रयास करना चाहिए कि आधारभूत संरचना विकास समावेशी और टिकाऊ हो। मुझे यकीन है कि आज के सम्मेलन के दौरान उपस्थित प्रतिनिधि इनमें से कुछ मुद्दों पर सार्थक चर्चा करेंगे।

मैं सम्मेलन की सफलता के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं।

धन्यवाद एवं नमस्कार।

[8] यूएनएफसीसी (जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन) जलवायु वित्त को स्थानीय, राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय वित्तपोषण - वित्तपोषण के सार्वजनिक, निजी और वैकल्पिक स्रोतों से लिए गए वित्त के रूप में परिभाषित करता है - जो जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने वाले न्यूनीकरण और अनुकूलन कार्यों का समर्थन करना चाहता है।

*जमा बीमा: बदलते समय के साथ तालमेल बनाए रखना**

श्री एम राजेश्वर राव

उप-गवर्नर स्वामीनाथन जे, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ डिपॉजिट इंश्योरर्स (आईएडीआई) और वैश्विक डिपॉजिट इंश्योरर्स के प्रतिष्ठित प्रतिनिधिगण, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (डीआईसीजीसी) के बोर्ड सदस्य और अधिकारीगण, आरबीआई के अधिकारीगण, देवियो और सज्जनो, आप सभी को नमस्कार। सबसे पहले, मैं जयपुर के खूबसूरत शहर में आयोजित आईएडीआई एशिया-पैसिफिक क्षेत्रीय समिति अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में समापन भाषण देने के लिए मुझे आमंत्रित करने के लिए आईएडीआई और डीआईसीजीसी को धन्यवाद देना चाहता हूँ।

सम्मेलन का विषय 'विकसित होते वित्तीय परिदृश्य को समझना: जमा बीमाकर्ताओं के लिए उभरती चुनौतियां और संकट की तैयारी का महत्व', वर्तमान समय के लिए काफी प्रासंगिक है, क्योंकि वित्तीय सेवाओं में तेजी से नवाचार और डिजिटलीकरण हो रहा है, वैश्विक स्तर पर वित्तीय क्षेत्र का विस्तार हो रहा है, साथ ही वित्तीय सेवा संस्थाओं के बीच बढ़ते अंतर-संपर्क भी दुनिया भर में वित्तीय सेवाओं के परिदृश्य को बदल रहे हैं।

पिछले दो दिनों में, आपने विभिन्न दृष्टिकोणों, विशेषज्ञ अंतर्दृष्टि और उभरती चुनौतियों और जमा बीमाकर्ताओं को प्रभावित करने वाले जोखिमों पर विचारोत्तेजक बहस के साथ समृद्ध पैनल चर्चाएँ की होंगी। चाहे वह केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राओं (सीबीडीसी) का उद्भव हो, टोकनयुक्त जमा, जलवायु परिवर्तन से संबंधित जोखिम या भविष्य की वित्तीय प्रणाली जैसे फ़िन्टरनेट, विकसित और भविष्य के विकास से वैश्विक वित्तीय परिदृश्य को बदलने की संभावना है और बदले में जमा बीमा कार्यप्रणाली को बदल देगा। मुख्य मुद्दा जिस पर हमें विचार करने की आवश्यकता है वह यह है कि हम जमा बीमा कार्य को भविष्य के लिए कैसे तैयार कर सकते हैं। फ़िन्टरनेट, जमा का टोकनीकरण, सीबीडीसी / डिजिटलीकरण आदि जैसी चुनौतियाँ वित्तीय क्षेत्र की गतिविधियों का समर्थन करने के लिए वित्तीय ईकोसिस्टम के लिए उन्नत तकनीकी ढांचे की आवश्यकता को उजागर करती हैं। लेकिन यह किसी भी तरह से जमा बीमाकर्ताओं को जमाकर्ताओं के लिए एक बैकस्टॉप प्रदान करने के अपने मूल अधिदेश से विचलित नहीं करता है ताकि वित्तीय क्षेत्र की संस्थाओं में विश्वास पैदा हो जो वास्तविक क्षेत्र का समर्थन करते हैं और वित्तीय स्थिरता को भी बढ़ावा देते हैं। जैसा कि मैं देखता हूं, हमें इस बात की जांच करने की आवश्यकता पर विचार करना चाहिए कि क्या जमा बीमा का विस्तार ऊर्ध्वाधर रूप से होना चाहिए (अर्थात, प्रस्तावित कवर में वृद्धि होनी चाहिए) या क्षैतिज रूप से (बीमित उत्पादों के माध्यम से कवर की जाने वाली संस्थाओं की प्रकृति में वृद्धि होनी चाहिए) और साथ ही फिनटेक नवाचारों को प्रतिबिंबित करने वाले तीसरे आयाम के साथ इसकी भूमिका का भी पता लगाना चाहिए, जो वित्तीय सेवा क्षेत्र के भीतर जमाकर्ताओं की देनदारियों के तरीके को बदलता है।

इन चुनौतियों के मद्देनजर, मैं इस अवसर पर विशिष्ट मुद्दों पर भारतीय परिप्रेक्ष्य में कुछ विचार साझा करना चाहता हूं, जिनमें बीमा कवरेज की पर्याप्तता, वित्त पोषण, जोखिम आधारित प्रीमियम, डिजिटल उत्पादों का कवरेज, भुगतान की समयबद्धता और संचार रणनीति आदि पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जिन पर हमें सामूहिक रूप से विचार करने और आगे बढ़ने के लिए संभावित समाधानों की तलाश करने की आवश्यकता है।

भारत में जमा बीमा का इतिहास

इन मुद्दों के संदर्भ को स्पष्ट करने के लिए, मैं संक्षेप में भारत में जमा बीमा के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को साझा करना चाहता हूँ। जमा बीमा, जैसा कि हम आज जानते हैं, भारत में 1962 में शुरू किया गया था। उस समय, हम संयुक्त राज्य अमेरिका (जहाँ इसे 1933 में पेश किया गया था) के बाद ऐसी योजना शुरू करने वाले दुनिया के दूसरे देश थे। हमने जमा बीमा निगम (डीआईसी) से शुरुआत की। बाद में 1978 में डीआईसी को एक अन्य इकाई क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (सीजीसीआई) के साथ विलय कर दिया गया, जिससे डीआईसीजीसी का

* 14 अगस्त, 2024 को जयपुर में जमा बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) द्वारा आयोजित आईएडीआई एशिया-पैसिफिक रीजनल कमेटी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस 2024 में उप गवर्नर श्री एम. राजेश्वर राव द्वारा दिया गया समापन भाषण। लता विश्वनाथ, अभिनव पुष्प, अमृता प्रभु और मथियाझगन के द्वारा दिए गए सुझावों का आभार।

निर्माण हुआ। इस विलय का उद्देश्य जमा बीमा और ऋण गारंटी कार्यों को एक साथ लाना था, जिससे एक अधिक सुसंगत और कुशल प्रणाली बनाई जा सके। वित्तीय क्षेत्र के उदारीकरण के परिणामस्वरूप, अप्रैल 2003 में ऋण गारंटी योजना को बंद कर दिया गया था। आज जमा बीमा डीआईसीजीसी का मुख्य कार्य बना हुआ है और नीति का उद्देश्य बैंकों के 'छोटे जमाकर्ताओं' को संभावित बैंक विफलताओं से उत्पन्न होने वाली उनकी बचत के नुकसान के जोखिम से बचाना है। इसका उद्देश्य बैंकिंग प्रणाली में जमाकर्ताओं का विश्वास बढ़ाना और विकास और वृद्धि को गति देने के लिए जमाराशि जुटाने में सुविधा प्रदान करना है। जब 1962 में जमा बीमा योजना शुरू की गई थी, तब 287 बैंक बीमाकृत बैंकों के रूप में पंजीकृत थे, 31 मार्च 2024 के अंत तक यह संख्या बढ़कर 1,997 हो गई है[1]|

बीमा कवरेज की पर्याप्तता

मेरे विचार में एक महत्वपूर्ण मुद्दा ग्राहक जमा के लिए बीमा कवरेज की पर्याप्तता का मुद्दा होगा। आईएडीआई सर्वेक्षण [2] के अनुसार , औसत जमा बीमाकर्ता पात्र जमा के मूल्य का लगभग 41 प्रतिशत कवर करता है। भारत के लिए यह संख्या 43.1 प्रतिशत है जो थोड़ी अधिक है। भारत में, 31 मार्च, 2024 तक बैंकिंग प्रणाली में कुल खातों की संख्या के अनुसार पूरी तरह से संरक्षित खातों की संख्या 97.8 प्रतिशत है, जबकि अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क 80 प्रतिशत है। हालांकि इस समय दायरा और कवरेज संतोषजनक प्रतीत होता है, लेकिन आगे चलकर इसमें चुनौतियां होने की संभावना है।

मैं विस्तार से बताता हूँ। आज हम भारत को सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में से एक मानते हैं और निकट भविष्य में यह स्वस्थ विकास दर जारी रहने की उम्मीद है। एक बढ़ती और औपचारिक अर्थव्यवस्था में स्वाभाविक रूप से प्राथमिक और द्वितीयक बैंक जमा दोनों में तेज वृद्धि देखने को मिल सकती है, जो वांछनीय बीमा आरक्षित निधि आवश्यकता और उपलब्ध आरक्षित निधि के बीच एक खाई पैदा करती है। वर्तमान में, भारत में सीमित कवरेज विकल्प को अपनाया जाता है, जिसमें प्रत्येक बीमित बैंक के प्रति जमाकर्ता ₹5,00,000 की राशि तक सीमित एक समान जमा बीमा कवरेज होता है। बैंक जमा के मूल्य में वृद्धि, आर्थिक विकास दर, मुद्रास्फीति, आय के स्तर में वृद्धि आदि जैसे कई कारकों पर विचार करते हुए, इस सीमा में समय-समय पर ऊपर की ओर संशोधन की आवश्यकता हो सकती है। इसका मतलब है कि जमा बीमाकर्ता को अतिरिक्त फंडिंग के बारे में सावधान रहना होगा और उसे पूरा करने के लिए उपयुक्त विकल्पों पर काम करना होगा।

वित्तपोषण और जोखिम आधारित प्रीमियम

इसके बाद जमा बीमा प्रणाली के वित्तपोषण का मुद्दा सामने आता है और क्या वित्तीय संस्थानों द्वारा भुगतान किया जाने वाला प्रीमियम उनके संबंधित जोखिम प्रोफाइल पर आधारित होना चाहिए। वैश्विक स्तर पर, 96 प्रतिशत [3] से अधिक जमा बीमा प्रणाली, जिसमें भारत में डीआईसीजीसी शामिल है, प्रत्याशित निधियन प्रणालियां हैं जिनमें जमा बीमाकर्ता एक जमा बीमा निधि रखता है, जो मुख्य रूप से बीमित संस्थानों से एकत्र किए गए प्रीमियम द्वारा वित्तपोषित होता है और बैंक की विफलता की स्थिति में जमाकर्ताओं को भुगतान करने के लिए निधि का उपयोग किया जाता है।

जमा बीमाकर्ता सदस्य वित्तीय संस्थानों से या तो एक फ्लैट दर पर या किसी व्यक्तिगत बैंक के जोखिम प्रोफाइल के आधार पर एक विभेदित दर पर प्रीमियम एकत्र करते हैं। हालांकि फ्लैट दर प्रीमियम संरचना का लाभ यह है कि इसे समझना और प्रशासित करना अपेक्षाकृत आसान है, यह उस जोखिम के स्तर पर विचार नहीं करता है जो बैंक जमा बीमा प्रणाली के लिए उत्पन्न करता है और इसे बीमा की अवधारणा के विपरीत माना जा सकता है। विभेदक प्रीमियम प्रणालियों का प्राथमिक उद्देश्य बैंकों को अत्यधिक जोखिम लेने से बचने, नैतिक जोखिम को कम करने और प्रीमियम मूल्यांकन प्रक्रिया में अधिक इक्विटी लाने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, कई

[1] आरबीआई वार्षिक रिपोर्ट 2023-24.

[2] आईएडीआई रिपोर्ट - 2023 बैंकिंग उथल-पुथल और जमा बीमा प्रणाली - संभावित निहितार्थ और उभरते नीतिगत मुद्दे

[3] आईएडीआई रिपोर्ट - 2024 में जमा बीमा - वैश्विक रुझान और प्रमुख मुद्दे - (www.iadi.org).

अधिकार क्षेत्र जोखिम आधारित प्रीमियम (आरबीपी) की ओर बढ़ रहे हैं। आईएडीआई के अनुसार, लगभग 55 प्रतिशत[4] जमा बीमाकर्ता एक विभेदक प्रीमियम प्रणाली का उपयोग करते हैं।

भारत में[5], बैंकिंग क्षेत्र सुधारों पर नरसिम्हम समिति (1998) और भारत में जमा बीमा में सुधारों पर कपूर समिति (आरबीआई, 1999), डीआईसीजीसी द्वारा गठित क्रेडिट जोखिम मॉडल पर समिति (2006), और विभेदक प्रीमियम प्रणाली पर समिति (2015) सहित विभिन्न समितियों ने आरबीपी की सिफारिश की थी, लेकिन उस सिफारिश को अपनाया नहीं जा सका। आईएडीआई कोर सिद्धांत 9 कुछ शर्तों को निर्धारित करता है, जिन्हें सुनिश्चित करने की आवश्यकता है यदि जमा बीमाकर्ता विभेदक प्रीमियम प्रणाली का उपयोग करता है, जैसे यह सुनिश्चित करना कि प्रीमियम की गणना के लिए प्रणाली पारदर्शी है; स्कोरिंग / प्रीमियम श्रेणियां काफी विभेदित हैं; और व्यक्तिगत बैंकों से संबंधित प्रणाली से उत्पन्न रेटिंग और रैंकिंग को गोपनीय रखा जाता है। बीमा के मूल्य निर्धारण में निष्पक्षता के मुद्दे का समाधान करने के लिए आरबीपी की शुरूआत एक स्वाभाविक परिणाम है। हालांकि, यह अत्यंत डेटा संचालित है और बीमित बैंक की रेटिंग और संबंधित बीमा प्रीमियम पर पहुंचने के लिए एक मजबूत मॉडल पर निर्भर करता है जो बदले में एक क्षेत्राधिकार द्वारा अपनाए गए जमा बीमा मॉडल पर निर्भर करता है।

भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में विविधता को देखते हुए, वैश्विक परिचालन वाले अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से लेकर सीमित कम्प्यूटरीकृत परिचालन वाले एकल शाखा मॉडल के रूप में संचालित सहकारी बैंकों तक, डेटा आवश्यकताओं को पूरा करना एक बड़ी चुनौती है। एक दुविधा यह भी है कि आरबीपी की शुरूआत जोखिम भरे संस्थानों को जमाराशि बहिर्वाह के प्रति अधिक संवेदनशील बना सकती है और विफलता की दूरी को कम कर सकती है। हालांकि, हमें यह भी पहचानने की जरूरत है कि बैंकों द्वारा उत्पाद पेशकशों में अधिक नवाचारों के साथ नए जोखिम जो जमा वृद्धि को प्रभावित कर सकते हैं, जमा के लिए उच्च कवरेज की मांग, जोखिम आधारित प्रीमियम जमा बीमाकर्ता के लिए अपने वित्त की मजबूती सुनिश्चित करने और बदले हुए वित्तीय परिवेश में संचालन करने की अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए एक बेहतर विकल्प होगा। इसलिए हमारे लिए जोखिम-आधारित जमा बीमा कवर को अपनाने के विकल्प की सावधानीपूर्वक जांच करना महत्वपूर्ण है।

समाधान के लिए पेबॉक्स प्लस अधिदेश

बीमित जमाराशियों की प्रतिपूर्ति के अलावा, कुछ जमा बीमाकर्ता बैंकों के विलय के मामलों में वित्तीय सहायता भी प्रदान करते हैं। भारत में, डीआईसीजीसी अधिनियम, विनियामक द्वारा विलय की मंजूरी के बाद एक कमजोर बैंक के एक मजबूत बैंक के साथ विलय के मामले में वित्तीय सहायता के संदर्भ में एक सीमित समाधान कार्य प्रदान करता है। जब अधिग्रहण करने वाला बैंक इस देयता को पूरी तरह से पूरा करने में असमर्थ होता है, तो डीआईसीजीसी कवरेज सीमा तक जमाकर्ताओं के दावे में कमी को पूरा करके विलय में सहायता करता है। हाल ही में, डीआईसीजीसी ने एक शहरी सहकारी बैंक (यूसीबी) के दूसरे बैंक के साथ विलय के बाद उसके बीमित जमाराशियों के दावों के संबंध में वित्तीय सहायता प्रदान की। भारत में यूसीबी क्षेत्र के महत्व को देखते हुए, क्योंकि इसमें सीमित साधनों वाले लोगों को वित्तीय समावेशन और ऋण वितरण को चलाने की क्षमता है, इस क्षेत्र में समेकन का समर्थन करने में डीआईसीजीसी की भूमिका एक ऐसा मामला है जिस पर कम से कम लागत सिद्धांतों के तहत अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।

डिजिटल उत्पादों के लिए बीमा कवर

वित्तीय क्षेत्र में तेजी से तकनीकी विकास के परिणामस्वरूप ग्राहकों के लिए विभिन्न नवीन डिजिटल वित्तीय उत्पाद और सेवाएं शुरू हुई हैं। जमा बीमा वाले देश आम तौर पर अपने बाजार संरचना, कानूनी और नियामक ढांचे और इन उत्पादों को व्यापक रूप से अपनाने से जुड़े जोखिमों के आकलन के आधार पर डिजिटल "जमा जैसे" उत्पादों के लिए तीन अलग-अलग दृष्टिकोण अपनाते हैं।[6] जबकि प्रत्यक्ष दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से डिजिटल जमा

[4] आईएडीआई रिपोर्ट - 2023 बैंकिंग उथल-पुथल और जमा बीमा प्रणाली - संभावित निहितार्थ और उभरते नीतिगत मुद्दे

[5] आरबीआई वार्षिक रिपोर्ट - 2020-21 - बॉक्स VI.6.

[6] शोध पत्र - डिजिटल वित्तीय उत्पादों और सेवाओं के लिए जमा बीमा डॉ. एंड्रियास जे. ज़िमरमैन प्रो. डॉ. वाल्टर फ़ार्कस द्वारा, नवंबर 2021, लुकास मेट्ज़गर (esisuisse) द्वारा सितंबर 2022 में संशोधित।

जैसे उत्पादों को बीमाकृत जमा के रूप में परिभाषित करता है, बहिष्करण दृष्टिकोण के तहत, ये खाते स्पष्ट रूप से जमा बीमा प्रणाली द्वारा कवर नहीं किए जाते हैं क्योंकि डिजिटल भुगतान सेवा खातों को भुगतान या स्थानान्तरण करने के लिए अस्थायी मूल्य भंडारण के साधन के रूप में माना जाता है। तीसरा दृष्टिकोण इन उत्पादों को अप्रत्यक्ष रूप से जमा बीमा कवर प्रदान करता है यदि डिजिटल भुगतान सेवा प्रदाताओं द्वारा एकत्र "फ्लोट" को बीमाकृत डिपॉजिटरी संस्थान के साथ पूल किए गए कस्टोडियल खातों में रखा जाता है। तथापि, भारत में, जमाराशि की परिभाषा में जमाकर्ता को दिए गए सभी बकाया राशि को कवर करने के लिए समावेशी स्वरूप है, चाहे वह किसी भी नाम से हो।

वित्तीय क्षेत्र में नवाचारों को आम तौर पर नियामकों द्वारा सुगम बनाया जाता है क्योंकि वे वित्तीय उत्पादों और सेवाओं की पहुंच को आबादी के अब तक बहिष्कृत वर्गों तक बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन नवाचारों ने वित्तीय समावेशन पहलों को भी काफी लाभान्वित किया है। यहां तक कि जब डिजिटल उत्पाद अधिक व्यापक हो जाते हैं, तब भी इस बात पर विचार करने की आवश्यकता होगी कि क्या इस तरह के डिजिटल जमा जैसे उत्पादों का कवरेज भी जमा बीमाकर्ता के लिए एक विकल्प होना चाहिए। अपने विनियमित संस्थाओं में ग्राहक सेवा मानकों की समीक्षा के लिए आरबीआई द्वारा गठित एक समिति ने अपनी हालिया रिपोर्ट में प्रीपेड कार्ड जारीकर्ताओं के वॉलेट में रखे धन को भी जमा बीमा कवर देने की सिफारिश की है। हालांकि डिजिटल उत्पादों को कवर करने के लिए स्पष्ट रूप से कोई “एक आकार सभी के लिए फिट” समाधान नहीं है, हमें एक उपयुक्त दृष्टिकोण चुनने की जरूरत है जो जमा बीमा कार्य के प्राथमिक उद्देश्य के अनुरूप हो।

संयोग से, जलवायु परिवर्तन से संबंधित वित्तीय जोखिमों से जुड़ी अनिश्चितता पहले से कहीं अधिक है और तेजी से सामने आ रही है। जलवायु परिवर्तन उधारकर्ताओं की क्रेडिट गुणवत्ता और पुनर्भुगतान क्षमताओं को प्रभावित करके वित्तीय संस्थानों के डिफ़ॉल्ट जोखिम को बढ़ा सकता है। जमा बीमा पर जलवायु परिवर्तन और उससे संबंधित जोखिमों के प्रभाव को काफी हद तक अनदेखा किया गया है। आईएडीआई सदस्यों के 2022 के सर्वेक्षण [7] ने संकेत दिया कि 60 प्रतिशत जमा बीमाकर्ताओं के पास औपचारिक पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ईएसजी) नीति नहीं है जो मौजूदा कानूनी दायित्वों से परे हो। इसलिए, जमा बीमाकर्ताओं के लिए जोखिमों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का आकलन करना और जलवायु परिवर्तन के तत्वों को शामिल करते हुए एक व्यापक नीति तैयार करना भी सभी अधिकार क्षेत्रों में किए जाने की आवश्यकता हो सकती है।

बीमाकृत जमाराशियों तक त्वरित पहुंच

जमा बीमा प्रणाली का एक प्रमुख कार्य बैंक के परिसमापन की स्थिति में जमाकर्ताओं को उनकी बीमित जमाराशियों तक तुरंत पहुँच प्रदान करना है। भारत में, डीआईसीजीसी अधिनियम को 2021 में संशोधित किया गया था ताकि डीआईसीजीसी को उन बैंकों के जमाकर्ताओं को अंतरिम बीमा भुगतान करने का अधिकार दिया जा सके जो आरबीआई द्वारा लगाए गए सर्व-समावेशी-निर्देशों (जो जमाकर्ताओं को उनकी जमाराशियों तक पहुँचने से रोकते हैं) के अंतर्गत आते हैं, बैंक के परिसमापन की प्रतीक्षा किए बिना। संशोधन से पहले की स्थिति के विपरीत, संकटग्रस्त बैंकों के जमाकर्ताओं को अपनी जमाराशियों के पुनर्भुगतान के लिए लंबी अवधि तक प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है।

पात्र जमाकर्ताओं की सूची समय पर प्रस्तुत करने में देरी, बैंक के पास पूरी जानकारी उपलब्ध न होना और/या इन जमाकर्ताओं के वैकल्पिक बैंक खातों की कमी के कारण दावों का समय पर निपटान चुनौतीपूर्ण हो सकता है, खासकर छोटे सहकारी बैंकों के मामले में। इसलिए, हमें इस प्रक्रिया को और अधिक सुव्यवस्थित बनाने और संकटग्रस्त बैंकों के अधिकारियों पर कम निर्भर बनाने के लिए उठाए जा सकने वाले अन्य कदमों पर विचार करने की आवश्यकता है ताकि पात्र जमाकर्ता कम से कम व्यवधान के साथ अपने धन तक पहुँच सकें।

2023 में अमेरिका और यूरोप के कुछ बैंकों की विफलता और विफलता के निकट पहुंचाना, दुनिया भर के विनियामकों के लिए महत्वपूर्ण क्षण थे। हालाँकि विफलताएँ स्पष्ट रूप से उनके चलनिधि कुप्रबंधन, दोषपूर्ण व्यवसाय मॉडल और जमाकर्ताओं

[7] ईएसजी और जमा बीमा पर आईएडीआई सर्वेक्षण संक्षिप्त: बर्ट वैन रूजबेके और रयान डेफिना द्वारा स्टॉक लेना और आगे देखना।

के विशिष्ट वर्ग पर केंद्रित ध्यान के कारण थीं, लेकिन इसने कई कारकों के संगम से उत्पन्न वित्तीय स्थिरता जोखिम पर बहस को जन्म दिया है, जिसमें बीमा रहित जमा की मात्रा, जमा बीमा कवरेज की पर्याप्तता के साथ-साथ वित्तीय सेवाओं के डिजिटलीकरण की भूमिका और इस प्रकरण में सोशल मीडिया की भूमिका शामिल है। चूंकि जमा राशि की यह दौड़ सोशल मीडिया के माध्यम से सूचना के प्रसार और जमाकर्ताओं द्वारा अभूतपूर्व गति से समन्वित तरीके से जमा राशि की निकासी के कारण शुरू हुई थी, इसलिए इस संकट ने न केवल जमाकर्ताओं के व्यवहार पर सोशल मीडिया के प्रभाव को सामने लाया है, बल्कि बीमा कवरेज जैसे सुरक्षा जाल, जमाकर्ताओं के बदलते व्यवहार के मद्देनजर बीमित संस्थानों द्वारा अपनाई गई चलनिधि जोखिम प्रबंधन नीतियों और प्रभावी समाधान के लिए जमा बीमाकर्ता के पास पर्याप्त संसाधनों की उपलब्धता के महत्व को भी सामने लाया है। इसने बैंक रन के जोखिम को कम करने के लिए कवरेज के दायरे और स्तर की उपयुक्तता का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए बड़ी संख्या में जमा बीमाकर्ताओं और अधिकारियों को प्रेरित किया है।

प्रथम दृष्टया, जमाराशि के लिए पूर्ण बीमा कवर होना जमाकर्ताओं के लिए आदर्श प्रतीत होता है और इससे बैंक से आहरण के लिए भगदड़ से बचने में भी मदद मिलती है। हालांकि, इससे जुड़े नैतिक जोखिम और वित्तीय अव्यवहार्यता को देखते हुए यह एक उप-इष्टतम समाधान होने की संभावना है। साथ ही, हम छोटे जमाकर्ताओं, वरिष्ठ नागरिकों आदि जैसे ग्राहकों के कुछ वर्गों के लिए पूर्ण कवरेज के साथ वैकल्पिक लक्षित बीमा दृष्टिकोण की संभावित आर्थिक व्यवहार्यता की भी जांच कर सकते हैं या ऐसे दृष्टिकोण की संरचनाओं, लागतों और लाभ के सावधानीपूर्वक मूल्यांकन के आधार पर छोटे जमाकर्ताओं की जमाराशियों को जमा कर सकते हैं।

जन जागरण

जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, चौबीसों घंटे बैंकिंग सेवाओं की उपलब्धता और सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव के कारण जमा राशि की निकासी पहले की तुलना में बहुत तेजी से संभव हो गई है। कभी-कभी, गलत सूचना भी जमाकर्ताओं की उन्मादी प्रतिक्रिया का कारण बन सकती है। इसलिए, गलत सूचना के प्रभाव को कम करने के लिए, जमा बीमा के बारे में सार्वजनिक जागरूकता को मजबूत करने की आवश्यकता है। फिर से, हाल ही में आईएडीआई द्वारा प्रायोजित अध्ययन का हवाला देते हुए, यह स्पष्ट है कि जमा बीमा के बारे में सार्वजनिक जागरूकता जमाकर्ताओं की अपने बैंक से भागने की प्रवृत्ति को 67 प्रतिशत[8] तक कम कर सकती है। इसलिए जमा बीमाकर्ताओं को जमा बीमा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए पहल करनी चाहिए, क्योंकि जमा बीमा के बारे में जमाकर्ताओं को शिक्षित करना जमाकर्ताओं की जल्दबाजी और अपनी जमा राशि निकालने की सहज प्रतिक्रिया को सीमित करने में बहुत मददगार हो सकता है, जो अंततः वित्तीय प्रणाली में व्यवधान को कम करने में मदद करता है। विविध ग्राहक आधार की आवश्यकता को पूरा करने वाली सर्वोत्तम संचार रणनीति और उसके प्रभावी कार्यान्वयन की सूक्ष्म खोज की आवश्यकता होगी।

निष्कर्ष

निष्कर्ष के तौर पर, मैं इस तथ्य पर फिर से जोर देना चाहता हूँ कि जमा बीमा और जमा बीमाकर्ता एक स्थिर और भरोसेमंद वित्तीय प्रणाली के आवश्यक घटक हैं। वे न केवल जमाकर्ताओं की सुरक्षा करके जनता का विश्वास बनाए रखने में मदद करते हैं, बल्कि समग्र आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वित्तीय सुरक्षा जाल प्रदान करके, जमा बीमाकर्ता वित्तीय स्थिरता में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। विनियामकों और जमा बीमाकर्ताओं के लिए अपनी नीतियों और विनियमों को फिर से संरेखित करना अनिवार्य हो गया है ताकि बैंक अपनी जोखिम प्रबंधन क्षमताओं, विशेष रूप से चलनिधि जोखिम प्रबंधन को बेहतर ढंग से प्रबंधित और बढ़ा सकें। तेजी से बदलते वित्तीय परिदृश्य में जमा बीमा के क्षेत्र में नई चुनौतियाँ आती रहेंगी, लेकिन हमें इन चुनौतियों को बढ़ने, सीखने और विकसित होने के अवसरों के रूप में देखना चाहिए। बदलते समय के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए बहुत सतर्क और सक्रिय जमा बीमाकर्ता की आवश्यकता होती है।

इसलिए, सतर्क और सक्रिय रहें।

धन्यवाद।

[8] आईएडीआई रिपोर्ट - 2023 बैंकिंग उथल-पुथल और जमा बीमा प्रणाली - संभावित निहितार्थ और उभरते नीतिगत मुद्दे।

*धारणीय कृषि के लिए वित्तपोषण**

श्री स्वामीनाथन जे.

विशिष्ट अतिथिगण, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के उप महानिदेशक डॉ. आर.सी. अग्रवाल; कृषि विश्वविद्यालय, राहुरी के पूर्व अनुसंधान निदेशक डॉ. सुनील गोरंटीवार; सीएबी के प्रधानाचार्य; वित्तीय और शैक्षणिक संस्थानों के वरिष्ठ अधिकारीगण; आरबीआई के सहकर्मीगण; देवियो और सज्जनो। आप सभी को सुप्रभात।

मुझे आज इस अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान सम्मेलन में आप सभी को संबोधित करते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है, इसका विषय है *"खाद्य सुरक्षा और कृषि आय के लिए सतत वित्तपोषण - अवसर, चुनौतियां और भावी मार्ग"*। आरबीआई की स्थापना के 90वें वर्ष के समारोह के अंग के रूप में यह और भी सुखद है।

जलवायु परिवर्तन और धारणीयता, दो ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जिन्होंने वैश्विक स्तर पर ध्यान आकर्षित किया है। हाल के वर्षों में, हमने खराब मौसम की घटनाओं में वृद्धि देखी है, जिसमें प्रचंड सूखा, मूसलाधार वर्षा, बाढ़, भूस्खलन, पीछे की ओर घटती हुई तटरेखा तथा आर्कटिक बर्फ और हिमालय के ग्लेशियरों का खतरनाक रूप से पिघलना शामिल है। दावाग्नि (जंगल की आग) की प्रचंड घटनाएँ बार-बार देखी जाती हैं। विडंबना यह है कि ऐसे संवेदनशील समुदाय जिन्होंने संभवतः जलवायु परिवर्तन में सबसे कम योगदान दिया हो, इसके विनाशकारी प्रभावों का सबसे अधिक खामियाजा भुगत रहे हैं[1]।

इस संदर्भ में, धारणीय कृषि एक महत्वपूर्ण समाधान के रूप में उभरती है। धारणीय कृषि से तात्पर्य ऐसी कृषि पद्धतियों से है, जो आज की खाद्य आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भावी पीढ़ियों के लिए संसाधनों को संरक्षित करती हैं। इसका अर्थ है ऐसे तरीके अपनाना जो पर्यावरण की रक्षा करें, रासायनिक निविष्टियों पर निर्भरता कम करें, जल और भूमि का कुशलतापूर्वक उपयोग करें तथा किसानों के लिए सामाजिक और आर्थिक समानता सुनिश्चित करें।

भविष्य में, सभी कृषि-आधारित अर्थव्यवस्थाओं के लिए कृषि धारणीयता प्राप्त करना एक प्रमुख प्राथमिकता होगी। इसमें पारंपरिक कृषि पद्धतियों को प्रौद्योगिकी-संचालित प्रणालियों में बदलना, कृषि वस्तुओं के प्रसंस्करण और संरक्षण तकनीकों में वृद्धि करना, खेती के स्तर पर मूल्य संवर्धन में योगदान देना शामिल होगा। हमें फसल उत्पादन प्रणालियों को जलवायु-सुदृढ़ कृषि के साथ संरेखित करने की भी आवश्यकता है। साथ ही, इन सभी को बनाए रखने के लिए समय पर पर्याप्त वित्त सुनिश्चित करने की भी आवश्यकता है।

भारतीय कृषि क्षेत्र के समक्ष चुनौतियाँ

भारतीय संदर्भ में, कृषि महज एक आर्थिक गतिविधि नहीं है; यह हमारे देश की खाद्य सुरक्षा और आजीविका का आधार है। यह क्षेत्र हमारी आबादी के एक महत्वपूर्ण हिस्से को रोजगार देता है। इतने वृहत महत्व के बावजूद भी, भारतीय कृषि को कई संरचनात्मक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। मैं इनमें से कुछ चुनौतियों के बारे में संक्षेप में बताना चाहूँगा जो इस क्षेत्र को अपने पूरे सामर्थ्य तक पहुँचने से रोक रही हैं।

कम उत्पादकता

सर्वप्रथम, कई फसल उत्पादक देशों की तुलना में भारत की कृषि उत्पादकता कम है। यह कम उपज - जिसे प्रति इकाई भूमि पर उत्पादित फसल की मात्रा के रूप में मापा जाता है - विभिन्न कारकों के कारण है, जिनमें बीज प्रतिस्थापन[2] की निम्न दर, अप्रभावी उर्वरक उपयोग और उन्नत प्रौद्योगिकियों का सीमित उपयोग शामिल हैं।

लघु एवं सीमांत भूमि जोतों की प्रधानता

दूसरा, लघु और सीमांत भूमि जोतों की अत्यधिक प्रधानता से अपनी अलग चुनौतियां पनपती हैं। यह खंडित भूमि संरचना खेती की व्यवहार्यता को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है।

* 11 सितंबर 2024 को कृषि बैंकिंग महाविद्यालय (सीएबी), पुणे द्वारा आयोजित अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान सम्मेलन में भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर श्री स्वामीनाथन जे. का मुख्य भाषण।

[1] जलवायु परिवर्तन 2023, संश्लेषण रिपोर्ट, जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल (आईपीसीसी)।

[2] बीज प्रतिस्थापन दर, खेत में संरक्षित बीज के अलावा प्रमाणित/गुणवत्तापूर्ण बीजों का उपयोग करके मौसम में बोई गई फसल के कुल क्षेत्रफल में से बोए गए क्षेत्रफल का प्रतिशत है।

विपणन-योग्य कम उपज अधिशेष और धारण क्षमता के साथ, छोटे किसानों की सौदेबाजी की शक्ति अक्सर सीमित होती है, उन्हें लेनदेन की उच्च लागतों का सामना करना पड़ता है, और अपनी उपज के विपणन के लिए संघर्ष करना पड़ता है। ये कारक नई प्रौद्योगिकियों में निवेश करने या उत्पादकता में सुधार लाने की उनकी क्षमता में बाधा डालते हैं।

मानसून/वर्षा पर निर्भरता

तीसरा, भारत की वर्षा-आधारित कृषि पर अत्यधिक निर्भरता एक और गंभीर चुनौती है। देश की लगभग 45 प्रतिशत कृषि संबंधी भूमि वर्षा पर निर्भर है, जिससे किसान मानसून की अप्रत्याशित प्रकृति के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हो जाते हैं। वर्षा-आधारित खेती पर इस अत्यधिक निर्भरता के कारण कृषि उत्पादन में असंतुलन होता है, जिससे किसानों को गंभीर जोखिमों का सामना करना पड़ता है। असल चुनौती, सिंचाई कवरेज का विस्तार करते हुए मौजूदा जल संसाधनों के उपयोग को अनुकूलित करने में निहित है। अधिक पूर्वानुमानित और स्थिर कृषि उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी जल प्रबंधन, सिंचाई अवसंरचना और जलवायु-सुदृढ़ कृषि पद्धतियों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होगी।

अपर्याप्त कृषि प्रसंस्करण क्षमता

कृषि के विकास में सीमित प्रसंस्करण, अवसंरचना में महत्वपूर्ण बाधा के रूप में चौथा कारण है। पर्याप्त प्रसंस्करण और संरक्षण सुविधाओं के बिना कृषि उपज का एक बड़ा हिस्सा कटाई के बाद नष्ट हो जाता है, जिससे समग्र आपूर्ति और किसानों की आय कम हो जाती है। निम्न मूल्य संवर्धन का मतलब है कि किसानों को अक्सर उनके कच्चे उत्पाद के लिए कम कीमत मिलती है, जिससे वे प्रसंस्कृत वस्तुओं से होने वाली संभावित आय से वंचित रह जाते हैं। इसके अतिरिक्त, प्रसंस्करण क्षमताओं की कमी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय, दोनों बाजारों तक पहुँच को बाधित करती है, निर्यात के अवसरों को सीमित करती है और वैश्विक स्तर पर भारतीय कृषि उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मकता को कम करती है।

कृषि मशीनीकरण का निम्न स्तर

पाँचवाँ, भारत में कृषि उत्पादकता बढ़ाने में कृषि मशीनीकरण का निम्न स्तर एक महत्वपूर्ण बाधा है। खेती के व्यस्ततम मौसम के दौरान मज़दूरों की कमी के साथ-साथ अधिक मज़दूरी की मांग इस समस्या को और बढ़ा देती है, जिससे किसानों के लिए अधिकतम उत्पादन बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। इसके अतिरिक्त, भारतीय कृषि को जनसांख्यिकीय चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, जहाँ किसानों की औसत आयु अब 50.1 वर्ष है, जो इस क्षेत्र में युवा पीढ़ी को आकर्षित करने की आवश्यकता को रेखांकित करता है। आधुनिक कृषि तकनीकें और बढ़ा हुआ मशीनीकरण न केवल उत्पादकता को बढ़ाएंगे बल्कि महिला सशक्तीकरण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। पारंपरिक खेती की शारीरिक/भौतिक माँगों को कम करके, मशीनीकरण और कृषि-प्रसंस्करण महिलाओं के लिए नए अवसर खोल सकते हैं, जिससे वे कृषि उत्पादकता और व्यापक ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर अधिक प्रभाव डाल सकेंगी।

कृषि और जलवायु परिवर्तन

जब हम भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों पर विचार करते हैं, तो जलवायु परिवर्तन का सबसे अधिक भार कृषि क्षेत्र पर देखने को मिलता है। आज कृषि, 21वीं सदी की तीन सबसे बड़ी चुनौतियों के संगम पर है – यथा खाद्य और पोषण सुरक्षा को बनाए रखना, जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूलन और न्यूनीकरण तथा जल, ऊर्जा और भूमि जैसे महत्वपूर्ण संसाधनों का सतत उपयोग।

जलवायु परिवर्तन पहले से ही पारंपरिक कृषि पद्धतियों को नया रूप दे रहा है और आज हमारे भोजन विकल्पों को भी प्रभावित कर रहा है। उदाहरण के लिए, दक्षिण कोरिया की प्रसिद्ध *किमची,* जो पारंपरिक रूप से ठंडे पहाड़ी क्षेत्रों में उगाई जाने वाली नापा गोभी से बनाई जाती है, खतरे में है क्योंकि बढ़ते तापमान से गोभी की फसल खराब हो जाती है। इसी तरह, फ्रांसीसी वाइन निर्माता बढ़ती गर्मी के कारण *मेरलो (वाइन)* के भविष्य को लेकर चिंतित हैं, और अमेरिका के पूर्वी तट से झींगा मछलियों की आबादी शीतल जल-प्रवाहों की ओर रुख कर रही है, जिससे स्थानीय उद्योग प्रभावित हो रहे हैं। इसका प्रभाव दूरगामी है, जो खेती और खाद्य उद्योग के लिए हरित पद्धतियों को अपनाने और जलवायु परिवर्तन के न्यूनीकरण में योगदान देने की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करता है[3]।

[3] एडिट, टी. (6 सितंबर 2024)। किम्ची बाइट्स। टाइम्स ऑफ इंडिया ब्लॉग। https://timesofindia.indiatimes.com/blogs/toi-editorials/kimchi-bites/(अंतिम बार 8 सितंबर 2024 को एक्सेस किया गया)।

धारणीय कृषि के लिए वित्तपोषण

जबकि धारणीय कृषि पद्धतियाँ आवश्यक हैं, उन्हें लागू करना अक्सर पारंपरिक तरीकों की तुलना में अधिक महंगा पड़ता है। जैविक खेती, जलवायु-सुदृढ़ प्रौद्योगिकी और आधुनिक सिंचाई प्रणाली जैसी धारणीय प्रथाएँ शुरू में महंगी लग सकती हैं, लेकिन वे उत्पादकता, सुदृढ़ता और पर्यावरण संरक्षण में सुधार ला कर दीर्घकालिक लाभ प्रदान करती हैं। सुलभ और किफायती वित्तपोषण विकल्पों के बिना, धारणीय कृषि पद्धतियों में अतिआवश्यक बदलाव कई लोगों के लिए सुहावना स्वप्न ही बना रहेगा।

कई किसान, खास तौर पर ग्रामीण या अल्प-सेवित क्षेत्रों में रहने वाले कृषक आर्थिक, संस्थागत और सामाजिक बाधाओं से जूझते हैं, जो उनकी पहुँच को सीमित करते हैं। इसलिए, धारणीय वित्त को न केवल पर्यावरण-अनुकूल प्रथाओं को बढ़ावा देना चाहिए, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि वित्तीय संसाधन उन किसानों को उपलब्ध हों जिन्हें उनकी सबसे अधिक आवश्यकता है, जिससे उन्हें साधन, प्रौद्योगिकी और ज्ञान तक समान पहुँच मिल सके।

कृषि के लिए संस्थागत ऋण वर्ष 2023-24[4] के दौरान ₹25.10 लाख करोड़ के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया, जो कृषि विकास को गति देने में वित्तपोषण के महत्व को दर्शाता है। लगभग 7.4 करोड़ सक्रिय किसान क्रेडिट कार्ड[5] समय पर और लचीले ऋण प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण साधन के रूप में उभरे हैं, विशेषकर अल्पकालिक आवश्यकताओं के लिए। हालांकि, ऋण तक पहुंच के लिए क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने की स्थिति अभी भी संकटपूर्ण है। अगर हम यह सुनिश्चित कर सकें कि सभी किसानों, चाहे वे किसी भी क्षेत्र से हों, को समय पर पर्याप्त वित्तपोषण मिल सके, तो हम कृषि में स्थिरता और सुदृढ़ता की चुनौतियों का समाधान करने के लिए बेहतर स्थिति में होंगे।

कृषि क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने में उधार देने की पारंपरिक ऋण प्रथाओं की कतिपय सीमाएँ हैं। कृषि संबंधी गतिविधियां स्वाभाविक रूप से मौसमी है, और उपज अक्सर देरी से या कम होती है। किसानों की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप और लचीले अभिनव वित्तीय समाधानों की आवश्यकता है। इससे मौसम संबंधी जोखिमों को कवर करने वाले फसल बीमा उत्पादों के साथ मिलकर, किसानों के सामने आने वाली अनिश्चितताओं को कम करने में मदद मिल सकती है। इसके अतिरिक्त, मिश्रित वित्त मॉडल - जहाँ सार्वजनिक निधियों का उपयोग निजी निवेशों को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है - स्थायी बदलावों के लिए आवश्यक पूंजी प्रदान करने में सहायक हो सकता है। इससे न केवल कई स्रोतों से संसाधन जुटाए जाएँगे बल्कि जोखिम और रिटर्न को अधिक समान रूप से वितरित किया जा सकेगा।

इस संदर्भ में, मैं पांच समाधानों पर प्रकाश डालना चाहूंगा जो धारणीय कृषि के वित्तपोषण के मुद्दे को सुलझाने में काफी मददगार हो सकते हैं।

सामूहिक संगठनों की भूमिका

कृषक उत्पादक संगठन या एफपीओ, लघु और सीमांत किसानों के समक्ष आने वाली विशिष्ट चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक महत्वपूर्ण तंत्र के रूप में उभरे हैं। 31 मार्च 2023 तक 24,000 से अधिक किसान उत्पादक कंपनियों (एफपीसी) के गठन के साथ उनकी वृद्धि उल्लेखनीय रही है[6]।

ये संगठन अनुसंधान संस्थाओं द्वारा विकसित धारणीय कृषि प्रौद्योगिकियों को अपनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किसानों को एकत्रित करके एफपीओ उनकी सौदेबाजी की शक्ति वर्धित करते हैं और साथ ही प्रौद्योगिकी तक उनकी पहुँच में सुधार लाते हैं और बाज़ार में उनकी उपज के लिए अवसर बढ़ाते हैं।

इन संगठनों के लिए वित्तपोषण का समर्थन करने हेतु, आरबीआई के विनियमों में प्रावधान है कि कृषि और संबद्ध गतिविधियों में संलग्न एफपीओ के लिए प्रति इकाई ₹2 करोड़ की कुल सीमा तक के ऋण प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार के रूप में योग्य हैं। यदि एफपीओ पूर्व-निर्धारित कीमतों पर अपनी उपज के सुनिश्चित विपणन के साथ खेती में संलग्न हैं, तो ₹5 करोड़ तक के ऋण पीएसएल के रूप में योग्य हैं।

[4] नाबार्ड वार्षिक रिपोर्ट – 2023-24; पीपी80।

[5] नाबार्ड वार्षिक रिपोर्ट – 2023-24; पीपी10।

[6] एनएएफपीओ, 2023। भारत में कृषक उत्पादक संगठन: क्षेत्र की स्थिति रिपोर्ट। राष्ट्रीय कृषक उत्पादक संगठन, नई दिल्ली।

मूल्य श्रृंखला वित्तपोषण

मूल्य श्रृंखला वित्तपोषण मॉडल विभिन्न हितधारकों - किसानों, एग्रीगेटर्स, व्यापारियों, प्रसंस्करणकर्ताओं और वित्तीय संस्थाओं को एक समन्वित प्रणाली में एकीकृत करता है जो कृषि प्रक्रिया की दक्षता में सुधार लाता है। ब्रांडेड, अच्छी तरह से पैक किए गए, सुरक्षित और स्वस्थ भोजन के प्रति उपभोक्ता की बदलती प्राथमिकताओं के साथ, संरचित कृषि मूल्य श्रृंखलाओं और उनके वित्तपोषण पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। वित्तीय संस्थाओं के लिए मूल्य श्रृंखला में विभिन्न भागीदारों तक पहुँच, कारोबार संबंधी अतिरिक्त अवसर प्रदान करती है।

गोदाम वित्तपोषण

भारत में कृषि संबंधी मूल्य में उतार-चढ़ाव एक आवर्ती चुनौती है, जो प्रायः किसानों को फसल पकने के दौरान तत्काल वित्तीय आवश्यकताओं के कारण कम कीमतों पर अपनी उपज बेचने के लिए मजबूर करती है। वेयरहाउस रसीद वित्तपोषण के माध्यम से किसान अपने उत्पाद को गोदामों में संग्रहीत करते हैं, और जब तक कि बाजार मूल्य अनुकूल न हो जाएं, तब तक बिक्री नहीं करते हैं। इस प्रतीक्षा अवधि के दौरान, किसान बैंकों से पण्य वित्तपोषण के माध्यम से अति-आवश्यक निधियाँ प्राप्त कर सकते हैं। वित्तपोषण का यह रूप कृषि वस्तुओं की कीमतों को स्थिर करने में सहायता करता है, किसानों को विपणन जोखिमों का प्रबंधन करने में मदद करता है, और वहीं बैंकों को विविधतापूर्ण वित्तपोषण के अवसर प्रदान करता है। हालांकि, इस तरह के कारोबार के फलने-फूलने के लिए, देश को और भी सुदृढ़ तृतीय-पक्ष वेयरहाउसिंग एजेंसियों की आवश्यकता है।

प्रौद्योगिकी अंगीकरण के लिए वित्तपोषण

कृषि में प्रौद्योगिकी अपनाने से उत्पादकता और स्थिरता को बढ़ावा मिलने की अपार संभावनाएं हैं। सिंचाई अवसंरचना के विस्तार, सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों को बढ़ावा देने और कृषि मशीनीकरण को प्रोत्साहित करने से कृषि आय में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है और दक्षता में सुधार आ सकता है। वर्तमान में, भारत में सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत केवल 12.54 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र है, यानी शुद्ध बोए गए क्षेत्र का लगभग 9 प्रतिशत[7], जो विस्तार की बड़ी संभावना को दर्शाता है। "प्रति बूंद अधिक फसल" जैसी केंद्र प्रायोजित योजनाओं के साथ अभिसरण, सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली स्थापित करने के लिए संस्थागत ऋण के प्रवाह को बढ़ा सकता है।

संरक्षित खेती, जो प्रति इकाई क्षेत्र में फसल की पैदावार को 5 से 8 गुना तक बढ़ा सकती है, यह जल पर 50 प्रतिशत तथा उर्वरकों और कीटनाशकों पर 25 प्रतिशत की बचत जैसे पर्याप्त लाभ भी प्रदान करती है। संरक्षित खेती के अंतर्गत केवल 3 लाख हेक्टेयर भूमि होने के कारण, आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके इस प्रथा को विस्तारित करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है जो जलवायु परिस्थितियों के बावजूद पूरे वर्ष के दौरान अधिक मूल्य वाली फसलों की खेती को सक्षम बनाता है।

सरकारी योजनाओं के साथ अभिसरण के माध्यम से पूंजी निर्माण

भारत सरकार पूंजी सब्सिडी योजनाओं और ब्याज सहायता के माध्यम से निवेश को बढ़ावा देकर कृषि में पूंजी निर्माण को बढ़ावा दे रही है। कृषि-अवसंरचना कोष (₹1 लाख करोड़), सौर पंपों के लिए पीएम-कुसुम, कृषि यंत्रीकरण पर उप-मिशन (एसएमएएम) और बागवानी के एकीकृत विकास मिशन (एमआईडीएच) जैसी योजनाओं के साथ संस्थागत ऋण का समर्थन करता है। कृषि विपणन अवसंरचना (एएमआई) जैसी अन्य पहलें तथा प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना (पीएमएफएमई), पशुपालन अवसंरचना विकास कोष (एएचआईडीएफ) और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जैसे कार्यक्रम कृषि विकास को और बढ़ाते हैं। इन योजनाओं के साथ संस्थागत ऋण को जोड़ने से आधुनिक प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने और कृषि पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ बनाने में मदद मिलेगी।

प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना

प्रौद्योगिकी और डेटा-संचालित अंतर्दृष्टि वित्तपोषण मॉडल को बेहतर बना सकती है। वित्तीय संस्थानों को ऋण तक पहुँच में सुधार करने और जोखिमों को कम करने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना चाहिए। फसल की पैदावार, मौसम के पैटर्न और मिट्टी के स्वास्थ्य को ट्रैक करने वाले डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के साथ सहयोग, वास्तविक समय का डेटा प्रदान कर सकता है जिसका उपयोग वित्तीय संस्थाएं जोखिम का अधिक सटीक आकलन लगाने के लिए कर सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म उनके पर्यावरणीय प्रभाव को कम करते हुए, किसानों को अधिक सूचित निर्णय लेने और उत्पादकता बढ़ाने में मदद कर सकते हैं।

[7] कृषि सांख्यिकी एक दृष्टि में, 2022।

आरबीआई ने सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करते हुए नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नीतिगत पहलों के अलावा डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना को सुविधाजनक बनाने और संस्थागत व्यवस्था बनाने के लिए कई पहलें की हैं। पिछले वर्ष, आरबीआई ने आरबीआई नवोन्मेष केंद्र (इनोवेशन हब) के माध्यम से पब्लिक टेक प्लेटफ़ॉर्म पहल की घोषणा की, जिसका उद्देश्य ऋणदाताओं को डिजिटल जानकारी के निर्बाध प्रवाह को सक्षम करके निर्बाध ऋण प्रदान करना था। यह खुला, प्लग-एंड-प्ले डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म, जिसे अब यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफ़ेस नाम दिया गया है, वित्तीय क्षेत्र के भागीदारों को आसानी से कनेक्ट करने देता है। हाल ही में, नाबार्ड ने आरबीआई इनोवेशन हब के साथ मिलकर ई-केसीसी लोन ऑरिजिनेटर सिस्टम को प्लेटफ़ॉर्म में एकीकृत किया, जिससे कृषि ऋणों के लिए निस्तारण समय हफ्तों से मिनटों में तब्दील हो गया।

भावी मार्ग

निष्कर्ष में, चुनौतियाँ बहुत-सी हैं, लेकिन अवसर भी उतने ही अधिक हैं। आगे चल कर दो महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान दिया जाना चाहिए: धारणीय कृषि को बढ़ावा देना और इसके लिए पर्याप्त वित्तपोषण सुनिश्चित करना। संस्थागत ऋण में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, लेकिन क्षेत्रीय असमानताएँ बनी हुई हैं। मूल्य श्रृंखला वित्तपोषण और गोदाम वित्तपोषण संभाव्यतायुक्त समाधान प्रदान करते हैं, जबकि कृषि अवसंरचना कोष, पीएमएफएमई और एएचआईडीएफ जैसी सरकारी पहलें, कृषि विकास को बढ़ावा देने में मदद कर रही हैं। भारतीय कृषि के लिए एक अधिक धारणीय और सुदृढ़ भविष्य हेतु क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने, ऋण तक पहुँच को और बढ़ाने और मूल्य श्रृंखला वित्तपोषण को एकीकृत करने पर मजबूती से ध्यान केंद्रित करना महत्वपूर्ण है।

मुझे आशा है कि यह सम्मेलन शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं और वित्तीय संस्थाओं के प्रतिनिधियों को भारतीय कृषि क्षेत्र के सामने आने वाले विभिन्न मुद्दों पर गहनतापूर्वक विचार करने, जलवायु परिवर्तन की बढ़ती चुनौतियों की पृष्ठभूमि में इसका विश्लेषण करने तथा वैकल्पिक समाधान, दृष्टिकोण और नीति सुझाव देने का एक मूल्यवान अवसर प्रदान करेगा।

इसके साथ ही, मैं अगले दो दिनों में उपयोगी आदान-प्रदान के लिए अपनी शुभकामनाएं देना चाहता हूं ताकि ऐसे समाधान तलाशे जा सकें जो धारणीय कृषि और इसके वित्तपोषण के भविष्य को आकार दे सकें।

धन्यवाद।

*वित्तीय परिदृश्य में परिवर्तन: आर्थिक स्थिरता के लिए समुत्थानशीलता का निर्माण**

श्री स्वामीनाथन जे.

श्री वी अनंथा नागेश्वरन, मुख्य आर्थिक सलाहकार, सुश्री शेरीन भान, प्रबंध संपादक, सीएनबीसी टीवी 18, सुश्री लता वेंकटेश, कार्यकारी संपादक सीएनबीसी टीवी 18, बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, फिनटेक उद्योग के अग्रणी, विशिष्ट अतिथिगण, देवियो और सज्जनों। आप सभी को नमस्कार।

मुझे आज यहां आपके बीच उपस्थित होकर बहुत प्रसन्नता हो रही है, ताकि मैं आपको उभरते बैंकिंग परिदृश्य के बारे में बता सकूं तथा यदि भारत को 2047 तक विकसित अर्थव्यवस्था बनने की अपनी आकांक्षाओं को प्राप्त करना है, तो वित्तीय क्षेत्र में समुत्थानशीलता के निर्माण और उसे बनाए रखने की अनिवार्य आवश्यकता के बारे में बता सकूं।

आर्थिक संवृद्धि के लिए वित्तीय स्थिरता का महत्व

भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्था में जहां निजी पूंजी स्रोत सीमित हैं, वहां बैंकिंग प्रणाली द्वारा संचालित वित्तपोषण मॉडल ही पूंजीगत व्यय को बढ़ावा देता है। इसलिए, वित्तीय संस्थानों को भारत की आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी ढांचे, उद्योग और नवोन्मेष में महत्वपूर्ण निवेश का समर्थन करने के लिए एक मजबूत वित्तीय स्थिति और मजबूत बैलेंस शीट बनाए रखना चाहिए।

कॉरपोरेट और वित्तीय संस्थाएँ, दोनों की वित्तीय सेहत दशकों में सबसे मजबूत स्तर पर है। हालांकि, इस वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए, सेक्टर को मजबूत कॉर्पोरेट सुदृढ़ता के साथ-साथ वित्तीय और परिचालन लचीलेपन को प्राथमिकता देनी चाहिए। इसके अलावा, बैंकों और वित्तीय संस्थानों को अपने आंतरिक सुरक्षा तंत्रों को मजबूत करने की जरूरत है, अर्थात् उनके आश्वासन कार्य, अनुपालन और निष्पक्षता की संस्कृति विकसित करना ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे हर समय विनियामकों और सबसे महत्वपूर्ण रूप से अपने ग्राहकों का भरोसा बनाए रखें।

* भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर, श्री स्वामीनाथन जे. का मुख्य भाषण - 30 अगस्त 2024 - मुंबई में सीएनबीसी टीवी 18 द्वारा आयोजित 'बैंकिंग परिवर्तन शिखर सम्मेलन - सीजन 2' में।

विनियामक एक परिचालक है।

वित्तीय प्रणाली की स्थिरता सुनिश्चित करने और उसे बनाए रखने की दिशा में, रिज़र्व बैंक कई निर्णायक कदम उठा रहा है। आज, मैं आप सभी को रिज़र्व बैंक द्वारा उठाए गए ऐसे ही कुछ कदमों के बारे में बताना चाहूँगा।

विनियमनों के प्रति परामर्शात्मक दृष्टिकोण

वैश्विक स्तर पर, और विशेष रूप से भारत में, विनियामक दृष्टिकोण अधिक परामर्शात्मक हो गए हैं, जिसमें संतुलित और प्रभावी विनियमन विकसित करने के लिए हितधारकों की प्रतिक्रिया को शामिल किया गया है। 2021 में विनियमन समीक्षा प्राधिकरण 2.0[1] की स्थापना विनियामकीय निर्देशों को सुव्यवस्थित करने, अनुपालन बोझ को कम करने और अप्रचलित आवश्यकताओं को समाप्त करने के लिए आरबीआई की प्रतिबद्धता का प्रमाण है, जिससे अधिक कुशल विनियामक वातावरण को बढ़ावा मिलता है।

उद्योग का प्रतिनिधित्व करने वाले सलाहकार समूह के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के बाद, मैं व्यक्तिगत रूप से उद्योग की चिंताओं के प्रति विनियामक की प्रतिक्रियाशीलता और संवेदनशीलता की पुष्टि कर सकता हूं।

आरआरए 2.0 की विभिन्न सिफारिशों के कार्यान्वयन के साथ-साथ रिज़र्व बैंक के भीतर कई अंतर-विभागीय समूहों के अथक प्रयासों के परिणामस्वरूप पहले से ही कई सुसंगत, समेकित और अद्यतन मास्टर निदेश जारी किए गए हैं और साथ ही 1,000 से अधिक परिपत्रों को वापस लिया गया है, साथ ही कई विनियामक और पर्यवेक्षी विवरणियों को समाप्त किया गया है जो अनावश्यक हो गए थे। इन उपायों ने विनियमित संस्थाओं पर अनुपालन बोझ को काफी कम कर दिया है।

[1] इससे पहले, भारतीय रिज़र्व बैंक ने 1 अप्रैल 1999 से एक वर्ष की अवधि के लिए विनियमन समीक्षा प्राधिकरण (आरआरए) की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य जनता, बैंकों और वित्तीय संस्थानों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर विनियमों, परिपत्रों, रिपोर्टिंग प्रणालियों की समीक्षा करना था। आरआरए 2.0 की स्थापना 1 मई 2021 में की गई और इसने जून 2022 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

बेहतर अभिशासन सुनिश्चित करने की दिशा में

इतिहास में भारत और विदेश दोनों जगह ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं कि कैसे सफल दिखने वाले कारोबारी उद्यम खराब अभिशासन और अत्यधिक लालच के कारण जल्दी ही बंद हो गए। इसलिए, रिज़र्व बैंक ने जागरूकता पैदा करने के साथ-साथ अच्छे कॉर्पोरेट अभिशासन प्रथाओं का पालन सुनिश्चित करने के लिए इसे अपने फोकस क्षेत्रों में से एक के रूप में लिया है। हम विनियमित संस्थाओं के बोर्ड और शीर्ष प्रबंधन के साथ-साथ स्व-नियामक संगठनों के साथ अधिक लगातार और सीधे संपर्क में हैं। इन संवादों के माध्यम से, हम अपनी चिंताओं और प्राथमिकताओं को साझा करते हैं, और उद्योग के सामने आने वाली चुनौतियों को समझने का भी प्रयास करते हैं ताकि उचित नियामक उपाय किए जा सकें।

अनुपालन की संस्कृति को बढ़ावा देना

वित्तीय संस्थाओं की दीर्घायु को बनाए रखने के लिए एक आवश्यक तत्व यह है कि संस्था में अनुपालन की संस्कृति बनी रहे। आश्वासन कार्यों के प्रमुखों के साथ-साथ सीएफओ और लेखा परीक्षकों के साथ हाल ही में किया गया सीधा जुड़ाव हमारे वित्तीय संस्थानों के भीतर आंतरिक सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए रिज़र्व बैंक के प्रयासों का प्रमाण है। आश्वासन कार्यकर्ताओं की स्वतंत्रता और पेशेवर आचरण, बोर्ड और शीर्ष प्रबंधन द्वारा दृढ़ता से समर्थित, इस संस्कृति को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। मुझे आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि इन पहलों को बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिली है और मैं अपने वित्तीय संस्थानों के प्रमुखों को उनके संगठनों में इन पहलों को प्राथमिकता देने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ।

उद्योग चक्रीय है, यह विवेकपूर्ण और निर्णायक कार्रवाई के लिए सबसे अच्छा समय है।

वित्तीय उद्योग, किसी भी अन्य क्षेत्र की तरह, चक्रों का अनुभव करता है, और यह वर्तमान में उफान पर है। इसलिए, यह हमारे संस्थानों को मजबूत करने, उनके वित्तीय और परिचालनगत सुदृढ़ता को बढ़ाने और हमारी वित्तीय प्रणाली की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने का सही समय है। जो लोग सोच रहे हैं कि अभी क्यों, मैं इस बात पर जोर देता हूं कि अभी निर्णायक कार्रवाई करना, भले ही इसका मतलब कुछ कड़वी गोलियां निगलना हो, यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि हमारे वित्तीय संस्थान 2047 तक विकसित अर्थव्यवस्था बनने के राष्ट्रीय लक्ष्य का समर्थन करने के लिए पर्याप्त मजबूत रहें।

विनियामक और पर्यवेक्षी ढांचे का न केवल सरलीकरण, सामंजस्य और आधुनिकीकरण करना महत्वपूर्ण है, बल्कि उसे मजबूत करना भी महत्वपूर्ण है। अपेक्षित ऋण हानि, परियोजना वित्त और तरलता कवरेज अनुपात पर हाल के मसौदे इस दृष्टिकोण का उदाहरण हैं, जिसका उद्देश्य वित्तीय मजबूती और स्थिरता को बढ़ाने की कोशिश करते हुए उद्योग की जरूरतों को प्रतिबिंबित करना है।

नवोन्मेष को बढ़ावा देने के लिए विनियामक पहल

आरबीआई ने डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के विकास को समर्थन देने तथा मजबूत संस्थागत ढांचे की स्थापना के लिए कई पहल की हैं, जिसके पूरक के रूप में वित्तीय क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न नीतिगत उपाय किए गए हैं।

2019 में, आरबीआई ने विनियामक निगरानी के तहत वास्तविक ग्राहकों के साथ नए वित्तीय उत्पादों, सेवाओं या व्यावसायिक मॉडलों के परीक्षण के लिए एक नियंत्रित वातावरण प्रदान करने के लिए 'विनियामक सैंडबॉक्स' ढांचा पेश किया। यह पहल उभरती प्रौद्योगिकियों के लाभों और जोखिमों का आकलन करने के लिए विनियामकों, नवोन्मेषों और वित्तीय सेवा प्रदाताओं के बीच सहयोग की सुविधा प्रदान करती है। अपनी स्थापना के बाद से, सैंडबॉक्स के पांच समूहों ने विभिन्न विचारों का मूल्यांकन किया है, जिनमें से कुछ व्यवहार्य साबित हुए हैं। ऐसी स्थितियों को ठीक करने के लिए जहां कोई उत्पाद या सेवा कई वित्तीय क्षेत्र नियामकों के अंतर्गत आ सकती है, 2022 में एक अंतर-संचालन योग्य विनियामक सैंडबॉक्स तंत्र पेश किया गया था।

इन प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए, आरबीआई ने 'Harbinger' पहल के तहत वैश्विक हैकथॉन का भी आयोजन किया है, जो न केवल विजेताओं को उदारतापूर्वक पुरस्कृत करता है, बल्कि शॉर्टलिस्ट की गई टीमों को उनके समाधानों के प्रोटोटाइप का समर्थन करने के लिए वजीफा भी प्रदान करता है। तीसरा संस्करण, 'Harbinger' 2024, जिसका विषय 'परिवर्तन के लिए नवोन्मेष' है, 'शून्य वित्तीय धोखाधड़ी' को प्राप्त करने और 'दिव्यांग अनुकूल' तकनीक बनाने के उद्देश्य से समाधान आमंत्रित करता है।

2021 में, आरबीआई ने रिज़र्व बैंक इनोवेशन हब की स्थापना की, जो किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) कृषि ऋणों की पूरी तरह से डिजिटल और सुव्यवस्थित डिलीवरी जैसे डिजिटल समाधानों को आगे बढ़ाने में सहायक रहा है। पिछले साल, इसने पब्लिक टेक प्लेटफ़ॉर्म पर पायलट लॉन्च किया, जिसे अब यूएलआई नाम दिया गया है, जिसे ऋणदाताओं को डिजिटल जानकारी के निर्बाध प्रवाह को सक्षम करके घर्षण रहित ऋण की सुविधा के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस प्लेटफ़ॉर्म में एक ओपन आर्किटेक्चर और ओपन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई) है, जो वित्तीय क्षेत्र के प्रतिभागियों को 'प्लग एंड प्ले' मॉडल में कनेक्ट करने की अनुमति देता है।

क्या विनियामक बाधाकारक है?

कुछ ऐसे पहलों पर विस्तार से चर्चा करने के बाद, जो यह दर्शाते हैं कि रिज़र्व बैंक एक सक्षमकर्ता के रूप में कार्य करता है, अब मैं बाजार में होने वाले विनियामक व्यवधानों की कुछ टिप्पणियों पर चर्चा करना चाहूंगा, सौभाग्य से केवल कुछ ही लोगों द्वारा, लेकिन हमारे लिए इनकी जांच करना अभी भी आवश्यक है।

ऐसी ही एक कहानी यह है कि विनियामक की कार्रवाइयां नवोन्मेष को रोक सकती हैं या व्यावसायिक संचालन में अत्यधिक हस्तक्षेप कर सकती हैं। यह भी महसूस किया जा रहा है कि विनियामकों को जोखिम लेने के मामले में अधिक सहायक होना चाहिए। यहाँ यह समझने की आवश्यकता है कि जहाँ व्यवसाय जोखिम उठाने के लिए साहसी हो सकते हैं और लाभ और निवेशक प्रतिलाभ की तलाश में अधिक जोखिम उठाने के लिए इच्छुक हो सकते हैं, वहीं विनियामकों की जिम्मेदारी जमाकर्ताओं और ग्राहकों के हितों की रक्षा करना और वित्तीय स्थिरता को बनाए रखना है। विनियामक की भूमिका सुरक्षा या संतुलित ढाँचा स्थापित करना है जो नवोन्मेष को प्रोत्साहित करता है जबकि यह सुनिश्चित करता है कि जोखिमों का विवेकपूर्ण तरीके से प्रबंधन किया जाए।

उदाहरण के लिए, फिनटेक प्लेटफ़ॉर्म अक्सर ग्राहकों को एक सहज, कुशल अनुभव प्रदान करते हैं। डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का लाभ उठाकर, ये प्लेटफ़ॉर्म व्यापक ग्राहक आधार तक पहुँच सकते हैं, जिनमें वे लोग भी शामिल हैं जिनकी पहले वित्तीय सेवाओं तक सीमित पहुँच थी, जिससे वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलेगा और वंचित समुदायों को सशक्त बनाया जा सकेगा। वे ग्राहक अधिग्रहण की लागत के साथ-साथ लेन-देन की लागत को कम करने में मदद करते हैं। डिजिटलीकरण बैंकों और एनबीएफसी को अपने ग्राहकों की आवश्यकताओं और व्यवहार के बारे में अधिक जानकारी के लिए डेटा का लाभ उठाने की अनुमति देता है जिसका उपयोग बेहतर जोखिम प्रबंधन और अनुपालन की सुविधा के अलावा ग्राहक-लक्षित (बेस्पोक) उत्पादों को विकसित करने के लिए किया जा सकता है। रिज़र्व बैंक ऐसी सभी पहलों के माध्यम से उत्साहजनक भूमिका निभा रहा है।

हालांकि, यह डिजिटल बदलाव ऐसे जोखिम भी लाता है जिन्हें स्थिर और सुरक्षित वित्तीय परितंत्र बनाए रखने के लिए उचित रूप से पहचाना, कम किया और प्रबंधित किया जाना चाहिए। डिजिटल उत्पाद प्रदान करने वाली अलग-अलग संस्थाओं के एकीकरण से अक्सर अतिव्यापी जिम्मेदारियों के साथ जटिल संरचनाएं बनती हैं। कई मामलों में, पारदर्शिता के लिए विनियामक आवश्यकताओं के बावजूद, वास्तविक ऋणदाता उधारकर्ता को दिखाई भी नहीं दे सकता है। जबकि फिनटेक प्लेटफ़ॉर्म नवोन्मेष और राजस्व को बढ़ावा देते हैं, ऋण और परिचालन जोखिम और परिणामी नुकसान अभी भी मुख्य रूप से विनियमित ऋणदाताओं के पास हैं जो इन प्लेटफ़ॉर्म के साथ सहयोग करते हैं। यह सेवा प्रदाताओं और जोखिम उठाने वालों के बीच एक अलगाव पैदा कर सकता है, जिससे व्यक्तिगत ऋणदाता के साथ-साथ वित्तीय प्रणाली के लिए संभावित कमज़ोरियाँ पैदा हो सकती हैं।

उदाहरण के लिए, जबकि ऋण स्वीकृति और संवितरण तेजी से डिजिटल हो गए हैं, प्रभावी संग्रह और समुत्थान अभी भी चल रहा है और सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण की आवश्यकता है। कई फिनटेक प्लेटफ़ॉर्म एक ऐसे व्यवसाय मॉडल पर काम करते हैं जिसमें अक्सर खराब क्रेडिट प्रोफ़ाइल वाले ग्राहकों को छोटे-मूल्य के ऋण देना शामिल होता है। दुर्भाग्य से, इसके बाद अक्सर आक्रामक वसूली रणनीति अपनाई जाती है, जैसे कि ग्राहकों के संपर्क और व्यक्तिगत डेटा तक पहुँच कर उनकी गोपनीयता का उल्लंघन करना। ये प्रथाएँ इन प्लेटफ़ॉर्म से जुड़े विनियमित ऋणदाताओं की प्रतिष्ठा को गंभीर रूप से नुकसान पहुँचा सकती हैं। आउटसोर्सिंग पर आरबीआई के नियमों के अनुसार, भले ही एक विनियमित इकाई कुछ गतिविधियों को करने के लिए तीसरे पक्ष पर निर्भर हो सकती है, लेकिन यह अपने आउटसोर्स एजेंटों के कार्यों के लिए अंततः उत्तरदायी रहती है।

एक और कहानी जिस पर मैं आज बात करना चाहूँगा, वह यह है कि पर्यवेक्षक कारोबार पर प्रतिबंध लगाने के लिए बहुत उत्सुक हैं, कभी-कभी उन्हें "ट्रिगर-हैप्पी" के रूप में चित्रित किया जाता है। यह गलत धारणा बनाती है कि विनियामक लगातार वित्तीय संस्थाओं पर लगाम लगाने के अवसरों की तलाश में रहते हैं। कभी-कभी मीडिया द्वारा हमसे पूछा जाता है, "अगला कौन है?" - जिसका अर्थ है कि पर्यवेक्षी कार्रवाई प्रकृति में विनियामक है।

हकीकत में, व्यापार प्रतिबंध लगाने का निर्णय कभी भी आसानी से नहीं लिया जाता है। सख्त पर्यवेक्षी कार्रवाई केवल सावधानीपूर्वक ऑनसाइट जांच, ऑफसाइट डेटा विश्लेषण और सुधार के लिए संबंधित विनियमित संस्थाओं के साथ व्यापक जुड़ाव के बाद ही की जाती है, जो अक्सर कई महीनों तक चलती है। हमारा प्राथमिक लक्ष्य वित्तीय प्रणाली की स्थिरता और अखंडता सुनिश्चित करना है, न कि व्यावसायिक संचालन में बाधा डालना। 150 से अधिक बैंकों, 9,000 से अधिक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और साथ ही लगभग 1,500 यूसीबी और अन्य संस्थाओं में से जिनकी हम निगरानी करते हैं, केवल मुट्ठी भर मामलों में ही सख्त कार्रवाई की गई है। वह भी, प्रत्येक श्रेणी में सबसे अलग-थलग को इस तरह की दंडात्मक कार्रवाई के लिए बुलाया गया है ताकि इसका बाकी उद्योग पर एक प्रदर्शनकारी प्रभाव हो। ये उपाय दंड देने के बारे में नहीं हैं, बल्कि जमाकर्ताओं, ग्राहकों और व्यापक वित्तीय प्रणाली के हितों की रक्षा के बारे में हैं।

इन प्रयासों के बावजूद, विनियमों की नवीन गलत व्याख्या देखना निराशाजनक है। हाल ही का एक मामला पीयर-टू-पीयर (पी2पी) ऋण विनियमन का है। मूल रूप से परिकल्पित विनियमों में, प्लेटफ़ॉर्म को ऋणदाताओं को उधारकर्ताओं से जोड़ने वाले ऑनलाइन मार्केटप्लेस की तरह काम करने की परिकल्पना की गई थी, जिसमें प्लेटफ़ॉर्म द्वारा कोई क्रेडिट जोखिम नहीं उठाया गया था और न ही धन का सह-मिलन या प्रतिधारण किया गया था। हालाँकि, पिछले एक साल में पर्यवेक्षी निष्कर्षों से पता चला है कि इनमें से कुछ प्लेटफ़ॉर्म ने ऐसे अभ्यास अपनाए जो विनियमों का उल्लंघन करते थे। इस महीने की शुरुआत में पी2पी ऋण प्लेटफ़ॉर्म पर जारी किए गए निर्देश कोई नई बात नहीं हैं, बल्कि कुछ मामलों में देखे गए गंभीर उल्लंघनों की प्रतिक्रिया मात्र हैं। हालाँकि, कुछ तिमाहियों में इसे इस तरह प्रस्तुत किया जा रहा है जैसे कि ये 'नए' नियम इस उद्योग को 'खत्म' कर देंगे। इसके विपरीत, ऐसी संस्थाओं को दिए गए विभेदित लाइसेंसिंग और हल्के स्पर्श वाले विनियमन का उद्देश्य उन्हें एक अनूठा प्लेटफ़ॉर्म स्थापित करने में मदद करना है, न कि बैंकों या एनबीएफसी की नकल करना जो अधिक मज़बूती से पूंजीकृत और सख्त विनियमित हैं।

निष्कर्ष

निष्कर्ष में, कभी-कभार आलोचनाओं के बावजूद, विनियामक ढाँचे परामर्शी दृष्टिकोण अपनाते रहे हैं, जिससे एक लचीले वित्तीय क्षेत्र को आकार देने में मदद मिली है। पिछले कुछ दशकों में, भारतीय बैंकिंग क्षेत्र ने एशियाई वित्तीय संकट, वैश्विक वित्तीय संकट और हाल ही में कोविड-19 महामारी सहित कई चुनौतियों का सामना किया है। हर बार, भारतीय वित्तीय क्षेत्र न केवल उद्योग के प्रयासों और अनुकूलनशीलता के कारण बल्कि विनियामक ढाँचे की विवेकशीलता और दूरदर्शिता के कारण भी मजबूत होकर उभरा है।

हम सभी विकसित भारत 2047 के विजन को साकार करने की इस यात्रा में भागीदार हैं। हालांकि, सपनों का निर्माण कमजोर नींव पर नहीं किया जा सकता है, यही कारण है कि विनियामक की जिम्मेदारी है कि वह ऐसे परिचालन और सुरक्षा-व्यवस्था स्थापित करे जो यह सुनिश्चित करे कि हम सुरक्षित रूप से अपने गंतव्य तक पहुंचें और आगे बढ़ते रहें।

मैं उद्योग जगत से आग्रह करूंगा कि वे विनियामकों को विघटनकारी के रूप में देखने के बजाय, विनियामक को एक स्थिर और समृद्ध वित्तीय परितंत्र के भागीदार के रूप में देखें। इसलिए विनियमों के पीछे की मंशा को समझना आवश्यक है, जो ग्राहकों की सुरक्षा, निष्पक्षता सुनिश्चित करने और स्थिरता बनाए रखने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। आइए हम अपनी रचनात्मकता को ऐसे उत्पादों और सेवाओं में लगाएं जो न केवल विनियमों का अनुपालन करते हैं बल्कि वित्तीय प्रणाली के समग्र स्वास्थ्य और समावेशिता को भी बढ़ाते हैं। आइए हम ऐसे समाधान विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करें जो वास्तविक मूल्यवर्धन करते हैं, बजाय विनियमों को दरकिनार करने या उसी तरह से और अधिक करने के तरीके खोजने के। विनियामक उद्देश्यों के साथ नवोन्मेषों को जोड़कर, हम एक मजबूत, अधिक भरोसेमंद वित्तीय क्षेत्र का निर्माण कर सकते हैं जो सभी को लाभान्वित करता है।

इसके साथ ही मैं श्रोताओं को उनके धैर्यपूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद देता हूं, तथा सीएनबीसी टीवी 18 को मुझे इस शिखर सम्मेलन में आमंत्रित करने और आज आपको संबोधित करने का अवसर प्रदान करने के लिए धन्यवाद देता हूं।

*स्थानिक से वैश्विक: एमएसएमई के विकास में वित्तीय क्षेत्र की भूमिका**

श्री स्वामीनाथन जे.

विशिष्ट अतिथिगण, देवियो और सज्जनो। आप सभी को नमस्कार !

एफईडीएआई के वार्षिक दिवस पर इस प्रतिष्ठित सभा में बोलना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है। अंतर-बैंक विदेशी मुद्रा व्यापार की जटिलताओं को स्पष्ट करने और विनियामकों के साथ एक महत्वपूर्ण आवाज़ के रूप में काम करने के अपने अथक प्रयासों के माध्यम से, एफईडीएआई ने भारत में विदेशी मुद्रा व्यापार के नियमों को आकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसलिए, जब मुख्य कार्यकारी श्री सिंधवानी ने मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया, तो मुझे पता था कि यह एक ऐसा अवसर है जिसे मैं नहीं छोड़ सकता।

जैसा कि हम एफईडीएआई की उपलब्धियों का उत्सव मना रहे हैं, यह भारत के आर्थिक भविष्य के लिए समष्टि दृष्टिकोण पर विचार करने का भी एक उपयुक्त अवसर है। 2022 में, जब हमारा देश स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाएगा, माननीय प्रधानमंत्री ने देश के लिए पाँच प्रमुख संकल्पों को रेखांकित किया, जिनमें से एक 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र में बदलने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य था। इस दृष्टिकोण को साकार करने के लिए सभी क्षेत्रों में एकीकृत प्रयास की आवश्यकता होगी, जिसमें सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) आर्थिक उत्पादन को बढ़ाने और निर्यात को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। एमएसएमई, जिन्हें अक्सर हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है, राष्ट्रीय चैंपियन बनने की अपार क्षमता रखते हैं - ऐसी क्षमता जिसका अभी तक बड़े पैमाने पर दोहन नहीं हुआ है। इसे ध्यान में रखते हुए, मैंने आज अपने संबोधन के लिए *'स्थानिक से वैश्विक: भारत के विकास में वित्तीय क्षेत्र की भूमिका'* विषय चुना है।

* 21 अगस्त 2024 को मुंबई में आयोजित भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (एफईडीएआई) के वार्षिक दिवस पर उप गवर्नर, श्री स्वामीनाथन जे. का भाषण।

भारत की आर्थिक संवृद्धि में एमएसएमई की भूमिका

लगभग 63 मिलियन इकाइयों के विशाल नेटवर्क के साथ, एमएसएमई देश के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग एक तिहाई का योगदान देते हैं और इसके विनिर्माण उत्पादन में लगभग 40 प्रतिशत का योगदान देते हैं।[1]

इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि एमएसएमई क्षेत्र की उद्यमिता को बढ़ावा देने और पर्याप्त रोजगार अवसर पैदा करने की क्षमता भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश को साकार करने में महत्वपूर्ण कारक है। इसके अतिरिक्त, महत्वपूर्ण सहायक इकाइयों के रूप में, एमएसएमई बड़े उद्योगों का समर्थन करते हैं और द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। लाखों नौकरियों के सृजन के साथ, एमएसएमई क्षेत्र भारत में रोजगार के सबसे महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक है, जो आजीविका को बनाए रखने और समावेशी संवृद्धि को आगे बढ़ाने में इसके महत्व को रेखांकित करता है।

एमएसएमई क्षेत्र का प्रभाव घरेलू सीमाओं से परे तक फैला हुआ है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में, इन उद्यमों ने अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता साबित की है, जो भारत के निर्यात में 40 प्रतिशत से अधिक का योगदान देता है। वैश्विक बाजारों में इसकी बढ़ती उपस्थिति भारतीय एमएसएमई उत्पादों और सेवाओं की बढ़ती स्वीकृति और मांग को दर्शाती है, जो इस क्षेत्र को भारत के वैश्विक आर्थिक पदचिह्न को बढ़ाने में एक प्रमुख इकाई के रूप में स्थापित करती है।

इन उपलब्धियों के बावजूद, इस क्षेत्र को महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, खास तौर पर *"मिसिंग मिड्ल"* का मुद्दा। जबकि सूक्ष्म उद्यम एमएसएमई के अधिकांश रोजगार का निर्माण करते हैं, वे अक्सर छोटे या मध्यम आकार की फर्मों में बदलने के लिए संघर्ष करते हैं। यह सीमा पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं को प्राप्त करने, अचल संपत्तियों में निवेश करने और नवीन तकनीकों को अपनाने की उनकी क्षमता को बाधित करती है। आज अपने संबोधन में, मैं इन चुनौतियों पर ध्यान

[1] सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा 11 दिसंबर 2023 को जारी प्रेस प्रकाशनी के अनुसार, वित्त वर्ष 2021-22 के लिए अखिल भारतीय सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में एमएसएमई सकल मूल्यवर्धन (जीवीए) की हिस्सेदारी 29.15 प्रतिशत थी और इसी अवधि के लिए अखिल भारतीय विनिर्माण जीवीए में एमएसएमई विनिर्माण जीवीए की हिस्सेदारी 40.83 प्रतिशत थी। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए अखिल भारतीय निर्यात में एमएसएमई से संबंधित उत्पादों के निर्यात की हिस्सेदारी 43.59 प्रतिशत थी।

केंद्रित करूंगा और पता लगाऊंगा कि वित्तीय क्षेत्र उन्हें ठीक करने में कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, जिससे एमएसएमई के विकास और विकास को बड़े निगमों में समर्थन मिल सके।

एमएसएमई के समक्ष चुनौतियां

मैं आज एमएसएमई के सामने आने वाली कुछ चुनौतियों पर चर्चा करना चाहता हूँ। मुझे यकीन है कि आप उनमें से ज़्यादातर के बारे में जानते होंगे, इसलिए मैं सिर्फ़ चार मुख्य मुद्दों पर ही बात करूँगा।

वित्त तक पहुंच

पहला मुद्दा किफायती वित्त तक पहुंच है। एमएसएमई के विकास के लिए ऋण महत्वपूर्ण है, और किफायती फंड उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ा सकते हैं। बैंक अक्सर परिसंपत्ति-आधारित ऋण का उपयोग करते हैं, जो नकदी प्रवाह के बजाय संपार्श्विक पर निर्भर करता है। हालांकि, कई एमएसएमई के पास संपार्श्विक के लिए पर्याप्त संपत्ति नहीं है, खासकर कार्यशील पूंजी की जरूरतों के लिए, जिससे अक्सर छोटे व्यवसाय औपचारिक बैंकिंग क्षेत्र से वित्तपोषण के अवसरों से वंचित रह जाते हैं। इसके अलावा, चूंकि कई एमएसएमई मुख्य रूप से अनौपचारिक क्षेत्र में काम करते हैं, इसलिए सूचना विषमता के कारण उनकी ऋण पात्रता का आकलन करना मुश्किल हो सकता है, खासकर उनके व्यवसायों के वित्तीय प्रदर्शन के संबंध में। हालांकि जीएसटी और डिजिटल भुगतान जैसी पहलों का उद्देश्य एमएसएमई के बीच डिजिटलीकरण को सुविधाजनक बनाना है, लेकिन औपचारिक डिजिटल दस्तावेज़ीकरण विधियों को अपनाना सीमित है, जो एक कुशल ऋण हामीदारी प्रक्रिया में बाधा डालता है।

विलंबित भुगतान

दूसरा, एमएसएमई को अक्सर भुगतान में देरी की समस्या का सामना करना पड़ता है। भुगतान प्राप्त करने में देरी से उनका परिचालन चक्र लंबा हो जाता है और मौजूदा ऑर्डर को पूरा करने या नए ऑर्डर प्राप्त करने की उनकी क्षमता कम हो जाती है। खरीदारों द्वारा भुगतान में देरी के लिए दंड लगाने वाले वैधानिक प्रावधानों के अस्तित्व के बावजूद, एमएसएमई अक्सर इन प्रावधानों का उपयोग करने से बचते हैं। उनकी अनिच्छा कमजोर सौदेबाजी शक्ति और भविष्य के व्यावसायिक अवसरों को खोने के डर के संयोजन से उत्पन्न होती है।

अवसंरचना की अड़चनें

तीसरा, अवसंरचना को बढ़ाने के प्रयासों के बावजूद, एमएसएमई क्लस्टर, विशेष रूप से सूक्ष्म उद्यमों में महत्वपूर्ण सहायता प्रणालियों का अभाव है। यह कमी न केवल उनके दैनिक कार्यों में बाधा डालती है, बल्कि उनके भविष्य की विकास क्षमता में भी बाधा डालती है। एमएसएमई क्लस्टर विकसित करने से साझा बुनियादी ढांचा, सेवाएं और बड़े बाजारों तक पहुंच मिल सकती है, जिससे उनकी विकास क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है।

अनुपालन की आवश्यकताएं

जैसे-जैसे व्यवसाय अनौपचारिक से औपचारिक इकाई में परिवर्तित होते हैं, उन्हें विनियामक दायित्वों और अनुपालन की लागत में उल्लेखनीय वृद्धि का सामना करना पड़ता है। कभी-कभी इन आवश्यकताओं में कानूनों की व्याख्या, अनुपालन प्रक्रियाओं का ज्ञान आदि शामिल होते हैं। एमएसएमई के विस्तार के प्रयासों के दौरान वित्तपोषण संस्थाओं के साथ कठिनाइयों के उदाहरण असामान्य नहीं हैं। सरकार और विनियामक कठिनाइयों को कम करने और व्यवसाय करने की लागत को कम करने के लिए विभिन्न पहल कर रहे हैं।

एमएसएमई को सशक्त बनाने में वित्तीय क्षेत्र की भूमिका

एमएसएमई क्षेत्र के समक्ष आ रही कुछ प्रमुख चुनौतियों पर चर्चा करने के बाद, तथा वित्तीय क्षेत्र से यहां उपस्थित विशाल श्रोतागण का लाभ उठाते हुए, मैं कुछ ऐसे तरीकों पर प्रकाश डालना चाहूंगा, जिनसे हम इसके विकास और संवृद्धि में सहायता कर सकते हैं।

डिजिटलीकरण और नवीन वित्तपोषण समाधान

अधिकाधिक एमएसएमई द्वारा डिजिटल भुगतान प्रणाली, मोबाइल बैंकिंग और ऑनलाइन लेखा उपकरण अपनाने के कारण, परिणामी डिजिटल फुटप्रिंट वित्तीय संस्थाओं को एमएसएमई के वित्तीय स्वास्थ्य, लेन-देन इतिहास और नकदी प्रवाह पैटर्न पर अधिक सटीक और व्यापक डेटा एकत्र करने की अनुमति देता है।

हमने पिछले कुछ वर्षों में ऋण वितरण के एंड-टू-एंड डिजिटलीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति देखी है, मुख्य रूप से खुदरा क्षेत्र में और कुछ हद तक एमएसएमई क्षेत्र में। मैं बैंकरों

से एमएसएमई के साथ अपने लेन-देन के अधिक डिजिटलीकरण के लिए इन अवसरों का और अधिक पता लगाने का आग्रह करूंगा। डिजिटल एप्लिकेशन और प्लेटफ़ॉर्म पारंपरिक ऋण देने से जुड़े कागजी काम और प्रशासनिक बोझ को कम करते हैं, और पूरी पारदर्शिता भी लाते हैं। आवेदन प्रसंस्करण, सत्यापन और संवितरण के लिए डिजिटल उपकरणों का उपयोग करके, वित्तीय संस्थान अनुमोदन के समय को तेज कर सकते हैं और ऋण प्राप्त करने की लागत को काफी कम कर सकते हैं।

बढ़े हुए डिजिटल फुटप्रिंट से प्राप्त डेटा बेहतर जोखिम मूल्यांकन और अनुकूलित वित्तपोषण उत्पादों के विकास को सक्षम करेगा। वास्तव में, एमएसएमई के नकदी प्रवाह की उचित समझ के बाद वित्त प्रदान करना, जिसमें उनके खरीदारों से संभावित विलंबित भुगतानों को शामिल करना शामिल है, वास्तविक कार्यशील पूंजी चक्र का उचित वाचन सुनिश्चित करेगा और पर्याप्त वित्तपोषण सुनिश्चित करेगा। वास्तविक नकदी प्रवाह और उसके समय की अपर्याप्त समझ के परिणामस्वरूप पुनर्भुगतान कार्यक्रम वास्तविकता के अनुरूप नहीं हो सकते हैं।

अपनी ओर से, आरबीआई ने एमएसएमई को वित्तपोषण में नवोन्मेष को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न पहल की हैं। हाल ही में, आरबीआई विनियामक सैंडबॉक्स[2] का तीसरा समूह एमएसएमई ऋण देने के लिए समर्पित था, जहाँ पाँच विचारों को व्यवहार्य पाया गया। इससे पहले, एमएसएमई को विलंबित भुगतान के मुद्दे को हल करने के लिए, आरबीआई ने 2014 में व्यापार प्राप्य छूट प्रणाली (TReDS) शुरू की थी। यह योजना कई फाइनेंसरों के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) सहित कॉर्पोरेट और अन्य खरीदारों से एमएसएमई के व्यापार प्राप्तियों के वित्तपोषण की सुविधा प्रदान करती है। जबकि पिछले कुछ वर्षों में लेन-देन में तेजी आई है, लेकिन इसकी पूरी क्षमता का दोहन करने के लिए प्लेटफॉर्म पर अधिक कॉर्पोरेट खरीदारों और एमएसएमई विक्रेताओं द्वारा ऑनबोर्डिंग में एक लंबा रास्ता तय करना है।

[2] आरबीआई ने नियंत्रित/परीक्षण विनियामक वातावरण में नए उत्पादों या सेवाओं के लाइव परीक्षण की सुविधा के लिए विनियामक सैंडबॉक्स के लिए एक सक्षम ढांचा तैयार किया है, जिसके लिए विनियामक परीक्षण के सीमित उद्देश्य के लिए कुछ विनियामक छूट की अनुमति दे सकते हैं (या नहीं भी दे सकते हैं)। अगस्त 2019 में इसके जारी होने के बाद से इस ढांचे के तहत पाँच समूह हैं।

क्षमता निर्माण और वित्तीय साक्षरता

वित्त और डिजिटल उपकरणों तक पहुँच के अलावा, एमएसएमई के बीच वित्तीय साक्षरता बढ़ाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। कई छोटे व्यवसाय मालिकों के पास अपने वित्त को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए ज्ञान और कौशल की कमी होती है, जो उनके विकास में बाधा बन सकती है।

जबकि आरबीआई एनएएमसीएबीएस[3] कार्यक्रम के तहत बैंकरों के लिए एमएसएमई वित्त पर क्षमता निर्माण की सुविधा प्रदान कर रहा है, मेरा मानना है कि वित्तीय क्षेत्र एमएसएमई की जरूरतों के अनुरूप क्षमता निर्माण कार्यक्रम प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

इन कार्यक्रमों में वित्तीय प्रबंधन, ऋण और विदेशी मुद्रा उत्पादों को समझना और डिजिटल उपकरणों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने का प्रशिक्षण शामिल हो सकता है। एमएसएमई को सही ज्ञान और कौशल से लैस करके, हम उन्हें संसूचित वित्तीय निर्णय लेने, उनके संचालन को अनुकूलित करने और डिफ़ॉल्ट के जोखिम को कम करने में मदद कर सकते हैं। वित्तीय संस्थानों, सरकारी एजेंसियों और उद्योग निकायों के बीच साझेदारी यह सुनिश्चित कर सकती है कि ये क्षमता-निर्माण पहल उन व्यवसायों तक पहुँचें जिन्हें उनकी सबसे अधिक आवश्यकता है।

जैसा कि आप जानते होंगे, भारत सरकार ने सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) की उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के साथ-साथ क्षमता निर्माण के लिए एक प्रमुख रणनीति के रूप में क्लस्टर विकास दृष्टिकोण को अपनाया है। इस संबंध में, आरबीआई ने सभी राज्य स्तरीय बैंकर्स समितियों (एसएलबीसी) के संयोजकों को इन पहचाने गए क्लस्टरों की ऋण आवश्यकताओं को अपनी वार्षिक ऋण योजनाओं में शामिल करने की सलाह दी है। इस पहल को और अधिक समर्थन देने के लिए, मैं बैंकों से अनुरोध करूंगा कि वे इन क्लस्टरों के भीतर अधिक एमएसई-केंद्रित शाखा कार्यालय खोलने पर विचार करें, अधिमानतः विदेशी मुद्रा सुविधा के साथ। ये विशेष शाखाएँ न केवल एमएसई के लिए ऋण तक आसान पहुँच की सुविधा प्रदान करेंगी, बल्कि इन उद्यमों को अनुरूप वित्तीय सलाह और क्षमता निर्माण सेवाएँ प्रदान करते हुए परामर्श केंद्र के रूप में भी काम करेंगी।

[3] बैंकरों की क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय मिशन (एनएएमसीएबी)।

एमएसएमई निर्यात को बढ़ावा देना

वित्तीय क्षेत्र, लक्षित समर्थन और अनुरूपित सेवाएं प्रदान करके एमएसएमई निर्यात को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, जो वैश्विक बाजार में इन व्यवसायों के सामने आने वाली विशिष्ट चुनौतियों का समाधान करता है।

प्री- और पोस्ट-शिपमेंट फाइनेंस, फैक्टरिंग और इनवॉइस डिस्काउंटिंग जैसे पारंपरिक उत्पादों के अलावा, यह क्षेत्र निर्यात ऋण बीमा और मुद्रा जोखिम हेजिंग समाधानों के माध्यम से एमएसएमई को जोखिमों के प्रबंधन में महत्वपूर्ण रूप से सहायता कर सकता है। ये वित्तीय साधन न केवल भुगतान चूक और मुद्रा में उतार-चढ़ाव से सुरक्षा प्रदान करते हैं, बल्कि एमएसएमई को नए अंतरराष्ट्रीय बाजारों की खोज और विस्तार करने का आत्मविश्वास भी प्रदान करते हैं।

मौजूदा नियमों के अनुसार, नकदी और हेजिंग उत्पादों सहित विदेशी मुद्रा की ज़रूरतों को अधिकृत डीलरों के ज़रिए पूरा किया जाना चाहिए, जिसमें अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की प्रमुख भूमिका होती है। विशेषाधिकार प्राप्त स्थिति वाले इन बैंकों का यह कर्तव्य है कि वे निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से काम करें, खास तौर पर एमएसएमई जैसे छोटे ग्राहकों के साथ।

2019 में एफएक्स-रिटेल प्लेटफॉर्म की शुरुआत का उद्देश्य खुदरा विदेशी मुद्रा लेनदेन में पारदर्शिता और निष्पक्षता बढ़ाना था, लेकिन इसमें सीमित सफलता ही मिली है। मैं बैंकों से अनुरोध करूंगा कि वे जागरूकता बढ़ाने और एफएक्स-रिटेल प्लेटफॉर्म पर ग्राहकों की अधिक भागीदारी को सुविधाजनक बनाने के लिए सक्रिय कदम उठाएं।

क्षेत्र के प्रति संवेदनशीलता

अंत में, अर्थव्यवस्था में एमएसएमई की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए, वित्तीय क्षेत्र को उनके प्रति अधिक संवेदनशील और सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। जहाँ वित्तीय अनुशासन महत्वपूर्ण है, एमएसएमई के सामने आने वाली अनूठी चुनौतियाँ - जैसे कम पूंजी आधार, पैमाने की कमी, विलंबित भुगतानों से नकदी प्रवाह की बाधाएँ, उतार-चढ़ाव वाले बाज़ार की स्थितियाँ और बाहरी आर्थिक दबाव - मूल्यांकन के साथ-साथ अनुवर्ती कार्रवाई के लिए अधिक सूक्ष्म दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

जहाँ वित्तीय प्रणाली के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए बकाया राशि का समय पर अदायगी महत्वपूर्ण है, वहीं वित्तीय संस्थानों को, पुनर्गठन विकल्प, रियायती अवधि और अनुरूप पुनर्भुगतान योजनाओं; जैसे सहायक उपायों को लागू करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जिससे एमएसएमई को मुश्किल परिस्थितियों का सामना करते समय उबरने और पटरी पर लौटने के लिए आवश्यक राहत मिल सके।

ऋणदाताओं और उधारकर्ताओं के बीच सहयोग और संवाद से ऐसे समाधान तैयार करने में मदद मिल सकती है जो ऋणदाता के वित्तीय हितों और एमएसएमई की व्यवहार्यता दोनों की रक्षा कर सकें।

निष्कर्ष

निष्कर्षत: भारत के आर्थिक परिवर्तन की यात्रा हमारे एमएसएमई क्षेत्र के मजबूत विकास के बिना पूरी नहीं हो सकती। एमएसएमई न केवल हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, वे विकास, नवोन्मेष और रोजगार के इंजन भी हैं। हालांकि, इन उद्यमों को वास्तव में फलने-फूलने और आगे बढ़ने के लिए, वित्तीय क्षेत्र को अभिनव समाधान, संवेदनशीलता और दूरंदेशी दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ना चाहिए। यह केवल ऋण प्रदान करने के बारे में नहीं है; यह इन उद्यमों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने, निर्यात को बढ़ावा देने और 2047 तक विकसित अर्थव्यवस्था बनने के देश के लक्ष्य में योगदान देने में सक्षम बनाने के बारे में है। जहाँ वित्तीय साधन और समर्थन तंत्र महत्वपूर्ण हैं, वहीं जिस तरह से हम एमएसएमई क्षेत्र के साथ जुड़ते हैं, यानी उनकी चुनौतियों के प्रति हमारी संवेदनशीलता और उनकी सफलता के लिए हमारी प्रतिबद्धता अंततः इस साझेदारी की ताकत और स्थिरता का निर्धारण करेगी।

इसके साथ ही मैं मुझे आमंत्रित करने के लिए एफईडीएआई को धन्यवाद देता हूँ और हितधारकों के साथ घनिष्ठ समन्वय के माध्यम से विदेशी मुद्रा बाजारों के सुचारू संचालन के लिए उत्प्रेरक के रूप में अपनी भूमिका में निरंतर सफलता की कामना करता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।

आलेख

अर्थव्यवस्था की स्थिति

भारतीय राज्यों के व्यापार चक्र का समन्वय

प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र ऋण : भारतीय अनुभव

गहन विश्लेषण: हाल के समय में एनबीएफसी क्षेत्र की समीक्षा

*अर्थव्यवस्था की स्थिति**

वैश्विक आर्थिक गतिविधि धीमी हो रही है, जबकि अवस्फीति की गति सुस्त बनी हुई है, जिससे मौद्रिक नीति अधिकारियों के बीच सावधानी बरती जा रही है। भारत में, घरेलू वाहक - निजी खपत और सकल निर्धारित निवेश - मजबूत रहे और निवल निर्यात 2024-25 की पहली तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि के समर्थन में क्रमिक रूप से सकारात्मक रहे। कृषि के कमजोर प्रदर्शन के कमी की पूर्ति एक उत्साही विनिर्माण क्षेत्र और आघात-सहनीय सेवाओं द्वारा की गई। घरेलू खपत दूसरी तिमाही में तेजी से बढ़ने की ओर अग्रसर है क्योंकि हेडलाइन मुद्रास्फीति कम हो रही है, ग्रामीण मांग का पुनरुद्धार पहले से ही जोर पकड़ रहा है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मुद्रास्फीति अगस्त में लगातार दूसरे महीने रिज़र्व बैंक के लक्ष्य से नीचे आ गई, हालांकि हाल के अनुभव के प्रकाश में, खाद्य मूल्य अस्थिरता एक आकस्मिक जोखिम बनी हुई है।

भूमिका

1961 की अमेरिकी फिल्म “कम सेप्टेम्बर” के थीम स्कोर ने दुनिया भर में धूम मचाई। इसने कई हिंदी और तमिल गीतों और फिल्मों को भी प्रेरित किया, इतना कि सितंबर का महीना संगीत का पर्याय बन गया। लेकिन सितंबर पश्चिम के बाजारों के लिए सबसे क्रूर महीना भी है, जहां से हाल की अवधि में, लगभग सभी वैश्विक प्रभावविस्तार हो रहे हैं। जैसे-जैसे लोग गर्मी की छुट्टियों से वापस लौटते हैं और प्रतिलाभ के लिए फिर से तरोताजा होकर व्यापार शुरू करते हैं, अस्थिरता चरम पर पहुंच जाती है। सितंबर की मौसमी परिस्थितियों से बचाव करने में जल्द ही बचत की तुलना में अधिक खर्च होता है।

यह सितंबर प्रमुख केंद्रीय बैंकों द्वारा कार्यों की गर्मागर्मी के साथ अपनी प्रतिष्ठा पर खरा उतर रहा है - यूरोपीय सेंट्रल बैंक (ईसीबी) ने वर्ष की अपनी दूसरी दर में कटौती लागू की, इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएस) फेडरल रिज़र्व द्वारा 50 आधार अंक (बीपीएस) की कटौती की गई, जबकि बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ जापान ने यथास्थिति बनाए रखते हुए विचलन किया। 2 अगस्त को अमेरिकी गैर-कृषि पेरोल डेटा की उथल-पुथल भरी रिलीज से तेजी से उबरते हुए, जिसने दुनिया भर के बाजारों में हलचल पैदा कर दी थी क्योंकि येन कैरी ट्रेडों में गिरावट आई थी, निवेशकों ने संतुलन हासिल कर लिया, पोर्टफोलियो को फिर से व्यवस्थित किया और लीवरेज का पुनर्निर्माण किया। एक बार फिर, हालांकि, 3 सितंबर को एक एकल डेटा रिलीज-यूएस इंस्टीट्यूट फॉर सप्लाई मैनेजमेंट (आईएसएम) विनिर्माण सूचकांक - पर मंदी की आशंका फिर से उभर आई, जिससे अमेरिकी इक्विटी बाजारों में एक मार्ग स्थापित हो गया जो जल्दी से एशिया और यूरोप में फैल गया। इस प्रकार, जैसे-जैसे बाजार केंद्रीय बैंकों की अपनी अपेक्षाओं को विचलन से अभिसरण की ओर ले जा रहे हैं, इसमें रूसी असर दिखाई देता है। प्रत्येक आने वाला डेटा सॉफ्ट लैंडिंग की एकत्रित अच्छी भावना को दूर कर देता है और अवस्फीतिकारी मौद्रिक नीति मार्गों के जोरदार अंत की आशंकाओं को जन्म देता है। कुल मिलाकर, हालांकि, बाजारों ने उच्च अस्थिरता के सामने पर्याप्त आघात-सहनीयता प्रदर्शित की है। सुधार की गति उल्लेखनीय रही है, और पिछले एपिसोड की तुलना में विनिमय दर में बदलाव अधिक नहीं था। व्यापार व्यवस्थित रहा, चलनिधि की स्थिति द्वारा सक्षम किया गया जिसने केंद्रीय प्रतिपक्षों में मार्जिन में बड़े बदलावों को समायोजित किया।

चारों ओर, संकेतक वैश्विक आर्थिक गतिविधि में तेजी से धीमापन इंगित करते नज़र आ रहे हैं, अटलांटिक के पूर्वी तटों पर अधिक, जिसने नरम लैंडिंग को सुरक्षित करने के लिए ईसीबी की सितंबर दर में कटौती को सही ठहराया। अमेरिका में, अब प्रसिद्ध टिप्पणी - "नीति को समायोजित करने का समय आ गया है" - उम्मीद जगी है कि अर्थव्यवस्था मौद्रिक नीति चर्चा में प्रमुखता हासिल कर रही है[1]। चीन में, भले ही चरम मौसम से संबंधित आपूर्ति बाधाओं के कारण उपभोक्ता मुद्रास्फीति में मामूली वृद्धि

* यह आलेख माइकल देबब्रत पात्र, जीवी नथनएल, बिस्वजीत मोहंती, श्रेया कंसल, बजरंगी लाल गुप्ता, रमेश कुमार गुप्ता, शेसाद्री बनर्जी, हरेंद्र बेहरा, के एम नीलिमा, अमित कुमार, सत्यार्थ सिंह, एलिस सेबेस्टियन, सिद्धार्थ आर्य, आकाश राज, अमृता बसु, शिवम, शैलजा भाटिया, सत्येंद्र कुमार, शुभम अग्निहोत्री, शिवांगी मिश्रा, मनीष त्रिपाठी, सत्यम कुमार, खुशी सिन्हा, श्रेया गुप्ता, कार्तिकेय भार्गव, युवराज कश्यप, आशीष संतोष खोबरागड़े, आशीष थॉमस जॉर्ज, समीर रंजन बेहरा, विनीत कुमार श्रीवास्तव और रेखा मिश्र द्वारा तैयार किया गया है।। इस आलेख में व्यक्त किए गए विचार लेखकों के हैं और भारतीय रिज़र्व बैंक के विचारों को नहीं दर्शाते हैं।

[1] जेरोम पॉवेल द्वारा जैक्सन होल, व्योमिंग में फेड के वार्षिक आर्थिक सम्मेलन में मुख्य भाषण। उन्होंने आगे कहा कि "यात्रा की दिशा स्पष्ट है, और दर में कटौती आने वाले डेटा का समय और गति, विकसित दृष्टिकोण और जोखिमों के संतुलन पर निर्भर करेगी।

हुई है, लेकिन उत्पादक कीमतों में कमी चिंताओं को बढ़ावा दे रही है कि अपस्फीति बल जड़ ले रहे हैं। विनिर्माण उद्योगों की बढ़ती संख्या अब अपने तीसरे वर्ष में एक गहरी संपत्ति बाजार मंदी के साथ कमजोर मांग का सामना करती है। जैसा कि खंड II में चर्चा की गई है, हमारे विश्व मॉनिटर का आकलन है कि वैश्विक वृद्धि ने 2024 की पहली छमाही में पहले के सापेक्ष कुछ गति खो दी है, और तीसरी तिमाही में गति और धीमी हो गई है।

वैश्विक आर्थिक गतिविधि के हाल के उच्च आवृत्ति संकेतकों में, नौकरी की वृद्धि शुरू में प्रत्याशित की तुलना में कम हो रही है क्योंकि श्रम बाजार धीमा हो रहा है, बेरोजगारी दर बढ़ रही है और मजदूरी वृद्धि आसान हो रही है, हालांकि ऐतिहासिक रूप से उच्च आप्रवासन कुछ संतुलन प्रदान कर रहा है। उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण नौकरियों की उम्मीदों में गिरावट दिखाते हैं। इक्विटी की कीमतें अभी भी बढ़ी हुई हैं, लेकिन सितंबर की शुरुआत में एनवीडिया के स्टॉक गिरने से बाजार मूल्य में लगभग 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर का सफाया कर दिया, यह संकेत देते हुए कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) ओवरहाइप कम हो सकती है और उम्मीदें वास्तविकता का साथ पकड़ रही हैं। विदेशी निवेशकों ने भी एशियाई टेक शेयरों से आक्रामक रूप से निकासी की, हालांकि भारत ने प्राथमिक बाजार में रुचि खरीदने से समर्थित बिकवाली को रोक दिया है। प्रतिफल वक्र व्युत्क्रम उल्टे होने से अल्पकालिक प्रतिफल लंबी-अवधि के नीचे आ गया और स्वैप वक्र के साथ, वे सुझाव देते हैं कि मौद्रिक नीति में ढील देय है। कम प्रतिलाभ से वेंचर कैपिटल इकोसिस्टम भी खत्म हो रहे हैं। बिगड़ते व्यापक आर्थिक आंकड़ों से उत्पन्न अस्थिरता को दूर करने और उधार लेने और पुनर्वित्त लागत में गिरावट से लाभ उठाने के लिए कॉर्पोरेट ऋण की रिकॉर्ड मात्रा जारी की जा रही है। ओपेक प्लस ने योजनाबद्ध उत्पादन वृद्धि में देर करने का फैसला किया क्योंकि कच्चे तेल की कीमतें 10 सितंबर को 70 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल से नीचे आ गई थी, लेकिन यह अभी भी 2025 के दौरान निष्क्रिय आपूर्ति के प्रति दिन 2.2 मिलियन बैरल करने की योजना बना रहा है। इस बीच, गैर-ओपेक आपूर्ति तेजी से बढ़ रही है, और जैसा कि ऊर्जा एजेंसी ने अपनी सितंबर 2024 की रिपोर्ट में सचेत किया है, वैश्विक तेल की मांग तेजी से धीमी हो रही है - इलेक्ट्रिक वाहन पहले से ही प्रतिदिन 1.8 मिलियन बैरल तेल विस्थापित कर रहे हैं - और यह तेल बाजारों में बिकवाली को बढ़ावा दे रहा है। धातु बाजारों में, तांबा-स्वर्ण कीमत अनुपात 4 पर बंद हुआ- एक बढ़ता अनुपात उच्च औद्योगिक मांग को इंगित करता है और इसलिए सकारात्मक वृद्धि परिदृश्य है।

हालांकि ऊपर की ओर दबाव कम होने की संभावना है, अवस्फीति की गति सुस्त बनी हुई है, जिससे मौद्रिक नीति अधिकारियों के बीच सहजता की गति के बारे में सावधानी बरती जा रही है। वास्तव में, ईसीबी की गवर्निंग काउंसिल ने अपनी सितंबर की बैठक में उल्लेख किया कि मुद्रास्फीति के इस वर्ष के उत्तरार्ध में फिर से बढ़ने की अपेक्षा की जाती है, आंशिक रूप से क्योंकि ऊर्जा की कीमतों में पिछली तीक्ष्ण गिरावट वार्षिक दरों से बाहर हो जाएगी। इसलिए, यह आंका जाता है कि मुद्रास्फीति उच्च बनी हुई है क्योंकि मजदूरी अभी भी उच्च गति से बढ़ रही है। मुद्रास्फीति के समयबद्ध तरीके से 2 प्रतिशत मध्यावधि लक्ष्य पर लौटने का दृढ़ संकल्प व्यक्त करते हुए रिज़र्व बैंक ने नीतिगत दरों को तब तक सीमित रखने का निर्णय लिया जब तक इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए जरूरी हो। अमेरिका में, यह तर्क दिया जाता है कि अवस्फीति में फेड की मामूली सफलता जोखिम में है क्योंकि अमेरिका मौद्रिक प्रभुत्व के शासन से राजकोषीय प्रभुत्व[2] की ओर बढ़ रहा है। वास्तव में, अमेरिकी ट्रेजरी की ऋण जारी करने की कार्यनीति अप्रत्यक्ष ब्याज दर में कटौती प्रदान कर सकती है, जो फेडरल फंड्स दर में एक प्रतिशत की कटौती के बराबर है, जिसमें अल्पकालिक बिलों के माध्यम से उठाए गए नए ऋण का 70 प्रतिशत है। सब कुछ, "हमारे ज्ञान की सीमाएं ... विनम्रता और एक पूछताछ की भावना की मांग करती हैं जो अतीत से सबक सीखने और उन्हें हमारी वर्तमान चुनौतियों के लिए लचीले ढंग से लागू करने पर केंद्रित है।"[3]

गंभीर स्थिति को देखते हुए, नवीनतम विश्व व्यापार संगठन (डबल्यूटीओ) गुड्स ट्रेड बैरोमीटर के अनुसार, बढ़ते

[2] लाइवमिंट, "फेड अब शहर में एकमात्र खेल नहीं है" 31 अगस्त, 2024। https://www.livemint.com/economy/the-fed-is-no-longer-the-only-game-in-town-11725044399193.html

[3] फेडरल रिज़र्व बैंक ऑफ कैनसस सिटी, जैक्सन होल, व्योमिंग द्वारा 23 अगस्त 2024 को प्रायोजित आर्थिक संगोष्ठी में "समीक्षा और आउटलुक" पर पॉवेल जे का भाषण।

भू-राजनीतिक तनाव, चल रहे क्षेत्रीय संघर्षों, उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (एई) में मौद्रिक नीति को बदलने और निर्यात आदेशों को कमजोर करने के बीच, वैश्विक व्यापारिक व्यापार की मात्रा 2024 की तीसरी तिमाही में ठीक होती रही। जैसा कि खंड II में बताया गया है, इलेक्ट्रॉनिक्स के उप-प्रदर्शन को छोड़कर, वैश्विक व्यापार के अन्य घटक जैसे ऑटोमोटिव उत्पाद, कंटेनर शिपिंग और हवाई मालभाड़ा सभी दृढ़ता से प्रवृत्ति से ऊपर हैं, लेकिन नए निर्यात ऑर्डर कम हो रहे हैं, और कच्चे माल में गिरावट आई है – जो आगे बढ़ने के लिए चिंता का कारण है। डब्ल्यूटीओ के अनुसार, वैश्विक व्यापार वृद्धि अगले दो वर्षों में धीरे-धीरे बढ़ने की उम्मीद है क्योंकि कम मुद्रास्फीति और बढ़ती आय वास्तविक मजदूरी को बढ़ाती है और आयात सहित वस्तुओं की मांग को बढ़ावा देती है। पण्य वस्तु व्यापार की मात्रा में 2024 में 2.6 प्रतिशत और 2025 में 3.3 प्रतिशत की वृद्धि होने की उम्मीद है। वाणिज्यिक सेवाओं के व्यापार और डिजिटल रूप से वितरित सेवाओं के लिए भी दृष्टिकोण सकारात्मक है। व्यापार वृद्धि में एशिया का सबसे बड़ा योगदान होगा। 2025 के लिए दृष्टिकोण अधिक सकारात्मक है, जिसमें सभी क्षेत्र निर्यात और आयात वृद्धि में योगदान करते हैं, लेकिन इस पूर्वानुमान के जोखिम पर्याप्त हैं। अपनी 2024 विश्व व्यापार रिपोर्ट में, विश्व व्यापार संगठन ने तर्क दिया है कि व्यापार अधिक समावेशी वैश्विक अर्थव्यवस्था बनाने के समाधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनकर वैश्विक विकास के चक्र को बढ़ाने में मदद करता है। फिर भी, कुछ अर्थव्यवस्थाएं और क्षेत्र व्यापार के वृद्धि करने वाले गुणों का उपयोग करने में विफल रहे हैं क्योंकि वे वैश्विक अर्थव्यवस्था में पर्याप्त रूप से एकीकृत नहीं हैं या क्योंकि वे उच्च व्यापार लागत, कमजोर संस्थागत क्षमता, बुनियादी ढांचे की कमी और कुछ प्रकार की व्यापार नीतियों जैसे सुरक्षात्मक टैरिफ से चुनौतियों के बीच कम मूल्य वाली अतिरिक्त या अत्यधिक अस्थिर वस्तुओं का निर्यात करने तक सीमित हैं। उदाहरण के लिए, यह माना जाता है कि भू-राजनीतिक विचारों पर बड़े सौदों का युग समाप्त हो रहा है। महत्वपूर्ण धातुओं को सुरक्षित करने और सेमीकंडक्टर और हरित प्रौद्योगिकियों में वर्चस्व की लड़ाई उत्तरोत्तर विघटनकारी होती जा रही है।

इस पृष्ठभूमि में, डब्ल्यूटीओ अर्थव्यवस्थाओं के भीतर समावेशिता का विस्तार करने और अर्थव्यवस्थाओं में एक दूसरे में बराबरी बनाए रखने और आय अभिसरण की सुविधा के लिए एक खुली, नियम-आधारित और पूर्वानुमानित बहुपक्षीय प्रणाली को बढ़ावा देने का मौका प्रदान करता है। हालाँकि, अन्य लोगों का तर्क है कि विवैश्वीकरण एक मिथक है जो वास्तविक बदलावों को छुपाता है।[4] यह 2024 की शुरुआत से विश्व व्यापार के नए सिरे से विस्तार में स्पष्ट है, महामारी के बाद जब आपूर्ति श्रृंखला में रुकावट खत्म हुई और उपभोक्ताओं ने वस्तुओं से सेवाओं की ओर रुख किया, तो सुधार हुआ। वास्तविक बदलावों में से एक यह है कि उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) के लिए निर्यात वृद्धि महामारी से पहले ही एई से कहीं अधिक हो गई है, जिससे पता चलता है कि वैश्वीकरण वास्तव में जारी है। एक और बदलाव वस्तुओं के वैश्विक व्यापार और औद्योगिक उत्पादन के अनुपात में है, जिसमें गिरावट आ रही है और इसे विवैश्वीकरण के रूप में पढ़ा जा रहा है। हालाँकि, यह मुख्य रूप से चीन की घटना है। इस अनुपात की, जब चीन को छोड़कर गणना की जाती है, तो यह बढ़ रहा है और महामारी के बाद के सुधार की वजह से तेज हो गया है। यह वर्तमान में अपने दीर्घकालिक रुझान से ऊपर है। इस प्रकार, जो हो सकता है वह विवैश्वीकरण के बजाय व्यापार के पैटर्न में भौगोलिक बदलाव है। फिर भी एक अन्य कारक कार्गो आवाजाही का कंटेनरीकरण है जिसने वैश्विक परिवहन के एक नए युग की शुरुआत की है। यद्यपि यह वैश्विक समुद्री व्यापार की मात्रा का केवल लगभग 17 प्रतिशत है, लेकिन यह तेजी से बढ़ता हुआ खंड एशिया के नेतृत्व में मूल्य के हिसाब से वैश्विक व्यापार का लगभग दो-तिहाई हिस्सा है।

एक अन्य गंभीर चुनौतीपूर्ण गतिविधि में जिसे 'बाकी के उदय' के रूप में वर्णित किया गया है, ईएमई एई से अधिक ऐसी वृद्धि दर का निर्माण कर रहे हैं जो 15 वर्षों में नहीं देखी गई है अनुमानों से पता चलता है कि चीन के अलावा अन्य ईएमई का अनुपात, जिसमें प्रति व्यक्ति जीडीपी अमेरिका की तुलना में तेजी से बढ़ने की संभावना है, पिछले पांच वर्षों में 48 प्रतिशत से बढ़कर अगले पांच वर्षों में 88 प्रतिशत हो जाएगी।[5] इन ईएमई का बजट और चालू खाता घाटा अमेरिका की तुलना में बहुत

[4] बादेर क्लाउज़, डीग्लोबलाइज़ेशन का मिथक वास्तविक बदलावों को छुपाता है, फाइनेंशियल टाइम्स, 23 अगस्त 2024।

[5] शर्मा, रुचिर, पूंजीवाद के साथ क्या गलत हुआ, एलन लेन, 2024।

कम है, जिससे उनके पास निवेश करने और भविष्य में वृद्धि की अधिक क्षमता है। आने वाले दशक में, उनके निर्यात विशेष रूप से हरित प्रौद्योगिकियों और उन्हें बनाने के लिए आवश्यक कच्चे माल के लिए मजबूत होने की संभावना है, जैसे लिथियम और तांबा जो मुख्य रूप से उनके द्वारा आपूर्ति की जाती हैं। एआई बूम पहले से ही ताइवान और कोरिया जैसे मौजूदा आपूर्तिकर्ताओं से चिप्स के निर्यात को बढ़ावा दे रहा है, और भारत, मलेशिया और मैक्सिको जैसे देशों में निवेश बढ़ रहा है। कॉर्पोरेट आय अमेरिका में 10 प्रतिशत के मुकाबले इन ईएमई में 19 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ रही है और वे अप्रैल-जून 2024 तिमाही में आय के पूर्वानुमान में भी आगे हैं। नतीजतन, लाभ मार्जिन में भी सुधार हुआ है। उनके शेयर बाजार इस पुनरुद्धार से प्रभावित हो रहे हैं और उनमें से कुछ में, यह घरेलू निवेशकों के एक मजबूत और तेजी से बढ़ते आधार द्वारा संचालित है। हाल की अवधि में, अमेरिकी डॉलर में गिरावट आई है; जिसके कारण ऐतिहासिक रूप से, उभरते बाजारों में अधिक पूंजी प्रवाह हुआ है। निवेशकों को ईएमई को एक ही आस्ति वर्ग के व्यापक दायरे में सीमित करने की संभावना नहीं है - वे सितारों के एक चुनिंदा समूह की तलाश करेंगे जो वैश्विक व्यापार, अमेरिकी डॉलर, आर्थिक सुधारों और राजनीतिक परिवर्तन में बन रहे अनुकूल रुझानों से ताकत हासिल करने में सक्षम हैं। "वे गुमनामी से उभरते हैं, और जितनी गहरी छायाओं से वे निकलते हैं, उतना ही अधिक नाटक उनकी वापसी में होता है।"[6]

घरेलू गतिविधियों और उभरते जोखिमों को देखें तो, केवल निराशा के बजाय 2024-25 की पहली तिमाही में भारत के सकल घरेलू उत्पाद की धीमी गति की अधिक समझ की आवश्यकता है। जैसा कि खंड III में बताया गया है, घरेलू वाहक - निजी खपत और सकल निश्चित निवेश - मजबूत थे और सकल निर्यात जीडीपी के समर्थन में क्रमिक रूप से सकारात्मक रहे। ति1 में जीडीपी की मौसमी रूप से समायोजित गति मजबूत थी। सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) वृद्धि वास्तव में पहली तिमाही में क्रमिक रूप से बढ़ी, लेकिन सब्सिडी में वृद्धि – केंद्र सरकार द्वारा 3.6 प्रतिशत और राज्यों द्वारा 26 प्रतिशत – जीडीपी में दिखने वाली वृद्धि को बराबर कर देती है।

[6] द फाइनेंशियल टाइम्स, "द वर्ल्ड शुड टेक नोटिस - द रेस्ट आर राइजिंग अगेन", 24 अगस्त, 2024

घरेलू खपत दूसरी तिमाही में तेजी से बढ़ने की ओर अग्रसर है क्योंकि हेडलाइन मुद्रास्फीति कम हो रही है, ग्रामीण मांग में बढ़ोतरी पहले से ही जोर पकड़ रही है। शीघ्र विक्रेय/ खपत वाली उपभोक्ता वस्तुओं (एफएमसीजी) की मांग भी बढ़ रही है क्योंकि कंपनियां बढ़ती दीर्घायु और संपन्नता के बदौलत स्वस्थ जीवन शैली उत्पादों के साथ पुराने ग्राहकों को लक्षित करती हैं और युवा लोगों को प्रीमियमाइजेशन के साथ। त्योहारी सीजन से पहले न केवल महानगरों में बल्कि टियर 2 और टियर 3 शहरों में भी ई-कॉमर्स की बड़ी कंपनियों द्वारा हायरिंग में बढ़ोतरी से खपत को बढ़ावा मिला है। परिवहन, भंडारण और वितरण गतिविधियों में वृद्धि का समर्थन करने के लिए लॉजिस्टिक्स हायरिंग भी बढ़ रही है। टीमलीज सर्विसेज के अनुसार, दूरसंचार, इंटरनेट सेवा प्रदाताओं और संबद्ध उद्योगों की लगभग 62 प्रतिशत कंपनियां इस वर्ष में अपने कार्यबल का विस्तार करने का इरादा रखती हैं।

निवल निर्यात के संबंध में, बढ़ते व्यापार घाटे और भारतीयों द्वारा विदेश यात्रा में तेजी से चालू खाता शेष को जनवरी-मार्च 2024 में थोड़े से अधिशेष से 2024-25 की पहली छमाही में सकल घरेलू उत्पाद के 1-1.2 प्रतिशत के घाटे में बदलने की संभावना है। पोर्टफोलियो ऋण प्रवाह, निवल एफडीआई और अनिवासी जमाराशियों के रूप में पूंजी प्रवाह सहजतापूर्ण वित्तपोषण प्रदान कर रहे हैं। 2024 में एशिया-प्रशांत क्षेत्र में विलय और अधिग्रहण सौदे कम हो रहे हैं, लेकिन भारत मात्रा में वृद्धि के साथ एक उज्ज्वल स्थान के रूप में उभरा है।

आपूर्ति पक्ष पर, कृषि को 2024-25 की पहली तिमाही में नुकसान उठाना पड़ा क्योंकि भारत ने 2024 की गर्मियों में सबसे अधिक तेज़ गर्म दिनों का अनुभव किया, जो 2010 में पिछले उच्च स्तर को पार कर गया। इसलिए, कृषि क्षेत्र के विकास की नीति-संचालित प्राथमिकता का महत्व है, विशेष रूप से जलवायु आघात-सहनीयता, उत्पादकता, नवाचार और मूल्य वर्धित निर्यात पर ध्यान केंद्रित करना। 50 प्रतिशत के वैश्विक औसत की तुलना में केवल लगभग 25 प्रतिशत कृषि निर्यात संसाधित किए जाते हैं। भारत में उत्पादन करने और निर्यात करने के लिए बड़ी, विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी फर्मों को आकर्षित करने से मजबूत भारतीय ब्रांड विकसित हो सकते हैं, वैश्विक बाजार में उपस्थिति बढ़ सकती है, रोजगार पैदा हो सकता है और किसानों की आय बढ़

सकती है। इसके अलावा, एग्रीस्टैक जैसे हस्तक्षेप – एक किसान-केंद्रित डिजिटल बुनियादी ढांचा – किसान जनसांख्यिकी, भूमि जोत, फसल बुवाई, पशुधन स्वामित्व और योजनाओं और लाभों के विवरण पर व्यापक और प्रमाणित डेटाबेस तैयार करेगा। कृषि निर्णय समर्थन प्रणाली एक व्यापक भू-स्थानिक प्रणाली प्रदान करने के लिए फसलों, मिट्टी, मौसम और जल संसाधनों पर जानकारी को एकीकृत करेगी।

पहली तिमाही में कृषि के कमजोर प्रदर्शन की भरपाई एक उत्साही विनिर्माण क्षेत्र और आघात-सहनीय सेवाओं द्वारा की गई। वास्तव में, परिचालन लाभ में निरंतर वृद्धि और ब्याज खर्चों में मंदी ने कॉर्पोरेट ब्याज कवरेज अनुपात को 9-तिमाही के उच्च स्तर को छूने में सक्षम बनाया, जो आने वाले वर्ष के लिए अच्छा है। कार्यशील पूंजी चक्र की भारी कमी का भी सबूत है - वह समय जो कंपनी वर्तमान आस्तियों जैसे इन्वेंट्री को बिक्री में बदलने में लेती है। ऑनलाइन भुगतान में वृद्धि ने कार्यशील पूंजी के इस बेहतर उपयोग में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिसे औपचारिकता में वृद्धि से समर्थन प्राप्त है। इससे पता चलता है कि कार्यशील पूंजी आगे चलकर लाभप्रदता में बड़ी भूमिका निभा सकती है।

वित्तीय बाजारों में बदलाव हो रहा है। प्राथमिक इक्विटी बाजार में, छोटे और मध्यम उद्यमों (एसएमई) के प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्तावों (आईपीओ) में रुचि बढ़ गई है, जिसमें घरेलू म्यूचुअल फंड भी शामिल हैं, जिसमें बड़े पैमाने पर ओवरसब्सक्रिप्शन है। निवेशकों को आवंटित आईपीओ शेयरों का 54 प्रतिशत लिस्टिंग के एक सप्ताह के भीतर बेच दिया गया।[7] सितंबर आईपीओ – मेनबोर्ड और एसएमई – के लिए 14 वर्षों में सबसे व्यस्त महीना होने वाला है, जिसमें अब तक 28 से अधिक कंपनियां बाजार में प्रवेश कर चुकी हैं। सूचीबद्ध कंपनियों की बढ़ती संख्या पूंजी जुटाने के लिए योग्य संस्थागत स्थानन की ओर रुख कर रही है, जिसका अनुमान 2024 के पहले आठ महीनों में लगभग ₹60,000 करोड़ है। वैश्विक संकेतों पर रुक-रुक कर सुधार के साथ, द्वितीयक बाजार में बेंचमार्क सूचकांक बढ़ गए हैं, और परिदृश्य तेज़ी का बना हुआ है।

वैश्विक फंड मई 2024 से लगातार पांचवें महीने भारतीय कर्ज़ बाज़ार में भारी निवेश कर रहे हैं। दूसरी ओर, प्रतिफल में कमी के बावजूद वित्त वर्ष के दौरान कॉरपोरेट ऋण निर्गम अब तक कम रहा क्योंकि जारीकर्ता अमेरिकी दर में कटौती का इंतजार कर रहे थे।

ऋण बाजार में, जमा संग्रहण एक चुनौती बन गया है, ऐसे में बैंक निधियन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जमा प्रमाणपत्रों पर बहुत अधिक निर्भर बने हुए हैं ताकि जमा वृद्धि में कमी ऋण को बाधित न करे। बैंक जमा पर उच्च ब्याज दरों की पेशकश कर रहे हैं, जिसमें दो-तिहाई से अधिक सावधि जमा 7 प्रतिशत और उससे अधिक अर्जित करते हैं। तथापि, ऋण और जमा वृद्धि के बीच का अंतर कम होने लगा है। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां तेजी से ऑफशोर बॉण्ड की ओर रुख कर रही हैं। सूक्ष्म वित्त संस्थानों को आस्ति गुणवत्ता से जुड़ी कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिससे ऋण वृद्धि की रफ्तार धीमी पड़ रही है।

चूंकि बड़े जोखिम पूंजी निवेशक सावधानी से चलते हैं, शुरुआती चरण के निवेश परिदृश्य में सूक्ष्म उद्यम पूंजी फर्मों और संस्थापक-द्वारा फंडों की बढ़ती संख्या देखी जा रही है। विनियमित वित्तीय प्रणाली के साथ परस्पर संबंध के बारे में एहतियात और चिंताओं के बावजूद, निजी ऋण के फुटप्रिंट - उच्च प्रतिफल वाले और अतरल ऋण जैसे साधनों में गैर-बैंक ऋण - धीरे-धीरे उधारकर्ताओं की अनुकूलित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विस्तार कर रहे हैं जो पूंजी के पारंपरिक स्रोतों से कम हैं। मोटे अनुमान के अनुसार निजी ऋण आस्तियां प्रबंधन के अधीन लगभग 15 बिलियन अमरीकी डालर हैं। फिनटेक ऋणदाता, जिनके बारे में बताया जाता है कि उन्होंने व्यक्तिगत ऋणों के बाजार हिस्सेदारी का 52 प्रतिशत से अधिक पर कब्जा कर लिया है, तेजी से धन जुटाने और उधार स्रोतों में विविधता लाने के लिए निजी ऋण की ओर रुख कर रहे हैं। क्रेडिट मंदी में निजी ऋण की आघात-सहनीयता, हालांकि, अप्रयुक्त रहती है।

हेडलाइन सीपीआई मुद्रास्फीति अगस्त रीडिंग में लगातार दूसरे महीने रिज़र्व बैंक के लक्ष्य से नीचे आ गई। यह एक सकारात्मक विकास है, खासकर जब सूचकांक जुलाई और

[7] सेबी अध्ययन (2024), "प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ) में निवेशक व्यवहार का विश्लेषण", आर्थिक और नीति विश्लेषण विभाग, सितंबर।

अगस्त के बीच सपाट रहा है। सब्जियों की कीमतों के कुछ आघात उलटने लगे हैं, और यदि यह जारी रहता है और व्यापक होता है, तो 2024-25 की पहली तिमाही में खाद्य मुद्रास्फीति के विकास की विशेषता वाली दृढ़ता हमारे सामने होगी। प्रतिकूल आधार प्रभाव सितंबर अंक को परेशान कर सकता है। ओपेक से संबंधित घटनाक्रम और पहले की कमजोर मांग को देखते हुए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों का परिदृश्य नरम हो गया है और इसे बरकरार रखा जा सकता है। मौद्रिक नीति समिति के अगस्त 2024 के प्रस्ताव में निर्धारित 2024-25 की दूसरी छमाही में हेडलाइन मुद्रास्फीति की औसत 4.5 प्रतिशत की संभावनाओं में सुधार हुआ है। बहरहाल, हाल के अनुभव के आलोक में, खाद्य कीमतों में अस्थिरता एक आकस्मिक जोखिम बनी हुई है।

इस पृष्ठभूमि में, शेष आलेख को चार खंडों में संरचित किया गया है। खंड II में वैश्विक अर्थव्यवस्था में तेजी से विकसित हो रहे विकास को शामिल किया गया है। घरेलू समष्टि आर्थिक स्थितियों का आकलन खंड III में निर्धारित किया गया है। खंड IV भारत में वित्तीय स्थितियों को समाहित करता है, जबकि अंतिम खंड में निष्कर्ष है।

II. वैश्विक व्यवस्था

श्रम बाजारों में कमी के वातावरण, चल रहे भू-राजनीतिक तनाव और कमोडिटी की कीमतों में गिरावट के कारण वैश्विक वृद्धि का परिदृश्य अनिश्चित हो गया है। हालांकि, प्रमुख केंद्रीय बैंकों द्वारा मौद्रिक नीति में नरमी की बढ़ती उम्मीदें सॉफ्ट लैंडिंग के बारे में विश्वास पैदा करना जारी रखती हैं। हमारा मॉडल-आधारित तात्कालिक पूर्वानुमान 2024 की तीसरी तिमाही के दौरान वैश्विक वृद्धि की गति में कमी की ओर इशारा करता है (चार्ट II.1)।

वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला दबाव सूचकांक (जीएससीपीआई) अगस्त 2024 में बढ़ा, जो नवंबर 2023 के बाद पहली बार अपने ऐतिहासिक औसत से ऊपर उठा (चार्ट II.2ए)। यद्यपि अगस्त 2024 में अनुक्रमिक कमी के साथ मध्य पूर्व एशिया में जारी तनाव के कारण भू-राजनीतिक जोखिम उच्च बने रहे (चार्ट II.2बी)। आपूर्ति व्यवधानों ने कंटेनर शिपिंग लागत को ऊंचा रखा है, हालांकि उन्होंने जुलाई में दर्ज किए गए चरम स्तरों से अगस्त-सितंबर 2024 के दौरान कुछ कमी दर्ज की (चार्ट II.2सी)।

उपभोक्ता भावना भौगोलिक क्षेत्रों में अलग-अलग थी, पांच महीनों में पहली बार अमेरिका में बढ़ रही थी जबकि यूरो क्षेत्र में यह खराब हो गई थी (चार्ट II.3सी)। एई और ईएमई दोनों में वित्तीय स्थितियों में सहजता आई (चार्ट II.3बी)।

चार्ट II.1: वैश्विक जीडीपी वृद्धि का तात्कालिक पूर्वानुमान (ति-द-ति)

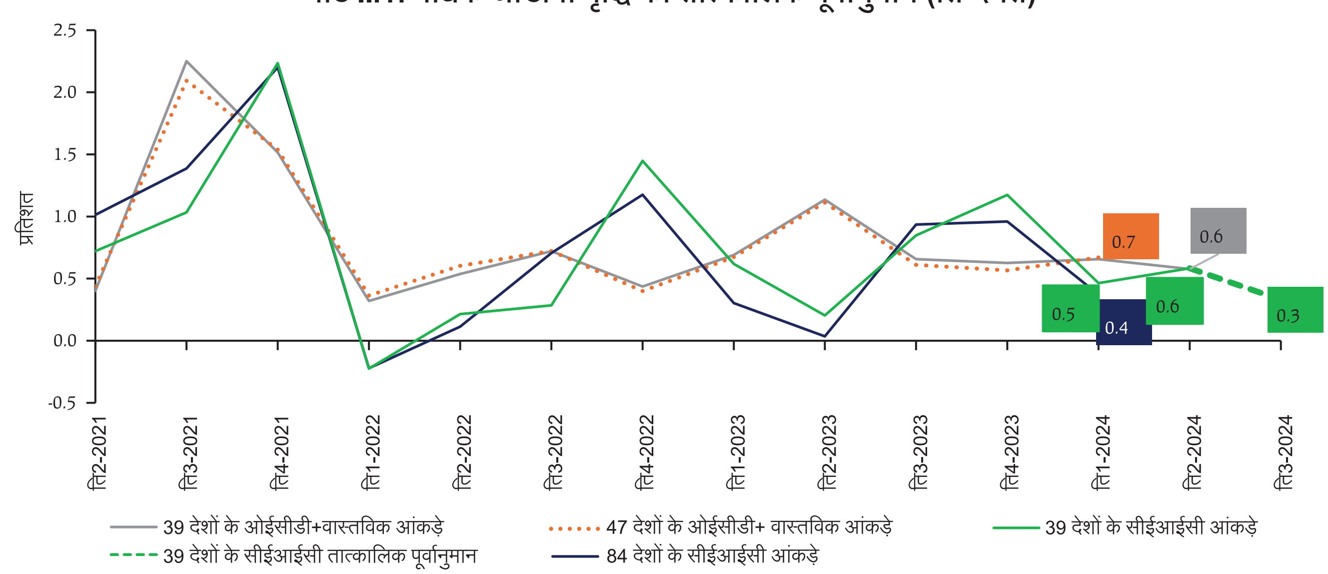

स्रोत : सीईआईसी; ओईसीडी; आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

चार्ट II.2: भू-राजनीतिक जोखिम और वैश्विक आपूर्ति शृंखला दबाव में रुझान

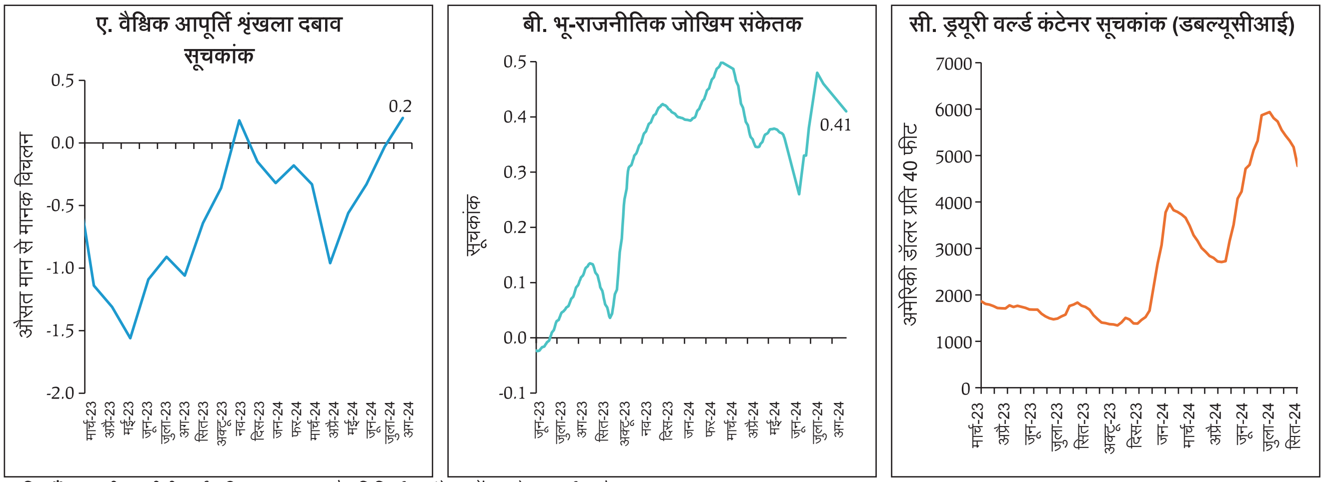

टिप्पणियाँ: 1. जीएससीपीआई परिवहन लागत और विनिर्माण संकेतकों पर डेटा दर्शाता है।
2. ड्रयूरी द्वारा साप्ताहिक मूल्यांकन किया गया डब्ल्यूसीआई प्रमुख पूर्व-पश्चिम व्यापार मार्गों के लिए वास्तविक स्पॉट कंटेनर माल ढुलाई दरों की रिपोर्ट करता है। समग्र 8 शिपिंग मार्गों की मात्रा के भारित औसत को 40-फुट कंटेनर प्रति अमेरिकी डॉलर के रूप में दर्शाता है।

स्रोत: फ़ेडरल रिज़र्व बैंक ऑफ़ न्यूयॉर्क; ब्लैकरॉक इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूट, अगस्त 2024; और ब्लूमबर्ग।

वैश्विक समग्र क्रय प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) विनिर्माण में कमी से सेवा गतिविधि में एक मजबूत विस्तार के साथ अगस्त में मामूली रूप से बढ़ा (चार्ट II.4)। जबकि सेवा पीएमआई जून 2023 के बाद से नए बिज़नेस में अधिक लाभ से प्रेरित रहा, नए ऑर्डर और आउटपुट वृद्धि में संकुचन के कारण अगस्त में विनिर्माण पीएमआई आठ महीने के निचले स्तर पर गिर गया।

निर्यात आदेशों के लिए समग्र पीएमआई अगस्त में तेज दर से घट गया (चार्ट II.5)। हालांकि सेवाओं के मामले में नए निर्यात में तेज गति से विस्तार हुआ, लेकिन अगस्त 2024 में विनिर्माण निर्यात ऑर्डर में स्पष्ट रूप से गिरावट आई जिससे कुल निर्यात में संकुचन हुआ।

अगस्त 2024 में वैश्विक कमोडिटी की कीमतें कम हो गईं। ब्लूमबर्ग कमोडिटी सूचकांक में अगस्त में 0.4 प्रतिशत (म-द-म)

चार्ट II.3: उपभोक्ता भाव और वित्तीय स्थितियां

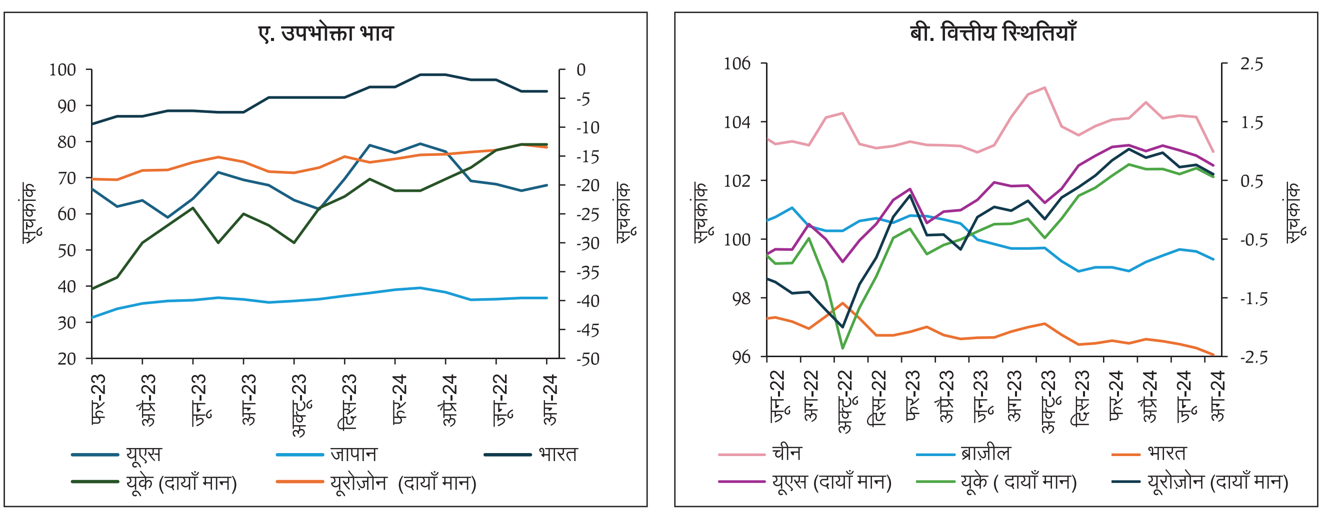

टिप्पणियाँ: 1. जापान: 50 से ऊपर का स्कोर उपभोक्ता आशावाद को दर्शाता है, 50 से नीचे उपभोक्ता विश्वास की कमी को दर्शाता है और 50 तटस्थता को दर्शाता है।
2. यूरोज़ोन और यूके: -100 आत्मविश्वास की अत्यधिक कमी का संकेत देता है, 0 तटस्थता को दर्शाता है जबकि 100 अत्यधिक आत्मविश्वास को दर्शाता है।
3. भारत और अमेरिका: सूचकांक का मान जितना अधिक होगा, उपभोक्ता विश्वास उतना ही अधिक होगा।

स्रोत: ब्लूमबर्ग।

चार्ट II.4 : वैश्विक पीएमआई

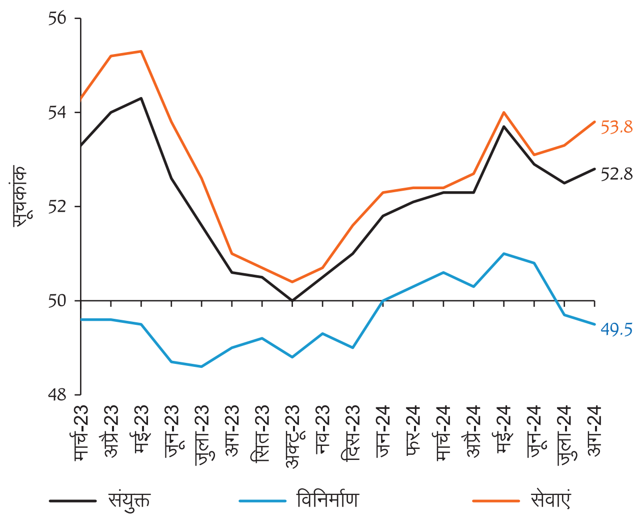

टिप्पणी: 50 का स्तर गतिविधि में कोई बदलाव नहीं होने और 50 से ऊपर की रीडिंग विस्तार और इसके विपरीत दर्शाते हैं।
स्रोत: एस एंड पी वैश्विक।

चार्ट II.5: वैश्विक पीएमआई: निर्यात आदेश

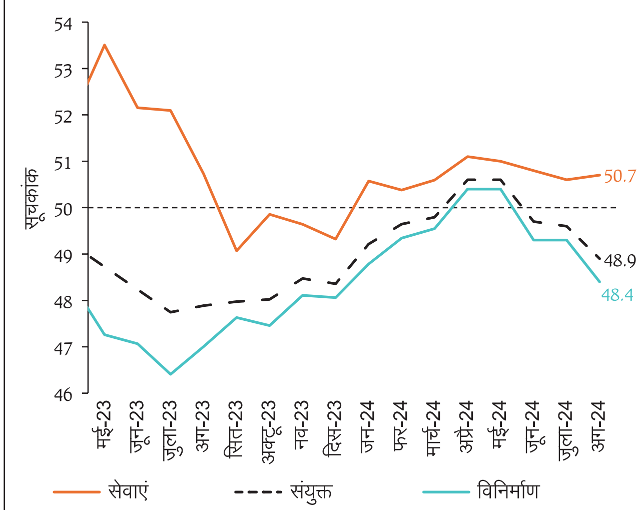

टिप्पणी: 50 का स्तर गतिविधि में कोई बदलाव नहीं होने और 50 से ऊपर की रीडिंग विस्तार और इसके विपरीत दर्शाते हैं।
स्रोत: एस एंड पी वैश्विक।

की गिरावट आई (चार्ट II.6ए)। अगस्त में ब्रेंट कच्चे तेल की कीमतों में 1.9 प्रतिशत (म-द-म) की गिरावट आई क्योंकि कमजोर मांग लीबिया में तेल नाकाबंदी के कारण आपूर्ति व्यवधान की भरपाई से अधिक थी (चार्ट II.6बी)। सितंबर की शुरुआत में तेल की

चार्ट II.6: कमोडिटी और खाद्य कीमतें

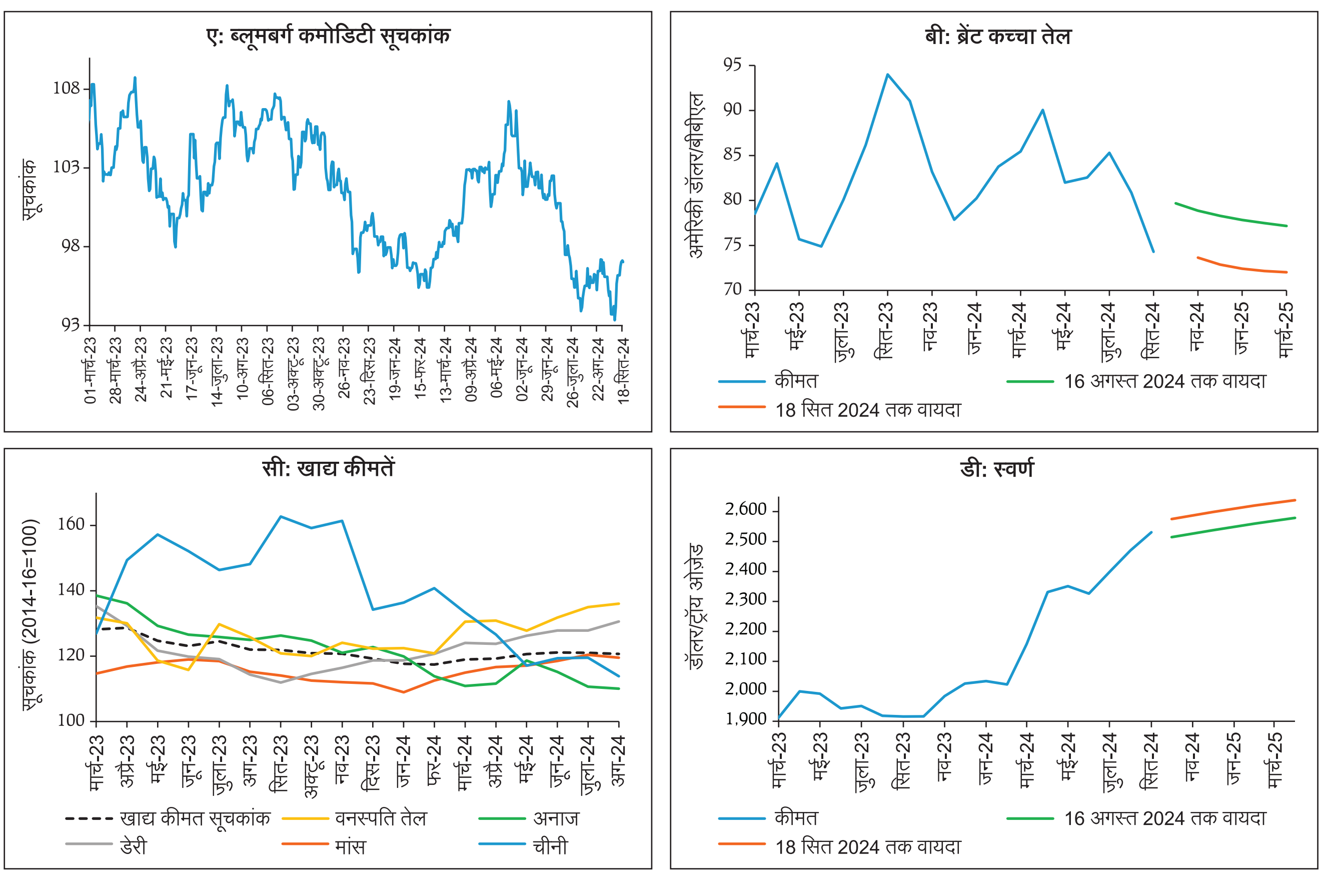

स्रोत: ब्लूमबर्ग; वर्ल्ड बैंक पिंक शीट; और एफएओ।

कीमतों में गिरावट जारी रही, जो दिसंबर 2021 के बाद पहली बार 70 अमेरिकी डॉलर से नीचे गिर गई क्योंकि मांग की भावना कमजोर होती रही। खाद्य और कृषि संगठन (एफ़एओ) के खाद्य मूल्य सूचकांक ने अगस्त 2024 में मामूली गिरावट दर्ज की क्योंकि चीनी, मांस और अनाज के मूल्य सूचकांकों में कमी वनस्पति तेलों और डेयरी उत्पादों में वृद्धि से अधिक है (चार्ट II.6सी)। हालांकि, अगस्त में स्वर्ण की कीमतों में 4.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो भू-राजनीतिक तनाव के बीच दर में कटौती और सुरक्षित स्थान की मांग के बारे में अपेक्षाओं से समर्थित थी (चार्ट II.6डी)।

प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति में गिरावट आई, हालांकि धीमी और असमान गति से। अमेरिका में, सीपीआई मुद्रास्फीति अगस्त में घटकर 2.5 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) हो गई, जो जुलाई में 2.9 प्रतिशत थी। हालांकि, अमेरिकी हेडलाइन व्यक्तिगत उपभोग व्यय (पीसीई) मुद्रास्फीति जुलाई में 2.5 प्रतिशत पर स्थिर रही। अनुमान के अनुसार यूरो क्षेत्र की मुद्रास्फीति अगस्त में घटकर 2.2 प्रतिशत रह गई, जो जुलाई में 2.6 प्रतिशत थी। यूके में हेडलाइन मुद्रास्फीति अगस्त में 2.2 प्रतिशत पर स्थिर रही, जबकि जापान में मुद्रास्फीति (ताजा खाद्य को छोड़कर सीपीआई) 2.8 प्रतिशत तक बढ़ गई (चार्ट II.7ए)। ईएमई के बीच, चीन में मुद्रास्फीति बढ़ी, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका में कम हुई, और अगस्त में रूस में स्थिर रही (चार्ट II.7बी)। प्रमुख एई में कोर और सेवाओं की मुद्रास्फीति नीचे की ओर बढ़ी, हालांकि यह हेडलाइन से अधिक रही (चार्ट II.7सी और 7डी)।

बिक्री मूल्यों के लिए वैश्विक स्फीतिकारी दबावों में गिरावट को पीएमआई द्वारा भी मापा जाता है (चार्ट II.8)। वैश्विक स्तर पर, वस्तुओं और सेवाओं के लिए ली जाने वाली कीमतें अगस्त 2024 में लगभग चार वर्षों में सबसे धीमी दर से बढ़ीं।

वैश्विक इक्विटी बाजारों ने अगस्त के पहले सप्ताह में भारी बिकवाली से सुधार किया क्योंकि प्रमुख केंद्रीय बैंकों द्वारा दरों में कटौती की उम्मीदों ने आर्थिक गतिविधि को धीमा करने पर

चार्ट II.7: मुद्रास्फीति – एई और ईएमई

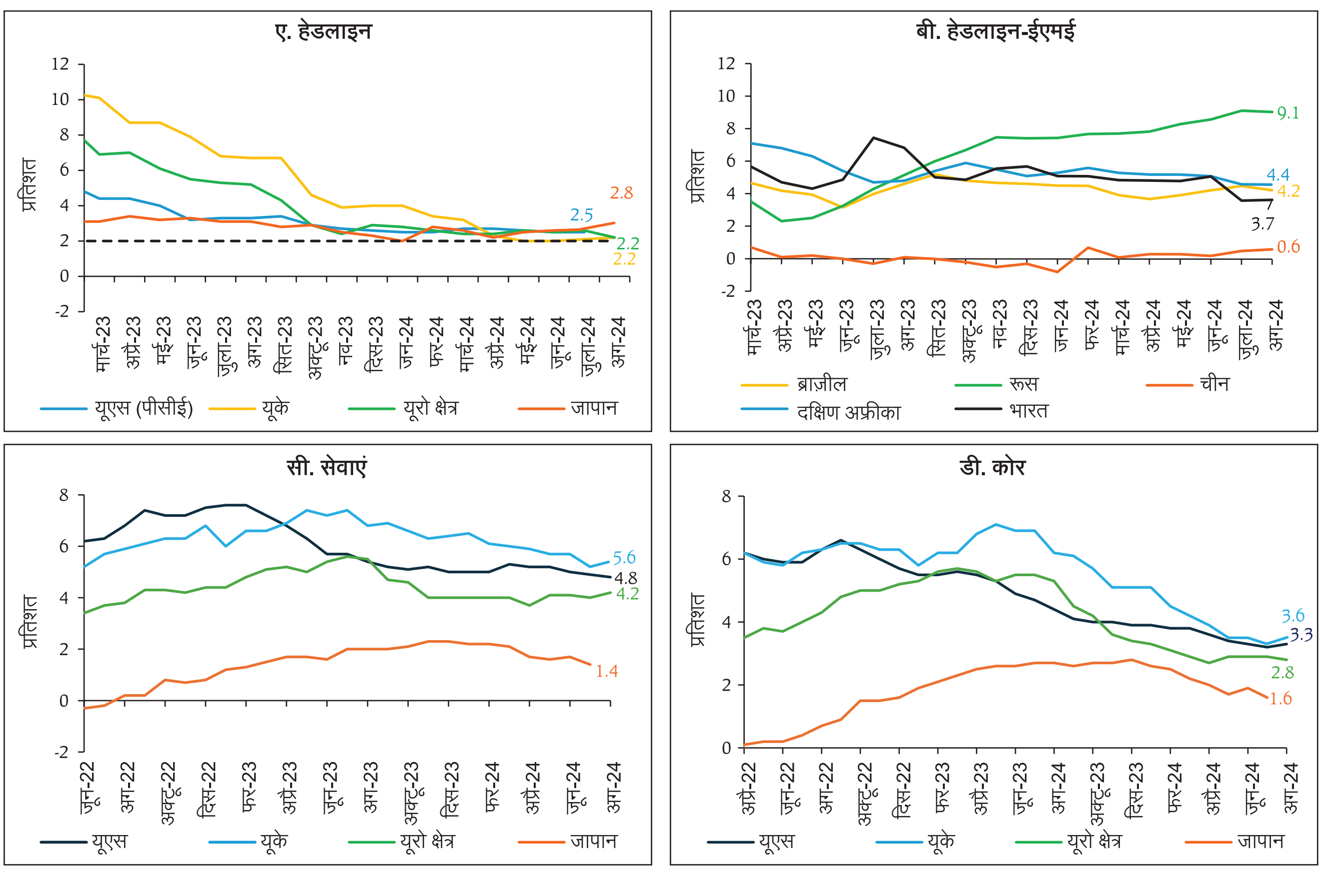

स्रोत: ब्लूमबर्ग; और ओईसीडी।

चार्ट II.8: वैश्विक पीएमआई-बिक्री कीमत

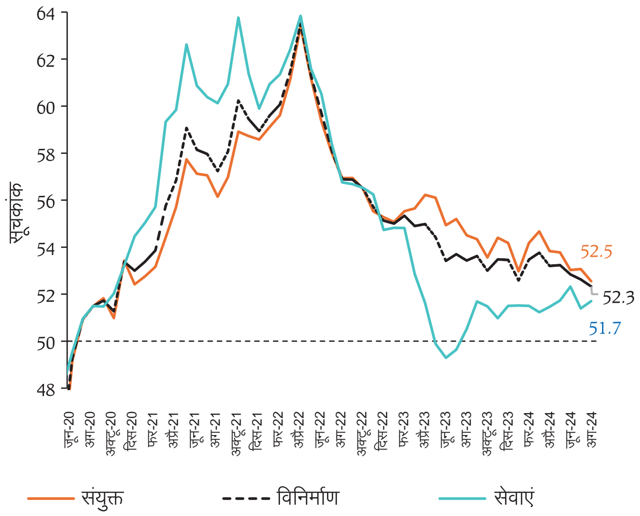

टिप्पणी: 50 का स्तर गतिविधि में कोई बदलाव नहीं होने और 50 से ऊपर की रीडिंग विस्तार और इसके विपरीत दर्शाते हैं।
स्रोत: एस एंड पी वैश्विक।

चिंताओं को पीछे छोड़ दिया। तदनुसार, मॉर्गन स्टेनली कैपिटल इंटरनेशनल (एमएससीआई) विश्व सूचकांक ने अगस्त में म-द-म में 2.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की (चार्ट II.9ए)। अमेरिका में कमजोर श्रम बाजार के आंकड़ों से प्रेरित सितंबर के पहले सप्ताह में मंदी के बाद, इक्विटी बाजारों ने उम्मीद से बेहतर अमेरिकी सीपीआई डेटा जारी होने के बाद सितंबर के बाकी हिस्सों में अपनी बढ़त जारी रखी।

अगस्त में 10-वर्षीय और 2-वर्षीय बॉण्ड पर अमेरिकी सरकार की प्रतिभूतियों के प्रतिफल क्रमशः 13 आधार अंक और 32 आधार अंक हो गए। प्रतिफल वक्र व्युत्क्रम (10-वर्ष और 2-वर्षीय प्रतिफल के बीच नकारात्मक स्प्रेड) सितंबर की शुरुआत में उल्टा होने लगा क्योंकि वित्तीय बाजारों ने दर में कटौती की अपेक्षाओं को ध्यान में रखा (चार्ट II.9 बी)।

मुद्रा बाजारों में, पिछले सप्ताह में कुछ मजबूती के बावजूद, अगस्त में अमेरिकी डॉलर 2.3 प्रतिशत कमजोर हो गया। इसके साथ ही, पूंजी प्रवाह के कारण अगस्त में ईएमई के लिए एमएससीआई मुद्रा सूचकांक में 2.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई (चार्ट II.9सी और II.9डी)।

चार्ट II.9: वैश्विक वित्तीय बाजार

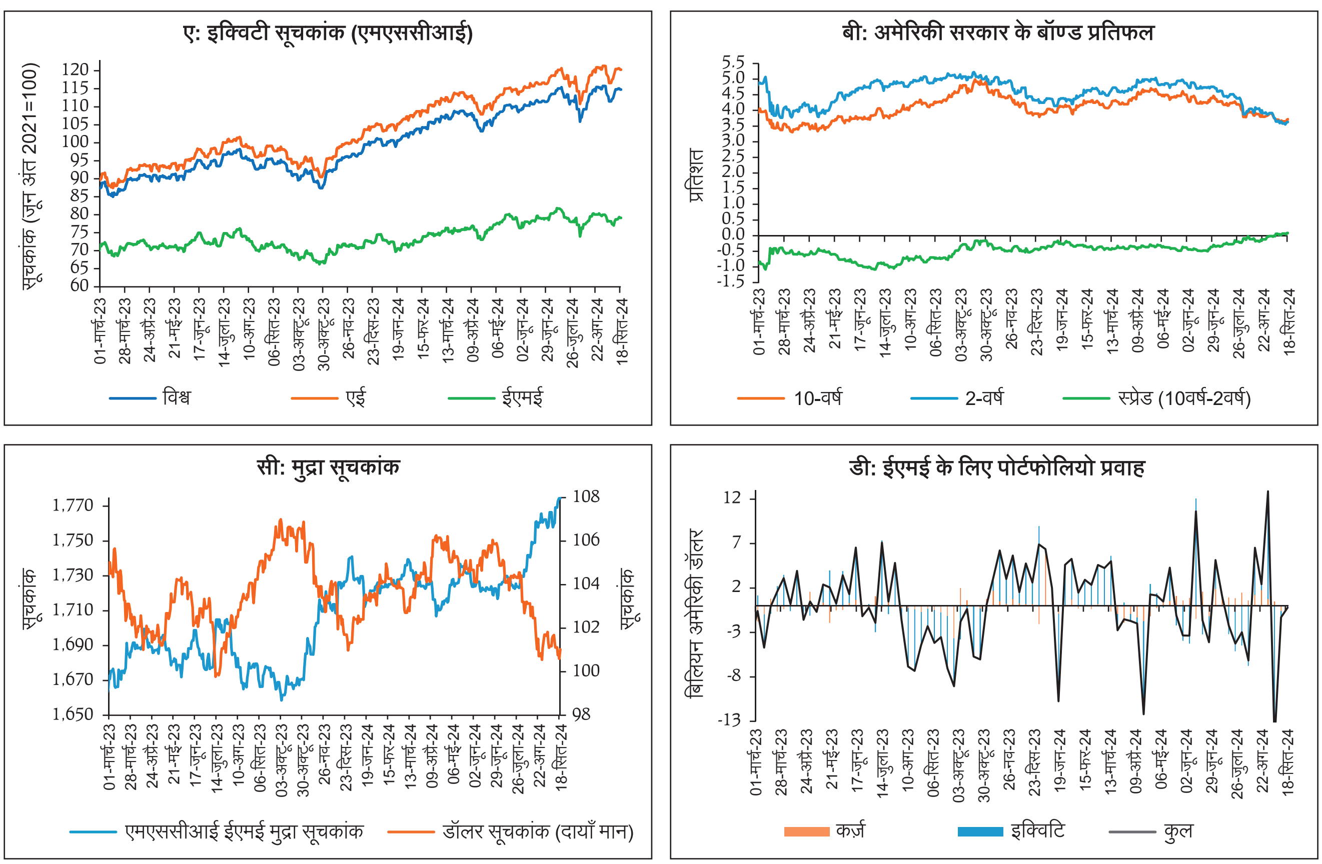

स्रोत: ब्लूमबर्ग; और अंतर्राष्ट्रीय वित्त संस्थान (आईआईएफ)।

चार्ट II.10: वीआईएक्स सूचकांक

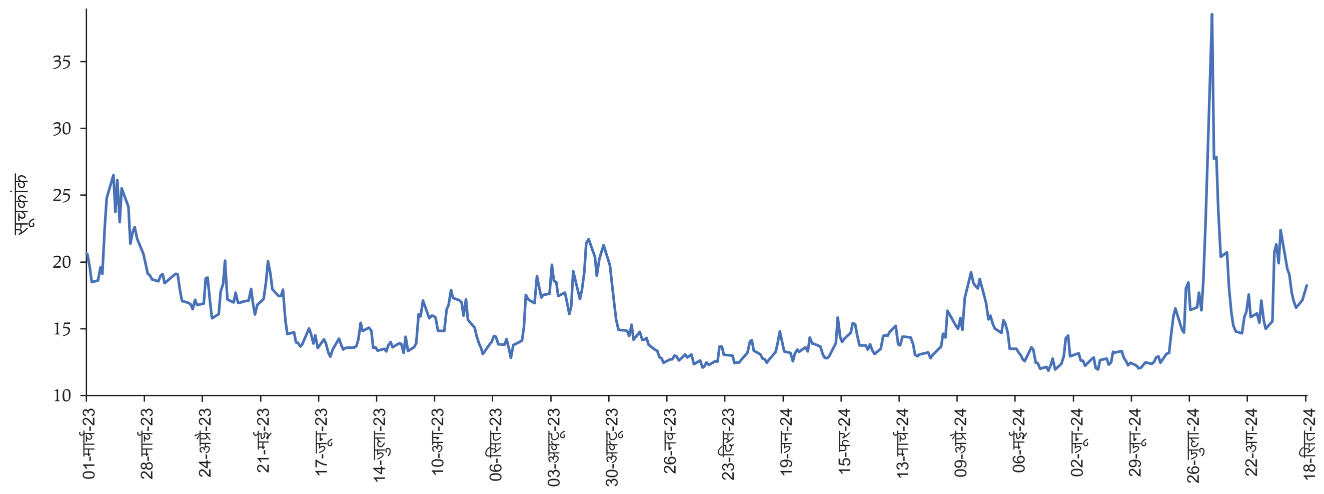

टिप्पणी: वीआईएक्स सूचकांक एक वित्तीय बेंचमार्क है जिसे एस एंड पी 500 सूचकांक की अपेक्षित अस्थिरता के एकदम हर एक मिनट के बाज़ार अनुमान के लिए डिज़ाइन किया गया है और इसकी गणना रीयल-टाइम एस एंड पी 500 सूचकांक (एसपीएक्स) विकल्प बोली/पूछें उद्धरण के मध्य बिंदु का उपयोग करके की जाती है।
स्रोत: ब्लूमबर्ग।

येन कैरी ट्रेड के अनवाइंडिंग पर तेज वृद्धि के बाद अगस्त के उत्तरार्ध में अमेरिकी शेयर बाजार अस्थिरता सूचकांक (वीआईएक्स) में उल्लेखनीय गिरावट आई, हालांकि यह सितंबर के पहले सप्ताह में फिर से बढ़ गया (चार्ट II.10)।

एई केंद्रीय बैंकों में, यूएस फेड ने सितंबर में अपने लक्ष्य सीमा को 50 बीपीएस घटाकर 4.75-5.0 प्रतिशत कर दिया, जो चार वर्ष में पहली कटौती को चिह्नित करता है। ईसीबी और बैंक ऑफ कनाडा दोनों ने नीतिगत दरों में 25 आधार अंकों की कमी की, जबकि बीओई और जापान ने अपनी सितंबर की बैठकों में नीतिगत दरों को अपरिवर्तित रखा (चार्ट II.11ए)। न्यूजीलैंड ने अपनी अगस्त की बैठक में अपनी बेंचमार्क दर में 25 आधार अंकों की कटौती की, जो मार्च 2020 के बाद पहली कटौती को चिह्नित करता है जबकि स्वीडन और चेक गणराज्य ने अगस्त में नीतिगत दरों में कमी की थी। दूसरी ओर, इज़राइल, आइसलैंड, नॉर्वे और दक्षिण कोरिया जैसे अन्य एई केंद्रीय बैंकों ने अपनी नीतिगत दरों में यथास्थिति बनाए रखी। ईएमई केंद्रीय बैंकों में, चिली, पेरू और

चार्ट II.11: नीतिगत दरों में परिवर्तन

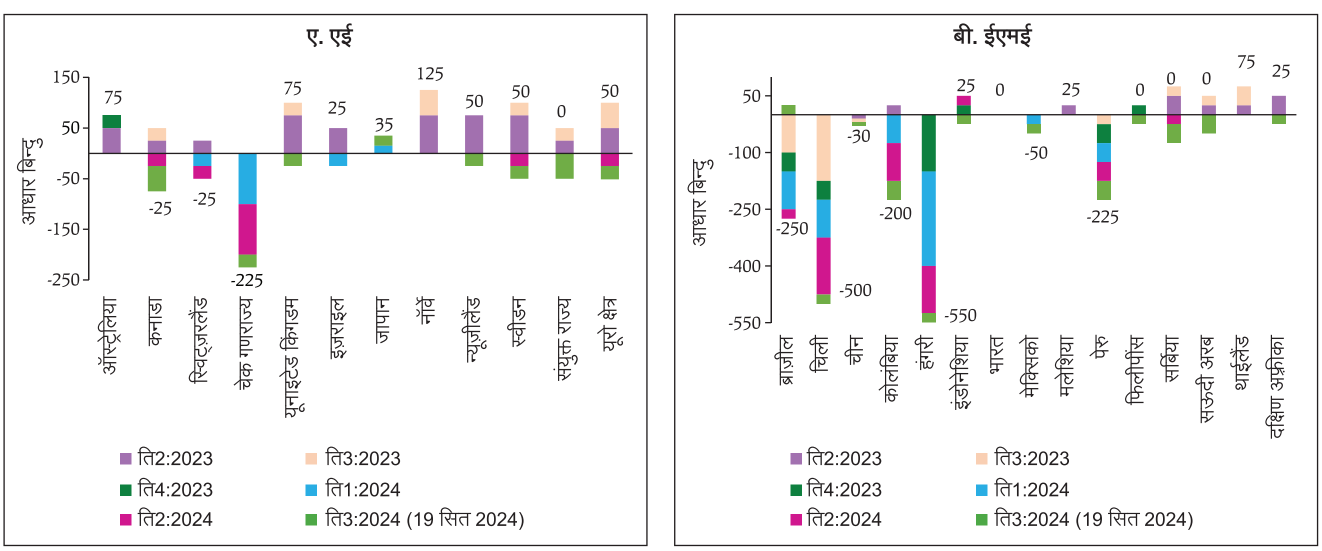

स्रोत: ब्लूमबर्ग; और आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

इंडोनेशिया ने सितंबर में अपनी प्रमुख दरों में 25 आधार अंकों की कटौती की, जबकि ब्राजील और रूस ने क्रमशः 25 आधार अंकों और 100 अंकों तक अपनी नीतिगत दरों में बढ़ोतरी की। फिलीपींस, मेक्सिको और रोमानिया ने अपनी अगस्त की बैठकों के दौरान अपनी प्रमुख दरों में 25 आधार अंकों की कमी की। (चार्ट II.11बी)।

III. घरेलू गतिविधियां

भारतीय अर्थव्यवस्था ने आपूर्ति श्रृंखला दबावों से विपरीत परिस्थितियों का अनुभव किया, जो ऐतिहासिक औसत स्तरों से ऊपर उठ गया (चार्ट III.1ए)। हमारा आर्थिक गतिविधि सूचकांक (ईएआई)[8], उच्च आवृत्ति संकेतकों की एक श्रृंखला के आधार पर, पिछली तिमाही के सापेक्ष गति में सुधार के आधार पर 2024-25 की दूसरी तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि 7.0 प्रतिशत होने का अनुमान लगाता है (चार्ट III.1बी और III.1सी)।

सारणी III.1: आधारभूत अनुमान

(व-द-व प्रतिशत में)

अवधि	जीडीपी वृद्धि	सीपीआई मुद्रास्फीति
ति3: 2024-25	8.4	4.4
ति4: 2024-25	6.6	4.6
वित्तीय वर्ष 2024-25	7.3	4.6
ति1: 2025-26	8.0	4.1
ति2: 2025-26	6.4	3.9
ति3: 2025-26	6.4	3.8
ति4: 2025-26	6.2	3.7
वित्तीय वर्ष 2025-26	6.7	3.9

स्रोत: आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

इन-हाउस डायनेमिक स्टोकेस्टिक जनरल इक्विलिब्रियम (डीएसजीई) मॉडल 2024-25 के दौरान जीडीपी वृद्धि 7.3 प्रतिशत (व-द-व) और हेडलाइन सीपीआई मुद्रास्फीति 4.6 प्रतिशत (व-द-व) अनुमानित करता है (सारणी III.1 और चार्ट III.2)। 2025-26 के दौरान, सकल घरेलू उत्पाद के 6.7 प्रतिशत

चार्ट III.1 : आर्थिक गतिविधि और जीडीपी वृद्धि का तात्कालिक पूर्वानुमान

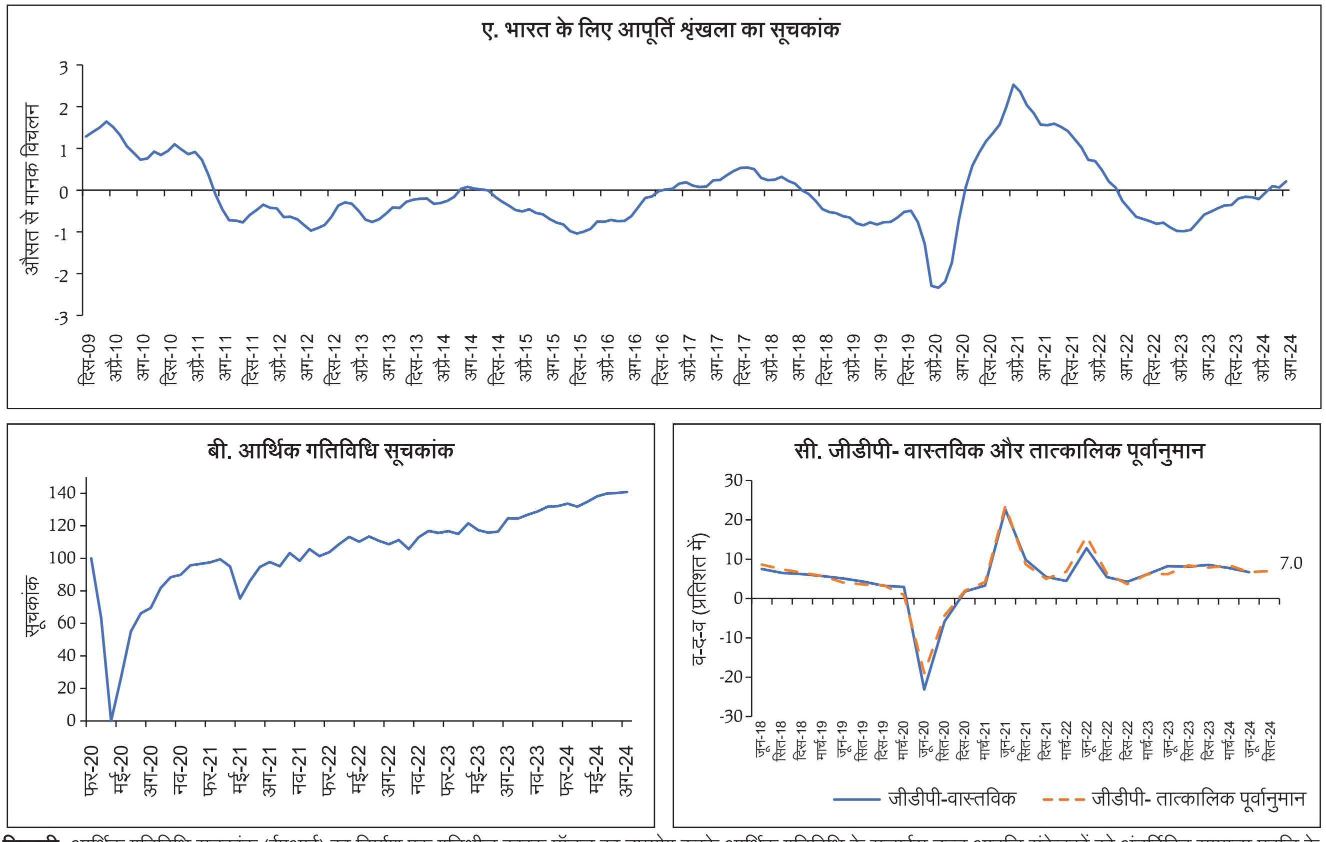

टिप्पणी: आर्थिक गतिविधि सूचकांक (ईएआई) का निर्माण एक गतिशील कारक मॉडल का उपयोग करके आर्थिक गतिविधि के सत्ताईस उच्च आवृत्ति संकेतकों को अंतर्निहित सामान्य प्रवृत्ति के आधार पर किया गया है। फरवरी 2020 में ईएआई को 100 और अप्रैल 2020 में 0 तक बढ़ाया गया, जो गतिशीलता प्रतिबंधों के कारण सबसे अधिक प्रभावित महीना था।
स्रोत: राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ); उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण (सीसीएस); आरबीआई; और आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

8 सूचकांक उद्योग, सेवाओं, वैश्विक और विविध गतिविधियों का प्रतिनिधित्व करने वाले 27 मासिक संकेतकों में अंतर्निहित गतिशील सामान्य कारक को दर्शाता है।

चार्ट III.2: जीडीपी वृद्धि और सीपीआई मुद्रास्फीति फैन चार्ट

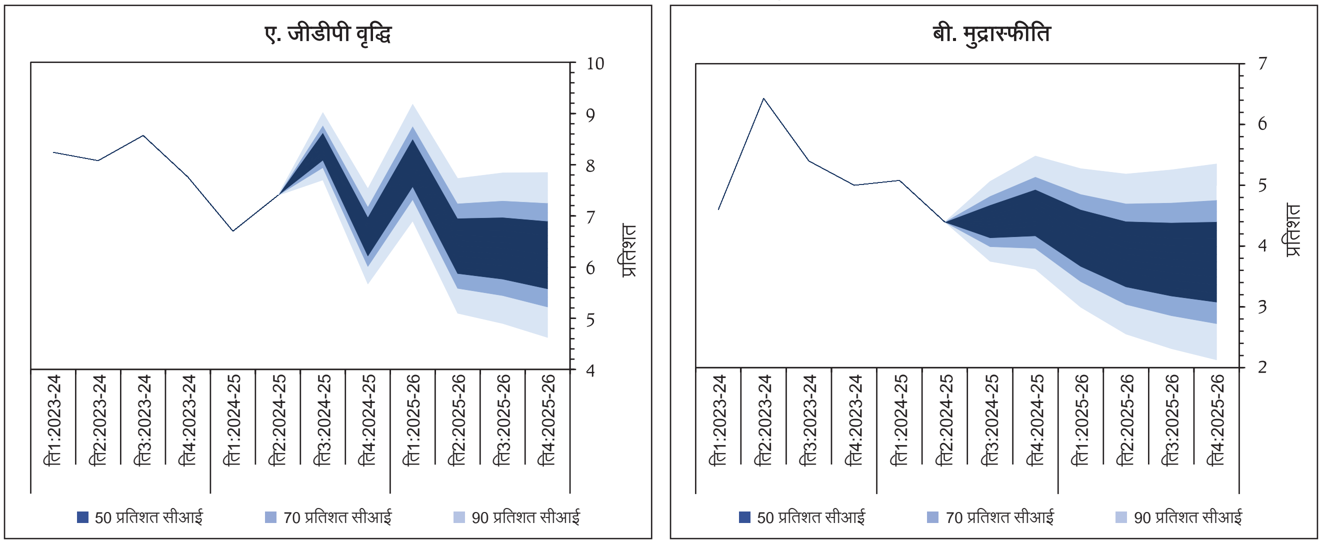

टिप्पणी: सीआई: विश्वास अंतराल।
स्रोत: आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

की दर से बढ़ने का अनुमान है, जिसमें हेडलाइन सीपीआई मुद्रास्फीति 3.9 प्रतिशत तक कम हो जाएगी।

सकल मांग

वास्तविक जीडीपी वृद्धि 2023-24 की पहली तिमाही के 8.2 प्रतिशत (ति4: 2023-24 में 7.8 प्रतिशत) के संबंध में ति1: 2024-25 में 6.7 प्रतिशत तक कम हो गई। वृद्धि में गिरावट आम चुनावों से पहले ति1: 2024-25 में सरकारी अंतिम उपभोग व्यय (जीएफ़सीई) में 0.2 प्रतिशत के संकुचन को दर्शाती है (चार्ट III.3)।

चार्ट III.3: जीडीपी वृद्धि में भारित योगदान

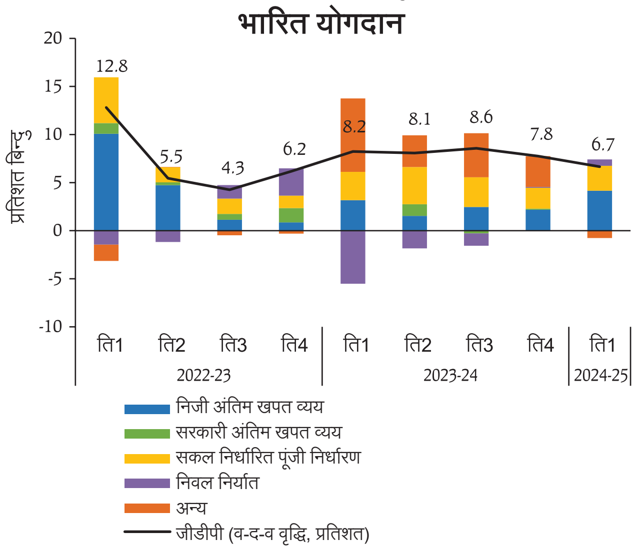

टिप्पणी: अन्य में स्टॉक, क़ीमती सामान और सांख्यिकीय विसंगतियों में परिवर्तन शामिल हैं।
स्रोत: एनएसओ।

निजी अंतिम उपभोग व्यय (पीएफसीई) की वृद्धि 2024-25 की पहली तिमाही में सात तिमाही के उच्च स्तर 7.4 प्रतिशत पर पहुंच गई, जिसका कारण आघात सहनीय शहरी मांग और ग्रामीण मांग की स्थिति में सुधार है। ति1: 2024-25 में सकल स्थिर पूंजी निर्माण (जीएफ़सीएफ़) में 7.5 प्रतिशत की वृद्धि ने जीडीपी में जीएफ़सीएफ़ की हिस्सेदारी को 34.8 प्रतिशत तक कर दिया – जो ति2: 2012-13 के बाद से सबसे अधिक है। बाहरी मोर्चे पर, ति1: 2024-25 में निर्यात में 8.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि आयात ने 4.4 प्रतिशत की अपेक्षाकृत मामूली वृद्धि दर्ज की। तदनुसार, निवल निर्यात ने ति1: 2024-25 में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में 0.7 प्रतिशत अंकों का सकारात्मक योगदान दिया।

उच्च-आवृत्ति संकेतक बताते हैं कि अगस्त 2024 में मांग अधिक रही, ई-वे बिल रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया, हालांकि पिछले महीने की तुलना में वृद्धि दर धीमी हो गई (चार्ट III.4ए)। हालांकि, अगस्त में टोल संग्रह पिछले महीने में 9.4 प्रतिशत (व-द-व) से घटकर 6.8 प्रतिशत (व-द-व) हो गया (चार्ट III.4बी)।

अगस्त 2024 में ऑटोमोबाइल बिक्री में 7.5 प्रतिशत (व-द-व) की वृद्धि दर्ज की गई, जिसमें दोपहिया वाहनों का योगदान रहा (चार्ट III.5ए)। लगातार तीन महीनों के विस्तार के बाद अगस्त में घरेलू ट्रैक्टर की बिक्री में 5.8 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की गिरावट आई (चार्ट III.5बी)। जुलाई में दोहरे अंकों की वृद्धि दर्ज करने के

चार्ट III.4: ई-वे बिल और टोल संग्रह

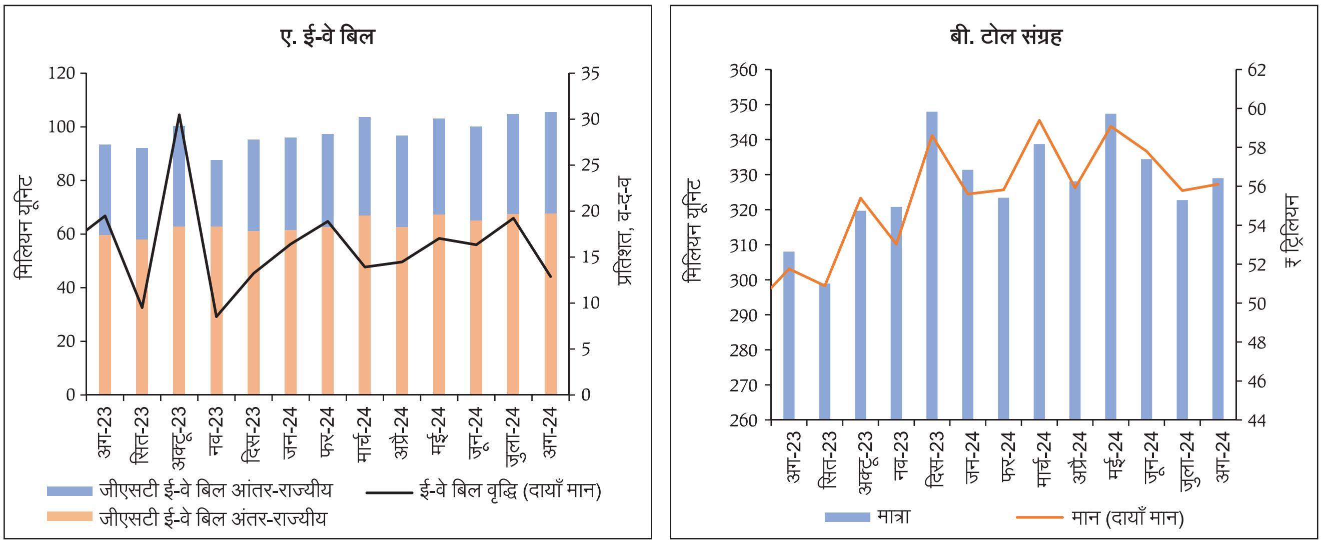

स्रोत: जीएसटीएन; आरबीआई।

बाद, परिवहन वाहन खंड में संकुचन के कारण अगस्त में वाहन पंजीकरण में कमी आई (चार्ट III.5सी)। अगस्त 2024 में औसत दैनिक पेट्रोलियम खपत में 2.6 प्रतिशत (व-द-व) की कमी आई, जो डीजल की खपत में गिरावट से प्रेरित थी (चार्ट III.5डी)।

चार्ट III.5: ऑटोमोबाइल क्षेत्र संकेतक

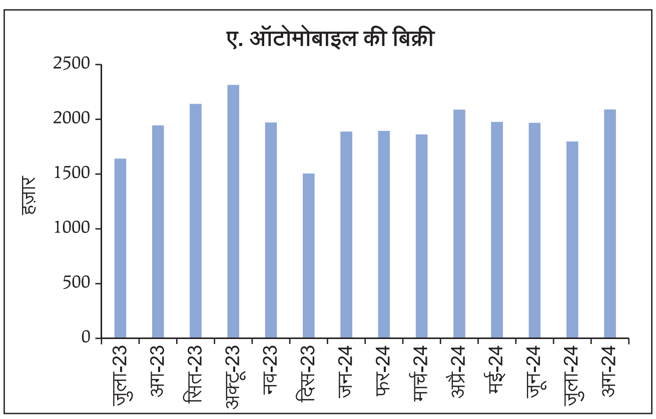

स्रोत: सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैनुफैक्चरर्स (सियाम)।

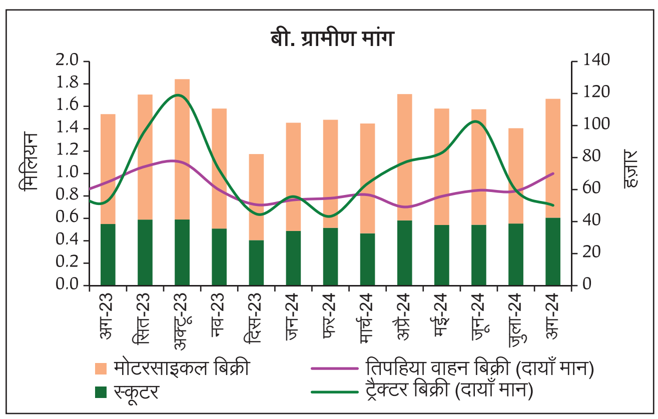

स्रोत: सियाम; और ट्रैक्टर मेकनाइज़ेशन एसोसिएशन (टीएमए)।

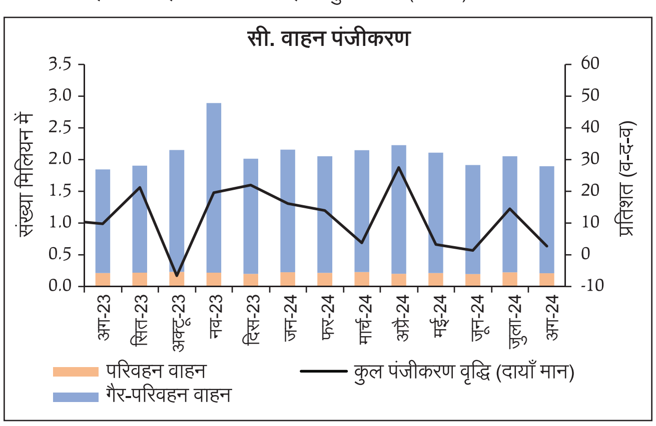

स्रोत: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय।

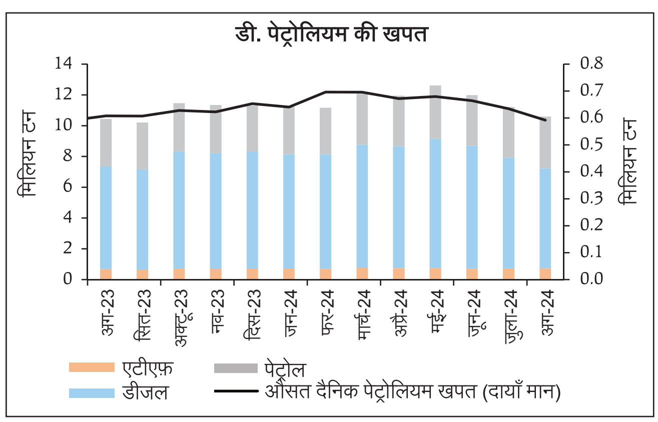

स्रोत: पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण प्रकोष्ठ।

2030 तक भारत के अद्यतन राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) लक्ष्यों[9] को पूरा करने के लिए, 2024-2030 की अवधि में सौर ऊर्जा, इलेक्ट्रोलाइज़र, पवन और बैटरी, और हरित हाइड्रोजन के लिए विनिर्माण क्षमता में आवश्यक निवेश का अनुमान 30 लाख करोड़ रुपये है। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजारों में निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों की संस्थाओं द्वारा अब तक 3.43 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के हरित बॉन्ड जारी किए गए हैं, जिसमें भारत सरकार के सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड (एसजीआरबी) सबसे बड़े योगदानकर्ता हैं (चार्ट III.6)।

रिज़र्व बैंक ने सौर-आधारित बिजली जनरेटर, बायोमास-आधारित बिजली जनरेटर, पवन चक्कियों, माइक्रो-हाइडल संयंत्रों और नवीकरणीय ऊर्जा-आधारित सार्वजनिक उपयोगिताओं जैसे उद्देश्यों के लिए ₹ 30 करोड़ की सीमा तक बैंक ऋण को प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के तहत शामिल किया है। 31 मार्च 2024 तक गैर-पारंपरिक ऊर्जा क्षेत्र के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) की ऋण सीमा ₹1.19 लाख करोड़ थी, जिसमें कुल बकाया ₹75,251 करोड़ था (चार्ट III.7)। इसके अलावा, भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड (आईआरईडीए), जो अक्षय ऊर्जा स्रोतों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है, का ऋण पोर्टफोलियो 2024 में अब तक जून तक ₹63,207 करोड़ तक पहुंच गया, जिसमें 33.9 प्रतिशत की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर्ज की गई। आगे देखें तो, आईआरईडीए ने वित्तीय वर्ष 2030 तक हरित वित्तपोषण को ₹1.36 लाख करोड़ तक विस्तारित करने की योजना बनाई है।

चार्ट III.6 : हरित बॉण्ड निर्गम

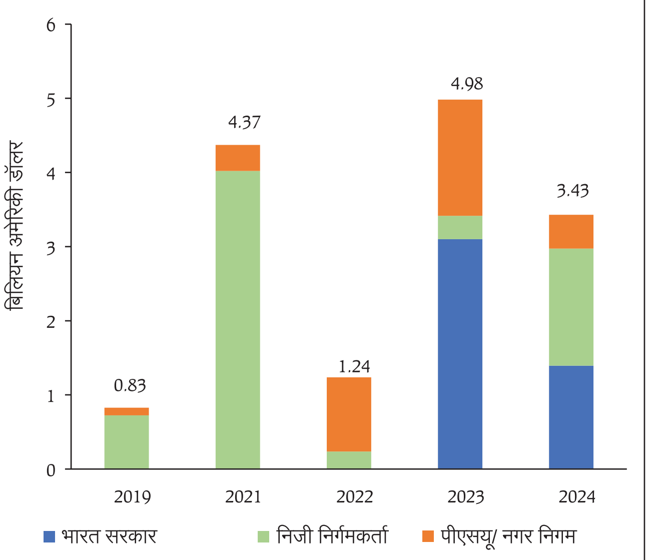

स्रोत : एकोना।

चार्ट III.7: एससीबी द्वारा गैर-पारंपरिक ऊर्जा क्षेत्र को ऋण

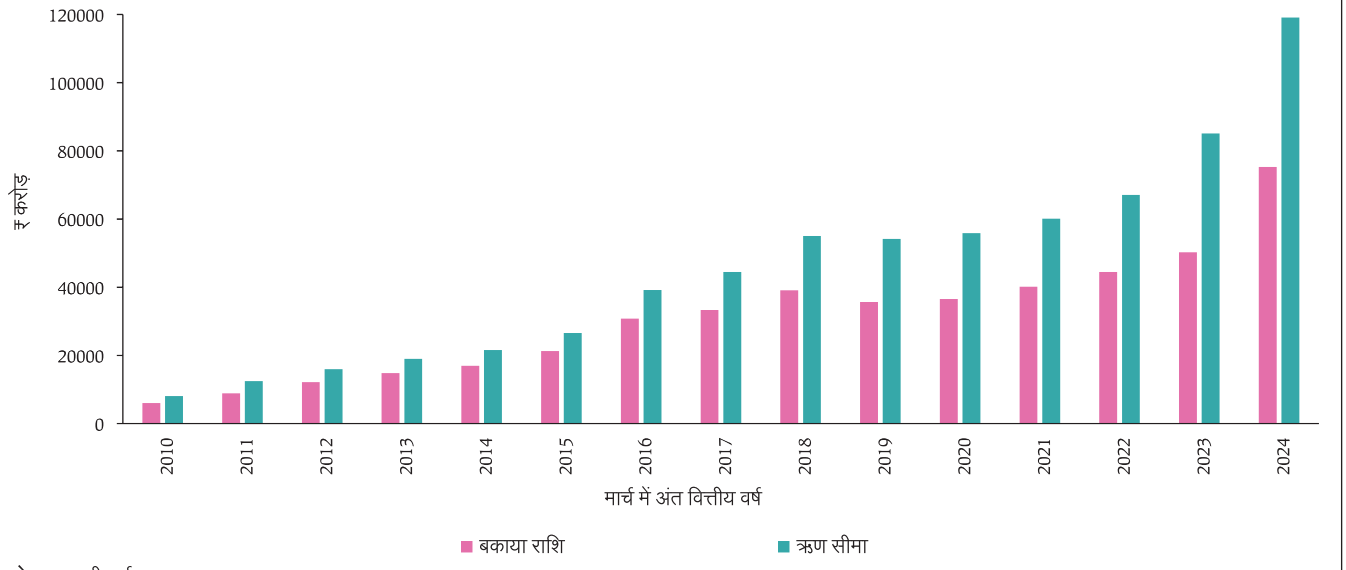

स्रोत : आरबीआई।

9 इनमें गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों जैसे सौर, पवन, पनबिजली की क्षमता बढ़ाना और दूसरों के बीच अतिरिक्त कार्बन सिंक का निर्माण शामिल है।

चार्ट III.8: इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकरण

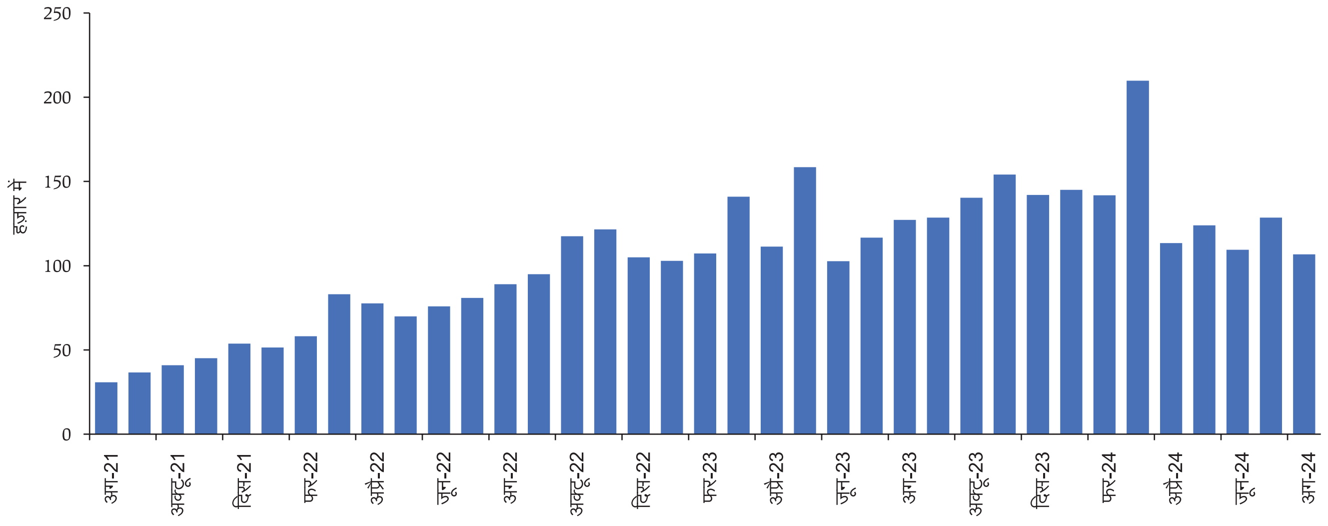

स्रोत: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय।

हाल के वर्षों में भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में तेजी आ रही है (चार्ट III.8)। इस प्रक्रिया को और तेज करने के लिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11 सितंबर 2024 को ₹10,900 करोड़ के परिव्यय के साथ इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट (पीएम ई-ड्राइव) योजना[10] को मंजूरी दी।

नवीनतम आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) डेटा[11] के अनुसार, शहरी भारत में श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) और श्रमिक जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) में पिछली तिमाही (जनवरी-मार्च 2024) की तुलना में अप्रैल-जून 2024 के दौरान मामूली गिरावट आई। अप्रैल-जून 2024 के दौरान शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर घटकर 6.6 प्रतिशत हो गई, जो पिछली तिमाही में 6.7 प्रतिशत थी (चार्ट III.9)। कुल रोजगार में नियमित वेतनभोगी

चार्ट III.9: पीएलएफएस तिमाही (आयु 15 और उससे अधिक)

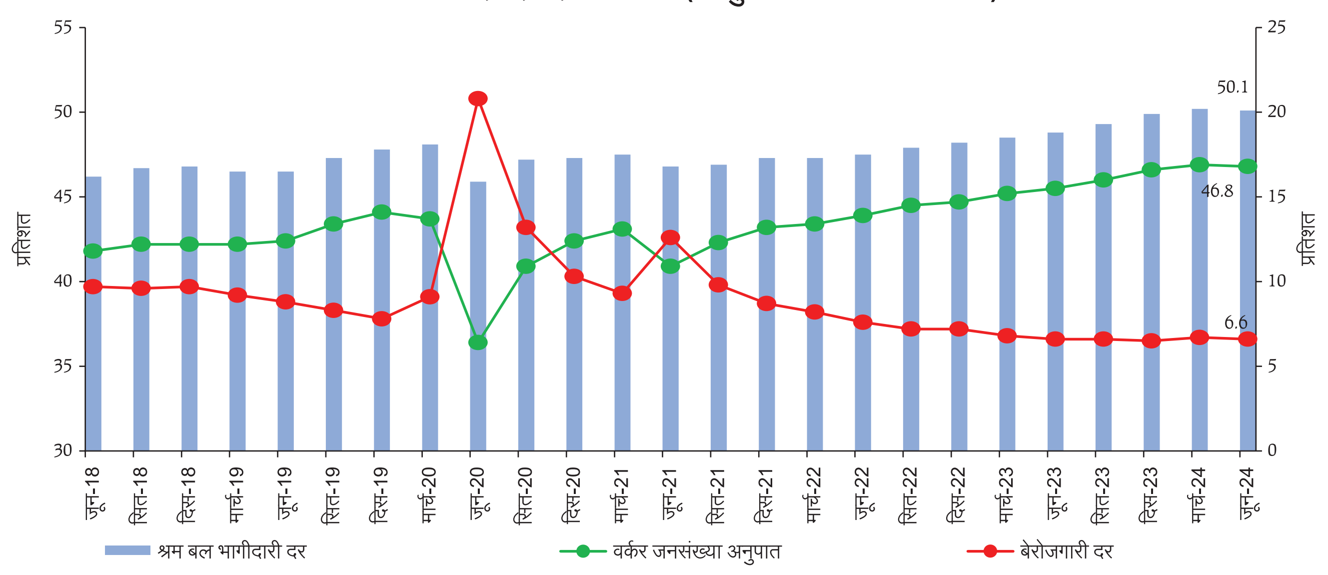

स्रोत : सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएस एंड पीआई)।

[10] https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=2053959.

[11] तिमाही बुलेटिन पीएलएफएस अप्रैल-जून 2024।

चार्ट III.10: पीएलएफ़एस तिमाही (श्रेणी और क्षेत्र के आधार पर रोजगार)

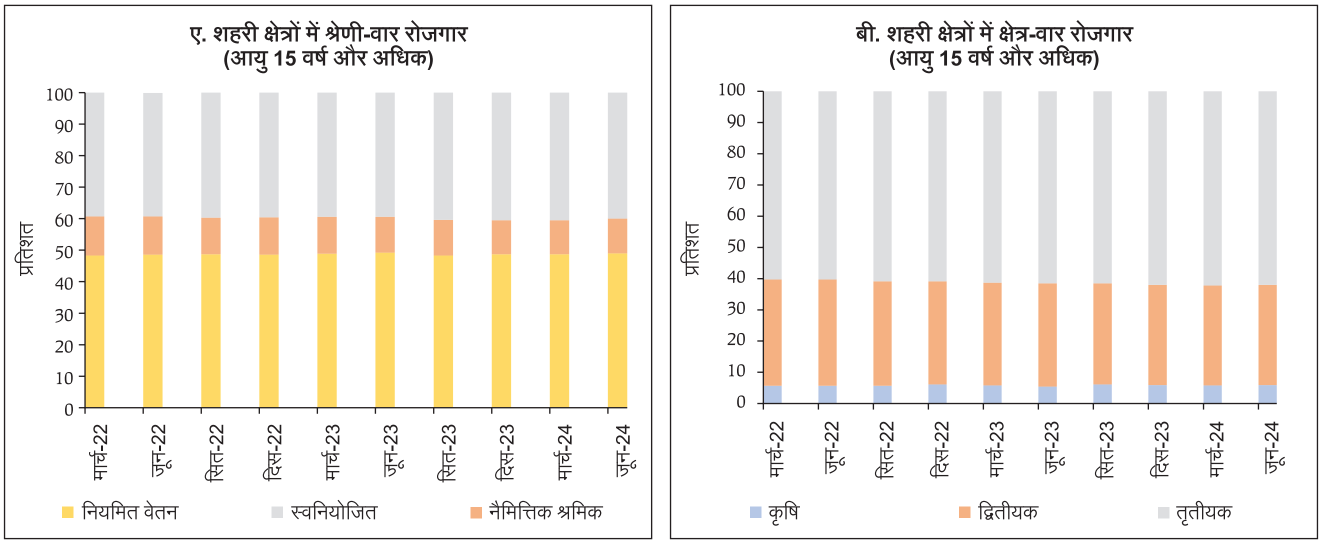

टिप्पणी: निर्माण क्षेत्र को चार्ट III.10बी में द्वितीयक में शामिल किया गया है।
स्रोत: एमओएस एंड पीआई।

और आकस्मिक श्रम की हिस्सेदारी में वृद्धि हुई, जबकि स्व-नियोजित श्रमिकों की हिस्सेदारी अप्रैल-जून 2024 में पिछली तिमाही से घट गई (चार्ट III.10ए)। कुल मिलाकर, तृतीयक क्षेत्र में रोजगार ने अप्रैल-जून 2024 के दौरान कुल शहरी रोजगार में 62.4 प्रतिशत का योगदान दिया (चार्ट III.10बी)।

पीएमआई रोजगार सूचकांकों के अनुसार, संगठित विनिर्माण रोजगार ने अगस्त 2024 में लगातार छठे महीने विस्तार दर्ज किया, जिसमें मध्यवर्ती वस्तुओं के खंड में मजबूत वृद्धि हुई। विनिर्माण और सेवा दोनों क्षेत्रों में रोजगार सृजन का विस्तार जारी रहा, यद्यपि यह मध्यम गति से हुआ (चार्ट III.11)।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत परिवारों की काम की मांग अगस्त में लगातार तीसरे महीने संकुचित हुई, जो खरीफ बुवाई के मौसम के दौरान कृषि श्रमिकों की उच्च मांग को दर्शाती है। वर्ष-दर-वर्ष आधार पर,

चार्ट III.11: पीएमआई रोजगार सूचकांक

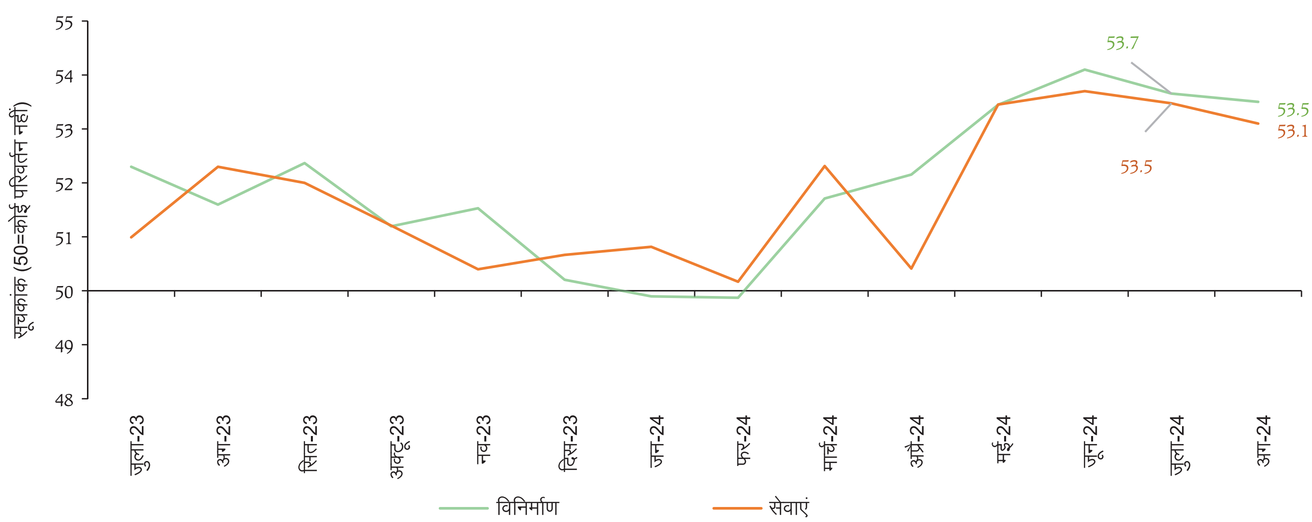

नोट: 50 से ऊपर का पीएमआई मूल्य विस्तार को इंगित करता है।
स्रोत: एस एंड पी ग्लोबल।

चार्ट III.12: मनरेगा के तहत काम की मांग करने वाले परिवार

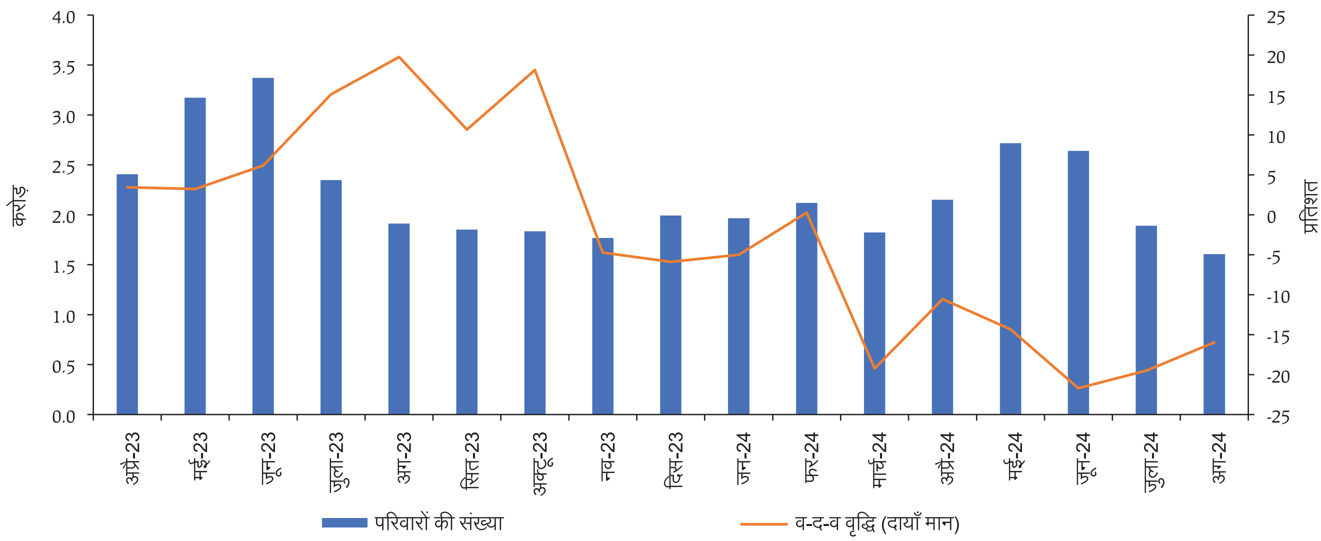

स्रोत: ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार।

इसमें लगातार छह महीनों तक गिरावट दर्ज की गई, जो ग्रामीण क्षेत्रों में खेतों और निर्माण में नौकरियों की उपलब्धता में वृद्धि को दर्शाता है (चार्ट III.12)।

अगस्त 2024 में भारत का पण्य वस्तु निर्यात 34.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक 9.3 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) संकुचित हुआ, मुख्य रूप से प्रतिकूल आधार प्रभाव के कारण जो सकारात्मक गति को संतुलित करने से अधिक है (चार्ट III.13)।

अगस्त में 30 प्रमुख वस्तुओं में से 11 (निर्यात बास्केट का 37.8 प्रतिशत हिस्सा) का निर्यात अगस्त में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर संकुचित हुआ। पेट्रोलियम उत्पादों, रत्न और आभूषण, चावल, समुद्री उत्पादों और लौह अयस्क ने संकुचन में योगदान दिया, जबकि इंजीनियरिंग सामान, कार्बनिक और अकार्बनिक रसायन, इलेक्ट्रॉनिक सामान, रेडीमेड वस्त्र (आरएमजी), और ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स ने माह में निर्यात वृद्धि का समर्थन किया (चार्ट III.14)। हालांकि, अप्रैल-अगस्त 2024 के दौरान,

चार्ट III.13: भारत का पण्य वस्तु निर्यात

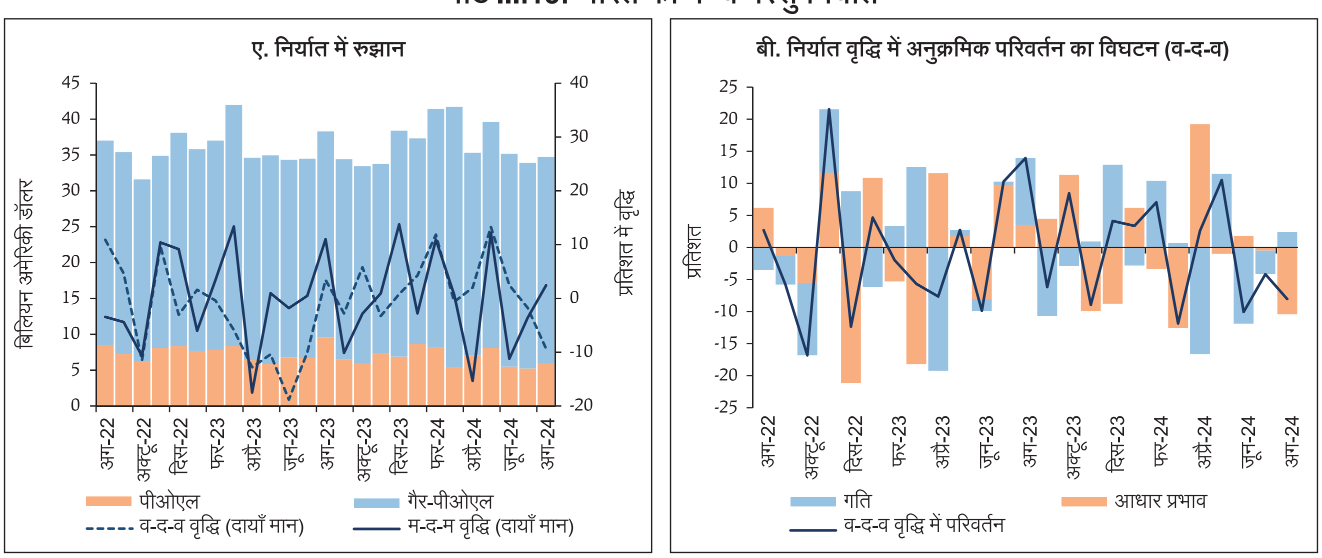

टिप्पणी: पीओएल: पेट्रोलियम, तेल और स्नेहक।
स्रोत: पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी); डीजीसीआई एंड एस और आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

चार्ट III.14: भारत का व्यापारिक निर्यात – सापेक्ष योगदान (अगस्त 2024 अगस्त 2023 की तुलना में)

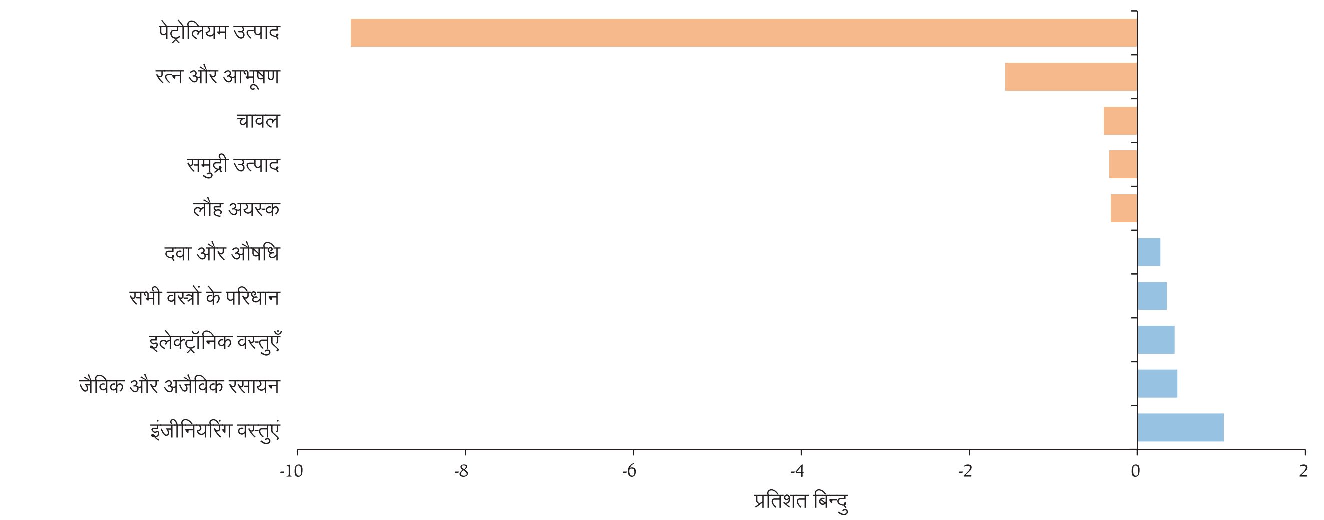

स्रोत : पीआईबी; और आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

भारत का पण्य वस्तु निर्यात 1.1 प्रतिशत बढ़कर 178.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जिसमें मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक सामान, इंजीनियरिंग सामान, ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स, सभी वस्त्रों के आरएमजी और कार्बनिक और अकार्बनिक रसायन शामिल थे, जबकि पेट्रोलियम उत्पाद, रत्न और आभूषण, चावल, समुद्री उत्पाद और लौह अयस्क ने निर्यात को नीचे लाया।

अगस्त 2024 में 20 प्रमुख गंतव्यों में से 12 के निर्यात में कमी आई, जबकि अप्रैल-अगस्त 2024 के दौरान, 20 प्रमुख गंतव्यों में से 11 ने निर्यात में विस्तार दर्ज किया। विशेष रूप से, अप्रैल-अगस्त 2024 के दौरान शीर्ष 3 गंतव्यों, अर्थात अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात और नीदरलैंड में भारत का निर्यात बढ़ गया।

अगस्त में 64.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर के पण्य वस्तु आयात में वृद्धि के कारण 3.3 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि हुई (चार्ट III.15)। 30 प्रमुख पण्य वस्तुओं में से 18 वस्तुओं (आयात

चार्ट III.15: भारत का पण्य वस्तु आयात

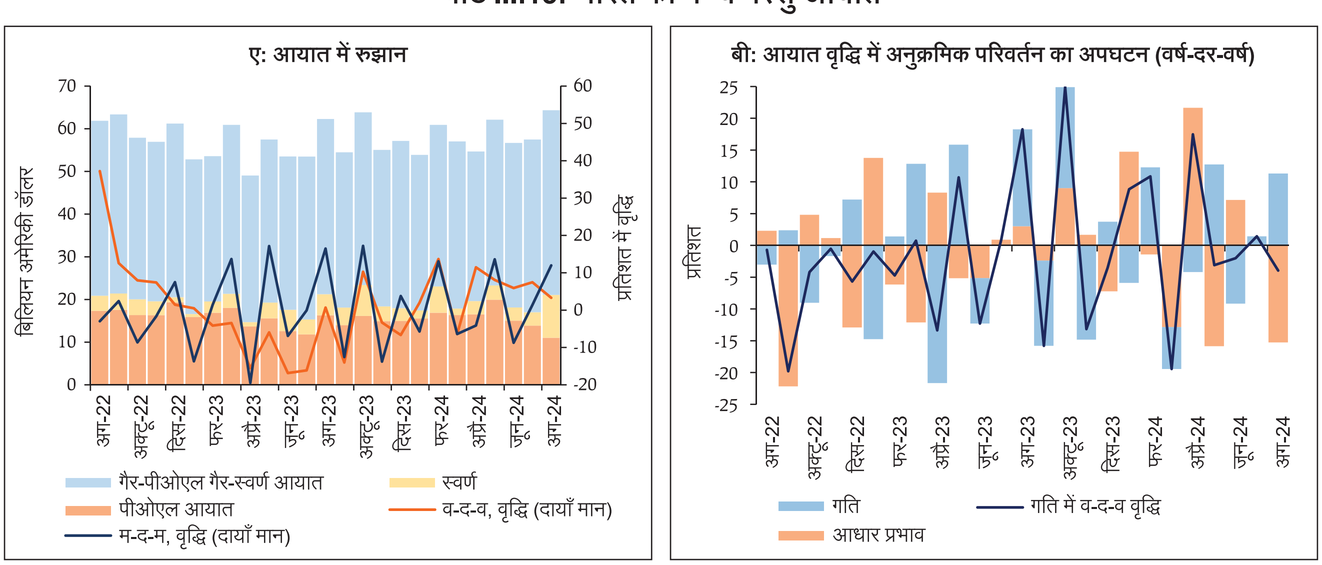

स्रोत: पीआईबी; डीजीसीआईएस; और आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

चार्ट III.16: भारत का पण्य वस्तु आयात – सापेक्ष योगदान (अगस्त 2023 की तुलना में अगस्त 2024)

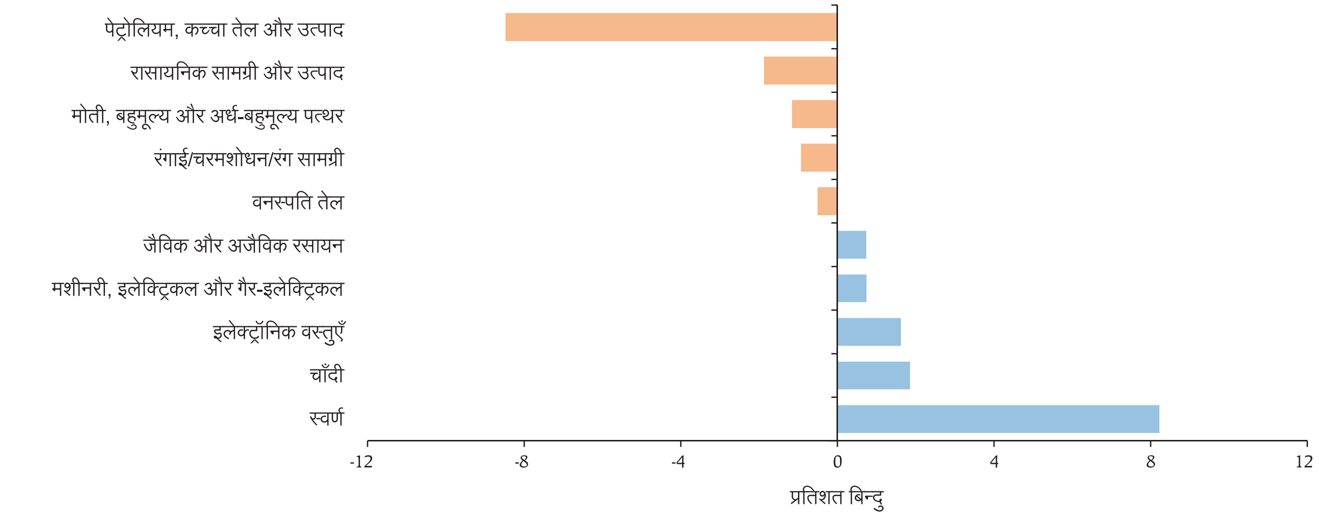

स्रोत : पीआईबी; और आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

बास्केट का 54.1 प्रतिशत हिस्सा) ने वर्ष-दर-वर्ष आधार पर वृद्धि दर्ज की।

स्वर्ण, चांदी, इलेक्ट्रॉनिक सामान, मशीनरी और रसायनों ने सकारात्मक योगदान दिया, जबकि पीओएल, रासायनिक सामग्री और उत्पाद, मोती, कीमती और अर्ध-कीमती पत्थर, रंगाई, टैनिंग और रंग सामग्री, और वनस्पति तेल ने समग्र आयात वृद्धि में नकारात्मक योगदान दिया (चार्ट III.16)। अप्रैल-अगस्त 2024 के दौरान, पेट्रोलियम, कच्चा तेल और उत्पाद, स्वर्ण, इलेक्ट्रॉनिक सामान, परिवहन उपकरण और चांदी के नेतृत्व में भारत का पण्य वस्तु आयात 7.1 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) बढ़कर 295.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जबकि मोती, कीमती और अर्ध-कीमती पत्थर, रासायनिक सामग्री और उत्पाद, कोयला, कोक और ब्रिकेट, उर्वरक और रंगाई, टैनिंग और रंग सामग्री ने नकारात्मक योगदान दिया।

अगस्त 2024 में 20 स्रोत देशों में से 9 से आयात में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर विस्तार हुआ। अप्रैल-अगस्त 2024 के दौरान 20 स्रोत देशों में से 14 से आयात में वृद्धि हुई, जिसमें शीर्ष 3 स्रोत देशों, अर्थात चीन, रूस और संयुक्त अरब अमीरात से आयात का विस्तार दर्ज किया गया।

अगस्त 2024 में पण्य वस्तु व्यापार घाटा बढ़कर 10 महीने के उच्च स्तर 29.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। कुल पण्य वस्तु व्यापार घाटे में पीओएल की हिस्सेदारी अगस्त 2024 में घटकर 17.1 प्रतिशत हो गई, जो एक वर्ष पहले 28.1 प्रतिशत थी (चार्ट III.17)।

अप्रैल-अगस्त 2024 के दौरान, भारत का पण्य वस्तु व्यापार घाटा एक वर्ष पहले 99.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर

चार्ट III.17: भारत के पण्य वस्तु व्यापार घाटे का अपघटन

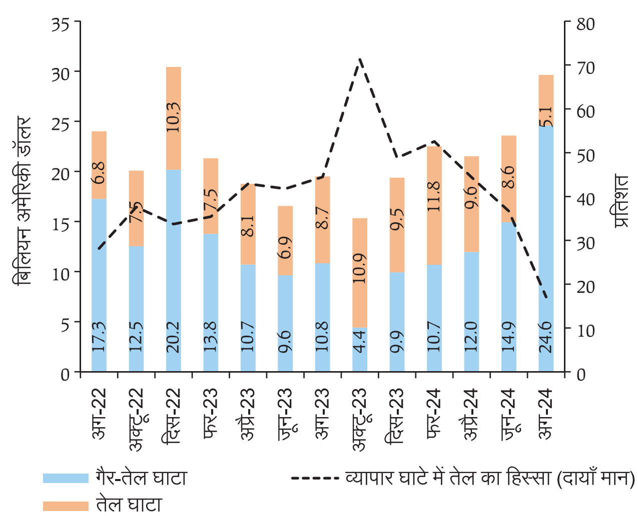

स्रोत : पीआईबी और डीजीसीआईएस।

चार्ट III.18: कमोडिटी-वार पण्य वस्तु व्यापार घाटा

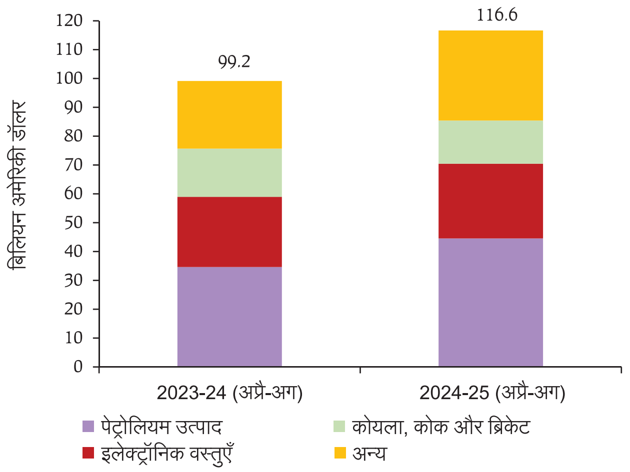

टिप्पणी: अगस्त 2024 में कोयला, कोक और ब्रिकेट निर्यात जुलाई 2024 के समान रहे।
स्रोत: पीआईबी; डीजीसीआई एंड एस और आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

से बढ़कर 116.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। घाटे का सबसे बड़ा स्रोत पेट्रोलियम उत्पाद थे, इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक सामान थे (चार्ट III.18)।

जुलाई 2024 में 30.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर का सेवा निर्यात 16.6 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) बढ़ा और सेवाओं का आयात 15.7 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) बढ़कर 15.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया (चार्ट III.19)। परिणामस्वरूप, माह के दौरान निवल सेवा निर्यात आय 17.6 प्रतिशत (वर्षानुवर्ष) बढ़कर 14.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। वर्ष 2023 में भारत विश्व सेवा निर्यात में 4.3 प्रतिशत की हिस्सेदारी के साथ सातवां सबसे बड़ा सेवा निर्यातक था।

अप्रैल-जुलाई 2024 के दौरान केंद्र सरकार के सभी प्रमुख प्रमुख घाटा संकेतक, जैसे सकल राजकोषीय घाटा (जीएफडी), राजस्व घाटा (आरडी) और प्राथमिक घाटा (पीडी) में सुधार हुआ [पूर्ण रूप से और प्रतिशत दोनों में बजट अनुमान (बीई)] पिछले वर्ष की इसी अवधि (यानी, अप्रैल-जुलाई 2023)[12] के सापेक्ष अप्रैल-जुलाई 2024 के दौरान, जीएफडी बीई के 17.2 प्रतिशत तक कम हो गया है, जो एक दशक से अधिक में भी में सबसे कम है (चार्ट III.20ए)। इसके अलावा, अप्रैल-जुलाई 2024 के दौरान एक प्राथमिक खाता अधिशेष पोस्ट किया गया (चार्ट III.20बी)। अप्रैल-जुलाई 2024 के दौरान केंद्र सरकार की वित्तीय स्थिति में यह सुधार राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि के कारण हुआ। दूसरी ओर, केंद्र सरकार का कुल व्यय अप्रैल-जुलाई 2024 के दौरान वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 5.8 प्रतिशत संकुचित हुआ, जिसका मुख्य कारण ति1: 2024-25 में हुए आम चुनावों के कारण लागू आदर्श आचार संहिता है।

चार्ट III.19: सेवा निर्यात और आयात: वृद्धि दर

स्रोत : आरबीआई।

[12] केंद्र सरकार की वित्तीय स्थिति से संबंधित नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीजीए) द्वारा जारी नवीनतम डेटा।

चार्ट III.20: बजटीय घाटा (अप्रैल-जुलाई)

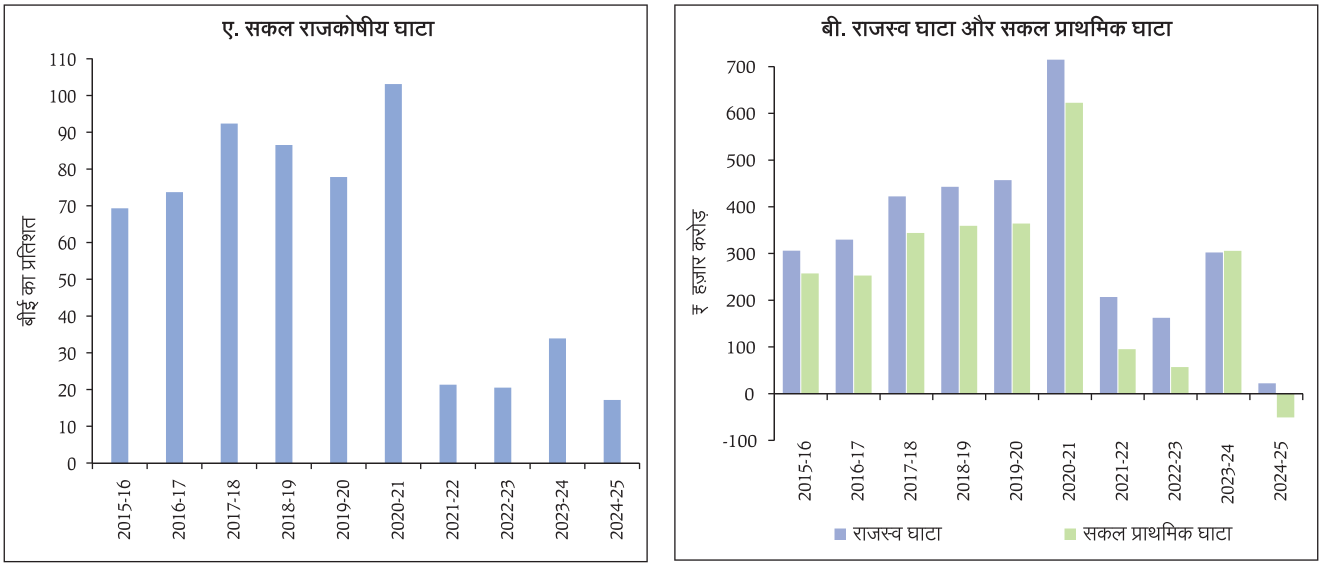

स्रोत : सीजीए।

प्राप्तियों के पक्ष में, सकल कर राजस्व में अप्रैल-जुलाई 2024 के दौरान 21.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जिसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर क्रमशः 35.4 प्रतिशत और 7.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। प्रत्यक्ष करों के तहत, आयकर ने 53.4 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की दोहरे अंकों की वृद्धि दर दर्ज की। अप्रत्यक्ष करों के तहत, माल और सेवा कर (जीएसटी) संग्रह में 9.5 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज की गई (चार्ट III.21ए)। रिज़र्व बैंक से ₹2.11 लाख करोड़ के अधिशेष हस्तांतरण के साथ, गैर-कर राजस्व प्राप्तियों ने पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में अप्रैल-जुलाई 2024 के दौरान 68.8 प्रतिशत की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर्ज की (चार्ट III.21बी)। दूसरी ओर, गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियों ने अप्रैल-जुलाई 2024 के

चार्ट III.21: केंद्र सरकार की राजस्व प्राप्तियां (अप्रैल-जुलाई)

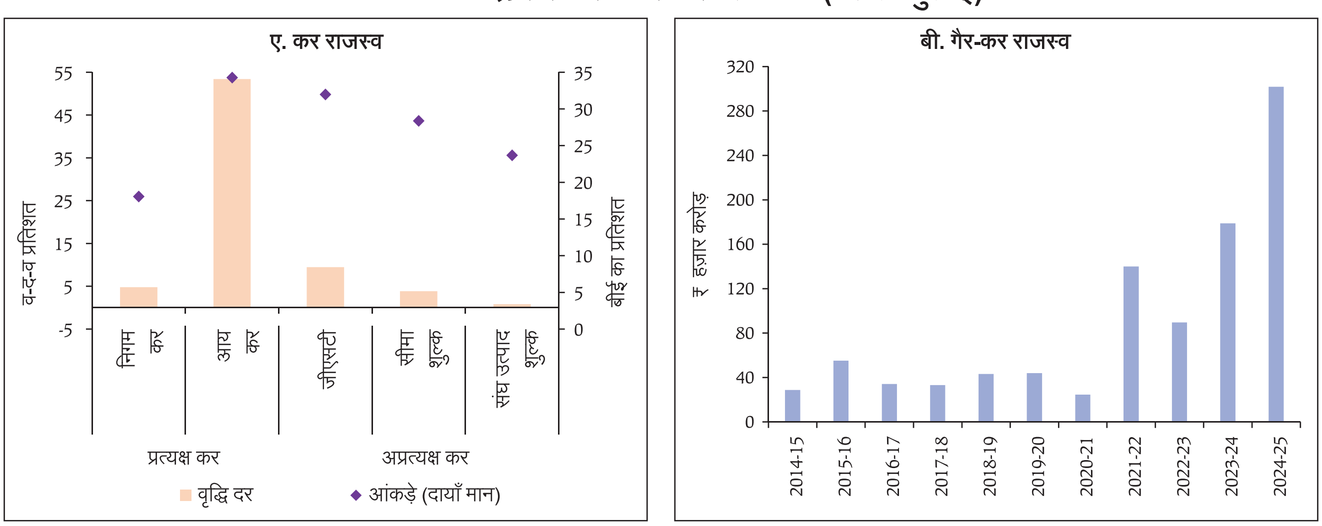

टिप्पणी: रिज़र्व बैंक ने 1 अप्रैल 2021 से अपना लेखा वर्ष जुलाई-जून से बदलकर अप्रैल-मार्च कर दिया। तदनुसार, 2021-22 से रिज़र्व बैंक का अधिशेष अगस्त के बजाय मई के महीने में केंद्र सरकार को हस्तांतरित किया जाता है।
स्रोत: सीजीए; और केंद्रीय बजट दस्तावेज।

चार्ट III.22: मासिक जीएसटी राजस्व

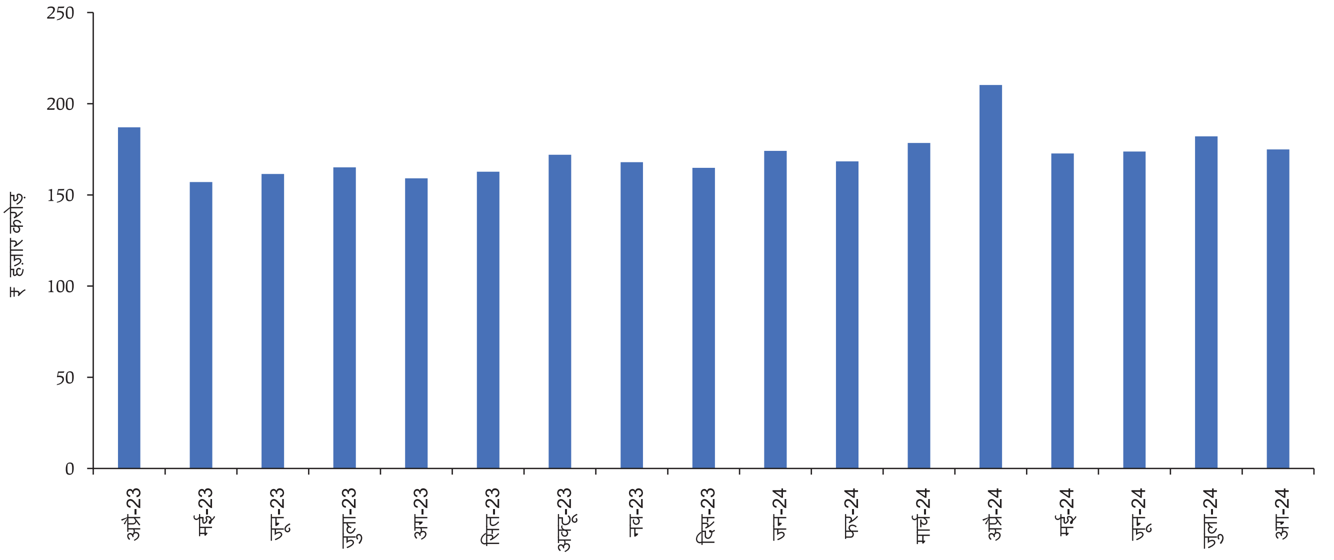

स्रोत : पीआईबी; और जीएसटी पोर्टल।

दौरान वर्ष-दर-वर्ष आधार (विनिवेश सहित) पर 53.4 प्रतिशत का संकुचन दर्ज किया। कुल मिलाकर कुल प्राप्तियों में वार्षिक आधार पर 32 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

अगस्त 2024 के महीने के लिए सकल जीएसटी संग्रह (केंद्र एवं राज्य) ₹1.75 लाख करोड़ रहा, जिसमें वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 10 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई (चार्ट III.22)। प्रतिदान का हिसाब लगाने के बाद निवल जीएसटी संग्रह ₹1.51 लाख करोड़ रहा, जो वार्षिक आधार पर 6.5 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है।

अप्रैल-जुलाई 2024 के लेखा आंकड़ों से संकेत मिलता है कि राज्यों के जीएफ़डी में 13.2 प्रतिशत की गिरावट आई और उनकी आरडी में 14.9 प्रतिशत (व-द-व) की गिरावट आई। यह समेकन राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि और पूंजीगत व्यय में संकुचन के माध्यम से प्राप्त किया गया था (चार्ट III.23ए)।

चार्ट III.23: राज्यों के प्रमुख राजकोषीय प्रदर्शन संकेतक (अप्रैल-जुलाई)

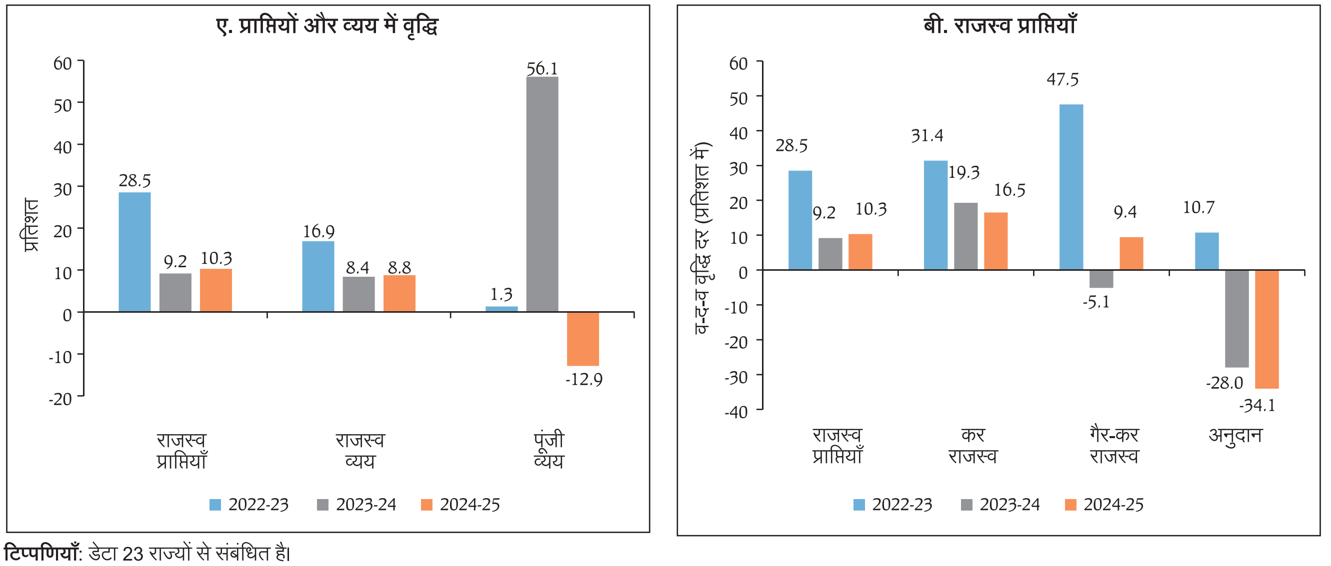

टिप्पणियाँ: डेटा 23 राज्यों से संबंधित है।
स्रोत: सीजीए।

कर और गैर-कर राजस्व में वृद्धि के कारण राज्यों की राजस्व प्राप्तियों में मामूली वृद्धि हुई, यहां तक कि केंद्र सरकार से अनुदान में भी कमी आई (चार्ट III.23बी)। राज्यों के अपने कर राजस्व के भीतर, वस्तु और सेवा कर (एसजीएसटी) में वृद्धि कम हुई, जबकि उत्पाद शुल्क और बिक्री कर/मूल्य वर्धित कर (वैट) एक वर्ष पहले की तुलना में अधिक थे।

व्यय पक्ष पर, राजस्व व्यय में वृद्धि हुई, जबकि अप्रैल-जुलाई 2024 के दौरान पूंजीगत व्यय में गिरावट आई। आगे चलकर केंद्र सरकार द्वारा ₹ 1.5 लाख करोड़ के दीर्घकालिक ब्याज मुक्त ऋणों की विशेष सहायता के प्रावधान के कारण पूंजीगत व्यय बढ़ने की उम्मीद है।

सकल आपूर्ति

सकल आपूर्ति – मूल कीमतों पर सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) द्वारा मापी गई – ति1: 2024-25 में 6.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि एक वर्ष पहले 8.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। वास्तविक जीवीए वृद्धि औद्योगिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र में आघात-सहनीयता से प्रेरित थी (चार्ट III.24)। कृषि में वृद्धि एक वर्ष पहले 3.7 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में ति1: 2024-25 में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 2.0 प्रतिशत तक कम हो गई, क्योंकि प्रमुख जलाशयों और नदी घाटियों में कम जल स्तर के कारण रबी खाद्यान्न उत्पादन में गिरावट आई थी। औद्योगिक क्षेत्र के भीतर, विनिर्माण - प्रमुख घटक - ने 7.0 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि दर्ज की, जबकि कोयला और प्राकृतिक गैस के उच्च उत्पादन के कारण खनन और उत्खनन में गतिविधि में वृद्धि हुई। सेवा क्षेत्र भी उत्साहित रहा, ति1: 2024-25 में 7.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जो उप-क्षेत्रों में व्यापक आधार पर थी। निर्माण क्षेत्र ने 10.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की, जिसका मुख्य कारण तैयार इस्पात की खपत में दोहरे अंकों की वृद्धि है। प्रसारण से संबंधित व्यापार, होटल, परिवहन, संचार और सेवाओं में वृद्धि में कमी आई, जबकि वित्तीय सेवाओं में वृद्धि मजबूत रही, जिसे सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) कंपनियों के स्थिर लाभ मार्जिन और निरंतर ऋण और जमा वृद्धि से समर्थन मिला। लोक प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवाओं (पीएडीओ) ने ति1: 2024-25 में 9.5 प्रतिशत की प्रभावशाली वृद्धि दर्ज की, जो अन्य सेवाओं में उत्साहित वृद्धि से प्रेरित है, जबकि लोक प्रशासन और रक्षा - सरकारी राजस्व व्यय, ब्याज भुगतान और सब्सिडी के निवल - ने तिमाही के दौरान एक संकुचन प्रदर्शित किया।

चार्ट III.24: जीवीए वृद्धि में भारित योगदान

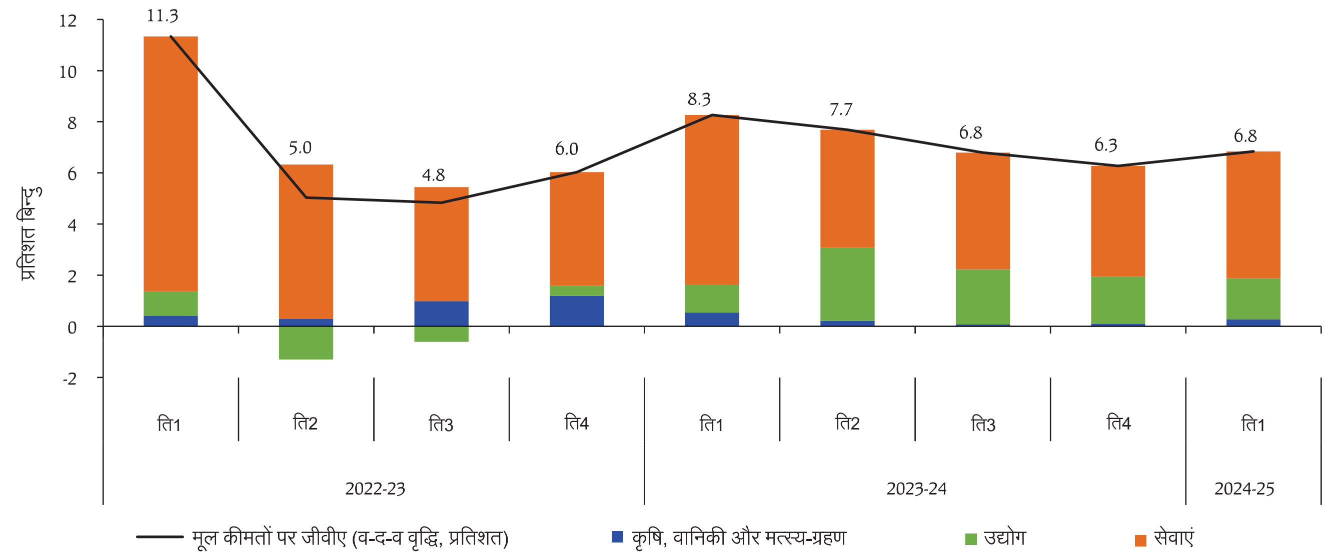

स्रोत: एनएसओ; और आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

चार्ट III.25: दक्षिण पश्चिम मानसून की प्रगति (एसडब्ल्यूएम)

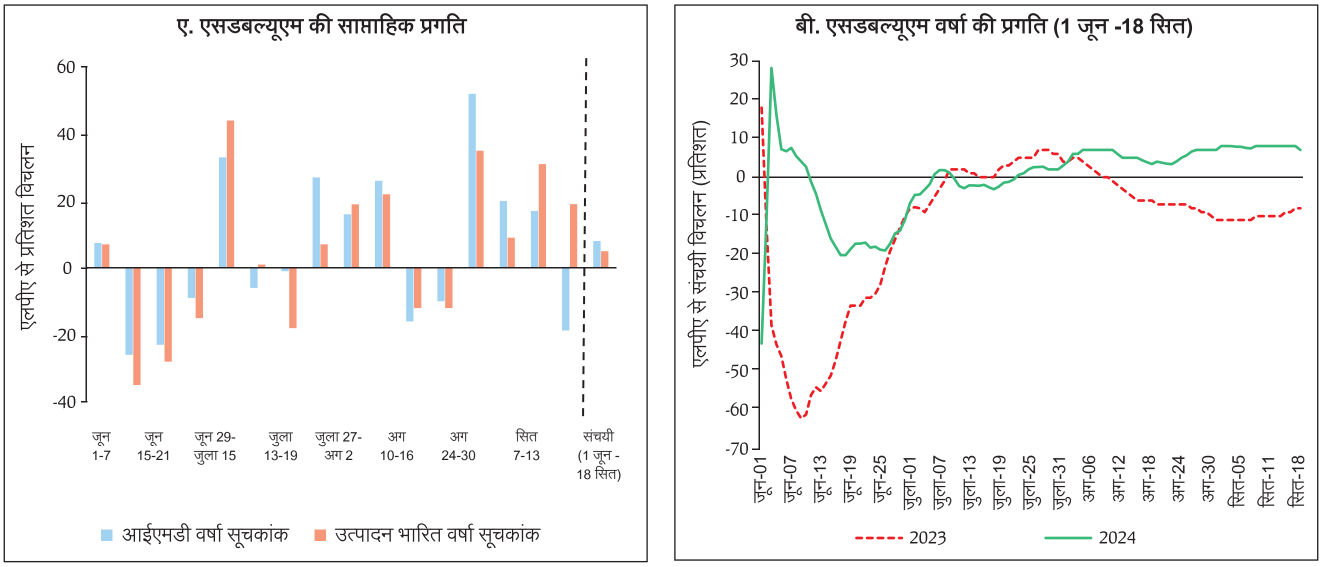

स्रोत: आईएमडी; और आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

दक्षिण-पश्चिम मानसून (एसडब्ल्यूएम) वर्षा की प्रगति से कृषि विकास की संभावनाओं को बढ़ावा मिला। इस वर्ष अब तक (1 जून से 18 सितंबर) संचयी एसडब्ल्यूएम वर्षा एलपीए से 7 प्रतिशत अधिक थी, जबकि एक वर्ष पहले एलपीए से 8 प्रतिशत कम थी (चार्ट III.25ए)। संचयी वर्षा लगातार जुलाई के मध्य से सामान्य एलपीए से ऊपर रही, पिछले वर्ष के विपरीत जब यह एसडब्ल्यूएम के उत्तरार्ध के दौरान कम हो गई थी (चार्ट III.25बी)।

उत्पादन भारित वर्षा सूचकांक (पीआरएन) एलपीए के 106 प्रतिशत पर मामूली रूप से कम रहा, लेकिन यह चावल को छोड़कर सभी प्रमुख फसलों के लिये 'सामान्य से अधिक' रहा, जिसके लिए यह 18 सितंबर, 2024 तक सामान्य था। इसके अलावा, सभी प्रमुख फसलों ने पीआरएन पिछले वर्ष की इसी अवधि में अपने स्तर से अधिक दर्ज किया (चार्ट III.26)।

वर्तमान दक्षिण पश्चिम मानसून मौसम के दौरान अब तक, 36 मौसम विज्ञान उप-प्रभागों में से 19 ने सामान्य वर्षा दर्ज की (चार्ट III.27ए)। अधिक/अत्यधिक वर्षा प्राप्त करने वाले उप-प्रभागों की संख्या एक वर्ष पूर्व 4 से बढ़कर चालू वर्ष में 13 हो गई है, जो पिछले वर्ष की तुलना में देश भर में वर्षा में उच्चतर स्थानिक भिन्नता में परिलक्षित होती है (चार्ट III.27बी)। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, बिहार और पंजाब जैसे राज्यों में मुख्य रूप से कम वर्षा देखी गई।

जलाशयों के स्तर को पिछले वर्ष की इसी अवधि में 71 प्रतिशत की तुलना में क्षमता का 87 प्रतिशत (19 सितंबर

चार्ट III.26: फसलवार पीआरएन

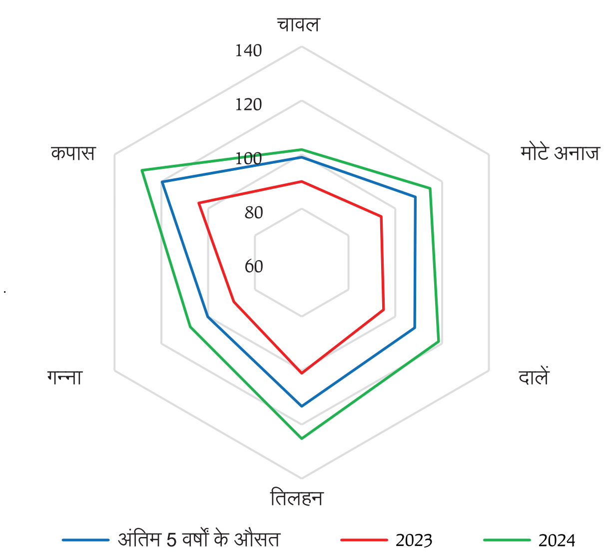

स्रोत: आईएमडी; और आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

चार्ट III.27: एसडब्ल्यूएम का स्थानिक वितरण

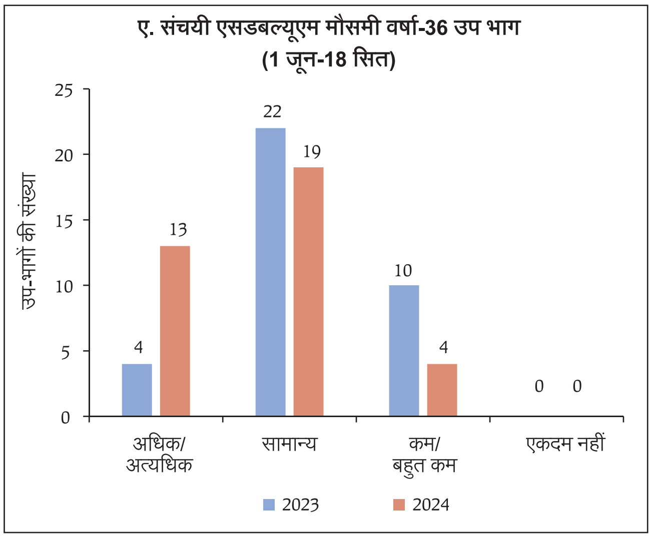

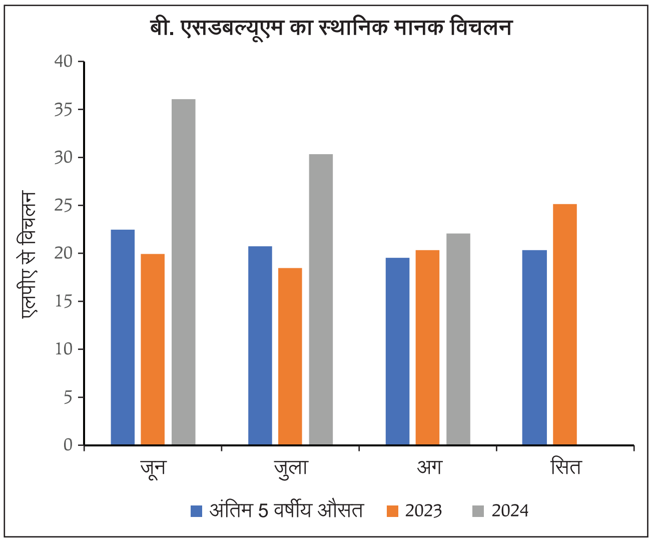

स्रोत: आईएमडी; और आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

2024 तक) भर दिया गया है, जिससे रबी बुवाई की संभावनाओं में वृद्धि हुई है (चार्ट III.28)। 155 प्रमुख जलाशयों का सक्रिय भंडारण पिछले वर्ष की इसी अवधि के स्तर का 123 प्रतिशत और पिछले 10 वर्षों के औसत का 118 प्रतिशत था।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, पूरे देश में सितंबर 2024 के लिए मासिक वर्षा सामान्य से अधिक होने की संभावना है (चार्ट III.29)। इसके अलावा, यह भविष्यवाणी करता है कि मानसून के मौसम के अंत तक तटस्थ हिंद महासागर डाईपोल (आईओडी) की स्थिति जारी रहने की संभावना है।

कुल बुवाई क्षेत्र 1096.6 लाख हेक्टेयर (13 सितंबर 2024 तक) रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 2.2 प्रतिशत अधिक है

चार्ट III.28: जलाशय स्तर (19 सितंबर तक)

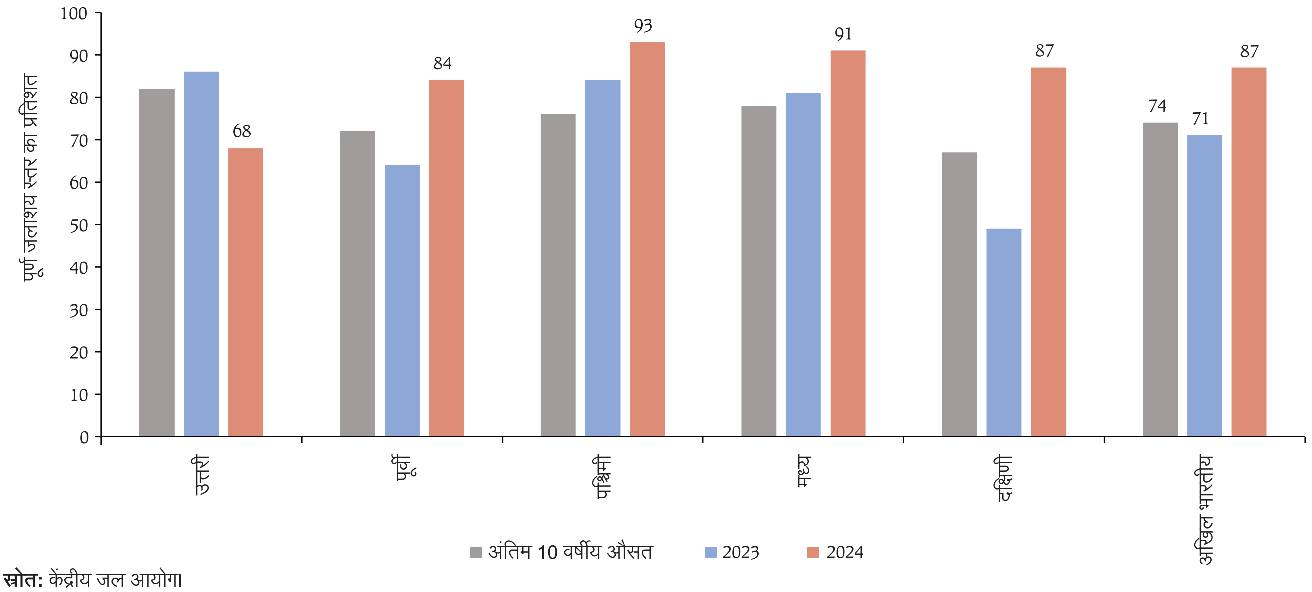

स्रोत: केंद्रीय जल आयोग।

चार्ट III.29: सितंबर 2024 के लिए दक्षिण-पश्चिम मानसून का पूर्वानुमान

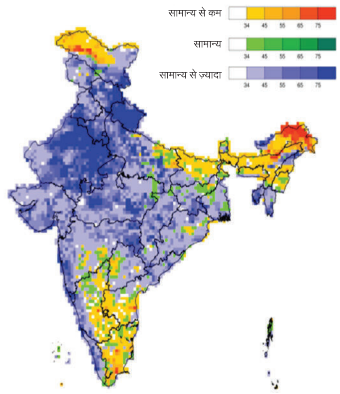

टिप्पणी:
1. चार्ट सितम्बर, 2024 के दौरान भारत में वर्षा के लिए वर्षा की टेरसाइल श्रेणियों (सामान्य से नीचे, सामान्य और सामान्य से अधिक) के संभाव्यता पूर्वानुमान को दर्शाता है।
2. आंकड़े सबसे संभावित श्रेणियों के साथ-साथ उनकी संभावनाओं को भी दर्शाते हैं।
3. टेरसाइल श्रेणियों में 33.33 प्रतिशत की समान जलवायु संबंधी संभावनाएं हैं।
4. हर मानचित्र केवल दृष्टांत उद्देश्यों के लिए हैं।

स्रोत: आईएमडी।

चार्ट III.30: खरीफ का रकबा (13 सितंबर 2024 तक)

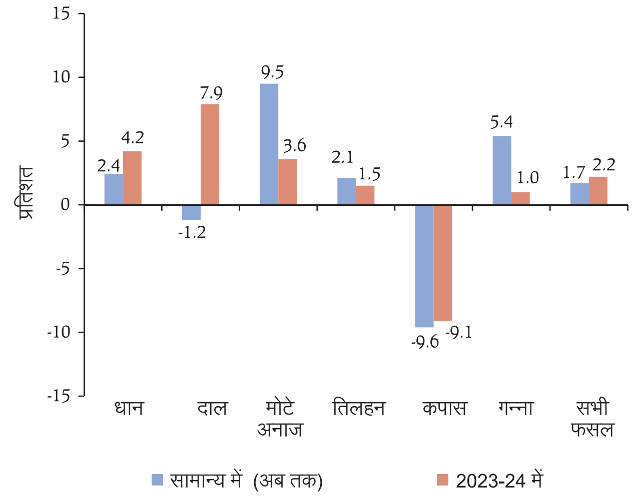

स्रोत: कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय।

और आज की तारीख के सामान्य क्षेत्र से 1.7 प्रतिशत अधिक है (चार्ट III.30)। कपास को छोड़कर सभी प्रमुख फसलों के अंतर्गत क्षेत्र में पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई है। दालों के रकबे में पिछले वर्ष की तुलना में सबसे अधिक 7.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। खरीफ क्षेत्र में लगभग 37 प्रतिशत हिस्सेदारी रखने वाली प्रमुख खरीफ फसल चावल के तहत रकबा वार्षिक आधार पर 4.2 प्रतिशत बढ़ा है। खरीफ में प्याज की बुवाई में 61 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि टमाटर का रकबा पीछे चल रहा है, प्रमुख उत्पादक राज्यों में जून तक लू की स्थिति बढ़ने के कारण कम बुवाई हुई है।

17 सितंबर, 2024 तक सरकार ने खरीफ विपणन सीजन (केएमएस) 2023-24 में 525 लाख टन चावल की खरीद की है, जो पिछले सीजन में खरीद की तुलना में 8 प्रतिशत कम है। भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के पास चावल का स्टॉक 01 सितंबर, 2024 तक 422 लाख टन था, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 24 प्रतिशत अधिक है। 1 अक्टूबर 2024 से शुरू होने वाले नए खरीद सीजन के शुरू होने से पहले चावल के अतिरिक्त स्टॉक को कम करने के लिए, डिस्टिलरी को साप्ताहिक ई-नीलामी के माध्यम से निर्धारित दर पर इथेनॉल उत्पादन के लिए एफसीआई से 23 लाख टन चावल खरीदने की अनुमति दी गई है। रबी विपणन सीजन (आरएमएस) 2024-25 में 266 लाख टन गेहूं की खरीद पिछले सीजन की तुलना में 1.6 प्रतिशत अधिक रही। 01 सितंबर 2024 को गेहूं का स्टॉक 252 लाख टन था और पिछले वर्ष की तुलना में 3.4 प्रतिशत कम रहा। जुलाई-सितंबर तिमाही के लिए चावल और गेहूं के स्टॉक का बफर मानदंड क्रमशः 135.4 लाख टन और 275.8 लाख टन है (चार्ट III.31)।

चार्ट III.31: केंद्रीय सार्वजनिक वितरण प्रणाली

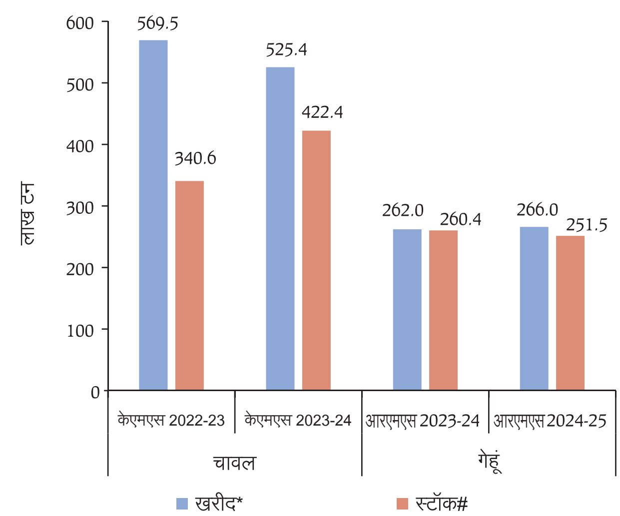

टिप्पणी: *:- 17 सितंबर तक संचयी खरीद; #:- 01 सितंबर की स्थिति के अनुसार।
स्रोत: एफसीआई; और सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी।

चार्ट III.32: क्रय प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई)

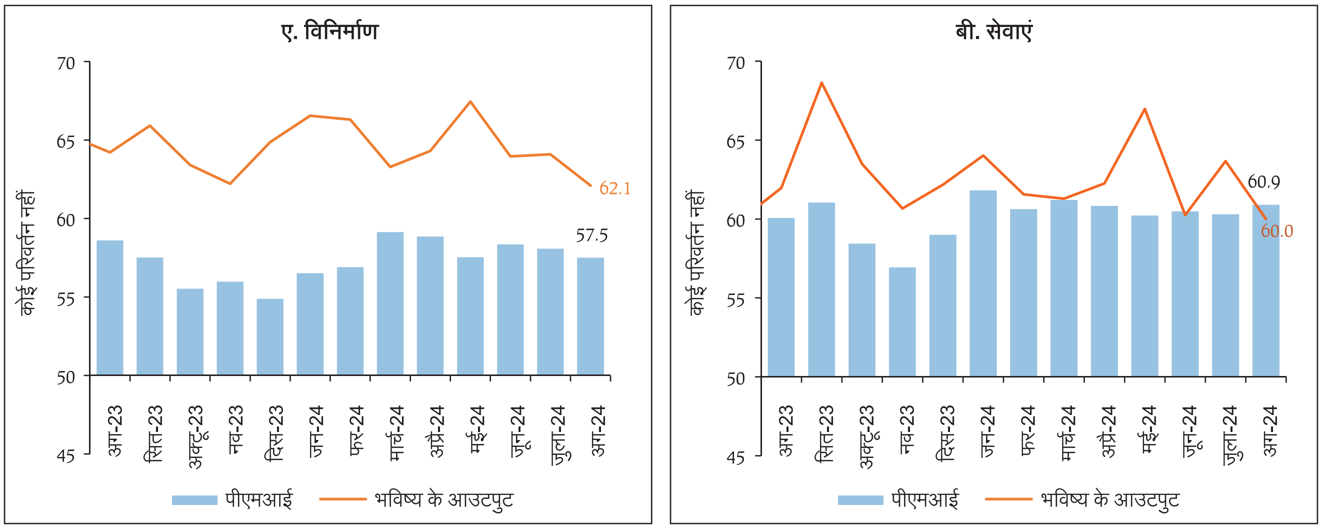

टिप्पणी: 50 का स्तर गतिविधि में कोई बदलाव नहीं होने के अनुरूप है और 50 से ऊपर का स्तर विस्तार को दर्शाता है और इसके विपरीत।
स्रोत: एस एंड पी ग्लोबल।

उत्पादन और नए व्यवसायों में विस्तार की गति में गिरावट के कारण भारत का विनिर्माण पीएमआई जुलाई में 58.1 से अगस्त 2024 में घटकर 57.5 हो गया (चार्ट III.32ए)। सेवा क्षेत्र पीएमआई, अगस्त में बढ़कर 60.9 हो गया, जो नई व्यावसायिक गतिविधियों में मजबूत विस्तार की वजह से है (चार्ट III.32bबी)। हालांकि विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में व्यावसायिक अपेक्षाएँ एक वर्ष के निचले स्तर पर आ गई हैं।

अगस्त 2024 में बंदरगाह यातायात में 6.7 प्रतिशत (व-द-व) की वृद्धि हुई, जो उर्वरक और अन्य विविध कार्गो द्वारा बढ़ाया गया (चार्ट III.33ए)। दूसरी ओर, रेलवे माल ढुलाई यातायात ने सीमेंट के कारण अगस्त में वर्ष-दर-वर्ष गिरावट दर्ज की (चार्ट III.33बी)।

निर्माण क्षेत्र के भीतर, अगस्त में इस्पात की खपत में 10.0 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि हुई (चार्ट III.34)। जुलाई 2024 में सीमेंट उत्पादन में 5.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

चार्ट III.33: पोर्ट कार्गो और रेलवे माल यातायात

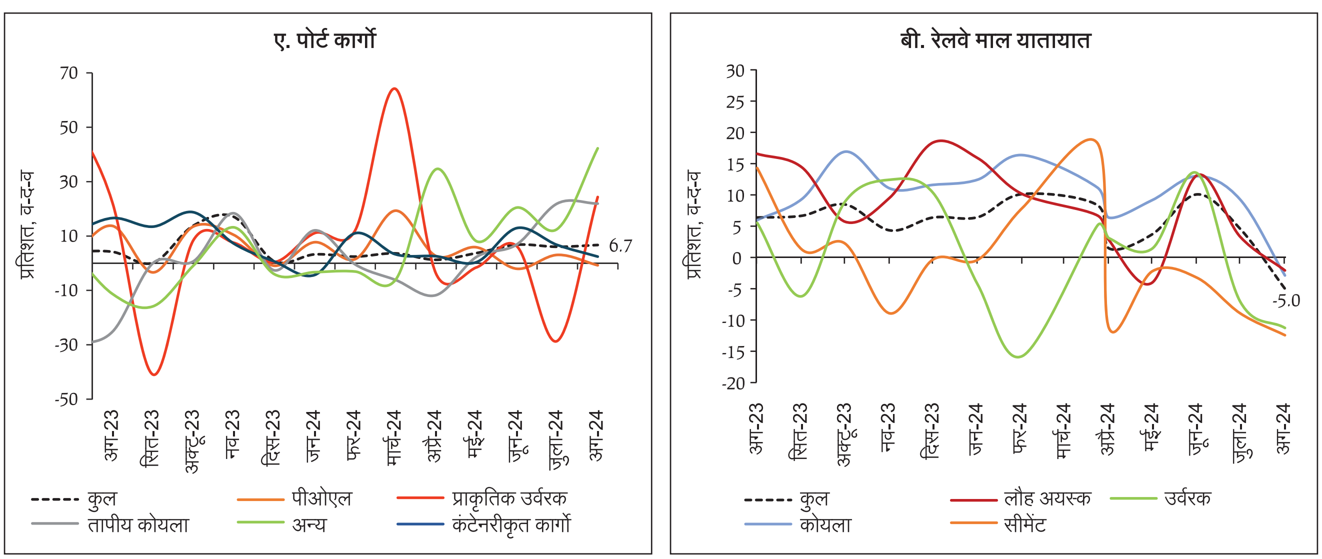

स्रोत: इंडियन पोर्ट्स एसोसिएशन; और रेल मंत्रालय।

चार्ट III.34: इस्पात की खपत और सीमेंट उत्पादन

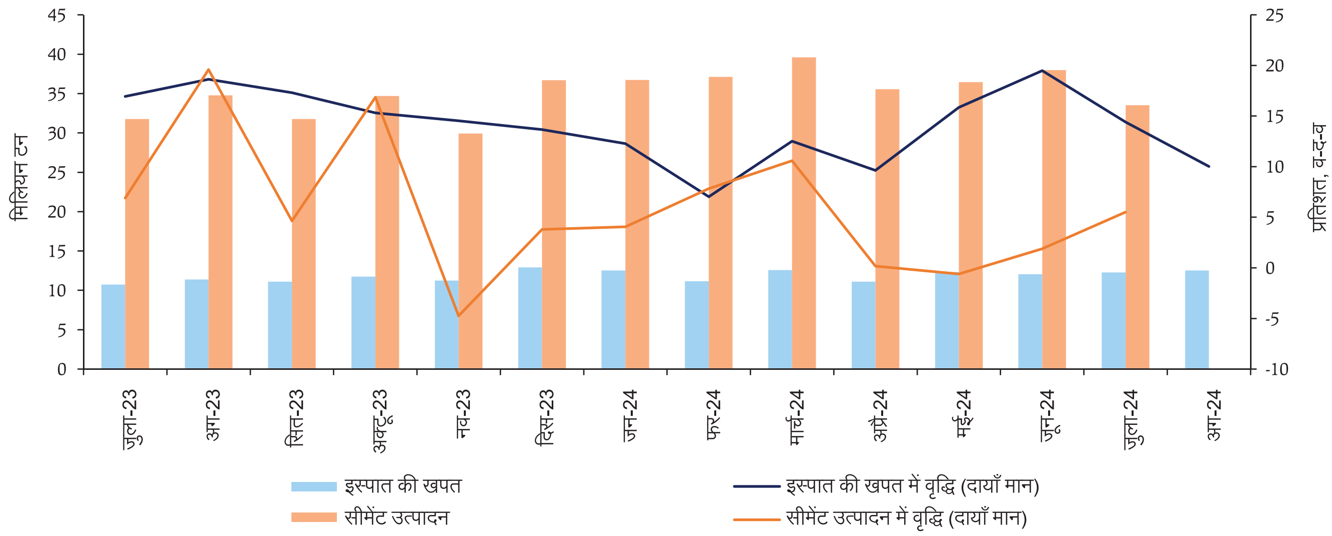

स्रोत: संयुक्त संयंत्र समिति; और आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

सेवा क्षेत्र के लिए उपलब्ध उच्च आवृत्ति संकेतक अगस्त 2024 में गतिविधि की आघात-सहनीयता को दर्शाते हैं, जो पोर्ट कार्गो, अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्री यातायात और इस्पात खपत द्वारा समर्थित है (सारणी III.2)।

सारणी III.2 : उच्च आवृत्ति संकेतक - सेवाएं

वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष, प्रतिशत)

क्षेत्र	संकेतक	अक्टू-23	नव-23	दिस-23	जन-24	फर-24	मार्च-24	अप्रै-24	मई-24	जून-24	जुला-24	अग-24
शहरी मांग	यात्री वाहनों की बिक्री	17.3	4.3	3.2	13.9	5.7	8.9	1.2	4.3	4.9	-2.0	-1.8
ग्रामीण मांग	दोपहिया वाहनों की बिक्री	20.1	31.3	16.0	26.2	34.6	15.3	30.8	10.1	21.3	12.5	9.3
	तिपहिया वाहनों की बिक्री	42.1	30.8	30.6	9.5	8.3	4.3	14.5	14.4	12.3	5.1	8.0
	ट्रैक्टर की बिक्री	-4.3	6.4	-19.8	-15.3	-30.6	-23.1	-3.0	0.0	3.6	1.6	-5.8
व्यापार, होटल, परिवहन, संचार	वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री	3.2			-3.8			3.5				
	रेलवे मालभाड़ा यातायात	8.5	4.3	6.4	6.4	10.1	8.6	1.4	3.7	10.1	4.5	0.0
	पोर्ट कार्गो यातायात	13.8	16.9	0.6	3.2	2.1	2.7	1.3	3.8	6.8	6.0	6.7
	घरेलू हवाई कार्गो यातायात*	10.6	9	8.7	10	11.5	8.7	0.3	10.3	10.3	8.8	-13.1
	अंतरराष्ट्रीय हवाई कार्गो यातायात*	15	4.9	12.2	19.3	30.2	22.5	16.2	19.2	19.6	24.4	7.4
	घरेलू हवाई यात्री यातायात*	10.7	8.7	8.1	5	5.8	4.7	3.8	5.9	6.9	7.6	6.7
	अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्री यातायात*	17.5	19.8	18.1	17	19.3	15	16.8	19.6	11.3	8.8	10.5
	जीएसटी ई-वे बिल (कुल)	30.5	8.5	13.2	16.4	18.9	13.9	14.5	17.0	16.3	19.2	12.9
	जीएसटी ई-वे बिल (आंतर राज्यीय)	30.0	22.7	14.2	17.9	21.1	15.8	17.3	18.9	16.4	19.0	13.1
	जीएसटी ई-वे बिल (अंतर-राज्यीय)	31.2	-16.2	11.4	13.8	15.0	10.7	9.6	13.6	16.3	19.6	12.5
	होटल अधिवास दर	62.5	63.0	70.0	66.6	72.5	64.4	62.3	60.3	62.0	63.1	
	प्रति कमरा औसत राजस्व	14.8	15.9	12.8	11.0	4.1	6.7	4.8	1.8	2.8	7.6	
	पर्यटकों का आगमन	19.8	16.8	7.8	10.4	15.8	8.0	7.7	0.3	9.0		
निर्माण	इस्पात की खपत	15.3	14.5	13.7	12.3	7.0	12.5	9.6	15.9	19.5	14.4	10.0
	सीमेंट उत्पादन	17.0	-4.8	3.8	4.0	7.8	10.6	0.2	-0.6	1.9	5.5	
पीएमआई सूचकांक#	सेवाएं	58.4	56.9	59.0	61.8	60.6	61.2	60.8	60.2	60.5	60.3	60.9

<< संकुचन ------------------------------------ विस्तार >>

टिप्पणी: #: सूचकांक स्तरों में डेटा। *: अगस्त 2024 का डेटा दैनिक आंकड़ों के मासिक औसत के आधार पर है। @: डेटा दर में है, वृद्धि की व-द-व दर में नहीं। जुलाई 2024 से अब तक के प्रत्येक संकेतक के लिए हीट-मैप बनाया गया है।

स्रोत: सीएमआईई; रेल मंत्रालय; ट्रैक्टर और मशीनीकरण संघ; भारतीय पोर्ट संघएल; वित्तीय सलाहकार का कार्यालय; जीएसटीएन; भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण; एचवीएस एनरॉक; पर्यटन मंत्रालय; संयुक्त संयंत्र समिति; और आईएचएस मार्किट।

मुद्रास्फीति

अखिल भारतीय सीपीआई[13] में वर्ष-दर-वर्ष परिवर्तनों द्वारा मापी गई हेडलाइन मुद्रास्फीति, जुलाई 2024 में 3.6 प्रतिशत से बढ़कर अगस्त 2024 में 3.7 प्रतिशत हो गई (चार्ट III.35)। मुद्रास्फीति में मामूली वृद्धि पूरी तरह से लगभग 5 आधार अंक के प्रतिकूल आधार प्रभाव से हुई, जबकि सूचकांक पिछले महीने के स्तर (शून्य गति) पर अपरिवर्तित रहा। सीपीआई ईंधन और सीपीआई कोर (यानी, खाद्य और ईंधन को छोड़कर सीपीआई) दोनों समूहों ने क्रमशः 34 बीपीएस और 27 बीपीएस की धनात्मक गति दर्ज की, जबकि सीपीआई खाद्य समूह ने 30 बीपीएस की ऋणात्मक गति दर्ज की।

खाद्य मुद्रास्फीति (वर्ष-दर-वर्ष) जुलाई में 5.1 प्रतिशत से अगस्त में 5.3 प्रतिशत तक मजबूत हो गई, क्योंकि 30 बीपीएस की ऋणात्मक गति 52 बीपीएस के प्रतिकूल आधार प्रभाव के हिसाब से अधिक थी। उपसमूहों के संदर्भ में अंडे, फल, सब्जियों और गैर-मादक पेय पदार्थों की मुद्रास्फीति बढ़ी जबकि अनाज, मांस और मछली, दालें और चीनी के मामले में मुद्रास्फीति कम रही। खाद्य तेलों और वसा में अपस्फीति की दर कम दर्ज की गई जबकि मसालों में अपस्फीति गहरी हुई। दूध की कीमतों में लगातार तीसरे महीने 3.0 प्रतिशत की मामूली मुद्रास्फीति दर्ज की गई (चार्ट III.36)।

मुख्य रूप से एलपीजी की कीमतों में 24.6 प्रतिशत (व-द-व) की गिरावट के कारण ईंधन और प्रकाश ने अगस्त 2024 में (-) 5.3 प्रतिशत की अपस्फीति दर्ज की (जुलाई में (-) 5.5 प्रतिशत के मुकाबले)। हालांकि, ईंधन समूह की अन्य वस्तुओं में अगस्त में धनात्मक मुद्रास्फीति दर्ज की गई।

अगस्त में मुख्य मुद्रास्फीति घटकर 3.3 प्रतिशत रह गई, जो जुलाई में 3.4 प्रतिशत थी। परिवहन और संचार, शिक्षा, आमोद-प्रमोद, और घरेलू वस्तुओं और सेवाओं के मामले में मुद्रास्फीति में वृद्धि हुई, जबकि यह कपड़े और जूते, आवास और स्वास्थ्य जैसे उप-समूहों के लिए स्थिर रही। व्यक्तिगत देखभाल और प्रभाव, और पान, तंबाकू और नशीले पदार्थों में एक कमी दर्ज की गई (चार्ट III.37)।

क्षेत्रीय वितरण के संदर्भ में, ग्रामीण मुद्रास्फीति 4.2 प्रतिशत

चार्ट III.35: सीपीआई मुद्रास्फीति के रुझान और वाहक

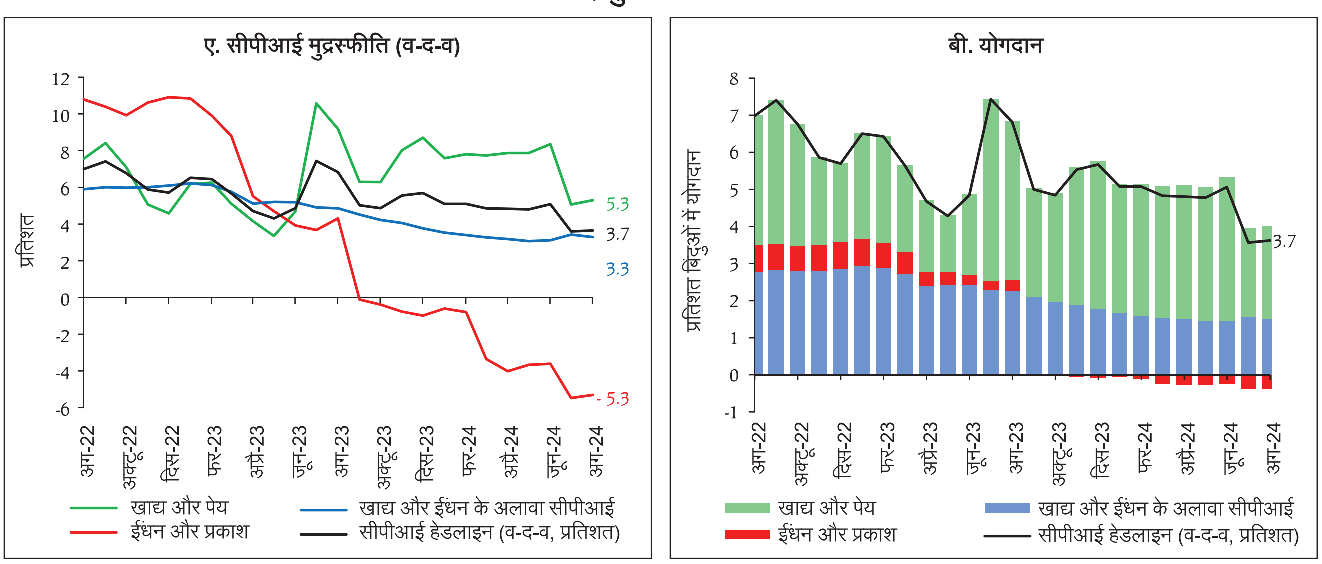

स्रोत: एनएसओ; और आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

[13] एनएसओ द्वारा 12 सितंबर, 2024 को जारी अनंतिम आंकड़ों के अनुसार।

चार्ट III.36: उपसमूहों में वार्षिक मुद्रास्फीति (वर्ष-दर-वर्ष) और गति (म-द-म)

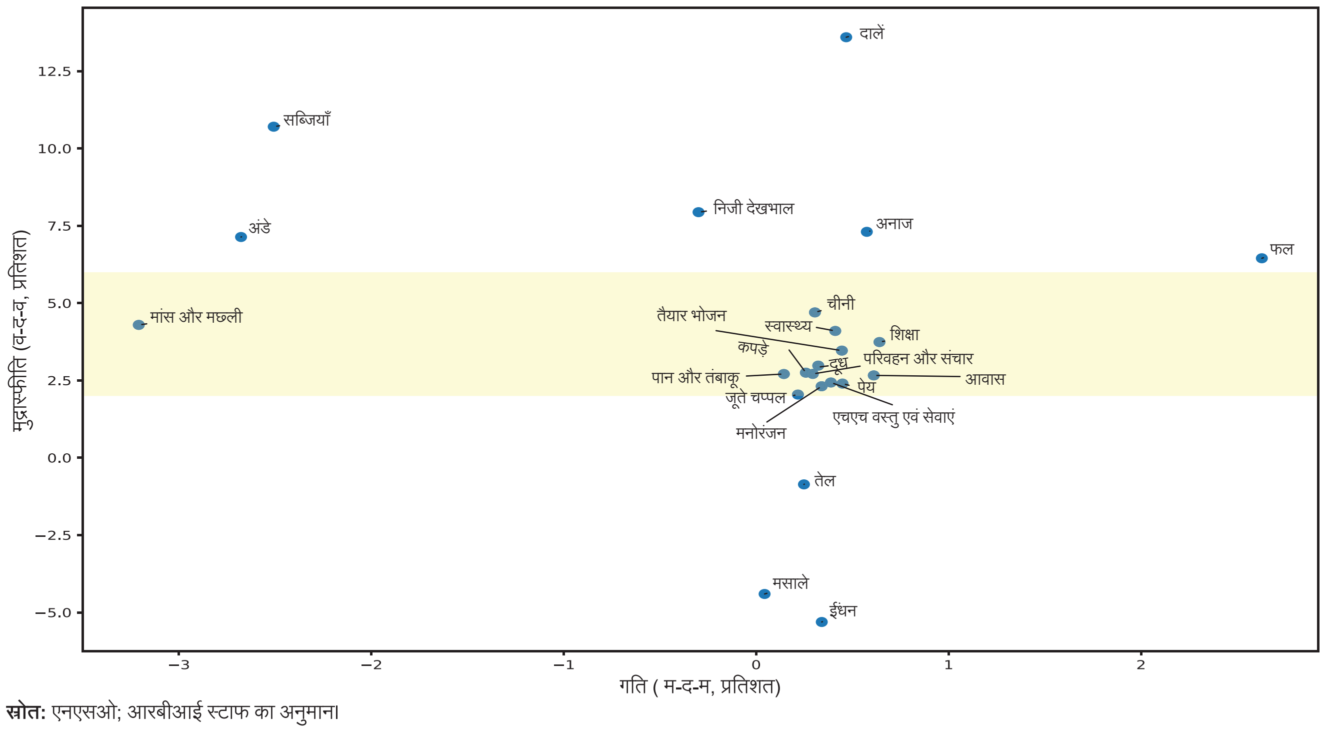

स्रोत: एनएसओ; आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

पर शहरी मुद्रास्फीति की 3.1 प्रतिशत से अधिक थी। अधिकांश राज्यों ने मुद्रास्फीति 6 प्रतिशत से कम दर्ज की (चार्ट III.38)।

सितम्बर के लिए अब तक (18 तारीख तक) खाद्य मूल्य के उच्च आवृत्ति आंकड़े अनाजों (मुख्यत चावल के लिए) और दालों

चार्ट III.37 : उपसमूहों में वार्षिक मुद्रास्फीति (जुलाई 2024 की तुलना में अगस्त 2024)

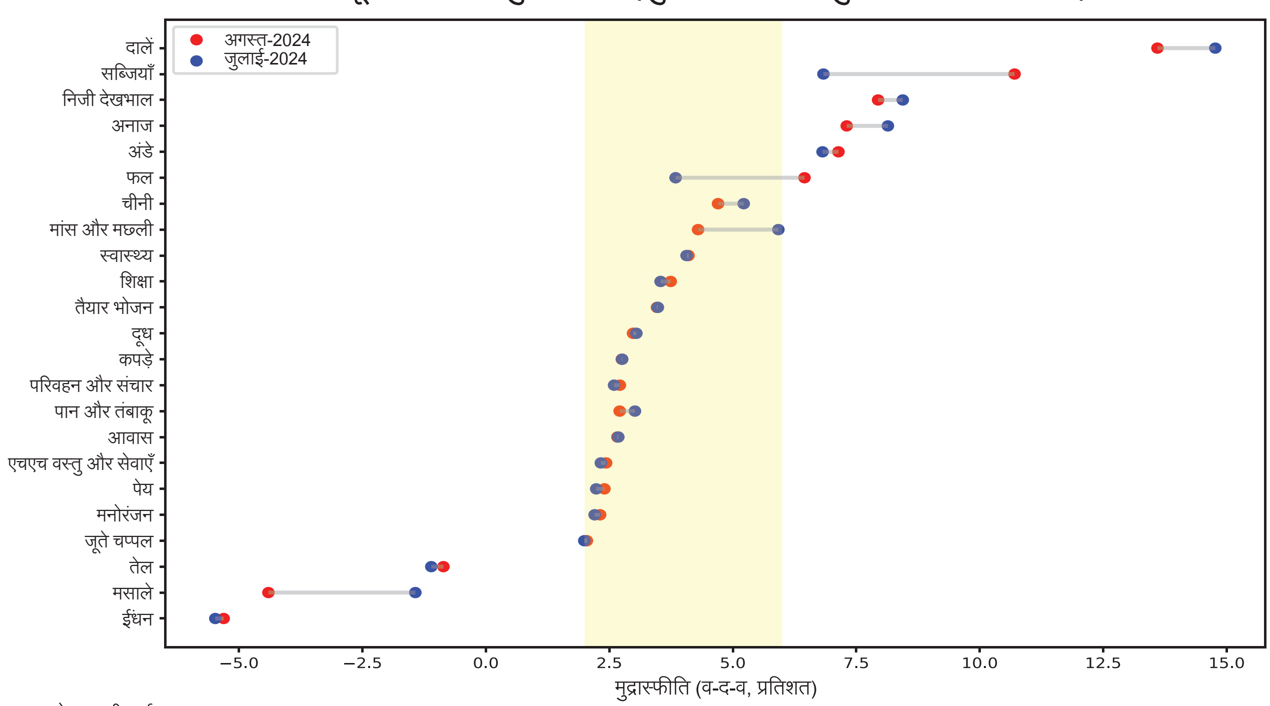

स्रोत: एनएसओ; आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

चार्ट III.38 : मुद्रास्फीति का स्थानिक वितरण: अगस्त 2024 (सीपीआई-संयुक्त, वर्ष-दर-वर्ष, प्रतिशत)

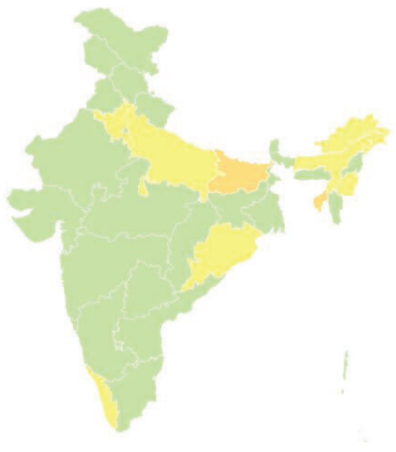

नोट: मानचित्र केवल दृष्टांत उद्देश्यों के लिए है।
स्रोत: एनएसओ; और आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

(चने को छोड़कर) की कीमतों में कमी दर्शाते हैं। सब्जियों में, आलू और टमाटर की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई, जबकि प्याज की कीमतों में वृद्धि दर्ज की गई। खाद्य तेल की कीमतें स्थिर रहीं (चार्ट III.39)।

पेट्रोल और डीजल के खुदरा बिक्री मूल्य सितंबर में अब तक (18 तारीख तक) अपरिवर्तित रखे गए थे। एलपीजी की कीमतें भी अपरिवर्तित रहीं, जबकि सब्सिडी वाले मिट्टी के तेल की कीमतों में कमी देखी गई (सारणी III.3)।

अगस्त 2024 के पीएमआई ने संकेत दिया कि इनपुट लागत और बिक्री मूल्य के विस्तार की दर विनिर्माण और सेवाओं दोनों के लिए कम रही। विनिर्माण पीएमआई इनपुट लागत पांच महीने के निचले स्तर पर आ गई, जबकि सेवा क्षेत्र में चार वर्षों

चार्ट III.39: डीसीए आवश्यक कमोडिटी की कीमतें

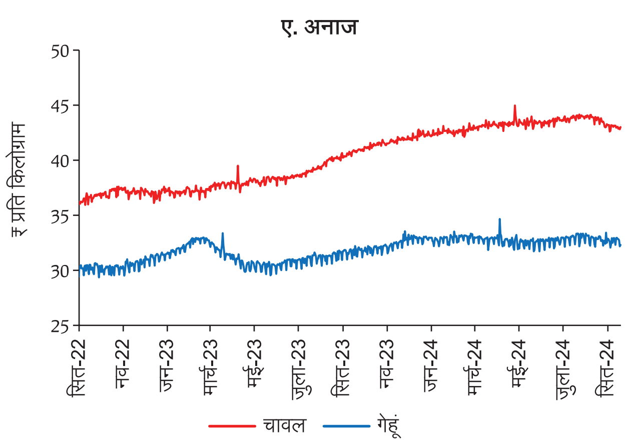

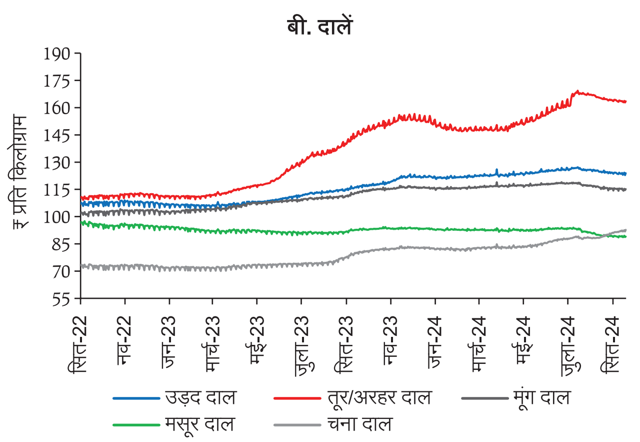

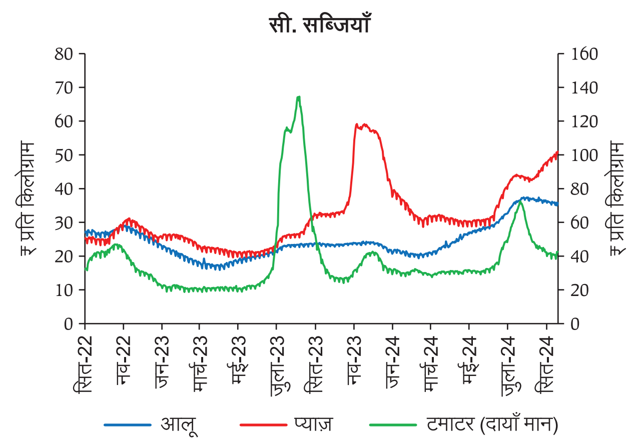

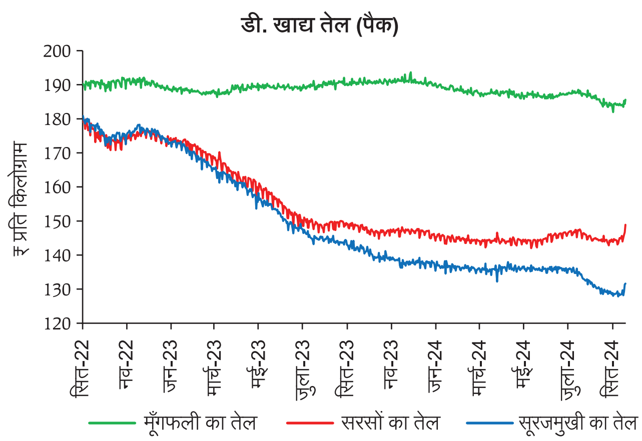

स्रोत: उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार; और आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

सारणी III.3: पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें

मद	इकाई	घरेलू कीमतें			माह-दर-माह (प्रतिशत)	
		सित-23	अग-24	सित-24^	अग-24	सित-24^
पेट्रोल	₹/लीटर	102.92	100.97	100.97	0.0	0.0
डीज़ल	₹/लीटर	92.72	90.42	90.42	0.0	0.0
केरोसिन (छूट सहित)	₹/लीटर	54.89	46.65	45.78	0.0	-1.9
एलपीजी (छूट रहित)	₹/सिलेंडर	913.25	813.25	813.25	0.0	0.0

^ : 1-18 सितंबर 2024 की अवधि के लिए।

टिप्पणी: केरोसिन तेल के अलावा, कीमतें चार प्रमुख महानगरों (दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई) में औसत इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) की कीमतों का प्रतिनिधित्व करती हैं। केरोसिन के लिए, कीमतें कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में सब्सिडी वाली कीमतों के औसत को दर्शाती हैं।

स्रोत: आईओसीएल; पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण प्रकोष्ठ (पीपीएसी); और आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

में इनपुट कीमतों में सबसे धीमी वृद्धि देखी गई (चार्ट III.40)। विनिर्माण के भीतर, बिक्री मूल्य और इनपुट लागत के बीच का अंतर अप्रैल 2020 के बाद से उच्चतम स्तर तक बढ़ गया।

2024-25 की पहली तिमाही के दौरान, अखिल भारतीय आवास मूल्य सूचकांक (एचपीआई)[14] पिछली तिमाही में 4.1 प्रतिशत और एक वर्ष पहले 5.1 प्रतिशत की वृद्धि से 3.3 प्रतिशत (व-द-व) बढ़ गया। क्रमिक (तिमाही-दर-तिमाही) आधार पर, अखिल भारतीय एचपीआई में 2024-25 की पहली तिमाही में 1.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जिसमें सूचकांक में शामिल दस प्रमुख शहरों में से नौ में वृद्धि देखी गई (चार्ट III.41)।

चार्ट III.40: पीएमआई इनपुट और आउटपुट कीमतें

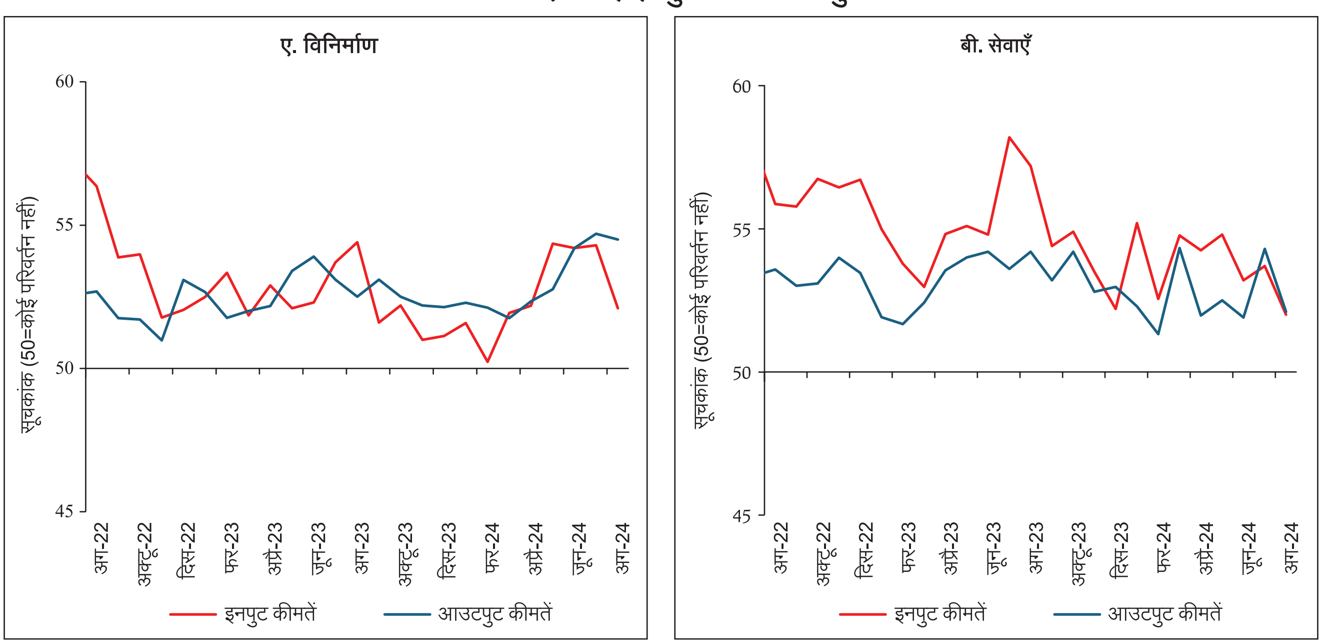

टिप्पणी: 50 का स्तर गतिविधि में कोई बदलाव नहीं होने के अनुरूप है और 50 से ऊपर का स्तर विस्तार को दर्शाता है और इसके विपरीत।

स्रोत: एस एंड पी ग्लोबल।

[14] आवास मूल्य सूचकांक (आधार: 2010-11=100) दस प्रमुख शहरों (अर्थात, अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, जयपुर, कानपुर, कोच्चि, कोलकाता, लखनऊ और मुंबई) में पंजीकरण अधिकारियों से प्राप्त लेनदेन-स्तर के आंकड़ों के आधार पर संकलित किया गया है।

चार्ट III.41: गृह मूल्य सूचकांक का उतार-चढ़ाव

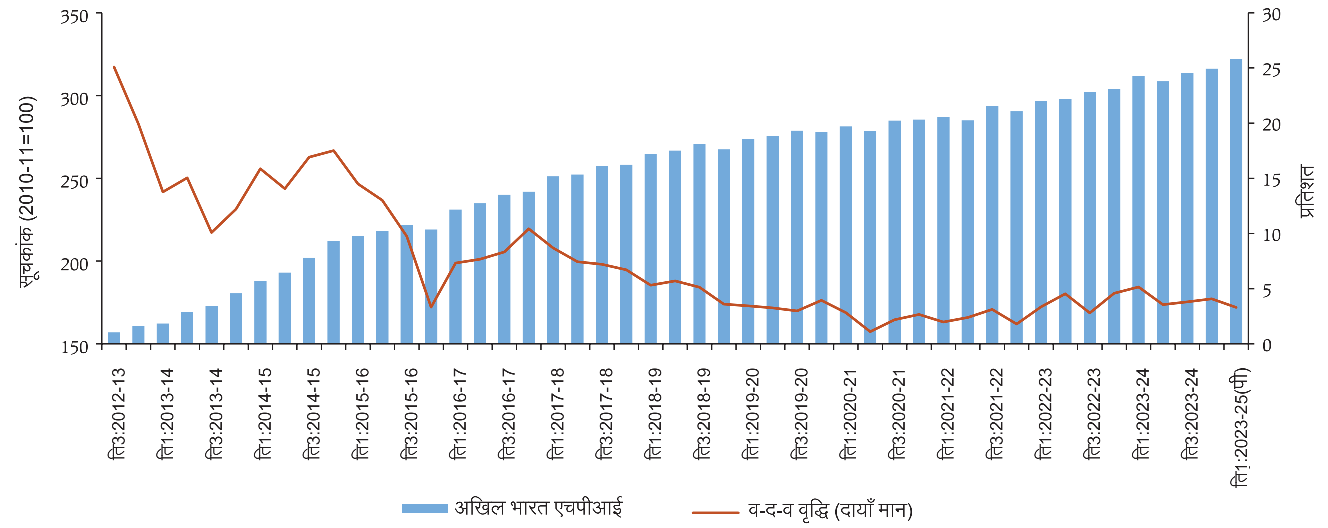

टिप्पणी : पी : आंकडे अनंतिम हैं।
स्रोत: राज्य सरकारों के पंजीकरण प्राधिकरण; और आरबीआई।

IV. वित्तीय स्थितियां

जीएसटी भुगतान के कारण सरकारी नकदी शेष के निर्माण से प्रेरित अगस्त के उत्तरार्ध में बैंकिंग प्रणाली में अधिशेष चलनिधि कम हो गई। हालांकि, सितंबर की शुरुआत में, सरकारी खर्च में तेजी के कारण बैंकिंग प्रणाली में चलनिधि की वापसी हुई। कुल मिलाकर, चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ़) के तहत औसत दैनिक निवल अवशोषण 16 अगस्त से 17 सितंबर 2024 के दौरान घटकर 1.45 लाख करोड़ रुपये हो गया, जो 16 जुलाई और 15 अगस्त 2024 के दौरान 1.52 लाख करोड़ रुपये था (चार्ट IV.1)।

16 अगस्त से 17 सितंबर 2024 तक 1.58 लाख करोड़ रुपये के औसत कुल अवशोषण में से, स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) के तहत धन का स्थानन लगभग 63 प्रतिशत था। रिज़र्व बैंक ने दो मुख्य और चौदह परिमार्जन परिवर्तनीय दर

चार्ट IV.1: चलनिधि परिचालन

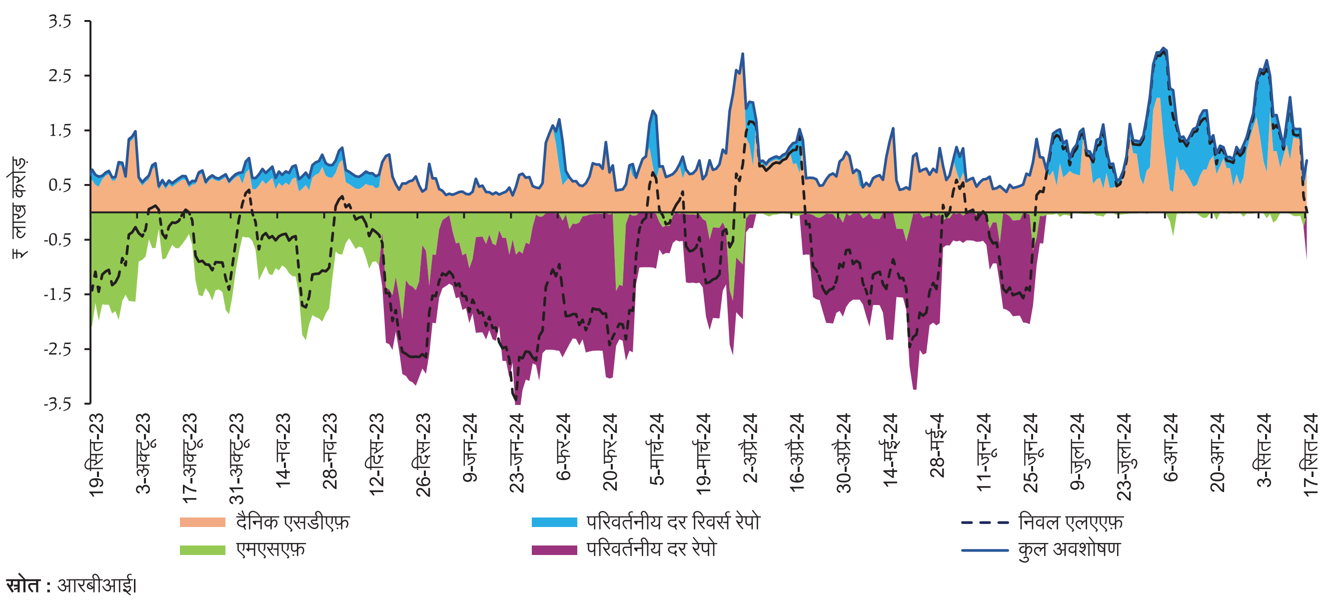

स्रोत : आरबीआई।

रिवर्स रेपो (वीआरआरआर) ऑपरेशन किए, जिनकी परिपक्वता एकदिवस से लेकर 7 दिनों तक थी, जो बैंकिंग प्रणाली से संचयी रूप से ₹5.41 लाख करोड़ अवशोषित करते थे। बैंकों ने लंबी अवधि के लिए चलनिधि के साथ भाग लेने में अनिच्छा दिखाई है, जैसा कि मुख्य परिचालन में कम ऑफर-कवर अनुपात से पता चलता है।[15] 3-दिन की परिपक्वता का एक परिवर्तनीय दर रेपो (वीआरआर)परिचालन भी 17 सितंबर 2024 को आयोजित किया गया, जिसमें बैंकिंग प्रणाली में ₹0.83 लाख करोड़ का अंतर्वेशन किया गया। सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ़) के तहत औसत दैनिक उधार 16 अगस्त से 17 सितंबर, 2024 के दौरान 0.05 लाख करोड़ रुपये रहा, जबकि 16 जुलाई और 15 अगस्त 2024 के दौरान 0.04 लाख करोड़ रूपये था।

भारित औसत कॉल दर (डब्ल्यूएसीआर) 16 जुलाई से 15 अगस्त, 2024 के दौरान 6.51 प्रतिशत की तुलना में 16 अगस्त और 17 सितंबर के दौरान औसतन 6.53 प्रतिशत रही (चार्ट IV.2ए)। संपार्श्विक खंड में, त्रिपक्षीय रेपो दर और बाजार रेपो दर डब्ल्यूएसीआर के साथ-साथ रही, जो इसी अवधि के दौरान नीतिगत रेपो दर से नीचे क्रमशः 13 आधार अंक (बीपीएस) और 5 बीपीएस औसत है (चार्ट IV.2बी)।

अल्पावधि मुद्रा बाजार खंड में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) द्वारा जारी 3 महीने के वाणिज्यिक पत्र (सीपी) और 3 महीने के खज़ाना बिल (टी-बिल) पर प्रतिफल मोटे तौर पर स्थिर रहा। इसके विपरीत, 3 माह के जमा प्रमाणपत्रों (सीडी) पर दरों में वृद्धि हुई (चार्ट IV.2बी)। मुद्रा बाजार में औसत जोखिम प्रीमियम (3-महीने के सीपी और 91-दिवसीय टी-बिल दरों के बीच स्प्रेड) 16 अगस्त से 17 सितंबर 2024 की अवधि के दौरान 107 बीपीएस था, जो 16 जुलाई से 15 अगस्त 2024 की तुलना में 3 बीपीएस अधिक था।

प्राथमिक बाजार में, ऋण और जमा वृद्धि के बीच अंतर को पाटने के लिए बैंकों की वित्त पोषण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 2024-25 (6 सितंबर तक) के दौरान ऋण जमा जारी करना 65 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) से बढ़कर ₹4.51 लाख करोड़ हो गया, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में ₹2.72 लाख करोड़ से काफी अधिक है (चार्ट IV.3)। सीपी निर्गम भी 2024-25 (31 अगस्त तक) के दौरान बढ़कर 6.28 लाख करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में 5.88 लाख करोड़ रुपये से अधिक है। रिज़र्व बैंक द्वारा एनबीएफसी को दिए जाने वाले बैंक ऋणों पर जोखिम भार बढ़ाने के साथ, एनबीएफसी द्वारा सीपी जारी करने में वृद्धि हुई क्योंकि उन्होंने बैंकों से परे अपने वित्तपोषण स्रोतों का विविधीकरण किया।

चार्ट IV.2 : नीतिगत कॉरिडोर और मुद्रा बाजार दरें

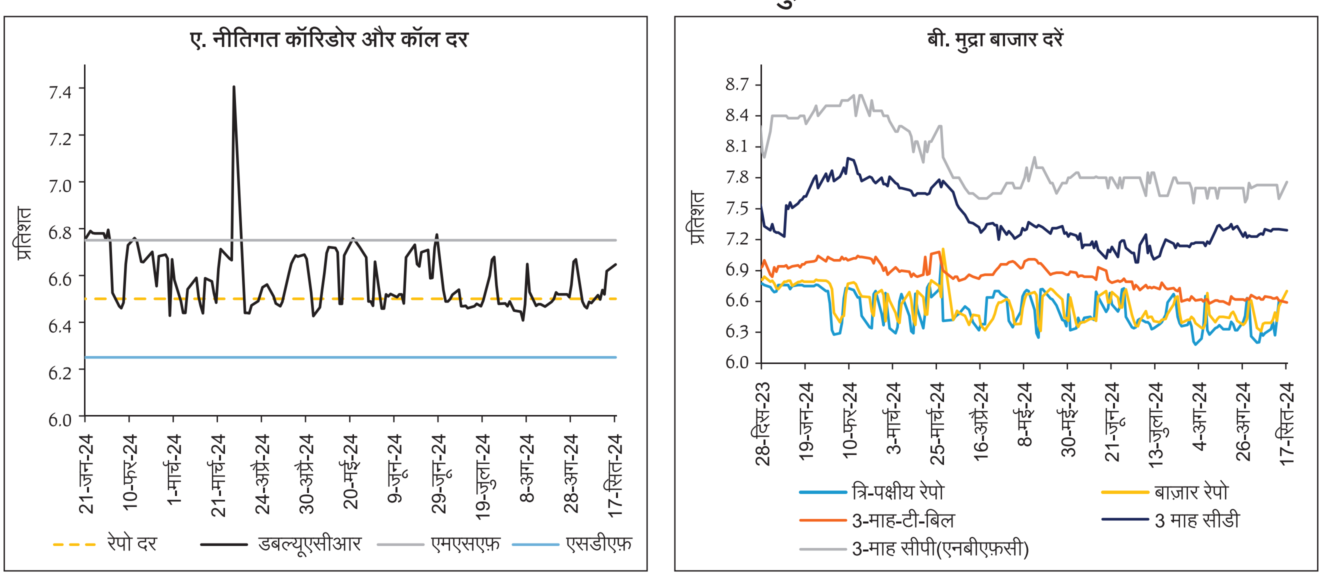

स्रोत: आरबीआई; सीसीआईएल; और ब्लूमबर्ग।

[15] 23 अगस्त और 6 सितंबर को आयोजित 14-दिवसीय वीआरआरआर नीलामी ने ₹1.50 लाख करोड़ की संचयी अधिसूचित राशि के मुकाबले क्रमशः ₹20,377 करोड़ और ₹17,083 करोड़ की बोलियां आकर्षित कीं।

चार्ट IV.3: जमा प्रमाणपत्र (सीडी) और वाणिज्यिक पत्र (सीपी) - पाक्षिक निर्गम

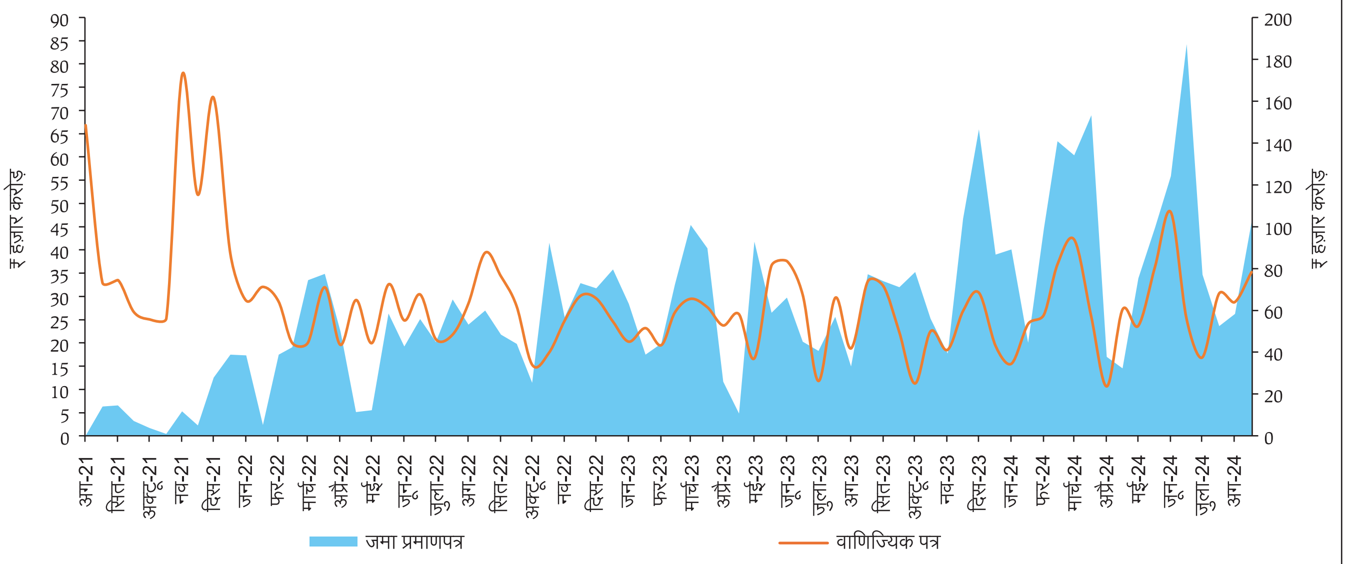

स्रोत : आरबीआई।

निर्धारित आय वाले भाग में अगस्त और सितंबर (17 सितंबर तक) में घरेलू बॉण्ड प्रतिफल में कमी आई है। 10-वर्षीय भारतीय बेंचमार्क सरकारी प्रतिभूति (जी-सेक) पर प्रतिफल 6.76 - 6.87 प्रतिशत की संकीर्ण सीमा में चला गया (चार्ट IV.4ए)। 16 अगस्त - 17 सितंबर के दौरान, औसत सावधि स्प्रेड (10-वर्ष से 91-दिवसीय टी-बिल घटाकर) 16 जुलाई - 15 अगस्त के दौरान 26 बीपीएस से 22 बीपीएस तक कम हो गया। कुल मिलाकर, सावधि संरचना में जी-सेक प्रतिफल में गिरावट मोटे तौर पर प्रतिफल वक्र के नीचे की ओर गिरावट में प्रकट हुई (चार्ट IV.4बी)।

कॉर्पोरेट बॉण्ड प्रतिफल ने मिश्रित उतार-चढ़ाव प्रदर्शित किए, जबकि संबंधित जोखिम प्रीमियम आमतौर पर अगस्त 16 - सितंबर 16, 2024 के दौरान बढ़ गया (सारणी IV.1)। 2024-25 (जुलाई तक) के दौरान, कॉर्पोरेट बॉण्ड निर्गम पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान ₹2.90 लाख करोड़ से कम ₹2.53 लाख करोड़

चार्ट IV.4: जी-सेक बाजार में गतिविधियां

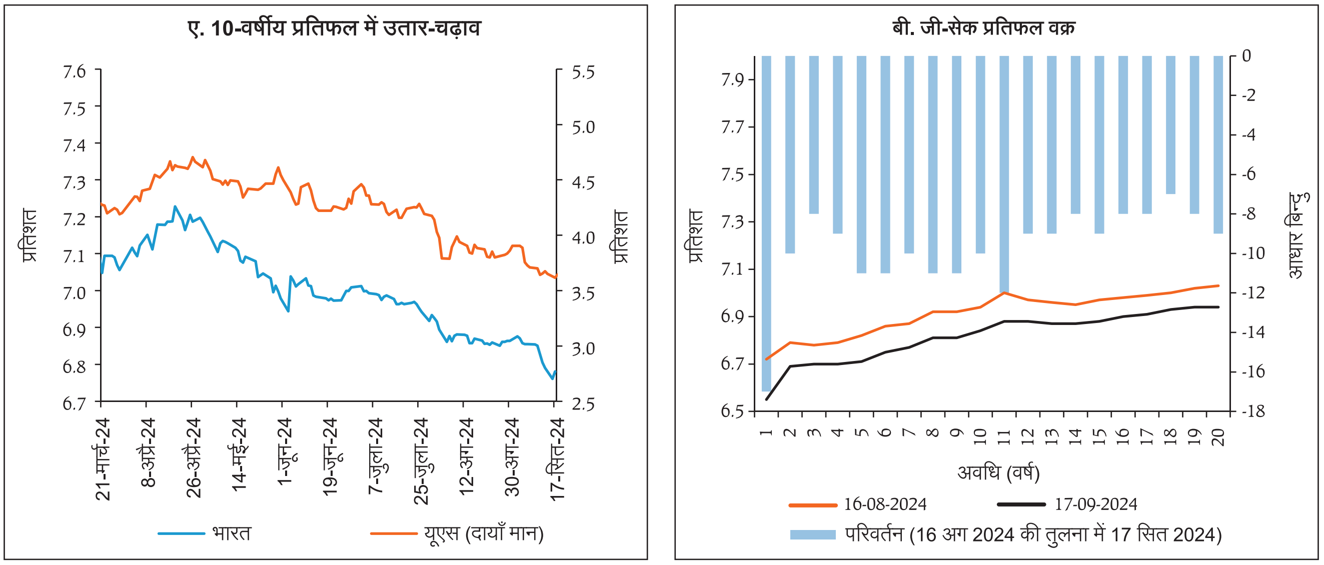

स्रोत: ब्लूमबर्ग; सीसीआईएल; और आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

सारणी IV.1: वित्तीय बाजार - दरें और स्प्रेड

लिखत	ब्याज दरें (प्रतिशत)			स्प्रेड (आधार बिंदु) (संबंधित जोखिम पर - मुक्त दर)		
	जुला 16, 2024 – अग 14, 2024	अग 16, 2024 – सित 16, 2024	भिन्नता (बीपीएस में)	जुला 16, 2024 – अग 14, 2024	अग 16, 2023 – सित 16, 2024	भिन्नता (बीपीएस में)
1	2	3	(4 = 3-2)	5	6	(7 = 6-5)
कॉर्पोरेट बॉन्ड						
(i) एएए (1-वर्ष)	7.69	7.94	25	80	113	33
(ii) एएए (3-वर्ष)	7.83	7.81	-2	88	95	7
(iii) एएए (5-वर्ष)	7.76	7.75	-1	79	86	7
(iv) एए (3 वर्ष)	8.53	8.56	3	158	170	12
(v) बीबीबी-(3-वर्ष)	12.12	12.14	2	517	528	11

टिप्पणी: प्रतिफल और स्प्रेड की गणना मासिक औसत के रूप में की जाती है।
स्रोत: एफ़आईएमएमडीए; और ब्लूमबर्ग।

थे। हालांकि, जुलाई 2024 के दौरान कॉर्पोरेट बॉण्ड निर्गम बढ़कर 94,306 करोड़ रुपये हो गए, जो 2024-25 में अब तक का सबसे अधिक मासिक निर्गम है और एक वर्ष पहले के ₹54,269 करोड़ रुपये का लगभग दोगुना है।

आरक्षित मुद्रा (आरएम), नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) में बदलाव के पहले दौर के प्रभाव को छोड़कर, 13 सितंबर 2024 को 5.9 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि दर्ज की गई (एक वर्ष पहले 8.4 प्रतिशत) [चार्ट IV.5]। आरएम के सबसे बड़े घटक, संचलन में मुद्रा (सीआईसी) में वृद्धि, 13 सितंबर 2024 को बढ़कर 6.1 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) हो गई, जो 17 मई 2024 को 3.0 प्रतिशत थी, जिसका कारण ₹2000 बैंकनोट[16] की निकासी का आधार प्रभाव था, जिसका 97.96 प्रतिशत बैंकिंग प्रणाली में वापस कर दिया गया है, ज्यादातर जमा के रूप में (31 अगस्त 2024 तक)।

आपूर्ति पक्ष (आस्तियां) पर, विदेशी मुद्रा आस्तियां (एनएफए के 90 प्रतिशत से अधिक के) ने 13 सितंबर 2024 तक 15.9

चार्ट IV.5 : आरक्षित मुद्रा और संचलन में मुद्रा में वृद्धि

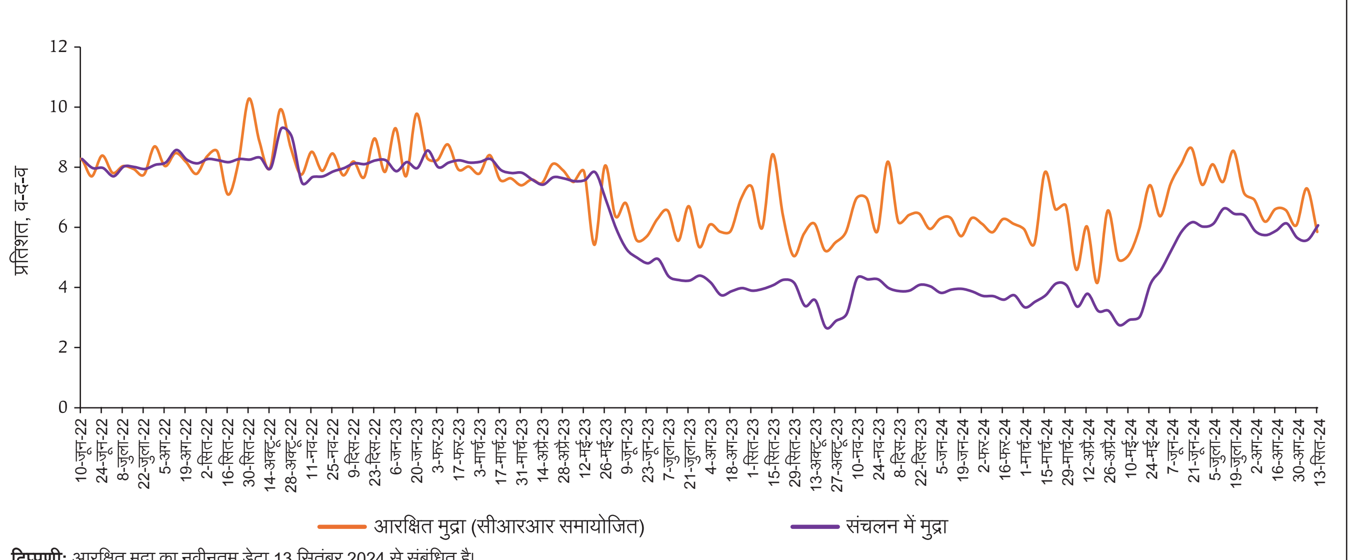

टिप्पणी: आरक्षित मुद्रा का नवीनतम डेटा 13 सितंबर 2024 से संबंधित है।
स्रोत: आरबीआई।

[16] 19 मई 2023 को घोषित।

चार्ट IV.6: आरबीआई की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां (एनएफए) - वृद्धि

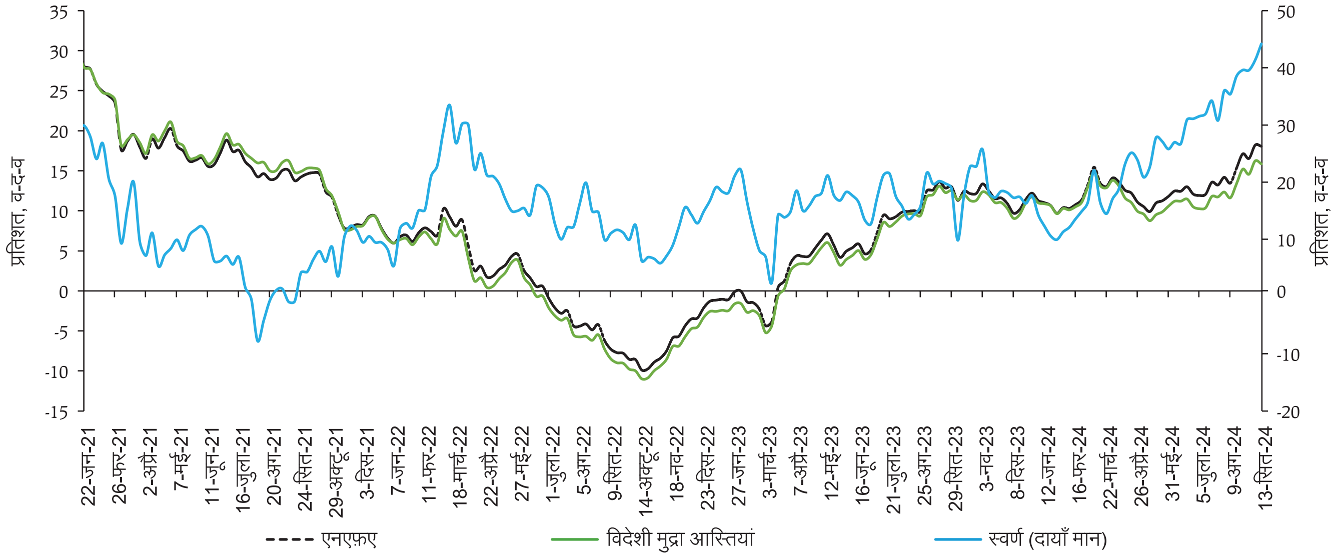

स्रोत : आरबीआई।

प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की दोहरे अंकों की वृद्धि दर्ज करना जारी रखा। स्वर्ण – एनएफए का अन्य प्रमुख घटक – 44.2 प्रतिशत बढ़ा, जो दिसंबर 2020 के बाद से सबसे अधिक है, मुख्य रूप से स्वर्ण की कीमतों में वृद्धि के कारण पुनर्मूल्यांकन लाभ के कारण रहा (चार्ट IV.6)।

मुद्रा आपूर्ति (एम$_3$) में 6 सितंबर 2024 को 10.4 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि हुई (एक वर्ष पहले 11.1 प्रतिशत)। 17 बैंकों के पास सकल जमा, जो एम$_3$ का लगभग 86 प्रतिशत था, 11.1 प्रतिशत (एक वर्ष पहले 12.3 प्रतिशत) बढ़ गया। एससीबी की ऋण वृद्धि 6 सितंबर 2024 को 14.7 प्रतिशत थी (एक वर्ष पहले 15.1 प्रतिशत) [चार्ट IV.7]।

चार्ट IV.7: एससीबी की एम$_3$ वृद्धि और ऋण वृद्धि - आधार प्रभाव और संवेग

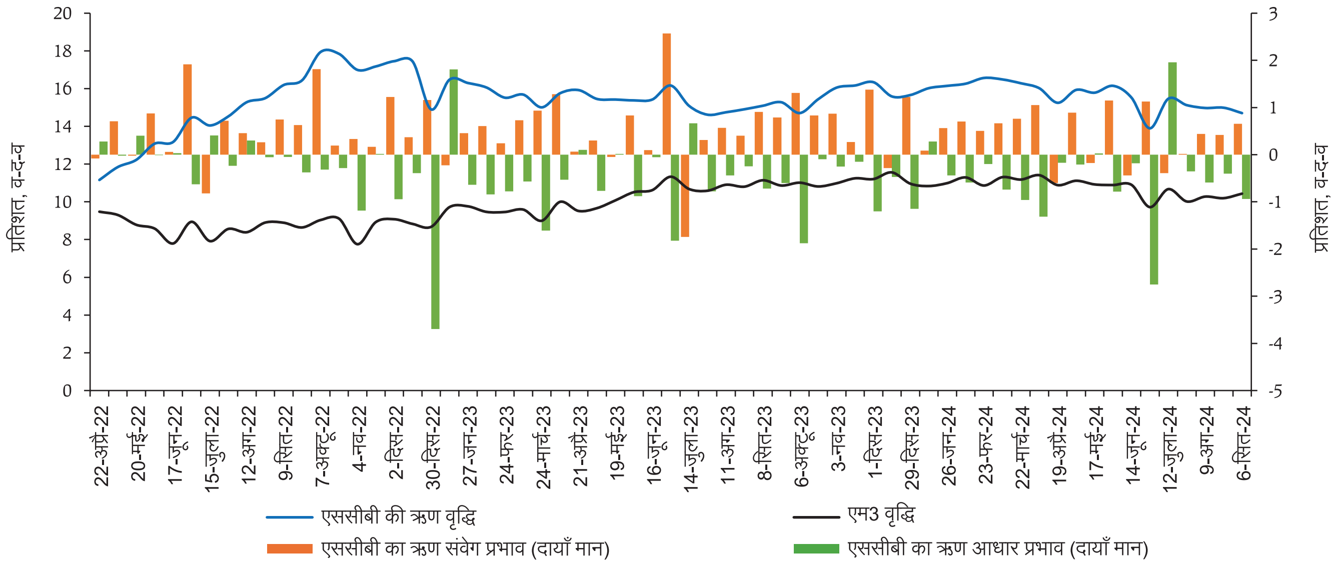

स्रोत : आरबीआई।

17 बैंक के साथ गैर-बैंक के विलय के प्रभाव को छोड़कर (1 जुलाई 2023 से प्रभावी)।

चार्ट IV.8: एससीबी की सकल जमाराशियां, ऋण वृद्धि और जमाराशियों के बकाया प्रमाणपत्र

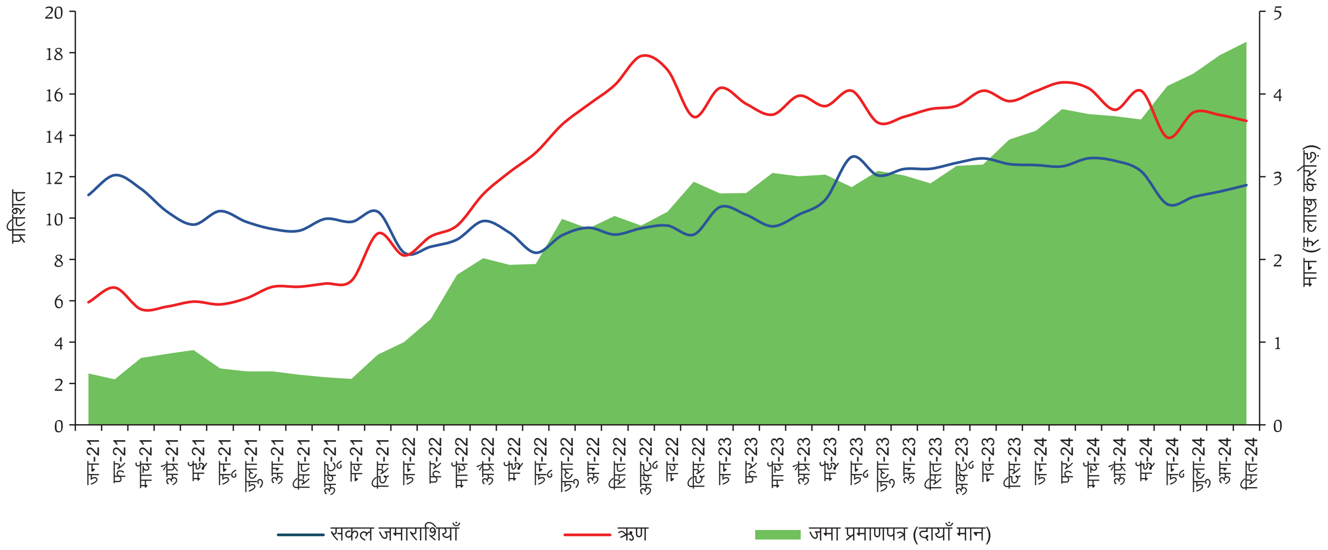

स्रोत : आरबीआई।

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की जमा वृद्धि[18], जो ₹2000 के बैंक नोटों की वापसी के बाद बढ़ी, अप्रैल 2023 से दोहरे अंकों में बनी हुई है (चार्ट IV.8)। सीडी निर्गम जमा आधार का पूरक होता है।

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का वृद्धिशील ऋण-जमा अनुपात मार्च 2024 के अंत में 95.8 से घटकर 6 सितंबर 2024 को 95.3 हो गया (चार्ट IV.9)। सीआरआर और सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) के लिए क्रमशः 4.5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत की सांविधिक आवश्यकताओं के साथ, लगभग 77 प्रतिशत जमा 6 सितंबर 2024 तक ऋण विस्तार के लिए बैंकिंग प्रणाली में उपलब्ध थे।

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ऋण में मजबूत गति से वृद्धि जारी रही (चार्ट IV.10)। हालांकि व्यक्तिगत ऋण खंड (आवास और गैर-आवास) में वृद्धि हाल के दिनों में कम हो गई

चार्ट IV.9: वृद्धिशील ऋण-जमा अनुपात

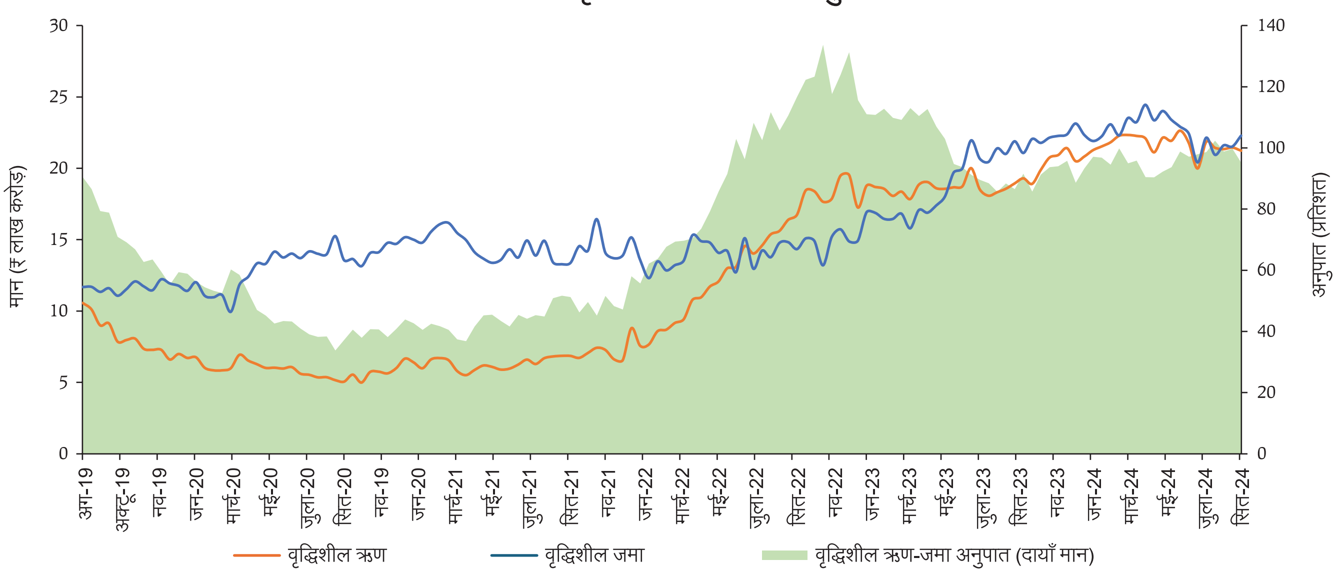

स्रोत : आरबीआई।

18 विलय के प्रभाव को छोड़कर।

चार्ट IV.10: बैंक ऋण में वार्षिक वृद्धि - प्रमुख क्षेत्र

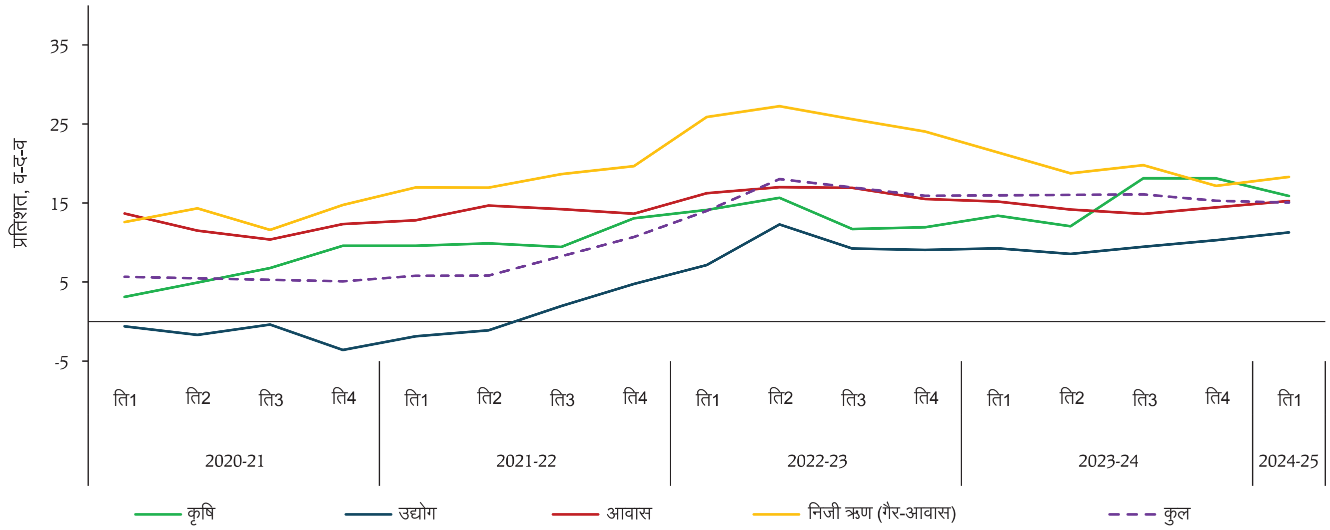

टिप्पणी : डेटा जुलाई 2023 से बैंक के साथ गैर-बैंक के विलय के प्रभाव को बाहर करता है।
स्रोत: आरबीआई।

है, यह समग्र ऋण विस्तार का प्रमुख वाहक बना हुआ है और हेडलाइन ऋण वृद्धि से अधिक जारी है। पिछली तिमाही में उद्योग को ऋण दो अंकों की रिकॉर्ड वृद्धि दर तक पहुंच गया है।

निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का ऋण, जो कुल अग्रिमों का लगभग एक चौथाई है, ने अपनी मजबूत वृद्धि जारी रखी, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं को ऋण देना 2024-25 की प्रथम तिमाही में कम हो गया (चार्ट IV.11ए)। कार्यशील पूंजी और मीयादी ऋण दोनों ने बैंक ऋण वृद्धि को बढ़ावा दिया है (चार्ट IV.11बी)।

मई 2022 से नीतिगत रेपो दर में 250 आधार अंक की वृद्धि की प्रतिक्रिया में, बैंकों ने अपनी रेपो-लिंक्ड बाह्य बेंचमार्क-आधारित उधार दरों (ईबीएलआर) को समान परिमाण से

चार्ट IV.11: बैंक ऋण में वार्षिक वृद्धि

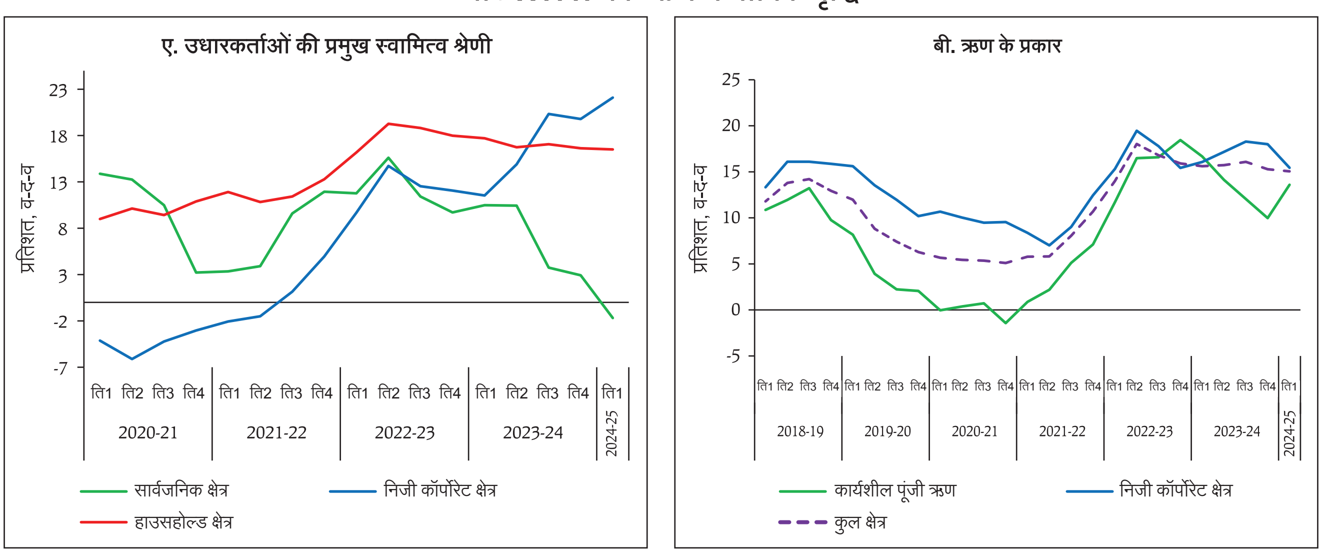

टिप्पणी: डेटा जुलाई 2023 से बैंक के साथ गैर-बैंक के विलय के प्रभाव को हटाकर है।
स्रोत: आरबीआई।

सारणी IV.2: बैंकों की जमा और उधार दरों में संचरण

(आधार बिंदु में परिवर्तन)

		मीयादी जमा दरें (बीपीएस)		उधार दर (बीपीएस)			
अवधि	**रेपो दर (बीपीएस)**	**डबल्यूएडीटीडीआर – नई जमाराशियाँ**	**डबल्यूएडीटीडीआर-बकाया जमाराशियाँ**	**ईबीएलआर**	**1-वर्षीय एमसीएलआर (माध्यिका)**	**डबल्यूएएलआर – नया रुपया ऋण**	**डबल्यूएएलआर-बकाया रुपया ऋण**
सहज अवधि फरवरी 2019 से मार्च 2022	-250	-259	-188	-250	-155	-232	-150
सख्त अवधि मई 2022 से जुला* 2024	+250	245	189	250	170	189	119

टिप्पणी: 1. ईबीएलआर पर डेटा 32 घरेलू बैंकों से संबंधित है।
2. *: एमसीएलआर पर डेटा अगस्त 2024 से संबंधित है।
3. **डब्ल्यूएएलआर**: भारित औसत उधार दर; **डब्ल्यूएडीटीडीआर:** भारित औसत घरेलू मीयादी जमा दर; **एमसीएलआर:** निधि-आधारित उधार दर की सीमांत लागत; **ईबीएलआर:** बाह्य बेंचमार्क-आधारित उधार दर।

स्रोत : आरबीआई।

संशोधित किया है। एससीबी की 1-वर्षीय औसत सीमांत लागत आधारित उधार दर (एमसीएलआर) मई 2022 से अगस्त 2024 के दौरान 170 आधार अंक बढ़ गई। नतीजतन, मई 2022 से जुलाई 2024 के दौरान नए और बकाया रुपया ऋणों पर भारित औसत उधार दरों (डबल्यूएएलआर) में क्रमशः 189 आधार अंक और 119 आधार अंक की वृद्धि हुई। जमा पक्ष पर, उसी अवधि के दौरान नए और बकाया रुपया मीयादी जमाओं पर भारित औसत घरेलू सावधि जमा दरों (डब्ल्यूएडीटीडीआर) में क्रमशः 245 आधार अंक और 189 आधार अंक की वृद्धि हुई (सारणी IV.2)।

बैंक समूहों में संचरण इंगित करता है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) की तुलना में निजी बैंकों के मामले में उधार दरों में वृद्धि अधिक थी; हालांकि, जमाराशियों के मामले में, यह उसी अवधि के दौरान पीएसबी के लिए अधिक रहा (चार्ट IV.12)।

मीयादी जमा पर बढ़ते प्रतिलाभ के अनुरूप, उच्च उपार्जन (जून 2024 में वर्ष-दर-वर्ष 16.6 प्रतिशत वृद्धि) रहा है (चार्ट IV.13)। कुल जमा में बचत जमा का भाग जून 2024 में घटकर 29.8 प्रतिशत रह गया, जो एक वर्ष पहले 31.8 प्रतिशत था।

चार्ट IV.12: बैंक समूहों में संचरण (मई 2022 से जुलाई 2024)

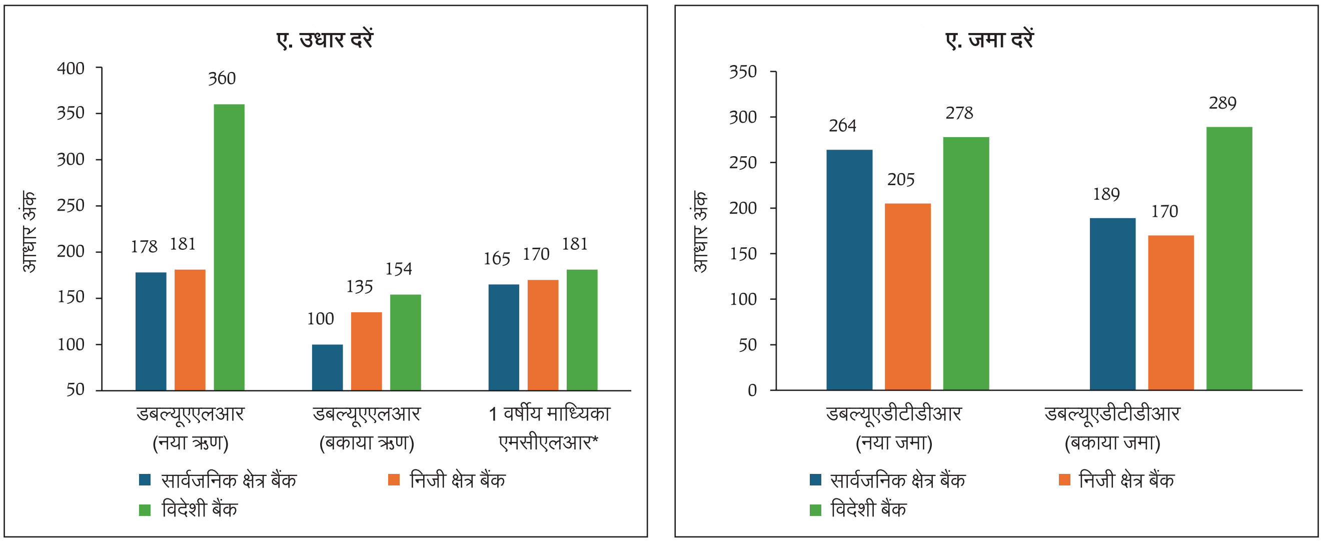

टिप्पणी: *1-वर्ष के माध्यिका एमसीएलआर पर डेटा मई 2022 से अगस्त 2024 से संबंधित है.
स्रोत: आरबीआई।

चार्ट IV.13: सकल जमाराशियों में वार्षिक वृद्धि - जमाराशियों का प्रकार

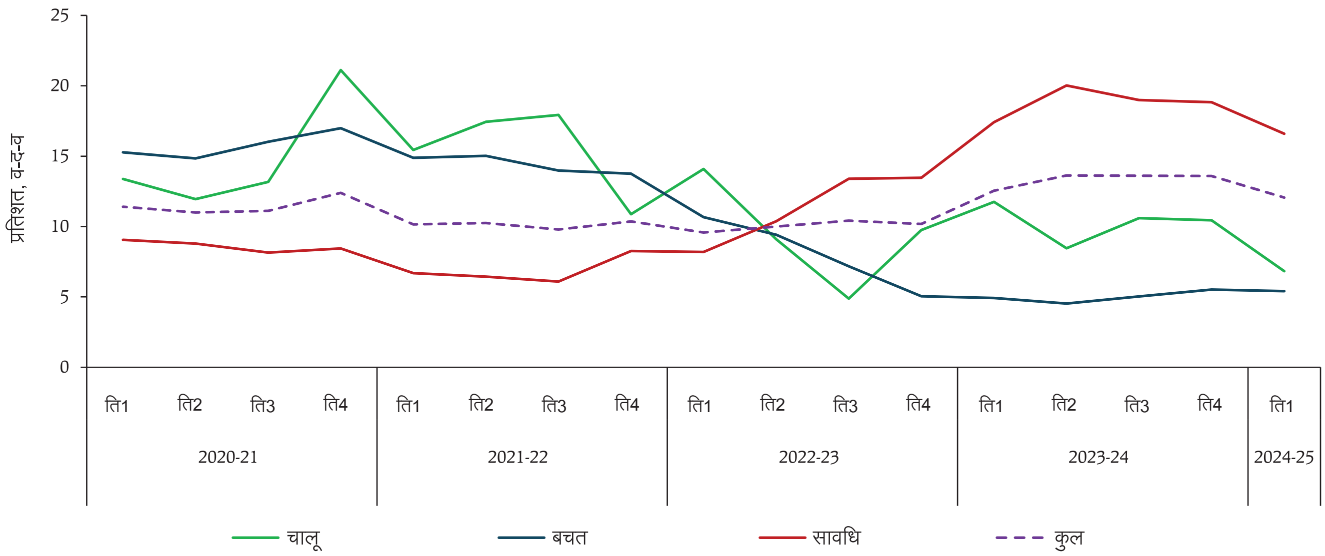

स्रोत : आरबीआई।

जैसा कि भूमिका में बताया गया है, 7 प्रतिशत से अधिक ब्याज दरों की पेशकश करने वाले मीयादी जमा का भाग जून 2024 में बढ़कर 66.9 प्रतिशत हो गया, जो मार्च 2023 में 33.5 प्रतिशत और मार्च 2022 में 4.5 प्रतिशत था (चार्ट IV.14)।

अमेरिकी फेडरल ओपन मार्केट कमेटी (एफओएमसी) के कार्यवृत्त जारी होने और जैक्सन होल इकोनॉमिक सिम्पोजियम) में यूएस फेड चेयरमैन की टिप्पणी के बाद अमेरिकी फेड दर में कटौती की उम्मीदों पर भू-राजनीतिक चिंताओं के बावजूद अगस्त की दूसरी छमाही में भारतीय इक्विटी बाजारों ने नई ऊंचाई हासिल की (चार्ट IV.15)। बेंचमार्क सूचकांक लगातार दस सत्रों में बढ़त के साथ बंद हुआ। हालांकि, नकारात्मक वैश्विक संकेतों के चलते सितंबर की शुरुआत में बाजार में गिरावट आई क्योंकि वैश्विक वृद्धि को लेकर चिंता और प्रौद्योगिकी कंपनियों के शेयरों में बिकवाली से निवेशकों की धारणा प्रभावित हुई। इसके बाद, बाजारों में तेजी आई और वैश्विक इक्विटी बाजारों में तेजी

चार्ट IV.14: बैंकों की सावधि जमा का ब्याज दर-वार हिस्सा

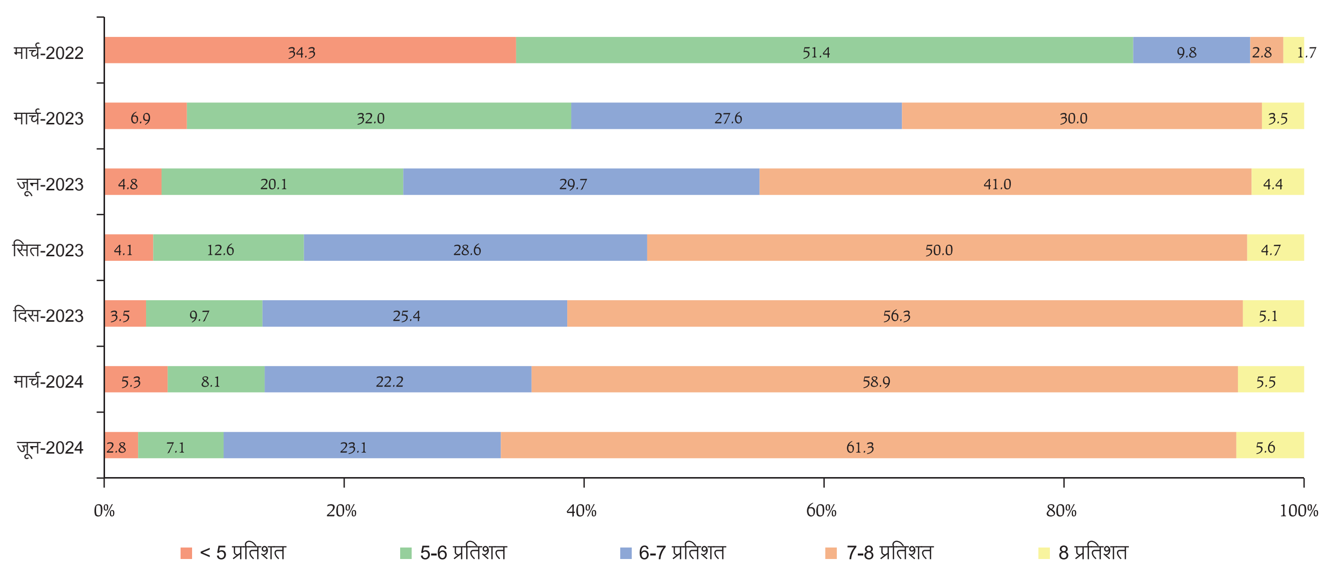

स्रोत : आरबीआई।

चार्ट IV.15: इक्विटी बाज़ार में रुझान

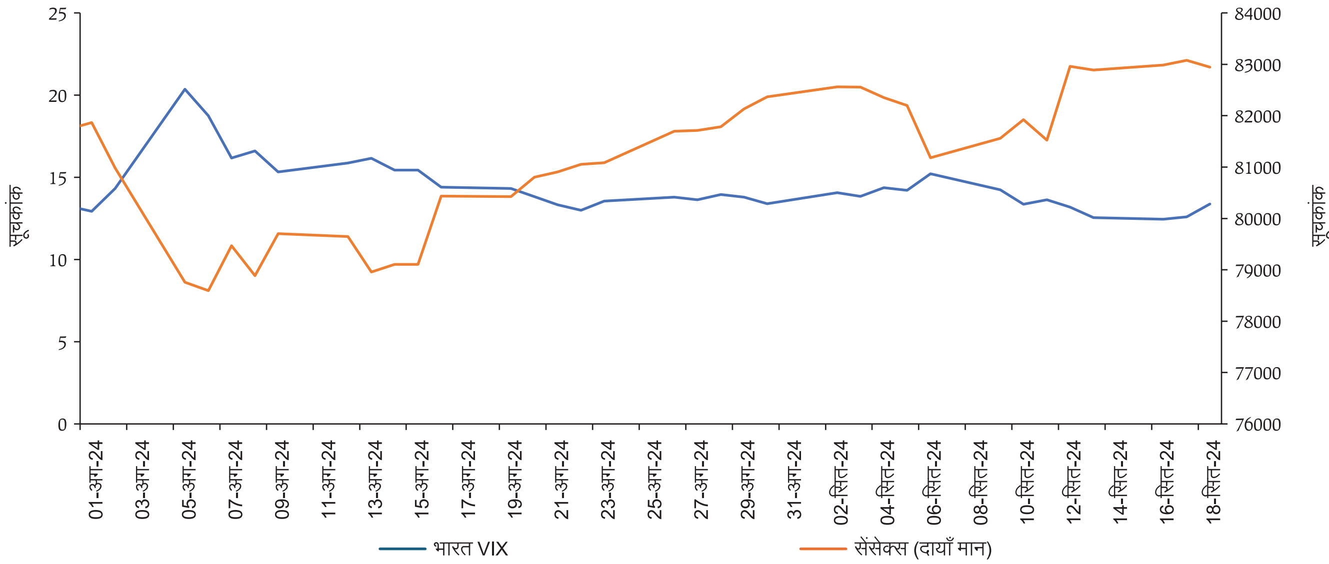

स्रोत : ब्लूमबर्ग।

के रुझानों को प्रतिबिंबित करते हुए नए सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गए। कुल मिलाकर, बीएसई सेंसेक्स 15 अगस्त 2024 से 6.9 प्रतिशत बढ़कर 20 सितंबर 2024 को 84,544 पर बंद हुआ।

प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ) के माध्यम से संसाधन जुटाना 2024 में अब तक मजबूत बना हुआ है, क्योंकि भारत ने 2024 की पहली छमाही में वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक आईपीओ (मात्रा के हिसाब से 27 प्रतिशत) किया, जो छोटे और मध्यम उद्यमों (एसएमई) की सार्वजनिक पेशकशों के कारण है। जुटाई गई राशि के संदर्भ में, आईपीओ के माध्यम से जुटाई गई कुल आय का 9 प्रतिशत भारत का था (चार्ट IV.16ए और 16बी)। प्राथमिक खंड में निवेशकों के उत्साह का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सितंबर के दूसरे सप्ताह में आवास वित्त कंपनी के आईपीओ ने ₹3 लाख करोड़ से अधिक की बोलियां प्राप्त कीं।

चार्ट IV.16 : पहली छमाही में वैश्विक आईपीओ में देशों का हिस्सा: 2024

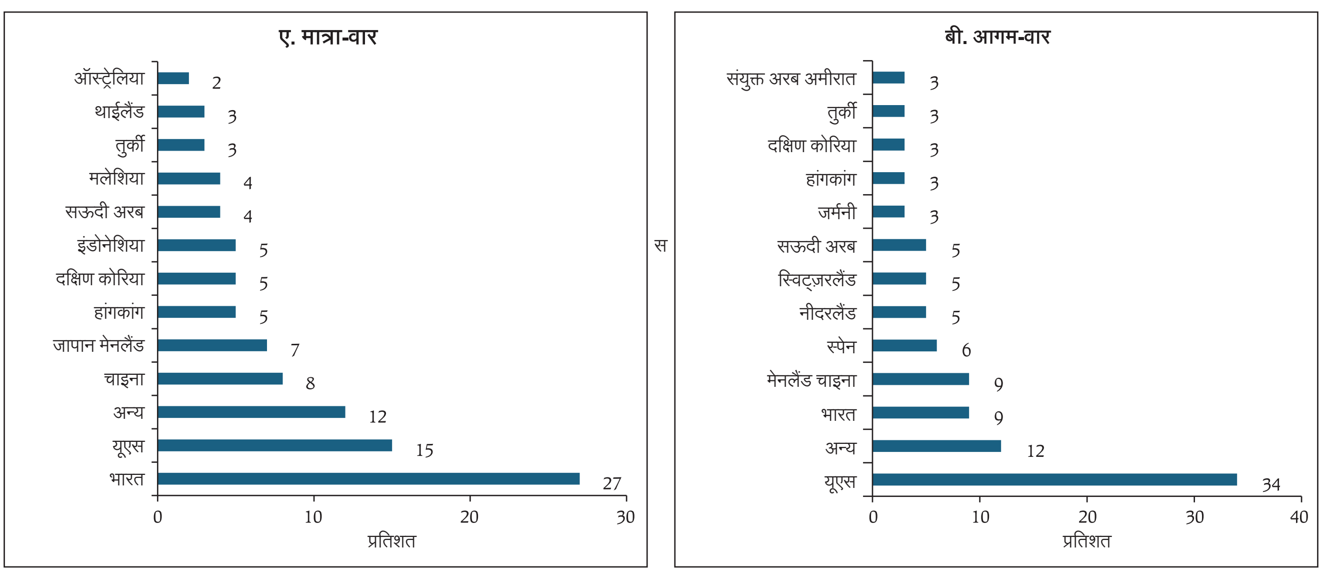

स्रोत: ईवाई वैश्विक आईपीओ रुझान की 2024 की दूसरी तिमाही की रिपोर्ट।

चार्ट IV.17: इक्विटी बाज़ार संसाधन जुटाना

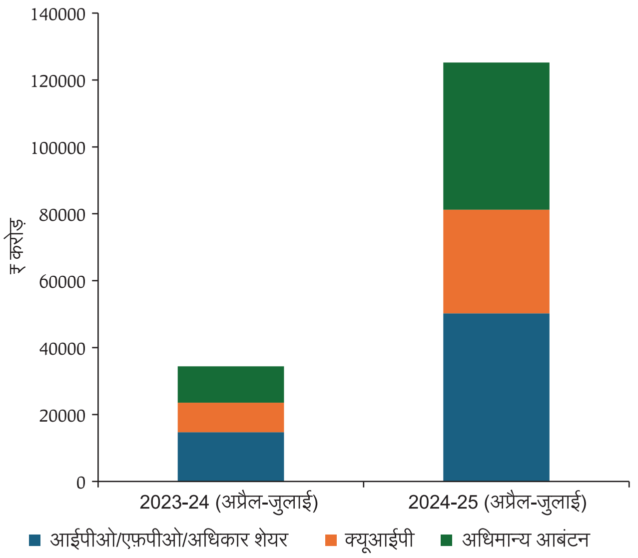

स्रोत : सेबी।

चार्ट IV.18: मेनबोर्ड आईपीओ में श्रेणी-वार ओवरसब्सक्रिप्शन

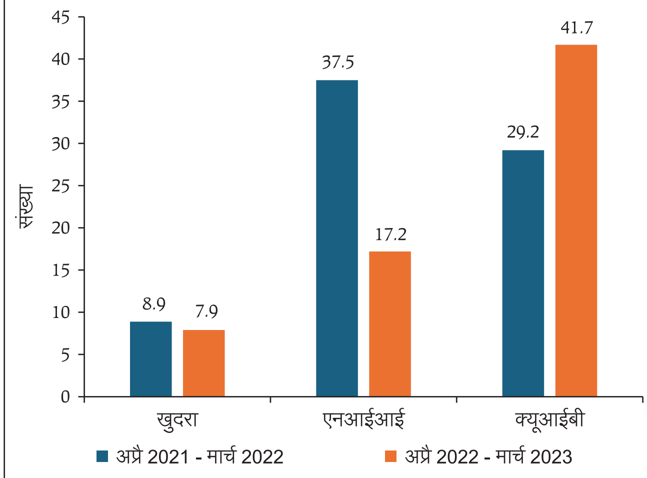

टिप्पणी: एनआईआई गैर-संस्थागत निवेशकों को संदर्भित करता है और क्यूआईबी क्वालिफाइड संस्थागत खरीदार को संदर्भित करता है।

स्रोत: सेबी।

अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थानन (क्यूआईपी) और अधिमान्य आवंटन जैसे अन्य तरीकों के माध्यम से संसाधन जुटाने में भी 2024-25 में अब तक महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई है[19], जो अनुकूल बाजार स्थितियों के कारण है (चार्ट IV.17)।

हाल के वर्षों में आईपीओ में निवेशकों की रुचि बढ़ी है।[20] जबकि प्राथमिक बाज़ार में उत्साह ने कंपनियों को पूंजी जुटाने में मदद की है, इसने प्रमोटरों के बारे में भी चिंता जताई है जो विशेष रूप से एसएमई वाले भाग में अपनी धारिता को ऊंची कीमतों पर ऑफलोड करने के अवसर का उपयोग करते हैं।[21] यह ध्यान दिया जा सकता है कि एनबीएफ़सी द्वारा आईपीओ फंडिंग पर सीलिंग[22] और आनुपातिकता-आधारित आवंटन विधि से लॉटरी-आधारित आवंटन विधि[23] में बदलाव जैसे नियामक परिवर्तनों ने मेनबोर्ड आईपीओ में पहले देखी गई भारी ओवरसब्सक्रिप्शन दरों में मदद की है (चार्ट IV.18)। एसएमई भाग में आनुपातिकता-आधारित आवंटन पद्धति की दृढ़ता आंशिक रूप से हाल के दिनों में एसएमई वाले भाग के सार्वजनिक प्रस्ताव में देखी गई भारी ओवरसब्सक्रिप्शन दरों की व्याख्या करती है।

अप्रैल-जुलाई 2024 के दौरान सकल आवक एफ़डीआई बढ़कर 27.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जो एक वर्ष पहले 22.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर था (चार्ट IV.19)। सकल

चार्ट IV.19: विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्रवाह

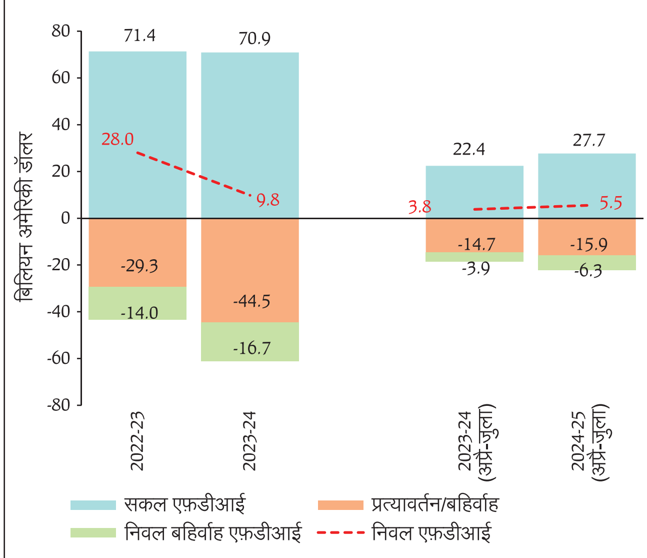

स्रोत : आरबीआइ।

[19] https://www.moneycontrol.com/news/business/markets/qips-gain-traction-to-hit-four-year-high-in-july-12791779.html#google_vignette

[20] https://www.sebi.gov.in/reports-and-statistics/research/sep-2024/study-analysis-of-investor-behavior-in-initial-public-offerings-ipos-_86385.html

[21] https://www.sebi.gov.in/media-and-notifications/press-releases/aug-2024/advisory-regarding-investment-in-securities-of-the-companies-listed-on-the-sme-segment-of-stock-exchanges_86205.html

[22] https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/Notification/PDFs/NT1127AD09AD866884557BD4DEEA150ACC91A.PDF

[23] 1 अप्रैल 2022 से, यथानुपात या आनुपातिकता आधारित आवंटन पद्धति को लॉटरी प्रणाली में बदल दिया गया।

एफडीआई प्रवाह में विनिर्माण, वित्तीय सेवाओं, संचार सेवाओं, कंप्यूटर सेवाओं, बिजली और अन्य ऊर्जा क्षेत्रों का योगदान तीन-चौथाई से अधिक है। तीन-चौथाई से अधिक प्रवाह के साथ, प्रमुख स्रोत देश सिंगापुर, मॉरीशस, नीदरलैंड, अमेरिका, बेल्जियम और जापान थे। सकल एफ़डीआई प्रवाह में वृद्धि के कारण अप्रैल-जुलाई 2024 के दौरान निवल एफ़डीआई बढ़कर 5.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जो एक वर्ष पहले 3.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।

निवल विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफ़पीआई) अगस्त 2024 के दौरान 4.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो लगातार तीसरे महीने निवल प्रवाह था (चार्ट IV.20ए)। इक्विटी वाले भाग में, वे अगस्त 2024 में संभावित अमेरिकी मंदी और येन कैरी ट्रेड के अनवाइंडिंग पर बढ़ती वैश्विक चिंताओं के कारण 1.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक कम हो गए। मंदी व्यापक आधार वाली थी, जिसने ईएमई में एफपीआई प्रवाह को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया, माह की शुरुआत में बड़ी बिकवाली के साथ, इसके बाद माह के मध्य से सुधार हुआ (चार्ट IV.20बी)। भारतीय इक्विटी के भीतर, वित्तीय सेवाओं और धातु और खनन ने सबसे अधिक बहिर्वाह दर्ज किया, जबकि हेल्थकेयर, टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं और उपभोक्ता सेवाओं को अगस्त 2024 में सबसे अधिक एफ़पीआई अंतर्वाह प्राप्त हुआ। अगस्त 2024 के दौरान 2.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवल प्रवाह वाला ऋण भाग एफ़पीआई प्रवाह पर हावी रहा। विभिन्न देशों के परिप्रेक्ष्य में, सितंबर 2023 में जेपी मॉर्गन के जीबीआई-ईएम सूचकांक में भारत सरकार के बॉण्ड को शामिल करने की घोषणा के बाद से भारतीय क़र्ज़ आकर्षक रहा। सितंबर 2024 (16 सितंबर तक) के दौरान, निवल एफपीआई अंतर्वाह 5.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।

अनिवासी जमा ने अप्रैल-जुलाई 2024 के दौरान एक वर्ष पहले 3.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में 5.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवल प्रवाह दर्ज किया, जिसमें सभी तीन खातों अर्थात् अनिवासी (बाहरी) रुपया खाते [एनआर (ई) आरए], अनिवासी साधारण (एनआरओ) और विदेशी मुद्रा अनिवासी [एफसीएनआर (बी)] खातों में उच्च प्रवाह रहा।

जुलाई 2024 (म-द-म) में बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) का पंजीकरण बढ़ा। अप्रैल-जुलाई 2024 के दौरान, हालांकि, यह पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 37.5 प्रतिशत कम था (चार्ट IV.21ए)। 2024-25 के दौरान अब तक सकल संवितरण (12.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर) और निवल ईसीबी प्रवाह (2.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर) दोनों पिछले वर्ष की इसी अवधि की

चार्ट IV.20: निवल पोर्टफोलियो निवेश

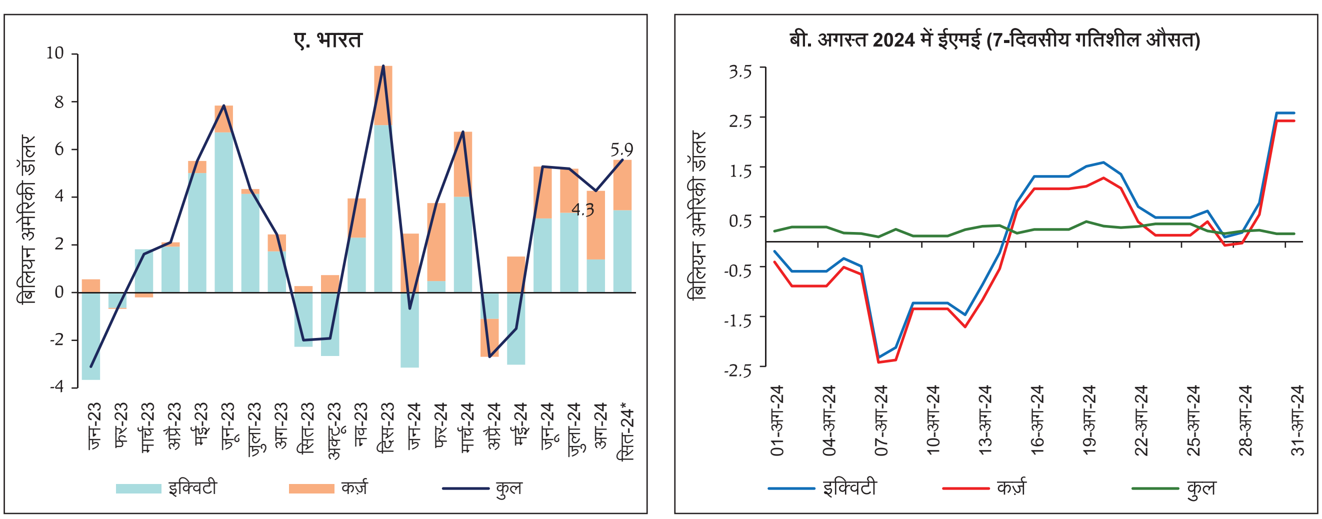

टिप्पणियाँ: 1. ऋण में स्वैच्छिक प्रतिधारण मार्ग और हाइब्रिड लिखतों के तहत निवेश शामिल हैं।
2. *: 16 सितंबर 2024 तक का डेटा।

स्रोत: नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल); और अंतरराष्ट्रीय वित्त संस्थान।

चार्ट IV.21: बाह्य वाणिज्यिक उधार

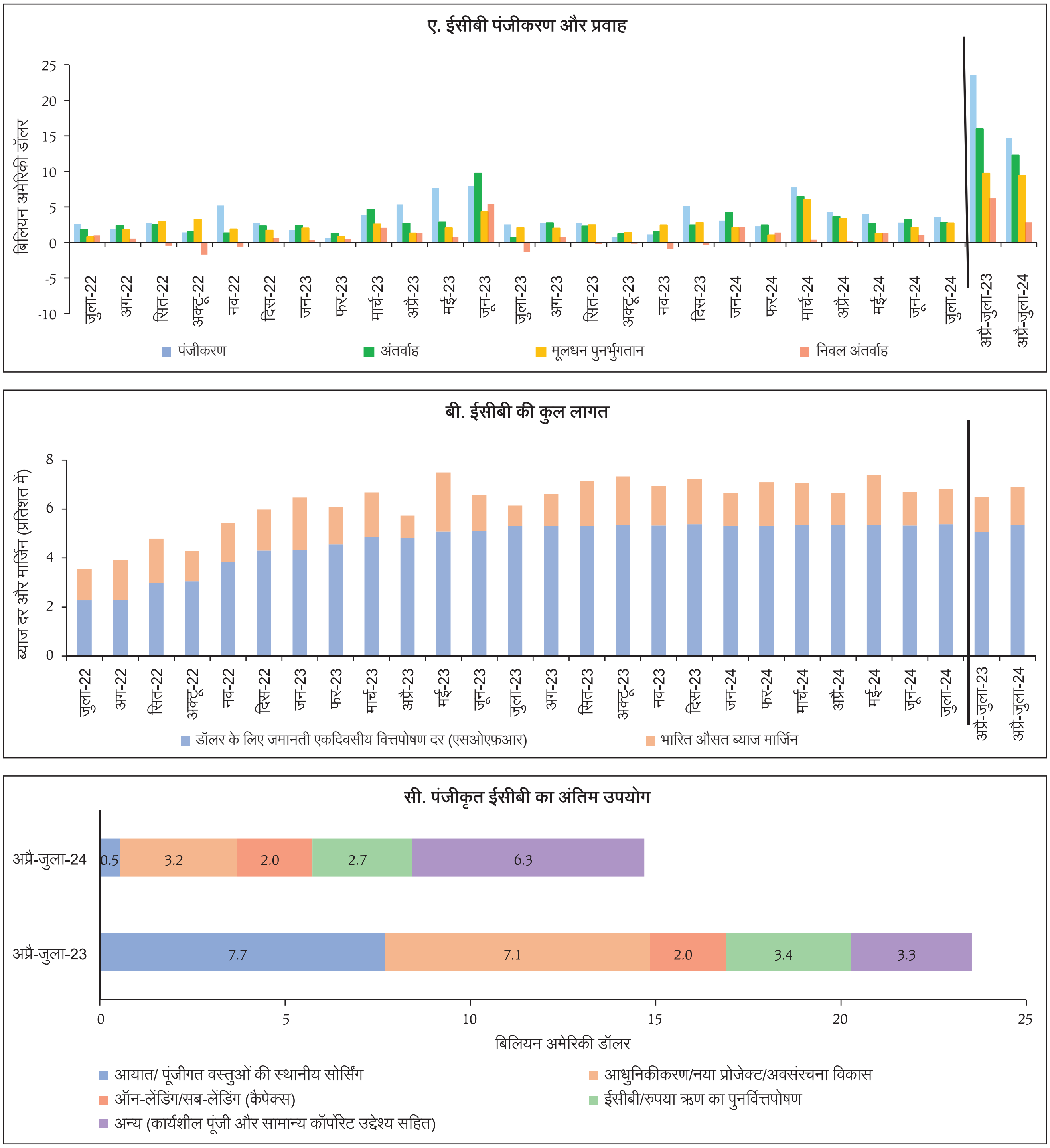

स्रोत : फॉर्म ईसीबी, आरबीआई।

तुलना में कम थे। अप्रैल-जुलाई 2024 के दौरान ईसीबी ऋणों की समग्र लागत में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 40 आधार अंक की वृद्धि हुई (चार्ट IV.21बी)। इस वर्ष अब तक अनुबंधित कुल ईसीबी ऋणों का लगभग दो-पांचवां हिस्सा पूंजीगत व्यय (कैपेक्स के लिए ऑन-लेंडिंग और सब-लेंडिंग सहित) के लिए रहा [चार्ट IV.21सी]।

चार्ट IV.22: विदेशी मुद्रा भंडार

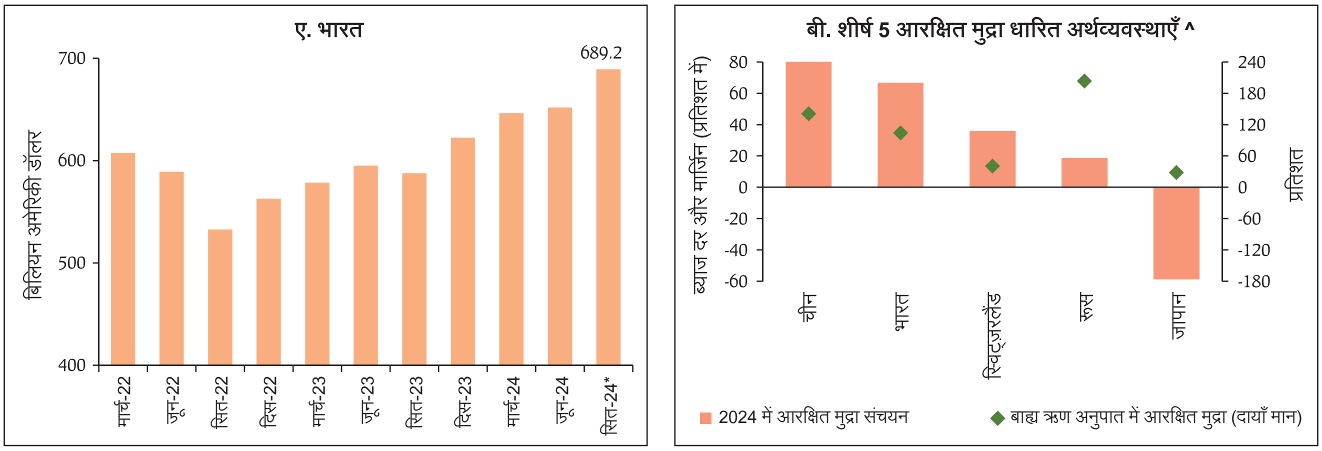

टिप्पणियाँ: 1. *: 6 सितंबर, 2024 का डेटा।
2. ^: देशों को 2024 में भंडार संचय के घटते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। भारत और रूस के लिए डेटा 6 सितंबर, 2024 तक, स्विट्जरलैंड के लिए जुलाई के अंत और अन्य देशों के लिए अगस्त के अंत तक है। बाह्य ऋण की तुलना में आरक्षित मुद्रा के अनुपात की गणना मार्च 2024 के अंत में प्रत्येक देश के नवीनतम उपलब्ध आरक्षित मुद्रा और बाह्य ऋण का उपयोग करके की जाती है।

स्रोत: आरबीआई; संबंधित केंद्रीय बैंक की वेबसाइटें; और आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

6 सितंबर 2024 तक, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर 689.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया, जो 2023-24 के 12 महीने से अधिक के आयात के बराबर और मार्च 2024 के अंत में बकाया कुल बाह्य ऋण के 103 प्रतिशत से अधिक के बराबर है (चार्ट IV.22ए)। भारत ने 2024 में अब तक (6 सितंबर तक) 66.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर जमा किए हैं, जो प्रमुख विदेशी मुद्रा भंडार रखने वाले देशों में दूसरा सबसे अधिक है (चार्ट IV.22बी)।

भारतीय रुपये (आईएनआर) ने अगस्त 2024 के दौरान प्रमुख मुद्राओं में सबसे कम अस्थिरता प्रदर्शित की, अमेरिकी डॉलर की तुलना में 0.4 प्रतिशत (म-द-म) की गिरावट आई (चार्ट IV.23)।

अगस्त 2024 में 40-मुद्रा वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (आरईईआर) के संदर्भ में आईएनआर में 1.9 प्रतिशत (म-द-म) की गिरावट आई, जो नाममात्र प्रभावी शर्तों में आईएनआर के मूल्यह्रास और नकारात्मक सापेक्ष मूल्य अंतर के कारण थी (चार्ट IV.24)।

चार्ट IV.23: अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये और प्रमुख मुद्राओं का उतार-चढ़ाव (जुलाई 2024 की तुलना में अगस्त 2024)

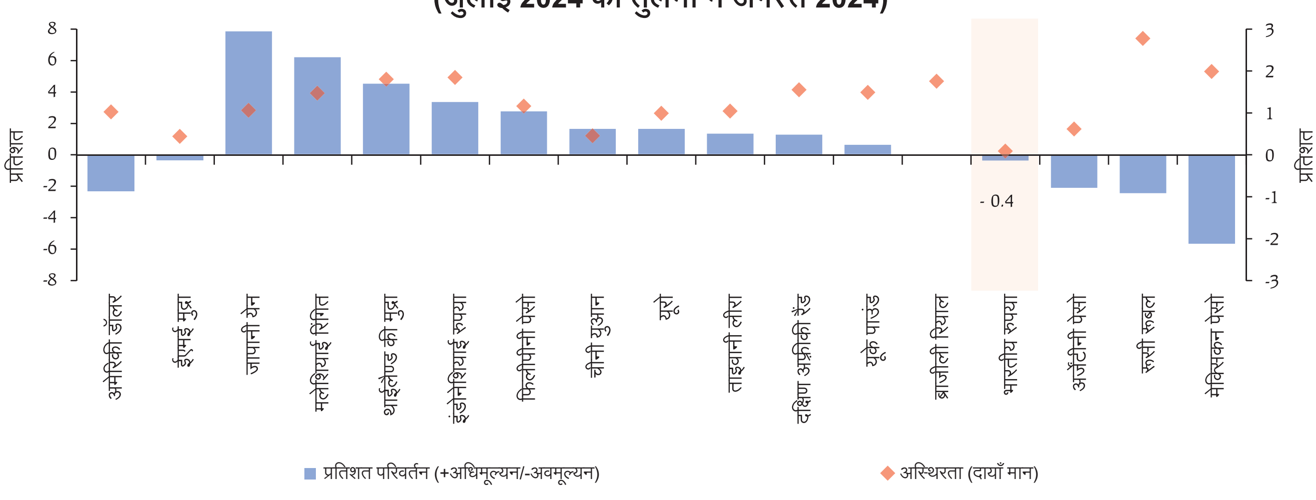

टिप्पणी: अमेरिकी डॉलर (डीएक्सवाई) प्रमुख मुद्राओं (यूरो, जापानी येन, ब्रिटिश पाउंड, कैनेडियन डॉलर, स्वीडिश क्रोना,स्विस फ्रैंक) की बास्केट की तुलना में अमेरिकी डॉलर में उतार-चढ़ाव को मापता है।

स्रोत: एफबीआईएल; आईएमएफ; थॉमसन रॉयटर्स; और आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

चार्ट IV.24: 40-मुद्रा वास्तविक प्रभावी विनिमय दर में उतार-चढ़ाव

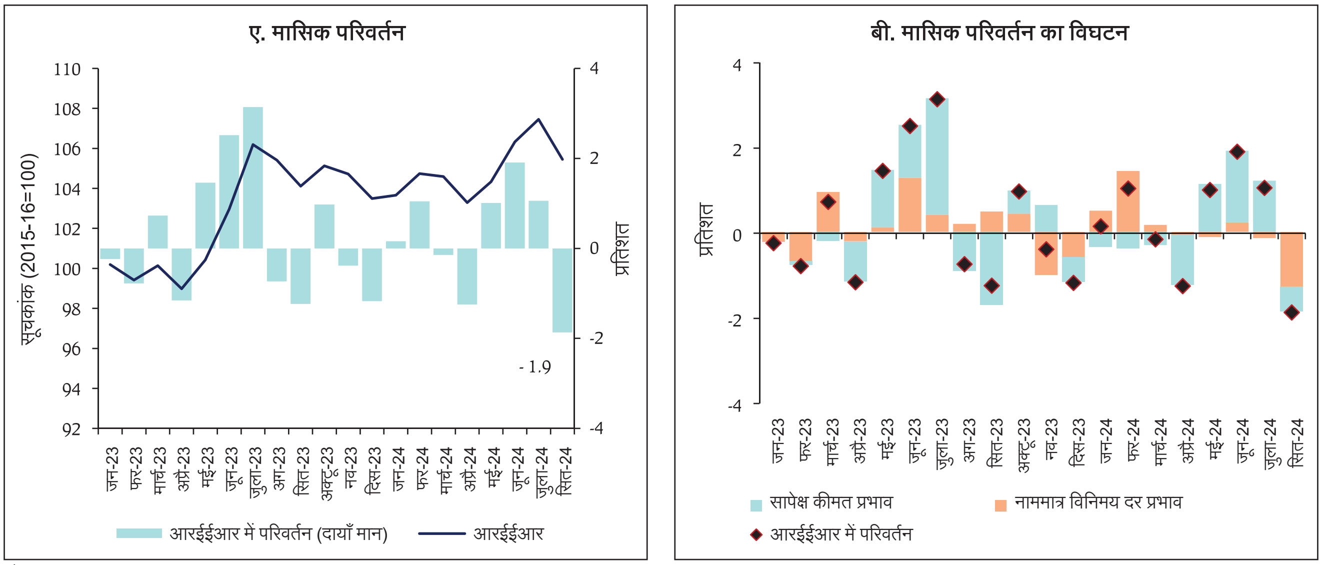

स्रोत : आरबीआई।

भुगतान प्रणाली

डिजिटल लेनदेन ने अगस्त 2024 में तत्काल सकल निपटान (आरटीजीएस), राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफ़टी), एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई), भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस), और राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन गृह (एनएसीएच) सहित प्रमुख भुगतान मोड में अच्छी वृद्धि प्रदर्शित की (सारणी IV.3)। अगस्त 2024 में यूपीआई पर्सन-टू-मर्चेंट (पी2एम) लेनदेन की मात्रा कुल यूपीआई लेनदेन का 62 प्रतिशत थी, जो पिछले वर्ष में 58 प्रतिशत की वृद्धि थी। अप्रैल-अगस्त 2024 के दौरान यूपीआई लेनदेन का मूल्य 35 प्रतिशत बढ़कर 101 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया। यूपीआई इकोसिस्टम भी अपनी नई सुविधाओं को व्यापक रूप से अपनाने का अनुभव कर रहा है, जिसमें यूपीआई[24] पर आईपीओ, ऑटोपे और नेपाल[25] में क्रॉस-बॉर्डर पी2एम भुगतान शामिल हैं। यूपीआई आईपीओ का निर्माण लगभग तीन गुना हो गया है, अगस्त 2024 में सफल अधिदेश निष्पादन की दर 100 प्रतिशत तक पहुंच गई है, जो

सारणी IV.3: चुनिंदा भुगतान प्रणालियों में वृद्धि

(व-द-व प्रतिशत में)

भुगतान प्रणाली संकेतक	लेनदेन की मात्रा				लेनदेन का मूल्य			
	जुला-23	जुला-24	अग-23	अग-24	जुला-23	जुला-24	अग-23	अग-24
आरटीजीएस	12.0	16.4	16.0	8.9	13.6	21.7	17.8	15.8
एनईएफ़टी	36.3	46.2	35.6	41.2	16.1	20.1	19.1	14.5
यूपीआई	58.4	44.9	60.8	41.3	44.2	34.6	46.9	30.7
आईएमपीएस	6.3	0.1	4.8	-7.3	15.2	15.8	15.3	12.4
एनएसीएच	30.3	0.9	14.1	23.9	23.3	17.5	17.9	25.6
एनईटीसी	11.3	9.4	13.3	6.8	19.7	12.0	21.9	8.4
बीबीपीएस	25.9	75.4	23.9	86.1	46.0	177.6	46.5	258.6

टिप्पणी : आरटीजीएस: तत्काल सकल निपटान, **एनईएफ़टी:** राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण, **यूपीआई:** एकीकृत भुगतान इंटरफेस, **आईएमपीएस:** त्वरित भुगतान सेवा, **एनएसीएच:** राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन गृह, **एनईटीसी:** राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह, **बीबीपीएस:** भारत बिल भुगतान प्रणाली।
स्रोत: आरबीआई।

24 ऐसी सुविधा जिसमें यूपीआई आईडी का प्रयोग निधियों को अवरुद्ध करने और सार्वजनिक निर्गम प्रक्रिया में भुगतान करने के लिए किया जा सकता है।

25 यह भारतीय उपभोक्ताओं को नेपाल के विभिन्न व्यावसायिक स्टोरों में यूपीआई भुगतान करने में सक्षम बनाता है।

अगस्त 2023 में 98 प्रतिशत थी। अगस्त 2024 में, यूपीआई ऑटोपे के तहत अधिदेश के निर्माण और निष्पादन में क्रमशः 178 प्रतिशत और 173 प्रतिशत की वृद्धि हुई। मार्च 2024 में लॉन्च होने के बाद से नेपाल में यूपीआई पी2एम लेनदेन एक लाख से अधिक हो गया।[26] ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल (जीएफ़एफ़) 2024 में यूपीआई सर्कल फीचर के लॉन्च के साथ समग्र यूपीआई लेनदेन में वृद्धि और बढ़ने की उम्मीद है, जो प्राथमिक उपयोगकर्ताओं को अधिकतम पांच द्वितीयक उपयोगकर्ताओं को यूपीआई भुगतान सौंपने में सक्षम बनाता है।

बीबीपीएस के तहत लेनदेन क्रेडिट कार्ड बिल भुगतान और डीटीएच, गैस और बिजली सहित उपयोगिता बिल भुगतान की मात्रा और मूल्य में वृद्धि के कारण बढ़ गया। जीएफ़एफ़ 2024 में बिजनेस के लिए भारत बिलपे की शुरुआत व्यवसाय के आकार की परवाह किए बिना एक केंद्रीकृत, इंटरऑपरेबल प्लेटफॉर्म के माध्यम से बिजनेस-टू-बिजनेस भुगतान और संग्रह को सुव्यवस्थित और स्वचालित करने का अनुमान है। आवर्ती लेनदेन के लिये ई-मैंडेट ढाँचे के तहत फास्टटैग और नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी) की स्वतः पुनःपूर्ति को शामिल करने से क्रमशः एनईटीसी और कार्ड लेनदेन को बढ़ावा मिलने की संभावना है।

फिनटेक पारिस्थितिकी तंत्र जीवंतता का प्रदर्शन कर रहा है, अप्रैल-अगस्त 2024 के दौरान कुल फंडिंग में 41 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो 2023[27] की इसी अवधि में 57 प्रतिशत संकुचन है। आगे देखते हुए, पारिस्थितिकी तंत्र में नवाचारों, नए व्यापार मॉडल और विकसित प्रौद्योगिकी के साथ, डिजिटल भुगतान की मात्रा 2028-29[28] में 481 बिलियन लेनदेन तक पहुंच के साथ तीन गुना बढ़ने का अनुमान है।

V. निष्कर्ष

ऊर्जा दृष्टिकोण पर हालिया शोध से संकेत मिलता है कि हाल के वर्षों में स्वच्छ प्रौद्योगिकी परिनियोजन और पूंजीगत निवेश की गति रिकॉर्ड स्तर तक बढ़ने के साथ ऊर्जा संक्रमण में तेजी आई है। जीवाश्म ईंधन के प्रभुत्व का युग समाप्त हो रहा है, इस दशक के अंत तक वैश्विक स्तर पर नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन का 50 प्रतिशत हिस्सा पार करने की उम्मीद है। स्वच्छ विद्युत उत्पादन आक्रामक उत्सर्जन कटौती के लक्ष्य तक पहुंचा सकता है जिसकी तत्काल आवश्यकता है, जिससे स्टीलमेकिंग और एविएशन जैसे 'हार्ड-टू-एबेट' क्षेत्रों से निपटने के लिए अधिक समय मिल सकता है, जहां लागत-प्रतिस्पर्धी कम कार्बन समाधान अभी तक पैमाने पर नहीं हैं। एक निवल-शून्य मार्ग अभी के और दशक के अंत के बीच नवीकरणीय क्षमता के तीन गुना पर टिका है। ऊर्जा आपूर्ति पक्ष पर, जीवाश्म ईंधन पर जाने वाले प्रत्येक अमेरिकी डॉलर के लिए, शेष दशक में कम कार्बन ऊर्जा में औसतन 3 अमेरिकी डॉलर का निवेश करने की आवश्यकता है - आज की समता से। 2050 तक एक पूरी तरह से विघटित वैश्विक ऊर्जा प्रणाली के 215 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य टैग के साथ आने का अनुमान है।

इस संदर्भ में, उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं (ईएमडीई) के लिए वित्तीय क्षेत्र के दृष्टिकोण का उद्घाटन मूल्यांकन महत्व रखता है।[29] विश्व बैंक ने पाया है कि एई की तुलना में अपेक्षाकृत उच्च जलवायु-संबंधित वित्तीय क्षेत्र के जोखिम और वित्तपोषण अंतराल के सामने, विनियामक प्राधिकरण ईएमडीई जलवायु वित्त को सक्षम करने के लिए अनुकूलित जलवायु जोखिम मूल्यांकन, निर्देशित ऋण और ब्याज दर समायोजन जैसे नए दृष्टिकोण अपना रहे हैं। टिकाऊ आधार पर, हालांकि, गहरी और अच्छी तरह से काम करने वाली पूंजी और बीमा बाजार दीर्घकालिक ग्रीन फंडिंग के लिए आवश्यक हैं, विकास बैंकों और ऋण गारंटी संस्थानों के साथ महत्वपूर्ण और लक्षित रिक्तियों की पूर्ति और बैकस्टॉप प्रदान करते हैं। इसके अलावा, सब्सिडी पर आधारित जलवायु नीतियां उत्सर्जन को रोकने में तेजी से अप्रभावी पाई जाती हैं और इसके बजाय, वित्तीय प्रोत्साहन, नियमों और करों के संतुलित संयोजन को प्राथमिकता दी जाती है। सक्षम स्थितियां सुधर रही हैं - इन देशों के कुछ कम आय वाले कमजोर देशों को छोड़कर, बड़े पैमाने पर ऋण और संप्रभु जोखिम आघात का सामना करने के लिए पर्याप्त बफर के साथ, अधिकांश बैंक अपेक्षाकृत मजबूत और आघात-सहनीय

[26] भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम प्रेस विज्ञप्ति। 09 अगस्त 2024।

[27] टीआरएसीएक्सएन डेटाबेस 04 सितंबर 2024 तक एक्सेस किया गया।

[28] पीडब्ल्यूसी इंडिया (2024) द इंडियन पेमेंट्स हैंडबुक – 2024-2029.

[29] वर्ल्ड बैंक, वित्त और समृद्धि, 2024.

दिखाई देते हैं। वित्तीय समावेशन में सुधार हुए हैं और सार्वजनिक नीति हस्तक्षेपों और बाजार आधारित प्रतिस्पर्धा की भूमिका के बीच सही संतुलन की खोज के बीच वित्तीय क्षेत्र को हरा-भरा करने के प्रयास चल रहे हैं। नकारात्मक पक्ष पर, ईएमडीई बैंकों ने सरकारी ऋण की अपनी धारिता में काफी वृद्धि की है, जो 'संप्रभु-बैंक नेक्सस' के बाद के जोखिम के कारण से वित्तीय स्थिरता के लिए जोखिम पैदा कर सकता है, जो विनियामक मानकों का पर्याप्त ध्यान नहीं रखता है।

जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी) के लिए कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी (सीओपी 29) के 29 वें सत्र से पहले, व्यापक चेतावनी है कि ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन विशेष रूप से एई में प्रति व्यक्ति आधार पर उच्च बना हुआ है। अगर नवीकरणीय ऊर्जा से लेकर हरित ईंधन तक हर चीज में और भी तेजी से वृद्धि के साथ निर्णायक कार्रवाई की जाए तो दुनिया के लिए अभी भी पटरी पर आने का समय है।[30]

[30] ब्लूमबर्गएनईएफ, द न्यू एनर्जी आउटलुक, 2024.

भारतीय राज्यों के व्यापार चक्र का समन्वय

सत्यानंद साहू, कुणाल प्रियदर्शी, चैताली भौमिक, सपना गोयल और प्रीतिका द्वारा^

भारतीय राज्यों में आर्थिक गतिविधि राष्ट्रीय और राज्य-स्तरीय नीतियों के साथ-साथ वैश्विक विकास से भी प्रभावित होती है। इस प्रकार उत्पादन सामान्य और विशिष्ट दोनों प्रकार के आघातों के अधीन होता है। राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय चक्रों के समन्वय की जांच वैकल्पिक फिल्टर का उपयोग करके क्षेत्रीय सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रवृत्ति-चक्र अपघटन के माध्यम से की जाती है। समन्वय को संचालित करने वाले कारकों का अधिक विस्तृत विश्लेषण राज्य-स्तरीय चक्रों से सहसंबंधों का उपयोग करके किया जाता है। अध्ययन में 2000 के दशक से राष्ट्रीय चक्र के साथ पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्रों के मजबूत सह-संचलन और क्षेत्रीय चक्रों पर सामान्य घटकों का बड़ा असर पाया गया है। अध्ययन व्यापार चक्रों के समन्वय पर भौगोलिक निकटता की सकारात्मक भूमिका को भी रेखांकित करता है।

परिचय

भारतीय अर्थव्यवस्था एक सुस्थापित संघीय ढांचे के तहत काम करती है जिसमें राज्य केंद्रीकृत नीतियों (उदाहरण के लिए, मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति, बाहरी व्यापार नीति) के साथ-साथ व्यक्तिगत राज्य सरकारों द्वारा अपनाई गई राज्य-विशिष्ट नीतियों द्वारा शासित होते हैं। भारतीय राज्य अलग-अलग व्यापक आर्थिक और सामाजिक संरचनाओं का प्रदर्शन करते हैं जो व्यापक रूप से भिन्न क्षेत्रीय संरचनाओं, मुद्रास्फीति की गतिशीलता, भौतिक और सामाजिक बुनियादी ढांचे, वित्तीय साक्षरता के स्तर आदि में परिलक्षित होते हैं। इन गतिशीलता को दर्शाते हुए, राज्य सामान्य और विशिष्ट आघातों के अधीन हैं। इन सभी कारकों का जटिल समामेलन इस बात की जांच की मांग करता है कि राज्य-स्तरीय आर्थिक समुच्चय राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) चक्र के मुकाबले कितने समकालिक हैं।

भारतीय राज्यों की विकास गतिशीलता पर अधिकांश शोध ने विकास अभिसरण या विचलन पर ध्यान केंद्रित किया है, जिसमें व्यापार चक्रों की गतिशीलता को पूरी तरह से अनदेखा किया गया है। राज्य या क्षेत्रीय स्तर पर व्यापार चक्रों पर अधिकांश अनुभवजन्य कार्य संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएस), ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय संघ (ईयू) के संदर्भ में मौजूद हैं। उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) में उप-राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार चक्रों का विश्लेषण मुख्य रूप से प्रासंगिक मैक्रो समुच्चयों पर लंबी समय श्रृंखला डेटा की अनुपलब्धता के कारण कम है। उपरोक्त के मद्देनजर, इस पेपर का उद्देश्य पिछले चार दशकों में भारतीय राज्यों के व्यापार चक्रों की सह-गति और सह-आंदोलन की प्रकृति की खोज करके इस अंतर को भरना है। पत्र यह समझने का भी प्रयास करता है कि राज्य की आर्थिक गतिविधि में उतार-चढ़ाव किस हद तक सभी राज्यों को एक साथ प्रभावित करने वाले सामान्य कारकों और विशिष्ट आघातों से प्रेरित होते हैं, जिसमें किसी राज्य में सूखा या कोई अन्य प्राकृतिक आपदा या राज्य-विशिष्ट राजकोषीय या नियामक उपाय शामिल हो सकते हैं। राज्यों में आघातों के फैलाव की जांच राज्य व्यापार चक्रों के गतिशील क्रॉस-सहसंबंध के संदर्भ में की जाती है।

अध्ययन की अवधि सामान्य डेटा सेट की उपलब्धता और कोविड-19 महामारी विचलन को छोड़कर 1980-81 से 2019-20 तक फैली हुई है। राज्यों के ट्रेंड-चक्रीय अपघटन के लिए बैक्सटर-किंग (बीके) बैंड-पास फ़िल्टर और अनऑब्जर्व्ड कंपोनेंट मॉडल (यूसीएम) फ्रेमवर्क के तहत कलमैन फ़िल्टर का उपयोग किया जाता है। राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय चक्रों के समन्वयन की जाँच संक्षिप्तता के लिए प्रमुख भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) को उनकी भौगोलिक सेटिंग्स के अनुसार पाँच क्षेत्रीय

^ सत्यानंद साहू, चैताली भौमिक और सपना गोयल भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग (डीईपीआर) से हैं, कुणाल प्रियदर्शी आरबीआई के वित्तीय बाजार विनियमन विभाग से हैं और प्रीतिका आरबीआई के डीईपीआर में एक शोध प्रशिक्षु थीं। पेपर का एक पुराना संस्करण मार्च 2024 में इंडियन एसोसिएशन फॉर रिसर्च इन नेशनल इनकम एंड वेल्थ के 42वें सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया था। लेखक सम्मेलन के प्रतिभागियों और अनाम समीक्षक को बहुमूल्य टिप्पणियों और सुझावों के लिए धन्यवाद देते हैं। इस लेख में व्यक्त किए गए विचार लेखकों के हैं और आरबीआई के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।

समूहों में एकत्रित करके की जाती है। इसके अलावा, राज्य-स्तरीय चक्रों का उपयोग करके व्यापार चक्र समन्वयन की गतिशीलता के अंतर्निहित कारकों को अधिक विघटित स्तर पर खोजा गया है। विशेष रूप से, अध्ययन ने यह पता लगाने का प्रयास किया कि क्या राज्यों की भौगोलिक स्थिति और आर्थिक संरचना साधारण न्यूनतम वर्ग (ओएलएस) प्रतिगमन का उपयोग करके चक्रों के समन्वयन की गतिशीलता के लिए मायने रखती है दूसरी ओर, राज्यों में आगे और पीछे के संबंध और क्षेत्रीय स्पिलओवर इतने मजबूत हो सकते हैं कि वे अलग-अलग आर्थिक संरचनाओं वाले राज्यों के चक्रों को प्रभावित कर सकें, लेकिन पूरकताएं साझा कर सकें। इसलिए, किसी राज्य की आर्थिक संरचना उसके व्यापार चक्र को आकार देने में किस तरह की भूमिका निभाती है, यह अस्पष्ट प्रतीत होता है और इसके लिए अनुभवजन्य अन्वेषण की आवश्यकता है।

अध्ययन में पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्रों के लिए 2000 के बाद राष्ट्रीय व्यापार चक्र के साथ चक्रों के बढ़ते समन्वय और क्षेत्रीय चक्रों पर आम घटकों के बड़े असर के प्रमाण मिलते हैं। इसके विपरीत, उत्तरी, पूर्वी और मध्य क्षेत्रों के लिए, राष्ट्रीय चक्र के साथ समन्वय की डिग्री कमजोर हो गई है, जो अन्य बातों के साथ-साथ, राष्ट्रीय स्तर की तुलना में इन क्षेत्रों की क्षेत्रीय संरचनाओं में विलक्षण आघातों और/या बढ़ते विचलन की व्यापकता को दर्शाता है। इसके अलावा, क्षेत्रीय और राज्य-स्तरीय विश्लेषण दोनों ने व्यापार चक्र समन्वय पर राज्यों की भौगोलिक निकटता के पर्याप्त प्रभाव को उजागर किया।

इस पृष्ठभूमि में, इस पेपर को छह खंडों में व्यवस्थित किया गया है। खंड II पिछले चार दशकों में भारतीय राज्यों की विकास गतिशीलता के बारे में प्रमुख शैलीगत तथ्यों को रेखांकित करता है। खंड III प्रासंगिक साहित्य पर चर्चा करता है, उसके बाद खंड IV में डेटा विवरण और कार्यप्रणाली पर चर्चा की गई है। खंड V विश्लेषण से प्रमुख निष्कर्ष प्रस्तुत करता है। खंड VI में पेपर का समापन किया गया है।

II. शैलीगत तथ्य

विश्लेषण के लिए बीस राज्यों और चार संघ[1] शासित प्रदेशों के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी), जो भारत के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद का 95.0 प्रतिशत से अधिक है, पर विचार किया गया है, जिसके लिए डेटा राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) से प्राप्त किए गए हैं। संक्षेप में, चुनिंदा राज्यों को उनकी भौगोलिक स्थितियों के आधार पर, भारत की क्षेत्रीय परिषदों (सारणी 1 और चार्ट 1) के आधार पर पांच अलग-अलग क्षेत्रों में एकत्रित किया गया है। चुनिंदा पूर्वोत्तर राज्यों अर्थात् मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम की लम्बी समयावधि श्रृंखला की अनुपलब्धता के कारण पूर्वोत्तर क्षेत्र को शामिल नहीं किया गया है।

भारत की विकास गाथा के अनुरूप, 2000 के दशक के दौरान सभी क्षेत्रों में चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र को शामिल करने वाले पश्चिमी क्षेत्र ने 1980 और 2010 के दशक के बीच

सारणी 1: भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का क्षेत्रीय वर्गीकरण

उत्तरी	पश्चिमी	पूर्वी	दक्षिण	केंद्रीय
चंडीगढ़	गोवा	बिहार	आंध्र प्रदेश	छत्तीसगढ
दिल्ली	गुजरात	झारखंड	कर्नाटक	मध्य प्रदेश
हरयाणा	महाराष्ट्र	ओडिशा	केरल	उत्तराखंड
हिमाचल प्रदेश		पश्चिम बंगाल	पुदुचेरी	उतार प्रदेश
जम्मू और कश्मीर			तमिलनाडु	
पंजाब			तेलंगाना	
राजस्थान				

स्रोत: भारतीय क्षेत्रीय परिषदें।

[1] चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) दिल्ली और पुडुचेरी।

चार्ट 1: भारतीय राज्यों का क्षेत्रीय वर्गीकरण

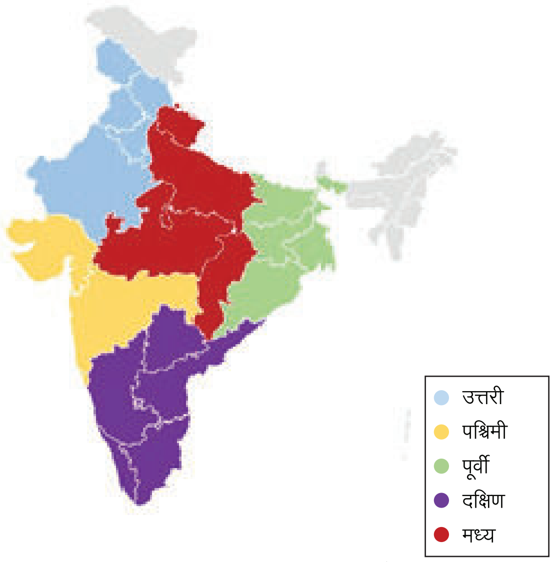

स्रोत: भारतीय क्षेत्रीय परिषदें।

चार्ट 2: आर्थिक गतिविधि की क्षेत्रीय संरचना - 2011-12 से 2019-20

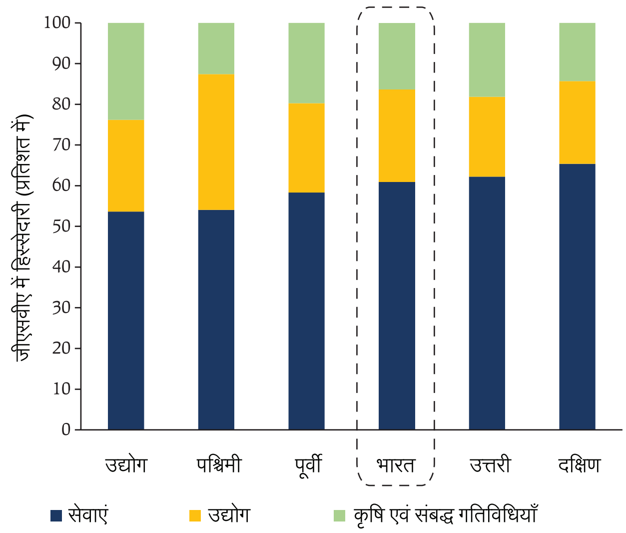

स्रोत: एनएसओ; और लेखकों की गणना।

अन्य क्षेत्रों से बेहतर प्रदर्शन किया, जबकि पिछले दशक (2010-11 से 2019-20) में दक्षिणी क्षेत्र में सीएजीआर पश्चिमी राज्यों से आगे निकल गया। समतल शब्दों में, स्थिर कीमतों पर दक्षिणी क्षेत्र का जीएसडीपी 2019-20 में पश्चिमी क्षेत्र से 27.6 प्रतिशत अधिक है (सारणी 2)।

आर्थिक गतिविधि संरचना का अवलोकन दर्शाता है कि पिछले दशक में, सेवाओं ने सभी क्षेत्रों में सकल राज्य मूल्य वर्धन (जीएसवीए) में औसतन 50.0 प्रतिशत से अधिक का योगदान दिया है। जबकि दक्षिणी क्षेत्र में सेवाओं में गतिविधि का औसत 65.4 प्रतिशत शामिल है, मध्य क्षेत्र में सबसे कम हिस्सेदारी 53.6 प्रतिशत है। अन्य क्षेत्रों और राष्ट्रीय स्तर की तुलना में, पश्चिमी क्षेत्र में उद्योग द्वारा योगदान दिया जाने वाला सबसे बड़ा अनुपात (क्षेत्र की अर्थव्यवस्था का लगभग एक-तिहाई) है; गुजरात में उद्योग का औसत हिस्सा राष्ट्रीय स्तर के दोगुने के करीब है। मध्य और पूर्वी दोनों क्षेत्रों में उनके जीएसवीए में कृषि और संबद्ध गतिविधियों का औसतन 20 प्रतिशत हिस्सा है [चार्ट 2]। इन सबके बीच, उत्तरी क्षेत्र राष्ट्रीय क्षेत्रीय संरचना को करीब से प्रतिबिंबित करता है।

संबंधित क्षेत्रों के राज्यों में आगे जाने पर, राजस्थान का उत्तरी क्षेत्र जीएसडीपी में अधिकतम हिस्सा है, उसके बाद दिल्ली एनसीटी का स्थान है; पश्चिमी क्षेत्र के जीएसडीपी में महाराष्ट्र का सबसे बड़ा हिस्सा है, उसके बाद गुजरात का स्थान है; पूर्वी क्षेत्र में, पश्चिम बंगाल के बाद बिहार और ओडिशा का स्थान है; दक्षिणी क्षेत्र में तमिलनाडु और कर्नाटक का बड़ा हिस्सा है। मध्य क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश के पास क्षेत्र के जीएसडीपी हिस्से का आधे से अधिक हिस्सा है। राज्यों में विकास में अंतर ने कुछ क्षेत्रों में असमानताओं को बढ़ा दिया है, जबकि अन्य में, विकास काफी हद तक समकालिक रहा है (चार्ट 3)। राज्यों और क्षेत्रों में आर्थिक संरचनाओं में अंतर, अन्य बातों के साथ-साथ, विकास भिन्नताओं में योगदान कर सकते हैं(चार्ट 4)।

सारणी 2: वास्तविक जीएसडीपी का सीएजीआर (प्रतिशत में) – क्षेत्रवार

	उत्तरी	पश्चिमी	पूर्वी	दक्षिण	केंद्रीय	भारत
1981-82 से 1989-90	5.4	6.0	4.4	5.3	4.7	5.6
1990-91 से 1999-2000	5.4	6.7	4.7	5.9	4.1	5.7
2000-01 से 2009-10	7.1	7.8	6.4	7.1	6.3	6.3
2010-11 से 2019-20	6.7	7.2	6.0	7.3	6.5	6.6

स्रोत: एनएसओ; और लेखकों की गणना।

चार्ट 3: विभिन्न क्षेत्रों में वास्तविक जीडीपी – राज्यवार

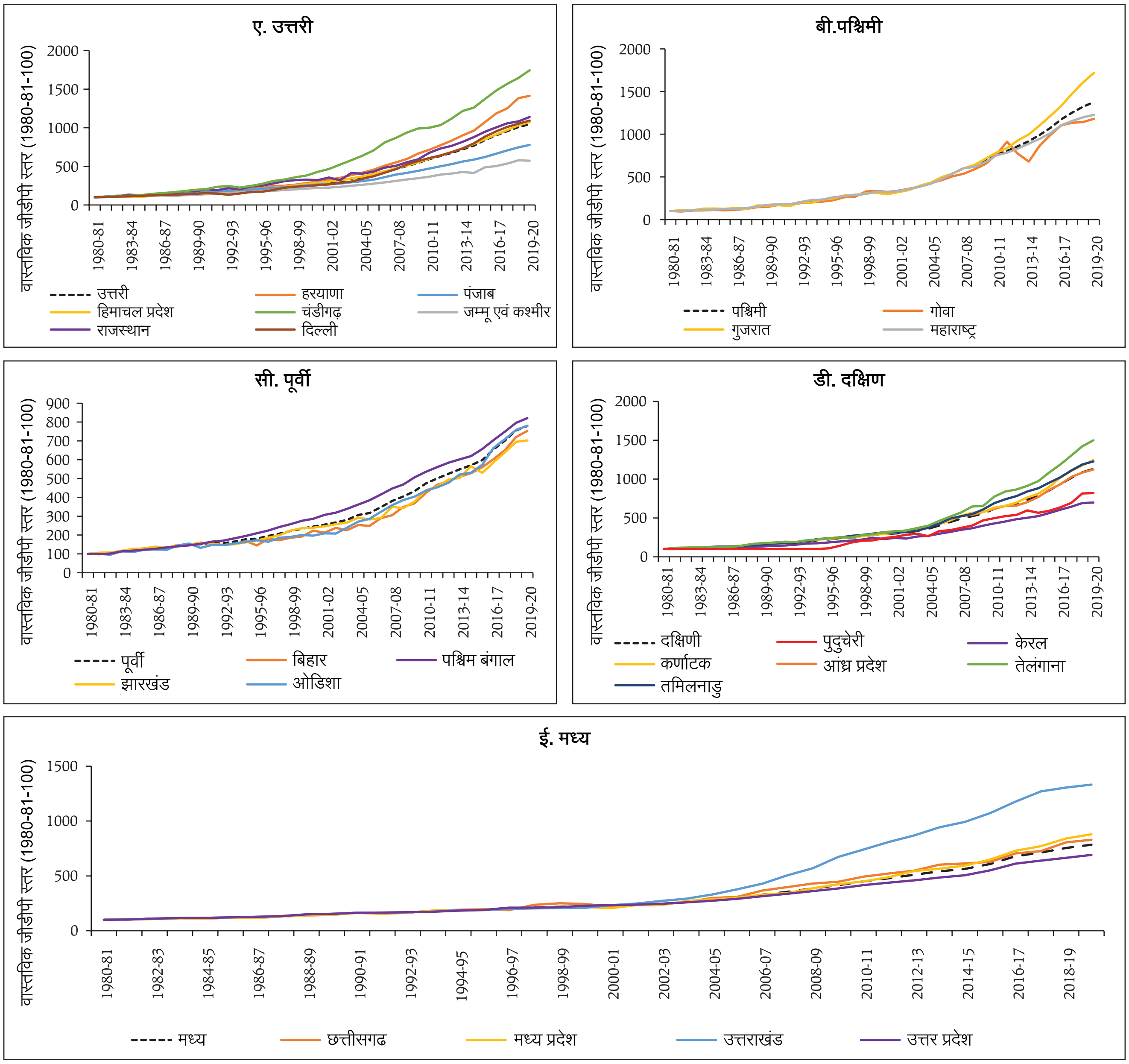

स्रोत: एनएसओ; और लेखकों की गणना।

III. साहित्य समीक्षा

व्यावसायिक चक्र एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करने वाले अनेक आर्थिक चरों में होने वाले गतिविधियों का परिणाम हैं। व्यावसायिक चक्रों पर शोध का इतिहास सिद्धांत और अनुभवजन्य कार्य दोनों से संबंधित है। व्यावसायिक चक्र विश्लेषण की शास्त्रीय तकनीकें नेशनल ब्यूरो ऑफ़ इकोनॉमिक रिसर्च (एनईबीआर) [मिशेल (1927); मिशेल और बर्न्स (1938); और बर्न्स और मिशेल (1946)] के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए अग्रणी कार्य से जुड़ी हैं। व्यावसायिक चक्रों से संबंधित अनुभवजन्य शोध मुख्य रूप से दो प्रमुख प्रश्नों पर केंद्रित है - पहला, वैकल्पिक चरणों की पहचान कैसे करें और उनमें अंतर कैसे करें, यानी व्यावसायिक चक्र के शिखर और गर्त और मोड़ बिंदुओं की पहचान कैसे करें?

चार्ट 4: दशकों में जीडीपी वृद्धि

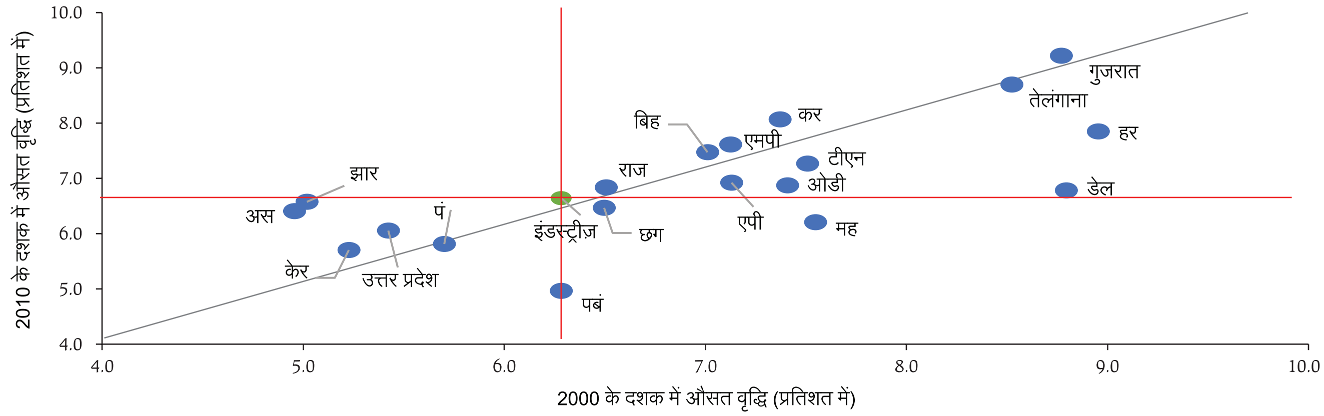

एपी: आंध्र प्रदेश: अस: असम: बिह: बिहार: छग: छत्तीसगढ़; डेल: दिल्ली: गुजरात: गुजरात: हर: हरियाणा: इंडस्ट्रीज़: भारत: झार: झारखंड; कर: कर्नाटक; केर: केरल; एमपी: मध्य प्रदेश; मह: महाराष्ट्र: ओडी: ओडिशा: पं: पंजाब; राज: राजस्थान; टीएन: तमिलनाडु; दूरभाष: तेलंगाना: उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश; पबं: पश्चिम बंगाल.

नोट: 1. 45° रेखा दोनों दशकों में समान औसत वृद्धि दर्शाती है। रेखा से ऊपर (नीचे) स्थित राज्य उच्च (कम) औसत वृद्धि दर्शाता है 2000 के दशक की तुलना में 2010 के दशक में वृद्धि हुई है।

2. यह अक्ष भारत बिंदु से होकर गुजरता है, जहां 2000 और 2010 के दशक में क्रमशः 6.3 प्रतिशत और 6.6 प्रतिशत की औसत वृद्धि हुई है।

स्रोत: एनएसओ; और लेखकों की गणना।

और, दूसरा, समग्र व्यावसायिक चक्र के साथ विशिष्ट समय श्रृंखला के देखे गए सह-आंदोलन की व्याख्या कैसे करें? काल्डोर (1957) द्वारा अर्थव्यवस्था के दीर्घकालिक प्रवृत्ति आंदोलन के संदर्भ में विकास के शैलीगत तथ्यों पर ध्यान केंद्रित किया गया तथा बाद में लुकास (1976) द्वारा सकल राष्ट्रीय उत्पाद में प्रवृत्तियों के बारे में गतिविधियों के शैलीगत तथ्यों ने उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (एई) के संदर्भ में व्यापार चक्रों पर अनुसंधान की लंबी परंपराओं की नींव रखी।

व्यापार चक्रों पर अधिकांश अनुभवजन्य कार्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपीय संघ और अफ्रीकी क्षेत्र पर केंद्रित रहा है। मैग्रिनी एट अल. (2013) ने 1990 और 2009 के बीच 48 सह-अवधि वाले अमेरिकी राज्यों के डेटा का उपयोग करते हुए व्यापार खुलेपन, वित्तीय एकीकरण और औद्योगिक विशेषज्ञता के माध्यम से समन्वय की डिग्री का विश्लेषण किया और उनके अंतर्संबंधों के साथ समन्वय की डिग्री और क्षेत्रीय विशेषज्ञता के सामान्य सूचकांक के बीच एक संभावित चक्रीय संबंध पाया। कोपरित्सस (2002) ने पाया कि क्षेत्र-विशिष्ट आघातों के फैलाव क्षेत्रीय प्रति व्यक्ति आय के व्यापार चक्र भिन्नता के सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण हिस्से के लिए जिम्मेदार नहीं हैं, लेकिन आम आघातों का एक बड़ा और सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्रीय व्यापार चक्रों पर एक अध्ययन में भी राज्य-विशिष्ट या विशिष्ट आघातों की तुलना में राज्य व्यापार चक्रों के सह-आंदोलन पर विश्व मांग या व्यापार की शर्तों में उतार-चढ़ाव जैसे सामान्य घटकों का बहुत बड़ा प्रभाव पाया गया है (नॉर्मन और वॉकर, 2007)।

एजेनोर एट अल. (2000) ने घरेलू औद्योगिक उत्पादन और विभिन्न मैक्रोइकॉनोमिक चर जैसे कि मजदूरी, मुद्रास्फीति, धन, ऋण और विनिमय दरों के बीच पारस्परिक संबंधों के आधार पर बारह विकासशील देशों के लिए मैक्रोइकॉनोमिक उतार-चढ़ाव की मुख्य शैलीगत विशेषताओं की खोज की। बत्तीस विकासशील देशों के एक बड़े नमूने पर आधारित एक अध्ययन में पाया गया कि विकासशील देशों का उत्पादन, खपत, निवेश, सरकारी राजस्व और व्यय विकसित देशों की तुलना में अधिक अस्थिर और कम स्थायी थे जबकि वास्तविक ब्याज दरें कम अस्थिर थीं (मेल, 2010)। हालाँकि भारत को नमूने में शामिल देशों में से एक के रूप में शामिल किया गया है, लेकिन ऐसे अध्ययन समय के साथ किसी विशिष्ट देश के व्यापार चक्र की बदलती प्रकृति को नहीं दिखाते हैं।

घाटे एट अल. (2013) ने उदारीकरण से पहले और बाद की दो अवधियों में भारतीय व्यापार चक्र की विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए विशेष रूप से भारतीय डेटा पर ध्यान केंद्रित किया। निष्कर्ष बताते हैं कि चक्र की विशेषताएं मुख्य रूप से उदारीकरण के बाद कृषि से बाजार आधारित औद्योगिक अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था के संक्रमण के कारण एई के करीब पहुंच गई थीं। भारतीय व्यापार चक्र के मापन, तिथि निर्धारण और चालकों पर व्यापक कार्य मौजूद है (पांडे और अन्य, 2016, 2018)। ये दोनों अध्ययन सुधार के बाद की अवधि में भारतीय व्यापार चक्र के कालक्रम पर ध्यान केंद्रित करते हैं और देखते हैं कि विस्तार की औसत अवधि लगभग बारह तिमाहियों की अनुमानित है जबकि मंदी की अवधि लगभग नौ तिमाहियों की है, जिसमें मंदी का आयाम विस्तार की तुलना में अधिक है। 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के बाद, भारतीय राज्यों में आर्थिक चक्रों ने राष्ट्रीय चक्र के साथ मजबूत सह-आंदोलन प्रदर्शित किया और कृषि राज्यों की तुलना में गैर-कृषि राज्यों में विकास चक्र अधिक स्पष्ट रहे हैं (अहमद एट अल., 2018)।

भारतीय राज्यों पर किए गए अधिकांश कार्य विकास दरों में अभिसरण या विचलन पर केंद्रित थे, जिसमें व्यापार चक्रों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया था। अहमद और अन्य (2018), राज्य स्तर पर विकास चक्रों को छूते हुए, देखे गए रुझानों की विस्तृत गतिशीलता में नहीं गए।

IV. डेटा और कार्यप्रणाली

किसी भी मजबूत मैक्रोइकॉनॉमिक विश्लेषण की पूर्वापेक्षाओं में से एक उपयुक्त लंबाई के मैक्रोइकॉनॉमिक चर की सुसंगत समय श्रृंखला की उपलब्धता है। हमारे अध्ययन में 1980-81 से 2019-20 तक की अवधि शामिल है। ऐसी समयावधि चुनने का मुख्य उद्देश्य सभी राज्यों के लिए एक सामान्य डेटासेट की उपलब्धता है। 1980 के दशक से पहले की अवधि पर विचार नहीं किया गया है क्योंकि यह घरेलू (जैसे सूखा) और बाहरी आघातों (जैसे तेल की कीमतों में उछाल) की एक श्रृंखला द्वारा चिह्नित थी, जिसने निवेश-इन्वेंट्री में उतार-चढ़ाव के परस्पर क्रिया को रोक दिया, जो व्यापार चक्र बनाता है (पांडे एट अल।, 2018)। इसके अलावा, जीएसडीपी डेटा कई आधार संशोधनों के अधीन हैं, और हमारे अध्ययन की अवधि के दौरान, जीएसडीपी डेटा पांच अलग-अलग आधार वर्षों में उपलब्ध हैं, अर्थात् 1980-81, 1993-94, 1999-2000, 2004-05 और 2011-12 । इसलिए, मानक स्प्लिसिंग पद्धति का उपयोग करके पूरी अवधि के लिए एकल आधार वर्ष 2011-12 पर जीएसडीपी श्रृंखला तैयार की गई है।[2] अध्ययन की अवधि के दौरान, चार राज्यों को विभाजित किया गया था - उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ क्रमशः 2000 में उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश से और तेलंगाना 2014 में आंध्र प्रदेश से। इसलिए, श्रृंखला बनाने के लिए जहां डेटा उपलब्ध नहीं है, दोनों विभाजित राज्यों के लिए संयुक्त राज्य की विकास दर मान ली गई है। इसके अलावा, महामारी से प्रेरित विचलन से बचने के लिए जिसने सामान्य प्रवृत्ति-चक्र गुणों को बाधित किया, कोविड के बाद के वर्षों को बाहर रखा गया है।

मानक व्यापार चक्र साहित्य का अनुसरण करते हुए, यह अध्ययन विकास चक्र पर जोर देता है,[3] चूंकि भारत एक तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, शास्त्रीय चक्रों के प्रमाण मौजूद नहीं हैं और राज्य स्तर पर भी यही सच है। जीएसडीपी डेटा से प्रवृत्ति-चक्र अपघटन के लिए उपलब्ध फ़िल्टरिंग तकनीकों में, बीके बैंड-पास फ़िल्टर जो अन्य लोकप्रिय फ़िल्टरों जैसे कि हॉड्रिक-प्रेस्कॉट (एचपी) फ़िल्टर की तुलना में कम विरूपण प्रस्तुत करता है, का उपयोग क्षेत्रों/राज्यों की प्रवृत्ति और चक्रीय घटकों को अपघटित करने के लिए किया गया है। इसके अलावा, हमने क्षेत्रीय आर्थिक उतार-चढ़ाव के प्रवृत्ति-चक्र अपघटन के लिए अप्रत्याशित घटक (यूसीएम) दृष्टिकोण का भी पालन किया है। वाटसन (1986) और

[2] स्प्लिसिंग विधि में पिछले आधार वर्ष के मूल्यों को उनके संबंधित लिंकिंग कारकों द्वारा पुनः मापना शामिल है, जो दो अलग-अलग आधार वर्षों में ओवरलैपिंग अवधि के लिए उपलब्ध डेटा के आधार पर प्राप्त किया जाता है।

[3] ओईसीडी की परिभाषा के अनुसार, 'क्लासिकल चक्र' का तात्पर्य आर्थिक गतिविधि के स्तर में उतार-चढ़ाव से है (अर्थात, जीडीपी द्वारा मापा जाता है); 'विकास चक्र', जिसे 'विचलन चक्र' के रूप में भी जाना जाता है, का तात्पर्य दीर्घकालिक संभावित स्तर के आसपास आर्थिक गतिविधि में उतार-चढ़ाव, या आउटपुट-अंतराल में उतार-चढ़ाव (अर्थात, डी-ट्रेंडेड जीडीपी द्वारा मापा जाता है) से है; तथा; 'विकास दर चक्र' का तात्पर्य आर्थिक गतिविधि की विकास दर (अर्थात, जीडीपी विकास दर) के उतार-चढ़ाव से है।

अन्य व्यापार चक्र साहित्य का अनुसरण करते हुए, यह अध्ययन मानता है कि समय t पर क्षेत्र i के लिए जीएसडीपी का लघुगणक y द्वारा दर्शाया गया और चक्रीय घटक एक स्थिर द्वितीय-क्रम ऑटोरिग्रेशन प्रक्रिया है (समीकरण 3)। μ यह समय t पर *क्षेत्र i के जीएसडीपी* का यादृच्छिक त्रुटि घटक है।

$$y_{it} = \tau_{it} + c_{it} \quad (1), \text{ for } i=1\ldots5.$$

$$\tau_{it} = \delta_{it} + \tau_{it-1} + \mu_{it} \quad (2),$$

$$c_{it} = \rho_1\, c_{it-1} + \rho_2\, c_{it-2} + \varepsilon_{nt} \quad (3)$$

राष्ट्रीय जीडीपी चक्र के विरुद्ध क्षेत्रीय चक्रों को जोड़कर व्यापार चक्रों के समन्वय का अध्ययन किया जाता है। चक्रों के दृश्य प्रतिनिधित्व से प्राप्त अवलोकनों को सहसंबंध विश्लेषण द्वारा और पुष्ट किया जाता है। चक्रों के समन्वय की गतिशीलता का मूल्यांकन राष्ट्रीय और क्षेत्रीय चक्रों के बीच रोलिंग विंडो सहसंबंधों के माध्यम से किया गया है। डेटा की वार्षिक आवृत्ति को देखते हुए, विंडो की लंबाई दस वर्ष निर्धारित की गई है जो एक पूर्ण पूर्ण-लंबाई वाले व्यापार चक्र को पकड़ने के लिए पर्याप्त अवधि है - शिखर से शिखर तक या गर्त से गर्त तक।

इसके अलावा, समन्वय की प्रकृति की गहराई से जांच करने पर, चक्रों की देखी गई सह-गति या तो कुछ सामान्य कारकों के कारण हो सकती है जैसे राष्ट्रीय स्तर पर नीति परिवर्तन जो सभी क्षेत्रों को एक साथ प्रभावित करते हैं, या क्षेत्रों में विशिष्ट आघातों का फैलाव। इस परिकल्पना का अध्ययन कि क्या घटक राज्यों की भौगोलिक निकटता और क्षेत्रीय संरचना क्षेत्रीय आघातों के मजबूत संचरण की ओर ले जाती है, क्षेत्रों में क्रॉस-सहसंबंधों की तुलना करके किया गया है। स्पिलओवर के मामले में, किसी विशेष क्षेत्र में कोई भी घटना तत्काल प्रभाव से उस क्षेत्र के व्यापार चक्र को प्रभावित करेगी लेकिन धीरे-धीरे विभिन्न आर्थिक लेनदेन या भावनाओं के माध्यम से अन्य क्षेत्रों में प्रसारित होगी और अन्य क्षेत्रों के चक्रों को देरी से प्रभावित करेगी। इसलिए, स्पिलओवर प्रभाव को क्षेत्र भर में चक्रों के लीड-लैग सहसंबंधों द्वारा मापा जा सकता है

अंत में, राज्य-स्तरीय विश्लेषण किया जाता है ताकि यह पता लगाया जा सके कि विभिन्न आघात और उनके स्पिलओवर प्रभाव व्यापार चक्र समन्वय को कैसे प्रभावित करते हैं। इस संबंध में ओएलएस प्रतिगमन ढांचे में दो परिकल्पनाओं का परीक्षण किया गया है।

परिकल्पना I: भौगोलिक निकटता व्यापार चक्रों की सह-गति को मजबूत करती है।

परिकल्पना II: राज्यों की आर्थिक संरचना क्षेत्रीय संबंधों और अनुपूरकताओं के माध्यम से व्यापार चक्र समन्वय को प्रभावित करती है।

राज्यों के युग्म-वार सहसंबंध गुणांकों को उक्त परिकल्पनाओं के लिए आश्रित चर के रूप में माना गया है। कुल बीस राज्यों और चार केंद्र शासित प्रदेशों के साथ, युग्म-वार सहसंबंधों के 276 अवलोकन पाए गए हैं। भौगोलिक निकटता को इस आधार पर परिभाषित किया जाता है कि क्या दो राज्य कम से कम एक सामान्य भौगोलिक सीमा साझा करते हैं और इसे मॉडल में एक डमी चर के रूप में शामिल किया जाता है, जो राज्यों द्वारा सीमा साझा करने पर एक मान लेता है और अन्यथा शून्य। किसी राज्य की आर्थिक संरचना को राज्य के जीएसवीए में सबसे अधिक योगदान देने वाले क्षेत्र के संदर्भ में परिभाषित किया जाता है, जो राष्ट्रीय स्तर पर उस क्षेत्र के हिस्से के मुकाबले सबसे अधिक है। उदाहरण के लिए, किसी राज्य को कृषि राज्य कहा जाता है यदि राज्य के जीएसवीए में कृषि के हिस्से और जीवीए में कृषि के राष्ट्रीय हिस्से के बीच का अंतर उद्योग और सेवा क्षेत्र के लिए समान होने पर सबसे अधिक है। मॉडल में उपयोग किए जाने वाले आर्थिक संरचना से संबंधित डमी चर का मान एक होता है यदि दो राज्य समान संरचना साझा करते हैं (मान लें कि दोनों कृषि राज्य हैं), और अन्यथा शून्य। इसके अतिरिक्त, सिंक्रोनाइज़ेशन पर प्रभाव को मापने के लिए दो डमी की परस्पर क्रिया को एक चर के रूप में जोड़ा गया है।

V . परिणाम

बीके फ़िल्टर और यूसीएम दोनों से व्युत्पन्न क्षेत्रीय व्यावसायिक चक्र राष्ट्रीय चक्र के साथ मध्यम समन्वय प्रदर्शित करते हैं और चक्रीय उतार-चढ़ाव समय के साथ कम होते जाते हैं जैसा कि बाद की अवधि में चक्रों के थोड़े कम आयामों में परिलक्षित होता है (चार्ट 5ए और 5बी)। चूंकि बीके फ़िल्टर और यूसीएम से व्युत्पन्न चक्र समान गति प्रदर्शित करते हैं, शेष विश्लेषण यूसीएम दृष्टिकोण से उत्पन्न चक्रों पर आधारित है। अन्य क्षेत्रों की तुलना में पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्रों के मामले में चक्रीयता अधिक स्पष्ट है। ये दोनों क्षेत्र राष्ट्रीय जीडीपी चक्र के प्रमुख चालकों के रूप में भी सामने आए, शायद इसलिए, क्योंकि इस अध्ययन में पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्रों को शामिल करने वाले नौ प्रमुख राज्य और केंद्र शासित प्रदेश राष्ट्रीय जीडीपी के आधे से अधिक के लिए जिम्मेदार हैं।

दृश्य प्रतिनिधित्व से चक्रीयता के देखे गए पैटर्न को सहसंबंध विश्लेषण (सारणी 3) द्वारा पुष्ट किया गया है। सभी क्षेत्र राष्ट्रीय चक्र के साथ उच्च और सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण सहसंबंध प्रस्तुत करते हैं, साथ ही कुछ को छोड़कर क्षेत्रों में उच्च क्रॉस-सहसंबंध भी प्रस्तुत करते हैं। समग्र अवधि के लिए, मध्य क्षेत्र राष्ट्रीय चक्र के साथ उच्चतम सहसंबंध दर्शाता है, उसके बाद पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्र हैं। क्रॉस-सहसंबंध यह संकेत देते हैं कि घटक राज्यों की भौगोलिक निकटता और क्षेत्रीय संरचना का क्षेत्रीय चक्रों के समन्वय पर प्रभाव पड़ता है। औद्योगिक गतिविधि के अपेक्षाकृत कम हिस्से और पूर्वी और मध्य क्षेत्रों के साथ अपेक्षाकृत निकटता वाले उत्तरी क्षेत्र ने उनके बीच उच्च क्रॉस-सहसंबंध प्रदर्शित किया। इसी तरह, पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्रों से संबंधित कई राज्य अपनी सीमाएँ साझा करते हैं और अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक औद्योगिक हैं, जो इन दो क्षेत्रों के बीच उच्च क्रॉस-सहसंबंध की व्याख्या कर सकते हैं। उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्रों के बीच सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण सहसंबंध नहीं होना उनके बीच जन्मजात संरचनात्मक और संरचनागत अंतर को दर्शा सकता है।

चार्ट 5: व्यापार चक्र

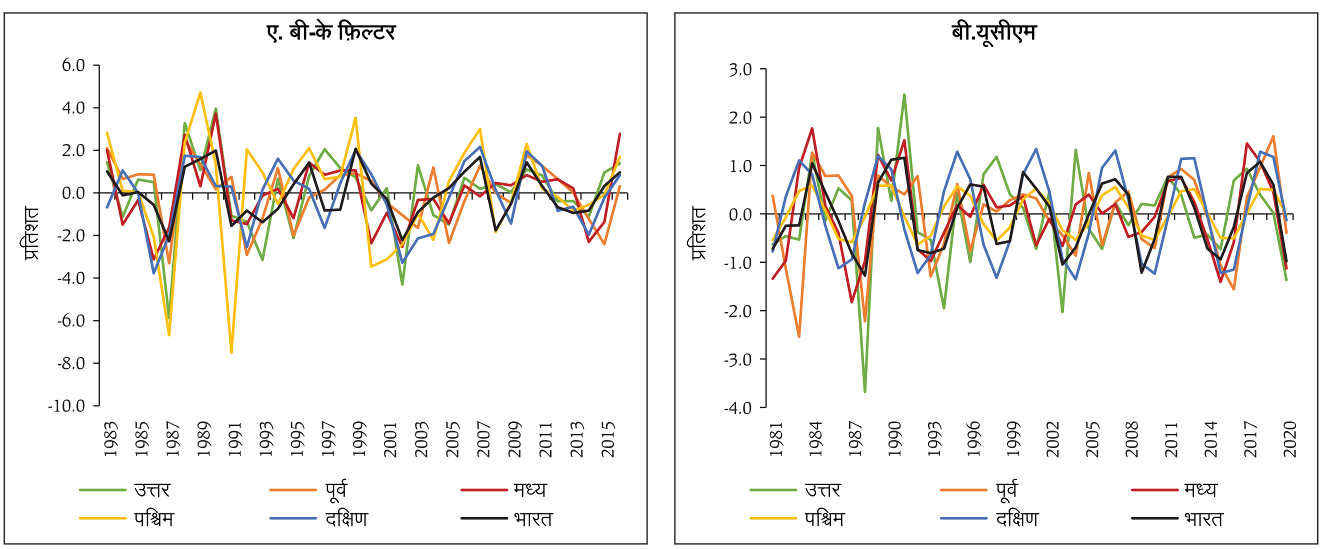

स्रोत: एनएसओ; और लेखकों की गणना।

चार्ट 6: क्षेत्रीय चक्र

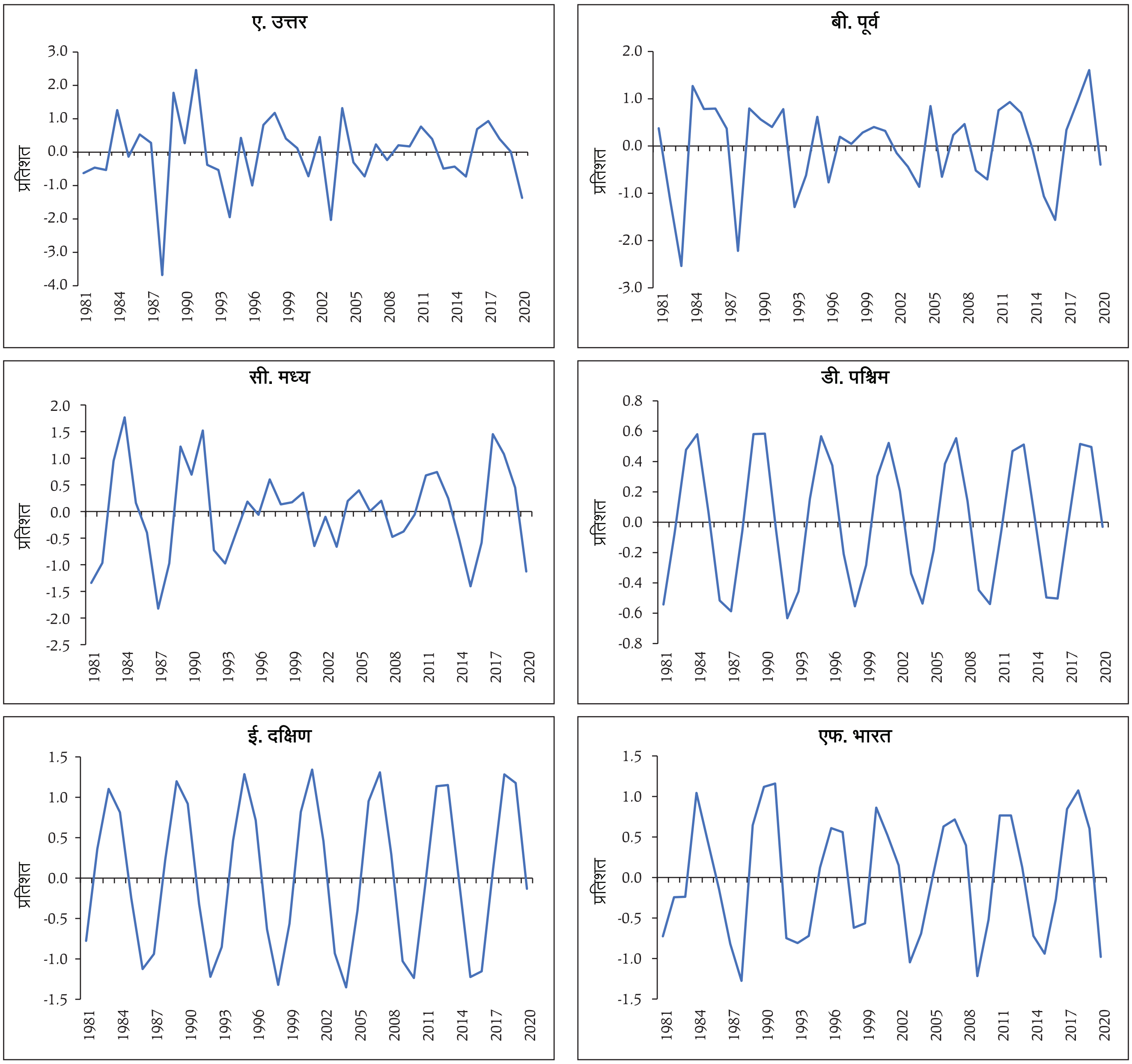

स्रोत: एनएसओ; और लेखकों की गणना।

सारणी 3: क्षेत्रों में क्रॉस-सहसंबंध

	उत्तरी	पूर्वी	केंद्रीय	पश्चिमी	दक्षिण	भारत
उत्तरी	1.00					
पूर्वी	0.47***	1.00				
केंद्रीय	0.60***	0.39**	1.00			
पश्चिमी	0.02	0.28*	0.55***	1.00		
दक्षिण	-0.06	0.24	0.45***	0.98***	1.00	
भारत	0.51***	0.55***	0.75***	0.70***	0.64***	1.00

नोट: ***, ** और * क्रमशः 1 प्रतिशत, 5 प्रतिशत और 10 प्रतिशत पर सांख्यिकीय महत्त्व दर्शाते हैं।
स्रोत: एनएसओ; और लेखकों की गणना।

चार्ट 7: राष्ट्रीय चक्र के साथ क्षेत्रीय चक्रों का रोलिंग-विंडो सहसंबंध

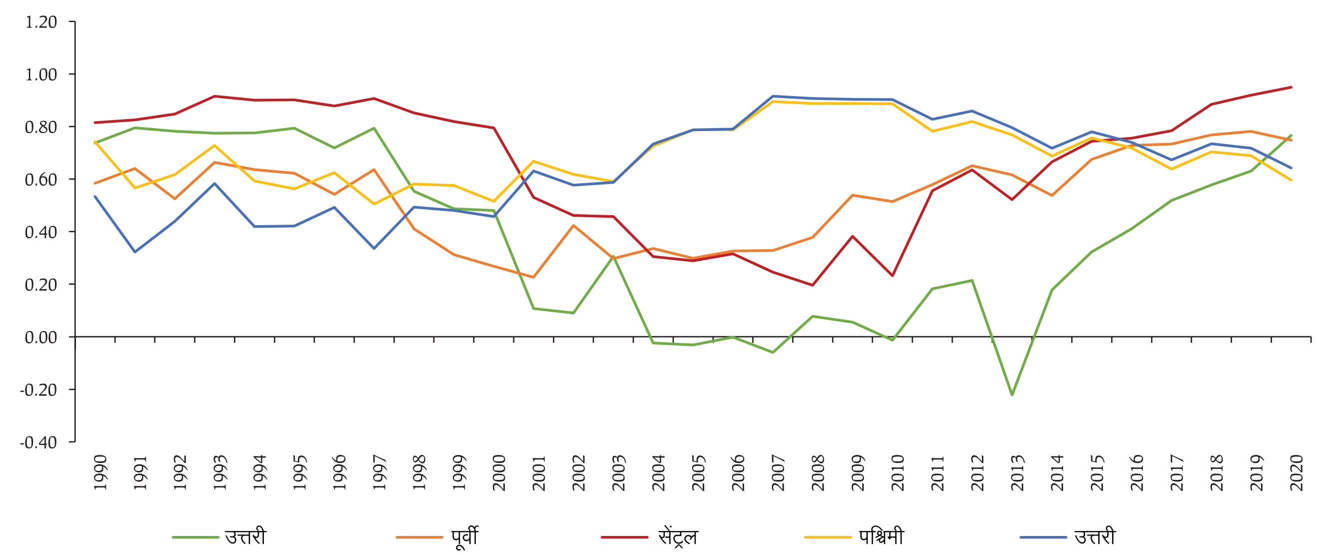

स्रोत: एनएसओ; और लेखकों की गणना।

समय के साथ समन्वय की डिग्री का मूल्यांकन राष्ट्रीय चक्र के साथ प्रत्येक क्षेत्र के चक्रों के बीच रोलिंग विंडो सहसंबंधों के संदर्भ में किया गया है। 1981-82 से शुरू होने वाले 10-वर्ष के प्रत्येक रोलिंग विंडो के लिए गणना किए गए सहसंबंध गुणांक को विंडो के अंतिम वर्ष के विरुद्ध रखा गया है (चार्ट 7)। चक्रों का समन्वय बड़े पैमाने पर आय के स्तरों द्वारा नियंत्रित होता है, जैसा कि शुरुआती वर्षों में 2000 के दशक के मध्य तक, अपेक्षाकृत समृद्ध उत्तरी राज्यों ने समग्र चक्रीय आंदोलन पर हावी रहा। बाद की अवधि में, पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्र, तेज गति से विकास के कारण, राष्ट्रीय चक्र पर बड़ा प्रभाव हासिल करने के लिए धीरे-धीरे उत्तरी और मध्य क्षेत्रों से आगे निकल गए। हालांकि, 2014 के बाद, उत्तरी क्षेत्र ने दोनों क्षेत्रों को काफी अच्छी तरह से पकड़ लिया है।

चक्रों की सह-गति को समझाने के लिए नॉर्मन और वॉकर (2007) में अपनाई गई रूपरेखा को अपनाया गया है जो देखे गए चक्रीय सह-गति को या तो सामान्य आघातों, विशिष्ट आघातों के फैलाव, या दोनों के संयोजन (खंड IV में वर्णित) के परिणामस्वरूप व्याख्या करता है। एक क्षेत्र की गतिविधि और दूसरे क्षेत्र की विलंबित गतिविधि के बीच उनके समकालीन

चार्ट 8: राष्ट्रीय चक्र के साथ समन्वय का माप

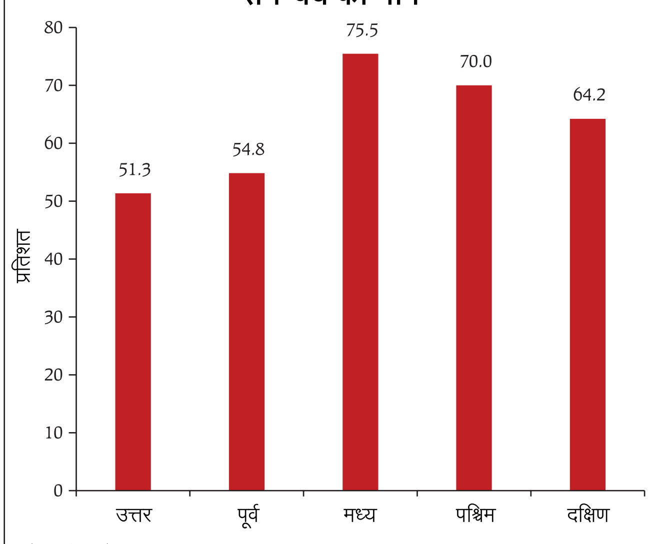

स्रोत: लेखकों की गणना.

[4] प्रत्येक क्षेत्र के चक्र के लिए राष्ट्रीय चक्र के साथ कोसाइन समानता की गणना करके समकालिकता की डिग्री को मापा गया है ताकि यह देखा जा सके कि क्षेत्रीय चक्र राष्ट्रीय चक्र के साथ कितना ओवरलैप करता है। 1 के करीब के मानों का समानता स्कोर मजबूत संरेखण को दर्शाता है और 0 के करीब के मान थोड़े या बिलकुल संरेखण को नहीं दर्शाते हैं। इसकी गणना इस प्रकार की गई है:

$$\text{कोसाइन समानता} = \frac{\sum(X * Y)}{\left(\sqrt{\sum X^2}\right) + \left(\sqrt{\sum Y^2}\right)}$$

जहाँ X क्षेत्रीय चक्र को दर्शाता है और Y राष्ट्रीय चक्र को दर्शाता है।

सारणी 4: एक वर्ष का विलंबित सहसंबंध

	उत्तरी	पूर्वी	केंद्रीय	पश्चिमी	दक्षिण	भारत
उत्तरी पिछड़ा हुआ	-0.23	-0.30*	0.23	0.11	0.02	0.08
पूर्वी पिछड़ा हुआ	0.23	0.03	0.72***	0.37**	0.29*	0.47***
केंद्रीय विलंबित	-0.07	-0.47***	0.32**	0.20	0.19	0.11
पश्चिमी पिछड़ा हुआ	-0.16	-0.11	0.25	0.46***	0.57***	0.23
दक्षिणी पिछड़ा हुआ	-0.15	-0.07	0.17	0.34**	0.47***	0.19
भारत पिछड़ गया	0.03	-0.17	0.45***	0.37**	0.35**	0.32**

नोट: ***, ** और * क्रमशः 1 प्रतिशत, 5 प्रतिशत और 10 प्रतिशत पर सांख्यिकीय महत्त्व दर्शाते हैं।
स्रोत: एनएसओ; और लेखकों की गणना।

सहसंबंधों की तुलना में उच्च सहसंबंध यह सुझाव देगा कि फैलाव सामान्य आघातों से अधिक महत्वपूर्ण हैं। हालाँकि, अधिकांश समकालीन सहसंबंध (सारणी 3) विलंबित सहसंबंधों (सारणी 4) की तुलना में सभी क्षेत्रों के लिए अधिक निकले, जो राष्ट्रीय नीतियों, कम बारिश/प्रतिकूल जलवायु घटनाओं जैसे घरेलू आघातों , या वैश्विक चरों को आघातों इत्यादि जैसे सामान्य घटकों के उच्च प्रभाव का सुझाव देते हैं। मध्य क्षेत्र में अधिक फैलाव, जलवायु संबंधी व्यवधानों के प्रभाव को प्रतिबिंबित कर सकता है, जैसे कि 2013 में उत्तराखंड में आई बाढ़, 2002, 2009 और 2015-16 के दौरान उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सूखा और गर्म लहरें, जो मध्य क्षेत्र के कृषि-प्रधान राज्यों को प्रभावित कर रही हैं और धीरे-धीरे अन्य क्षेत्रों में भी फैल रही हैं।

क्षेत्रीय चक्रों का विश्लेषण करने के बाद, इन चक्रीय गतिविधियों को आकार देने वाले कारकों के बारे में और अधिक जानकारी राज्य-स्तरीय डेटा का उपयोग करके खींची गई है, विशेष रूप से, दो पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए – राज्यों की भौगोलिक स्थिति और आर्थिक संरचना। जैसा कि पहले ही समझाया गया है, किसी राज्य की आर्थिक संरचना राष्ट्रीय जीवीए में उस क्षेत्र के हिस्से के सापेक्ष उसके जीएसवीए में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी का योगदान करने वाले क्षेत्र पर आधारित होती है। यदि क्षेत्र-विशिष्ट आघात प्रमुख हैं, तो वे संरचनात्मक रूप से समान राज्यों के चक्रों के उच्च सह-आंदोलन में प्रतिबिंबित होने की संभावना है। दूसरी ओर, मजबूत अंतर-क्षेत्रीय संबंध विभिन्न क्षेत्रीय अभिविन्यासों वाले राज्यों के व्यापार चक्रों के बेहतर समन्वयन में प्रतिबिंबित होंगे। आर्थिक संरचना के सभी संभावित संयोजनों के लिए राज्य व्यापार चक्रों के क्रॉस-सहसंबंध मैट्रिसेस का उपयोग इन कारकों का पता लगाने के लिए किया गया है।

समान क्षेत्रीय अभिविन्यास वाले समूहों में, औद्योगिक और सेवा-उन्मुख राज्यों की तुलना में कृषि राज्यों में व्यापार चक्र अधिक मजबूत प्रतीत होते हैं (सारणी 5 ए , 5 बी और 5 सी)। यह कृषि क्षेत्र के जलवायु संबंधी व्यवधानों जैसे सूखे, अधिक या अनियमित वर्षा से अपेक्षाकृत अधिक प्रभावित होने के कारण हो सकता है, जो खेती की गतिविधि को प्रभावित करते हैं। राज्यों की भौगोलिक स्थिति का कृषि राज्यों में चक्रों के सह-आंदोलन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। भारत के अग्रणी कृषि राज्यों में से एक उत्तर प्रदेश ने आंध्र प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और हरियाणा जैसे राज्यों के साथ काफी मजबूत व्यापार चक्र सहसंबंध प्रदर्शित किया। सेवा-उन्मुख राज्यों में, भौगोलिक निकटता महत्वपूर्ण हो सकती है क्योंकि कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और तेलंगाना जैसे सेवा-उन्मुख राज्यों में चक्रों का सहसंबंध काफी अधिक है।

कृषि-उद्योग जोड़ी और कृषि-सेवा जोड़ी के बीच चक्रों का समन्वय कई राज्यों के लिए काफी अधिक है - पड़ोसी और दूर के राज्य दोनों (सारणी 6ए और 6बी)। यह मूल्य नियंत्रण

सारणी 5: समान क्षेत्रीय अभिविन्यास में क्रॉस-सहसंबंध

क. कृषि

कृषि	हर	पं	राज	पश्चिम बंगाल	युपी	एमपी	एपी
हर	1						
पं	-0.17	1					
राज	0.35**	-0.10	1				
पश्चिम बंगाल	0.15	-0.12	0.13	1			
युपी	0.37**	0.02	0.43***	0.31*	1		
एमपी	0.23	0.11	0.41***	0.09	0.31**	1	
एपी	0.26	0.40**	0.22	-0.21	0.66***	0.27*	1

ख. उद्योग

उद्योग	हिमाचल प्रदेश	झार	ओडी	छग	यूके	गोवा	गुजरात	महा	पुडु
हिमाचल प्रदेश	1								
झार	0.05	1							
ओडी	0.51***	0.03	1						
छग	0.31*	0.01	0.34**	1					
यूके	0.12	0.18	0.01	-0.16	1				
गोवा	0.04	0.10	-0.00	0.19	0.12	1			
गुजरात	0.42***	0.27*	0.32**	0.01	0.30*	0.11	1		
महा	0.45***	-0.22	0.25	0.45***	0.04	0.04	0.05	1	
पुडु	-0.39**	0.18	-0.20	-0.33**	-0.14	0.16	-0.11	-0.94***	1

सी. सेवाएं

सेवाएं	जम्मू और कश्मीर	छग	डेल	बिह	कर	केर	तमिलनाडु	तेलंगाना
जम्मू और कश्मीर	1.00							
छग	0.09	1						
डेल	0.04	0.91***	1					
बिह	0.27*	-0.03	0.03	1				
कर	-0.02	-0.84***	-0.70***	0.09	1			
केर	0.22	-0.40**	-0.56***	-0.26	0.22	1		
तमिलनाडु	0.25	-0.73***	-0.78***	0.14	0.58***	0.52***	1	
तेलंगाना	0.04	-0.77***	-0.60***	0.15	0.75***	0.23	0.54***	1

टिप्पणियाँ: (i) एपी: आंध्र प्रदेश; बिह: बिहार; चा: चंडीगढ़; छग: छत्तीसगढ़; डेल: दिल्ली; गुजरात: गुजरात; हर: हरियाणा; जम्मू और कश्मीर: जम्मू और कश्मीर; झारः झारखंड; कर: कर्नाटक; केर: केरल; एमपी: मध्य प्रदेश; मह: महाराष्ट्र; ओडीआई: ओडिशा; पुडु: पुडुचेरी; पुन: पंजाब; राज: राजस्थान; टीएन: तमिलनाडु; दूरभाष: तेलंगाना; यूके: उत्तराखंड; उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश; पश्चिम बंगाल: पश्चिम बंगाल.

(ii) ***, ** और * क्रमशः 1 प्रतिशत, 5 प्रतिशत और 10 प्रतिशत पर सांख्यिकीय महत्व दर्शाते हैं।

स्रोत: लेखकों की गणना।

और सब्सिडी सहित राष्ट्रीय स्तर की नीतियों, या प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे के विकास के प्रसार के कारण हो सकता है, जिसके परिणामस्वरूप कृषि और सेवा राज्यों में बेहतर आर्थिक संबंध बन रहे हैं। महाराष्ट्र, एक प्रमुख औद्योगिक राज्य, ने भी सेवा उन्मुख दक्षिणी राज्यों (सारणी 6सी) के साथ मजबूत सहसंबंधों को दर्शाया।

राज्य व्यापार चक्रों के समन्वय में भौगोलिक स्थिति और आर्थिक संरचना द्वारा निभाई गई भूमिका की आगे ओएलएस प्रतिगमन विश्लेषण के माध्यम से जांच की गई है। राज्य चक्रों के जोड़ी-वार सहसंबंध को आश्रित चर के रूप में लिया जाता है जबकि राज्य की सीमाओं और आर्थिक संरचना से संबंधित डमी चर जैसा कि पहले परिभाषित किया गया है, उनकी परस्पर क्रिया के साथ प्रासंगिक परिकल्पनाओं का परीक्षण करने के

सारणी 6: अंतर-क्षेत्रीय क्रॉस सहसंबंध

क. कृषि

कृषि	हर	पं	राज	पश्चिम बंगाल	युपी	एमपी	एपी
हिमाचल प्रदेश	0.36***	0.45***	0.36**	-0.12	0.10	0.18	0.36**
झार	0.25	-0.24	0.25	0.21	0.10	-0.02	0.03
ओडी	0.20	0.26	0.31*	0.20	0.12	0.11	0.24
छग	-0.04	0.45***	0.17	0.03	-0.06	0.57***	0.10
यूके	0.45***	-0.01	0.29*	0.13	0.75***	0.08	0.54**
गोवा	0.14	0.04	0.28*	0.33**	0.45***	0.30*	0.21
गुजरात	0.30*	0.02	0.70***	0.05	0.29*	0.20	0.18
महा	-0.16	0.99***	-0.09	-0.13	0.08	0.12	0.44***
पुडु	0.13	-0.92***	0.07	0.18	-0.12	-0.06	-0.50***

ख. कृषि

सेवाएं	हर	पं	राज	पश्चिम बंगाल	युपी	एमपी	एपी
जम्मू और कश्मीर	0.47***	-0.07	0.31**	0.52***	0.36**	0.06	0.05
छग	0.14	-0.96***	0.08	0.17	-0.09	-0.08	-0.47***
डेल	0.15	-0.98***	0.11	0.09	0.01	-0.11	-0.33**
बिह	0.39**	-0.07	0.10	0.16	0.22	-0.16	0.10
कर	-0.22	0.76***	-0.07	-0.11	0.19	-0.14	0.49***
केर	0.23	0.52***	0.15	0.13	0.04	0.49***	0.14
तमिलनाडु	0.07	0.77***	-0.04	0.39**	0.15	0.03	0.24
तेलंगाना	0.12	0.67***	0.14	-0.13	0.50***	0.22	0.83***

सी. सेवाएं

उद्योग	जम्मू और कश्मीर	छग	डेल	बिह	कर	केर	तमिलनाडु	तेलंगाना
हिमाचल प्रदेश	0.17	-0.42***	-0.45***	0.13	0.21	0.23	0.40**	0.41***
झार	0.08	0.20	0.22	0.33**	-0.09	-0.04	-0.06	-0.12
ओडी	0.26	-0.21	-0.24	-0.14	0.33**	0.25	0.29*	0.24
छग	0.01	-0.37**	-0.48***	-0.15	0.17	0.47***	0.35**	0.20
यूके	0.26	-0.10	0.05	0.42***	0.12	-0.23	0.04	0.36**
गोवा	0.25	0.09	-0.14	0.06	-0.15	0.34**	0.20	0.05
गुजरात	0.33**	-0.10	-0.02	0.15	0.12	0.10	0.05	0.16
महा	-0.07	-0.98***	-0.98***	-0.02	0.79***	0.49***	0.77***	0.72***
पुडु	0.01	0.99***	0.86***	-0.05	-0.85***	-0.34**	-0.69***	-0.79***

टिप्पणियाँ: (i) एपी: आंध्र प्रदेश; बिह: बिहार; चा: चंडीगढ़; छग: छत्तीसगढ़; डेल: दिल्ली; गुजरात: गुजरात; हर: हरियाणा; जम्मू और कश्मीर: जम्मू और कश्मीर; झारः झारखंड; कर: कर्नाटक; केर: केरल; एमपी: मध्य प्रदेश; मह: महाराष्ट्र; ओडीआई: ओडिशा; पुडु: पुडुचेरी; पुन: पंजाब; राज: राजस्थान; टीएन: तमिलनाडु; दूरभाष: तेलंगाना; यूके: उत्तराखंड; उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश; पश्चिम बंगाल: पश्चिम बंगाल.

(ii) ***, ** और * क्रमशः 1 प्रतिशत, 5 प्रतिशत और 10 प्रतिशत पर सांख्यिकीय महत्व दर्शाते हैं।

स्रोत: लेखकों की गणना।

लिए उपयोग किए जाने वाले व्याख्यात्मक चर का गठन करते हैं। परिणामों की मजबूती और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए, वैकल्पिक समय अवधि को कवर करने वाले तीन प्रतिगमन क्रम में निर्दिष्ट किए गए हैं - 1980-2020, 1980-2010 और नवीनतम 1991-2020 अवधि, जिसमें बाद के दो में ओवरलैपिंग अवधि (1991-2010) है (सारणी 7)।

प्रतिगमन विश्लेषण से पता चलता है कि राज्यों की निकटता जितनी अधिक होगी, सभी समय अवधि के लिए उनके व्यापार चक्रों का सहसंबंध उतना ही अधिक होगा, हालांकि प्रतिगमन 3 में शामिल अपेक्षाकृत हाल की अवधि के लिए संबंध थोड़ा कमजोर हुआ है। दूसरी ओर, राज्यों की आर्थिक संरचना का चक्रों के सहसंबंध पर कोई सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण प्रभाव

सारणी 7: प्रतिगमन विश्लेषण

आश्रित चर: राज्यों में जोड़ी-वार सहसंबंध

	(1)	(2)	(3)
स्वतंत्र प्रभावित करने वाली वस्तुएँ	**1980-2020**	**1980-2010**	**1991-2020**
सीमा साझा करना	0.144** (0.07)	0.163** (0.07)	0.127* (0.07)
आर्थिक संरचना	-0.052 (0.05)	-0.049 (0.05)	-0.056 (0.06)
सीमा साझा करना * आर्थिक संरचना	0.029 (0.10)	0.009 (0.10)	0.068 (0.11)
स्थिर	0.092*** (0.03)	0.061** (0.03)	0.097*** (0.03)
टिप्पणियों	**276**	**276**	**276**
एफ सांख्यिकी	**3.48****	**3.65****	**2.78****
आर चुकता	**0.0313**	**0.0328**	**0.0243**

टिप्पणियाँ: (i) ***, ** और * क्रमशः 1 प्रतिशत, 5 प्रतिशत और 10 प्रतिशत पर सांख्यिकीय महत्त्व दर्शाते हैं।
(ii) कोष्ठक में दिए गए आंकड़े मानक त्रुटियों को दर्शाते हैं।

स्रोत: लेखकों की गणना।

नहीं दिखता है। समान आर्थिक संरचना वाले पड़ोसी राज्यों को दर्शाने वाला अंतःक्रिया शब्द भी सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण नहीं निकला। उदाहरण के लिए, महाराष्ट्र और गुजरात दोनों उद्योग-उन्मुख राज्यों में नगण्य क्रॉस-सहसंबंध है (सारणी 5बी)।

VI. निष्कर्ष

यद्यपि उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में प्रचलित है, भारतीय संदर्भ में व्यापार चक्रों से संबंधित अनुसंधान मुख्य रूप से उच्च आवृत्ति डेटा (कम से कम त्रैमासिक आवृत्ति पर) की अनुपलब्धता के कारण राष्ट्रीय स्तर तक सीमित है, जो व्यापार चक्र विश्लेषण के लिए आदर्श है। भारतीय राज्यों की विशिष्ट आर्थिक विशेषताओं को देखते हुए, यह पत्र पिछले चार दशकों में राज्य व्यापार चक्रों के समन्वय को चलाने वाले कारकों की जाँच करके भारतीय व्यापार चक्र पर विरल साहित्य में योगदान देता है। राज्यों के जीएसडीपी को भौगोलिक क्षेत्रों में एकत्रित करके और बीके फिल्टर और यूसीएम फ्रेमवर्क का उपयोग करके आगामी क्षेत्रों से चक्रों को निकालकर राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय चक्रों के समन्वय का आकलन किया गया है। राज्य-स्तरीय डेटा का उपयोग करके एक विस्तृत विश्लेषण इस प्रकार है, जहां चक्रों के समन्वय को प्रभावित करने में राज्यों की भौगोलिक स्थिति और आर्थिक संरचना जैसे कारकों की भूमिका का पता लगाया गया है।

राष्ट्रीय और क्षेत्रीय चक्रों के बीच समन्वय समय के साथ बढ़ा है, जिसमें पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्र 2000 के दशक से राष्ट्रीय चक्र के साथ मजबूत सह-संचलन दिखा रहे हैं। क्षेत्रीय चक्रों के बीच उच्च सहसंबंध मानसून और मौसम के आघात , वैश्विक कच्चे तेल और कमोडिटी मूल्य आघात , वैश्विक मांग और वैश्विक वित्तीय बाजार स्पिलओवर, राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति और विनिमय दर में उतार-चढ़ाव जैसे सामान्य कारकों के बड़े असर के कारण हो सकते हैं, जो सभी क्षेत्रों को एक साथ प्रभावित करते हैं। फिर भी, मध्यम रूप से उच्च एक वर्षीय विलंबित क्रॉस-सहसंबंध भी कुछ क्षेत्रों में विशिष्ट आघातों के स्पिलओवर प्रभावों की उपस्थिति को रेखांकित करते हैं। घटक राज्यों की भौगोलिक निकटता का समन्वय पर प्रभाव पड़ने की संभावना है क्योंकि सीमावर्ती राज्यों वाले क्षेत्रों ने उच्च क्रॉस-सहसंबंध दिखाए। कृषि राज्यों ने औद्योगिक और सेवा-उन्मुख राज्यों की तुलना में आपस में अधिक समन्वय दिखाया। भौगोलिक निकटता औद्योगिक और सेवा राज्यों के साथ अंतर्संबंधों के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रतिगमन विश्लेषण व्यापार चक्रों के समन्वय पर भौगोलिक निकटता की सकारात्मक भूमिका को मान्य करता है, हालांकि अपेक्षाकृत हाल की अवधि में इसका परिमाण छोटा है।

हालाँकि, राज्यों की क्षेत्रीय संरचना का चक्रों के समन्वय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

इस अध्ययन में किए गए व्यवसाय चक्र सहसंबंध विश्लेषण से अर्थव्यवस्था में आर्थिक उतार-चढ़ाव को कम करने के लिए प्रति-चक्रीय नीतियों के निर्माण में सहायता मिल सकती है, साथ ही व्यापार और श्रम गतिशीलता को सुविधाजनक बनाने के लिए क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे के निवेश को मजबूत करने में सहयोग करने में मदद मिल सकती है। प्रभावी नीति निर्माण के लिए व्यवसाय चक्रों की प्रासंगिकता को देखते हुए, उप-राष्ट्रीय खातों को मजबूत करना सबसे महत्वपूर्ण है, जिसमें राज्यों और राष्ट्रीय खातों के बीच संकलन में स्थिरता, राष्ट्रीय खातों के समान एक परिभाषित डेटा रिलीज कैलेंडर, नीचे से ऊपर के दृष्टिकोण से उप-राष्ट्रीय खातों का संकलन और मांग पक्ष (निजी और सरकारी खपत, और निश्चित निवेश) से डेटा की उपलब्धता से संबंधित पहलू शामिल हैं।

संदर्भ

Agénor, P. R., McDermott, C. J., and Prasad, E. S. (2000). Macroeconomic fluctuations in developing countries: some stylized facts. *The World Bank Economic Review*, 14(2), 251-285.

Ahmad, J. K., Blum, F. M., Gupta, P., and Jain, D. (2018). India's Growth Story. *World Bank Policy Research Working Paper*, (8599).

Bonilla Bolaño, A. G. (2014). An Examination of the Convergence in the Output of South American Countries: The Influence of the Region's Integration Projects. *GATE Working Papers WP*, 1424.

Bry, G., and Boschan, C. (1971). Front matter to Cyclical Analysis of Time Series: Selected Procedures and Computer Programs. In Cyclical analysis of time series: Selected procedures and computer programs (pp. 13-2). *NBER.*

Burns, A. F., and Mitchell, W. C. (1946). Measuring business cycles. *NBER*

Dua P, Banerji A (2012). Business and Growth Rate Cycles in India. *Working papers 210, Centre for Development Economics, Delhi School of Economics.*

Ghate, C., Pandey, R., and Patnaik, I. (2013). Has India emerged? Business cycle stylized facts from a transitioning economy. *Structural Change and Economic Dynamics*, 24, 157-172.

Kaldor, N. (1957). A model of economic growth. *The Economic Journal*, 67(268), 591-624.

Kishor, N. K., and Ssozi, J. (2011). Business cycle synchronization in the proposed East African Monetary Union: An unobserved component approach. *Review of Development Economics*, 15(4), 664-675.

Kouparitsas, M. A. (2003). Understanding US regional cyclical co-movement: How important are spillovers and common shocks? Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=377781 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.377781

Kumar, U., and Subramanian, A. (2012). Growth in India's states in the first decade of the 21st century: four facts. *Economic and Political Weekly*, 48-57.

Magrini, S., Gerolimetto, M., and Duran, H. E. (2013). Business cycle dynamics across the US states. *The BE Journal of Macroeconomics*, 13(1), 795-822.

Male, R. (2011). Developing Country Business Cycles: Characterizing the Cycle. *Emerging Markets Finance and Trade*, *47*, 20–39. http://www.jstor.org/stable/23047441

Male, R. (2010). Developing country business cycles: Revisiting the stylised facts (No. 664). *World Bank Policy Research Working paper.*

Martínez-García, E. (2014). US Business Cycles, Monetary Policy and the External Finance Premium. In Advances in Non-Linear Economic Modeling: Theory and Applications (pp. 41-114). Berlin, Heidelberg: *Springer* Berlin Heidelberg.

Mitchell, W. C. (1927). Economic Organization and Business Cycles. In Business cycles: the problem and its setting (pp. 61-188). *NBER.*

Mitchell, W. C., and Burns, A. F. (1938). Statistical indicators of cyclical revivals. In Statistical indicators of cyclical revivals (pp. 1-12). *NBER.*

Norman, D., and Walker, T. (2007). Co-movement of Australian state business cycles. *Australian Economic Papers*, 46(4), 360-374.

NSO (2020). Report of the Committee for Sub-National Accounts. National Statistical Office, Ministry of Statistics and Programme Implementation, Government of India. March 2020.

Owyang, M. T., Rapach, D. E., and Wall, H. J. (2009). States and the business cycle. *Journal of Urban Economics*, 65(2), 181-194.

Pandey, R., Patnaik, I., and Shah, A. (2017). Dating business cycles in India. *Indian Growth and Development Review*, 10(1), 32-61.

प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र ऋण : भारतीय अनुभव

सांभवी ढींगरा, अर्पिता अग्रवाल, और स्नेहल एस. हेरवाडकर^ द्वारा

भारत में प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र ऋण (पीएसएल) का उपयोग अर्थव्यवस्था के जरूरतमंद क्षेत्रों को ऋण देने के लिए नीतिगत हस्तक्षेप उपकरण के रूप में किया गया है। मार्च 2006 से मार्च 2023 तक तिमाही बैंक-स्तरीय डेटा का लाभ उठाते हुए, अनुभवजन्य विश्लेषण से पता चलता है कि प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र ऋण प्रमाणपत्रों की शुरूआत ने प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र ऋण में वृद्धि की है। विश्लेषण आगे बताता है कि पीएसएल अपनी आस्ति गुणवत्ता के प्रति उत्तरदायी है और उच्च पीएसएल वृद्धि बैंकों की समग्र आस्ति गुणवत्ता में सुधार करती है।

परिचय

वाणिज्यिक बैंकिंग भारत की वित्तीय प्रणाली का एक प्रमुख हिस्सा है, जिसका दायरा और पहुंच लगातार बढ़ रही है। अनौपचारिक ऋण संस्थानों की व्यापकता और बैंकिंग सेवाओं तक असमान पहुंच ने वित्तीय समावेशन नीतियों की शुरुआत करना आवश्यक बना दिया। भारत में, प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र ऋण (पीएसएल) समावेशन उद्देश्य को आगे बढ़ाने की समग्र संरचना और योजना के अंतर्गत आता है। मुख्य रूप से, अर्थव्यवस्था के वे क्षेत्र जो आबादी के बड़े हिस्से को प्रभावित करते हैं और रोजगार-प्रधान हैं, प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं (आरबीआई, 2007)। इनमें मुख्य रूप से कृषि और संबद्ध गतिविधियों, सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई), आवास, निर्यात, शिक्षा और कमज़ोर वर्गों को प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र ऋण के लिए ऋण शामिल हैं। भारत में पीएसएल दिशा-निर्देशों की समय-समय पर समीक्षा और संशोधन किया गया है ताकि उन्हें उभरती राष्ट्रीय प्राथमिकता-प्राप्तओं के साथ जोड़ा जा सके और समावेशी विकास पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जा सके।

^ लेखक, आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग (डीईपीआर) से हैं। डॉ. टी. गोपीनाथ, नवजोत कौर, शिबी मथाई, शालिनी जैन, पर्यवेक्षण विभाग और आरबीआई बुलेटिन संपादकीय समिति से प्राप्त टिप्पणियों और सुझावों के लिए आभार व्यक्त किया जाता है। इस आलेख में व्यक्त किए गए विचार लेखकों के हैं और भारतीय रिज़र्व बैंक के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।

इस आलेख का उद्देश्य भारत में पीएसएल कार्यक्रम के रुझानों की जांच करना है, साथ ही इसके प्रमुख चालकों का मूल्यांकन करना है। यह बैंकों की आस्ति गुणवत्ता पर पीएसएल के प्रभाव का भी आकलन करता है। आलेख का शेष भाग इस प्रकार व्यवस्थित है। खंड II निर्देशित ऋण देने के औचित्य और अंतर-देशीय अनुभव पर साहित्य का दृष्टि प्रदान करता है। खंड III भारत में पीएसएल के विकास और अब तक के प्रदर्शन की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। खंड IV अनुभवजन्य विश्लेषणों के साथ अनुसंधान पद्धति प्रस्तुत करता है, जबकि खंड V आलेख का समापन किया गया है।

II. साहित्य की समीक्षा

उच्च लेन-देन लागत और सूचना विषमता की व्यापकता अपेक्षाकृत जोखिमपूर्ण लेकिन आर्थिक रूप से उत्पादक गतिविधियों और उधारकर्ताओं तक ऋण प्रवाह को सीमित कर सकती है। अपेक्षित परियोजना विवरणी के बारे में पूरी जानकारी के अभाव में, बैंक अपने ऋण देने के निर्णयों को अवलोकनीय जोखिम विशेषताओं और/या अच्छे संपार्श्विक की उपलब्धता पर आधारित करते हैं, जिससे पारंपरिक रूप से व्यवहार्य उधारकर्ताओं को ऋण प्रवाह जारी रहता है। ऐसी परियोजनाओं को कम लाभ पहुँचाने का यह जोखिम, जिनकी ऋण तक पहुँच पहले से ही सीमित है, सरकारों को पीएसएल-प्रकार के कार्यक्रम लागू करने के लिए प्रेरित कर सकता है (मुंद्रा, 2017)।

कृषि क्षेत्र में ऋण के प्रावधान को सीमित करने वाली असममित सूचना की समस्या और भी अधिक स्पष्ट हो जाती है। कृषि रोजगार पैदा करके, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करके और गरीबी को कम करके आर्थिक संवृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, खासकर भारत जैसी उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) में। हालांकि, वर्षा पर उनकी भारी निर्भरता और बार-बार होने वाले जलवायु झटकों के कारण कृषि उपज और कीमतों में अंतर्निहित अनिश्चितता को देखते हुए, किसान उधारकर्ताओं को अक्सर ऋण तक सीमित पहुंच का सामना करना पड़ सकता है (कैलोमिरिस और हिमेलबर्ग, 1993)। औपचारिक ऋण के अभाव में, उन्हें निर्देशित ऋण कार्यक्रमों के तहत लाना और भी अधिक आवश्यक हो जाता है (चक्रवर्ती, 2012)।

इसी तरह, लघु उद्योग अक्सर 'अनौपचारिक' प्रकृति के होते हैं और पर्याप्त दस्तावेज़ों की कमी उन्हें वित्तपोषित करने में एक बड़ी बाधा है। ये उद्योग, जिनमें आमतौर पर कम पूंजी-

उत्पादन अनुपात होता है और श्रम गहन होते हैं, जरूरी नहीं कि वाणिज्यिक बैंकों के पसंदीदा ग्राहकों में से हों और इसलिए, ऋण की कमी हो सकती है। ऐसे उद्योगों को ऋण देना विशेष रूप से श्रम-अधिशेष विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में फायदेमंद है, क्योंकि यह रोजगार पैदा करता है और आय असमानता को कम करता है (कोहली, 1997)।

निर्देशित उधार की प्रभावकारिता पर अलग-अलग विचार हैं, विशेष रूप से इसकी वाणिज्यिक व्यवहार्यता के संबंध में। उदाहरण के लिए, 1984-86 में तमिलनाडु में किए गए एक अध्ययन से पता चला है कि राष्ट्रीयकृत बैंक, जिन्होंने कृषि को भारी मात्रा में उधार दिया, सरकारी ऋण योजनाओं में पर्याप्त रूप से भाग लिया और कमजोर वर्गों और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों (एससी/एसटी) के उधारकर्ताओं को महत्वपूर्ण मात्रा में निर्देशित किया, उनकी वसूली दर सबसे अधिक थी (नारायण, 1992)। पीएसएल बैंकों की अनर्जक आस्ति (एनपीए) अनुपातों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालता है (गौर और महापात्रा, 2020)। दूसरी ओर, कुछ अध्ययनों के अनुसार, चार भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के लिए प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण देने से जुड़ी श्रम और प्रशासनिक लागत अनारक्षित क्षेत्र में ऋण देने की तुलना में अधिक थी, और ऐसे ऋणों ने बैंकों के एनपीए में आनुपातिक रूप से अधिक योगदान दिया (बनर्जी और डुफ्लो, 2000; बनर्जी और डुफ्लो, 2014)।

प्राथमिकता-प्राप्त ऋण के संभावित व्यापक आर्थिक प्रभावों ने मौजूदा साहित्य में कई तरह की प्रतिक्रियाएं दी हैं। कुछ शर्तों के तहत, निर्देशित ऋण कार्यक्रमों के रूप में सरकारी हस्तक्षेप न केवल वित्तीय विकास की शुरुआत करेगा, बल्कि संस्थानों की स्थिरता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश भी प्रदान करेगा (चक्रवर्ती और अन्य, 2019)। हालांकि, एक अन्य अध्ययन से पता चलता है कि छोटी फर्मो ने प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के ऋण तक पहुंच पाने के लिए अपने विस्तार का त्याग किया (भुए और अन्य, 2019)।

रोजगार के अवसरों को बढ़ाकर और सामाजिक समानता को बढ़ावा देकर, प्राथमिकता-प्राप्त वाले क्षेत्रों के लिए निर्देशित ऋण गैर-प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों पर भी प्रभाव डालता है, जिससे संतुलित आर्थिक विकास सुनिश्चित होता है (गौर और मोहपात्रा, 2020)। इस तरह के कार्यक्रम आय असमानता और अनौपचारिक ऋण पर निर्भरता को कम करने के कल्याण उद्देश्यों को पूरा करने के साथ-साथ गरीबी उन्मूलन (फेडरल रिज़र्व बैंक ऑफ सैन फ्रांसिस्को, 2014) में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसा कि मुहम्मद यूनुस (1987) ने टिप्पणी की, यदि पीएसएल का कार्यान्वयन दोषपूर्ण है और एनपीए अधिक है, तो *"किसी को विफलता के लिए प्राप्तकर्ता देश के लोगों को दोष देने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए; बल्कि किसी को उस ऋण संस्थान के डिजाइनर को दोष देना चाहिए जो काम करने में विफल रहा।"*

ऋण निर्देशन के तंत्र विभिन्न रूप लेते हैं, जैसे ब्याज सब्सिडी, ब्याज दर सीमा, सरकार द्वारा प्रत्यक्ष ऋण, सरकारी गारंटी, बैंकों के लिए ऋण कोटा, विकास वित्त संस्थानों (डीएफआई) के माध्यम से ऋण देना या इन तरीकों का संयोजन। कई देशों में, विशेष रूप से ईएमई में पीएसएल का कोई न कोई रूप मौजूद है। उदाहरण के लिए, इंडोनेशिया अपने कुल पोर्टफोलियो के 20 प्रतिशत के कोटा के साथ छोटे और मध्यम उद्यमों (एसएमई) को प्राथमिकता-प्राप्त ऋण देता है (आईएलओ, 2019)। मलेशिया और वियतनाम ने प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों को ऋण देने के लिए ब्याज दर छूट लागू की (फेडरल रिज़र्व बैंक ऑफ सैन फ्रांसिस्को, 2014)।

प्रत्यक्ष ऋण की नीति पूर्वी एशियाई देशों में मजबूत आर्थिक प्रदर्शन में योगदान देने वाला एक महत्वपूर्ण कारक थी (विश्व बैंक, 1993)। जापान विकास बैंक ने निजी बैंकों से वृद्धिशील ऋण देने, नई फर्मों को ऋण की बेहतर पहुँच प्रदान करने और युद्ध के बाद के जापान में नए निवेश को उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई (होरियुची और सुई, 1993)। कोरिया में, सरकार के नेतृत्व में ऋण की दिशा ने व्यापक बाजार खामियों को दूर करने और नए उधारों को निवेश में बदलने में मदद की, जिससे आगे की आर्थिक वृद्धि हुई (चो और हेलमैन, 1993; वर्नर, 2002)। फ्रांसीसी ऋण गारंटी कार्यक्रम ने नव निर्मित फर्मों के विकास को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया और लक्षित फर्मों को व्यवस्थित रूप से अधिक बाहरी वित्त जुटाने, कम ब्याज खर्च का भुगतान करने और अन्य समान फर्मों की तुलना में उच्च विकास दर का आनंद लेने में सक्षम बनाया (लेलार्ज और अन्य, 2010)।

अमेरिका में, जबकि निर्देशित ऋण कार्यक्रम लक्षित समूह को ऋण बढ़ाने में सफल रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वे उस समूह द्वारा निवेश में वृद्धि करें (श्वार्ट्ज, 1992)। कुछ मामलों में, अकुशल कार्यान्वयन ने संसाधनों के अधिक न्यायसंगत वितरण को बढ़ावा देने के बजाय आय असमानता को भी बढ़ाया है,

जैसे कोस्टा रिका में, जहां सब्सिडी वाले ऋण ने लक्षित समूह के बजाय आबादी के सबसे धनी 10 प्रतिशत लोगों की आय में वृद्धि की (वोगेल, 1984)। कई देशों में, ये कार्यक्रम उच्च एनपीए, कम लाभप्रदता और लक्ष्यों को पूरा करने में शामिल उच्च परिवर्तनीय लागतों के साथ-साथ नैतिक जोखिम संबंधी चिंताओं के मामले में बैंकिंग उद्योग के लिए विशेष रूप से महंगे साबित हुए। इंडोनेशिया में, बैंकिंग प्रणाली के एसएमई ऋण पोर्टफोलियो ने समग्र पोर्टफोलियो की तुलना में निम्न आस्ति गुणवत्ता प्रदर्शित की (फेडरल रिज़र्व बैंक ऑफ सैन फ्रांसिस्को, 2014)।

दक्षिण कोरिया और जापान में, निर्देशित ऋण कार्यक्रमों को आम तौर पर प्रभावी ढंग से लागू किया गया माना जाता है, जिनकी सफलता के लिए कई कारक जिम्मेदार हैं। इन देशों में हस्तक्षेपकारी नीतियों को उचित संस्थागत तंत्र द्वारा पूरक बनाया गया है। जापान में, एक बार जब किसी फर्म को ऋण तक प्राथमिकता पहुंच मिल जाती है, तो उन्हें पीएसएल के तहत आगे उधार लेने से प्रतिबंधित कर दिया जाता है और नए उधारकर्ताओं को ऋण दिया जाता है। कोरिया में, यदि लाभार्थियों द्वारा प्रदर्शन मानकों को पूरा नहीं किया जाता है, तो ऋण वापस ले लिया जाता है या नया ऋण देने से मना कर दिया जाता है। सख्त प्रदर्शन मानकों के साथ-साथ प्रभावी निगरानी तंत्र ने इन कार्यक्रमों की सफलता सुनिश्चित की।

संक्षेप में, उपलब्ध साहित्य निर्देशित ऋण कार्यक्रमों की प्रभावकारिता पर कई तरह के विचार प्रस्तुत करता है। आलेख में किया गया विश्लेषण निम्नलिखित तरीकों से मौजूदा साहित्य में योगदान देता है। सबसे पहले, जबकि भारतीय संदर्भ में पहले के अधिकांश शोधपत्र या तो सैद्धांतिक या केस स्टडी थे, यह आलेख अनुभवजन्य रूप से पीएसएल के चालकों का मूल्यांकन करता है। दूसरा, बैंकों की आस्ति गुणवत्ता पर पीएसएल के प्रभाव पर साहित्य बहुत कम है, खासकर भारत के लिए; यह आलेख इस कमी को पूरा करता है। तीसरा, यह बैंक-स्तरीय तिमाही पर्यवेक्षी डेटा का उपयोग करता है, जो विश्लेषण में अधिक विस्तृत जानकारी जोड़ता है।

III. भारत में प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र ऋण

III.1 इतिहास और उद्भव

1969 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद से भारत में प्राथमिकता-प्राप्त प्राप्त क्षेत्र को उधार देना, ऋण नियंत्रण नीतियों का मुख्य आधार रहा है। 1972 में, प्राथमिकता-प्राप्त प्राप्त क्षेत्र और उस योग्य क्षेत्रों का विवरण, रिज़र्व बैंक के एक अनौपचारिक अध्ययन समूह की सिफारिशों के आधार पर औपचारिक रूप दिया गया था, और 1974 में इसके लिए कुल ऋण का 33.33 प्रतिशत का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसे 1979 तक हासिल किया जाना था। 1980 में लक्ष्य को और बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दिया गया, साथ ही कृषि और कमजोर वर्गों को उधार देने के लिए विशिष्ट उप-लक्ष्य भी निर्धारित किए गए, जिन्हें 1985 तक हासिल किया जाना था। तब से, विभिन्न प्रकार के बैंकों पर अलग-अलग प्रयोज्यता, ऋण की मात्रा, लक्षित क्षेत्र और उप-लक्ष्य, और बैंकों द्वारा कमी के उपचार के संदर्भ में दिशानिर्देशों में और परिवर्तन हुए हैं। अप्रैल 2007 से, पीएसएल आवश्यकता को बैंक के समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी)[1] या ऑफ-बैलेंस शीट एक्सपोजर (सीईओबीई) के समतुल्य ऋण के प्रतिशत के रूप में निर्दिष्ट किया जा रहा है, जो भी अधिक हो।

अपने वर्तमान स्वरूप में, पीएसएल दिशा-निर्देशों के अनुसार घरेलू वाणिज्यिक बैंकों [क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) और लघु वित्त बैंकों (एसएफबी) को छोड़कर] और विदेशी बैंकों (एफबी) को अपने एएनबीसी या सीईओबीई का 40 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार देना आवश्यक है।[2] कुल लक्ष्य में से, 18 प्रतिशत कृषि के लिए निर्धारित है [लघु और सीमांत किसानों (एसएमएफ)[3] के लिए 10 प्रतिशत], सूक्ष्म उद्यमों के लिए

[1] एएनबीसी = बैंक ऋण + ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (आरआईडीएफ) के अंतर्गत बकाया जमाराशि तथा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी), भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) तथा माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी (मुद्रा) लिमिटेड के पास प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र ऋण लक्ष्य/उप-लक्ष्य की प्राप्ति न होने के एवज में अन्य पात्र निधियां + बकाया पीएसएलसी + प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के रूप में माने जाने योग्य अन्य निवेश + परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) श्रेणी के अंतर्गत गैर-सांविधिक तरलता अनुपात (एसएलआर) श्रेणियों में बांड/डिबेंचर - आरबीआई तथा अन्य अनुमोदित वित्तीय संस्थानों के पास पुनर्भुनाए गए बिल - अवसंरचना तथा किफायती आवास के लिए दीर्घकालिक बांड जारी करने पर छूट हेतु पात्र राशि - वृद्धिशील विदेशी मुद्रा अनिवासी बैंक [एफसीएनआर (बी)]/अनिवासी बाह्य (एनआरई) जमाराशियों के विरुद्ध भारत में दिए गए अग्रिम, जो नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर)/एसएलआर आवश्यकताओं से छूट के लिए अर्ह हैं - भारत सरकार द्वारा जारी पुनर्पूंजीकरण बांडों में पीएसबी द्वारा किए गए निवेश - लक्षित दीर्घकालिक रेपो परिचालन (टीएलटीआरओ) 2.0 के अंतर्गत एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत अर्जित और रखी गई प्रतिभूतियों का अंकित मूल्य।

[2] 20 से कम शाखाओं वाले वित्तीय बैंकों को एएनबीसी या सीईओबीई का 40 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार देना होगा, जिसमें से 32 प्रतिशत निर्यात के लिए और 8 प्रतिशत से कम अन्य प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों के लिए नहीं हो सकता है। आरआरबी और एसएफबी को अपने एएनबीसी या सीईओबीई का 75 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार देना होगा।

[3] 4 सितंबर, 2020 को जारी रिज़र्व बैंक के परिपत्र के अनुसार, एसएमएफ के लिए उप-लक्ष्य 2020-21 में 8 प्रतिशत से बढ़ाकर 2021-22 में 9 प्रतिशत, 2022-23 में 9.5 प्रतिशत और 2023-24 में 10 प्रतिशत कर दिया गया।

7.5 प्रतिशत और कमज़ोर वर्गों के लिए 12 प्रतिशत।[4] पीएसएल का दायरा धीरे-धीरे उन क्षेत्रों को शामिल करने के लिए व्यापक किया गया है, जिन्होंने समकालीन समय में प्रमुखता हासिल की है। तदनुसार, सामाजिक बुनियादी ढांचे और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए विस्तारित ऋण को 2015 में पीएसएल में शामिल किया गया था।

कोविड-19 के कारण प्राथमिकताओं पर फिर से ध्यान केंद्रित किया गया और डिजिटल सेवाओं तक पहुँच बढ़ाने के साथ-साथ स्वास्थ्य और शिक्षा के बुनियादी ढाँचे में निवेश करने का महत्व सामने आया। नवीनतम पीएसएल दिशानिर्देशों के अनुसार, स्कूल, पेयजल और स्वच्छता सुविधाएँ स्थापित करने के लिए प्रति उधारकर्ता 5 करोड़ रुपये तक के ऋण और टियर II से टियर VI केंद्रों में स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएँ (*'आयुष्मान भारत'* के तहत) बनाने के लिए प्रति उधारकर्ता 10 करोड़ रुपये तक के ऋण प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र वर्गीकरण के लिए पात्र हैं।[5]

III.2 लक्ष्यों और उप-लक्ष्यों की प्राप्ति

अपने जोखिम प्रोफाइल और मौजूदा ग्राहकों के आधार पर, बैंक अप्रत्यक्ष मार्गों का सहारा ले सकते हैं, जैसे अंतर-बैंक भागीदारी प्रमाणपत्र (आईबीपीसी) और प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के ऋणों का प्रतिभूतिकरण, साथ ही प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के लक्ष्य और उप-लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए। इसके अलावा, पीएसएल प्रमाणपत्र (पीएसएलसी) अप्रैल 2016 में पेश किए गए थे, जैसा कि वित्तीय क्षेत्र सुधारों पर रघुराम राजन समिति (2009) ने सिफारिश की थी, ताकि बैंकों को प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के तहत श्रेणियों को अधिशेष उधार देने को प्रोत्साहित करते हुए कमी की स्थिति में पीएसएल लक्ष्य और उप-लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम बनाया जा सके। यह पीएसएलसी में व्यापार करने वाले बैंकों को अपनी विशेषज्ञता के क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करने और अधिक कुशलता से ऋण वितरित करने का लाभ भी प्रदान करता है। रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के तहत चार श्रेणियों के लिए पीएसएलसी की ट्रेडिंग की अनुमति है - कृषि, एसएमएफ, सूक्ष्म उद्यम और सामान्य। जिन बैंकों के पास अभी भी कमी है, उन्हें आरआईडीएफ और नाबार्ड/एनएचबी/सिडबी/मुद्रा लिमिटेड के साथ अन्य फंड में योगदान करना आवश्यक है।

प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को दिया जाने वाला ऋण आम तौर पर विभिन्न समयावधियों और बैंक समूहों में 40 प्रतिशत से अधिक रहा है, तथा इसका सटीक अनुपात, अन्य बातों के साथ-साथ, बैंक की समग्र व्यावसायिक रणनीति, पहुंच, ऐसे ऋणों की आस्ति गुणवत्ता और उनकी विशेषज्ञता पर निर्भर करता है (चार्ट 1)।

चार्ट 1: पीएसएल लक्ष्य उपलब्धि

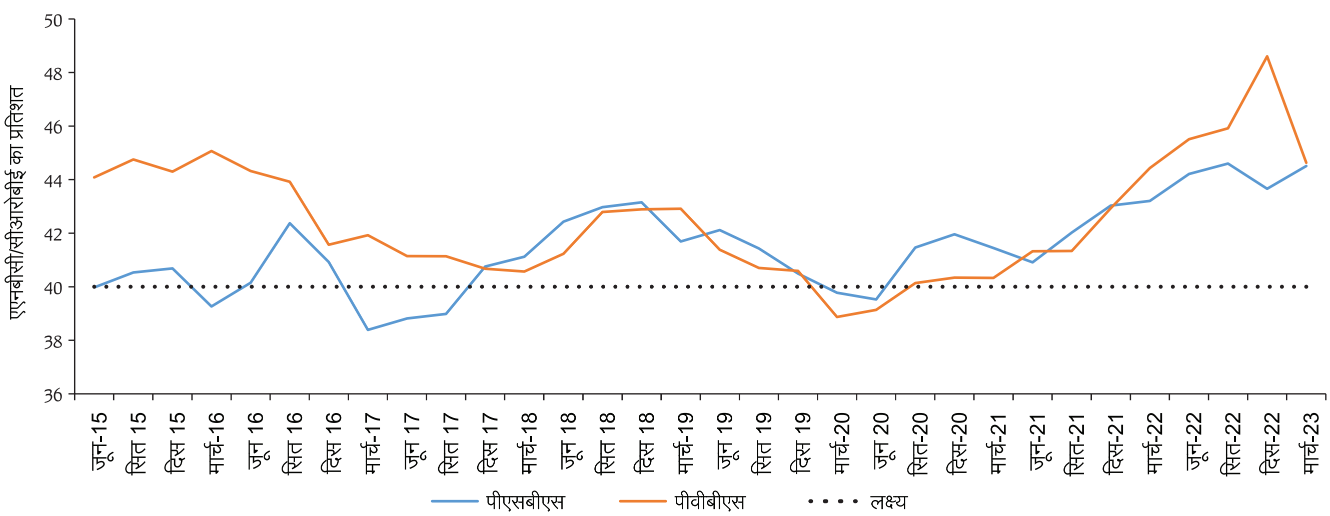

टिप्पणी : वार्षिक पीएसएल लक्ष्य प्राप्ति को चार तिमाहियों के औसत के रूप में मापा जाता है। इस प्रकार, चार्ट में प्रत्येक तिमाही में लक्ष्य से विचलन को कमी के रूप में व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है।

स्रोत: आरबीआई

4 कमजोर वर्गों के लिए उप-लक्ष्य को 2020-21 में 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 2021-22 में 11 प्रतिशत, 2022-23 में 11.5 प्रतिशत तथा 2023-24 में 12 प्रतिशत कर दिया गया।

5 नवीनतम दिशानिर्देश https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_ViewMasDirections.aspx?id=11959 पर देखे जा सकते हैं

चार्ट 2 : पीएसएल उप लक्ष्य उपलब्धि

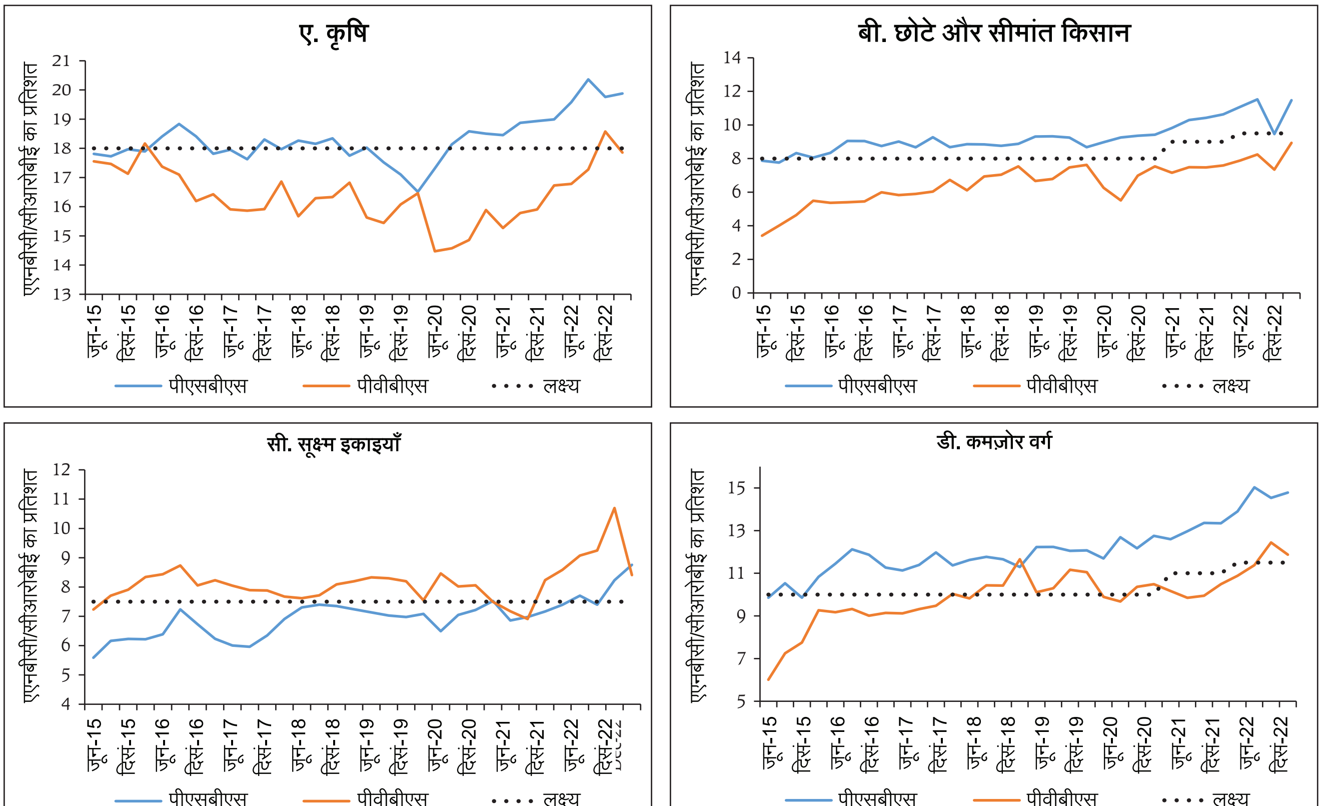

टिप्पणी : वार्षिक पीएसएल उप-लक्ष्य उपलब्धि को चार तिमाहियों के औसत के रूप में मापा जाता है। इस प्रकार, चार्ट में प्रत्येक तिमाही में उप-लक्ष्य से विचलन को कमी के रूप में व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है।
स्रोत: आरबीआई

कृषि के मामले में, पीएसबी ने अधिकांश अवसरों पर 18 प्रतिशत का अपना लक्ष्य पूरा किया है; निजी क्षेत्र के बैंक (पीवीबी), जो पहले लगातार लक्ष्य से पीछे रह जाते थे, हाल के वर्षों में लक्ष्य के अनुरूप हो गए हैं। दूसरी ओर, पीवीबी ने सूक्ष्म उद्यमों को अपने एएनबीसी या सीईओबीई का 7.5 प्रतिशत उधार देने के उप-लक्ष्य को प्राप्त करने में पीएसबी की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है। पीएसबी और पीवीबी दोनों ने कमजोर वर्गों को उधार देने के अपने लक्ष्य को पूरा किया है, जिसमें पीएसबी अपने निजी क्षेत्र के समकक्षों से आगे हैं (चार्ट 2)।

IV. साक्ष्य आधारित विश्लेषण

साक्ष्य आधारित विश्लेषण दो भागों में विभाजित है। सबसे पहले, बैंकों को अपने एएनबीसी/सीईओबीई का 40 प्रतिशत प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को आबंटित करने की आवश्यकता वाले सामान्य विनियामकीय अधिदेश के बावजूद, विभिन्न बैंकों के बीच महत्वपूर्ण भिन्नताएं मौजूद हैं। अध्ययन का यह भाग उन संभावित कारकों की जांच करता है जो बैंकों के पीएसएल की सीमा को प्रभावित कर सकते हैं। दूसरा, अध्ययन बैंकों की समग्र आस्ति गुणवत्ता पर पीएसएल के प्रभाव की जांच करता है।

IV.1 प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र ऋण के चालक

बैंकों द्वारा पीएसएल को प्रभावित करने वाले कारकों को निर्धारित करने के लिए एक अभ्यास निश्चित प्रभाव पैनल प्रतिगमन मॉडल का उपयोग करके किया जाता है। मार्च 2006 से मार्च 2023 की अवधि के लिए पीएसबी और पीवीबी के तिमाही डेटा का उपयोग किया जाता है। सभी डेटा रिज़र्व बैंक के पर्यवेक्षी विवरणी से प्राप्त किए जाते हैं। निम्नलिखित पैनल प्रतिगमन समीकरण का अनुमान लगाया गया है:

$$PSL\ share_{it} = \beta_1\ PSL\ share_{it-1} + \beta_2\ PSL\ GNPA\ ratio_{it-1} + \beta_3\ Branches\ to\ assets\ ratio_{it} + \beta_4\ \log(assets)_{it-1} + \beta_5\ PSLC\ dummy_t + \beta_6\ March\ dummy_t + \alpha_y + \vartheta_i + \varepsilon_{it} \quad (I)$$

जहां *PSL share*$_{it}$ समय t पर बैंक i के लिए सकल ऋणों और अग्रिमों[6] में प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के ऋणों का हिस्सा है, *PSL share*$_{it-1}$, *PSL share,* के एक अवधि के विलंबित मूल्य को संदर्भित करता है, *PSLGNPAratio*$_{it-1}$ प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के ऋणों के लिए विलंबित आस्ति गुणवत्ता सूचक है, *branches to asset ratio*$_{it}$ बैंक की पहुंच का एक प्रॉक्सी है, और *log(assets)*$_{it-1}$ बैंक के आकार का एक संकेतक है। *PSLCdummy* पीएसएलसी की शुरूआत के प्रभाव को पकड़ने के लिए जून 2016 से शुरू होने वाले सभी तिमाहियों के लिए मूल्य 1 लेता है। चूंकि पीएसएल की कमी की गणना हर वित्तीय वर्ष के अंत में डेटा पर आधारित होती है, इसलिए Mrchdummy$_{it}$ पेश किया जाता है, जो मार्च[7] को समाप्त होने वाली सभी तिमाहियों के लिए मूल्य 1 लेता है α_y वर्ष के निश्चित प्रभाव हैं, ϑ_i बैंक के निश्चित प्रभाव[8] हैं, और ε बैंक स्तर पर क्लस्टर की गई मानक त्रुटियाँ हैं और विषमता के लिए समायोजित की गई हैं। तीन वैकल्पिक विनिर्देशों का मूल्यांकन किया जाता है, जिसमें आश्रित चर कुल ऋण में संपूर्ण पीएसएल हिस्सा, कुल ऋण में कृषि के लिए पीएसएल और कुल ऋण में MSEs[9] के लिए पीएसएल हैं।

साक्ष्य आधारित आकलन के परिणाम बताते हैं कि प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र पोर्टफोलियो की आस्ति गुणवत्ता बैंकों के पीएसएल हिस्से को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालाँकि पीएसएल विनियामक आवश्यकताओं द्वारा अनिवार्य है, लेकिन बैंक इन ऋणों को विस्तारित करते समय सामान्य जोखिम-वापसी ट्रेड-ऑफ को ध्यान में रखते हैं।

बैंक शाखाओं-से-संपत्ति अनुपात द्वारा मापी गई व्यापक बैंक पहुंच, प्राथमिकता-प्राप्त वाले क्षेत्र को वितरित ऋणों के उच्च हिस्से के साथ सकारात्मक रूप से जुड़ी हुई है। अधिक भौतिक उपस्थिति वाले बैंक जमीनी स्तर पर प्राथमिकता-प्राप्त वाले ऋण देने के लिए बेहतर स्थिति में हैं। कृषि और एमएसई पीएसएल विनिर्देशों में, क्रमशः ग्रामीण शाखाओं-से-संपत्ति अनुपात और शहरी शाखाओं-से-संपत्ति अनुपात का उपयोग व्याख्यात्मक चर के रूप में किया गया है। परिणाम संकेत देते हैं कि शहरी क्षेत्रों में बड़े शाखा नेटवर्क वाले बैंक अपने ऋणों का बड़ा हिस्सा प्राथमिकता-प्राप्त वाले एमएसई को देते हैं। हालांकि, उच्च ग्रामीण उपस्थिति वाले बैंकों के लिए प्राथमिकता-प्राप्त वाले क्षेत्र के कृषि ऋणों के परिणाम महत्वपूर्ण नहीं हैं, संभवतः इन क्षेत्रों में आरआरबी, एसएफबी और ग्रामीण सहकारी बैंकों की उपस्थिति को दर्शाते हैं, जिनके पास कृषि वित्तपोषण में अधिक विशेषज्ञता है। बैंक के आकार का पीएसएल हिस्से पर महत्वपूर्ण और नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

सारणी 1: पीएसएल शेयर के निर्धारक

चर	पीएसएल शेयर	कृषि पीएसएल शेयर	एमएसई पीएसएल शेयर
	(1)	(2)	(3)
पीएसएल शेयर (एल1)	0.678*** (0.0435)		
कृषि पीएसएल शेयर (एल1)		0.810*** (0.0462)	
एमएसई पीएसएल शेयर (एल1)			0.628*** (0.0486)
पीएसएल जीएनपीए अनुपात (एल1)	-0.225*** (0.0609)		
कृषि पीएसएल जीएनपीए अनुपात (एल1)		-0.0971*** (0.0201)	
एमएसई पीएसएल जीएनपीए अनुपात (एल1)			-0.200*** (0.0386)
शाखाओं से आस्तियां	0.436* (0.251)		
ग्रामीण शाखाओं से आस्तियां		-0.0572 (0.253)	
शहरी शाखाओं से आस्तियां			1.340*** (0.458)
लॉग (आस्तियां) (एल1)	-1.453** (0.533)	-0.636*** (0.220)	-0.580* (0.292)
पीएसएलसी डमी	1.606** (0.658)	-0.139 (0.390)	1.603*** (0.425)
मार्च डमी	1.465*** (0.346)	0.471** (0.184)	1.149*** (0.164)
स्थिर	25.83*** (6.717)	9.049*** (2.436)	8.411** (3.324)
अवलोकन	2,162	2,162	2,161
समायोजित आर-स्क्वेयर्ड	0.626	0.762	0.698
बैंकों की संख्या	33	33	33
बैंक निश्चित प्रभाव	हाँ	हाँ	हाँ
वर्ष निश्चित प्रभाव	हाँ	हाँ	हाँ

टिप्पणी : 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े बैंक स्तर पर मजबूत मानक त्रुटियों को दर्शाते हैं।
2. ***, ** और * 1 प्रतिशत, 5 प्रतिशत और 10 प्रतिशत महत्व के स्तर को दर्शाते हैं।

स्रोत: लेखकों द्वारा गणना।

[6] आदर्श रूप से, अनुमान के लिए एएनबीसी/सीईओबीई में पीएसएल की हिस्सेदारी पर विचार किया जाना चाहिए। हालांकि, एएनबीसी/सीईओबीई डेटा की निरंतर उपलब्धता की कमी के कारण, इसके बजाय सकल ऋण और अग्रिम का उपयोग किया जाता है। यहां पीएसएल में बैंकों द्वारा लक्षित क्षेत्रों को सीधे वितरित किए गए ऋण के साथ-साथ अनुभाग III.2 में उल्लिखित लक्ष्य प्राप्ति के अन्य उपाय शामिल हैं।

[7] वार्षिक पीएसएल लक्ष्य प्राप्ति को चार तिमाहियों के औसत के रूप में मापा जाता है। बैंक अपने पीएसएल लक्ष्य को वार्षिक आधार पर प्राप्त कर सकते हैं, भले ही वे हर तिमाही में ऐसा न करें।

[8] निश्चित प्रभाव और यादृच्छिक प्रभाव के बीच उपयुक्त मॉडल विनिर्देश निर्धारित करने के लिए, हौसमैन परीक्षण आयोजित किया गया था, और परिणामों ने संकेत दिया कि निश्चित प्रभाव मॉडल अधिक उपयुक्त था।

[9] प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के ऋणों में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम शामिल हैं, और उप-लक्ष्य केवल सूक्ष्म उद्यमों को दिए जाने वाले ऋणों के लिए निर्धारित है। हालाँकि, इस विश्लेषण के लिए, डेटा सीमाओं के कारण केवल सूक्ष्म और लघु उद्यमों को दिए जाने वाले ऋणों को ही शामिल किया गया है।

पीएसएलसी की शुरुआत के बाद से बैंकों द्वारा दिए जाने वाले कुल ऋण में पीएसएल की हिस्सेदारी बढ़ गई है, जिससे कुछ बैंकों को विशिष्ट पीएसएल खंडों में अपनी जगह बनाने में मदद मिली है। डेटा से पता चलता है कि ऐसे बैंक अपने विशेष खंडों को विनियामक न्यूनतम से अधिक ऋण देते हैं और इन अतिरिक्त उपलब्धियों को पीएसएलसी में बदल देते हैं, जिसका वे प्रीमियम पर व्यापार करते हैं। पीएसएलसी डमी का सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण और सकारात्मक गुणांक दर्शाता है कि इसके शुरू होने से बैंकों को अपने समग्र और एमएसई पीएसएल शेयर में सुधार करने में मदद मिली है। मार्च तिमाही में पीएसएल शेयर के शिखर को भी मॉडल में शामिल किया गया है।

IV.2 पीएसएल की आस्ति गुणवत्ता

ऐतिहासिक रूप से, प्राथमिकता-प्राप्त वाले क्षेत्रों से प्राप्त ऋणों का एनपीए उनके गैर-प्राथमिकता-प्राप्त वाले क्षेत्रों के समकक्षों की तुलना में अधिक रहा है, जिनमें से अधिकांश पीएसबी के खातों में रहे हैं। हालांकि, 2015 में यह प्रवृत्ति उलट गई, आंशिक रूप से आस्ति गुणवत्ता समीक्षा के बाद एनपीए की बेहतर पहचान के कारण (जॉन और अन्य, 2016)[10] [चार्ट 3]।

आँकड़े आधारित साक्ष्य बताते हैं कि बैंकों के जीएनपीए बैंक विशिष्ट और समष्टि-वित्त (चव्हाण और गंबाकोर्टा, 2016) पर निर्भर करते हैं। इसके अलावा , हमारे अनुमान का फोकस यह जांचना है कि बैंकों के पीएसएल का उनकी समग्र आस्ति गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ता है या नहीं। इसके लिए, पिछले उपखंड में इस्तेमाल किए गए समान डेटासेट पर पैनल रिग्रेशन मॉडल का उपयोग करके एक अभ्यास किया गया था।

$$GNPA\ Ratio_{it} = \beta_1\ PriorityLoanGrowth_{it-1} + \beta_2 AQR_t + \beta_3 X_{it-1} + \alpha_y + \vartheta_i + \varepsilon_{it} \qquad (II)$$

जहाँ आश्रित चर समय t पर बैंक i का जीएनपीए अनुपात है। $PriorityLoanGrowth_{it-1}$ एक अवधि है जो बैंक के पीएसएल में वर्ष-दर-वर्ष पिछड़ी हुई वृद्धि है। AQR_t संपत्ति गुणवत्ता समीक्षा के लिए एक डमी चर है जो सितंबर 2015 और मार्च 2018 के बीच की तिमाहियों के लिए 1 और अन्यथा 0 लेता है। X_{it-1} बैंक-स्तरीय नियंत्रण हैं, जिसमें बैंक समूह के लिए डमी, आस्तियों पर विलंबित विवरणी और बैंक आकार का पिछड़ा हुआ लॉग (ऋण और जमा का योग) शामिल है। α_y वर्ष के निश्चित-प्रभाव हैं, ϑ_i बैंक के निश्चित प्रभाव हैं[11], और ε_{it} बैंक स्तर पर क्लस्टर की गई मानक त्रुटियाँ हैं और विषमता के लिए समायोजित की गई हैं।

चार्ट 3 : आस्ति गुणवत्ता: प्राथमिकता क्षेत्र ऋण बनाम गैर-प्राथमिकता क्षेत्र ऋण

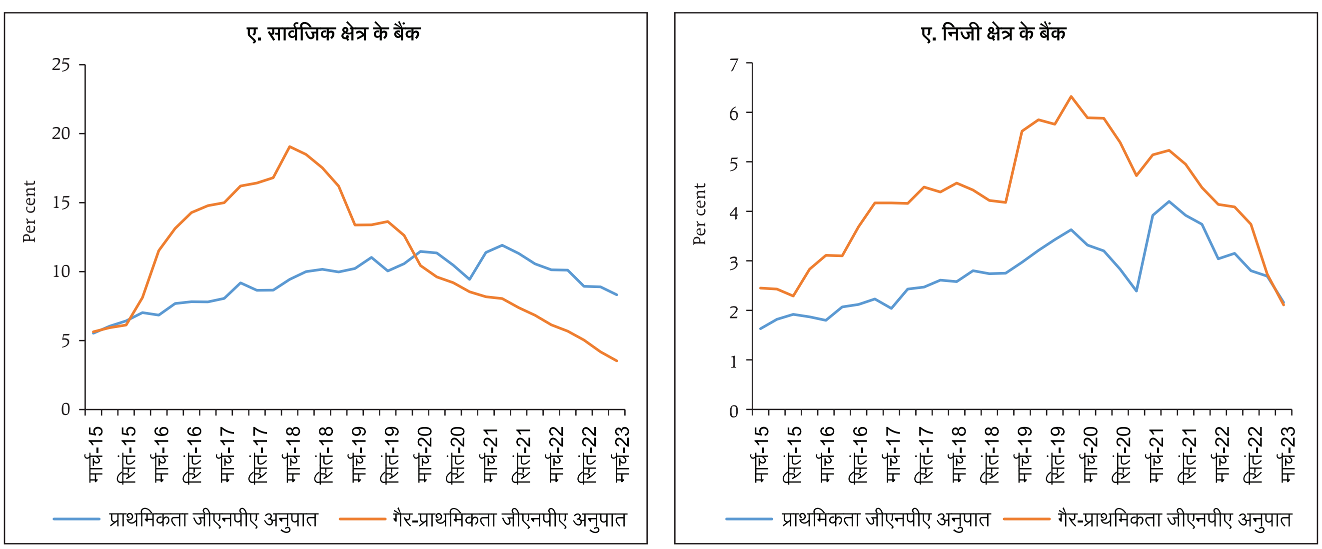

स्रोत: ऑफ-साइट रर्टिन (घरेलू परिचालन), आरबीआई।

[10] जुलाई 2015 में आस्ति गुणवत्ता समीक्षा (एक्यूआर) का उद्देश्य बैंकों की बैलेंस शीट को साफ करना तथा उनकी पारदर्शिता में सुधार लाना था, साथ ही उनके एनपीए प्रावधानों को बढ़ाना था।

[11] निश्चित प्रभाव और यादृच्छिक प्रभाव के बीच उपयुक्त मॉडल विनिर्देश निर्धारित करने के लिए, हौसमैन परीक्षण आयोजित किया गया था, और परिणामों ने संकेत दिया कि निश्चित प्रभाव मॉडल अधिक उपयुक्त था।

सारणी 2: बैंक की परिसंपत्ति गुणवत्ता पर पीएसएल वृद्धि का प्रभाव

चर	आश्रित चर : जीएनपीए अनुपात			
	(1)	(2)	(3)	(4)
प्राथमिकता अग्रिम वृद्धि (L1)	-0.0254*** (0.00457)	-0.0483*** (0.00841)	-0.0210*** (0.00382)	-0.0226*** (0.00455)
एक्यूआर डमी	0.757*** (0.185)	0.539*** (0.153)	0.742*** (0.180)	9.751*** (1.667)
संपत्तियों पर प्रतिफल (L1)	-3.188*** (0.327)		-3.187*** (0.308)	-3.238*** (0.319)
लॉग (आकार) (L1)	-1.860*** (0.383)		-3.338*** (0.684)	-3.401*** (0.711)
बैंक समूह डमी	5.200*** (1.264)			
स्थिर	24.82*** (3.864)	4.205*** (0.597)	42.68*** (7.253)	
अवलोकन	2,030	2,030	2,030	
बैंक निश्चित प्रभाव	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ
वर्ष निश्चित प्रभाव	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं
समय निश्चित प्रभाव	नहीं	नहीं	नहीं	हाँ
समायोजित R-स्क्वायर	0.534#	0.465	0.713	0.716
बैंकों की संख्या	33	33	33	33

टिप्पणियाँ:: 1. कोष्ठक में दिये गए आंकड़े बैंक स्तर पर बड़े मानक त्रुटियों को दर्शाते हैं।

2. ***, ** और * क्रमशः 1 प्रतिशत, 5 प्रतिशत और 10 प्रतिशत महत्व के स्तर को दर्शाते हैं।

3. #: समग्र आर-स्क्वायर की रिपोर्ट की गई है।

स्रोत : लेखकों द्वारा गणना।

जैसा कि अपेक्षित था, प्रतिगमन से प्राप्त प्राथमिक परिणाम दर्शाते हैं कि एक्यूआर अवधि के दौरान जीएनपीए अनुपात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। परिणाम यह भी दर्शाते हैं कि प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र में अग्रिमों में उच्च वृद्धि ने बैंकों के जीएनपीए अनुपात को कम कर दिया है।

सारणी 2 के कॉलम (1) में, यह पाया गया है कि बैंक समूह डमी का गुणांक, जो पीएसबी के लिए 1 और पीवीबी के लिए 0 का मान लेता है, सकारात्मक और महत्वपूर्ण है क्योंकि अध्ययन अवधि के दौरान पीवीबी की तुलना में पीएसबी का जीएनपीए अनुपात अधिक था। कॉलम (2) में, बैंक के निश्चित प्रभाव जोड़े गए हैं और उनके समावेश के परिणाम मजबूत बने हुए हैं। कॉलम (3) में, अन्य बैंक-स्तरीय नियंत्रण जोड़े गए हैं और यह पाया गया है कि बैंकों की उच्च लाभप्रदता और बड़े आकार के साथ आस्ति की गुणवत्ता में सुधार होता है। इसके अलावा, कॉलम (4) में, सभी बहिर्जात समय-भिन्न कारकों के लिए नियंत्रण में समय-निश्चित प्रभाव जोड़ने के बाद भी, परिणाम मजबूत बने हुए हैं।

V. निष्कर्ष

पीएसएल जैसी ऋण योजनाएं जरूरतमंद क्षेत्रों को औपचारिक ऋण उपलब्धता बढ़ाने के लिए शुरू किए गए हैं। निर्देशित ऋण पर देशांतर साहित्य बैंकों के स्वास्थ्य पर इसके प्रभाव के बारे में अनिर्णय में हैं। एक दृष्टिकोण से, इस तरह के ऋण तभी सफल हो सकते हैं जब उचित संस्थागत तंत्र, सख्त प्रदर्शन मानकों और नीतिगत ढांचे द्वारा पूरक हों। विरोधी दृष्टिकोण के अनुसार, ये ऋण, विनियामकीय बाध्यताओं के कारण, बैंकों के व्यावसायिक हितों के अनुरूप नहीं हो सकते हैं और संभावित रूप से उनकी समग्र आस्ति गुणवत्ता को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिससे उनकी वाणिज्यिक व्यवहार्यता पर सवाल उठ सकते हैं। यह आलेख इन तर्कों का साक्ष्य आधारित मूल्यांकन करता है।

मार्च 2006 से मार्च 2023 तक बैंक-स्तरीय पीएसएल डेटा का उपयोग करते हुए, अध्ययन में पाया गया है कि बैंकों के कुल ऋण पोर्टफोलियो में प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के ऋणों की हिस्सेदारी, अन्य बातों के साथ-साथ, ऐसे ऋणों की आस्ति गुणवत्ता पर निर्भर करती है। इसके अलावा, पीएसएलसी की शुरूआत ने बैंकों को कुछ प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों में एक जगह बनाने में मदद करने और परिणामस्वरूप, इन क्षेत्रों में ऋण देने में वृद्धि करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साक्ष्य आधारित विश्लेषण यह भी बताता है कि पीएसएल में उच्च वृद्धि बैंकों की आस्ति गुणवत्ता में गिरावट से जुड़ी नहीं है।

संदर्भ

Banerjee, A., and Duflo, E. (2000). Efficiency of Lending Operations and the Impact of Priority Sector Regulations. *MIMEO, MIT.*

Banerjee, A., and Duflo, E. (2014). Do Firms Want to Borrow More? Testing Credit Constraints using a Directed Lending Program. *The Review of Economic Studies*, 81(2), 572–607. doi: 10.1093/restud/rdt046

Bhue, G., Prabhala, N., and Tantri, P. (2019). Can Small Business Lending Programs Disincentivize Growth? Evidence from India's Priority Sector Lending Program. *Indian School of Business.*

Calomiris, C. W., and Himmelberg, C. P. (1993). Directed Credit Programs for Agriculture and Industry: Arguments from Theory and Fact. *The World Bank Economic Review*, 7(1), 113-138. https://doi.org/10.1093/wber/7.suppl_1.113

Chakrabarty, K. C. (2012). *Revised Guidelines on Priority Sector Lending: Rationale and Logic.* Retrieved from https://www.bis.org/review/r120906b.pdf

Chakrabarti, D., Sethi, P., and Bhattacharjee, S. (2019). Directed Credit, Financial Development and Financial Structure: Theory and Evidence. *Applied Economics*, 51(16), 1711-1729. https://doi.org/10.1080/00036846.2018.1528338

Chavan, P., and Gambacorta, L. (2016). Bank Lending and Loan Quality: The Case of India. *BIS Working Papers*, 595. https://www.bis.org/publ/work595.pdf

Cho, Y. J., and Hellman, T. (1993). The Government's Role in Japanese and Korean Credit Markets: A New Institutional Economics Perspective. *The World Bank, Policy Research Working Papers Series*, 1190. https://ideas.repec.org/p/wbk/wbrwps/1190.html

Federal Reserve Bank of San Francisco. (2014). *Priority Sector Lending in Asia.* Retrieved from https://www.frbsf.org/banking/wp-content/uploads/sites/5/Asia-Focus-Priority-Sector-Lending-in-Asia-September-2014.pdf

Gaur, D., and Mohapatra, D. R. (2020). The Nexus of Economic Growth, Priority Sector Lending and Non-Performing Assets: Case of Indian Banking Sector. *South Asian Journal of Business Studies.* https://www.emerald.com/insight/2398-628X.htm

Horiuchi, A., and Sui, Q.-Y. (1993). The Influence of the Japan Development Bank Loans on Corporate Investment Behaviour. *Journal of the Japanese and International Economies*, 7(4), 441-465. doi:10.1006/jjie.1993.1025

ILO. (2019). Financing Small Businesses in Indonesia: Challenges and Opportunities. International Labour Organization.

John, J., Mitra, A.K., Raj, J., and Rath, D.P. (2016). Asset Quality and Monetary Transmission in India. *Reserve Bank of India Occasional Papers*, 37(1and2). Available at https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/Publications/PDFs/RBIOP37020520185C7D2C48AFA9427993B773BD194D95A2.PDF

Kohli, R. (1997). Directed Credit and Financial Reform. *Economic and Political Weekly*, 32(42), 2667-2676. http://www.jstor.com/stable/4405977

Lelarge, C., Sraer, D., and Thesmar, D. (2010). Entrepreneurship and Credit Constraints: Evidence from a French Loan Guarantee Program. *International Differences in Entrepreneurship*, 243 - 273. https://ideas.repec.org/s/nbr/nberch.html

Mundra, S. S. (2017). *Priority Sector Lending – Status, Issues and Future Agenda.* Retrieved from https://www.bis.org/review/r170724f.pdf

Narayana, D. (1992). Institutional Credit for Rural Development: Proper Risk-Management of Group Lending? *Economic and Political Weekly*, 27(39), A122-A127. https://www.jstor.org/stable/4398941

RBI. (2007). *Master Circular- Lending to Priority Sector.* Available at https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/notification/PDFs/78389.pdf

Schwarz, A. M. (1992). How Effective are Directed Credit Policies in the US? *The World Bank, Policy*

Research Working Paper Series, 1019. https://ideas.repec.org/p/wbk/wbrwps/1019.html

Vogel, R. C. (1984). The Effect of Subsidised Agricultural Credit on Income Distribution in Costa Rica. In D. W. Adams, D. H. Graham, and J. D. Pishke (Eds.), *Undermining Rural Development with Cheap Credit.* New York: Routledge.

Werner, R. A. (2002). A Reconsideration of the Rationale for Bank Centered Economic Systems and the Effectiveness of Directed Credit Policies in the Light of Japanese Evidence. *Japanese Economy*, 30(3), 3-45. https://doi.org/10.2753/JES1097-203X30033

World Bank. (1993). *The East Asian Miracle.* Available at https://documents1.worldbank.org/curated/en/975081468244550798/pdf/multi-page.pdf

Yunus, M. (1987). The Poor as the Engine of Development. *The Washington Quarterly*, 10(4), 139–145. https://doi.org/10.1080/01636608709477624

गहन विश्लेषण: हाल के समय में एनबीएफसी क्षेत्र की समीक्षा

*अभ्युदय हर्ष, रजनीश कुमार चंद्रा, नंदिनी जयकुमार और ब्रिजेश पी. द्वारा^*

वैश्विक स्तर पर, गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान (एनबीएफआई) पिछले कुछ वर्षों में आकार और जटिलता में बढ़े हैं, जिससे वे वित्तीय प्रणाली में अन्य संस्थाओं के साथ जुड़ गए हैं। भारत में भी, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (एनबीएफसी) वित्तीय प्रणाली का एक अभिन्न अंग बन गई हैं, जो एनबीएफसी के ऋण से जीडीपी अनुपात में क्रमिक वृद्धि में परिलक्षित होती है। इस क्षेत्र में तेजी से हो रहे विकास के साथ-साथ बढ़ती अंतर्संबंधता और एनबीएफसी के बदलते जोखिम प्रोफाइल को देखते हुए, रिज़र्व बैंक ने अक्तूबर 2022 में स्केल-आधारित विनियमन (एसबीआर) की शुरुआत की। इस बदलाव के बीच, एनबीएफसी क्षेत्र सुदृढ़ बना हुआ है, जिसमें ऋण, पर्याप्त पूंजी और कम चूक अनुपात में लगातार दोहरे अंकों की वृद्धि हो रही है।

परिचय

गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान[1] (एनबीएफआई) वैश्विक वित्तीय प्रणाली में महत्वपूर्ण मध्यस्थ हैं, जो वर्तमान में वैश्विक वित्तीय आस्तियों का लगभग आधा हिस्सा हैं। एनबीएफआई क्षेत्र की विशेषताएं विभिन्न क्षेत्राधिकारों में भिन्न होती हैं। तेजी से विविध और जटिल गतिविधियों के साथ, एनबीएफआई वित्तीय और वास्तविक अर्थव्यवस्था (एफएसबी, 2023ए) के अन्य क्षेत्रों के साथ गहराई से जुड़ रहे हैं। इसलिए, यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण हो जाता है कि पर्यवेक्षित संस्थाओं पर लागू विभिन्न नीतियां एक प्रणाली-व्यापी परिप्रेक्ष्य से एक साथ फिट हों।

किसी भी विविध वित्तीय प्रणाली की महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक अलग-अलग जोखिम प्रोफाइल वाले विभिन्न प्रकार के वित्तीय संस्थानों की उपस्थिति है, जो विभेदित नियामकीय समाधान के लिए आवश्यक होती है। इस उद्देश्य के लिए, अक्टूबर 2022 में भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों[2] (एनबीएफसी) के लिए स्केल -आधारित विनियमन (एसबीआर) लागू किया गया, जो एनबीएफसी के आकार, गतिविधि और कथित जोखिम के आधार पर विभेदक नियामक आवश्यकताओं को निर्धारित करता है। यह प्रणालीगत जोखिम प्रबंधन के व्यापक लक्ष्य का त्याग किए बिना, गतिविधि-आधारित और इकाई-आधारित विनियमन की सर्वोत्तम विशेषताओं को जोड़ता है। भारत में, एनबीएफसी वित्तीय प्रणाली के एक अभिन्न अंग बन गए हैं, जो एनबीएफसी के ऋण से जीडीपी अनुपात और एनबीएफसी के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) के ऋण जैसे मेट्रिक्स में क्रमिक वृद्धि से परिलक्षित होता है।

यह लेख हाल के समय में एनबीएफसी क्षेत्र के प्रदर्शन का विश्लेषण करता है। लेख का शेष भाग निम्नलिखित खंडों में विभाजित है। खंड II एनबीएफसी क्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य का अवलोकन प्रदान करता है, जिसमें भारत पर विशेष ध्यान दिया गया है। खंड III भारत में एनबीएफसी क्षेत्र के विनियामकीय विकास का विवरण प्रस्तुत करता है, जिसमें बैंकों और एनबीएफसी तथा एनबीएफसी के बीच विद्यमान विनियामकीय विभेदों पर प्रकाश डाला गया है। खंड IV तुलन पत्र की गतिशीलता, साथ ही एनबीएफसी के ऋण के क्षेत्रीय वितरण, लाभप्रदता और आस्ति गुणवत्ता का विश्लेषण करता है। लेख का अंतिम खंड उभरती चुनौतियों पर कुछ टिप्पणियों के साथ समाप्त होता है।

II. भारत में एनबीएफआई: एक वैश्विक परिप्रेक्ष्य

एनबीएफआई वैश्विक वित्तीय प्रणाली में ऐसी सेवाएँ प्रदान करके महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जो ज़रूरी नहीं कि बैंक ही प्रदान करें। वे ऋण तक पहुँच बढ़ाने और आर्थिक विकास को समर्थन देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। समय के साथ, एनबीएफआई

^ लेखक आर्थिक एवं नीति अनुसंधान विभाग से हैं। यह आलेख श्री गोपीनाथ प्रहलाद चार तुलसी, परामर्शदाता के मार्गदर्शन में तैयार किया गया है। इस आलेख में व्यक्त विचार लेखकों के हैं और भारतीय रिज़र्व बैंक के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।

[1] वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी) एनबीएफआई क्षेत्र को सभी गैर-बैंक वित्तीय संस्थाओं के एक व्यापक माप के रूप में परिभाषित करता है, जिसमें वे सभी वित्तीय संस्थान शामिल हैं जो केंद्रीय बैंक, बैंक या सार्वजनिक वित्तीय संस्थान नहीं हैं।

[2] भारत में एनबीएफसी व्यापक एनबीएफआई क्षेत्र का एक उपसमूह हैं और इस आलेख में एनबीएफसी से तात्पर्य आरबीआई द्वारा विनियमित गैर-बैंकों से है, जैसा कि आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए के तहत परिभाषित किया गया है।

का आकार और जटिलता बढ़ी है, जिसने उन्हें वित्तीय प्रणाली में अन्य संस्थाओं के साथ जोड़ दिया है। निहितार्थ से, एनबीएफआई क्षेत्र में दबाव वित्तीय प्रणाली के अन्य प्रतिभागियों को अधिक तेज़ी से और व्यापक रूप से प्रभावित कर सकता है। इस हद तक वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी) ने एनबीएफआई के लिए नवाचारों को ट्रैक करने और प्रणालीगत और उभरते जोखिमों की पहचान करने के लिए एक वार्षिक प्रणाली-व्यापी निगरानी ढांचा बनाया (एफएसबी, 2023बी)।

वैश्विक वित्तीय संकट (जीएफसी) के बाद से, एनबीएफआई का आकार बढ़ गया है और अब वे वैश्विक वित्तीय प्रणाली (चार्ट 1 ए) का सबसे बड़ा घटक बन गए हैं। संस्थानों का यह पारिस्थितिकी तंत्र बहुत ही विविध है और व्यापार मॉडल तथा क्षेत्राधिकार के आधार पर अलग-अलग है। जीएफसी के बाद, पहली बार, 2022 में वैश्विक स्तर पर एनबीएफआई आस्तियों में 5 प्रतिशत से अधिक की कमी आई है। यह मुख्य रूप से उच्च ब्याज दरों और कठोर चलनिधि तथा वित्तीय स्थितियों के प्रभाव के कारण था, जिसे मुद्रास्फीति के दबाव के कारण 2022 में अधिकांश अर्थव्यवस्थाओं ने अनुभव किया (एफएसबी, 2023 बी)।

भारत में, वित्तीय प्रणाली बैंक-प्रधान बनी हुई है। एनबीएफआई क्षेत्र की आस्तियों के आकार के मामले में बैंकिंग क्षेत्र से पीछे है, हालांकि, समय के साथ उनके बीच का अंतर कम हो रहा है (चार्ट 1बी और सारणी 1)। उनका प्रणालीगत महत्व बढ़ रहा है, जैसा कि जीडीपी के हिस्से के रूप में एनबीएफआई के आकार में संकेत दिया गया है। 2022 में, भारत में एनबीएफआई ने वैश्विक स्तर पर संकुचन के विपरीत लगभग 12 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि दर्ज की (चार्ट 2)। घरेलू एनबीएफसी क्षेत्र के निवेश कोष में संकुचन की भरपाई उधार देने वाली कंपनियों के आकार में विस्तार से अधिक हुई, जो नैरो मेजर में कुल एनबीएफआई आस्तियों का 79 प्रतिशत हिस्सा है (सारणी 2)।

सारणी 1: भारतीय वित्तीय प्रणाली में प्रमुख प्रतिभागी

(मार्च 2023 के अंत में)

	कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में
1. अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक*	53.7
2. सहकारी बैंक#	4.7
3. एनबीएफआई	41.6
*3.1. एनबीएफसी^*	*15.2*
*3.2. एआईएफआई^^*	*3.2*
3.3. बीमा कम्पनियां	*12.8*
3.4. पेंशन निधि	*1.9*
3.5. म्यूचुअल फंड	*8.4*
कुल	**100.0**

नोट: * आरआरबी सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को संदर्भित करता है।

शहरी और ग्रामीण ऋण सहकारी समितियाँ शामिल हैं। उत्तरार्द्ध के लिए डेटा मार्च 2022 के अंत से संबंधित हैं।

^ इसमें आरबीआई के साथ पंजीकृत सभी एनबीएफसी और एआरसी शामिल हैं; और एनएचबी के साथ पंजीकृत सभी एचएफसी शामिल हैं।

^^ पांच अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों को संदर्भित करता है, अर्थात् नाबार्ड, एक्जिम बैंक, सिडबी, एनएचबी और एनएबीएफआईडी।

स्रोत: आरबीआई, आईआरडीएआई और पीएफआरडीए।

चार्ट 1: कुल वित्तीय आस्तियां

(दिसंबर के अंत में)

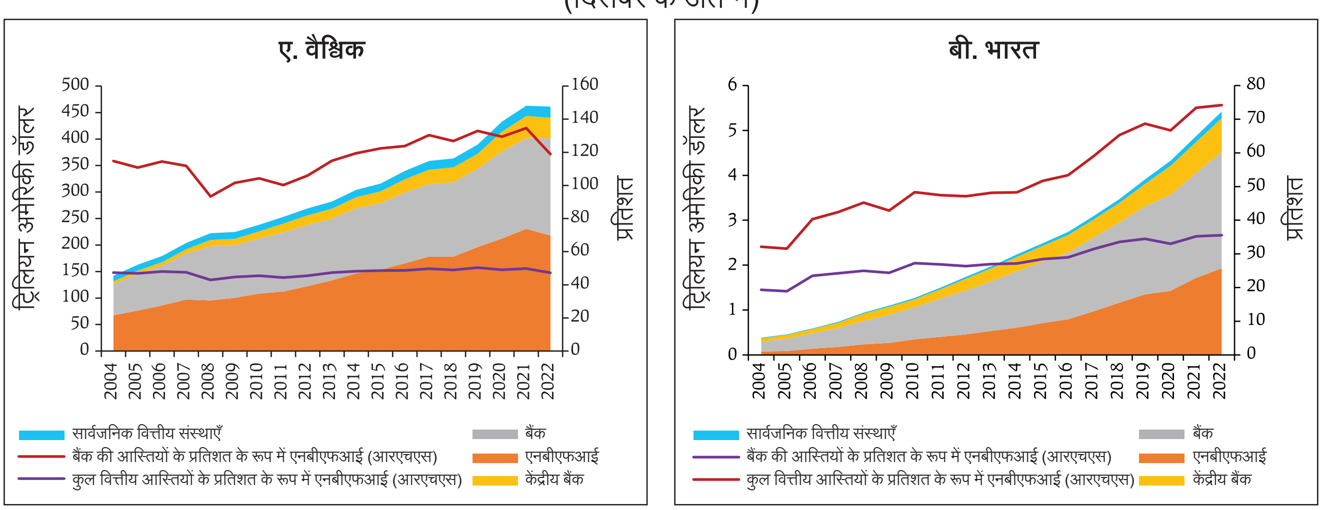

नोट: वैश्विक में भारत भी शामिल है।

स्रोत: गैर-बैंक वित्तीय मध्यस्थता पर वैश्विक निगरानी रिपोर्ट, 2023.

चार्ट 2: भारत में एनबीएफआई के घटक और विकास
(दिसंबर के अंत में)

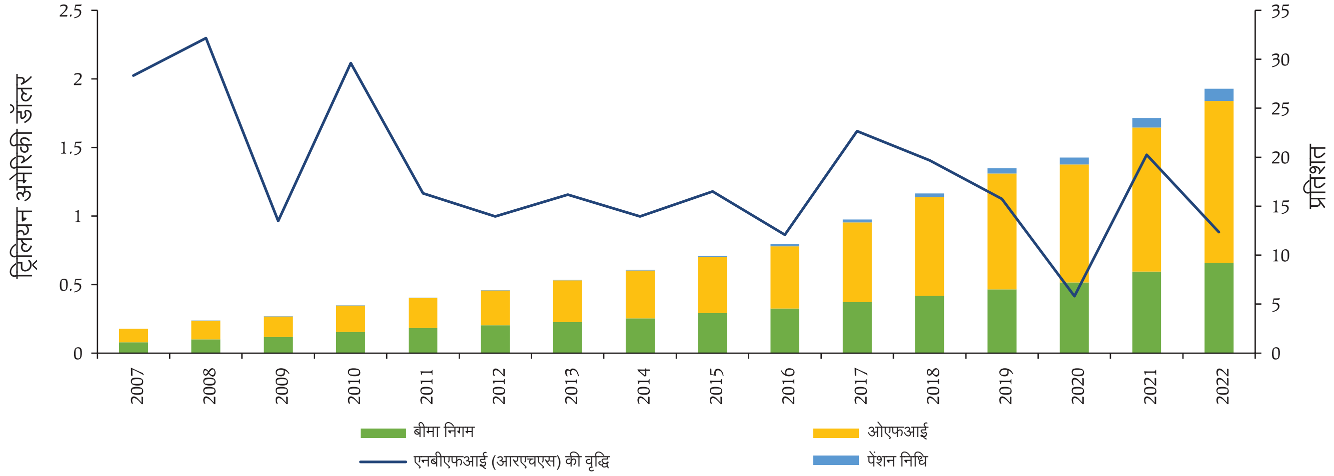

नोट: अन्य वित्तीय मध्यस्थ (ओपीआई) एनबीएफआई क्षेत्र के एक उप समूह को संदर्भित करते हैं, जिसमें वे सभी वित्तीय संस्थान शामिल होते हैं जो केंद्रीय बैंक, बैंक, सार्वजनिक वित्तीय संस्थान, बीमा निगम, पेंशन निधि संस्था या वित्तीय सहायक संस्था नहीं हैं।
स्रोत: गैर-बैंक वित्तीय मध्यस्थता पर वैश्विक निगरानी रिपोर्ट, 2023.

एनबीएफआई द्वारा अपने अंतर्संबंधों के कारण उत्पन्न बैंक जैसी वित्तीय स्थिरता जोखिमों की सीमा का आकलन करने के लिए, एफएसबी ने एक 'नैरो मेजर' तैयार किया, जो एनबीएफआई गतिविधियों के एक उपसमूह पर केंद्रित है। यह मेजर एनबीएफआई को पांच आर्थिक कार्यों (ईएफ) या गतिविधियों में विभाजित करता है (सारणी 2)। दिसंबर 2022 के अंत में, वैश्विक नैरो मेजर आस्तियों में उनके हिस्से के अनुसार सबसे बड़े क्षेत्राधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका (30.4 प्रतिशत), आठ प्रतिभागी यूरो क्षेत्र क्षेत्राधिकार (21.5 प्रतिशत), चीन (16.3 प्रतिशत) और केमैन द्वीप (12.8 प्रतिशत) थे। वैश्विक नैरो मेजर में 2022 में गिरावट आई, जो लगभग पूरी तरह से ईएफ1 में गिरावट के कारण हुई, जबकि अन्य चार ईएफ में वृद्धि जारी रही। भारत में, नैरो मेजर में 7.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो लगभग पूरी तरह से ईएफ2 के कारण हुई, जबकि ईएफ1 में गिरावट दर्ज की गई।

सारणी 2: इकाई के प्रकार और गतिविधियों के अनुसार नैरो मेजर संरचना
(दिसंबर 2022 के अंत में)

आर्थिक कार्य / गतिविधि	निकाय प्रकार	नैरो मेजर में आर्थिक कार्यवार हिस्सेदारी (प्रतिशत में)			
		एई	ईएमई	वैश्विक	भारत
ईएफ1	मनी मार्केट फंड, फिक्स्ड इनकम फंड, मिक्स्ड फंड, क्रेडिट हेज फंड, रियल एस्टेट फंड	72.6	81.0	74.3	20.1
ईएफ2	वित्त कंपनियां, लीजिंग/फैक्टरिंग कंपनियां, उपभोक्ता ऋण कंपनियां	7.7	9.0	7.9	79.0
ईएफ3	ब्रोकर-डीलर, कस्टोडियल खाते, प्रतिभूति वित्त कंपनियां	7.3	6.5	7.1	0.4
ईएफ4	क्रेडिट बीमा कंपनियां, वित्तीय गारंटर, मोनोलाइन बीमाकर्ता	0.3	0.1	0.2	0.0
ईएफ5	प्रतिभूतिकरण साधन, संरचित वित्त साधन, आस्ति समर्थित प्रतिभूतियाँ	9.1	3.1	7.8	0.4
गैर-आवंटित	अन्य वित्तीय सहायक जिन्हें एनबीएफआई से बैंक जैसी वित्तीय स्थिरता जोखिमों में शामिल माना जाता है, लेकिन जिन्हें किसी विशिष्ट आर्थिक कार्य प्रदान नहीं किए जा सकते हैं।	3.2	0.3	2.6	-
कुल		100.0	100.0	100.0	100.0
कुल एनबीएफआई क्षेत्र के हिस्से के रूप में नैरो मेजर		26.1	49.2	28.9	42.2

टिप्पणियाँ: 1. 29 अलग-अलग अधिकार क्षेत्रों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर, जो वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में 85 प्रतिशत का योगदान करते हैं और जिनके लिए अधिक विस्तृत डेटा उपलब्ध था।
2. सूचीबद्ध संस्थाएँ संपूर्ण नहीं हैं, लेकिन विशिष्ट उदाहरण दर्शाती हैं।
स्रोत: गैर-बैंक वित्तीय मध्यस्थता पर वैश्विक निगरानी रिपोर्ट, 2023।

वैश्विक स्तर पर, अधिकांश उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (एई) के साथ-साथ उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) में, ईएफ1 सबसे बड़ा घटक है। दूसरी ओर, भारत और इंडोनेशिया जैसे देशों में, ईएफ2, जिसमें अल्पकालिक वित्तपोषण पर निर्भर ऋण देने वाली संस्थाएँ शामिल हैं, सबसे बड़ा घटक है। ईएफ2 में वित्त कंपनियों का वर्चस्व है, जो उपभोक्ता वित्त, ऑटो वित्त, खुदरा बंधक प्रावधान, वाणिज्यिक संपत्ति वित्त और उपकरण वित्त जैसे क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखती हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम के बाद भारत में वैश्विक स्तर पर तीसरी सबसे बड़ी ईएफ2 आस्ति थी।

ईएफ2 में संस्थाएं विशेष ध्यान देने योग्य हैं क्योंकि वे परिपक्वता परिवर्तन में शामिल हैं और बैंकिंग क्षेत्र के साथ उनका अधिक अंतर्संबंध हो सकता है। बैंकों की तरह, ऋण मध्यस्थता के साथ, इनमें से कुछ संस्थाएं सार्वजनिक जमा और/या खुदरा वित्त पोषण के अन्य रूपों को भी स्वीकार कर सकती हैं, जो दबाव की अवधि के दौरान प्रणालीगत जोखिम को बढ़ा सकती हैं। इन चिंताओं को दूर करने के लिए, जमाराशि स्वीकार करने वाली एनबीएफआई के संचालन वाले क्षेत्राधिकारों में नियामक, आमतौर पर एनबीएफआई को चालू खाते/मांग जमा की पेशकश करने से प्रतिबंधित करके इन संस्थाओं को बैंकों से अलग करते हैं। इसके अलावा, ये संस्थाएं सामान्य रूप से अन्य एनबीएफआई उधारदाताओं की तुलना में अधिक कठोर अपेक्षाओं के अधीन रखे जाते हैं (एहरेनट्राड, म्यूर, नोबल, और ज़मिल, 2024)। भारत में जमाराशि स्वीकार करने वाली एनबीएफआई के पास जमा बीमा कवरेज नहीं है क्योंकि जमा बीमा के अंतर्गत केवल बैंकों की जमाराशि ही आती है। लगभग सभी क्षेत्राधिकारों में इन संस्थाओं को मांग जमाराशि स्वीकार करने की अनुमति नहीं दी जाती है (चार्ट 3)। इस प्रकार, बैंक विनियमन के विपरीत, जिसके लिए वैश्विक विवेकपूर्ण मानक हैं, एनबीएफआई विनियमन के लिए ऐसा कोई ढांचा मौजूद नहीं है।

III. भारत में एनबीएफसी क्षेत्र का विनियामकीय विकास

1964 से, एनबीएफसी को आरबीआई अधिनियम, 1934 (आरबीआई, 2021बी) के अध्याय III बी के प्रावधानों के तहत रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित किया जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में इस क्षेत्र के विकास के क्रम में, रिज़र्व बैंक ने समय-समय पर एनबीएफसी पर लागू विनियमों को अद्यतन किया है, जो नियम-आधारित से सिद्धांत-आधारित विनियामकीय दृष्टिकोण में परिवर्तित हो रहा है। 1998 में, एनबीएफसी को सार्वजनिक जमाराशि स्वीकार करने के आधार पर वर्गीकृत किया गया था, इसके बाद 2006 में ₹100 करोड़ और उससे अधिक की आस्ति आकार वाली प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली एनबीएफसी (एनबीएफसी-एनडी-एसआई) की शुरुआत की गई। 2014 में, एनबीएफसी के लिए विनियामकीय

चार्ट 3: जमाराशि स्वीकार करने वाली एनबीएफआई की विशेषताएं

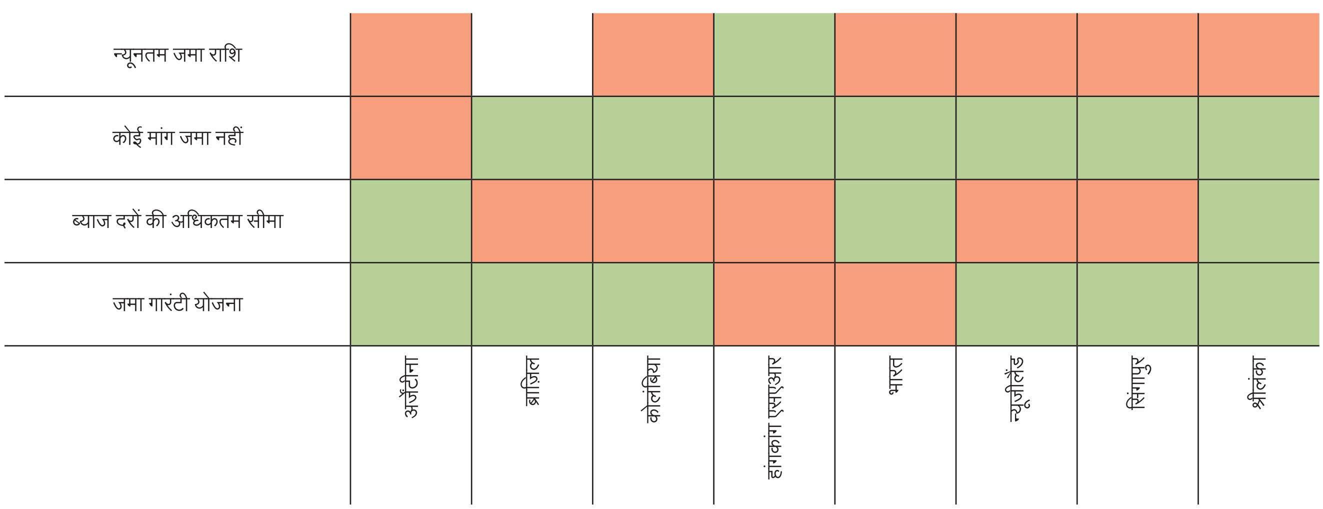

नोट: हरा लागू; लाल = लागू नहीं; और रिक्त = उपलब्ध नहीं।
स्रोत: एहरेनट्राड, म्यूर, नोबल, और ज़मिल, 2024; श्रीलंका केंद्रीय बैंक।

ढांचे की समीक्षा की गई और इस क्षेत्र को गतिविधि आधारित विनियमन में परिवर्तित कर दिया गया। विशेषज्ञ समितियों[3] की सिफारिशों से संकेत लेते हुए नए नियम बनाए गए, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण की सीमा को ₹100 से बढ़ाकर ₹500 करोड़ कर दिया गया, आस्ति वित्त कंपनियों के लिए मौजूदा जमा को नवीनीकृत करने या नए सार्वजनिक जमाराशि स्वीकार करने के लिए निवेश ग्रेड रेटिंग अनिवार्य कर दी गई और रेटेड एनबीएफसी के लिए पूरे क्षेत्र में सार्वजनिक जमा स्वीकार करने की सीमा को सुसंगत बनाया गया। इसके अलावा, एनबीएफसी-एनडी-एसआई और एनबीएफसी-डी (जमाराशि स्वीकार करने वाले) के लिए, न्यूनतम टियर-1 पूंजी आवश्यकता को 7.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया और साथ ही एनबीएफसी-डी और एनडीएसआई के आस्ति वर्गीकरण मानदंडों को बैंकों के अनुरूप बनाया गया (आरबीआई, 2014)।

सबसे हालिया बदलाव स्केल-आधारित विनियमन (एसबीआर) के रूप में हुआ, जो 1 अक्तूबर, 2022 से प्रभावी हुआ। इस क्षेत्र में तेजी से हो रहे विकास के साथ-साथ बढ़ते अंतर्संबंध और एनबीएफसी के बदलते जोखिम प्रोफाइल के कारण यह जरूरी हो गया था। इस नए नियामकीय ढांचे के तहत, एनबीएफसी को आकार, गतिविधि या कथित जोखिम के आधार पर चार लेयरों (टॉप, अपर, मिडिल और बेस) में से किसी में रखा जाता है। वर्तमान में, टॉप लेयर को खाली रखा गया है, और यदि आवश्यकता हुई तो रिज़र्व बैंक सघन जांच के लिए एनबीएफसी को अपर लेयर से टॉप लेयर में स्थानांतरित कर सकता है। एसबीआर विनियमन के लिए एक संकर दृष्टिकोण को शामिल किया जाता है, जो विवेकपूर्ण और सदाचार विनियमन के स्तंभों के तहत इकाई और गतिविधि-आधारित विनियमन दृष्टिकोणों को जोड़ता है। यह दृष्टिकोण लगातार विकसित हो रहे एनबीएफसी क्षेत्र के लिए उनकी गतिशीलता को बाधित किए बिना तैयार किया गया है।

एनबीएफसी क्षेत्र के भीतर विविध व्यावसायिक मॉडलों को देखते हुए, एसबीआर नियामकीय तीव्रता में लेयर-वार प्रगतिशील वृद्धि की परिकल्पना करता है। एक ओर बैंकों और अपर लेयर वाली एनबीएफसी (एनबीएफसी-यूएल) के बीच और दूसरी ओर विभिन्न लेयरों वाली एनबीएफसी के बीच पूंजी, विवेकपूर्ण और अभिशासन संबंधी दिशा-निर्देशों के प्रमुख क्षेत्रों में विनियमन के सामंजस्य की सीमा सारणी 3 में प्रस्तुत की गई है। एसबीआर अन्य लेयरों की तुलना में एनबीएफसी-यूएल के लिए उन्नत नियामकीय जांच करता है, किन्तु बैंकों के समान नहीं। इस तरह, एसबीआर विनियमन के लिए समायोजन दृष्टिकोण को संरक्षित करता है जहां भारतीय वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न प्रतिभागियों के अलग-अलग व्यावसायिक मॉडल और क्षमता को बनाए रखा जाता है, जबकि यह सुनिश्चित किया जाता है कि वित्तीय स्थिरता से समझौता न हो।

बैंकों और एनबीएफसी के बीच अंतर का एक प्रमुख क्षेत्र सार्वजनिक जमा स्वीकार करने की अनुमति है, जो केवल मुट्ठी भर एनबीएफसी के लिए उपलब्ध है[4]। 1997 से, नए एनबीएफसी को सार्वजनिक जमा स्वीकार करने के लिए पंजीकरण का कोई प्रमाण पत्र नहीं दिया गया है। वास्तव में, विनियामकीय दृष्टिकोण एनबीएफसी की जमा-प्राप्ति गतिविधियों को हतोत्साहित कर रहा है। यह रिज़र्व बैंक को क्रमशः एनबीएफसी के व्यवसाय को शुरू करने या बंद करने के लिए कम प्रवेश और निकास बाधाओं को बनाए रखने और उनके संबंधित व्यावसायिक डोमेन में नवाचार और विशेषज्ञता की सुविधा प्रदान करने की अनुमति देता है (राव, 2024)।

बेस लेयर वाले एनबीएफसी अपने छोटे आकार और सीमित अंतर्संबंधों के कारण मिडिल और अपर लेयरों की तुलना में कम कठोर विनियमन के अधीन हैं। नतीजतन, इस आलेख में विश्लेषण केवल एनबीएफसी-यूएल और एमएल तक ही सीमित रखा है। एनबीएफसी क्षेत्र[5] में एनबीएफसी-यूएल, एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जिसमें मार्च 2023 के अंत में अपर लेयर वाली नौ एनबीएफसी की आस्तियां कुल आस्तियों का लगभग पांचवां हिस्सा रहा है। (चार्ट 4)।

[3] कार्य समूह (अध्यक्ष: श्रीमती उषा थोरात) और लघु व्यवसायों और निम्न आय वाले परिवारों के लिए व्यापक वित्तीय सेवाओं पर समिति (अध्यक्ष: डॉ. नचिकेत मोर)।

[4] सितंबर 2023 के अंत तक 26 एनबीएफसी।

[5] विश्लेषण के उद्देश्य से यहाँ एनबीएफसी क्षेत्र में केवल एनबीएफसी-यूएल और एनबीएफसी-एमएल शामिल हैं, जिसमें स्टैंड-अलोन प्राइमरी डीलर्स (एसपीडी), मूल निवेश कंपनियाँ (सीआईसी) और आवास वित्त कंपनियां (एचएफसी) शामिल नहीं हैं। दो एनबीएफसी-आईसीसी (एनबीएफसी-यूएल सहित) के एक सीआईसी में विलय के मद्देनजर, संबंधित कंपनियों को दिसंबर 2023 के अंत में नमूने में शामिल नहीं किया गया है।

सारणी 3: बैंकों और एनबीएफसी की महत्वपूर्ण नियामकीय विशेषताएं

मौजूदा विनियामकीय आवश्यकताएं	एनबीएफसी			बैंक	टिप्पणी
	बेस लेयर	मिडिल लेयर	अपर लेयर		
पूंजीगत दिशानिर्देश					
न्यूनतम प्रारंभिक पूंजी	✓	✓	✓	✓*	एक सार्वभौमिक बैंक के लिए यह 1,000 करोड़ रुपये है, जबकि एनबीएफसी के लिए यह 10 करोड़ रुपये है (चरणबद्ध तरीके से 31 मार्च 2027 तक हासिल किया जाना है)।
जोखिम-भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात	–	✓	✓*	✓**	एक सार्वभौमिक बैंक की पूँजी आवश्यकता में ऋण, बाजार और परिचालन जोखिम पूँजी शुल्क शामिल हैं। एनबीएफसी के लिए, यह केवल ऋण जोखिम पूँजी शुल्क पर आधारित है। एनबीएफसी-यूएल को 15 प्रतिशत की समग्र पूँजी आवश्यकता के भीतर जोखिम भारित आस्तियों के न्यूनतम नौ प्रतिशत की सामान्य इक्विटी टियर 1 पूँजी बनाए रखने की आवश्यकता होती है। बेस लेयर में गोल्ड लोन एनबीएफसी को न्यूनतम 12 प्रतिशत की टियर 1 पूंजी बनाए रखनी होगी।
मानक आस्ति प्रावधान	✓	✓*	✓**	✓**	बैंकों की तरह, एनबीएफसी-यूएल को भी मानक आस्तियों के लिए विभेदक प्रावधान बनाए रखना होगा।
आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आईसीएएपी)	–	✓	✓	✓*	एनबीएफसी के लिए आईसीएएपी उसी प्रकार होगा जैसा कि बेसल III मानदंडों के पिलर 2 के अंतर्गत बैंकों के लिए निर्धारित किया गया है।
विवेकपूर्ण दिशानिर्देश					
ऋण / निवेश का संकेन्द्रण	–	✓	✓*	✓**	बैंकों के समान, एनबीएफसी-यूएल@ पर भी बड़ी जोखिम संरचना लागू है, हालांकि बैंकों के लिए अधिक विस्तृत संरचना है।
आंतरिक जोखिम सीमाएँ	–	✓	✓	✓*	संवेदनशील क्षेत्र में निवेश की आंतरिक सीमाओं के अलावा, एनबीएफसी-यूएल को अन्य महत्वपूर्ण (एनबीएफसी सहित) क्षेत्र में भी निवेश की आंतरिक सीमाएं रखनी चाहिए। बैंकों के लिए अधिक विस्तृत विनियमन।
अभिशासन और प्रकटीकरण दिशानिर्देश					
प्रकटीकरण विनियमन	✓	✓*	✓***	✓**	बैंकों और एनबीएफसी-यूएल को सूचीबद्ध कंपनी की तरह ही प्रकटीकरण आवश्यकताओं को पूरा करना होगा। हालांकि, एनबीएफसी-यूएल को वास्तविक लिस्टिंग से पहले भी इन आवश्यकताओं को पूरा करना होगा।
लिस्टिंग	–	–	✓*	✓	एक नए सार्वभौमिक बैंक को परिचालन शुरू होने के बाद छह साल के भीतर सूचीबद्ध होना होगा, जबकि एक एनबीएफसी को एनबीएफसी-यूएल के रूप में पहचान के बाद सूचीबद्ध होने के लिए तीन साल का समय मिलता है।
कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) / कोर वित्तीय सेवा समाधान (सीएफएसएस)	–	✓	✓	✓	10 या अधिक शाखाओं वाली एनबीएफसी को सीएफएसएस अपनाना होगा।
अन्य					
प्रासंगिक अधिनियमों के तहत अनुमत गतिविधियाँ	–	–	–	✓	बैंक केवल उन्हीं गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं, जिनका बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत विशेष प्रावधान है। एनबीएफसी को नियंत्रित करने वाले आरबीआई अधिनियम, 1934 के तहत ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।
वाणिज्यिक विस्तार	–	–	–	✓	एनबीएफसी (स्वर्ण ऋण एनबीएफसी को छोड़कर) के परिचालन पर लगभग कोई विनियामक प्रतिबंध नहीं है, जबकि बैंकों के लिए विस्तृत नीति मौजूद है।
प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (पीएसएल)	–	–	–	✓	समायोजित निवल बैंक ऋण का न्यूनतम 40% पीएसएल के लिए होना चाहिए और एसएफबी के लिए यह 75 प्रतिशत है। एनबीएफसी के लिए ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है।
आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ) वित्तपोषन की अधिकतम सीमा	✓	✓	✓	✓*	बैंकों और एनबीएफसी दोनों के लिए आईपीओ हेतु वित्तीय अभिदान की अधिकतम सीमा।

नोट: 1. – लागू नहीं; ✓ लागू; ✓* लागू और कठोर; ✓** लागू और अधकि कठोर

2. ^ एनबीएफसी-पी2पी, एनबीएफसी-एए और सार्वजनिक निधियों का लाभ नहीं उठाने वाली और कोई ग्राहक इंटरफ़ेस नहीं रखने वाली एनबीएफसी के लिए एनओएफ ₹2 करोड़ है। एनबीएफसी-आईएफसी और आईडीएफएनबीएफसी के लिए एनओएफ ₹300 करोड़ है।

एसपीडी को छोड़कर जहां बाजार जोखमि पूंजी लागू होती है।

@ एनबीएफसी-आईएफसी पर थोड़ी अधकि सीमा लागू होती है।

स्रोत: आरबीआई, 2021ए; आरबीआई, 2021बी और राव, 2024।

चार्ट 4: एनबीएफसी का लेयर-वार वितरण
(मार्च 2023 के अंत में प्रतिशत में हिस्सेदारी)

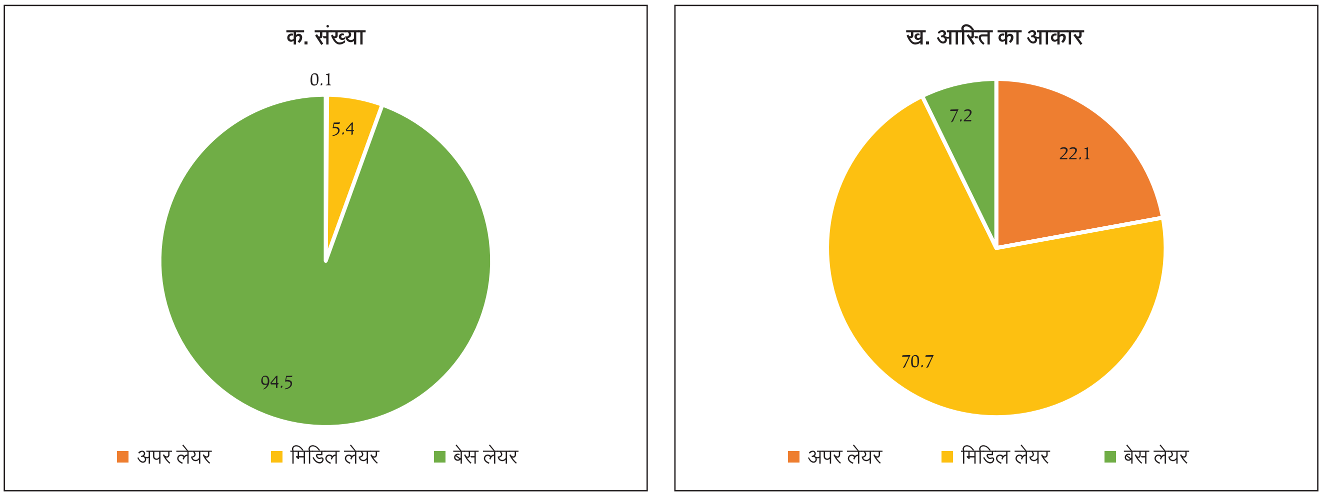

नोट: टॉप लेयर अभी रिक्त है।
स्रोत: पर्यवेक्षी विवरणी, आरबीआई।

IV. एनबीएफसी क्षेत्र का प्रदर्शन

ए. तुलन पत्र

एनबीएफसी क्षेत्र ने 2023 के दौरान निरंतर वृद्धि प्रदर्शित करना जारी रखा, जो मुख्य रूप से ऋण वृद्धि द्वारा संचालित था, भले ही निवेश में गिरावट आई हो। देयताओं के मामले में, एनबीएफसी द्वारा उधार पिछले वर्ष की तुलना में कम दर से बढ़ा (सारणी 4)।

आस्तियां

उपभोक्ता ऋण के कुछ घटकों में उच्च वृद्धि के बारे में कुछ चिंताओं को दूर करने के लिए, रिज़र्व बैंक ने नवंबर 2023 में एनबीएफसी द्वारा खुदरा ऋणों की चुनिंदा श्रेणियों पर जोखिम भार बढ़ा दिया। इन उपायों के बाद अप्रतिभूत ऋणों में वृद्धि कम हो गई है (चार्ट 5)।

सारणी 4: एनबीएफसी का समेकित तुलन पत्र

(₹ करोड़)

	वर्ष के अंत में बकाया राशि			वार्षिक वृद्धि (प्रतिशत में)	
	दिसं -22	मार्च-23	दिसं-23	22 दिसं से 21 दिसं तक	23 दिसं से 22 दिसं तक
1. शेयर पूंजी	1,14,533	1,19,432	1,29,479	11.6	13.0
2. आरक्षित निधियाँ और अधिशेष	7,97,827	8,58,744	8,79,323	20.8	10.2
3. सार्वजनिक जमा	1,15,850	89,322	1,06,405	22.5	-8.2
4. कुल उधार	27,67,612	29,43,224	30,72,171	16.3	11.0
5. अन्य देयताएं	2,91,141	3,29,415	3,25,561	7.1	11.8
कुल देयताएँ / आस्तियां	**40,86,963**	**43,40,138**	**45,12,938**	**16.4**	**10.4**
1. ऋण और अग्रिम	31,42,244	33,65,863	35,88,631	16.4	14.2
2. निवेश	5,25,669	5,38,714	4,98,172	19.7	-5.2
3. नकदी एवं बैंक शेष	1,61,094	1,70,274	1,57,821	6.7	-2.0
4. अन्य आस्तियां	2,57,956	2,65,287	2,68,315	17.0	4.0

नोट: 1. डेटा अनंतिम है और केवल एनबीएफसी-यूएल और एनबीएफसी-एमएल से संबंधित है।
2. आकड़े मेल नहीं खा सकते हैं; क्योंकि सभी घटकों की रिपोर्ट यहाँ नहीं की गई है।
स्रोत: पर्यवेक्षी विवरणी, आरबीआई।

चार्ट 5: एनबीएफसी द्वारा ऋण और अग्रिम

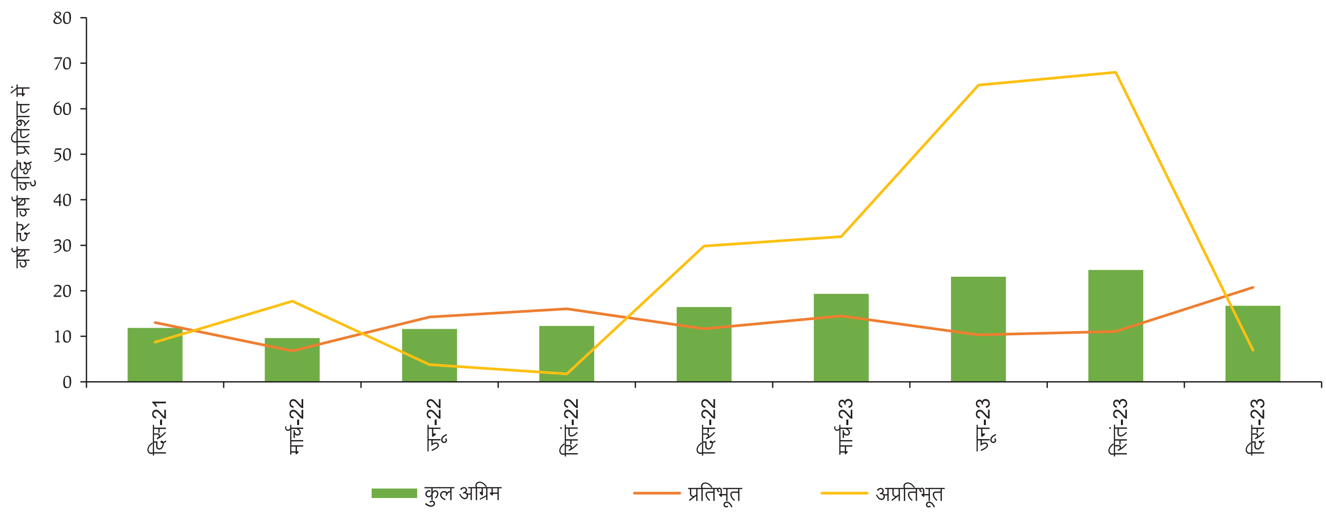

नोट: आंकड़े अनंतिम हैं और केवल एनबीएफसी-यूएल और एनबीएफसी-एमएल से संबंधित हैं।
स्रोत: पर्यवेक्षी विवरणी, आरबीआई।

एनबीएफसी के ऋण में अप्रतिभूत ऋण लगभग 26 प्रतिशत है, जबकि मिडिल लेयर की ऋण पोर्टफोलियो में इसकी हिस्सेदारी अधिक है (चार्ट 6ए)। सभी एनबीएफसी लेयरों पर अप्रतिभूत ऋणों में शुरुआती तेज वृद्धि और उसके बाद आई मंदी मिडिल लेयर की एनबीएफसी द्वारा संचालित थी। अपर लेयर की एनबीएफसी द्वारा अप्रतिभूत ऋणों में विस्तार की गति भी धीमी हो गई है, हालांकि यह दोहरे अंकों में बनी हुई है (चार्ट 6बी)।

एनबीएफसी क्रेडिट का 70 प्रतिशत से अधिक उद्योग और खुदरा क्षेत्रों को जाता है, जिसमें दिसंबर 2023 के अंत में उद्योग का लगभग दो-पांचवां हिस्सा रहा है, जो इसे एनबीएफसी ऋण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बनाता है (चार्ट 7 ए)। 2023 में, उद्योग, सेवाओं और खुदरा ऋणों के लिए ऋण दोहरे अंकों में बढ़ा, जबकि कृषि और संबद्ध गतिविधियों में आधार प्रभाव के कारण कमी आई (चार्ट 7 बी)। खुदरा क्षेत्र को ऋण वाहनों, उपभोक्ता टिकाऊ

चार्ट 6: लेयर-वार अप्रतिभूत ऋणों में रुझान

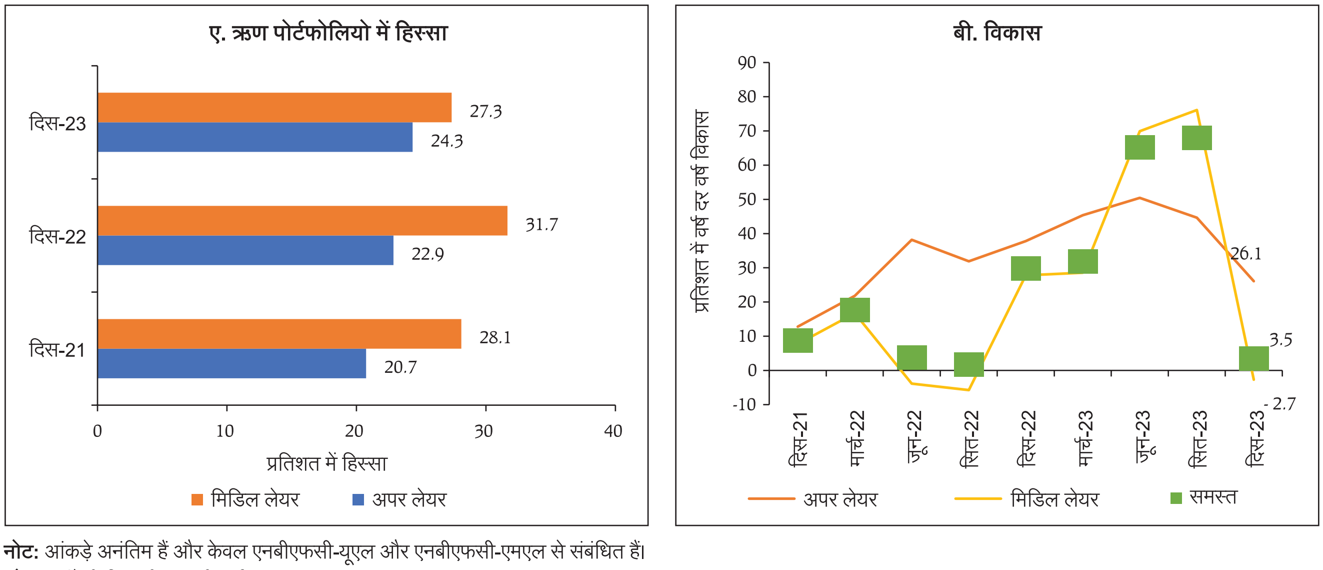

नोट: आंकड़े अनंतिम हैं और केवल एनबीएफसी-यूएल और एनबीएफसी-एमएल से संबंधित हैं।
स्रोत: पर्यवेक्षी विवरणी, आरबीआई।

चार्ट 7: एनबीएफसी ऋण का क्षेत्रकवार वितरण

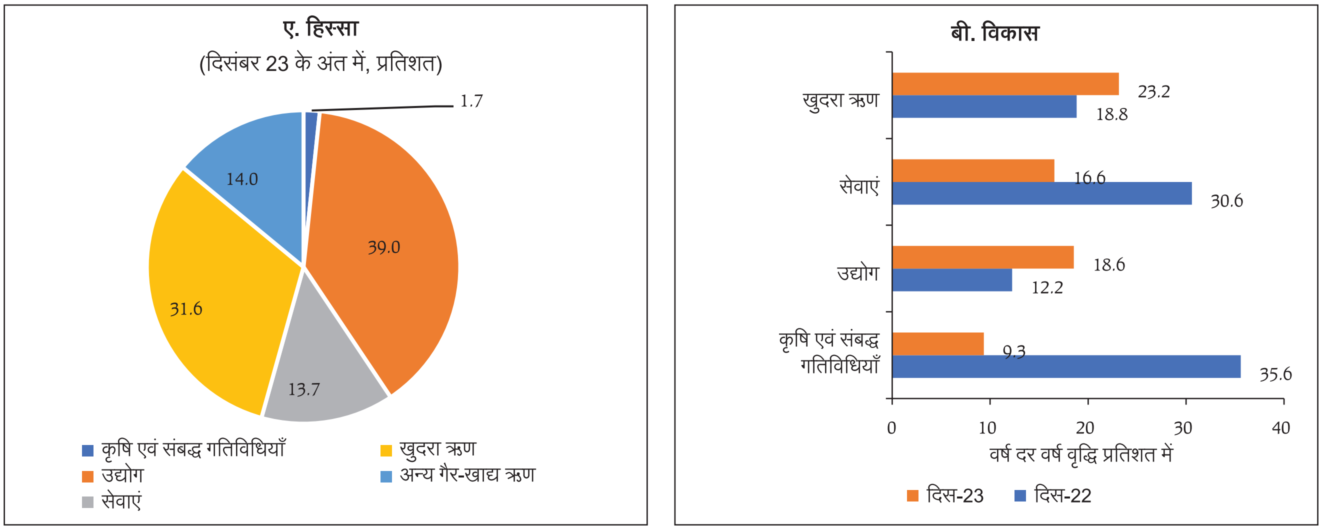

नोट: आंकड़े अनंतिम हैं और केवल एनबीएफसी-यूएल और एनबीएफसी-एमएल से संबंधित हैं।
स्रोत: पर्यवेक्षी विवरणी, आरबीआई।

वस्तुओं, स्वर्ण ऋण और क्रेडिट कार्ड प्राप्तियों के क्षेत्रों के लिए उधार में मजबूत वृद्धि के कारण संचालित किया गया था।

लेयर-वार और स्वामित्व-वार विश्लेषण से इस क्षेत्र की संरचना के बारे में जानकारी मिलती है। एनबीएफसी ऋण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता उद्योग है, जो बड़े सरकारी स्वामित्व वाली[6] एनबीएफसी की उपस्थिति से लाभान्वित होता है जो बुनियादी ढांचा क्षेत्र को ऋण देते हैं। अपर लेयर में सभी एनबीएफसी निजी स्वामित्व वाली हैं और मुख्य रूप से खुदरा क्षेत्र की ऋण मांगों को पूरा करती हैं (चार्ट 8)।

देयताएं

एनबीएफसी अपनी निधीयन जरूरतों के लिए बाजारों और बैंकों दोनों से उधारी पर बहुत अधिक निर्भर करती हैं (आरबीआई, 2023)। एनबीएफसी-यूएल, अपनी मजबूत तुलन पत्र और बाजार स्थिति के कारण प्रतिभूत उधारी पर अधिक निर्भर करती हैं।

चार्ट 8: एनबीएफसी क्षेत्र का क्षेत्रकवार ऋण पोर्टफोलियो
(दिसंबर 2023 के अंत में)

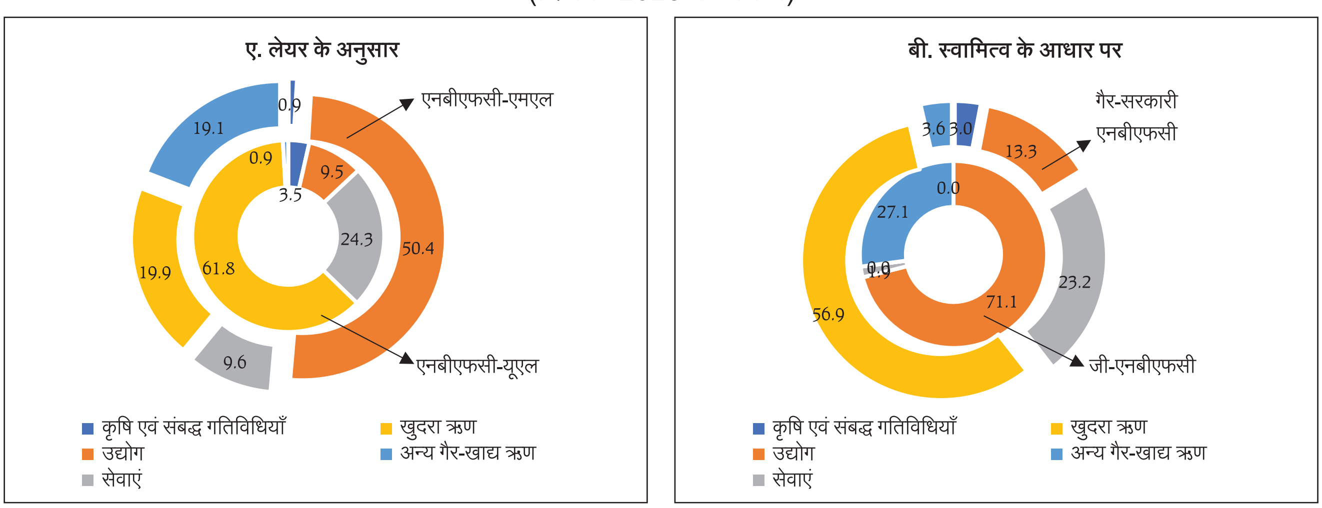

नोट: आंकड़े अनंतिम हैं और केवल एनबीएफसी-यूएल और एनबीएफसी-एमएल से संबंधित हैं।
स्रोत: पर्यवेक्षी विवरणी, आरबीआई।

[6] सरकारी एनबीएफसी को डिजाइन के अनुसार या तो मिडिल लेयर या बेस लेयर पर रखा जाता है। यह आलेख केवल मिडिल लेयर की सरकारी एनबीएफसी पर विचार करता है।

दिस-23
दिस-23
दिस-23

चार्ट 9: एनबीएफसी का उधार प्रोफ़ाइल

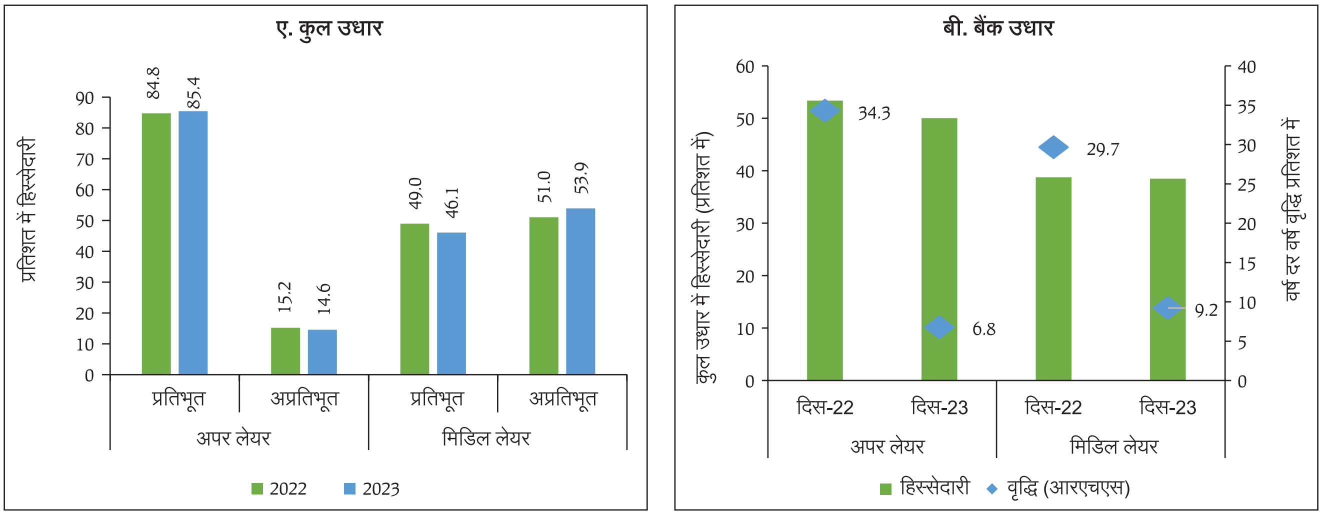

नोट: 1. आंकड़े अनंतिम हैं और केवल एनबीएफसी-यूएल और एनबीएफसी-एमएल से संबंधित हैं।
2. बैंक उधार में प्रत्यक्ष उधार के साथ-साथ बाजार साधनों के माध्यम से उधार लेना भी शामिल है।
स्रोत: पर्यवेक्षी विवरणी, आरबीआई।

दूसरी ओर, एनबीएफसी-एमएल संभवतः उच्च दरों पर अप्रतिभूत उधारी पर अधिक निर्भर करती हैं (चार्ट 9 ए)। बैंक एनबीएफसी के लिए निधि का प्रमुख स्रोत बने हुए हैं, न केवल प्रत्यक्ष उधार के माध्यम से, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से एनबीएफसी द्वारा जारी किए गए डिबेंचर और वाणिज्यिक पत्र की सदस्यता के माध्यम से भी। एनबीएफसी को अपने निधि जुटाने के आधार को व्यापक बनाने और बैंकों पर निर्भरता को सीमित करने के लिए प्रोत्साहित करने के प्रयास में, रिज़र्व बैंक ने नवंबर 2023 में एनबीएफसी को बैंक ऋण पर जोखिम भार बढ़ा दिया था।

बी. एनबीएफसी क्षेत्र का वित्तीय प्रदर्शन और विवेकपूर्ण संकेतक

लाभप्रदता संकेतकों, अर्थात आस्तियों पर आय (आरओए) और इक्विटी पर आय (आरओई) [चार्ट 10] के अनुसार, इस क्षेत्र की आधार रेखा में लगातार सुधार हुआ है। एनबीएफसी-

चार्ट 10: एनबीएफसी क्षेत्र की लाभप्रदता

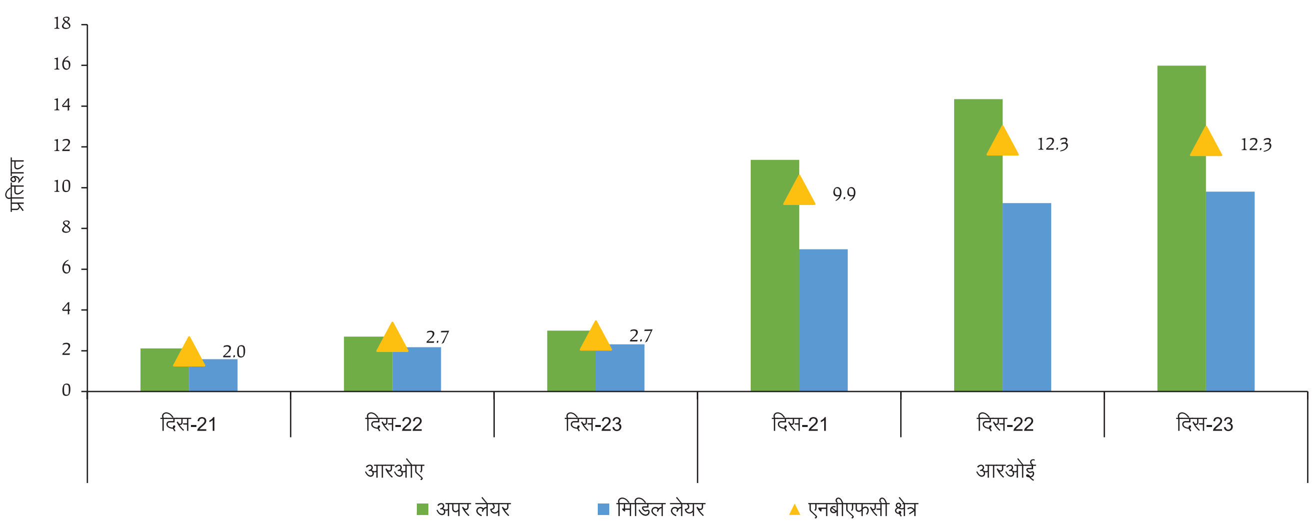

नोट: आंकड़े अनंतिम हैं और केवल एनबीएफसी-यूएल और एनबीएफसी-एमएल से संबंधित हैं।
स्रोत: पर्यवेक्षी विवरणी, आरबीआई।

चार्ट 11: आस्ति गुणवत्ता

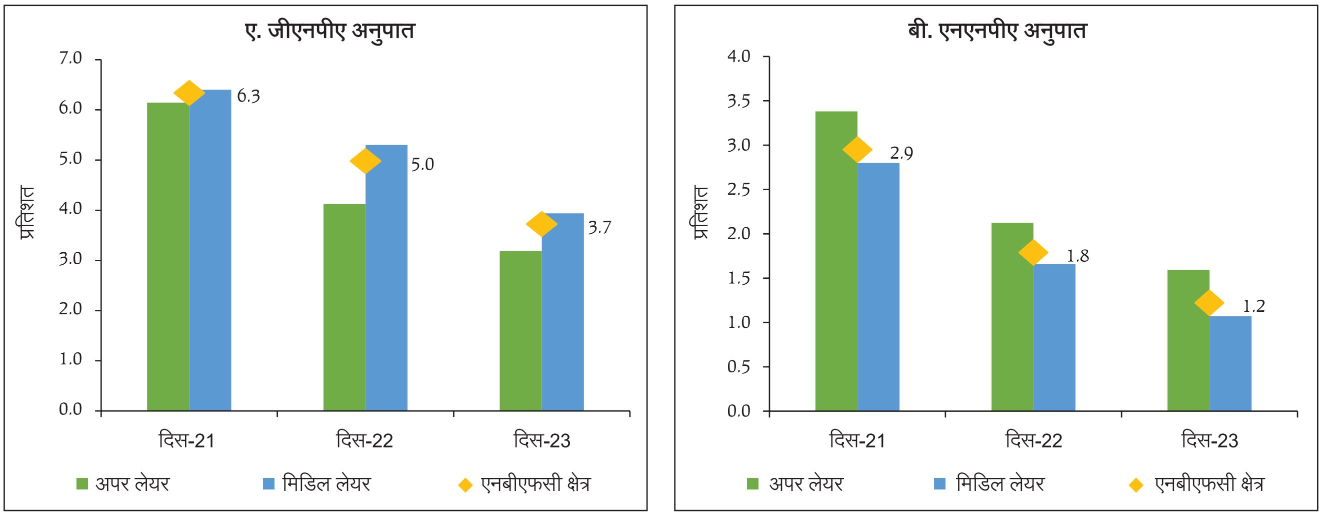

नोट: आंकड़े अनंतिम हैं और केवल एनबीएफसी-यूएल और एनबीएफसी-एमएल से संबंधित हैं।
स्रोत: पर्यवेक्षी विवरणी, आरबीआई।

यूएल ने लाभप्रदता के संबंध में एनबीएफसी-एमएल की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है, जिसका मुख्य कारण अनर्जक आस्तियों (एनपीए) के बदले कम प्रावधान और कम ब्याज व्यय रहा है।

इस क्षेत्र की आस्ति गुणवत्ता में भी सुधार हुआ है। अपर लेयर में यद्यपि एनबीएफसी का सकल एनपीए (जीएनपीए) अनुपात मिडिल लेयर की तुलना में कम है, तथापि मिडिल लेयर ने अपने जोखिम युक्त ऋण पोर्टफोलियो के लिए पर्याप्त प्रावधान बनाए रखा, जिससे उनका निवल एनपीए (एनएनपीए) अनुपात एनबीएफसी-यूएल (चार्ट 11) से नीचे आ गया।

जीएनपीए अनुपात में गिरावट सभी क्षेत्रों में देखी गई है, खुदरा ऋण खंड में अप्रतिभूत खुदरा उधार के बावजूद सबसे कम जीएनपीए अनुपात है (चार्ट 12ए)। खुदरा ऋणों

चार्ट 12: आस्ति गुणवत्ता, क्षेत्रकवार

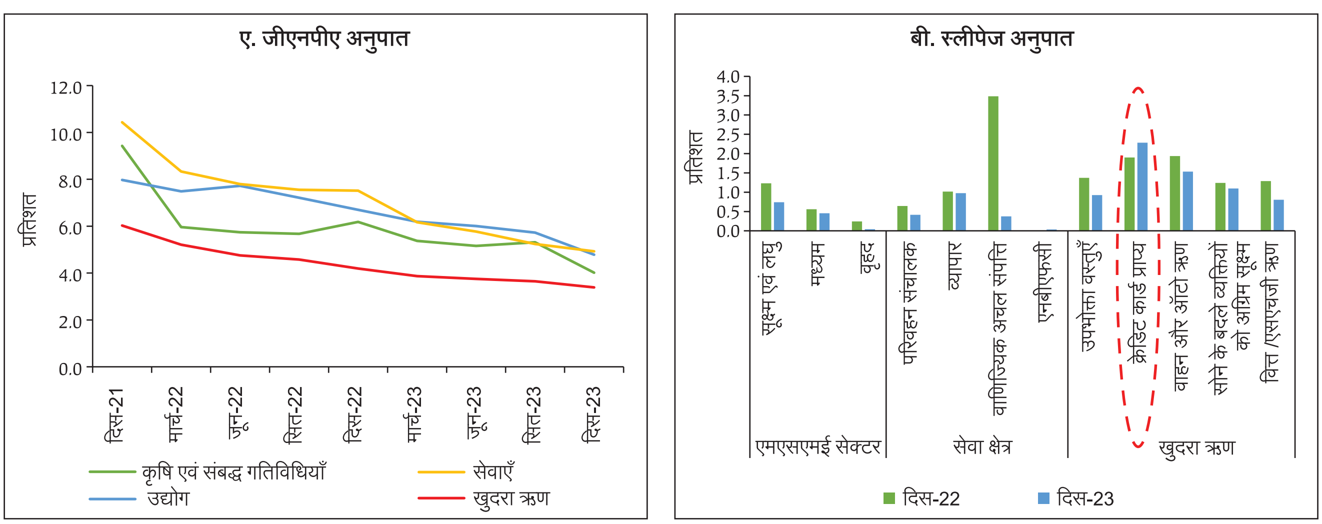

नोट: आंकड़े अनंतिम हैं और केवल एनबीएफसी-यूएल और एनबीएफसी-एमएल से संबंधित हैं।
स्रोत: पर्यवेक्षी विवरणी, आरबीआई

[7] स्लिपेज अनुपात से तात्पर्य तिमाही के दौरान कुल बकाया अग्रिमों में अनर्जक आस्तियों में वृद्धि के अनुपात से है।

चार्ट 13: स्वामित्व के आधार पर आस्ति गुणवत्ता (जीएनपीए अनुपात)

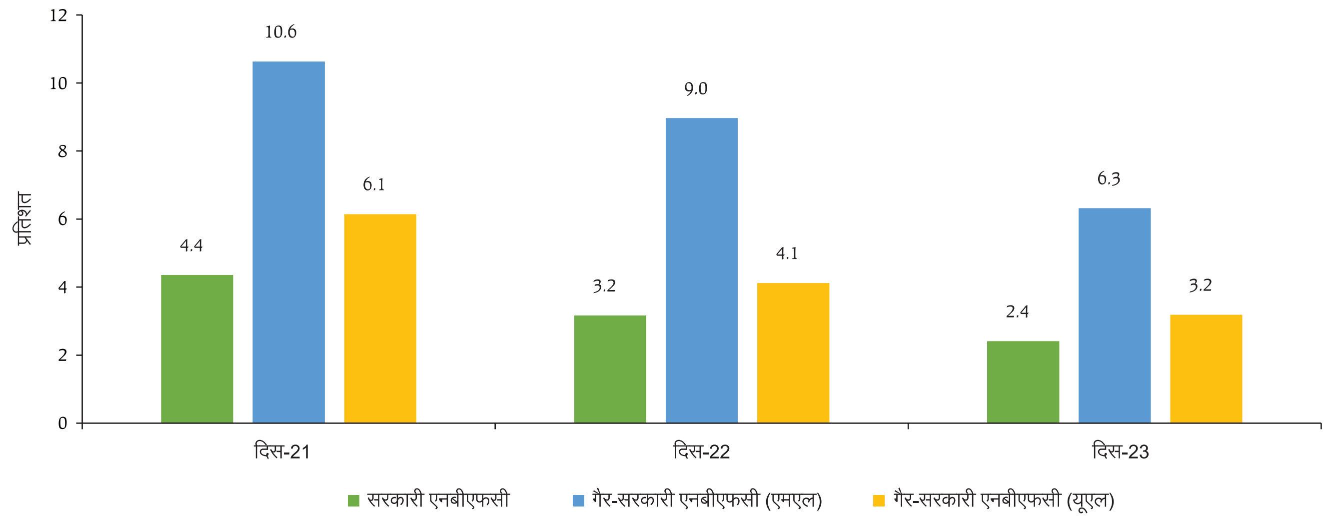

नोट: आंकड़े अनंतिम हैं और केवल एनबीएफसी-यूएल और एनबीएफसी-एमएल से संबंधित हैं।
स्रोत: पर्यवेक्षी विवरणी, आरबीआई

की महत्वपूर्ण श्रेणियों जैसे कि वाहन ऋण और स्वर्ण ऋण में स्लीपेज अनुपात[7] अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक रहा है, हालांकि क्रेडिट कार्ड प्राप्य खंड को छोड़कर दिसंबर 2023 के अंत में इसमें कमी आई है (चार्ट 12बी)।

सरकारी स्वामित्व वाली एनबीएफसी का अपेक्षाकृत कम एनपीए अनुपात है (चार्ट 13)। जैसा कि पहले बताया गया है, गैर-सरकारी एनबीएफसी, विशेष रूप से मिडिल लेयर वाले वाले, खुदरा ऋण पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जहां हाल के दिनों में स्लीपेज बढ़ गई है।

खुदरा ऋणों की कुछ श्रेणियों पर जोखिम भार में वृद्धि के साथ, गैर-प्रतिभूत ऋणों के बड़े पोर्टफोलियो वाले एनबीएफसी को विनियामकीय पूंजी अपेक्षाओं का पालन करने के लिए अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता हो सकती है। हालांकि, समग्र रूप से क्षेत्र, एनबीएफसी-यूएल और

चार्ट 14: पूंजी पर्याप्तता

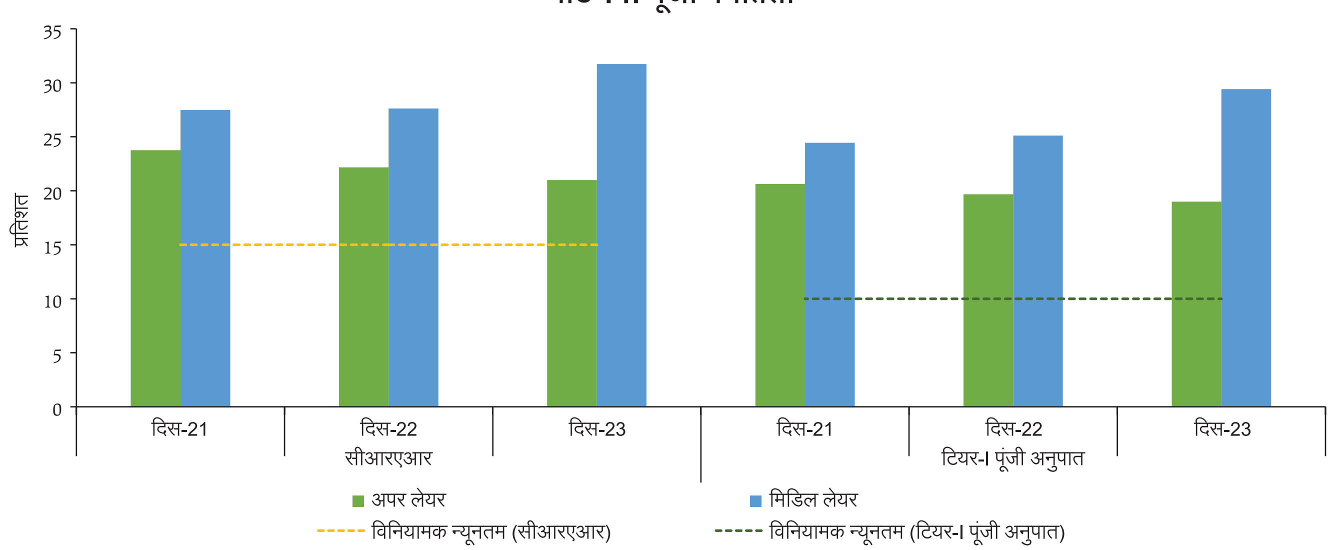

नोट: आंकड़े अनंतिम हैं और केवल एनबीएफसी-यूएल और एनबीएफसी-एमएल से संबंधित हैं।
स्रोत: पर्यवेक्षी विवरणी, आरबीआई।

एनबीएफसी-एमएल दोनों, अच्छी तरह से पूंजीकृत बने हुए हैं, जो उच्च आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उनकी वित्तीय सुदृढ़ता को दर्शाता है (चार्ट 14)।

त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) ढांचे के तहत, पूंजी और आस्ति गुणवत्ता एनबीएफसी की वित्तीय स्थिति की निगरानी के लिए प्रमुख क्षेत्र हैं, और यह 1 अक्तूबर, 2024 से सरकारी स्वामित्व वाली एनबीएफसी के लिए लागू हो जाएगा। दिसंबर 2023 के अंत में पर्याप्त पूंजी और कम एनएनपीए के साथ, ये एनबीएफसी आरामदायक स्थिति में हैं। पीसीए ढांचा 1 अक्तूबर, 2022 से अन्य एनबीएफसी के लिए पहले से ही प्रभावी है।

निष्कर्ष

वैश्विक स्तर पर, एनबीएफआई वास्तविक अर्थव्यवस्था को वित्तपोषित करने और आर्थिक विकास का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विभिन्न देश एनबीएफआई के लिए ऐसे नियम लागू करते हैं जो उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप हों। भारत की तुलना में, उन्नत देशों में गैर-बैंक आकार में बहुत बड़े हैं और जटिल बाजार परिवेश में काम करते हैं।

भारत में एनबीएफसी क्षेत्र एसबीआर ढांचे के अंतर्गत सुदृढ़ बना हुआ है। दिसंबर 2023 के अंत में, इस क्षेत्र ने ऋण, पर्याप्त पूंजी और कम चूक अनुपात में दोहरे अंकों की वृद्धि प्रदर्शित करना जारी रखा। सरकारी स्वामित्व वाली एनबीएफसी को पीसीए मानदंडों के विस्तार के हालिया नियामकीय उपाय से इस क्षेत्र को और मजबूती मिलने की उम्मीद है। एनबीएफसी को बैंक ऋण पर जोखिम भार में हाल ही में हुई वृद्धि के प्रतिक्रिया स्वरूप, उन्होंने अपने वित्तपोषण स्रोतों में विविधता लाना शुरू कर दिया है और बैंकों से उधार लेने पर अत्यधिक निर्भरता कम कर दी है। उद्योग और सेवा क्षेत्र के ऋणों के साथ-साथ स्वर्ण ऋण, वाहन और आवास ऋण जैसे प्रतिभूत खुदरा ऋण में मजबूत वृद्धि जारी है।

आगे बढ़ते हुए, एनबीएफसी को तेजी से विकसित हो रहे वित्तीय परिदृश्य और उभरते जोखिमों और चुनौतियों, विशेष रूप से साइबर-सुरक्षा और जलवायु जोखिम के क्षेत्रों में, के प्रति सचेत रहने की जरूरत है। जोखिम प्रबंधन, अनुपालन और आंतरिक लेखा परीक्षा जैसे आश्वासन कार्य, वित्तीय इकाई और समग्र वित्तीय प्रणाली दोनों की मजबूती और सुदृढ़ बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं (जे, स्वामीनाथन, 2024)। भारतीय वित्तीय प्रणाली में उनकी बढ़ती भूमिका को ध्यान में रखते हुए, एनबीएफसी पर यह दायित्व है कि वे जोखिमों की पहचान करें और उनका प्रबंधन करें और अपने आश्वासन कार्यों को मजबूत करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि एनबीएफसी क्षेत्र एक सतत विकास पथ बना रहे।

संदर्भ

Ehrentraud, J., Mure, S., Noble, E., & Zamil, R. (2024). Safeguarding the financial system's spare tyre: regulating non-bank retail lenders in the digital era. *FSI Insights on policy implementation No 56.* Bank for International Settlements.

FSB. (2023a). *Enhancing the Resilience of Non-Bank Financial Intermediation- Progress report.*

FSB. (2023b). Global Monitoring Report on Non-Bank Financial Intermediation.

J, Swaminathan. (2024). Shared Vision, Shared Responsibilities: Advancing Assurance in Banking Supervision. *Speech by Shri Swaminathan J, Deputy Governor, Reserve Bank of India.*

Rao, M. R. (2024). No More a Shadow (of a) Bank. *Remarks delivered by Shri M. Rajeshwar Rao, Deputy Governor, Reserve Bank of India.*

RBI. (2014). *Revised Regulatory Framework for NBFC.* Retrieved from https://www.rbi.org.in/scripts/NotificationUser.aspx?Id=9327 .

RBI. (2023). *Report on Trend and Progress of Banking in India, 2022-23*

RBI. (2021a). Scale Based Regulation (SBR): A Revised Regulatory Framework for NBFCs.

RBI. (2021b). *Discussion Paper on Revised Regulatory Framework for NBFCs- A Scale Based Approach.*

वर्तमान सांख्यिकी

चुनिंदा आर्थिक संकेतक

भारतीय रिज़र्व बैंक

मुद्रा और बैंकिंग

मूल्य और उत्पादन

सरकारी खाते और खज़ाना बिल

वित्तीय बाजार

बाह्य क्षेत्र

भुगतान और निपटान प्रणालियाँ

आवसरिक श्रृंखलाएं

विषयवस्तु

संख्या	शीर्षक	पृष्ठ
1	चुनिंदा आर्थिक संकेतक	151
	भारतीय रिज़र्व बैंक	
2	भारतीय रिज़र्व बैंक - देयताएं और आस्तियां	152
3	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा चलनिधि परिचालन	153
4	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अमेरिकी डॉलर का क्रय/विक्रय	154
4ए	भारतीय रिज़र्व बैंक के बकाया वायदे का (अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार) परिपक्वता विश्लेषण (मिलियन अमेरिकी डॉलर)	155
5	भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थायी सुविधाएं	155
	मुद्रा और बैंकिंग	
6	मुद्रा स्टॉक मात्रा	156
7	मुद्रा स्टॉक (एम$_3$) के स्रोत	157
8	मौद्रिक सर्वेक्षण	158
9	कुल चलनिधि राशियाँ	159
10	भारतीय रिज़र्व बैंक सर्वेक्षण	160
11	आरक्षित मुद्रा- घटक और स्रोत	160
12	वाणिज्यिक बैंक सर्वेक्षण	161
13	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के निवेश	161
14	भारत में कारोबार - सभी अनुसूचित बैंक और सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	162
15	प्रमुख क्षेत्रों द्वारा सकल बैंक ऋण का विनियोजन	163
16	सकल बैंक ऋण का उद्योग-वार विनियोजन	164
17	भारतीय रिज़र्व बैंक में खाते रखने वाले राज्य सहकारी बैंक	165
	मूल्य और उत्पादन	
18	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधारः 2012=100)	166
19	अन्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	166
20	मुंबई में सोने और चांदी का मासिक औसत मूल्य	166
21	थोक मूल्य सूचकांक	167
22	औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आधारः 2011-12=100)	171
	सरकारी खाते और खज़ाना बिल	
23	केन्द्र सरकार के खाते - एक नज़र में	171
24	खज़ाना बिल - स्वामित्व का स्वरूप	172
25	खज़ाना बिलों की नीलामी	172
	वित्तीय बाजार	
26	दैनिक मांग मुद्रा दरें	173
27	जमाराशि प्रमाण-पत्र	174
28	वाणिज्यिक पत्र	174
29	चुनिंदा वित्तीय बाजारों में औसत दैनिक टर्नओवर	174
30	गैर-सरकारी पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के नए पूंजी निर्गम	175

संख्या	शीर्षक	पृष्ठ
	बाह्य क्षेत्र	
31	विदेशी व्यापार	176
32	विदेशी मुद्रा भंडार	176
33	अनिवासी भारतीयों की जमाराशियाँ	176
34	विदेशी निवेश अंतर्वाह	177
35	निवासी भारतीयों के लिए उदारीकृत विप्रेषण योजना (एलआरएस) के अंतर्गत जावक विप्रेषण	177
36	भारतीय रुपये का सांकेतिक प्रभावी विनिमय दर (एनईईआर) और वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (आरईईआर) सूचकांक	178
37	बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) - पंजीकरण	179
38	भारत का समग्र भुगतान संतुलन (मिलियन अमेरिकी डॉलर)	180
39	भारत का समग्र भुगतान संतुलन (₹ करोड़)	181
40	बीपीएम 6 के अनुसार भारत में भुगतान संतुलन का मानक प्रस्तुतीकरण (मिलियन अमेरिकी डॉलर)	182
41	बीपीएम 6 के अनुसार भारत में भुगतान संतुलन का मानक प्रस्तुतीकरण (₹ करोड़)	183
42	भारत की अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थिति	184
	भुगतान और निपटान प्रणालियाँ	
43	भुगतान प्रणाली संकेतक	185
	आवसरिक श्रृंखलाएं	
44	लघु बचत	187
45	केंद्र और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों के स्वामित्व का स्वरूप	188
46	केन्द्र और राज्य सरकारों की संयुक्त प्राप्तियां और संवितरण	189
47	विभिन्न सुविधाओं के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा ली गई वित्तीय सहायता	190
48	राज्य सरकारों द्वारा किए गए निवेश	191
49	राज्य सरकारों की बाज़ार उधारियां	192
50 (ए)	हाउसहोल्ड की वित्तीय आस्तियों और देयताओं का प्रवाह-लिखत-वार	193
50 (बी)	हाउसहोल्ड की वित्तीय आस्तियों और देयताओं का स्टॉक-चुनिंदा संकेतक	196

टिप्पणियां: .. = उपलब्ध नहीं।

– = शून्य/नगण्य

प्रा/अ = प्रारंभिक/अनंतिम   आंसं = आंशिक रूप से संशोधित

सं. 1: चुनिंदा आर्थिक संकेतक

मद	2023-24	2022-23	2023-24		2024-25
		ति4	ति1	ति4	ति1
	1	2	3	4	5
1 वास्तविक क्षेत्र (% परिवर्तन)					
1.1 आधार मूल्यों पर जीवीए	7.2	6.0	8.3	6.3	6.8
1.1.1 कृषि	1.4	7.6	3.7	0.6	2.0
1.1.2 उद्योग	9.3	1.7	5.0	8.3	7.4
1.1.3 सेवाएं	7.9	7.3	10.4	7.0	7.7
1.1ए अंतिम खपत व्यय	3.8	3.5	4.6	3.4	6.3
1.1बी सकल नियत पूंजी निर्माण	9.0	3.8	8.5	6.5	7.5
	2023-24	2023		2024	
		जून	जुला	जून	जुला
	1	2	3	4	5
1.2 औद्योगिक उत्पादन सूचकांक	5.9	4.0	6.2	4.7	4.8
2 मुद्रा और बैंकिंग (% परिवर्तन)					
2.1 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक					
2.1.1 जमाराशियाँ	12.9	12.9	12.0	10.6	11.0
	(13.5)		(12.9)	(11.1)	(10.6)
2.1.2 ऋण#	16.3	16.2	14.6	13.9	15.1
	(20.2)		(19.5)	(17.4)	(13.7)
2.1.2.1 गैर-खाद्यान्न ऋण#	16.3	16.3	14.7	13.9	15.1
	(20.2)		(19.7)	(17.4)	(13.7)
2.1.3 सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	11.1	14.3	14.2	7.4	9.1
	(12.8)		(16.5)	(8.6)	(8.1)
2.2 मुद्रा स्टॉक मात्रा					
2.2.1 आरक्षित मुद्रा (एम0)	5.6	6.5	5.4	7.4	7.2
2.2.2 स्थूल मुद्रा (एम3)	11.1	13.4	10.6	9.7	10.0
			(11.3)	(10.1)	(9.7)
3 अनुपात (%)					
3.1 आरक्षित नकदी निधि अनुपात	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50
3.2 सांविधिक चलनिधि अनुपात	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00
3.3 नकदी-जमा अनुपात	5.0	5.1	5.2	5.1	5.1
	(5.0)		(5.2)	(5.1)	(5.1)
3.4 ऋण-जमा अनुपात	78.1	75.1	74.6	77.3	77.3
	(80.3)		(77.1)	(79.3)	(79.3)
3.5 वृद्धिशील ऋण-जमा अनुपात#	95.8	63.7	51.6	58.4	56.3
	(113.4)		(99.0)	(56.0)	(53.1)
3.6 निवेश-जमा अनुपात	29.5	29.6	30.1	28.8	29.6
	(29.8)		(30.5)	(28.9)	(29.8)
3.7 वृद्धिशील निवेश-जमा अनुपात	25.8	23.0	32.1	9.4	31.4
	(28.4)		(37.8)	(6.4)	(28.8)
4 ब्याज दरें (%)					
4.1 नीति रेपो दर	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50
4.2 स्थायी रिवर्स रेपो दर	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35
4.3 स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) दर*	6.25	6.25	6.25	6.25	6.25
4.4 सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर	6.75	6.75	6.75	6.75	6.75
4.5 बैंक दर	6.75	6.75	6.75	6.75	6.75
4.6 आधार दर	9.10/10.25	8.75/10.10	8.85/10.10	9.10/10.40	9.10/10.40
4.7 एमसीएलआर (एक दिन के लिए)	8.00/8.60	7.95/8.35	7.95/8.35	8.10/8.60	8.10/8.60
4.8 मीयादी जमा दर >1 वर्ष	6.50/7.25	6.00/7.25	6.00/7.25	6.00/7.30	6.00/7.30
4.9 बचत जमा दर	2.70/3.00	2.70/3.00	2.70/3.00	2.70/3.00	2.70/3.00
4.10 मांग मुद्रा दर (भारित औसत)	6.85	6.79	6.50	6.67	6.59
4.11 91-दिवसीय खज़ाना बिल (प्राथमिक) प्रतिफल	-	6.76	6.72	6.80	6.67
4.12 182-दिवसीय खज़ाना बिल (प्राथमिक) प्रतिफल	7.28	6.87	6.86	6.92	6.79
4.13 364-दिवसीय खज़ाना बिल (प्राथमिक) प्रतिफल	7.31	6.87	6.89	6.96	6.80
4.14 10-वर्षीय सरकारी प्रतिभूतियों सममूल्य प्रतिफल (एफबीआईएल)	7.31	7.10	7.17	7.04	6.97
5 संदर्भ दर और वायदा प्रीमियम					
5.1 भा.रु.-अमेरिकी डालर हाजिर दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)	83.37	82.04	82.25	83.45	83.73
5.2 भा.रु.-यूरो हाजिर दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)	90.22	89.13	90.32	89.25	90.86
5.3 अमेरिकी डॉलर का वायदा प्रीमियम 1-माह (%)	1.00	1.39	1.17	1.10	1.11
3-माह (%)	1.11	1.32	1.22	1.14	1.20
6-माह (%)	1.31	1.38	1.33	1.26	1.43
6 मुद्रास्फीति (%)					
6.1 अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	5.4	4.9	7.4	5.1	3.6
6.2 औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	5.19	5.6	7.5	3.7	2.1
6.3 थोक मूल्य सूचकांक	-0.7	-4.2	-1.2	3.4	2.0
6.3.1 प्राथमिक वस्तुएं	3.6	-3.0	8.2	9.2	3.1
6.3.2 ईंधन और बिजली	-4.6	-12.5	-12.7	0.5	1.7
6.3.3 विनिर्मित उत्पाद	-1.7	-2.8	-2.6	1.5	1.6
7 विदेशी व्यापार (% परिवर्तन)					
7.1 आयात	-5.3	-16.8	-16.1	5.9	7.5
7.2 निर्यात	-3.1	-18.8	-10.0	2.5	-1.7

टिप्पणी : फाइनेंसियल बेंचमार्क इंडिया प्रा. लि. (एफबीआईएल) ने भारतीय रिज़र्व बैंक के 31 मार्च 2018 के परिपत्र एफएमआरडी.डीआईआरडी.7/14.03.025/ 2017-18 के अनुसार 31 मार्च 2018 से जी सेक बेंचमार्क का प्रकाशन शुरू किया है। एफबीआईएल ने 10 जुलाई 2018 से संदर्भ दरों का प्रसार शुरू किया है।

#: 3 दिसंबर 2021 से 18 नवंबर 2022 तक सभी पखवाड़ों के लिए चुनिंदा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) द्वारा बैंक ऋण वृद्धि और संबंधित अनुपात को पिछली रिपोर्टिंग त्रुटियों के लिए समायोजित किया जाता है। कोष्टकों में दिए गए आंकड़ों में एक गैर-बैंक के बैंक के साथ विलय का प्रभाव शामिल है।

*: दिनांक 8 अप्रैल 2022 की प्रेस प्रकाशनी सं. 2022-2023/41 के अनुसार।

भारतीय रिज़र्व बैंक

सं. 2: भारतीय रिज़र्व बैंक - देयताएं और आस्तियां*

(₹ करोड़)

मद	अंतिम शुक्रवार/शुक्रवार की स्थिति						
	2023-24	2023	2024				
		अग	अग 02	अग 09	अग 16	अग 23	अग 30
	1	2	3	4	5	6	7
1 निर्गम विभाग							
1.1 देयताएं							
1.1.1 संचलन में नोट	3482333	3278665	3489264	3491350	3482555	3478635	3458493
1.1.2 बैंकिंग विभाग में रखे गए नोट	11	11	13	12	14	15	14
1.1/1.2 कुल देयताएं (जारी किए गए कुल नोट) या आस्तियां	**3482344**	**3278676**	**3489277**	**3491361**	**3482569**	**3478650**	**3458507**
1.2 आस्तियां							
1.2.1 स्वर्ण	162996	138185	183666	180881	183520	186147	188699
1.2.2 विदेशी प्रतिभूतियां	3318885	3140180	3305234	3310172	3298588	3292110	3269461
1.2.3 रुपया सिक्का	463	311	377	308	461	393	347
1.2.4 भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियां	-	-	-	-	-	-	-
2 बैंकिंग विभाग							
2.1 देयताएं							
2.1.1 जमाराशियाँ	1782333	1613239	1724157	1689026	1702879	1713393	1702744
2.1.1.1 केंद्र सरकार	101	101	101	101	100	101	100
2.1.1.2 बाजार स्थिरीकरण योजना	-		-	-	-	-	-
2.1.1.3 राज्य सरकारें	42	42	42	42	42	42	42
2.1.1.4 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	1008618	1010361	984745	971052	983701	960220	1019456
2.1.1.5 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	10092	8808	8344	8160	8250	8279	8019
2.1.1.6 गैर-अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	6412	4686	5730	5315	5241	5537	5186
2.1.1.7 अन्य बैंक	48725	49758	49362	49287	49452	49559	49701
2.1.1.8 अन्य	545400	407378	544469	504228	502137	533728	479121
2.1.1.9 भारत के बाहर के वित्तीय संस्थान	162944	132104	131364	150839	153956	155927	141119
2.1.2 अन्य देयताएं	1804747	1514949	1795429	1821931	1855035	1899261	1917383
2.1/2.2 कुल देयताएं या आस्तियां	**3587080**	**3128188**	**3519586**	**3510957**	**3557914**	**3612654**	**3620127**
2.2 आस्तियां							
2.2.1 नोट और सिक्के	11	11	13	12	14	15	14
2.2.2 विदेशों में धारित राशियाँ	1480408	1245172	1690591	1662873	1704888	1758981	1790736
2.2.3 ऋण और अग्रिम							
2.2.3.1 केन्द्र सरकार	-	-	-	-	-	-	-
2.2.3.2 राज्य सरकारें	2300	16470	31072	32993	26767	26802	13381
2.2.3.3 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	266021	93310	5921	7825	11850	6708	6968
2.2.3.4 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	-	-	-	-	-	-	-
2.2.3.5 भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	-	-	-	-	-	-	-
2.2.3.6 नाबार्ड	-	-	-	-	-	-	-
2.2.3.7 एक्जिम बैंक	-	-	-	-	-	-	-
2.2.3.8 अन्य	12398	3122	8593	8547	8541	8541	8547
2.2.3.9 भारत के बाहर की वित्तीय संस्थाएं	162650	131569	131306	151272	154678	156604	141402
2.2.4 खरीदे और भुनाए गए बिल							
2.2.4.1 आंतरिक	-	-	-	-	-	-	-
2.2.4.2 सरकारी खज़ाना बिल	-	-	-	-	-	-	-
2.2.5 निवेश	1365425	1400911	1321941	1320389	1319318	1318323	1317280
2.2.6 अन्य आस्तियां	297868	237622	330148	327046	331858	336680	341800
2.2.6.1 स्वर्ण	272028	228431	319664	316457	321074	325671	330135

* डेटा अनंतिम हैं।

सं. 3: भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा चलनिधि परिचालन

(₹ करोड़)

दिनांक	चलनिधि समायोजन सुविधा						स्थायी चलनिधि सुविधाएं	ओएमओ (एकमुश्त)		निवल अंतर्वेशन (+)/ अवशोषण (-) (1+3+5+7+9-2-4-6 -8)
	रेपो	रिवर्स रेपो	परिवर्तन-शील रेपो दर	परिवर्तन-शील रिवर्स रेपो दर	एमएसएफ	एसडीएफ		विक्रय	क्रय	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
जुला 1, 2024	-	-	-	4200	4418	73290	-	-	-	-73072
जुला 2, 2024	-	-	-	38227	4150	66906	-994	-	-	-101977
जुला 3, 2024	-	-	-	25145	4265	76547	851	-	-	-96576
जुला 4, 2024	-	-	-	33020	1937	48665	-709	-	-	-80457
जुला 5, 2024	-	-	-	61731	8267	90005	759	-	-	-142710
जुला 6, 2024	-	-	-	-	2566	61220	-	-	-	-58654
जुला 7, 2024	-	-	-	-	63	51508	-	-	-	-51445
जुला 8, 2024	-	-	-	22890	6474	75706	-	0	-	-92122
जुला 9, 2024	-	-	-	21310	1765	71134	92	485	-	-91072
जुला 10, 2024	-	-	-	10770	1735	69256	-	490	-	-78781
जुला 11, 2024	-	-	-	25006	2326	67682	-	860	-	-91222
जुला 12, 2024	-	-	-	9581	3064	143541	-	1570	-	-151628
जुला 13, 2024	-	-	-	-	204	56909	-	-	-	-56705
जुला 14, 2024	-	-	-	-	320	55552	-	-	-	-55232
जुला 15, 2024	-	-	-	37220	1854	52129	-	640	-	-88135
जुला 16, 2024	-	-	-	25009	6251	60632	-	820	-	-80210
जुला 17, 2024	-	-	-	-	4688	46819	-	-	-	-42131
जुला 18, 2024	-	-	-	45360	7927	43465	-974	335	-	-82207
जुला 19, 2024	-	-	-	33705	1276	72071	975	940	20	-104445
जुला 20, 2024	-	-	-	-	504	41100	-	-	-	-40596
जुला 21, 2024	-	-	-	-	83	32270	-	-	-	-32187
जुला 22, 2024	-	-	-	-	4545	47923	-	345	-	-43723
जुला 23, 2024	-	-	-	-	4635	51630	-	370	-	-47365
जुला 24, 2024	-	-	-	3860	3401	62865	-	-	-	-63324
जुला 25, 2024	-	-	-	-	2807	89489	-	1710	-	-88392
जुला 26, 2024	-	-	-	23420	2021	138026	-	1560	-	-160985
जुला 27, 2024	-	-	-	-	71	78287	-	-	-	-78216
जुला 28, 2024	-	-	-	-	92	77632	-	-	-	-77540
जुला 29, 2024	-	-	-	41785	716	63919	-	105	-	-105093
जुला 30, 2024	-	-	-	23855	468	50963	-	200	-	-74550
जुला 31, 2024	-	-	-	7000	2891	76182	-469	125	-	-80885

सं. 4: भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अमेरिकी डॉलर का क्रय/विक्रय

i) तटीय/ अपतटीय ओटीसी खंड में परिचालन

मद	2023-24	2023	2024	
		जुला	जून	जुला
	1	2	3	4
1 विदेशी मुद्रा का निवल क्रय/विक्रय (मिलियन अमेरिकी डॉलर) (1.1-1.2)	41271	3472	-2107	6934
1.1 क्रय (+)	194296	5315	15936	23569
1.2 विक्रय (-)	153025	1843	18043	16635
2 संविदा दर पर ₹ के बराबर (₹ करोड़)	339528	28535	-17688	57887
3 संचयी (मार्च के अंत से) (मिलियन अमेरिकी डॉलर)	41271	23051	-1532	5402
(₹ करोड़)	339528	189273	-13016	44872
4 माह के अंत में बकाया निवल वायदा विक्रय (-)/क्रय (+) (मिलियन अमेरिकी डॉलर)	-541	19468	-15835	-9100

ii) मुद्रा वायदा खंड में परिचालन

मद	2023-24	2023	2024	
		जुला	जून	जुला
	1	2	3	4
1 विदेशी मुद्रा का निवल क्रय/विक्रय (मिलियन अमेरिकी डॉलर) (1.1-1.2)	0	0	0	0
1.1 क्रय (+)	7930	0	2338	2144
1.2 विक्रय (-)	7930	0	2338	2144
2 माह के अंत में बकाया निवल मुद्रा वायदा विक्रय (-)/क्रय (+) (मिलियन अमेरिकी डॉलर)	-1080	0	-1974	-340

सं. 4ए: भारतीय रिज़र्व बैंक के बकाया वायदे का (अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार) परिपक्वता विश्लेषण (मिलियन अमेरिकी डॉलर)

मद	31 जुलाई 2024 तक		
	दीर्घ (+)	अल्प (-)	निवल (1-2)
	1	2	3
1. 1 माह तक	0	8700	-8700
2. 1 माह से अधिक और 3 माह तक	0	400	-400
3. 3 माह से अधिक और 1 वर्ष तक	0	0	0
4. 1 वर्ष से अधिक	0	0	0
कुल (1+2+3+4)	**0**	**9100**	**-9100**

सं. 5: भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थायी सुविधाएं

रिपोर्टिंग अंतिम शुक्रवार की स्थिति (₹ करोड़)

मद	2023-24	2023	2024					
		अग 25	मार्च 22	अप्रै 19	मई 31	जून 28	जुला 26	अग 23
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 सीमांत स्थायी सुविधा	49906	73658	49906	3238	14601	46848	2021	1818
2 अनुसूचित बैंकों के लिए निर्यात ऋण पुर्नवित्त								
2.1 सीमा	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 बकाया	-	-	-	-	-	-	-	-
3 प्राथमिक व्यापारियों के लिए चलनिधि सुविधा								
3.1 सीमा	9900	4900	9900	9900	9900	9900	9900	9900
3.2 बकाया	9810	3122	9810	8770	9311	9061	9062	8541
4 अन्य								
4.1 सीमा	76000	76000	76000	76000	76000	76000	76000	76000
4.2 बकाया	-	-	-	-	-	-	-	-
5 कुल बकाया (1+2.2+3.2+4.2)	59716	76780	59716	12008	23912	55909	11083	10359

मुद्रा और बैंकिंग

सं. 6: मुद्रा स्टॉक मात्रा

(₹ करोड़)

मद	मार्च 31 /माह के रिपोर्टिंग अंतिम शुक्रवार/रिपोर्टिंग शुक्रवार की बकाया स्थिति				
	2023-24	**2023**	**2024**		
		जुला 28	जून 28	जुला 12	जुला 26
	1	2	3	4	5
1 जनता के पास मुद्रा (1.1 + 1.2 + 1.3 - 1.4)	3410276	3215903	3446055	3468893	3426089
1.1 संचलन में नोट	3477795	3293330	3528333	3539912	3502389
1.2 रुपये सिक्के का संचलन	32689	30405	33322	33322	33563
1.3 छोटे सिक्कों का संचलन	743	743	743	743	743
1.4 बैंकों के पास नकदी	101185	108660	116948	105513	111091
2 जनता की जमाराशियाँ	2681424	2469202	2842003	2625539	2678638
2.1 बैंकों के पास मांग जमाराशियाँ	2586888	2398078	2746237	2533569	2587413
2.2 रिजर्व बैंक के पास 'अन्य' जमाराशियाँ	94536	71123	95766	91971	91225
3 एम1 (1+2)	**6091700**	**5685104**	**6288057**	**6094432**	**6104726**
4 डाकघर बचत बैंक जमाराशियाँ	225927	208417	225927	225927	225927
5 एम2 (3+4)	**6317627**	**5893521**	**6513984**	**6320359**	**6330653**
6 बैंकों के पास मीयादी जमाराशियाँ	18739918	17574391	19413975	19520094	19485726
	(18848160)	(17724850)	(19503372)	(19606801)	(19568928)
7 एम3 (3+6)	24831618	23259495	25702033	25614526	25590453
	(24939860)	(23409955)	(25791429)	(25701233)	(25673654)
8 कुल डाकघर जमाराशियाँ	1298623	1202947	1298623	1298623	1298623
9 एम4 (7+8)	26130241	24462442	27000656	26913149	26889076
	(26238483)	(24612902)	(27090052)	(26999856)	(26972277)

कोष्ठक में दिए गए आंकड़ों में एक गैर-बैंक के बैंक में विलय का प्रभाव शामिल है।

सं. 7: मुद्रा भंडार (एम$_3$) के स्रोत

(₹ करोड़)

स्रोत	मार्च 31 / माह के रिपोर्टिंग अंतिम शुक्रवार/रिपोर्टिंग शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया				
	2023-24	2023	2024		
		जुला 28	जून 28	जुला 12	जुला 26
	1	2	3	4	5
1 सरकार को निवल बैंक ऋण	**7512016**	**7224878**	**7424141**	**7629016**	**7612861**
1 सरकार को निवल बैंक ऋण (विलय सहित)	(7603571)	(7337446)	(7489485)	(7694364)	(7678213)
1.1 आरबीआई का सरकार को निवल ऋण (1.1.1-1.1.2)	1193213	1197085	1026142	1081536	1060910
1.1.1 सरकार पर दावे	1370428	1415005	1355438	1362848	1341836
1.1.1.1 केन्द्र सरकार	1363828	1401096	1348151	1346488	1320596
1.1.1.2 राज्य सरकारें	6600	13909	7286	16359	21239
1.1.2 आरबीआई के पास सरकार की जमाराशियाँ	177215	217920	329296	281311	280926
1.1.2.1 केन्द्र सरकार	177172	217877	329254	281269	280883
1.1.2.2 राज्य सरकारें	42	42	42	42	42
1.2 सरकार को अन्य बैंक ऋण	6318803	6027793	6397999	6547480	6551951
1.2 सरकार को अन्य बैंक ऋण (विलय सहित)	(6410358)	(6140360)	(6463344)	(6612828)	(6617302)
2 वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक ऋण	**16672145**	**14915606**	**17144910**	**17081633**	**17084181**
2 वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक ऋण (विलय सहित)	(17202832)	(15525886)	(17645141)	(17576178)	(17577818)
2.1 आरबीआई का वाणिज्यिक क्षेत्र को ऋण	14406	5144	10922	11107	10935
2.2 वाणिज्यिक क्षेत्र को अन्य बैंकों द्वारा दिया गया ऋण	16657739	14910462	17133988	17070526	17073246
2.2 वाणिज्यिक क्षेत्र को अन्य बैंक ऋण (विलय सहित)	(17188426)	(15520742)	(17634219)	(17565071)	(17566883)
2.2.1 वाणिज्यिक बैंकों द्वारा बैंक ऋण	15901477	14176844	16381945	16317573	16320298
2.2.1 वाणिज्यिक बैंकों द्वारा बैंक ऋण (विलय सहित)	(16432164)	(14787123)	(16882176)	(16812117)	(16813935)
2.2.2 सहकारी बैंकों द्वारा बैंक ऋण	738194	716715	733421	734189	733892
2.2.3 वाणिज्यिक और सहकारी बैंकों द्वारा अन्य प्रतिभूतियों में निवेश	18068	16904	18621	18765	19056
2.2.3 वाणिज्यिक और सहकारी बैंकों द्वारा अन्य प्रतिभूतियों में निवेश (विलय सहित)	(18068)	(16904)	(18621)	(18765)	(19056)
3 बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां (3.1 + 3.2)	**5543700**	**5042528**	**5589632**	**5721304**	**5736662**
3.1 आरबीआई की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां (3.1.1-3.1.2)	5240824	4799704	5286756	5418428	5433786
3.1.1 सकल विदेशी आस्तियां	5241083	4799965	5287015	5418686	5434044
3.1.2 विदेशी देयताएं	259	262	259	259	259
3.2 अन्य बैंकों की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	302876	242825	302876	302876	302876
4 जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं	**33432**	**31148**	**34065**	**34065**	**34306**
5 बैंकिंग क्षेत्र की निवल गैर-मौद्रिक देयताएं	**4929674**	**3954665**	**4490716**	**4851492**	**4877557**
5 बैंकिंग क्षेत्र की निवल गैर-मौद्रिक देयताएं (विलय सहित)	(5443674)	(4527053)	(4966894)	(5324678)	(5353343)
5.1 आरबीआई की निवल गैर-मौद्रिक देयताएं	1789875	1543892	1631572	1718864	1718379
5.2 अन्य बैंकों की निवल गैर-मौद्रिक देयताएं (अवशिष्ट)	3139799	2410773	2859144	3132628	3159178
5.2 अन्य बैंकों की निवल गैर-मौद्रिक देयताएं (अवशिष्ट) (विलय सहित)	(3653798)	(2983160)	(3335322)	(3605814)	(3634964)
एम$_3$ (1+2+3+4-5)	**24831618**	**23259495**	**25702033**	**25614526**	**25590453**
एम$_3$ (1+2+3+4-5) (विलय सहित)	(24939860)	(23409955)	(25791429)	(25701233)	(25673654)

कोष्ठक में दिए गए आंकड़ों में एक गैर-बैंक के बैंक में विलय का प्रभाव शामिल है।

सं. 8: मौद्रिक सर्वेक्षण

(₹ करोड़)

मद	मार्च 31/माह के रिपोर्टिंग अंतिम शुक्रवार/रिपोर्टिंग शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया				
	2023-24	2023	2024		
		जुला 28	जून 28	जुला 12	जुला 26
	1	2	3	4	5
समग्र मौद्रिक राशियाँ					
एनएम$_1$ (1.1 + 1.2.1+1.3)	6091700	5685104	6288057	6094432	6104726
एनएम$_2$ (एनएम$_1$ + 1.2.2.1)	14424855	13513039	14915799	14768110	14761845
एनएम$_2$ (एनएम$_1$ + 1.2.2.1) (विलय सहित)	(14473564)	(13580746)	(14956028)	(14807128)	(14799285)
एनएम$_3$ (एनएम$_2$ + 1.2.2.2 + 1.4 = 2.1 + 2.2 + 2.3 - 2.4 - 2.5)	25387764	23864857	26225278	26254050	26277956
एनएम$_3$ (एनएम$_2$ + 1.2.2.2 + 1.4 = 2.1 + 2.2 + 2.3 - 2.4 - 2.5) (विलय सहित)	(25496006)	(24015316)	(26314675)	(26340757)	(26361158)
1 घटक					
1.1 जनता के पास मुद्रा	3410276	3215903	3446055	3468893	3426089
1.2. निवासियों की कुल जमाराशियाँ	21105009	19793489	21918997	21808409	21825453
1.2. निवासियों की कुल जमाराशियाँ (विलय सहित)	(21213252)	(19943948)	(22008393)	(21895116)	(21908655)
1.2.1 मांग जमाराशियाँ	2586888	2398078	2746237	2533569	2587413
1.2.2 निवासियों की सावधि जमाराशियाँ	18518121	17395411	19172760	19274840	19238040
1.2.2 निवासियों की सावधि जमाराशियाँ (विलय सहित)	(18626364)	(17545870)	(19262157)	(19361548)	(19321242)
1.2.2.1 अल्पावधि सावधि जमाराशियाँ	8333155	7827935	8627742	8673678	8657118
1.2.2.1 अल्पावधि सावधि जमाराशियाँ (विलय सहित)	(8381864)	(7895642)	(8667971)	(8712696)	(8694559)
1.2.2.1.1 जमा प्रमाण-पत्र (सीडी)	369399	303075	407354	418531	420069
1.2.2.2 दीर्घावधि सावधि जमाराशियाँ	10184967	9567476	10545018	10601162	10580922
1.2.2.2 दीर्घावधि सावधि जमाराशियाँ (विलय सहित)	(10244500)	(9650229)	(10594186)	(10648851)	(10626683)
1.3 आरबीआई के पास 'अन्य' जमाराशियाँ	94536	71123	95766	91971	91225
1.4 वित्तीय संस्थाओं से मांग/सावधि निधीयन	777942	784342	764461	884777	935190
2 स्रोत					
2.1 देशी ऋण	25295986	23278576	26017302	25825273	25825974
2.1 देशी ऋण (विलय सहित)	(25918227)	(24001423)	(26582877)	(26385167)	(26384962)
2.1.1 सरकार को निवल बैंक ऋण	7512016	7224878	7424141	7629016	7612861
2.1.1 सरकार को निवल बैंक ऋण (विलय सहित)	(7603571)	(7337446)	(7489485)	(7694364)	(7678213)
2.1.1.1 सरकार को निवल आरबीआई ऋण	1193213	1197085	1026142	1081536	1060910
2.1.1.2 बैंकिंग प्रणाली द्वारा सरकार को ऋण	6318803	6027793	6397999	6547480	6551951
2.1.1.2 बैंकिंग प्रणाली द्वारा सरकार को ऋण (विलय सहित)	(6410358)	(6140360)	(6463344)	(6612828)	(6617302)
2.1.2 वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक ऋण	17783970	16053697	18593161	18196257	18213113
2.1.2 वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक ऋण (विलय सहित)	(18314656)	(16663977)	(19093392)	(18690802)	(18706750)
2.1.2.1 वाणिज्यिक क्षेत्र को आरबीआई ऋण	14406	5144	10922	11107	10935
2.1.2.2 बैंकिंग प्रणाली द्वारा वाणिज्यिक क्षेत्र को ऋण	17769564	16048553	18582239	18185151	18202178
2.1.2.2 बैंकिंग प्रणाली द्वारा वाणिज्यिक क्षेत्र को ऋण (विलय सहित)	(18300250)	(16658833)	(19082470)	(18679695)	(18695815)
2.1.2.2.1 अन्य निवेश (गैर-एसएलआर प्रतिभूतियां)	1089184	1119528	1432378	1096760	1112229
2.2 जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं	33432	31148	34065	34065	34306
2.3 बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	5110820	4837647	5180164	5282474	5304164
2.3.1 आरबीआई की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	5240824	4799704	5286756	5418428	5433786
2.3.2 बैंकिंग प्रणाली की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	-130004	37943	-106593	-135954	-129622
2.4 पूंजी खाता	3912897	3932845	4258925	4310491	4317778
2.5 अन्य मदें (निवल)	1653576	922057	1223505	1050458	1044496

कोष्ठक में दिए गए आंकड़ों में एक गैर-बैंक के बैंक में विलय का प्रभाव शामिल है।

सं. 9: चलनिधि समग्र राशियाँ

(₹ करोड़)

समग्र राशियाँ	2023-24	2023	2024		
		जूल	मई	जून	जूल
	1	2	3	4	5
1 एनएम$_3$	**25387764**	**23864857**	**26023034**	**26225278**	**26277956**
	(25496006)	(24015316)	(26118212)	(26314675)	(26361158)
2 डाकघर जमाराशियाँ	729246	684023	729246	729246	729246
3 एल$_1$ (1 + 2)	**26117010**	**24548880**	**26752280**	**26954524**	**27007202**
	(26225252)	(24699339)	(26847458)	(27043921)	(27090404)
4 वित्तीय संस्थाओं की देयताएं	85150	73298	72510	68179	68324
4.1 सावधि मुद्रा उधार	2375	1107	1324	748	748
4.2 जमा प्रमाण-पत्र	70245	62185	58570	54670	54670
4.3 सावधि जमाराशियाँ	12531	10006	12616	12761	12905
5 एल$_2$ (3 + 4)	**26202160**	**24622178**	**26824789**	**27022704**	**27075526**
	(26310403)	(24772637)	(26919968)	(27112100)	(27158728)
6 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के पास जनता की जमाराशियाँ	102994	..	..	102994	..
7 एल$_3$ (5 + 6)	**26305155**	**..**	**..**	**27125698**	**..**

टिप्पणी : 1. संभव है कि पूर्णांकन के कारण कॉलम के आंकड़ों का जोड़ कुल के बराबर न हो।
2. कोष्ठक में दिए गए आंकड़ों में एक गैर-बैंक के बैंक में विलय का प्रभाव शामिल है।

सं. 10: भारतीय रिज़र्व बैंक सर्वेक्षण

(₹ करोड़)

मद	मार्च 31/माह के रिपोर्टिंग अंतिम शुक्रवार/रिपोर्टिंग शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया				
	2023-24	2023	2024		
		जुला 28	जून 28	जुला 12	जुला 26
	1	2	3	4	5
1 घटक					
1.1 संचलन में मुद्रा	3511461	3324563	3563002	3574406	3537180
1.2 आरबीआई के पास बैंकरों की जमाराशियाँ	1025449	959639	1036368	1014996	1039059
1.2.1 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	956011	899279	973455	952094	976073
1.3 आरबीआई के पास 'अन्य' जमाराशियाँ	94536	71123	95766	91971	91225
आरक्षित मुद्रा (1.1+1.2+1.3=2.1+2.2+2.3-2.4-2.5)	4631446	4355324	4695137	4681373	4667464
2 स्रोत					
2.1 आरबीआई के देशी ऋण	1147066	1068365	1005887	947743	917751
2.1.1 सरकार को निवल आरबीआई ऋण	1193213	1197085	1026142	1081536	1060910
2.1.1.1 केन्द्र सरकार को निवल आरबीआई ऋण (2.1.1.1.1+2.1.1.1.2+2.1.1.1.3+2.1.1.1.4-2.1.1.1.5)	1186655	1183219	1018898	1065219	1039713
2.1.1.1.1 केन्द्र सरकार को ऋण और अग्रिम	-	-	-	-	-
2.1.1.1.2 खज़ाना बिलों में निवेश	-	-	-	-	-
2.1.1.1.3 दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	1363369	1400820	1347914	1346159	1320373
2.1.1.1.3.1 केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियां	1363369	1400820	1347914	1346159	1320373
2.1.1.1.4 रुपया सिक्के	459	276	237	330	223
2.1.1.1.5 केन्द्र सरकार की जमाराशियाँ	177172	217877	329254	281269	280883
2.1.1.2 राज्य सरकारों को निवल आरबीआई ऋण	6557	13866	7244	16317	21197
2.1.2 बैंकों पर आरबीआई के दावे	-60553	-133864	-31176	-144900	-154094
2.1.2.1 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को ऋण और अग्रिम	-60553	-133864	-31176	-144900	-154094
2.1.3 वाणिज्यिक क्षेत्र को आरबीआई के ऋण	14406	5144	10922	11107	10935
2.1.3.1 प्राथमिक व्यापारियों को ऋण और अग्रिम	9358	3082	9061	9061	9062
2.1.3.2 नाबार्ड को ऋण और अग्रिम	-	-	-	-	-
2.2 जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं	33432	31148	34065	34065	34306
2.3 आरबीआई की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	5240824	4799704	5286756	5418428	5433786
2.3.1 स्वर्ण	439319	369359	471350	490045	483062
2.3.2 विदेशी मुद्रा आस्तियां	4801522	4430362	4815423	4928400	4950741
2.4 पूंजी खाता	1589134	1685487	1728614	1789370	1774642
2.5 अन्य मदें (निवल)	200741	-141594	-97042	-70506	-56263

सं. 11: आरक्षित मुद्रा - घटक और स्रोत

(₹ करोड़)

मद	2023-24	मार्च 31/माह के रिपोर्टिंग अंतिम शुक्रवार/रिपोर्टिंग शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया					
		2023	2024				
		जुला 28	जून 28	जुला 5	जुला 12	जुला 19	जुला 26
	1	2	3	4	5	6	7
आरक्षित मुद्रा (1.1 + 1.2 + 1.3 = 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 - 2.6)	4631446	4355324	4695137	4717510	4681373	4714625	4667464
1 घटक							
1.1 संचलन में मुद्रा	3511461	3324563	3563002	3571740	3574406	3554532	3537180
1.2 भा.रि.बैं. के पास बैंकरों की जमाराशियाँ	1025449	959639	1036368	1053615	1014996	1069565	1039059
1.3 भा.रि.बैं. के पास 'अन्य' जमाराशियाँ	94536	71123	95766	92154	91971	90528	91225
2 स्रोत							
2.1 सरकार को निवल रिज़र्व बैंक ऋण	1193213	1197085	1026142	1141339	1081536	1062945	1060910
2.2 बैंकों को रिज़र्व बैंक ऋण	-60553	-133864	-31176	-137576	-144900	-108935	-154094
2.3 वाणिज्यिक क्षेत्र को रिज़र्व बैंक ऋण	14406	5144	10922	11030	11107	11120	10935
2.4 भा.रि.बैं. की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	5240824	4799704	5286756	5334956	5418428	5459293	5433786
2.5 जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं	33432	31148	34065	34065	34065	34065	34306
2.6 भा.रि.बैं. की निवल गैर मौद्रिक देयताएं	1789875	1543892	1631572	1666304	1718864	1743863	1718379

सं. 12: वाणिज्यिक बैंक सर्वेक्षण

(₹ करोड़)

मद	माह के रिपोर्टिंग अंतिम शुक्रवार / माह के रिपोर्टिंग शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया				
	2023-24	2023	2024		
		जुला 28	जून 28	जुला 12	जुला 26
	1	2	3	4	5
1 घटक					
1.1 निवासियों की कुल जमाराशियाँ	20145188	18837513	20955209	20845356	20862822
	(20253430)	(18987973)	(21044606)	(20932064)	(20946024)
1.1.1 मांग जमाराशियाँ	2443853	2257972	2601677	2390322	2444220
1.1.2 निवासियों की सावधि जमाराशियाँ	17701334	16579541	18353531	18455034	18418602
	(17809577)	(16730001)	(18442928)	(18541742)	(18501804)
1.1.2.1 अल्पावधि सावधि जमाराशियाँ	7965600	7460794	8259089	8304765	8288371
1.1.2.1.1 जमा प्रमाण-पत्र (सीडी)	369399	303075	407354	418531	420069
1.1.2.2 दीर्घावधि सावधि जमाराशियाँ	9735734	9118748	10094442	10150269	10130231
1.2 वित्तीय संस्थाओं से मांग/सावधि निधीयन	777942	784342	764461	884777	935190
2 स्रोत					
2.1 देशी ऋण	23019606	21033028	23914360	23665796	23688947
	(23641847)	(21755875)	(24479935)	(24225689)	(24247935)
2.1.1 सरकार को ऋण	6014054	5726039	6091725	6241235	6247305
	(6105610)	(5838607)	(6157070)	(6306583)	(6312657)
2.1.2 वाणिज्यिक क्षेत्र को ऋण	17005551	15306989	17822634	17424561	17441642
	(17536238)	(15917269)	(18322865)	(17919106)	(17935278)
2.1.2.1 बैंक ऋण	15901477	14176844	16381945	16317573	16320298
	(16432164)	(14787123)	(16882176)	(16812117)	(16813935)
2.1.2.1.1 गैर-खाद्यान्न ऋण	15878397	14156007	16348042	16287310	16292108
	(16409083)	(14766287)	(16848272)	(16781855)	(16785745)
2.1.2.2 प्राथमिक व्यापारियों को निवल ऋण	22904	18826	16136	18128	16966
2.1.2.3 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश	949	753	1137	1063	1111
2.1.2.4 अन्य निवेश (गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों में)	1080222	1110566	1423416	1087798	1103267
2.2 वाणिज्यिक बैंकों की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां (2.2.1-2.2.2-2.2.3)	-130004	37943	-106593	-135954	-129622
2.2.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	241661	328316	304848	274230	284197
2.2.2 अनिवासी विदेशी मुद्रा प्रत्यावर्तनीय मीयादी जमाराशियाँ	221796	178980	241215	245254	247686
2.2.3 ओवरसीज़ विदेशी मुद्रा उधार	149868	111393	170226	164931	166133
2.3 निवल बैंक रिज़र्व (2.3.1+2.3.2-2.3.3)	893350	1130067	1109609	1190784	1229518
2.3.1 भा.रि.बैं. के पास शेष	931483	899279	973455	952094	976073
2.3.2 उपलब्ध नकदी	89433	96924	104977	93790	99350
2.3.3 भा.रि.बैं. से ऋण और अग्रिम	127566	-133864	-31176	-144900	-154094
2.4 पूंजी खाता	2299592	2223187	2506141	2496950	2518965
2.5 अन्य मदें (निवल) (2.1+2.2+2.3-2.4-1.1-1.2)	560230	355996	691565	493542	471866
2.5.1 अन्य मांग और मीयादी देयताएं (2.2.3 का निवल)	787560	709381	759345	721487	732752
2.5.2 निवल अंतर-बैंक देयताएं (प्राथमिक व्यापारियों से इतर)	197781	175419	148239	159658	149681

कोष्ठक में दिए गए आंकड़ों में एक गैर-बैंक के बैंक में विलय का प्रभाव शामिल है।

सं. 13: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के निवेश

(₹ करोड़)

मद	22 मार्च, 2024 की स्थिति	2023	2024		
		जुला 28	जून 28	जुला 12	जुला 26
	1	2	3	4	5
1 एसएलआर प्रतिभूतियां	6106558	5839360	6158207	6307646	6313767
	(6015003)	(5726793)	(6092862)	(6242298)	(6248416)
2 अन्य सरकारी प्रतिभूतियाँ (गैर-एसएलआर)	177136	180324	157944	157987	157537
3 वाणिज्यिक पत्र	61175	54410	51636	48177	52091
4 निम्नलिखित द्वारा जारी शेयर					
4.1 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम	8475	9178	13259	12415	12950
4.2 निजी कॉरपोरेट क्षेत्र	77722	84154	92861	93269	93730
4.3 अन्य	5624	5454	7014	7180	7367
5 निम्नलिखित द्वारा जारी बांड / डिबेंचर					
5.1 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम	103070	89456	119057	114158	121092
5.2 निजी कॉरपोरेट क्षेत्र	287596	291299	248618	245204	242161
5.3 अन्य	124690	108987	134187	138703	138806
6 निम्नलिखित द्वारा जारी लिखत					
6.1 म्यूचुअल फंड	62499	92914	66115	93133	96391
6.2 वित्तीय संस्थाएं	172340	194388	178493	177572	181142

टिप्पणी : कॉलम सं. (1), (2) व (3)में दिया गया डेटा अंतिम है और कॉलम सं.(4) व (5)में दिया गया डेटा अनंतिम है।

1. 14 जुलाई 2023 के बाद के डेटा में, एक गैर-बैंक के बैंक के साथ विलय के प्रभाव शामिल हैं।
2. कोष्ठक में दिए गए आंकड़ों में विलय के प्रभाव शामिल नहीं है।

सं. 14: भारत में कारोबार - सभी अनुसूचित बैंक और सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक

(₹ करोड़)

मद	अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार (मार्च के संबंध में) / अंतिम शुक्रवार की स्थिति							
	सभी अनुसूचित बैंक				सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक			
	2023-24	2023	2024		2023-24	2023	2024	
		जुला	जून	जुला		जुला	जून	जुला
	1	2	3	4	5	6	7	8
रिपोर्टिंग बैंकों की संख्या	210	212	208	208	137	137	135	135
1 बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं	**554117**	**509583**	**512993**	**499880**	**549351**	**506511**	**508633**	**495504**
1.1 बैंकों से माँग और मीयादी जमाराशियाँ	298452	249424	285944	285333	294471	247165	281871	281245
1.2 बैंकों से उधार राशि	182566	193383	150174	138779	182429	193269	150168	138752
1.3 अन्य माँग और मीयादी देयताएं	73100	66776	76875	75768	72452	66077	76594	75507
2 अन्य के प्रति देयताएं	**22664868**	**21232155**	**23454519**	**23497836**	**22190597**	**20772069**	**22979527**	**23027785**
2.1 कुल जमाराशियाँ	20932067	19609571	21743132	21647188	20475226	19166953	21285496	21193710
	(20823825)	(19459112)	(21653735)	(21563986)	(20366984)	(19016494)	(21196099)	(21110508)
2.1.1 माँग	2492916	2303947	2651692	2493057	2443853	2257972	2601677	2444220
2.1.2 मीयादी	18439151	17305624	19091439	19154131	18031373	16908981	18683818	18749490
2.2 उधार	782260	789050	768687	939516	777942	784342	764461	935190
2.3 अन्य माँग और मीयादी देयताएं	950541	833534	942700	911133	937428	820774	929570	898885
3 रिज़र्व बैंक से उधार	**222716**	**45028**	**102741**	**7161**	**222716**	**45028**	**102741**	**7161**
3.1 मीयादी बिल / वचन पत्रों की जमानत पर	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 अन्य	222716	45028	102741	7161	222716	45028	102741	7161
4 उपलब्ध नकदी और रिज़र्व बैंक के पास शेषराशि	1043272	1018457	1100832	1097622	1020916	996203	1078433	1075424
4.1 उपलब्ध नकदी	91886	99358	107446	101784	89433	96924	104977	99350
4.2 रिज़र्व बैंक के पास शेषराशि	951386	919099	993386	995838	931483	899279	973455	976073
5 बैंकिंग प्रणाली के पास आस्तियां	**455057**	**413394**	**446434**	**430424**	**374474**	**349919**	**376205**	**362788**
5.1 अन्य बैंकों के पास शेषराशि	246384	234362	250069	241621	198327	191554	200204	192802
5.1.1 चालू खाते में	12010	13536	15362	11939	8971	10234	12536	9487
5.1.2 अन्य खातों में	234373	220826	234707	229681	189357	181319	187668	183315
5.2 माँग और अल्पसूचना पर मुद्रा	39614	38996	27374	28548	12355	22908	11606	13930
5.3 बैंकों को अग्रिम	51325	44273	51727	42711	48368	42737	50288	41613
5.4 अन्य आस्तियां	117734	95763	117264	117544	115424	92720	114106	114443
6 निवेश	**6256962**	**5985714**	**6310568**	**6464961**	**6106558**	**5839360**	**6158207**	**6313767**
	(6165407)	(5873147)	(6245223)	(6399609)	(6015003)	(5726793)	(6092862)	(6248416)
6.1 सरकारी प्रतिभूतियां	6249319	5979513	6302648	6456607	6105610	5838607	6157070	6312657
6.2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	7643	6201	7919	8354	949	753	1137	1111
7 बैंक ऋण	**16866336**	**15188521**	**17319966**	**17247802**	**16432164**	**14787123**	**16886029**	**16813935**
	(16335650)	(14578241)	(16819735)	(16754166)	(15901477)	(14176844)	(16385798)	(16320298)
7ए खाद्यान्न ऋण	75472	72807	84526	78811	23081	20836	33904	28190
7.1 ऋण, नकदी-ऋण और ओवरड्राफ्ट	16565348	14926259	16995175	16931204	16134303	14527984	16564523	16500433
7.2 देशी बिल - खरीदे गए	60471	43575	69416	68987	60467	43561	68064	67638
7.3 देशी बिल- भुनाए गए	199761	174526	214495	208216	197358	172106	213232	207073
7.4 विदेशी बिल - खरीदे गए	16662	18756	17139	16061	16412	18528	16909	15852
7.5 विदेशी बिल - भुनाए गए	24094	25405	23741	23334	23624	24944	23301	22940

टिप्पणी: कॉलम सं. (4) व (8) में दिया गया डेटा अनंतिम है।

1. जुलाई 2023 के बाद के डेटा में एक गैर-बैंक के बैंक के साथ विलय के प्रभाव शामिल हैं।
2. कोष्ठक में दिए गए आंकड़ों में विलय के प्रभाव शामिल नहीं है।

सं. 15: प्रमुख क्षेत्रों द्वारा सकल बैंक ऋण का विनियोजन

(₹ करोड़)

क्षेत्र	बकाया स्थिति				वृद्धि (%)	
	मार्च 22, 2024	2023	2024		वित्तीय वर्ष में अब तक	वर्ष-दर-वर्ष
		जुला 28	जून 28	जुला 26	2024-25	2024
	1	2	3	4	%	%
I. बैंक ऋण (II+III)	**16432164**	**14787123**	**16880782**	**16814792**	**2.3**	**13.7**
	(15901477)	(14176844)	(16380551)	(16321156)	(2.6)	(15.1)
II. खाद्यान्न ऋण	**23081**	**20836**	**33904**	**28190**	**22.1**	**35.3**
III. गैर-खाद्यान्न ऋण	**16409083**	**14766287**	**16846879**	**16786602**	**2.3**	**13.7**
	(15878397)	(14156007)	(16346648)	(16292966)	(2.6)	(15.1)
1. कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियां	**2071251**	**1826031**	**2159559**	**2155991**	**4.1**	**18.1**
2. उद्योग (सूक्ष्म और लघु, मध्यम और बड़े)	**3652804**	**3380957**	**3728156**	**3722147**	**1.9**	**10.1**
	(3635810)	(3363118)	(3712270)	(3705319)	(1.9)	(10.2)
2.1 सूक्ष्म और लघु	726315	644363	731625	729948	0.5	13.3
2.2 मध्यम	303998	270729	316322	317323	4.4	17.2
2.3 बड़े	2622490	2465866	2680209	2674877	2.0	8.5
3. सेवाएं	**4592227**	**4039465**	**4707069**	**4604567**	**0.3**	**14.0**
	(4490467)	(3917134)	(4616040)	(4518736)	(0.6)	(15.4)
3.1 परिवहन परिचालक	230175	204076	242193	237195	3.0	16.2
3.2 कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	25917	22790	26677	27353	5.5	20.0
3.3 पर्यटन, होटल और रेस्टरां	77513	72955	78351	78992	1.9	8.3
3.4 शिपिंग	7067	6977	7019	7075	0.1	1.4
3.5 विमानन	43248	39667	45360	44637	3.2	12.5
3.6 पेशेवर सेवाएं	167234	146789	172138	163442	-2.3	11.3
3.7 व्यापार	1025752	903950	1059459	1041017	1.5	15.2
3.7.1 थोक व्यापार[1]	538744	473895	557604	545116	1.2	15.0
3.7.2 खुदरा व्यापार	487008	430055	501856	495900	1.8	15.3
3.8 वाणिज्यिक स्थावर संपदा	469013	438109	483297	484531	3.3	10.6
	(400470)	(343708)	(421756)	(426515)	(6.5)	(24.1)
3.9 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (एनबीएफसी)[2] जिसमें से	1548027	1356108	1555496	1528856	-1.2	12.7
3.9.1 आवास वित्त कंपनियां (एचएफसी)	325626	320132	328232	322052	-1.1	0.6
3.9.2 सार्वजनिक वित्त संस्थाएं (पीएफआई)	226963	182924	197127	202991	-10.6	11.0
3.10 अन्य सेवाएं[3]	998281	848044	1037078	991468	-0.7	16.9
	(978198)	(834300)	(1018174)	(972972)	(-0.5)	(16.6)
4. व्यक्तिगत ऋण	**5331290**	**4833574**	**5486107**	**5529815**	**3.7**	**14.4**
	(4919468)	(4364342)	(5091342)	(5139980)	(4.5)	(17.8)
4.1 उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं	23713	22113	24123	24607	3.8	11.3
4.2 आवास	2718715	2491005	2798568	2810109	3.4	12.8
	(2331935)	(2052114)	(2427447)	(2443530)	(4.8)	(19.1)
4.3 मीयादी जमाराशि की जमानत पर अग्रिम	125239	110529	126533	120373	-3.9	8.9
4.4 शेयरों और बॉण्डों की जमानत पर व्यक्तियों को अग्रिम	8492	7566	9357	9422	10.9	24.5
4.5 क्रेडिट कार्ड बकाया	257016	225950	273044	275601	7.2	22.0
4.6 शिक्षा	119380	103401	121990	123066	3.1	19.0
4.7 वाहन ऋण	589251	531547	603829	618600	5.0	16.4
4.8 स्वर्ण आभूषण पर ऋण	102562	95344	123776	132536	29.2	39.0
4.9 अन्य व्यक्तिगत ऋण	1386921	1246120	1404889	1415500	2.1	13.6
	(1362113)	(1216369)	(1381337)	(1392327)	(2.2)	(14.5)
5. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र (मेमो)						
(i) कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियां[4]	2081856	1835737	2186829	2196939	5.5	19.7
(ii) सूक्ष्म और लघु उद्यम[5]	1974191	1748225	2020474	1998597	1.2	14.3
(iii) मध्यम उद्यम[6]	490703	434298	511467	511874	4.3	17.9
(iv) आवास	755222	765099	752911	748840	-0.8	-2.1
	(660572)	(663149)	(661668)	(633763)	(-4.1)	(-4.4)
(v) शिक्षा ऋण	62235	59932	61269	61523	-1.1	2.7
(vi) नवीकरणीय ऊर्जा	5991	4605	6279	7075	18.1	53.6
(vii) सामाजिक अवसंरचना	2613	2571	2949	2937	12.4	14.2
(viii) निर्यात ऋण	11774	12212	11721	12163	3.3	-0.4
(ix) अन्य	61336	52978	60871	58548	-4.5	10.5
(x) नेट पीएसएलसी- एसएफ /एमएफ सहित कमजोर वर्ग	1647778	1455992	1716930	1743686	5.8	19.8

टिप्पणियाँ:

(1) डेटा अनंतिम है। बैंक ऋण, खाद्य ऋण और गैर-खाद्य ऋण डेटा धारा-42 रिटर्न पर आधारित हैं, जिसमें सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (एससीबी) शामिल हैं, जबकि क्षेत्रीय गैर-खाद्य ऋण डेटा क्षेत्र वार और उद्योग वार बैंक क्रेडिट (एसआईबीसी) रिटर्न पर आधारित हैं जिसमें चुनिंदा बैंकों के लेखांकन के आधार पर महीने के आखिरी रिपोर्टिंग शुक्रवार से संबंधित सभी एससीबी द्वारा दिए गए कुल गैर-खाद्य ऋण के लगभग 95 प्रतिशत को शामिल किया गया है।

(2) 28 जुलाई 2023 के बाद के डेटा में एक गैर-बैंक के बैंक के साथ विलय का प्रभाव शामिल है। कोष्ठक में दिए गए आंकड़ों में विलय के प्रभाव शामिल नहीं है।

1. थोक व्यापार में खाद्य ऋण संघ के बाहर के खाद्य खरीद ऋण शामिल है।
2. एनबीएफसी के अंतर्गत एचएफसी, पीएफआई, माइक्रोफाइनेंस संस्थाएं (एमएफआई), स्वर्ण ऋण से जुड़ी एनबीएफसी और अन्य शामिल हैं।
3. "अन्य सेवाओं" के अंतर्गत म्यूचुअल फंड, एनबीएफसी और एमएफ के अलावा बैंकिंग व वित्त तथा अन्य सेवाएं जो सेवाओं के अंतर्गत अन्यत्र नहीं दर्शाए गए हैं।
4. प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत ''कृषि और संबद्ध गतिविधियां'' में प्राथमिकता क्षेत्र ऋण प्रमाणपत्र (पीएसएलसी) भी शामिल हैं।
5. प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत ''सूक्ष्म और लघु उद्यम'' में उद्योग और सेवा क्षेत्रों में सूक्ष्म और लघु उद्यमों को ऋण शामिल है और इसमें पीएसएलसी भी शामिल हैं।
6. प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत ''मध्यम उद्यम'' में उद्योग और सेवा क्षेत्रों में मध्यम उद्यमों को ऋण शामिल है।

सं. 16: सकल बैंक ऋण का उद्योग-वार विनियोजन

(₹ करोड़)

उद्योग	बकाया स्थिति				वृद्धि (%)	
	मार्च 22, 2024	2023	2024		वित्तीय वर्ष में अब तक	वर्ष-दर-वर्ष
		जुला 28	जून 28	जुला 26	2024-25	2024
	1	2	3	4	%	%
2 उद्योग (2.1 से 2.19)	3652804	3380957	3728156	3722147	1.9	10.1
	(3635810)	(3363118)	(3712270)	(3705319)	(1.9)	(10.2)
2.1 खनन और उत्खनन (कोयला सहित)	54166	51796	55600	54637	0.9	5.5
2.2 खाद्य प्रसंस्करण	208864	175680	206410	204970	-1.9	16.7
2.2.1 चीनी	26383	19344	24945	22622	-14.3	16.9
2.2.2 खाद्य तेल और वनस्पति	19700	17955	18123	18167	-7.8	1.2
2.2.3 चाय	5692	5513	5853	6049	6.3	9.7
2.2.4 अन्य	157089	132867	157490	158133	0.7	19.0
2.3 पेय पदार्थ और तंबाकू	31136	22886	30518	30398	-2.4	32.8
2.4 वस्त्र	256048	234904	255274	255052	-0.4	8.6
2.4.1 सूती वस्त्र	99199	90173	96345	94890	-4.3	5.2
2.4.2 जूट से बने वस्त्र	4280	3581	4245	4125	-3.6	15.2
2.4.3 मानव - निर्मित वस्त्र	45111	39612	45229	45737	1.4	15.5
2.4.4 अन्य वस्त्र	107458	101538	109456	110300	2.6	8.6
2.5 चमड़ा और चमड़े से बने उत्पाद	12588	11762	12621	12547	-0.3	6.7
2.6 लकड़ी और लकड़ी से बने उत्पाद	23839	21685	24222	24440	2.5	12.7
2.7 काग़ज़ और काग़ज़ से बने उत्पाद	46426	43725	47584	47826	3.0	9.4
2.8 पेट्रोलियम, कोयला उत्पाद और आण्विक ईंधन	132356	111125	150054	136958	3.5	23.2
2.9 रसायन और रासायनिक उत्पाद	249347	218487	254950	254822	2.2	16.6
2.9.1 उर्वरक	37569	32626	36925	34891	-7.1	6.9
2.9.2 औषधि और दवाइयां	81036	70962	81818	82303	1.6	16.0
2.9.3 पेट्रो केमिकल्स	23157	21050	25356	27879	20.4	32.4
2.9.4 अन्य	107584	93849	110852	109749	2.0	16.9
2.10 रबड़, प्लास्टिक और उनके उत्पाद	90420	82968	88917	89571	-0.9	8.0
2.11 कांच और कांच के सामान	12090	9580	12340	12423	2.7	29.7
2.12 सीमेन्ट और सीमेन्ट से बने उत्पाद	59757	57119	60571	60689	1.6	6.2
2.13 मूल धातु और धातु उत्पाद	384447	355567	398182	402690	4.7	13.3
2.13.1 लोहा और स्टील	273803	239594	281763	285042	4.1	19.0
2.13.2 अन्य धातु और धातु से बने उत्पाद	110645	115973	116419	117648	6.3	1.4
2.14 सभी अभियांत्रिकी	196643	184743	203490	204641	4.1	10.8
2.14.1 इलेक्ट्रानिक्स	43175	42954	45351	45156	4.6	5.1
2.14.2 अन्य	153468	141789	158139	159485	3.9	12.5
2.15 वाहन, वाहन के पुर्जे और परिवहन उपस्कर	113185	106565	113222	109182	-3.5	2.5
2.16 रत्न और आभूषण	84860	85993	84039	82939	-2.3	-3.6
2.17 निर्माण	133520	125938	137097	140382	5.1	11.5
2.18 इन्फ्रास्ट्रक्चर	1304096	1253131	1323860	1301069	-0.2	3.8
2.18.1 बिजली	644042	616494	646566	636923	-1.1	3.3
2.18.2 दूरसंचार	138192	130920	132542	129613	-6.2	-1.0
2.18.3 सड़क	318072	309873	335841	327542	3.0	5.7
2.18.4 हवाई अड्डा	7280	7782	7779	8004	9.9	2.8
2.18.5 बंदरगाह	6681	7882	6483	6331	-5.2	-19.7
2.18.6 रेलवे	13062	11447	13275	11834	-9.4	3.4
2.18.7 अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर	176767	168732	181374	180822	2.3	7.2
2.19 अन्य उद्योग	259016	227304	269206	296912	14.6	30.6

टिप्पणी : 28 जुलाई 2023 के बाद के डेटा में एक गैर-बैंक के बैंक के साथ विलय का प्रभाव शामिल है। कोष्ठक में दिए गए आंकड़ों में विलय के प्रभाव शामिल नहीं है।

सं. 17: भारतीय रिज़र्व बैंक में राज्य सहकारी बैंकों के खाते

(₹ करोड़)

मद	रिपोर्टिंग अंतिम शुक्रवार (मार्च के संबंध में)/अंतिम शुक्रवार/रिपोर्टिंग शुक्रवार की स्थिति								
	2023-24	2023	2024						
		जून 5	अप्रै. 19	अप्रै. 26	मई 03	मई 17	मई 31	जून 14	जून 28
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
रिपोर्टिंग बैंकों की संख्या	33	33	33	33	33	33	33	33	33
1 कुल जमाराशियाँ (2.1.1.2+2.2.1.2)	**138788.9**	**138579.7**	**137357.2**	**135856.4**	**137855.6**	**135672.9**	**135938.7**	**134828.9**	**133938.0**
2 मांग और मीयादी देयताएं									
2.1 मांग देयताएं	**30226.7**	**28185.3**	**28302.3**	**28654.1**	**29748.9**	**27309.7**	**28297.6**	**28943.0**	**27801.7**
2.1.1 जमाराशियाँ									
2.1.1.1 अंतर-बैंक	9101.3	6015.4	8096.3	7965.2	7934.7	7634.3	7482.3	7685.6	7904.7
2.1.1.2 अन्य	15000.4	15613.8	14869.0	14417.9	16196.2	14617.1	15241.7	15296.8	14567.8
2.1.2 बैंकों से उधार	130.0	439.8		679.5	499.7		154.9	179.9	
2.1.3 अन्य मांग देयताएं	5995.0	6116.4	5337.0	5591.5	5118.3	5058.3	5418.7	5780.7	5329.2
2.2 मीयादी देयताएं	**198141.8**	**182740.2**	**192115.1**	**189681.3**	**190499.2**	**189412.7**	**187897.4**	**185975.8**	**185708.9**
2.2.1 जमाराशियाँ									
2.2.1.1 अंतर-बैंक	72308.4	57869.2	67955.0	66557.0	66911.4	66378.9	65382.8	64573.2	64501.4
2.2.1.2 अन्य	123788.5	122965.9	122488.2	121438.5	121659.4	121055.8	120697.0	119532.1	119370.2
2.2.2 बैंकों से उधार	673.6	839.7	652.8	652.8	879.3	920.1	663.8	653.2	653.2
2.2.3 अन्य मीयादी देयताएं	1371.3	1065.4	1019.1	1033.0	1049.1	1057.9	1153.8	1217.2	1184.1
3 रिज़र्व बैंक से उधार	0.0				150.0			0.0	0.0
4 अधिसूचित बैंक/ सरकार से उधार	95914.5	73630.1	87425.2	86593.2	85136.5	84716.3	84175.6	84574.6	85281.4
4.1 मांग	27317.7	15253.8	24184.6	23967.7	23767.7	23507.7	23112.7	23242.7	23887.4
4.2 मीयादी	68596.8	58376.2	63240.6	62625.5	61368.8	61208.6	61062.9	61331.9	61394.0
5 उपलब्ध नकदी और रिज़र्व बैंक के पास शेषराशि	**16263.7**	**11981.9**	**13393.3**	**12135.1**	**13141.4**	**10494.5**	**12165.3**	**11435.2**	**13323.7**
5.1 उपलब्ध नकदी	960.0	845.0	874.7	777.3	819.5	853.6	714.6	770.9	759.4
5.2 रिज़र्व बैंक के पास शेषराशि	15303.7	11136.9	12518.6	11357.8	12321.9	9640.9	11450.7	10664.3	12564.3
6 चालू खाते में अन्य बैंकों के पास शेषराशि	**2088.1**	**2666.2**	**1725.5**	**1625.6**	**1573.3**	**1480.0**	**1528.5**	**1694.6**	**1631.9**
7 सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	**77700.5**	**72286.7**	**75605.0**	**75501.1**	**75604.0**	**76369.8**	**76376.5**	**76482.9**	**75500.4**
8 मांग और अल्प सूचना पर मुद्रा	**34355.3**	**19661.2**	**26097.0**	**23246.7**	**22827.2**	**22441.5**	**21180.5**	**19092.4**	**20740.5**
9 बैंक ऋण (10.1+11)	**135141.9**	**128006.9**	**134755.3**	**137382.4**	**137182.4**	**135776.2**	**135733.7**	**137026.6**	**134324.1**
10 अग्रिम									
10.1 ऋण, नकदी-ऋण और ओवरड्राफ्ट	**134936.8**	**127932.8**	**134570.3**	**137200.4**	**136992.2**	**135600.7**	**135524.3**	**136811.1**	**134111.9**
10.2 बैकों से प्राप्य राशि	142185.2	120521.3	136863.1	136586.9	135859.4	135411.7	136109.4	136794.5	135046.8
11 खरीदे और भुनाए गए बिल	205.1	74.2	185.0	182.0	190.2	175.5	209.4	215.5	212.2

कीमत और उत्पादन

सं. 18: उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार: 2012=100)

समूह/उप समूह	2023-24			ग्रामीण			शहरी			मिश्रित		
	ग्रामीण	शहरी	मिश्रित	अग 23	जुला 24	अग 24 (अ)	अग 23	जुला 24	अग 24 (P)	अग 23	जुला 24	अग 24 (अ)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 खाद्य और पेय पदार्थ	**185.9**	**192.7**	**188.4**	**189.5**	**200.4**	**200.2**	**197.6**	**208.3**	**207.0**	**192.5**	**203.3**	**202.7**
1.1 अनाज और उत्पाद	181.4	181.7	181.5	179.0	191.4	192.6	179.8	191.2	191.9	179.3	191.3	192.4
1.2 मांस और मछली	213.0	221.3	215.9	211.1	227.1	220.1	219.7	237.4	229.1	214.1	230.7	223.3
1.3 अंडा	185.4	189.5	187.0	174.2	192.5	188.1	180.1	197.2	190.7	176.5	194.3	189.1
1.4 दूध और उत्पाद	181.4	181.5	181.4	181.2	185.6	186.3	181.1	186.6	187.1	181.2	186.0	186.6
1.5 तेल और चर्बी	165.3	158.7	162.9	165.2	163.4	164.0	159.0	157.1	157.1	162.9	161.1	161.5
1.6 फल	172.1	179.9	175.7	174.2	181.4	186.1	186.2	192.4	197.4	179.8	186.5	191.4
1.7 सब्जी	183.9	229.9	199.5	216.4	248.8	245.0	272.3	303.4	291.0	235.4	267.3	260.6
1.8 दाल और उत्पाद	192.2	196.5	193.7	187.8	211.5	212.5	191.5	218.0	219.0	189.0	213.7	214.7
1.9 चीनी और उत्पाद	126.2	128.1	126.9	124.8	130.4	130.7	127.0	132.3	132.7	125.5	131.0	131.4
1.10 मसाले	238.0	228.4	234.8	242.1	229.4	229.5	231.4	225.0	224.9	238.5	227.9	228.0
1.11 गैर नशीले पेय पदार्थ	180.7	168.2	175.5	180.3	183.0	183.8	167.7	172.1	172.8	175.0	178.4	179.2
1.12 तैयार भोजन, नाश्ता, मिठाई	193.3	200.9	196.8	192.9	197.6	198.5	200.0	207.2	208.3	196.2	202.1	203.0
2 पान, तंबाकू और मादक पदार्थ	**202.0**	**207.1**	**203.3**	**201.7**	**206.5**	**206.8**	**206.7**	**212.9**	**213.1**	**203.0**	**208.2**	**208.5**
3 कपड़ा और जूते	**192.9**	**181.5**	**188.4**	**192.3**	**196.7**	**197.2**	**180.8**	**185.5**	**186.0**	**187.7**	**192.3**	**192.8**
3.1 कपड़ा	193.5	183.5	189.6	192.9	197.5	198.0	182.8	187.6	188.1	188.9	193.6	194.1
3.2 जूते	189.4	170.2	181.4	189.1	191.8	192.3	169.7	173.8	174.1	181.0	184.3	184.7
4 आवास	--	**176.7**	**176.7**	--	--	--	**176.4**	**180.0**	**181.1**	**176.4**	**180.0**	**181.1**
5 ईंधन और बिजली	**183.0**	**178.9**	**181.4**	**185.9**	**180.0**	**180.8**	**187.4**	**169.5**	**169.8**	**186.5**	**176.0**	**176.6**
6 विविध	**181.7**	**173.7**	**177.8**	**181.2**	**187.9**	**188.3**	**173.4**	**179.3**	**180.0**	**177.4**	**183.7**	**184.3**
6.1 घरेलू सामान और सेवा	181.5	171.8	176.9	181.3	184.3	184.9	171.3	175.6	176.4	176.6	180.2	180.9
6.2 स्वास्थ्य	190.8	185.2	188.7	189.8	196.5	197.3	184.3	191.4	192.2	187.7	194.6	195.4
6.3 परिवहन और संचार	171.1	161.4	166.0	171.1	175.5	176.0	161.2	164.8	165.3	165.9	169.9	170.4
6.4 मनोरंजन	175.8	171.1	173.2	175.6	179.0	179.6	170.8	174.2	174.8	172.9	176.3	176.9
6.5 शिक्षा	184.0	179.1	181.1	184.5	190.6	191.7	179.8	185.0	186.2	181.7	187.3	188.5
6.6 व्यक्तिगत देखभाल और संबंधित सामन	186.3	187.4	186.8	184.7	199.8	199.0	185.7	201.3	200.9	185.1	200.4	199.8
सामान्य सूचकांक (सभी समूह)	**185.6**	**182.4**	**184.1**	**187.6**	**195.3**	**195.4**	**184.5**	**190.3**	**190.3**	**186.2**	**193.0**	**193.0**

स्रोत : केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार।

अ: अनंतिम

सं. 19: अन्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

मद	आधार वर्ष	योजक कारक	2023-24	2023	2024	
				जुला	जून	जुला
	1	2	3	4	5	6
1 औद्योगिक कामगार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	2016	2.88	137.9	139.7	141.4	142.7
2 कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	1986-87	5.89	1229	1215	1280	1290
3 ग्रामीण श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	1986-87	-	1240	1226	1292	1302

स्रोत: श्रम ब्यूरो, श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार।

सं. 20: मुंबई में स्वर्ण और चांदी का मासिक औसत मूल्य

मद	2023-24	2023	2024	
		जुला	जून	जुला
	1	2	3	4
1 मानक स्वर्ण (₹ प्रति 10 ग्राम)	60624	58922	72014	71189
2 चांदी (₹ प्रति किलोग्राम)	72243	72945	88666	88058

स्रोत: मुंबई में स्वर्ण और चांदी के मूल्य के लिए इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन लि. मुंबई।

सं. 21: थोक मूल्य सूचकांक

(आधारः 2011-12=100)

पण्य वस्तुएँ	भार	2023-24	2023	2024		
			अग	जुन	जुला.(अ)	अग (अ)
	1	2	3	4	5	6
1 सभी पण्य	**100.000**	**151.4**	**152.5**	**154.0**	**155.2**	**154.5**
1.1 प्राथमिक वस्तुएं	**22.618**	**183.0**	**190.3**	**192.3**	**197.6**	**194.9**
1.1.1 खाद्य वस्तुएं	**15.256**	**191.3**	**202.8**	**205.5**	**213.0**	**209.1**
1.1.1.1 खाद्यान्न (अनाज+दाल)	3.462	193.8	190.1	206.6	208.1	209.7
1.1.1.2 फल और सब्जियाँ	3.475	210.2	263.6	245.4	276.9	259.1
1.1.1.3 दूध	4.440	180.3	179.6	185.5	186.0	185.9
1.1.1.4 अंडा, मांस और मछली	2.402	172.1	174.4	174.5	173.7	173.2
1.1.1.5 मसाले	0.529	235.4	251.7	237.2	237.2	237.0
1.1.1.6 अन्य खाद्य वस्तुएं	0.948	189.5	179.8	209.8	209.1	207.3
1.1.2 खाद्येतर वस्तुएं	**4.119**	**162.4**	**163.2**	**157.3**	**157.2**	**159.8**
1.1.2.1 फाइबर	0.839	168.0	170.6	160.2	164.2	160.6
1.1.2.2 तिलहन	1.115	185.0	187.8	180.0	179.8	177.7
1.1.2.3 अन्य खाद्येतर वस्तुएं	1.960	134.9	135.4	135.8	133.4	140.0
1.1.2.4 पुष्पोत्पादन	0.204	279.7	265.3	228.8	232.6	248.6
1.1.3 खनिज	**0.833**	**217.7**	**205.5**	**229.6**	**229.6**	**223.5**
1.1.3.1 धात्विक खनिज	0.648	204.2	189.0	225.4	225.4	212.4
1.1.3.2 अन्य खनिज	0.185	265.0	263.4	244.4	244.3	262.4
1.1.4 कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस	**2.410**	**153.6**	**152.3**	**156.0**	**157.9**	**155.0**
1.2 ईंधन और बिजली	**13.152**	**152.0**	**149.1**	**146.9**	**147.9**	**148.1**
1.2.1 कोयला	**2.138**	**136.4**	**137.6**	**135.8**	**135.6**	**135.6**
1.2.1.1 कुकिंग कोयला	0.647	143.4	143.4	143.4	143.4	143.4
1.2.1.2 नॉन-कुकिंग कोयला	1.401	124.8	125.8	125.8	125.8	125.8
1.2.1.3 लिग्नाइट	0.090	267.6	279.8	236.0	232.0	232.0
1.2.2 खनिज तेल	**7.950**	**159.0**	**157.6**	**155.7**	**157.4**	**156.9**
1.2.3 बिजली	**3.064**	**145.0**	**135.1**	**132.0**	**131.9**	**134.0**
1.3 विनिर्मित उत्पाद	**64.231**	**140.2**	**139.9**	**142.0**	**141.7**	**141.6**
1.3.1 खाद्य उत्पादों का विनिर्माण	**9.122**	**160.5**	**160.8**	**165.9**	**165.9**	**166.6**
1.3.1.1 मांस का परिरक्षण और प्रसंस्करण	0.134	145.3	143.0	157.2	156.6	153.7
1.3.1.2 मछली, क्रस्टेशियन, मोलस्क और उनके उत्पादों का प्रसंस्करण एवं परिरक्षण	0.204	142.9	144.0	143.8	141.9	147.1
1.3.1.3 फल और सब्जियों का परिरक्षण और प्रसंस्करण	0.138	130.4	132.3	132.1	131.9	131.8
1.3.1.4 सब्जियां और पशु तेल एवं चर्बी	2.643	145.0	147.5	148.4	149.2	150.2
1.3.1.5 डेयरी उत्पाद	1.165	179.1	178.8	180.1	179.2	178.5
1.3.1.6 अनाज मिल के उत्पाद	2.010	175.6	174.1	185.1	184.5	185.4
1.3.1.7 स्टार्च और स्टार्च के उत्पाद	0.110	157.1	150.3	165.6	168.9	173.2
1.3.1.8 बेकरी उत्पाद	0.215	165.4	164.3	166.0	166.1	167.3
1.3.1.9 चीनी, गुड़ और शहद	1.163	134.6	132.6	139.2	138.5	139.6
1.3.1.10 कोकोआ, चॉकलेट और चीनी कन्फेक्शनरी	0.175	139.8	137.9	153.3	155.8	157.1
1.3.1.11 मैक्रोनी, नूडल्स, और कूसकूस और उसके जैसे मैदे से बने उत्पाद	0.026	149.9	148.4	151.5	150.9	150.8
1.3.1.12 चाय और कॉफी उत्पाद	0.371	176.2	182.6	203.2	202.4	199.4
1.3.1.13 प्रसंस्कृत मसाले और नमक	0.163	192.1	189.6	193.6	191.1	192.9
1.3.1.14 प्रसंस्कृत तैयार खाद्य पदार्थ	0.024	146.3	146.2	152.9	152.1	151.1
1.3.1.15 स्वास्थ्य पूरक	0.225	179.1	179.2	176.3	184.6	186.2
1.3.1.16 पशु के लिए तैयार खाद्य	0.356	208.3	211.7	206.7	206.8	208.4
1.3.2 पेय पदार्थों का विनिर्माण	**0.909**	**131.5**	**131.4**	**133.4**	**133.6**	**133.9**
1.3.2.1 शराब और स्पिरीट	0.408	133.3	133.2	134.3	134.7	135.7
1.3.2.2 माल्ट लिकर और माल्ट	0.225	135.6	135.6	139.0	138.9	138.7
1.3.2.3 शीतल पेय, मिनरल वॉटर और बोतलबन्द पानी का उत्पादन	0.275	125.5	125.1	127.4	127.5	127.3
1.3.3 तंबाकू उत्पादों का विनिर्माण	**0.514**	**173.5**	**172.6**	**176.2**	**177.2**	**178.9**
1.3.3.1 तंबाकू के उत्पाद	0.514	173.5	172.6	176.2	177.2	178.9

सं. 21: थोक मूल्य सूचकांक (जारी)

(आधारः 2011-12=100)

पण्य वस्तुएँ	भार	2023-24	2023	2024		
			अग	जुन	जुला.(अ)	अग (अ)
	1	2	3	4	5	6
1.3.4 वस्त्र विनिर्माण	**4.881**	**134.6**	**134.1**	**136.4**	**136.7**	**136.5**
1.3.4.1 धागों की कताई और वस्त्र तैयार करना	2.582	120.1	119.8	122.1	122.5	122.5
1.3.4.2 बुनाई और तैयार वस्त्र	1.509	157.5	156.9	158.1	158.1	157.6
1.3.4.3 बुने हुए और क्रोशिए से बना कपड़ा	0.193	120.0	119.9	124.1	125.2	123.6
1.3.4.4 कपड़ों को छोड़कर निर्मित वस्त्र सामग्री	0.299	156.6	156.6	159.3	158.8	160.2
1.3.4.5 डोरियाँ, रस्सी, सुतली और नेटिंग	0.098	139.2	141.8	138.8	141.1	141.1
1.3.4.6 अन्य वस्त्र	0.201	129.6	124.5	135.1	133.1	133.7
1.3.5 तैयार वस्त्र का विनिर्माण	**0.814**	**150.8**	**150.6**	**152.3**	**152.1**	**152.8**
1.3.5.1 फर से बने वस्त्रों को छोड़कर, तैयार वस्त्र (बुने हुए) का विनिर्माण	0.593	148.7	149.0	150.3	150.1	150.2
1.3.5.2 बुने हुए और क्रोशिए से बने वस्त्र	0.221	156.6	154.8	157.6	157.4	159.7
1.3.6 चमड़ा और संबंधित उत्पाद का विनिर्माण	**0.535**	**124.1**	**125.5**	**124.6**	**124.5**	**124.7**
1.3.6.1 चमड़े की टैनिंग और ड्रेसिंग; ड्रेसिंग और फर की रंगाई	0.142	107.3	110.8	105.1	104.5	103.6
1.3.6.2 सामान, हैंडबैग, काठी और हार्नेस	0.075	140.9	140.9	141.8	141.6	142.9
1.3.6.3 जूते-चप्पल	0.318	127.7	128.4	129.2	129.4	129.9
1.3.7 लकड़ी व लकड़ी और कॉर्क के उत्पादों का विनिर्माण	**0.772**	**146.6**	**144.9**	**149.5**	**149.5**	**149.5**
1.3.7.1 आरा मिलिंग और लकड़ी के उत्पाद	0.124	137.8	137.6	139.6	139.8	140.8
1.3.7.2 विनियर शीट, प्लायवुड, लैमिन बोर्ड, पार्टिकल बोर्ड और अन्य पैनल और बोर्ड का विनिर्माण	0.493	146.1	143.8	149.3	149.2	149.0
1.3.7.3 बिल्डरों की बढ़ईगीरी	0.036	206.4	201.8	215.4	215.6	215.9
1.3.7.4 लकड़ी के डिब्बे	0.119	139.8	139.8	141.4	141.2	141.1
1.3.8 कागज़ और कागज़ के उत्पादों का विनिर्माण	**1.113**	**140.3**	**139.0**	**138.4**	**138.7**	**139.7**
1.3.8.1 लुगदी, कागज़ और पेपर बोर्ड	0.493	147.6	146.8	144.3	144.6	145.3
1.3.8.2 लहरदार कागज़ और पेपर बोर्ड और कागज़ के पात्र और पेपर बोर्ड	0.314	140.9	140.3	144.6	145.6	146.1
1.3.8.3 कागज़ की अन्य सामग्री और पेपर बोर्ड	0.306	128.0	125.1	122.6	121.9	124.1
1.3.9 मुद्रण और रिकार्डेड मीडिया का पुनरुत्पादन	**0.676**	**182.3**	**183.1**	**185.2**	**186.3**	**186.0**
1.3.9.1 मुद्रण	0.676	182.3	183.1	185.2	186.3	186.0
1.3.10 रसायन और रासायनिक उत्पादों का विनिर्माण	**6.465**	**136.9**	**136.3**	**136.4**	**136.8**	**136.6**
1.3.10.1 मूल रसायन	1.433	139.9	138.3	137.8	137.9	137.7
1.3.10.2 उर्वरक और नाइट्रोजन यौगिक	1.485	142.8	141.4	143.3	143.3	143.2
1.3.10.3 प्लास्टिक और प्राथमिक रूप में सिंथेटिक रबड़	1.001	132.3	132.8	134.1	135.3	134.2
1.3.10.4 कीटनाशक और अन्य एग्रोकेमिकल उत्पाद	0.454	132.8	132.9	128.0	128.6	128.8
1.3.10.5 पेन्ट, वार्निश और समान कोटिंग, मुद्रण स्याही और मैस्टिक्स	0.491	143.7	143.6	139.0	140.2	140.3
1.3.10.6 साबुन और डिटर्जेंट, सफाई और चमकाने की सामग्री, इत्र और शौचालय सफाई की सामग्री	0.612	139.7	140.1	139.0	138.9	138.9
1.3.10.7 अन्य रासायनिक उत्पाद	0.692	134.4	134.3	135.8	136.4	136.4
1.3.10.8 मानव निर्मित फाइबर	0.296	103.6	103.5	107.2	107.3	106.9
1.3.11 फार्मास्यूटिकल्स, औषधीय रसायन और वनस्पति उत्पाद का विनिर्माण	**1.993**	**142.9**	**141.8**	**144.0**	**144.7**	**144.6**
1.3.11.1 फार्मास्यूटिकल्स, औषधीय रसायन और वनस्पति उत्पाद	1.993	142.9	141.8	144.0	144.7	144.6
1.3.12 रबड़ और प्लास्टिक उत्पादों का विनिर्माण	**2.299**	**127.5**	**127.1**	**128.8**	**129.0**	**129.0**
1.3.12.1 रबड़ टायर और ट्यूब, रबड़ टायर की रिट्रीडिंग और पुनर्निर्माण	0.609	113.7	113.6	113.6	114.9	114.6
1.3.12.2 रबड़ के अन्य उत्पाद	0.272	107.3	106.7	110.4	112.1	112.7
1.3.12.3 प्लास्टिक उत्पाद	1.418	137.3	136.8	138.9	138.3	138.3
1.3.13 अन्य अधात्विक खनिज उत्पादों का विनिर्माण	**3.202**	**134.7**	**135.0**	**130.7**	**130.5**	**129.8**
1.3.13.1 कांच और कांच उत्पाद	0.295	163.8	163.0	162.7	163.5	163.2
1.3.13.2 आग रोधक उत्पाद	0.223	119.7	123.1	118.5	118.1	118.8
1.3.13.3 मिट्टी से बनी भवन निर्माण सामग्री	0.121	123.9	123.5	112.7	117.1	121.6
1.3.13.4 चीनी मिट्टी और चीनी मिट्टी के उत्पाद	0.222	122.3	121.8	124.4	124.6	124.6
1.3.13.5 सीमेन्ट, चूना और प्लास्टर	1.645	137.3	137.5	130.3	129.9	127.9

सं. 21: थोक मूल्य सूचकांक (जारी)

(आधारः 2011-12=100)

पण्य वस्तुएँ	भार	2023-24	2023	2024		
			अग	जुन	जुला.(अ)	अग (अ)
	1	2	3	4	5	6
1.3.13.6 कंक्रीट, सीमेन्ट और प्लास्टर से बनी वस्तुएं	0.292	137.7	138.4	139.7	138.4	138.2
1.3.13.7 पत्थरों को काटना, आकार देना और संवारना	0.234	130.3	130.7	132.3	132.8	133.7
1.3.13.8 अन्य अधात्विक खनिज उत्पाद	0.169	102.4	103.0	97.4	95.7	96.8
1.3.14 मूल धातुओं का विनिर्माण	**9.646**	**141.0**	**140.6**	**143.3**	**141.1**	**139.5**
1.3.14.1 स्टील तैयार करने में प्रयुक्त सामग्री	1.411	140.3	136.1	140.3	135.0	133.1
1.3.14.2 मेटेलिक आयरन	0.653	153.6	154.9	150.9	148.4	146.5
1.3.14.3 नरम इस्पात - अर्ध निर्मित इस्पात	1.274	119.9	120.7	121.7	119.2	117.8
1.3.14.4 नरम इस्पात - लंबे उत्पाद	1.081	141.3	140.8	143.6	140.2	138.9
1.3.14.5 नरम इस्पात - चपटे उत्पाद	1.144	143.4	141.8	140.6	139.6	137.0
1.3.14.6 स्टेनलेस स्टील के अतिरिक्त एलॉय स्टील-आकार	0.067	137.6	136.6	141.3	136.5	134.6
1.3.14.7 स्टेनलेस स्टील - अर्ध निर्मित	0.924	136.4	139.7	132.9	131.3	128.9
1.3.14.8 पाइप और ट्यूब	0.205	169.7	167.8	166.1	167.1	166.3
1.3.14.9 कीमती धातु सहित अलौह धातु	1.693	144.8	143.7	158.2	156.6	154.7
1.3.14.10 कास्टिंग	0.925	141.0	143.0	144.5	145.0	145.4
1.3.14.11 स्टील से गढ़ी वस्तुएं	0.271	173.3	174.5	174.4	171.4	170.7
1.3.15 मशीनरी और उपकरणों को छोड़कर गढ़े हुए धातु उत्पादों का विनिर्माण	**3.155**	**138.6**	**138.9**	**136.1**	**136.2**	**136.8**
1.3.15.1 इमारती धातु उत्पाद	1.031	132.3	133.3	130.4	130.9	131.2
1.3.15.2 धातु से बने टैंक, जलाशय और डिब्बे	0.660	157.6	158.3	151.6	151.4	152.0
1.3.15.3 वाष्प चालित जनरेटर, सेंट्रल हीटिंग हॉट वाटर बॉयलरर्स को छोड़कर	0.145	106.3	105.6	109.6	111.2	111.5
1.3.15.4 धातु की फोर्जिंग, दबाना, स्टैम्पिंग और रोल फॉरमिंग, पाउडर धातुकर्म	0.383	141.4	142.5	135.3	135.5	138.4
1.3.15.5 कटलरी, हस्त चालित उपकरण और सामान्य हार्डवेयर	0.208	108.4	108.5	101.5	101.7	101.9
1.3.15.6 अन्य गढ़े हुए धातु उत्पाद	0.728	143.8	142.5	145.8	145.2	145.1
1.3.16 कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक और ऑप्टिकल उत्पादों का विनिर्माण	**2.009**	**119.3**	**119.4**	**121.9**	**121.1**	**121.3**
1.3.16.1 इलेक्ट्रॉनिक पुरजे	0.402	115.0	115.6	117.7	117.6	117.4
1.3.16.2 कंप्यूटर और संबंधित उपकरण	0.336	135.3	135.1	135.3	136.0	136.2
1.3.16.3 संचार उपकरण	0.310	136.1	136.9	145.9	145.9	145.4
1.3.16.4 उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स	0.641	103.6	103.4	103.3	100.5	100.5
1.3.16.5 मापने, जांचने, नेविगेशन और नियंत्रण उपकरण	0.181	113.8	114.2	117.8	118.1	118.1
1.3.16.6 हाथ घड़ी और दीवार घड़ी	0.076	157.2	156.6	163.0	163.1	166.3
1.3.16.7 विभासन, विद्युत चिकित्सकीय एवं विद्युत उपचारात्मक उपकरण	0.055	108.3	108.9	109.9	109.9	115.0
1.3.16.8 ऑप्टिकल उपकरण और फोटोग्राफिक उपकरण	0.008	103.8	103.6	109.8	107.2	106.7
1.3.17 इलेक्ट्रिकल उपकरण का विनिर्माण	**2.930**	**131.4**	**132.1**	**133.6**	**133.4**	**133.4**
1.3.17.1 विद्युत मोटर्स, जनरेटर, ट्रांसफार्मर और बिजली वितरण और नियंत्रण संबंधी उपकरण	1.298	130.1	131.6	131.3	131.1	131.4
1.3.17.2 बैटरी और एक्युम्युलेटर	0.236	137.8	136.5	141.7	141.7	141.8
1.3.17.3 डेटा संचरण या छवियों के सजीव प्रसारण के लिए फाइबर ऑप्टिक केबल	0.133	123.4	123.6	121.0	120.7	120.7
1.3.17.4 अन्य इलेक्ट्रानिक और बिज़ली के वायर और केबल	0.428	146.1	146.3	155.8	154.4	153.4
1.3.17.5 वायरिंग संबंधी चीजें और बिजली के प्रकाश और सजावट के उपकरण	0.263	116.8	116.1	119.5	119.0	119.1
1.3.17.6 घरेलू उपकरण	0.366	133.8	135.2	132.0	131.9	132.4
1.3.17.7 अन्य इलेक्ट्रिकल उपकरण	0.206	120.9	121.1	122.2	123.2	122.6
1.3.18 मशीनरी और उपकरणों का विनिर्माण	**4.789**	**129.0**	**128.5**	**130.8**	**130.4**	**130.7**
1.3.18.1 इंजन और टर्बाइन, एयरक्राफ्ट, वाहन और दुपहिया वाहनों के इंजन को छोड़कर	0.638	128.9	127.9	132.4	133.0	132.4
1.3.18.2 तरल बिजली उपकरण	0.162	131.9	130.5	133.9	133.9	133.9
1.3.18.3 अन्य पंप, कंप्रेसर, नल और वाल्व	0.552	117.4	116.7	118.2	118.2	118.2
1.3.18.4 बेयरिंग, गियर्स, गेयरिंग और ड्राइविंग उपकरण	0.340	127.7	126.7	129.0	128.4	127.9
1.3.18.5 ओवन, फर्नेस और फर्नेस बर्नर	0.008	83.7	84.0	86.6	83.7	83.8
1.3.18.6 माल उठाने एवं चढ़ाने – उतारने वाले उपकरण	0.285	128.6	128.7	130.3	130.3	129.6

सं. 21: थोक मूल्य सूचकांक (समाप्त)

(आधारः 2011-12=100)

पण्य वस्तुएँ	भार	2023-24	2023	2024		
			अग	जुन	जुला.(अ)	अग (अ)
	1	2	3	4	5	6
1.3.18.7 कार्यालय मशीनरी और उपकरण	0.006	130.2	130.2	130.2	130.2	130.2
1.3.18.8 सामान्य प्रयोजन के अन्य उपकरण	0.437	145.2	145.4	148.4	146.6	149.2
1.3.18.9 कृषि और वानिकी मशीनरी	0.833	142.5	141.2	145.0	143.5	144.3
1.3.18.10 धातु निर्माण करनेवाली मशीनरी और मशीन टूल्स	0.224	122.5	122.3	122.4	122.4	122.8
1.3.18.11 खनन, उत्खनन और निर्माण के लिए मशीनरी	0.371	88.6	88.4	89.4	89.0	88.9
1.3.18.12 खाद्य, पेय और तंबाकू प्रसंस्करण के लिए मशीनरी	0.228	124.4	124.4	125.8	125.9	126.2
1.3.18.13 कपड़ा, परिधान और चमड़े के उत्पादन से जुड़ी मशीनरी	0.192	137.2	138.6	136.3	137.6	141.9
1.3.18.14 अन्य विशेष प्रयोजनों के लिए मशीनरी	0.468	144.7	144.1	145.7	145.2	145.1
1.3.18.15 अक्षय ऊर्जा उत्पादन मशीनरी	0.046	70.8	71.0	69.6	69.7	69.1
1.3.19 मोटर वाहन, ट्रेलरों और अर्ध-ट्रेलरों का विनिर्माण	**4.969**	**128.4**	**128.3**	**130.0**	**129.7**	**130.0**
1.3.19.1 मोटर वाहन	2.600	128.5	128.9	130.8	130.2	130.5
1.3.19.2 मोटर वाहन पुरजे और सहायक उपकरण	2.368	128.2	127.7	129.2	129.1	129.4
1.3.20 अन्य परिवहन उपकरणों का विनिर्माण	**1.648**	**143.1**	**142.8**	**143.8**	**144.4**	**144.6**
1.3.20.1 जहाजों और तैरने वाली – वस्तुओं का निर्माण	0.117	163.7	163.7	177.9	177.9	177.9
1.3.20.2 रेलवे इंजन और रोलिंग स्टॉक	0.110	107.4	106.4	108.3	109.8	110.0
1.3.20.3 मोटर साइकल	1.302	144.7	144.4	144.4	145.0	145.4
1.3.20.4 साइकल और अवैध गाड़ी	0.117	137.9	138.5	135.7	136.0	135.2
1.3.20.5 अन्य परिवहन उपकरण	0.002	159.2	157.5	161.5	160.2	158.9
1.3.21 फर्नीचर का विनिर्माण	**0.727**	**159.6**	**160.1**	**157.5**	**157.4**	**159.1**
1.3.21.1 फर्नीचर	0.727	159.6	160.1	157.5	157.4	159.1
1.3.22 अन्य विनिर्माण	**1.064**	**158.2**	**154.7**	**177.9**	**178.8**	**174.1**
1.3.22.1 आभूषण और संबंधित सामग्री	0.996	157.9	154.1	179.1	180.0	175.0
1.3.22.2 संगीत उपकरण	0.001	187.0	179.0	201.9	200.0	201.4
1.3.22.3 खेल के सामान	0.012	155.2	155.4	161.7	163.0	163.6
1.3.22.4 खेल और खिलौने	0.005	159.6	160.4	161.7	161.5	164.1
1.3.22.5 चिकित्सा और दंत चिकित्सा उपकरण और संबंधित सामग्री	0.049	163.1	164.5	158.6	158.6	159.7
2 खाद्य सूचकांक	**24.378**	**179.8**	**187.1**	**190.7**	**195.4**	**193.2**

स्रोत: आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार।

सं. 22: औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आधारः 2011-12=100)

उद्योग	भार	2022-23	2023-24	अप्रैल-जुला		जुला	
				2023-24	2024-25	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7
सामान्य सूचकांक	100.00	138.5	146.7	143.2	150.7	142.7	149.6
1 क्षेत्रवार वर्गीकरण							
1.1 खनन	14.37	119.9	128.9	121.2	129.6	111.9	116.0
1.2 विनिर्माण	77.63	137.1	144.7	141.4	147.4	142.1	148.6
1.3 बिजली	7.99	185.2	198.3	200.8	221.1	204.0	220.2
2 उपयोग आधारित वर्गीकरण							
2.1 मूल वस्तुएं	34.05	139.2	147.7	145.2	154.8	141.8	150.1
2.2 पूंजीगत माल	8.22	100.3	106.6	101.1	106.6	102.1	114.4
2.3 मध्यवर्ती माल	17.22	149.4	157.3	154.2	161.0	153.8	164.3
2.4 इन्फ्रास्ट्रक्चर/निर्माण वस्तुएं	12.34	160.7	176.3	171.1	182.5	170.3	178.7
2.5 उपभोक्ता टिकाऊ माल	12.84	114.5	118.6	114.4	125.8	117.0	126.6
2.6 उपभोक्ता गैर-टिकाऊ माल	15.33	147.7	153.7	151.2	149.0	153.5	146.8

स्रोत: राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार।

सरकारी लेखा और खजाना बिल

सं. 23: केन्द्र सरकार का लेखा - एक नज़र में

(₹ करोड़)

मद	वित्तीय वर्ष	अप्रैल-जुला			
	2024-25 (संशोधित अनुमान)	2024-25 वास्तविक आंकड़े	2023-24 वास्तविक आंकड़े	बजट अनुमानों का प्रतिशत	
				2024-25	2023-24
	1	2	3	4	5
1 राजस्व प्राप्तियां	**3129200**	**1017020**	**761389**	**32.5**	**28.9**
1.1 कर राजस्व (निवल)	2583499	715224	582585	27.7	25.0
1.2 करेतर राजस्व	545701	301796	178804	55.3	59.3
2 गैर कर्ज पूंजीगत प्राप्तियां	**78000**	**6386**	**13718**	**8.2**	**16.3**
2.1 ऋण की वसूली	28000	6381	8253	22.8	35.9
2.2 अन्य प्राप्तियां	50000	5	5465	0.0	9.0
3 कुल प्राप्तियां (लिए गए उधार को छोड़कर) (1+2)	**3207200**	**1023406**	**775107**	**31.9**	**28.5**
4 राजस्व व्यय जिसमें से :	3709401	1039091	1063621	28.0	30.4
4.1 ब्याज भुगतान	1162940	327887	299889	28.2	27.8
5 पूंजी व्यय	1111111	261260	317079	23.5	31.7
6 कुल व्यय (4+5)	**4820512**	**1300351**	**1380700**	**27.0**	**30.7**
7 राजस्व घाटा (4-1)	**580201**	**22071**	**302232**	**3.8**	**34.7**
8 राजकोषीय घाटा (6-3)	**1613312**	**276945**	**605593**	**17.2**	**33.9**
9 सकल प्राथमिक घाटा [8-4.1]	**450372**	**-50942**	**305704**	**-11.3**	**43.2**

स्रोत: महालेखानियंत्रक (सीजीए), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार और अंतरिम केंद्रीय बजट 2024-25।

सं. 24: खज़ाना बिल - स्वामित्व का स्वरूप

(₹ करोड़)

मद	2023-24	2023	2024					
		जुला. 28	जून 21	जून 28	जुला. 5	जुला. 12	जुला. 19	जुला. 26
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 91-दिवसीय								
1.1 बैंक	18054	20183	6606	10411	5790	3856	2323	2466
1.2 प्राथमिक व्यापारी	22676	19282	27126	24135	18519	17056	16734	9749
1.3 राज्य सरकारें	5701	35727	44835	46310	38710	30300	41340	46140
1.4 अन्य	88670	122735	95368	88554	94791	95188	93042	95885
2 182-दिवसीय								
2.1 बैंक	84913	63735	61859	54590	49091	48413	51095	51248
2.2 प्राथमिक व्यापारी	87779	119595	58731	66312	61856	63109	59966	57730
2.3 राज्य सरकारें	4070	20791	14592	14592	15592	15292	15292	14922
2.4 अन्य	102311	138170	127409	123098	129053	124478	120939	119522
3 364-दिवसीय								
3.1 बैंक	91819	81443	92156	92592	90418	88810	89690	90700
3.2 प्राथमिक व्यापारी	159085	182603	145237	143140	140991	142478	140420	137182
3.3 राज्य सरकारें	41487	49427	37753	38191	38184	38589	38603	38525
3.4 अन्य	165095	136953	158607	156268	160591	160712	161890	164118
4 14-दिवसीय मध्यवर्ती								
4.1 बैंक								
4.2 प्राथमिक व्यापारी								
4.3 राज्य सरकारें	318736	172959	245624	204835	143591	197638	177044	175531
4.4 अन्य	442	730	379	592	1345	720	646	1008
कुल खज़ाना बिल (14 दिवसीय मध्यवर्ती खज़ाना बिल को छोड़कर)#	871662	990645	870281	858193	843586	828282	831336	828188

14 दिवसीय मध्यवर्ती खज़ाना बिल बिक्री योग्य नहीं है, ये बिल 91 दिवसीय, 182 दिवसीय और 364 दिवसीय खज़ाना बिलों जैसे नहीं हैं। इन बिलों का स्वरूप मध्यवर्ती है, क्योंकि राज्य सरकारों के दैनिक न्यूनतम नकदी शेष में कमी को पूरा करने के लिए इन्हें परिसमाप्त किया जाता है।

टिप्पणी: प्राथमिक व्यापारियों (पीडी) में पीडी कारोबार करनेवाले बैंक शामिल हैं।

सं. 25: खज़ाना बिलों की नीलामी

(राशि करोड़ ₹ में)

नीलामी की तारीख	अधिसूचित राशि	प्राप्त बोलियां			स्वीकृत बोलियाँ			कुल निर्गम (6+7)	कट-ऑफ मूल्य (₹)	कट-ऑफ मूल्य पर निहित प्रतिफल (प्रतिशत)
		संख्या	कुल अंकित मूल्य		संख्या	कुल अंकित मूल्य				
			प्रतियोगी	गैर-प्रतियोगी		प्रतियोगी	गैर-प्रतियोगी			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
91-दिवसीय खज़ाना बिल										
2024-25										
जुला 3	8000	93	29591	1965	21	7935	1965	9900	98.34	6.7810
जुला 10	8000	99	30464	13565	25	7935	13565	21500	98.34	6.7578
जुला 18	8000	92	31361	13581	44	7959	13581	21540	98.35	6.7399
जुला 24	8000	102	30786	6054	35	7946	6054	14000	98.35	6.7130
जुला 31	8000	95	19776	748	47	7952	748	8700	98.36	6.6736
182-दिवसीय खज़ाना बिल										
2024-25										
जुला 3	6000	153	27489	1035	32	5965	1035	7000	96.67	6.9000
जुला 10	6000	99	20507	81	23	5919	81	6000	96.69	6.8699
जुला 18	6000	95	18666	1576	45	5924	1576	7500	96.70	6.8451
जुला 24	6000	119	19854	712	46	5943	712	6655	96.71	6.8249
जुला 31	6000	99	17547	1661	53	5964	1661	7625	96.73	6.7885
364-दिवसीय खज़ाना बिल										
2024-25										
जुला 3	6000	139	23190	137	53	5962	137	6099	93.52	6.9498
जुला 10	6000	148	28619	437	32	5975	437	6412	93.55	6.9194
जुला 18	6000	129	29830	35	14	5979	35	6014	93.58	6.8740
जुला 24	6000	128	27277	89	30	5982	89	6071	93.62	6.8365
जुला 31	6000	124	25880	361	49	5984	361	6345	93.65	6.7985

वित्तीय बाजार

सं. 26: दैनिक मांग मुद्रा दरें

(वार्षिक प्रतिशत)

स्थिति के अनुसार	दरों का दायरा	भारित औसत दरें
	उधार लेना / उधार देना	उधार लेना / उधार देना
	1	2
जुलाई 01 ,2024	5.10-6.65	6.54
जुलाई 02 ,2024	5.00-6.60	6.49
जुलाई 03 ,2024	5.10-6.55	6.49
जुलाई 04 ,2024	5.10-6.55	6.50
जुलाई 05 ,2024	4.50-6.65	6.52
जुलाई 06 ,2024	5.50-6.24	6.13
जुलाई 08 ,2024	5.10-6.65	6.54
जुलाई 09 ,2024	5.10-6.55	6.47
जुलाई 10 ,2024	5.10-6.60	6.47
जुलाई 11 ,2024	5.10-6.60	6.47
जुलाई 12 ,2024	5.10-6.55	6.46
जुलाई 15 ,2024	5.10-6.55	6.47
जुलाई 16 ,2024	5.10-6.55	6.48
जुलाई 18 ,2024	5.10-6.60	6.47
जुलाई 19 ,2024	5.10-6.60	6.49
जुलाई 20 ,2024	5.50-6.24	6.11
जुलाई 22 ,2024	5.10-6.75	6.60
जुलाई 23 ,2024	5.10-6.80	6.67
जुलाई 24 ,2024	5.10-6.80	6.67
जुलाई 25 ,2024	5.10-6.70	6.56
जुलाई 26 ,2024	5.10-6.55	6.48
जुलाई 29 ,2024	5.10-6.55	6.48
जुलाई 30 ,2024	5.10-6.55	6.47
जुलाई 31 ,2024	5.10-6.60	6.49
अगस्त 01 ,2024	5.10-6.55	6.47
अगस्त 02 ,2024	5.10-6.55	6.45
अगस्त 03 ,2024	5.50-6.50	6.08
अगस्त 05 ,2024	5.10-6.55	6.45
अगस्त 06 ,2024	5.10-6.50	6.41
अगस्त 07 ,2024	5.10-6.75	6.47
अगस्त 08 ,2024	5.10-6.80	6.65
अगस्त 09 ,2024	5.10-6.65	6.53
अगस्त 12 ,2024	5.10-6.55	6.47
अगस्त 13 ,2024	5.10-6.55	6.48
अगस्त 14 ,2024	5.10-6.60	6.48

टिप्पणीः नोटिस मुद्रा सहित।

सं. 27: जमा प्रमाण-पत्र

मद	2023	2024			
	जुला. 28	जून 14	जून 28	जुला. 12	जुला. 26
	1	2	3	4	5
1 बकाया राशि (₹ करोड़)	307002.89	352302.19	409554.44	424835.55	424747.21
1.1 पखवाड़े के दौरान जारी (₹ करोड़)	25601.63	55859.00	84271.02	34710.85	23643.34
2 ब्याज दर (प्रतिशत)	6.76-7.89	6.95-7.75	6.97-7.71	6.95-7.24	7.02-7.26

सं. 28: वाणिज्यिक पत्र

मद	2023	2024			
	जुला. 31	जून 15	जून 30	जुला. 15	जुला. 31
	1	2	3	4	5
1 बकाया राशि (र करोड़)	444567.60	431100.55	422447.45	440818.85	458911.05
1.1 पखवाड़े के दौरान रिपोर्ट किए गए (₹ करोड़)	65987.70	106920.70	56023.85	37452.10	67966.95
2 ब्याज दर (प्रतिशत)	6.75-12.23	6.95-12.08	6.99-15.06	6.93-11.69	6.89-12.07

सं. 29: चुनिंदा वित्तीय बाजारों में औसत दैनिक कारोबार

(₹ करोड़)

मद	2023-24	2023	2024					
		जुला. 28	जून 21	जून 28	जुला. 5	जुला. 12	जुला. 19	जुला. 26
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 मांग मुद्रा	17761	21447	19913	23962	16171	17506	15785	17812
2 नोटिस मुद्रा	2550	185	613	3722	3481	308	4624	228
3 मीयादी मुद्रा	871	491	673	613	1149	1050	733	618
4 त्रिपक्षीय रेपो	601363	615266	617320	799629	668230	607911	739055	693314
5 बाजार रेपो	574534	651665	539543	663566	545361	528564	632592	566606
6 कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो	1817	1178	2865	3558	3321	4071	3352	3283
7 फोरेक्स (यूएस मिलियन डॉलर)	95115	96828	110450	135891	93725	101334	105661	103577
8 भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां	90992	90813	108012	107938	77825	80996	119858	139737
9 राज्य सरकारों की प्रतिभूतियां	6102	4199	11282	9999	7107	7881	5759	6747
10 खज़ाना बिल								
10.1 91-दिवसीय	5378	3955	2336	8036	10592	5453	3400	3301
10.2 182-दिवसीय	6079	4788	3692	5128	9259	3380	6441	4933
10.3 364-दिवसीय	4307	2426	2813	4984	5608	3406	4208	4467
10.4 नकदी प्रबंधन बिल			0	0	0	0	0	0
11 कुल सरकारी प्रतिभूतियां (8+9+10)	112858	106181	128135	136084	110391	101115	139667	159184
11.1 भारतीय रिज़र्व बैंक	492	24	1026	948	87	1093	1196	2077

सं. 30: गैर-सरकारी सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों के नए पूंजी निर्गम

(राशि ₹ करोड़ में)

प्रतिभूति और निर्गम का प्रकार	2023-24		2023-24 (अप्रैल-जुला)		2024-25 (अप्रैल-जुला) *		जुला 2023		जुला 2024 *	
	निर्गमों की संख्या	राशि	निर्गमों की संख्या	राशि	निर्गमों की संख्या	राशि	निर्गमों की संख्या	राशि	निर्गमों की संख्या	राशि
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 इक्विटी शेयर	**339**	**80942**	**81**	**15126**	**154**	**50281**	**28**	**4387**	**42**	**9001**
1ए प्रीमियम	328	76319	75	13997	144	32249	27	3749	40	8481
1.1 पब्लिक	272	65832	57	10491	106	42592	21	3610	31	6210
1.1.1 प्रीमियम	272	62791	57	10040	106	25527	21	3301	31	6026
1.2 राइट्स	67	15110	24	4636	48	7690	7	777	11	2791
1.2.1 प्रीमियम	56	13527	18	3956	38	6722	6	448	9	2455
2 अधिमान शेयर	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2.1 पब्लिक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 राइट्स	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 बॉण्ड और डिबेंचर	**44**	**16342**	**12**	**3416**	**12**	**2716**	**3**	**841**	**2**	**262**
3.1 परिवर्तनीय	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.1 पब्लिक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.2 राइट्स	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 अपरिवर्तनीय	44	16342	12	3416	12	2716	3	841	2	262
3.1.1 पब्लिक	44	16342	12	3416	12	2716	3	841	2	262
3.1.2 राइट्स	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 कुल (1+2+3)	**383**	**97284**	**93**	**18542**	**166**	**52997**	**31**	**5228**	**44**	**9263**
4.1 पब्लिक	316	82174	69	13907	118	45307	24	4451	33	6472
4.2 राइट्स	67	15110	24	4636	48	7690	7	777	11	2791

टिप्पणी: 1. अप्रैल 2020 से इक्विटी निर्गमों का मासिक डेटा उनकी लिस्टिंग की तारीख के आधार पर संकलित किया गया है।

2. संख्याओं के पूर्णांकन के कारण कॉलम के आंकड़े कुल में न जुड़ पाने की संभावना है।

स्रोत: भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी)।

* : आंकड़े अनंतिम है।

बाह्य क्षेत्र

सं. 31 : विदेशी व्यापार

मद	इकाई	2023-24	2023	2024				
			जुला.	मार्च	अप्रै	मई	जून	जुला.
		1	2	3	4	5	6	7
1 निर्यात	₹ करोड़	3618952	283341	346040	294476	330245	293540	283332
	मिलियन अमेरिकी डॉलर	437072	34490	41693	35306	39601	35167	33894
1.1 तेल	₹ करोड़	696850	55171	44950	58783	67624	45865	43703
	मिलियन अमेरिकी डॉलर	84157	6716	5416	7048	8109	5495	5228
1.2 तेल से इतर	₹ करोड़	2922102	228170	301089	235693	262621	247675	239629
	मिलियन अमेरिकी डॉलर	352915	27774	36277	28258	31492	29672	28666
2 आयात	₹ करोड़	5616042	439397	473312	456100	518032	473168	480469
	मिलियन अमेरिकी डॉलर	678215	53486	57027	54684	62119	56687	57476
2.1 तेल	₹ करोड़	1480232	97042	135638	137648	166315	125611	115968
	मिलियन अमेरिकी डॉलर	178733	11813	16342	16503	19944	15048	13873
2.2 तेल से इतर	₹ करोड़	4135810	342355	337674	318452	351716	347557	364501
	मिलियन अमेरिकी डॉलर	499482	41673	40685	38181	42176	41638	43603
3 व्यापार शेष	₹ करोड़	-1997090	-156056	-127272	-161624	-187786	-179628	-197137
	मिलियन अमेरिकी डॉलर	-241143	-18996	-15334	-19378	-22518	-21520	-23582
3. 1 तेल	₹ करोड़	-783382	-41871	-90687	-78865	-98691	-79746	-72265
	मिलियन अमेरिकी डॉलर	-94576	-5097	-10927	-9456	-11835	-9554	-8645
3. 2 तेल से इतर	₹ करोड़	-1213708	-114185	-36584	-82759	-89095	-99882	-124871
	मिलियन अमेरिकी डॉलर	-146567	-13899	-4408	-9922	-10684	-11966	-14938

टिप्पणी : सारणी के आंकड़े अनंतिम हैं।

स्रोत : वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय तथा वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय।

सं. 32: विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियां

मद	इकाई	2023	2024					
		सितं. 01	जुला. 26	अग. 02	अग. 09	अग. 16	अग. 23	अग. 30
		1	2	3	4	5	6	7
1 कुल आरक्षित निधियां	₹ करोड़	**4953552**	**5587802**	**5652457**	**5625930**	**5664078**	**5719971**	**5736861**
	मिलियन अमेरिकी डॉलर	**598897**	**667386**	**674919**	**670119**	**674664**	**681688**	**683987**
1.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	₹ करोड़	4389432	4913727	4958347	4936193	4966459	5014012	5024359
	मिलियन अमेरिकी डॉलर	530691	586877	592039	587960	591569	597552	599037
१.२ स्वर्ण	₹ करोड़	371694	483062	503330	497338	504594	511818	518835
	मिलियन अमेरिकी डॉलर	44939	57695	60099	59239	60104	60997	61859
	मात्रा (मैट्रिक टन)	799.59	843.38	846.18	848.98	848.98	848.98	848.98
1.3 एसडीआर	एसडीआरएस मिलियन	13681	13699	13699	13699	13702	13702	13702
	₹ करोड़	150491	152398	152096	153484	153983	154888	154901
	मिलियन अमेरिकी डॉलर	18195	18202	18161	18282	18341	18459	18468
1.4 आईएमएफ में आरक्षित भाग की स्थिति	₹ करोड़	41935	38614	38685	38915	39042	39253	38766
	मिलियन अमेरिकी डॉलर	5073	4612	4620	4638	4650	4680	4622

* अंतर यदि कोई हो, तो पूर्णांकन की वजह से है।

टिप्पणी : आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी विदेशी मुद्रा में निर्दिष्ट बॉण्डों में निवेश, भारत सरकार द्वारा रिज़र्व बैंक को अंतरित एसडीआर तथा सार्क और एसीयू करेंसी स्वैप व्यवस्था के अंतर्गत प्राप्त विदेशी मुद्रा शामिल नहीं हैं। अमेरिकी डॉलर में दिखाई गई विदेशी मुद्रा को आस्तियों में रिज़र्व में रखी गैर यूएस मुद्राओं (जैसे यूरो, स्टर्लिंग, येन और ऑस्ट्रेलिया डॉलर) के मूल्यवृद्धि/मूल्यह्रास के लिए शामिल किया गया है। विदेशी मुद्रा धारिता को रुपया - अमेरिकी डॉलर आरबीआई धारिता दरों पर रुपए में परिवर्तित किया गया है।

सं. 33: अनिवासी भारतीयों की जमाराशियाँ

(मिलियन अमेरिकी डॉलर)

योजना	बकाया				प्रवाह	
	2023-24	2023	2024		2023-24	2024-25
		जुला	जून	जुला (अ)	अप्रै.-जुला	अप्रै.-जुला (अ)
	1	2	3	4	5	6
1 एनआरआई जमाराशियाँ	**151879**	**141850**	**155782**	**157157**	**3013**	**5820**
1.1 एफसीएनआर (बी)	25733	20808	27414	28572	1445	2839
1.2 एनआर (ई) आरए	98624	96351	100111	99981	568	1780
1.3 एनआरओ	27522	24690	28257	28603	1000	1201

अ: अनंतिम।

सं. 34: विदेशी निवेश अंतर्वाह

(मिलियन अमेरिकी डॉलर)

मद	2023-24	2023-24	2024-25 (अ)	2023	2024 (अ)	
		अप्रै.- मई	अप्रै.- मई	मई	अप्रै.	मई
	1	2	3	4	5	6
1.1 निवल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (1.1.1-1.1.2)	**9790**	**3422**	**7142**	**665**	**3891**	**3251**
1.1.1 भारत में प्रत्यक्ष निवेश (1.1.1.1-1.1.1.2)	**26469**	**5395**	**9853**	**1484**	**4880**	**4972**
1.1.1.1 सकल अंतर्वाह / सकल निवेश	**70941**	**12346**	**15159**	**4959**	**7269**	**7891**
1.1.1.1.1 इक्विटी	45817	7997	10977	2785	5017	5960
1.1.1.1.1.1 सरकारी (एसआईए/एफआईपीबी)	585	40	91	15	11	80
1.1.1.1.1.2 भारतीय रिज़र्व बैंक	31826	6746	8520	2120	4733	3787
1.1.1.1.1.3 शेयरों का अधिग्रहण	12013	999	2153	543	167	1986
1.1.1.1.1.4 अनिगमित निकायों की इक्विटी पूंजी	1394	213	213	107	107	107
1.1.1.1.2 पुनर्निवेशित आय	19768	3027	3027	1514	1514	1514
1.1.1.1.3 अन्य पूंजी	5355	1322	1155	661	738	417
1.1.1.2 प्रत्यावर्तन / विनिवेश	**44472**	**6952**	**5307**	**3476**	**2389**	**2918**
1.1.1.2.1 इक्विटी	41334	6234	4868	3117	2235	2633
1.1.1.2.2 अन्य पूंजी	3137	718	439	359	154	285
1.1.2 भारत द्वारा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (1.1.2.1+1.1.2.2+ 1.1.2.3-1.1.2.4)	**16678**	**1972**	**2711**	**819**	**989**	**1722**
1.1.2.1 इक्विटी पूंजी	9111	1385	1637	612	590	1046
1.1.2.2 पुनर्निवेशित आय	5786	964	964	482	482	482
1.1.2.3 अन्य पूंजी	5406	615	815	221	376	439
1.1.2.4 प्रत्यावर्तन / विनिवेश	3624	992	705	496	459	246
1.2 निवल संविभागीय निवेश (1.2.1+1.2.2+1.2.3-1.2.4)	**44081**	**8081**	**-4119**	**5986**	**-2663**	**-1456**
1.2.1 जीडीआर/एडीआर	-	-	-	-	-	-
1.2.2 एफआईआई	44626	8320	-4199	6106	-2691	-1508
1.2.3 अपतटीय निधियां और अन्य	-	-	-	-	-	-
1.2.4 भारत द्वारा संविभागीय निवेश	544	239	-80	119	-29	-51
1 विदेशी निवेश अंतर्वाह	**53872**	**11504**	**3023**	**6651**	**1229**	**1794**

अ: अनंतिम।

सं. 35: वैयक्तिक निवासियों के लिए उदारीकृत विप्रेषण योजना (एलआरएस) के अंतर्गत जावक विप्रेषण

(मिलियन अमेरिकी डॉलर)

मद	2023-24	2023	2024		
		जुला.	मई	जुला.	जुला.
	1	2	3	4	5
1 एलआरएस के अंतर्गत जावक विप्रेषण	**31735.74**	**2359.51**	**2420.58**	**2181.85**	**2754.05**
1.1 जमाराशियाँ	916.45	50.12	52.98	39.02	41.68
1.2 अचल संपत्ति की खरीद	242.51	14.89	21.69	18.77	24.54
1.3 इक्विटी / कर्ज में निवेश	1510.89	58.06	98.86	120.22	120.86
1.4 उपहार	3580.27	233.96	271.93	228.81	275.26
1.5 दान	11.31	0.65	0.58	2.01	0.68
1.6 यात्रा	17006.27	1419.42	1401.16	1275.63	1662.13
1.7 निकट संबंधियों से संबंधित खर्चे	4611.53	282.30	320.80	270.72	337.40
1.8 चिकित्सा उपचार	79.62	4.22	7.66	6.42	8.62
1.9 विदेश में शिक्षा	3478.65	267.28	210.99	177.07	272.16
1.10 अन्य	298.24	28.62	33.94	43.19	10.72

सं. 36: भारतीय रुपये का सांकेतिक प्रभावी विनिमय दर (एनईईआर) और वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (आरईईआर) सूचकांक

मद	2022-23	2023-24	2023	2024	
			अग	जुला.	अग
	1	2	3	4	5
40- मुद्रा समूह (आधार: 2015-16 = 100)					
1 व्यापार आधारित भारांक					
1.1 नीर	91.20	90.74	90.86	92.02	90.84
1.2 रीर	102.78	103.70	105.41	107.45	105.45
2 निर्यात आधारित भारांक					
2.1 नीर	93.01	93.12	93.08	94.48	93.46
2. 2 रीर	101.10	101.21	102.74	104.46	102.75
6- मुद्रा समूह (व्यापार-भारित)					
1 आधार : 2015-16 =100					
1.1 नीर	85.93	83.62	83.73	83.40	82.04
1.2 रीर	101.80	101.66	103.03	104.45	102.59
2 आधार : 2022-23 = 100					
2.1 नीर	100.00	97.31	97.44	97.06	95.47
2.2 रीर	100.00	99.86	101.20	102.60	100.77

सं. 37: बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) - पंजीकरण

(राशि मिलियन यूएस$ में)

मद	2023-24	2023	2024	
		जुला.	जून	जुला.
	1	2	3	4
1 स्वचालित मार्ग				
1.1 संख्या	1188	93	121	119
1.2 राशि	29461	485	1811	3581
2 अनुमोदन मार्ग				
2.1 संख्या	33	2	4	0
2.2 राशि	19748	2074	1005	0
3 कुल (1+2)				
3.1 संख्या	1221	95	125	119
3.2 राशि	49209	2559	2816	3581
4 भारित औसत परिपक्वता (वर्षों में)	5.60	5.00	5.80	5.20
5 ब्याज दर (प्रतिशत)				
5.1 अस्थिर दर के ऋणों@ के लिए वैकल्पिक संदर्भ दर पर भारित औसत मार्जिन	1.66	0.83	1.36	1.45
5.2 सावधि दर के ऋणों के लिए ब्याज दर की सीमा	0.00-27.00	0.00-11.25	0.00-11.00	0.00-10.00
उधारकर्ता श्रेणियाँ				
I. कॉरपोरेट विनिर्माण	15836	223	603	626
II. कॉरपोरेट - बुनियादी संरचना	15916	1635	808	1393
ए) परिवहन	1505	43	0	0
बी) ऊर्जा	3513	2	745	559
सी) पानी और सफाई व्यवस्था	33	0	27	0
डी) संचार	6309	1590	0	0
ई) सामाजिक और वाणिज्यिक बुनियादी संरचना	115	0	17	0
एफ) अन्वेषण, खनन और रिफाइनरी	2480	0	19	800
जी) अन्य उप-क्षेत्र	1961	0	0	34
III. कॉरपोरेट सेवा क्षेत्र	1526	101	37	349
IV. अन्य संस्थाएं	1728	0	19	4
ए) एसईज़ेड में इकाई	1	0	19	4
बी) सिडबी	0	0	0	0
सी) एक्जिम बैंक	1727	0	0	0
V. बैंक	0	0	0	0
VI. वित्तीय संस्थान (एनबीएफसी के अलावा)	20	0	0	0
VII. एनबीएफसी	13361	562	1311	1195
ए) एनबीएफसी - आईएफसी / एएफसी	7734	505	1062	0
बी) एनबीएफसी - एमएफआई	531	2	38	16
सी) एनबीफसी - अन्य	5096	55	211	1179
VIII. गैर -सरकारी संगठन (एनजीओ)	0	0	0	0
IX. सूक्ष्म वित्त संस्था (एमएफआई)	0	0	0	0
X. अन्य	822	38	38	14

टिप्पणी: ईसीबी/विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉण्ड (एफसीसीबी) के लिए आवेदनों के आधार पर जिन्हें निर्धारित अवधि के दौरान ऋण पंजीकरण संख्या आबंटित की गई है।

@ 01 जुलाई, 2023 से लागू, बेंचमार्क दर को बदलकर वैकल्पिक संदर्भ दर कर दिया गया है।

सं. 38: भारत का समग्र भुगतान संतुलन

(मिलियन अमेरिकी डॉलर)

मद	जन.-मार्च 2023			जन.-मार्च 2024 (प्रा)		
	जमा	नामे	निवल	जमा	नामे	निवल
	1	2	3	4	5	6
समग्र भुगतान शेष (1+2+3)	**391827**	**386248**	**5579**	**502210**	**471456**	**30754**
1 चालू खाता (1.1+1.2)	**238010**	**239366**	**-1356**	**253561**	**247879**	**5682**
1.1 पण्य	**115821**	**168408**	**-52587**	**121652**	**172546**	**-50894**
1.2 अप्रत्यक्ष मदें (1.2.1+1.2.2+1.2.3)	**122189**	**70959**	**51231**	**131909**	**75333**	**56576**
1.2.1 सेवाएं	85833	46758	39075	89357	46672	42685
1.2.1.1 यात्रा	8445	7698	747	9961	8063	1898
1.2.1.2 परिवहन	7956	8091	-135	7772	7829	-57
1.2.1.3 बीमा	824	455	369	927	650	277
1.2.1.4 जी.एन.आई.ई.	144	307	-163	129	315	-186
1.2.1.5 विविध	68464	30207	38256	70568	29814	40753
1.2.1.5.1 सॉफ्टवेयर सेवाएं	38473	4103	34370	41551	4908	36643
1.2.1.5.2 कारोबार सेवाएं	22260	16314	5945	22620	16388	6232
1.2.1.5.3 वित्तीय सेवाएं	2093	1303	790	1599	1269	330
1.2.1.5.4 संचार सेवाएं	2558	2217	341	498	506	-7
1.2.2 अंतरण	28650	3888	24762	32097	3378	28719
1.2.2.1 आधिकारिक	24	342	-318	51	282	-231
1.2.2.2 निजी	28627	3547	25080	32046	3096	28950
1.2.3 आय	7706	20312	-12606	10455	25283	-14828
1.2.3.1 निवेश आय	6010	19395	-13385	8523	24244	-15721
1.2.3.2 कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति	1695	917	778	1932	1039	893
2 पूंजी खाता (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	**153422**	**146882**	**6540**	**248111**	**223578**	**24534**
2.1 विदेशी निवेश (2.1.1+2.1.2)	**83781**	**79091**	**4691**	**158711**	**145366**	**13345**
2.1.1 विदेशी प्रत्यक्ष निवेश	17084	10730	6355	19834	17881	1954
2.1.1.1 भारत में	15858	6538	9319	19128	11411	7718
2.1.1.1.1 इक्विटी	9708	6254	3454	12762	10934	1829
2.1.1.1.2 पुनर्निवेशित आय	4976	0	4976	5332		5332
2.1.1.1.3 अन्य पूंजी	1173	284	889	1034	477	557
2.1.1.2 विदेश में	1227	4191	-2964	706	6470	-5764
2.1.1.1.1 इक्विटी	1227	2123	-896	706	3208	-2503
2.1.1.1.2 पुनर्निवेशित आय	0	1103	-1103	0	1446	-1446
2.1.1.1.3 अन्य पूंजी	0	965	-965	0	1815	-1815
2.1.2 संविभाग निवेश	66697	68361	-1664	138877	127485	11392
2.1.2.1 भारत में	66117	67704	-1588	138217	126638	11579
2.1.2.1.1 एफआईआई	66117	67704	-1588	138217	126638	11579
2.1.2.1.1.1 इक्विटी	57476	59959	-2483	120154	112150	8004
2.1.2.1.1.2 ऋण	8640	7745	895	18063	14487	3575
2.1.2.1.2 एडीआर / जीडीआर	0	0	0	0		0
2.1.2.2 विदेश में	580	657	-77	660	847	-187
2.2 ऋण (2.2.1+2.2.2+2.2.3)	**26512**	**23457**	**3055**	**30700**	**28949**	**1751**
2.2.1 बाह्य सहायता	3240	1522	1718	3587	1562	2025
2.2.1.1 भारत द्वारा	8	22	-14	8	31	-23
2.2.1.2 भारत को	3232	1500	1732	3579	1531	2048
2.2.2 वाणिज्यिक उधार	7323	5698	1624	15113	13418	1695
2.2.2.1 भारत द्वारा	272	382	-110	3401	4308	-907
2.2.2.2 भारत को	7051	5316	1735	11711	9110	2601
2.2.3 भारत को अल्पावधि	15950	16237	-287	12000	13969	-1969
2.2.3.1 खरीदार और आपूर्तिकर्ता का ऋण > 180 दिन	15950	13646	2305	12000	12865	-865
2.2.3.2 आपूर्तिकर्ता का 180 दिन तक का ऋण	0	2592	-2592	0	1104	-1104
2.3 बैंकिंग पूंजी (2.3.1+2.3.2)	**27997**	**32047**	**-4050**	**40722**	**33811**	**6911**
2.3.1 वाणिज्यिक बैंक	27922	32047	-4125	39768	33811	5957
2.3.1.1 आस्तियां	4274	13260	-8986	9220	12330	-3110
2.3.1.2 देयताएं	23648	18787	4861	30548	21481	9067
2.3.1.2.1 अनिवासी जमाराशियाँ	21066	17485	3581	26041	20678	5363
2.3.2 अन्य	75	0	75	955	0	955
2.4 रुपया कर्ज चुकौती	**0**	**7**	**-7**		**7**	**-7**
2.5 अन्य पूंजी	**15131**	**12280**	**2852**	**17978**	**15445**	**2533**
3 भूल-चक	**395**	**0**	**395**	**538**	**0**	**538**
4 मौद्रिक गतिविधियां (4.1+4.2)	**0**	**5579**	**-5579**	**0**	**30754**	**-30754**
4.1 आई.एम.एफ.	0	0	0	0	0	0
4.2 विदेशी मुद्रा भंडार (वृद्धि - / कमी +)	0	5579	-5579		30754	-30754

टिप्पणी: प्रा: प्रारंभिक

सं. 39: भारत का समग्र भुगतान संतुलन

(₹ करोड़)

मद	जन.-मार्च 2023			जन.-मार्च 2024 (प्रा)		
	जमा	नामे	निवल	जमा	नामे	निवल
	1	2	3	4	5	6
समग्र भुगतान शेष (1+2+3)	**3223390**	**3177490**	**45899**	**4169720**	**3914381**	**255339**
1 चालू खाता (1.1+1.2)	**1958005**	**1969160**	**-11155**	**2105253**	**2058074**	**47179**
1.1 पण्य	**952809**	**1385415**	**-432606**	**1010049**	**1432606**	**-422556**
1.2 अदृश्य मदें (1.2.1+1.2.2+1.2.3)	**1005196**	**583745**	**421451**	**1095204**	**625468**	**469735**
1.2.1 सेवाएं	706112	384660	321451	741908	387502	354406
1.2.1.1 यात्रा	69476	63331	6145	82705	66948	15758
1.2.1.2 परिवहन	65454	66565	-1111	64527	65002	-475
1.2.1.3 बीमा	6777	3740	3037	7699	5395	2304
1.2.1.4 जी.एन.आई.ई.	1185	2525	-1339	1073	2616	-1543
1.2.1.5 विविध	563219	248500	314719	585904	247541	338363
1.2.1.5.1 सॉफ्टवेयर सेवाएं	316497	33753	282744	344986	40752	304234
1.2.1.5.2 कारोबार सेवाएं	183122	134212	48910	187807	136067	51740
1.2.1.5.3 वित्तीय सेवाएं	17215	10718	6497	13280	10537	2743
1.2.1.5.4 संचार सेवाएं	21041	18237	2804	4136	4197	-61
1.2.2 अंतरण	235693	31986	203706	266491	28049	238442
1.2.2.1 आधिकारिक	194	2810	-2616	423	2344	-1921
1.2.2.2 निजी	235499	29176	206322	266068	25705	240363
1.2.3 आय	63392	167098	-103707	86804	209917	-123113
1.2.3.1 निवेश आय	49444	159555	-110111	70763	201290	-130527
1.2.3.2 कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति	13948	7544	6404	16041	8627	7414
2 पूंजी खाता (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	**1262134**	**1208330**	**53804**	**2060004**	**1856307**	**203698**
2.1 विदेशी निवेश (2.1.1+2.1.2)	**689231**	**650644**	**38587**	**1317736**	**1206932**	**110803**
2.1.1 विदेशी प्रत्यक्ष निवेश	140546	88268	52278	164679	148458	16220
2.1.1.1 भारत में	130453	53788	76665	158819	94741	64078
2.1.1.1.1 इक्विटी	79863	51450	28413	105963	90780	15183
2.1.1.1.2 पुनर्निवेशित आय	40937	0	40937	44274	0	44274
2.1.1.1.3 अन्य पूंजी	9652	2338	7315	8582	3960	4621
2.1.1.2 विदेश में	10093	34480	-24387	5860	53718	-47858
2.1.1.2.1 इक्विटी	10093	17465	-7372	5860	26638	-20778
2.1.1.2.2 पुनर्निवेशित आय	0	9073	-9073	0	12009	-12009
2.1.1.2.3 अन्य पूंजी	0	7941	-7941	0	15071	-15071
2.1.2 संविभाग निवेश	548685	562376	-13691	1153057	1058474	94583
2.1.2.1 भारत में	543912	556972	-13060	1147577	1051439	96139
2.1.2.1.1 एफआईआई	543912	556972	-13060	1147577	1051439	96139
2.1.2.1.1.1 इक्विटी	472831	493254	-20423	997608	931154	66454
2.1.2.1.1.2 ऋण	71080	63718	7363	149969	120285	29685
2.1.2.1.2 एडीआर /जीडीआर	0	0	0	0	0	0
2.1.2.2 विदेश में	4774	5404	-631	5480	7035	-1555
2.2 ऋण (2.2.1+2.2.2+2.2.3)	**218106**	**192973**	**25133**	**254894**	**240356**	**14538**
2.2.1 बाह्य सहायता	26652	12519	14133	29784	12969	16816
2.2.1.1 भारत द्वारा	63	180	-117	66	255	-188
2.2.1.2 भारत को	26589	12339	14250	29718	12714	17004
2.2.2 वाणिज्यिक उधार	60240	46876	13363	125478	111407	14071
2.2.2.1 भारत द्वारा	2237	3144	-907	28241	35769	-7528
2.2.2.2 भारत को	58003	43732	14271	97237	75638	21599
2.2.3 भारत को अल्पावधि	131214	133577	-2364	99631	115980	-16349
2.2.3.1 खरीदार और आपूर्तिकर्ता का ऋण > 180 दिन	131214	112256	18958	99631	106817	-7185
2.2.3.2 आपूर्तिकर्ता का 180 दिन तक का ऋण	0	21322	-21322	0	9163	-9163
2.3 बैंकिंग पूंजी (2.3.1+2.3.2)	**230320**	**263635**	**-33315**	**338106**	**280721**	**57384**
2.3.1 वाणिज्यिक बैंक	229701	263635	-33934	330180	280721	49459
2.3.1.1 आस्तियां	35162	109084	-73921	76548	102370	-25822
2.3.1.2 देयताएं	194539	154551	39988	253632	178351	75281
2.3.1.2.1 अनिवासी जमाराशियाँ	173302	143842	29461	216214	171683	44531
2.3.2 अन्य	619	0	619	7926	0	7926
2.4 रुपया ऋण चुकौती	**0**	**60**	**-60**	**0**	**60**	**-60**
2.5 अन्य पूंजी	**124477**	**101018**	**23459**	**149269**	**128237**	**21033**
3 भूल-चूक	**3250**	**0**	**3250**	**4463**	**0**	**4463**
4 मौद्रिक गतिविधियां (4.1+4.2)	**0**	**45899**	**-45899**	**0**	**255339**	**-255339**
4.1 आईएमएफ	0	0	0	0	0	0
4.2 विदेशी मुद्रा भंडार (वृद्धि - / कमी +)	0	45899	-45899	0	255339	-255339

टिप्पणी: प्रा: प्रारंभिक

सं. 40: बीपीएम6 के अनुसार भारत में भुगतान संतुलन का मानक प्रस्तुतीकरण

(मिलियन अमेरिकी डॉलर)

मद	जन.-मार्च 2023			जन.-मार्च 2024 (प्रा)		
	जमा	नामे	निवल	जमा	नामे	निवल
	1	2	3	4	5	6
1. चालू खाता (1.अ+1.आ+1.इ)	**238010**	**239346**	**-1336**	**253558**	**247857**	**5701**
1.अ माल और सेवाएं (1.अ.क.+ 1अ.ख.)	**201654**	**215166**	**-13512**	**211010**	**219218**	**-8208**
1.अ.क. माल (1.अ.क.1 से 1अ.क.3)	**115821**	**168408**	**-52587**	**121652**	**172546**	**-50894**
1.अ.क.1 बीओपी आधार पर सामान्य वाणिज्यिक वस्तुएं	115268	161779	-46511	121353	162955	-41602
1.अ.क.2 वाणिज्यिक के अंतर्गत माल का निवल निर्यात	553	0	553	300	0	300
1..अ.क.3 गैर-मौद्रिक स्वर्ण	0	6629	-6629		9591	-9591
1.अ.ख सेवाएं (1.अ.ख.1 से 1.अ.ख.13)	**85833**	**46758**	**39075**	**89357**	**46672**	**42685**
1.अ.ख.1 अन्य के स्वामित्व वाले भौतिक इनपुट पर विनिर्माण सेवाएं	327	52	275	352	18	335
1.अ.ख.2 अन्यत्र शामिल न की गई रखरखाव व मरम्मत सेवाएं	56	644	-587	55	456	-401
1.अ.ख.3 परिवहन	7956	8091	-135	7772	7829	-57
1.अ.ख.4 यात्रा	8445	7698	747	9961	8063	1898
1.अ.ख.5 निर्माण	1099	705	394	1658	791	867
1.अ.ख.6 बीमा और पेंशन सेवाएं	824	455	369	927	650	277
1.अ.ख.7 वित्तीय सेवाएं	2093	1303	790	1599	1269	330
1.अ.ख.8 अन्यत्र शामिल न किए गए बौद्धिक संपत्ति के उपयोग के लिए प्रभार	290	2729	-2438	319	3365	-3046
1.अ.ख.9 दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवाएं	41116	6606	34509	42137	5707	36430
1.अ.ख.10 अन्य कारोबारी सेवाएं	22260	16314	5945	22620	16388	6232
1.अ.ख.11 वैयक्तिक, सांस्कृतिक और मनोरंजन संबंधी सेवाएं	1045	1390	-346	1253	1496	-243
1.अ.ख.12 अन्यत्र शामिल न किए गए सरकारी माल और सेवाएं	144	307	-163	129	315	-186
1.अ.ख.13 अन्य जो अन्यत्र शामिल नहीं है	178	464	-286	575	324	251
1.आ प्राथमिक आय (1.आ.1 से 1.आ.3)	**7706**	**20312**	**-12606**	**10455**	**25283**	**-14828**
1.आ.1 कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति	1695	917	778	1932	1039	893
1.आ.2 निवेश आय	4839	18772	-13934	6758	23566	-16808
1.आ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश	2156	10609	-8453	2518	13929	-11411
1.आ.2.2 संविभाग निवेश	78	2755	-2676	94	2383	-2289
1.आ.2.3 अन्य निवेश	210	5246	-5035	874	7026	-6152
1.आ.2.4 रिज़र्व आस्तियां	2393	163	2231	3272	229	3043
1.आ.3 अन्य प्राथमिक आय	1172	623	549	1765	678	1087
1.इ द्वितीयक आय (1.इ.1+1.इ.2)	**28650**	**3868**	**24782**	**32093**	**3356**	**28737**
1.इ.1 वित्तीय निगम, वित्तेतर निगम, परिवार और एनपीआईएसएच	28627	3547	25080	32046	3096	28950
1.इ.1.1 वैयक्तिक अंतरण (निवासी और / अनिवासी परिवारों के बीच चालू अंतरण)	27984	2631	25352	31301	2324	28977
1.इ.1.2 अन्य चालू अंतरण	643	915	-272	745	772	-27
1.इ.2 सामान्य सरकार	23	321	-298	48	260	-212
2. पूँजी खाता (2.1+2.2)	**272**	**260**	**12**	**182**	**138**	**44**
2.1 अनुत्पादित वित्तेतर आस्तियों का सकल अधिग्रहण (नामे) / निस्तारण (जमा)	120	35	85	21	50	-30
2.2 पूँजी अंतरण	152	225	-73	161	87	74
3. वित्तीय खाता (3.1 से 3.5)	**153151**	**152222**	**929**	**247933**	**254216**	**-6283**
3.1 प्रत्यक्ष निवेश (3.1अ+3.1आ)	**17084**	**10730**	**6355**	**19834**	**17881**	**1954**
3.1अ भारत में प्रत्यक्ष निवेश	15858	6538	9319	19128	11411	7718
3.1.अ.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	14684	6254	8430	18095	10934	7161
3.1.अ.1.1 अर्जनों के पुनर्निवेश से इतर इक्विटी	9708	6254	3454	12762	10934	1829
3.1.अ.1.2 अर्जनों का पुनर्निवेश	4976	0	4976	5332		5332
3.1.अ.2 ऋण लिखत	1173	284	889	1034	477	557
3.1.अ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश उद्यमों में प्रत्यक्ष निवेशक	1173	284	889	1034	477	557
3.1.आ. भारत द्वारा प्रत्यक्ष निवेश	1227	4191	-2964	706	6470	-5764
3.1.आ.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	1227	3226	-1999	706	4655	-3949
3.1.आ.1.1 अर्जनों के पुनर्निवेश को छोड़कर इक्विटी	1227	2123	-896	706	3208	-2503
3.1.आ.1.2 अर्जनों का पुनर्निवेश	0	1103	-1103		1446	-1446
3.1.आ.2 ऋण लिखत	0	965	-965	0	1815	-1815
3.1.आ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश उद्यमों में प्रत्यक्ष निवेशक	0	965	-965		1815	-1815
3.2 संविभाग निवेश	**66697**	**68361**	**-1664**	**138877**	**127485**	**11392**
3.2अ भारत में संविभाग निवेश	66117	67704	-1588	138217	126638	11579
3.2.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	57476	59959	-2483	120154	112150	8004
3.2.2 ऋण प्रतिभूतियां	8640	7745	895	18063	14487	3575
3.2आ. भारत द्वारा संविभाग निवेश	580	657	-77	660	847	-187
3.3 वित्तीय डेरिवेटिव (रिज़र्व निधियों को छोड़कर) और कर्मचारी स्टॉक ऑप्शन	**3661**	**6332**	**-2671**	**6126**	**9280**	**-3154**
3.4 अन्य निवेश	**65708**	**61219**	**4489**	**83096**	**68816**	**14280**
3.4.1 अन्य इक्विटी (एडीआर/जीडीआर)	0	0	0	0	0	0
3.4.2 मुद्रा और जमाराशियां	21141	17485	3656	26996	20678	6318
3.4.2.1 केंद्रीय बैंक (रूपी कर्ज मूवमेंट; एनआरजी)	75	0	75	955	0	955
3.4.2.2 केंद्रीय बैंक को छोड़कर जमाराशियां लेनेवाले निगम (अनिवासी भारतीय जमाराशियां)	21066	17485	3581	26041	20678	5363
3.4.2.3 सामान्य सरकार	0	0	0			0
3.4.2.4 अन्य क्षेत्र	0	0	0			0
3.4.3 ऋण (बाह्य सहायता, ईसीबी और बैंकिंग पूँजी)	17418	21782	-4364	32426	28113	4313
3.4.3अ भारत को ऋण	17139	21378	-4239	29017	23774	5243
3.4.3आ भारत द्वारा ऋण	280	404	-125	3409	4339	-929
3.4.4 बीमा, पेंशन, और मानकीकृत गारंटी योजनाएं	41	30	11	54	85	-31
3.4.5 व्यापार ऋण और अग्रिम	15950	16237	-287	12000	13969	-1969
3.4.6 अन्य खाते प्राप्य/देय-अन्य	11157	5685	5472	11620	5972	5648
3.4.7 विशेष आहरण अधिकार	0	0	0			0
3.5 आरक्षित आस्तियां	**0**	**5579**	**-5579**	**0**	**30754**	**-30754**
3.5.1 मौद्रिक स्वर्ण	0	0	0			0
3.5.2 विशेष आहरण अधिकार एन.ए	0	0	0			0
3.5.3 आईएमएफ में रिज़र्व निधियों की स्थिति एन.ए	0	0	0			0
3.5.4 अन्य रिज़र्व आस्तियां (विदेशी मुद्रा आस्तियां)	0	5579	-5579	0	30754	-30754
4. कुल आस्तियां / देयताएं	**153151**	**152222**	**929**	**247933**	**254216**	**-6283**
4.1 इक्विटी तथा निवेश निधि शेयर	77670	76458	1212	145795	137951	7844
4.2 ऋण लिखत	64323	64499	-176	90518	79539	10979
4.3 अन्य वित्तीय आस्तियां और देयताएं	11157	11265	-107	11620	36725	-25105
5. निवल भूल-चूक	**395**	**0**	**395**	**538**		**538**

टिप्पणी: प्रा: प्रारंभिक

सं. 41: बीपीएम 6 के अनुसार भारत में भुगतान संतुलन का मानक प्रस्तुतीकरण

(₹ करोड़)

मद	जन.-मार्च 2023			जन.-मार्च 2024 (प्रा)		
	जमा	नामे	निवल	जमा	नामे	निवल
	1	2	3	4	5	6
1. चालू खाता (1.अ+1.आ+1.इ)	1958000	1968993	-10992	2105225	2057890	47336
1.अ माल और सेवाएं (1.अ.क.+ 1अ.ख.)	1658921	1770076	-111155	1751957	1820108	-68150
1.अ.क. माल (1.अ.क.1 से 1अ.क.3)	952809	1385415	-432606	1010049	1432606	-422556
1.अ.क.1 बीओपी आधार पर सामान्य वाणिज्यिक वस्तुएं	948262	1330884	-382622	1007561	1352971	-345410
1.अ.क.2 वाणिज्यिक के अंतर्गत माल का निवल निर्यात	4548	0	4548	2488	0	2488
1..अ.क.3 गैर-मौद्रिक स्वर्ण	0	54532	-54532	0	79635	-79635
1.अ.ख सेवाएं (1.अ.ख.1 से 1.अ.ख.13)	706112	384660	321451	741908	387502	354406
1.अ.ख.1 अन्य के स्वामित्व वाले भौतिक इनपुट पर विनिर्माण सेवाएं	2689	425	2264	2923	146	2778
1.अ.ख.2 अन्यत्र शामिल न की गई रखरखाव व मरम्मत सेवाएं	464	5295	-4831	455	3786	-3331
1.अ.ख.3 परिवहन	65454	66565	-1111	64527	65002	-475
1.अ.ख.4 यात्रा	69476	63331	6145	82705	66948	15758
1.अ.ख.5 निर्माण	9040	5797	3244	13763	6567	7196
1.अ.ख.6 बीमा और पेंशन सेवाएं	6777	3740	3037	7699	5395	2304
1.अ.ख.7 वित्तीय सेवाएं	17215	10718	6497	13280	10537	2743
1.अ.ख.8 अन्यत्र शामिल न किए गए बौद्धिक संपत्ति के उपयोग के लिए प्रभार	2389	22449	-20059	2648	27942	-25294
1.अ.ख.9 दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवाएं	338240	54349	283891	349851	47384	302467
1.अ.ख.10 अन्य कारोबारी सेवाएं	183122	134212	48910	187807	136067	51740
1.अ.ख.11 वैयक्तिक, सांस्कृतिक और मनोरंजन संबंधी सेवाएं	8596	11438	-2842	10404	12421	-2016
1.अ.ख.12 अन्यत्र शामिल न किए गए सरकारी माल और सेवाएं	1185	2525	-1339	1073	2616	-1543
1.अ.ख.13 अन्य जो अन्यत्र शामिल नहीं है	1463	3817	-2354	4771	2691	2081
1.आ प्राथमिक आय (1.आ.1 से 1.आ.3)	63392	167098	-103707	86804	209917	-123113
1.आ.1 कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति	13948	7544	6404	16041	8627	7414
1.आ.2 निवेश आय	39805	154433	-114627	56107	195663	-139556
1.आ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश	17740	87278	-69538	20904	115646	-94742
1.आ.2.2 संविभाग निवेश	644	22661	-22016	782	19786	-19004
1.आ.2.3 अन्य निवेश	1731	43156	-41425	7255	58332	-51077
1.आ.2.4 रिज़र्व आस्तियां	19690	1338	18352	27166	1900	25266
1.आ.3 अन्य प्राथमिक आय	9638	5122	4516	14656	5627	9029
1.इ द्वितीयक आय (1.इ.1+1.इ.2)	235688	31819	203869	266464	27865	238599
1.इ.1 वित्तीय निगम, वित्तेतर निगम, परिवार और एनपीआईएसएच	235499	29176	206322	266068	25705	240363
1.इ.1.1 वैयक्तिक अंतरण (निवासी और / अनिवासी परिवारों के बीच चालू अंतरण)	230210	21647	208563	259885	19295	240591
1.इ.1.2 अन्य चालू अंतरण	5288	7529	-2241	6183	6410	-227
1.इ.2 सामान्य सरकार	189	2642	-2453	396	2160	-1764
2. पूँजी खाता (2.1+2.2)	2237	2137	100	1509	1144	364
2.1 अनुत्पादित वित्तेतर आस्तियों का सकल अधिग्रहण (नामे) / निस्तारण (जमा)	986	288	698	171	419	-248
2.2 पूँजी अतंरण	1250	1849	-599	1338	725	613
3. वित्तीय खाता (3.1 से 3.5)	1259902	1252260	7643	2058523	2110686	-52163
3.1 प्रत्यक्ष निवेश (3.1अ+3.1आ)	140546	88268	52278	164679	148458	16220
3.1अ भारत में प्रत्यक्ष निवेश	130453	53788	76665	158819	94741	64078
3.1.अ.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	120800	51450	69350	150237	90780	59457
3.1.अ.1.1 अर्जनों के पुनर्निवेश से इतर इक्विटी	79863	51450	28413	105963	90780	15183
3.1.अ.1.2 अर्जनों का पुनर्निवेश	40937	0	40937	44274	0	44274
3.1.अ.2 ऋण लिखत	9652	2338	7315	8582	3960	4621
3.1.अ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश उद्यमों में प्रत्यक्ष निवेशक	9652	2338	7315	8582	3960	4621
3.1.आ. भारत द्वारा प्रत्यक्ष निवेश	10093	34480	-24387	5860	53718	-47858
3.1.आ.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	10093	26539	-16446	5860	38647	-32787
3.1.आ.1.1 अर्जनों के पुनर्निवेश को छोड़कर इक्विटी	10093	17465	-7372	5860	26638	-20778
3.1.आ.1.2 अर्जनों का पुनर्निवेश	0	9073	-9073	0	12009	-12009
3.1.आ.2 ऋण लिखत	0	7941	-7941	0	15071	-15071
3.1.आ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश उद्यमों में प्रत्यक्ष निवेशक	0	7941	-7941	0	15071	-15071
3.2 संविभाग निवेश	548685	562376	-13691	1153057	1058474	94583
3.2अ भारत में संविभाग निवेश	543912	556972	-13060	1147577	1051439	96139
3.2.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	472831	493254	-20423	997608	931154	66454
3.2.2 ऋण प्रतिभूतियां	71080	63718	7363	149969	120285	29685
3.2आ. भारत द्वारा संविभाग निवेश	4774	5404	-631	5480	7035	-1555
3.3 वित्तीय डेरिवेटिव (रिज़र्व निधियों को छोड़कर) और कर्मचारी स्टॉक ऑप्शन	30121	52094	-21973	50865	77053	-26187
3.4 अन्य निवेश	540550	503623	36927	689922	571362	118560
3.4.1 अन्य इक्विटी (एडीआर/जीडीआर)	0	0	0	0	0	0
3.4.2 मुद्रा और जमाराशियां	173921	143842	30080	224139	171683	52457
3.4.2.1 केंद्रीय बैंक (रूपी कर्ज मूवमेंट; एनआरजी)	619	0	619	7926	0	7926
3.4.2.2 केंद्रीय बैंक को छोड़कर जमाराशियां लेनेवाले निगम (अनिवासी भारतीय जमाराशियां)	173302	143842	29461	216214	171683	44531
3.4.2.3 सामान्य सरकार	0	0	0	0	0	0
3.4.2.4 अन्य क्षेत्र	0	0	0	0	0	0
3.4.3 ऋण (बाह्य सहायता, ईसीबी और बैंकिंग पूँजी)	143291	179189	-35898	269228	233414	35814
3.4.3अ भारत को ऋण	140991	175865	-34873	240921	197391	43530
3.4.3आ भारत द्वारा ऋण	2300	3324	-1024	28307	36024	-7717
3.4.4 बीमा, पेंशन, और मानकीकृत गारंटी योजनाएं	337	245	92	448	704	-257
3.4.5 व्यापार ऋण और अग्रिम	131214	133577	-2364	99631	115980	-16349
3.4.6 अन्य खाते प्राप्य/देय-अन्य	91787	46770	45017	96475	49580	46895
3.4.7 विशेष आहरण अधिकार	0	0	0	0	0	0
3.5 आरक्षित आस्तियां	0	45899	-45899	0	255339	-255339
3.5.1 मौद्रिक स्वर्ण	0	0	0	0	0	0
3.5.2 विशेष आहरण अधिकार एन.ए	0	0	0	0	0	0
3.5.3 आईएमएफ में रिज़र्व निधियों की स्थिति एन.ए	0	0	0	0	0	0
3.5.4 अन्य रिज़र्व आस्तियां (विदेशी मुद्रा आस्तियां)	0	45899	-45899	0	255339	-255339
4. कुल आस्तियां / देयताएं	1259902	1252260	7643	2058523	2110686	-52163
4.1 इक्विटी तथा निवेश निधि शेयर	638957	628987	9970	1210498	1145373	65124
4.2 ऋण लिखत	529159	530604	-1445	751550	660393	91157
4.3 अन्य वित्तीय आस्तियां और देयताएं	91787	92669	-883	96475	304919	-208444
5. निवल भूल-चूक	3250	0	3250	4463	0	4463

टिप्पणीः प्रा: प्रारंभिक

सं. 42: अंतरराष्ट्रीय निवेश की स्थिति

(मिलियन अमेरिकी डॉलर)

मद	वित्तीय वर्ष / समाप्त तिमाही की स्थिति							
	2023-24		2023				2024	
			मार्च		दिसं.		मार्च	
	आस्तियां	देयताएं	आस्तियां	देयताएं	आस्तियां	देयताएं	आस्तियां	देयताएं
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. विदेश/भारत में प्रत्यक्ष निवेश	242271	542516	225592	523322	236506	536795	242271	542516
1.1 इक्विटी पूंजी*	153343	511142	142071	493896	149394	505572	153343	511142
1.2 अन्य पूंजी	88927	31374	83521	29426	87112	31223	88927	31374
2. संविभाग निवेश	10286	283804	13106	243561	10661	269154	10286	283804
2.1 इक्विटी	8518	168679	7449	138958	8438	161206	8518	168679
2.2 ऋण	1768	115126	5657	104603	2223	107948	1768	115126
3. अन्य निवेश	129328	563664	101420	518847	120558	552330	129328	563664
3.1 व्यापार ऋण	33450	118598	27507	124304	31689	120355	33450	118598
3.2 ऋण	13578	221964	9256	202334	14845	215009	13578	221964
3.3 मुद्रा और जमाराशियां	52803	154787	33046	141133	44452	149326	52803	154787
3.4 अन्य आस्तियां/देयताएं	29497	46404	31612	28815	29572	45438	29497	46404
4. आरक्षित निधियाँ	646419		578449		622452		646419	
5. कुल आस्तियां/देयताएं	1028304	1389984	918567	1285729	990178	1358280	1028304	1389984
6. निवल आईआईपी (आस्तियां - देयताएं)	-361680		-367162		-368102		-361680	

टिप्पणी: * इक्विटी पूंजी में निवेश निधि और पुनर्निवेशित अर्जन का शेयर शामिल है।

भुगतान और निपटान प्रणाली

सं. 43: भुगतान प्रणाली संकेतक

भाग I - भुगतान प्रणाली संकेतक – भुगतान तथा निपटान प्रणाली सांख्यिकी

प्रणाली	मात्रा (लाख)				मूल्य (₹ करोड़)			
	वि.व. 2023-24	2023	2024		वि.व. 2023-24	2023	2024	
		जुला.	जून	जुला.		जुला.	जून	जुला.
	1	2	3	4	5	6	7	8
ए. निपटान प्रणाली								
वित्तीय बाजार अवसंरचना (एफएमआई)								
1 सीसीआईएल प्रचालित प्रणाली (1.1 से 1.3)	43.04	3.83	4.36	4.54	259206893	21113033	22580094	25280807
1.1 सरकारी प्रतिभूति समाशोधन (1.10.1 से 1.1.3)	16.80	1.53	1.60	1.71	170464587	14338395	15107943	17139102
1.1.1 आउटराइट	9.51	0.87	0.97	1.03	13463848	1200245	1372786	1524120
1.1.2 रेपो	4.94	0.46	0.42	0.44	76718788	6722022	6414226	7150905
1.1.3 त्रि-पक्षीय रेपो	2.35	0.20	0.21	0.23	80281951	6416128	7320931	8464077
1.2 विदेशी मुद्रा समाशोधन	24.92	2.17	2.67	2.71	80984671	5937050	6953169	7417106
1.3 रुपये के डेरिवेटिव @	1.31	0.13	0.09	0.12	7757636	837588	518982	724598
बी. भुगतान प्रणाली								
I वित्तीय बाजार अवसंरचना (एफएमआई)	-	-	-	-	-	-	-	-
1 ऋण अंतरण - आरटीजीएस (1.1 से 1.2)	2700.16	211.89	231.84	246.68	170886670	13124561	16037694	15970680
1.1 ग्राहक लेनदेन	2686.04	210.72	230.72	245.48	152406168	11615417	14570686	14531533
1.2 अंतर्बैंक लेनदेन	14.12	1.17	1.12	1.19	18480503	1509144	1467008	1439147
II खुदरा								
2 ऋण अंतरण - खुदरा (2.1 से 2.6)	1486106.89	114189.63	155567.02	161225.51	67542859	5250943	6073917	6480748
2.1 एईपीएस (निधि अंतरण) @	3.92	0.32	0.30	0.31	261	22	16	13
2.2 एपीबीएस $	25888.17	2850.05	2929.34	2481.39	390743	45524	43676	28605
2.3 आईएमपीएस	60053.35	4897.10	5167.51	4902.84	6495652	512312	577794	593177
2.4 एनएसीएच जमा $	16227.27	1322.80	1311.11	1479.29	1525104	110184	113888	132397
2.5 एनईएफटी	72639.50	5476.79	7307.34	8006.14	39136014	3049364	3331461	3662264
2.6 यूपीआई @	1311294.68	99642.56	138851.42	144355.54	19995086	1533536	2007081	2064292
2.6.1 जिसमें से यूएसएसडी@	26.19	2.77	1.41	1.40	352	43	15	15
3 डेबिट ट्रांसफर और डायरेक्ट डेबिट (3.1 से 3.3)	18249.53	1473.10	1697.73	1734.76	1687658	130931	171469	175789
3.1 भीम आधार पे @	193.59	14.42	21.07	19.25	6112	457	581	575
3.2 एनएसीएच नामे $	16426.49	1327.06	1544.59	1588.11	1678769	130240	170756	175014
3.3 एनईटीसी (बैंक खाते से जुड़ा) @	1629.45	131.62	132.07	127.40	2777	233	132	200
4 कार्ड भुगतान (4.1 से 4.2)	58469.79	4882.21	5003.43	5294.35	2423563	198421	200081	217435
4.1 क्रेडिट कार्ड (4.1.1 से 4.1.2)	35610.15	2780.90	3579.49	3837.80	1831134	145108	158822	172670
4.1.1 पीओएस आधारित $	18614.08	1434.21	1895.40	1970.94	651911	49789	59417	62284
4.1.2 अन्य $	16996.08	1346.69	1684.10	1866.86	1179223	95319	99405	110386
4.2 डेबिट कार्ड (4.2.1 से 4.2.1)	22859.64	2101.31	1423.94	1456.56	592429	53313	41259	44765
4.2.1 पीओएस आधारित $	16477.95	1485.21	1063.60	1068.60	393589	33513	27630	28600
4.2.2 अन्य $	6381.69	616.10	360.33	387.96	198840	19801	13629	16165
5 प्रीपेड भुगतान लिखत (5.1 से 5.2)	78775.40	6393.08	5236.08	5356.71	283048	23238	15897	16327
5.1 वालेट	63256.69	5068.53	4038.05	4009.69	234353	19736	11298	11386
5.2 कार्ड (5.2.1 से 5.2.2)	15518.71	1324.55	1198.03	1347.01	48695	3502	4599	4941
5.2.1 पीओएस आधारित $	8429.87	714.15	650.89	713.97	11247	775	946	940
5.2.2 अन्य $	7088.84	610.40	547.14	633.05	37447	2727	3653	4001
6 पेपर-आधारित लिखत (6.1 से 6.2)	6632.10	555.48	484.42	531.00	7212333	587310	553834	610685
6.1 सीटीएस (एनपीसीआई प्रबंधित)	6632.10	555.48	484.42	531.00	7212333	587310	553834	610685
6.2 अन्य	0.00	–	–	–	–	–	–	–
कुल - खुदरा भुगतान (2 + 3 + 4 + 5 + 6)	1648233.71	127493.51	167988.69	174142.33	79149461	6190842	7015198	7500984
कुल भुगतान (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	1650933.88	127705.40	168220.52	174389.01	250036131	19315404	23052892	23471665
कुल डिजिटल भुगतान (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	1644301.78	127149.92	167736.10	173858.01	242823799	18728094	22499058	22860979

भाग II - भुगतान के प्रकार तथा चैनल

प्रणाली	मात्रा (लाख)				मूल्य (₹ करोड़)			
	वि . व. 2023-24	2023	2024		वि.व. 2023-24	2023	2024	
		जुला.	जून	जुला.		जुला.	जून	जुला.
	1	2	3	4	5	6	7	8
ए. अन्य भुगतान चैनल								
1 मोबाइल भुगतान (मोबाइल ऐप आधारित) (1.1 से 1.2)	1252599.21	93340.31	134138.30	139896.47	30687088	2316954	3062709	3175645
1.1 अंतबैंक $	83000.56	6400.03	9156.28	9299.86	5676805	428279	571044	599267
1.2 अंतर-बैंक $	1169598.65	86940.28	124982.02	130596.61	25010283	1888674	2491666	2576378
2 इंटरनेट भुगतान (नेटबैंकिंग / इंटरनेट ब्राउज़र आधारित) @ (2.1 से 2.2)	45034.98	3938.95	3717.20	4236.74	102117736	8157864	9505759	9894263
2.1 अंतबैंक @	12033.28	1107.74	1026.53	1225.09	53247042	4353820	4873274	5064291
2.2 अंतर-बैंक @	33001.71	2831.21	2690.67	3011.65	48870694	3804045	4632484	4829973
बी. एटीएम								
3 एटीएम से नकद निकासी $ (3.1 से 3.3)	66440.72	5590.96	5076.57	5069.38	3259388	269298	255229	250318
3.1 क्रेडिट कार्ड का उपयोग करना $	95.80	7.58	8.29	8.54	4648	357	426	433
3.2 डेबिट कार्ड का उपयोग करना $	66001.01	5553.98	5045.81	5040.14	3241538	267870	253844	248968
3.3 प्री-पेड कार्ड का उपयोग करना $	343.90	29.39	22.47	20.70	13202	1071	959	917
4 पीओएस पर नकद निकासी $ (4.1 से 4.2)	15.18	2.23	0.28	0.29	148	22	3	3
4.1 डेबिट कार्ड का उपयोग करना $	15.06	2.23	0.27	0.27	147	22	3	3
4.2 प्री-पेड कार्ड का उपयोग करना $	0.12	0.01	0.02	0.02	1	0	0	0
5 माइक्रो एटीएम में नकद निकासी @	11754.95	1078.92	973.79	944.29	314003	28950	24426	23498
5.1 एईपीएस @	11754.95	1078.92	973.79	944.29	314003	28950	24426	23498

भाग III - भुगतान अवसंरचना (लाख)

प्रणाली	मार्च 2024 तक	2023	2024	
		जुला.	जून	जुला.
	1	2	3	4
भुगतान प्रणाली अवसंरचना				
1 कार्ड की संख्या (1.1 से 1.2)	10667.22	10606.14	10835.23	10850.30
1.1 क्रेडिट कार्ड	1018.03	898.73	1038.13	1045.68
1.2 डेबिट कार्ड	9649.19	9707.41	9797.10	9804.62
2 पीपीआई की संख्या @ (2.1 से 2.2)	16743.63	16646.89	15051.30	15211.55
2.1 वालेट @	13381.80	13678.38	11375.61	11419.62
2.2 कार्ड @	3361.82	2968.51	3675.69	3791.93
3 एटीएम की संख्या (3.1 से 3.2)	2.58	2.57	2.56	2.55
3.1 बैंक के स्वामित्व वाले एटीएम $	2.23	2.21	2.21	2.21
3.2 व्हाइट लेबल एटीएम $	0.35	0.36	0.35	0.34
4 माइक्रो एटीएम की संख्या @	17.55	15.37	15.18	14.71
5 पीओएस टर्मिनलों की संख्या	89.03	81.23	89.67	89.72
6 भारत क्यूआर @	62.50	58.06	61.64	61.87
7 यूपीआई क्यूआर *	3434.93	2807.25	3230.03	3286.40

@: नवंबर 2019 से नया समावेश

#: सहकारी बैंकों, एलएबी और आरआरबी द्वारा रिपोर्ट किया गया डेटा शामिल किया गया जो दिसंबर 2021 से प्रभावी है।

$: नवंबर 2019 से अलग से शुरू किया गया समावेश - अभी तक अन्य मदों का हिस्सा रहा होगा।

* सितंबर 2020 से नया समावेश; केवल स्थिर यूपीआई क्यूआर कोड शामिल है।

टिप्पणियां: 1. डेटा अनंतिम है।

2. 31 जनवरी 2020 से ईसीएस (डेबिट और क्रेडिट) एनएसीएच के साथ मिला दिया गया है।
3. कार्ड पेमेंट्स (डेबिट / क्रेडिट कार्ड्स) और प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट (पीपीआई) के लिए नवबंर 2019 के डेटा की पहले के महीनों / अवधि के साथ तलुना नहीं हो सकती है, क्योंकि डेटा की परिभाषाओं में संशोधनं के साथ अधिक ग्रेन्युलर डेटा प्रकाशित किया जा रहा है।
4. केवल घरेलू वित्तीय लेनदेन पर विचार किया गया है। नए प्रारूप में ई-कॉमर्स लेनदेन; फास्ट टैग लेनदेन; डिजिटल बिल भुगतान और एटीएम आदि के माध्यम से कार्ड-टू-कार्ड ट्रांसफर आदि शामिल हैं। इसके अलावा, असफल लेनदेन, चार्जबैक, रिवर्सल, एक्सपायर्ड कार्ड / वॉलेट को शामिल नहीं किया गया है।

भाग I-ए. निपटान प्रणाली

1.1.3: प्रतिभूति खंड के तहत त्रि-पक्षीय रेपो 05 नवंबर 2018 से चालू हो गया है।

भाग I-बी. भुगतान प्रणाली

4.1.2: 'अन्य' में ई-कॉमर्स लेनदेन और एटीएम के माध्यम से डिजिटल बिल भुगतान आदि शामिल हैं।

4.2.2: 'अन्य' में ई-कॉमर्स लेनदेन, कार्ड से कार्ड ट्रांसफर और एटीएम के माध्यम से डिजिटल बिल भुगतान आदि शामिल हैं।

5: दिसंबर 2010 से उपलब्ध।

5.1: वस्तुओं और सेवाओं की खरीद और वॉलेट के माध्यम से फंड ट्रांसफर शामिल है।

5.2.2: ऑनलाइन लेनदेन और अन्य लेनदेन के लिए पीपीआई कार्ड का उपयोग शामिल है।

6.1: तीन ग्रिडों से संबंधित - मुंबई, नई दिल्ली और चेन्नई।

6.2: 'अन्य' में गैर-एमआईसीआर लेनदेन शामिल हैं जो 21 बैंकों द्वारा प्रबंधित समाशोधन गृहों से संबंधित हैं।

भाग II-ए. अन्य भुगतान चैनल

1: मोबाइल भुगतान -

बैंकों के मोबाइल ऐप्स और यूपीआई ऐप्स के माध्यम से किए गए लेनदेन शामिल।

जुलाई 2017 के डेटा में केवल व्यक्तिगत भुगतान और मोबाइल डिवाइस का उपयोग करके शुरू किए गए, संसाधित और अधिकृत कॉर्पोरेट भुगतान शामिल हैं। अन्य कॉर्पोरेट भुगतान जो मोबाइल डिवाइस का उपयोग करके शुरू, संसाधित और अधिकृत नहीं किए गए हैं, उन्हें बाहर रखा गया है।

2: इंटरनेट भुगतान - इसमें 'नेटबैंकिंग' के माध्यम से केवल ई-कॉमर्स लेनदेन और बैंक की इंटरनेट बैंकिंग वेबसाइट का उपयोग करके वित्तीय लेनदेन शामिल हैं।

भाग II-बी. एटीएम

3.3 और 4.2: केवल बैंक द्वारा जारी पीपीआई का उपयोग करके लेनदेन से संबंधित है।

भाग III. भुगतान प्रणाली अवसंरचना

3: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) और व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटरों (डब्ल्यूएलएओ) द्वारा तैनात एटीएम शामिल हैं। डब्ल्यूएलए को अप्रैल 2014 से शामिल किया गया है।

आवसरिक श्रृंखला

सं. 44 लघु बचत

(₹ करोड़)

श्रेणी		2022-23	2023		2024	
			फर.	दिसं.	जन.	फर.
		1	2	3	4	5
1. लघु बचत	**प्राप्तियां**	**173993**	**11210**	**16670**	**16076**	**14570**
	बकाया	**1636935**	**1599193**	**1789946**	**1805716**	**1819758**
1.1 कुल जमाराशियां	**प्राप्तियां**	**125209**	**8093**	**12386**	**11340**	**10025**
	बकाया	**1137451**	**1113230**	**1247555**	**1258895**	**1268920**
1.1.1 डाक घर बचत बैंक जमाराशियां	प्राप्तियां	20680	1170	2279	3014	1520
	बकाया	209112	200257	213964	216978	218498
1.1.2 सुकन्या समृद्धि योजना	प्राप्तियां	29003	1965	2171	2130	2233
	बकाया	87787	77472	104859	106989	109222
1.1.3 राष्ट्रीय बचत योजना, 1987	प्राप्तियां	-244	0	0	0	0
	बकाया	0	0	0	0	0
1.1.4 राष्ट्रीय बचत योजना, 1992	प्राप्तियां	-20	0	0	0	0
	बकाया	0	0	0	0	0
1.1.5 मासिक आय योजना	प्राप्तियां	6492	484	1713	1895	1927
	बकाया	242313	242198	263383	265278	267205
1.1.6 वरिष्ठ नागरिक योजना, 2004	प्राप्तियां	17971	1475	2197	2290	2153
	बकाया	137304	135986	169033	171323	173476
1.1.7 डाक घर मीयादी जमाराशियां	प्राप्तियां	29155	1814	2429	2379	2632
	बकाया	280436	278939	297989	300368	303000
1.1.7.1 1 वर्ष की मीयादी जमाराशियां	बकाया	125951	125377	135196	136762	138552
1.1.7.2 2 वर्ष की मीयादी जमाराशियां	बकाया	9497	9282	11265	11483	11730
1.1.7.3 3 वर्ष की मीयादी जमाराशियां	बकाया	7543	7380	8472	8628	8782
1.1.7.4 5 वर्ष की मीयादी जमाराशियां	बकाया	137445	136900	143056	143495	143936
1.1.8 डाक घर आवर्ती जमाराशियां	प्राप्तियां	21552	1203	1616	-344	-420
	बकाया	178422	176836	196491	196147	195727
1.1.9 डाक घर संचयी मीयादी जमाराशियां	प्राप्तियां	0	0	0	0	0
	बकाया	0	0	0	0	0
1.1.10 अन्य जमाराशियां	प्राप्तियां	288	-18	-19	-24	-20
	बकाया	1745	1439	1488	1464	1444
1.1.11 पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन	प्राप्तियां	332	0	0	0	0
	बकाया	332	103	348	348	348
1.2 बचत प्रमाणपत्र	**प्राप्तियां**	**33965**	**2504**	**3957**	**4247**	**3940**
	बकाया	**366317**	**363564**	**407244**	**411185**	**414597**
1.2.1 राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र VIII निर्गम	प्राप्तियां	10793	658	1213	1581	1446
	बकाया	165836	164750	177154	178735	180181
1.2.2 इंदिरा विकास पत्र	प्राप्तियां	0	0	0	0	0
	बकाया	0	0	0	0	0
1.2.3 किसान विकास पत्र	प्राप्तियां	-1892	0	0	0	0
	बकाया	0	0	0	0	0
1.2.4 किसान विकास पत्र-2014	प्राप्तियां	25064	1846	1568	1561	1428
	बकाया	199624	197646	216509	218070	219498
1.2.5 राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र VI निर्गम	प्राप्तियां	0	0	0	0	0
	बकाया	0	0	0	0	0
1.2.6 राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र VII निर्गम	प्राप्तियां	0	0	0	0	0
	बकाया	0	0	0	0	0
1.2.7 एम.एस. प्रमाणपत्र	प्राप्तियां		0	1176	1105	1066
	बकाया		0	15064	16169	17235
1.2.8 अन्य प्रमाणपत्र	बकाया	857	1168	-1483	-1789	-2317
1.3 लोक भविष्य निधि	**प्राप्तियां**	**14819**	**613**	**327**	**489**	**605**
	बकाया	**133167**	**122399**	**135147**	**135636**	**136241**

टिप्पणी : अप्रैल 2017 से प्राप्तियों का डाटा निवल प्राप्तियाँ हैं, अर्थात सकल प्राप्तियों से सकल भुगतान को घटाने पर प्राप्त।

स्रोत : महालेखाकार, पोस्ट और टेलीग्राफ।

सं. 45 केंद्र और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों के स्वामित्व का स्वरूप

(प्रतिशत)

केंद्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां

श्रेणी	2023			2024	
	जून	सितं	दिसं.	मार्च	जून
	1	2	3	4	5
(क) कुल (₹ करोड़ में)	**9898751**	**10383607**	**10538792**	**10740389**	**10946860**
1. वाणिज्यिक बैंक	36.58	37.96	37.55	37.66	37.52
2. सहकारी बैंक	1.56	1.52	1.49	1.47	1.42
3. गैर-बैंक प्राथमिक व्यापारी	0.73	0.66	0.67	0.66	0.70
4. बीमाकृत कंपनियां	26.21	26.05	26.16	25.98	26.11
5. म्यूच्युअल फंड	2.69	3.02	3.03	2.90	2.87
6. भविष्य निधियां	4.59	4.42	4.57	4.47	4.41
7. पेंशन निधि	4.18	4.32	4.44	4.52	4.74
8. वित्तीय संस्थाएं	1.20	0.54	0.55	0.55	0.57
9. कॉरपोरेट	1.22	1.21	1.33	1.35	1.44
10. विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक	1.59	1.61	1.92	2.34	2.34
11. भारतीय रिज़र्व बैंक	13.78	13.06	12.54	12.31	11.92
12. अन्य	5.67	5.64	5.74	5.79	5.97
12.1 राज्य सरकार	2.03	2.04	2.07	2.04	2.13

राज्य सरकारों की प्रतिभूतियां

श्रेणी	2023			2024	
	जून	सितं	दिसं.	मार्च	जून
	1	2	3	4	5
(ख) कुल (₹ करोड़ में)	**5050874**	**5161642**	**5338587**	**5646219**	**5727482**
1. वाणिज्यिक बैंक	34.13	33.87	33.90	34.14	33.85
2. सहकारी बैंक	3.68	3.60	3.53	3.39	3.38
3. गैर-बैंक प्राथमिक व्यापारी	0.50	0.61	0.63	0.60	0.59
4. बीमाकृत कंपनियां	26.73	26.97	26.64	26.14	25.85
5. म्यूच्युअल फंड	2.08	1.86	2.00	2.09	2.08
6. भविष्य निधियां	21.19	21.70	22.00	22.35	22.94
7. पेंशन निधि	4.84	4.82	4.56	4.76	4.87
8. वित्तीय संस्थाएं	1.82	1.65	1.63	1.59	1.58
9. कॉरपोरेट	1.92	1.87	2.03	2.02	2.03
10. विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक	0.02	0.02	0.03	0.07	0.05
11. भारतीय रिज़र्व बैंक	0.70	0.69	0.66	0.63	0.62
12. अन्य	2.39	2.34	2.37	2.20	2.17
12.1 राज्य सरकार	0.27	0.27	0.27	0.25	0.26

खज़ाना बिल

श्रेणी	2023			2024	
	जून	सितं	दिसं.	मार्च	जून
	1	2	3	4	5
(ग) कुल (₹ करोड़ में)	**1012301**	**925317**	**849151**	**871662**	**858193**
1. वाणिज्यिक बैंक	47.64	56.35	57.18	58.53	47.79
2. सहकारी बैंक	1.20	1.20	1.28	1.67	1.49
3. गैर-बैंक प्राथमिक व्यापारी	1.99	0.54	1.70	1.66	2.69
4. बीमाकृत कंपनियां	4.93	5.26	5.50	5.06	5.78
5. म्यूच्युअल फंड	17.04	12.74	11.21	11.89	14.50
6. भविष्य निधियां	1.46	1.52	0.08	0.15	0.60
7. पेंशन निधि	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00
8. वित्तीय संस्थाएं	7.96	4.10	5.34	7.16	6.56
9. कॉरपोरेट	4.42	4.00	4.58	4.50	4.79
10. विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक	0.12	0.10	0.07	0.01	0.20
11. भारतीय रिज़र्व बैंक	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12. अन्य	13.23	14.17	13.06	9.36	15.59
12.1 राज्य सरकार	10.33	11.36	9.26	5.88	11.55

नोट: (-) शून्य या नगण्य को दर्शाता है

बुलेटिन के जून 2023 के संस्करण से टेबल फार्मेट संशोधित किया है।

राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (यूडीएवाई) के अंतर्गत जारी विशेष बॉण्ड शामिल हैं।

वाणिज्यिक बैंकों के अंतर्गत बैंक के प्राथमिक डीलरों को शामिल किया गया है। तथापि, कुल बकाया प्रतिभूतियों में इनका हिस्सा बहुत कम है।

अन्य' श्रेणी में राज्य सरकारें, डीआईसीजीसी, पीएसयू, ट्रस्ट, केंद्रीय विदेशी बैंक, हिंदू अविभक्त परिवार/व्यक्ति आदि शामिल हैं।

सितंबर 2023 के बाद के आंकड़ों में एक बैंक का एक गैर-बैंक के साथ विलय का प्रभाव शामिल है।

सं. 46: केन्द्र और राज्य सरकारों की संयुक्त प्राप्तियां और संवितरण

(₹ करोड़)

मद	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (सं.अ.)	2023-24 (ब.अ.)
	1	2	3	4	5	6
1. कुल वितरण	**5040747**	**5410887**	**6353359**	**7098451**	**8376972**	**9045119**
1.1 विकास संबंधी	2882758	3074492	3823423	4189146	5073367	5426440
1.1.1 राजस्व	2224367	2446605	3150221	3255207	3838714	3836447
1.1.2 पूंजी	596774	588233	550358	861777	1146013	1471534
1.1.3 ऋण	61617	39654	122844	72163	88639	118460
1.2 गैर-विकास संबंधी	2078276	2253027	2442941	2810388	3188699	3490946
1.2.1 राजस्व	1965907	2109629	2271637	2602750	2988556	3277722
1.2.1.1 ब्याज भुगतान	894520	955801	1060602	1226672	1403183	1589435
1.2.2 पूंजी	111029	141457	169155	175519	196688	208268
1.2.3 ऋण	1340	1941	2148	32119	3455	4957
1.3 अन्य	79713	83368	86995	98916	114906	127733
2. कुल प्राप्तियां	**5023352**	**5734166**	**6397162**	**7156342**	**8258187**	**9149787**
2.1 राजस्व प्राप्तियां	3797731	3851563	3688030	4823821	5706246	6337126
2.1.1 कर प्राप्तियां	3278947	3231582	3193390	4160414	4837048	5477428
2.1.1.1 पण्य और सेवाओं पर कर	2030050	2012578	2076013	2626553	2967610	3372525
2.1.1.2 आय और संपत्ति पर कर	1246083	1216203	1114805	1530636	1865298	2100430
2.1.1.3 संघशासित क्षेत्र (बिना विधान मंडल के) के कर	2814	2800	2572	3225	4140	4473
2.1.2 गैर-कर प्राप्तियां	518783	619981	494640	663407	869198	859698
2.1.2.1 ब्याज प्राप्तियां	36273	31137	33448	35250	37974	45199
2.2 गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियां	140287	110094	64994	44077	88273	119373
2.2.1 ऋण और अग्रिम की वसूली	44667	59515	16951	27665	25661	34501
2.2.2 विनिवेश से प्राप्त राशि	95621	50578	48044	16412	62611	84872
3. सकल वित्तीय घाटा [1-(2.1+2.2)]	**1102729**	**1449230**	**2600335**	**2230553**	**2582453**	**2588620**
3 क वित्तपोषण के स्रोत : संस्था-वार						
3क.1 घरेलू वित्तपोषण	1097210	1440548	2530155	2194406	2558579	2566503
3क.1.1 सरकार को निवल बैंक ऋण	387091	571872	890012	627255	687904	...
3क.1.1.1 सरकार को निवल भा.रि. बैंक का ऋण	325987	190241	107493	350911	529	...
3क.1.2 सरकार को गैर-बैंक ऋण	710119	868676	1640143	1567151	1870675	...
3क.2 बाह्य वित्तपोषण	5519	8682	70180	36147	23874	22118
3ख. वित्तपोषण के स्रोत : लिखत-वार						
3ख.1 घरेलू वित्तपोषण	1097210	1440548	2530155	2194406	2558579	2566503
3ख.1.1 बाज़ार उधार (निवल)	795845	971378	1696012	1213169	1776747	1902862
3ख.1.2 लघु बचत (निवल)	88961	209232	458801	526693	403838	441189
3ख.1.3 राज्य भविष्य निधियां (निवल)	51004	38280	41273	28100	36454	37114
3ख.1.4 आरक्षित निधियां	-18298	10411	4545	42153	3524	24429
3ख.1.5 जमाराशियां और अग्रिम	66289	-14227	25682	42203	82485	58404
3ख.1.6 नकद शेष	17395	-323279	-43802	-57891	118784	-104667
3ख.1.7 अन्य	96014	548753	347643	399980	136748	207172
3ख.2 बाह्य वित्तपोषण	5519	8682	70180	36147	23874	22118
4. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कुल वितरण	*26.7*	*26.9*	*32.0*	*30.1*	*31.1*	*30.0*
5. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कुल प्राप्तियां	*26.6*	*28.5*	*32.2*	*30.3*	*30.6*	*30.3*
6. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजस्व प्राप्तियां	*20.1*	*19.2*	*18.6*	*20.4*	*21.2*	*21.0*
7. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कर प्राप्तियां	*17.3*	*16.1*	*16.1*	*17.6*	*17.9*	*18.2*
8. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में सकल वित्तीय घाटा	*5.8*	*7.2*	*13.1*	*9.5*	*9.6*	*8.6*

… : उपलब्ध नहीं। सं.अ. संशोधित अनुमान, ब.अ. बज़ट अनुमान।
स्रोत : केन्द्रीय और राज्य सरकारों का बजट दस्तावेज।
टिप्पणी : जीडीपी डेटा 2011-12 के आधार पर है। 2023-24 के लिए जीडीपी केंद्रीय बजट 2023-24 से है।
डेटा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है।
1 और 2: डेटा केंद्र सरकार (एनएसएसएफ को पुनर्भुगतान सहित) और राज्य सरकारों के निवल पुनर्भुगतान का है।
1.3: राज्यों द्वारा स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर और समनुदेशन का प्रतिनिधित्व करता है।
2: डेटा केंद्र और राज्य सरकारों के नकदी शेष में निवल भिन्नता को दर्शाता है और इसमें केंद्र और राज्य सरकारों की उधार प्राप्तियां शामिल हैं।
3ए.1.1: आरबीआई रिकॉर्ड के अनुसार डेटा।
3बी.1.1: दिनांकित प्रतिभूतियों के माध्यम से उधार।
3बी.1.2: राष्ट्रीय अल्प बचत निधि (एनएसएसएफ) द्वारा केंद्र और राज्य सरकारों की विशेष प्रतिभूतियों में निवल निवेश को दर्शाता है।
नए डेटा की उपलब्धता के साथ घटकों में समायोजन के कारण यह डेटा पिछले प्रकाशनों से भिन्न हो सकता है।
3बी.1.6: केंद्र द्वारा राज्य सरकारों को अर्थोपाय अग्रिम शामिल हैं।
3बी.1.7: ट्रेजरी बिल, वित्तीय संस्थाओं से ऋण, बीमा और पेंशन निधि, विप्रेषण, नकद शेष निवेश खाता शामिल हैं।

सं.47: विभिन्न सुविधाओं के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा ली गई वित्तीय सहायता

(₹ करोड़)

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	जुलाई 2024 के दौरान					
		विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ)		अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए)		ओवरड्राफ्ट (ओडी)	
		प्राप्त औसत राशि	सुविधा प्राप्त करने के दिनों की संख्या	प्राप्त औसत राशि	सुविधा प्राप्त करने के दिनों की संख्या	प्राप्त औसत राशि	सुविधा प्राप्त करने के दिनों की संख्या
	1	2	3	4	5	6	7
1	आंध्र प्रदेश	5262.65	31	2128.16	9	-	-
2	अरुणाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	-
3	असम	262.43	8	-	-	-	-
4	बिहार	-	-	-	-	-	-
5	छत्तीसगढ़	-	-	-	-	-	-
6	गोवा	71.19	1	-	-	-	-
7	गुजरात	-	-	-	-	-	-
8	हरियाणा	580.75	16	-	-	-	-
9	हिमाचल प्रदेश	-	-	375.33	8	-	-
10	जम्मू और कश्मीर संघ शासित प्रदेश	-	-	934.81	22	363.92	4
11	झारखंड	-	-	-	-	-	-
12	कर्नाटक	-	-	-	-	-	-
13	केरल	1404.10	31	1415.14	23	568.18	8
14	मध्य प्रदेश	-	-	-	-	-	-
15	महाराष्ट्र	-	-	-	-	-	-
16	मणिपुर	102.42	30	182.53	29	62.50	6
17	मेघालय	311.10	23	18.58	1	-	-
18	मिज़ोरम	51.64	6	-	-	-	-
19	नगालैंड	-	-	-	-	-	-
20	उड़ीसा	-	-	-	-	-	-
21	पुदुचेरी	-	-	-	-	-	-
22	पंजाब	3620.09	31	-	-	-	-
23	राजस्थान	2883.39	25	1546.00	9	-	-
24	तमिलनाडु	-	-	-	-	-	-
25	तेलंगाना	4198.91	31	481.72	15	-	-
26	त्रिपुरा	-	-	-	-	-	-
27	उत्तरप्रदेश	-	-	-	-	-	-
28	उत्तराखंड	901.61	9	-	-	-	-
29	पश्चिम बंगाल	-	-	-	-	-	-

टिप्पणीयां : 1) राज्य सरकारों द्वारा समेकित ऋण शोधन निधि (सीएसएफ), गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ) और नीलामी खज़ाना बिल (एटीबी) के शेष तथा सरकारी प्रतिभूतियों में किए गए अन्य निवेशों को संपाश्विक के तौर पर रखते हुए विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ) प्राप्त की जाती है।

2) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा राज्य सरकारों को उनके अल्प कालिक नकदी असंतुलन से निपटने के लिए अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) दिया जाता है।

3) राज्य सरकारों को उनकी अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) सीमा से अधिक की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अग्रिम के तौर पर ओवरड्राफ्ट दिया जाता है।

4) प्राप्त कुल सहायता (एसडीएफ/डब्ल्यूएमए/ओडी) को उन दिनों की संख्या से भाग देने पर, जिनके लिए माह के दौरान सहायता प्राप्त हुई, औसत राशि प्राप्त होती है।

5) -: नगण्य

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक

सं. 48: राज्य सरकारों द्वारा किए गये निवेश

(₹ करोड़)

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	जून 2024 के अंत तक			
		समेकित ऋण शोधन निधि (सीएसएफ)	गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ)	सरकारी प्रतिभूतियाँ	नीलामी खज़ाना बिल (एटीबी)
	1	2	3	4	5
1	आंध्र प्रदेश	11131	1098	0	0
2	अरुणाचल प्रदेश	2552	6	0	2150
3	असम	7174	87	0	0
4	बिहार	10526	-	0	11700
5	छत्तीसगढ़	7514	62	0	6165
6	गोवा	1013	441	0	0
7	गुजरात	13867	642	0	9000
8	हरियाणा	2252	1634	0	0
9	हिमाचल प्रदेश	-	-	0	0
10	जम्मू और कश्मीर संघ शासित प्रदेश	19	18	0	0
11	झारखंड	2321	-	0	750
12	कर्नाटक	19569	724	0	49493
13	केरल	3001	-	0	0
14	मध्य प्रदेश	-	1229	0	0
15	महाराष्ट्र	67400	1680	0	0
16	मणिपुर	67	135	0	0
17	मेघालय	1230	105	0	0
18	मिज़ोरम	442	61	0	0
19	नगालैंड	1819	45	0	0
20	उड़ीसा	17527	1973	113	7154
21	पुदुचेरी	557	-	0	1300
22	पंजाब	8835	0	0	0
23	राजस्थान	466	-	129	8100
24	तमिलनाडु	3314	-	0	3476
25	तेलंगाना	7606	1663	0	0
26	त्रिपुरा	1178	26	0	300
27	उत्तरप्रदेश	4835	203	0	0
28	उत्तराखंड	10243	-	89	0
29	पश्चिम बंगाल	12520	942	239	0
	कुल	**218977**	**12773**	**570**	**99588**

टिप्पणियां 1. सीएसएफ और जीआरएफ कुछ राज्य सरकारों द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक के पास रखी गई आरक्षित निधियां हैं।
2. एटीबी में प्राथमिक बाजार में राज्य सरकारों द्वारा निवेश किए गए 91 दिनों, 182 दिनों और 364 दिनों के खजाना बिल शामिल हैं।
3. - : लागू नहीं (योजना का सदस्य नहीं)।

सं. 49: राज्य सरकारों की बाज़ार उधारियां

(₹ करोड़)

क्र.सं.	राज्य	2022-23		2023-24		2024-25						2024-25 में ली गई कुल राशि	
						मई		जून		जुला.			
		ली गई सकल राशि	ली गई निवल राशि	ली गई सकल राशि	ली गई निवल राशि	ली गई सकल राशि	ली गई निवल राशि	ली गई सकल राशि	ली गई निवल राशि	ली गई सकल राशि	ली गई निवल राशि	सकल	निवल
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	आंध्र प्रदेश	57478	45814	68400	55330	14000	11084	6000	4000	10000	10000	37000	29918
2	अरुणाचल प्रदेश	559	389	902	672	-	-50	-	-	-	-	-	-146
3	असम	17100	16105	18500	16000	2000	2000	-	-450	1000	1000	4000	3550
4	बिहार	36800	27467	47612	29910	-	-	-	-	-	-	-	-
5	छत्तीसगढ़	2000	-2287	32000	26213	-	-500	-	-250	-	-	-	-750
6	गोवा	1350	500	2550	1560	-	-	-	-200	200	100	200	-200
7	गुजरात	43000	28300	30500	11947	-	-	2000	-1000	-	-	2000	-1000
8	हरियाणा	45158	28638	47500	28364	2000	1000	5500	3925	3500	3345	12000	9270
9	हिमाचल प्रदेश	14000	11941	8072	5856	700	500	1200	1000	500	350	3400	2300
10	जम्मू और कश्मीर	8473	5969	16337	13904	2500	2350	2300	2150	3000	2700	7800	6900
11	झारखंड	4000	-155	1000	-2505	-	-	-	-	-	-	-	-
12	कर्नाटक	36000	26000	81000	63003	-	-1500	-	-1000	-	-2000	-	-4500
13	केरल	30839	15620	42438	26638	5500	3800	3500	2500	4500	3000	14500	8300
14	मध्य प्रदेश	40158	26849	38500	26264	-	-1000	-	-350	-	-2200	-	-3550
15	महाराष्ट्र	72000	42815	110000	79738	-	-2200	-	-2200	6000	3800	16000	8300
16	मणिपुर	1422	1147	1426	1076	200	200	-	-60	200	200	400	340
17	मेघालय	1753	1356	1364	912	200	200	200	120	400	400	900	820
18	मिज़ोरम	1315	1129	901	641	200	180	71	51	90	90	361	301
19	नगालैंड	1854	1199	2551	2016	-	-65	300	300	-	-	300	100
20	उड़ीसा	0	-7500	0	-4658	-	-	-	-	-	-500	-	-1000
21	पुदुचेरी	1200	698	1100	475	-	-	250	150	-	-	250	150
22	पंजाब	45500	33660	42386	29517	5700	4900	5500	3658	4993	4993	21693	17351
23	राजस्थान	46057	30110	73624	49718	10500	9000	8000	3688	7000	5500	25500	17188
24	सिक्किम	1414	1320	1916	1701	-	-	-	-	-	-	-	-
25	तमिलनाडु	87000	65722	113001	75970	8000	5500	8000	4750	12000	9500	33000	20750
26	तेलंगाना	40150	30922	49618	39385	4000	916	5000	5000	8000	8000	21000	17082
27	त्रिपुरा	0	-645	0	-550	-	-	-	-	-	-	-	-
28	उत्तरप्रदेश	55612	41797	97650	85335	-	-1000	-	-1233	-	-	-	-4233
29	उत्तराखंड	3200	1450	6300	3800	-	-	500	500	-	-	1400	1400
30	पश्चिम बंगाल	63000	42500	69910	48910	2000	200	3500	2500	7000	5500	12500	6400
	कुल	758392	518829	1007058	717140	57500	35515	51821	27549	68383	53778	214204	135041

- : शून्य.

टिप्पणी: 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू और कश्मीर राज्य संवैधानिक रुप से मौजूद नहीं है और उस राज्य की देयताएं जम्मू और कश्मीर के नए केंद्र शासित प्रदेश की देयताओं के रूप में बनी हुई हैं।

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक

सं.50 (ए): हाउसहोल्ड की वित्तीय आस्तियों और देयताओं का प्रवाह- लिखत-वार

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	2020-21				
	ति1	ति2	ति3	ति4	वार्षिक
निवल वित्तीय आस्तियां(I-II)	**583412.7**	**554437.6**	**463583.5**	**679174.4**	**2280608.2**
जीडीपी का प्रतिशत	*15.0*	*11.7*	*8.5*	*11.8*	*11.5*
I. वित्तीय आस्तियां	**788786.3**	**592945.3**	**633317.9**	**1047276.1**	**3062325.6**
जीडीपी का प्रतिशत	*20.3*	*12.5*	*11.6*	*18.2*	*15.4*
जिसमें:					
1. कुल जमाराशियां (ए+बी)	**297412.4**	**278631.7**	**158172.2**	**506213.3**	**1240429.7**
(ए) बैंक जमाराशि	**281191.3**	**264565.3**	**147096.0**	**507719.3**	**1200571.8**
i. वाणिज्यिक बैंक	279010.5	262033.7	143558.6	462689.8	1147292.5
ii. सहकारी बैंक	2180.8	2531.6	3537.3	45029.5	53279.3
(बी) गैर-बैंक जमाराशियां	**16221.1**	**14066.4**	**11076.3**	**-1506.0**	**39857.9**
जिसमें से:					
अन्य वित्तीय संस्थान (i+ii)	**11040.9**	**8886.2**	**5896.0**	**-6686.2**	**19137.0**
i. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां	1441.0	3763.0	3514.8	3521.2	12240.0
ii. आवास वित्त कंपनियां	9599.9	5123.2	2381.3	-10207.3	6897.0
2. जीवन बीमा निधियाँ	**124387.9**	**143462.2**	**157535.1**	**142216.5**	**567601.8**
3. भविष्य और पेंशन निधि (पीपीएफ़ सहित)	**114496.3**	**107087.9**	**105344.6**	**175769.3**	**502698.2**
4. मुद्रा	**202432.7**	**21286.9**	**91456.0**	**66800.5**	**381976.1**
5. निवेश	**6249.8**	**-12956.4**	**67659.3**	**63624.0**	**124576.7**
जिसमें:					
(ए) म्यूचुअल फंड	-16021.0	-28837.7	57675.4	51267.0	64083.8
(बी) इक्विटी	18599.4	8291.5	5307.1	6333.3	38531.2
6. अल्प बचत (पीपीएफ़ छोड़ कर)	**42751.6**	**54377.4**	**52095.1**	**91597.0**	**240821.1**
II. वित्तीय देयताएँ	**205373.6**	**38507.7**	**169734.4**	**368101.7**	**781717.4**
जीडीपी का प्रतिशत	*5.3*	*0.8*	*3.1*	*6.4*	*3.9*
ऋण/ उधार					
1. वित्तीय निगम (ए+बी)	**205490.3**	**38624.3**	**169851.0**	**368219.1**	**782184.7**
(ए) बैंकिंग क्षेत्र	**211058.8**	**13213.0**	**139622.0**	**276579.8**	**640473.6**
जिसमें:					
i. वाणिज्यिक बैंक	211259.3	13213.8	140514.3	240050.4	605037.9
(बी) अन्य वित्तीय संस्थान	**-5568.6**	**25411.3**	**30229.0**	**91639.4**	**141711.1**
i. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ	-15450.4	21627.1	15921.2	64881.1	86979.0
ii. आवास वित्त कंपनियाँ	10516.6	2875.1	13048.5	25336.1	51776.2
iii. बीमा कंपनियाँ	-634.8	909.2	1259.3	1422.2	2955.9
2. गैर-वित्तीय निगम (निजी कॉरपोरेट व्यापार)	**33.8**	**33.8**	**33.8**	**33.0**	**134.4**
3. सामान्य सरकार	**-150.4**	**-150.4**	**-150.4**	**-150.4**	**-601.7**

सं.50 (ए): हाउसहोल्ड की वित्तीय आस्तियों और देयताओं का प्रवाह- लिखत-वार (जारी)

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	2021-22				
	ति1	ति2	ति3	ति4	वार्षिक
निवल वित्तीय आस्तियां(I-II)	**370115.8**	**334234.9**	**489774.4**	**503089.0**	**1696155.6**
जीडीपी का प्रतिशत	*7.2*	*6.0*	*7.9*	*7.7*	*7.2*
I. वित्तीय आस्तियां	**364661.7**	**527896.1**	**818355.4**	**887657.3**	**2597511.9**
जीडीपी का प्रतिशत	*7.1*	*9.4*	*13.1*	*13.6*	*11.1*
जिसमें:					
1. कुल जमाराशियां (ए+बी)	**-82726.1**	**204033.6**	**426977.3**	**277625.7**	**824852.1**
(ए) बैंक जमाराशि	**-106428.9**	**197105.1**	**422392.9**	**264882.9**	**777952.1**
i. वाणिज्यिक बैंक	-107940.7	195441.8	418267.0	262326.1	768094.3
ii. सहकारी बैंक	1511.8	1663.4	4125.9	2556.8	9857.8
(बी) गैर-बैंक जमाराशियां	**23702.8**	**6928.5**	**4584.5**	**12742.8**	**46900.0**
जिसमें से:					
अन्य वित्तीय संस्थान (i+ii)	**16950.0**	**170.7**	**-2178.3**	**5960.0**	**20902.3**
i. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां	4972.6	-765.5	73.3	4211.8	8492.2
ii. आवास वित्त कंपनियां	11977.3	936.2	-2251.6	1748.2	12410.1
2. जीवन बीमा निधियाँ	**114711.5**	**127449.8**	**103248.6**	**121541.6**	**466951.5**
3. भविष्य और पेंशन निधि (पीपीएफ़ सहित)	**127624.0**	**115463.1**	**98146.0**	**221372.4**	**562605.5**
4. मुद्रा	**128660.2**	**-68631.2**	**62793.3**	**146845.0**	**269667.4**
5. निवेश	**24929.6**	**82305.4**	**69760.9**	**50972.1**	**227967.9**
जिसमें:					
(ए) म्यूचुअल फंड	14573.0	63151.3	37912.2	44963.7	160600.1
(बी) इक्विटी	4502.5	13218.5	27808.2	3084.1	48613.3
6. अल्प बचत (पीपीएफ़ छोड़ कर)	**50405.2**	**66218.1**	**56372.0**	**68243.2**	**241238.4**
II. वित्तीय देयताएँ	**-5454.1**	**193661.2**	**328581.0**	**384568.3**	**901356.3**
जीडीपी का प्रतिशत	*-0.1*	*3.5*	*5.3*	*5.9*	*3.8*
ऋण/ उधार					
1. वित्तीय निगम (ए+बी)	**-5562.3**	**193553.0**	**328472.8**	**384460.1**	**900923.7**
(ए) बैंकिंग क्षेत्र	**21436.5**	**138722.6**	**267950.7**	**348360.4**	**776470.2**
जिसमें:					
i. वाणिज्यिक बैंक	26978.6	140268.7	265271.5	337009.8	769528.5
(बी) अन्य वित्तीय संस्थान	**-26998.8**	**54830.4**	**60522.2**	**36099.7**	**124453.5**
i. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ	-34757.9	28876.8	29476.5	-2163.2	21432.2
ii. आवास वित्त कंपनियाँ	7132.0	24403.8	29494.8	37436.2	98466.8
iii. बीमा कंपनियाँ	627.1	1549.8	1550.9	826.7	4554.5
2. गैर-वित्तीय निगम (निजी कॉरपोरेट व्यापार)	**33.8**	**33.8**	**33.8**	**33.8**	**135.1**
3. सामान्य सरकार	**74.4**	**74.4**	**74.4**	**74.4**	**297.4**

सं.50 (ए): हाउसहोल्ड की वित्तीय आस्तियों और देयताओं का प्रवाह- लिखत-वार (समाप्त)

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	2022-23				
	ति1	ति2	ति3	ति4	वार्षिक
निवल वित्तीय आस्तियां(I-II)	**297770.4**	**293705.1**	**279460.1**	**505937.8**	**1376873.5**
जीडीपी का प्रतिशत	*4.6*	*4.5*	*4.0*	*7.0*	*5.1*
I. वित्तीय आस्तियां	**586920.5**	**646714.8**	**750856.7**	**974558.5**	**2959050.5**
जीडीपी का प्रतिशत	*9.0*	*9.8*	*10.8*	*13.6*	*10.9*
जिसमें:					
1. कुल जमाराशियां (ए+बी)	**183072.0**	**315216.2**	**276593.9**	**324746.6**	**1099628.6**
(ए) बैंक जमाराशि	**163162.9**	**299545.0**	**256363.7**	**307491.6**	**1026563.1**
i. वाणिज्यिक बैंक	158613.3	300565.0	248459.8	284968.0	992606.2
ii. सहकारी बैंक	4549.6	-1020.1	7903.8	22523.6	33956.9
(बी) गैर-बैंक जमाराशियां	**19909.1**	**15671.3**	**20230.2**	**17255.0**	**73065.5**
जिसमें से:					
अन्य वित्तीय संस्थान (i+ii)	**6314.4**	**2076.7**	**6635.6**	**3660.4**	**18687.1**
i. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां	4040.2	3267.2	1800.9	5372.2	14480.5
ii. आवास वित्त कंपनियां	2274.2	-1190.5	4834.7	-1711.8	4206.6
2. जीवन बीमा निधियाँ	**73669.9**	**152049.5**	**167894.1**	**141206.6**	**534820.1**
3. भविष्य और पेंशन निधि (पीपीएफ़ सहित)	**155604.2**	**132126.0**	**140204.4**	**235093.2**	**663027.7**
4. मुद्रा	**66438.9**	**-54579.3**	**76760.1**	**148990.2**	**237609.8**
5. निवेश	**51603.2**	**48630.6**	**49879.2**	**64168.5**	**214281.5**
जिसमें:					
(ए) म्यूचुअल फंड	35443.5	44484.0	40205.9	58954.5	179087.8
(बी) इक्विटी	13560.9	1378.2	6434.1	1664.9	23038.1
6. अल्प बचत (पीपीएफ़ छोड़ कर)	**54375.1**	**51114.5**	**37367.7**	**58196.2**	**201053.5**
II. वित्तीय देयताएँ	**289150.0**	**353009.7**	**471396.5**	**468620.7**	**1582177.0**
जीडीपी का प्रतिशत	*4.4*	*5.4*	*6.8*	*6.5*	*5.8*
ऋण/ उधार					
1. वित्तीय निगम (ए+बी)	**289141.6**	**353001.2**	**471388.1**	**468612.3**	**1582143.3**
(ए) बैंकिंग क्षेत्र	**234845.3**	**263782.5**	**368167.4**	**349555.0**	**1216350.1**
जिसमें:					
i. वाणिज्यिक बैंक	230283.8	261265.3	365304.6	331292.5	1188146.3
(बी) अन्य वित्तीय संस्थान	**54296.3**	**89218.8**	**103220.8**	**119057.3**	**365793.1**
i. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ	29281.6	54439.6	75878.8	80295.9	239895.9
ii. आवास वित्त कंपनियाँ	22336.7	33031.2	24903.3	36745.8	117017.0
iii. बीमा कंपनियाँ	2678.0	1747.9	2438.7	2015.6	8880.3
2. गैर-वित्तीय निगम (निजी कॉरपोरेट व्यापार)	**33.7**	**33.7**	**33.7**	**33.7**	**135.0**
3. सामान्य सरकार	**-25.3**	**-25.3**	**-25.3**	**-25.3**	**-101.3**

टिप्पणियां:
1. हाउसहोल्ड की निवल वित्तीय बचत से तात्पर्य निवल वित्तीय परिसपंत्तियों से है, जिन्हें वित्तीय परिसपंत्ति और देयताओं के प्रवाह के बीच अतंर के रूप में मापा जाता है।
2. 2022-23 के लिए प्रारंभिक अनुमान और 2020-21 और 2021-22 के लिए संशोधित अनुमान।
3. एनएसओ द्वारा राष्ट्रीय आय, उपभोग व्यय, बचत और पूंजी निर्माण, 2022-23 के पहले संशोधित अनुमान जारी होने के साथ 2022-23 के प्रारंभिक अनुमानों में संशोधन किया जाएगा।
4. अन्य वित्तीय संस्थानों के अलावा गैर-बैंक जमा में राज्य ऊर्जा उपयोगिताएँ, सहकारी गैर-ऋण समितियाँ आदि शामिल हैं।
5. संभव है कि पूर्णांकन के कारण कॉलम के आंकड़ों का जोड़ कुल के बराबर न हो।

50(बी): हाउसहोल्ड के वित्तीय आस्तियों और देयताओं का स्टॉक- चुनिंदा संकेतक

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	जून-2020	सितं-2020	दिसं-2020	मार्च-2021
वित्तीय आस्तियां (ए+बी+सी+डी+ई+एफ़+जी+एच)	**20405824.2**	**21066027.8**	**21906338.5**	**22874301.5**
जीडीपी का प्रतिशत	*107.2*	*111.5*	*114.0*	*115.4*
(ए) बैंक जमाराशियाँ (i+ii)	**9977865.6**	**10242430.9**	**10389526.9**	**10897246.1**
i. वाणिज्यिक बैंक	9192702.5	9454736.2	9598294.8	10060984.6
ii. सहकारी बैंक	785163.1	787694.7	791232.1	836261.6
(बी) गैर-बैंक जमा				
जिसमें से:				
अन्य वित्तीय संस्थान	**180857.4**	**189743.6**	**195639.6**	**188953.5**
i. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ	51463.0	55226.1	58740.8	62262.0
ii. आवास वित्त कंपनियाँ	129394.4	134517.6	136898.8	126691.5
(सी) जीवन बीमा निधि	**4102000.7**	**4274424.9**	**4551882.0**	**4752932.3**
(डी) मुद्रा	**2434693.7**	**2455980.6**	**2547436.6**	**2614237.0**
(ई) म्यूचुअल फंड	**1343752.0**	**1443784.4**	**1648999.0**	**1730461.0**
(एफ) सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ)	**663478.0**	**671884.3**	**678997.2**	**742189.5**
(जी) पेंशन निधि	**464705.0**	**494930.0**	**548913.0**	**578025.0**
(ज) लघु बचत (पीपीएफ को छोड़कर)	**1238471.7**	**1292849.1**	**1344944.2**	**1370257.1**
वित्तीय देयताएँ (ए+बी)	**7190710.8**	**7229335.1**	**7399186.1**	**7767405.3**
जीडीपी का प्रतिशत	*37.8*	*38.3*	*38.5*	*39.2*
ऋण/ उधार				
(ए) बैंकिंग क्षेत्र	**5728735.3**	**5741948.3**	**5881570.2**	**6158150.0**
जिसमें:				
i. वाणिज्यिक बैंक	5226482.2	5239696.0	5380210.4	5620260.7
ii. सहकारी बैंक	500870.2	500865.3	499968.8	536494.1
(बी) अन्य वित्तीय संस्थाएँ	**1461975.5**	**1487386.9**	**1517615.9**	**1609255.3**
जिसमें:				
i. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ	687643.6	709270.7	725191.9	790073.0
ii. आवास वित्त कंपनियाँ	673118.3	675993.4	689041.8	714377.9
iii.बीमा निगम	101213.7	102122.8	103382.2	104804.4

50(बी): हाउसहोल्ड के वित्तीय आस्तियों और देयताओं का स्टॉक- चुनिंदा संकेतक (जारी)

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	जून-2021	सितं-2021	दिसं-2021	मार्च-2022
वित्तीय आस्तियां (ए+बी+सी+डी+ई+एफ़+जी+एच)	**23318920.4**	**23991428.3**	**24700622.2**	**25435684.2**
जीडीपी का प्रतिशत	*110.7*	*109.3*	*108.7*	*108.4*
(ए) बैंक जमाराशियाँ (i+ii)	**10790817.3**	**10987922.4**	**11410315.3**	**11675198.2**
i. वाणिज्यिक बैंक	9953043.9	10148485.7	10566752.7	10829078.8
ii. सहकारी बैंक	837773.4	839436.7	843562.6	846119.4
(बी) गैर-बैंक जमा				
जिसमें से:				
अन्य वित्तीय संस्थान	**205903.4**	**206074.1**	**203895.8**	**209855.7**
i. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ	67234.6	66469.1	66542.3	70754.2
ii. आवास वित्त कंपनियाँ	138668.8	139605.0	137353.4	139101.6
(सी) जीवन बीमा निधि	**4929725.2**	**5142278.8**	**5213527.2**	**5357350.2**
(डी) मुद्रा	**2742897.3**	**2674266.1**	**2737059.4**	**2883904.4**
(ई) म्यूचुअल फंड	**1855000.1**	**2064363.5**	**2126112.0**	**2152140.5**
(एफ) सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ)	**757397.8**	**762264.0**	**767287.3**	**834147.6**
(जी) पेंशन निधि	**616517.0**	**667379.0**	**699173.0**	**736592.0**
(ज) लघु बचत (पीपीएफ को छोड़कर)	**1420662.3**	**1486880.4**	**1543252.3**	**1586495.5**
वित्तीय देयताएँ (ए+बी)	**7755119.8**	**7868215.0**	**8256715.7**	**8668329.0**
जीडीपी का प्रतिशत	*36.8*	*35.9*	*36.3*	*36.9*
ऋण/ उधार				
(ए) बैंकिंग क्षेत्र	**6172863.3**	**6231128.1**	**6559106.7**	**6934620.2**
जिसमें:				
i. वाणिज्यिक बैंक	5640516.1	5700327.0	6025626.4	6389789.3
ii. सहकारी बैंक	530937.1	529376.2	532040.6	543376.3
(बी) अन्य वित्तीय संस्थाएँ	**1582256.5**	**1637086.9**	**1697609.1**	**1733708.8**
जिसमें:				
i. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ	755315.1	784191.9	813668.4	811505.2
ii. आवास वित्त कंपनियाँ	721510.0	745913.7	775408.5	812844.7
iii.बीमा निगम	105431.4	106981.2	108532.1	109358.8

50(बी): हाउसहोल्ड के वित्तीय आस्तियों और देयताओं का स्टॉक- चुनिंदा संकेतक (समाप्त)

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	जून-2022	सितं-2022	दिसं-2022	मार्च-2023
वित्तीय आस्तियां (ए+बी+सी+डी+ई+एफ़+जी+एच)	**25689017.4**	**26240728.5**	**27208717.9**	**28083947.0**
जीडीपी का प्रतिशत	*103.2*	*101.5*	*102.4*	*103.1*
(ए) बैंक जमाराशियाँ (i+ii)	**11911196.2**	**11956360.9**	**12421907.5**	**12701761.3**
i. वाणिज्यिक बैंक	11060527.2	11106712.0	11564354.7	11821685.0
ii. सहकारी बैंक	850669.0	849648.9	857552.8	880076.4
(बी) गैर-बैंक जमा				
जिसमें से:				
अन्य वित्तीय संस्थान	**216170.2**	**218246.9**	**224882.5**	**228542.9**
i. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ	74794.4	78061.6	79862.5	85234.7
ii. आवास वित्त कंपनियाँ	141375.8	140185.3	145020.0	143308.2
(सी) जीवन बीमा निधि	**5325967.3**	**5559681.9**	**5786592.6**	**6038630.4**
(डी) मुद्रा	**2950343.2**	**2895763.9**	**2972524.0**	**3121514.2**
(ई) म्यूचुअल फंड	**2048097.3**	**2260209.7**	**2355315.8**	**2367792.5**
(एफ) सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ)	**851913.4**	**858591.1**	**864730.6**	**939814.6**
(जी) पेंशन निधि	**744459.2**	**799889.0**	**853412.0**	**898342.0**
(ज) लघु बचत (पीपीएफ को छोड़कर)	**1640870.6**	**1691985.1**	**1729352.9**	**1787549.1**
वित्तीय देयताएँ (ए+बी)	**8957470.6**	**9310471.8**	**9781859.9**	**10253472.2**
जीडीपी का प्रतिशत	*36.0*	*36.0*	*36.8*	*37.6*
ऋण/ उधार				
(ए) बैंकिंग क्षेत्र	**7169465.5**	**7433248.0**	**7801415.3**	**8153970.3**
जिसमें:				
i. वाणिज्यिक बैंक	6620073.1	6881338.5	7246643.0	7580935.6
ii. सहकारी बैंक	547894.8	550354.8	553201.4	571339.8
(बी) अन्य वित्तीय संस्थाएँ	**1788005.1**	**1877223.8**	**1980444.6**	**2099501.9**
जिसमें:				
i. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ	840786.9	895226.5	971105.3	1051401.1
ii. आवास वित्त कंपनियाँ	835181.3	868212.5	893115.8	929861.7
iii.बीमा निगम	112036.9	113784.8	116223.5	118239.1

टिप्पणियाँ: 1. जीडीपी के अनुपात के रूप में डेटा की गणना एनएसओ द्वारा 31 मई 2023 को जारी राष्ट्रीय आय 2022-23 के अनंतिम अनुमान के आधार पर की गई है।
2. पेंशन निधि में राष्ट्रीय पेंशन योजना की निधि शामिल है।
3. लघु बचत के साथ बकाया जमा राशि भारत सरकार के लेखा महानियंत्रक से प्राप्त की जाती है।
4. अन्य वित्तीय संस्थानों के अलावा गैर-बैंक जमा में राज्य ऊर्जा उपयोगिताएँ सहकारी गैर-ऋण समितियाँ आदि शामिल हैं। बकाया जमा के लिए आकंड़े केवल अन्य वित्तीय संस्थानों के लिए उपलब्ध हैं।
5. संभव है कि पूर्णांकन के कारण कॉलम के आंकड़ों का जोड़ कुल के बराबर न हो।

वर्तमान सांख्यिकी की व्याख्यात्मक टिप्पणियां

सारणी सं. 1

1.2 और 6 : वार्षिक आंकड़े महीनों के औसत हैं ।
3.5 और 3.7 : वित्त वर्ष में अब तक वृद्धि के अनुपात से संबंधित है।
4.1 से 4.4, 4.8, 4.9 और 5 : माह/वित्त वर्ष के अंतिम शुक्रवार से संबंधित है।
4.5, 4.6 और 4.7 : माह / वित्त वर्ष के अंतिम शुक्रवार को पांच प्रमुख बैंकों से संबंधित है।
4.10 से 4.12 : माह/ वित्त वर्ष के अंतिम नीलामी दिन से संबंधित है।
4.13 : माह/वित्त वर्ष के अंतिम दिन से संबंधित है।
7.1 और 7.2 : यूएस डॉलर में विदेशी व्यापार से संबंधित है।

सारणी सं. 2

2.1.2 : चुकता पूंजी, आरक्षित निधि और दीर्घावधि परिचालनगत निधि शामिल है।
2.2.2 : नकदी, सावधि जमाराशियाँ और अल्पावधि प्रतिभूतियाँ / बॉण्ड जैसे - आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी, शामिल है।

सारणी सं. 4

http ://nsdp.rbi.org.in के 'रिज़र्व टैम्पलेट' के अंतर्गत परिपक्वतावार बकाया फॉर्वर्ड संविदा की स्थिति दर्शायी गयी है।

सारणी सं. 5

अन्य अर्थात एक्सिम बैंक को विशेष पुनर्वित्त सुविधा 31 मार्च 2013 से बंद है।

सारणी सं. 6

अनुसूचित बैंकों के लिए, मार्च की समाप्ति के आंकडे रिपोर्टिंग अंतिम शुक्रवार से संबंधित हैं।
2.2 : आईएमएफ खाता सं. 1 की शेष राशि, आरबीआई कर्मचारी भविष्य निधि, पेंशन निधि, उपदान और अधिवर्षिता निधि शामिल नहीं हैं।

सारणी सं. 7 और 11

सारणी 7 में 3.1 और सारणी 11 में 2.4 : आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी विदेशी मुद्रा में निर्दिष्ट बॉण्ड शामिल हैं

सारणी सं. 8

एनएम$_2$ और एनएम$_3$ में एफसीएनआर (बी) जमाराशियां शामिल नहीं हैं।
2.4 : चुकता पूंजी और आरक्षित राशि शामिल हैं।
2.5 : बैंकिंग प्रणाली की अन्य मांग और मीयादी देयताएं शामिल हैं।

सारणी सं. 9

वित्तीय सस्थाओं में एक्जिम बैंक, सिडबी, नाबार्ड और एनएचबी शामिल हैं।
एल$_1$ और एल$_2$ मासिक आधार पर और एल$_3$ तिमाही आधार पर संकलित किए जाते हैं।
जहां आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, वहां अंतिम उपलब्ध आंकड़े पुनः दिए गए हैं।

सारणी सं. 13

कॉलम सं. (1) (2) और (3) में दर्शाये गए आंकड़े अंतिम और कॉलम सं. (4) और (5) में दर्शाए गए आंकड़े अनंतिम हैं।

सारणी सं. 14

कॉलम सं. (4) और (8) में दर्शाए गए आंकड़े अनंतिम हैं।

सारणी सं. 17

2.1.1 : राज्य सहकारी बैंकों में सहकारी सोसाइटियों द्वारा अनुरक्षित आरक्षित निधि शामिल नहीं है।

2.1.2 : आरबीआई, एसबीआई, आईडीबीआई, नाबार्ड, अधिसूचित बैंकों और राज्य सरकारों से लिए गए ऋण शामिल नहीं है।

4: आईडीबीआई और नाबार्ड से लिए गए ऋण शामिल हैं।

सारणी सं. 24

प्राथमिक व्यापारियों में, प्राथमिक व्यापारी का कारोबार करने वाले बैंक शामिल हैं।

सारणी सं. 30

प्राइवेट प्लेसमेंट और बिक्री के प्रस्ताव शामिल नहीं हैं

1 : बोनस शेयर शामिल नहीं हैं।

2 : संचयी परिवर्तनीय अधिमान शेयर और इक्वी - अधिमान शेयर शामिल हैं।

सारणी सं. 32

आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी विदेशी मुद्रा में निर्दिष्ट बॉण्डों में निवेश, भारत सरकार द्वारा रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया को अंतरित एसडीआर तथा सार्क और एसीयू करेंसी स्वैप व्यवस्था के अंतर्गत प्राप्त विदेशी मुद्रा शामिल नहीं हैं। अमेरिकी डॉलर में दिखाई गई विदेशी मुद्रा आस्तियों में रिज़र्व में रखी गैर यूएस मुद्राओं (जैसे यूरो, स्टर्लिंग, येन और ऑस्ट्रेलिया डॉलर) के मूल्यवृद्धि/मूल्यह्रास के लिए शामिल किया गया है। विदेशी मुद्रा धारिता को रुपया - अमेरिकी डॉलर आरबीआई धारिता दरों पर रुपए में परिवर्तित किया गया है।

सारणी सं. 34

1.1.1.1.2 और 1.1.1.1.1.4 : अनुमान

1.1.1.2 : नवीनतम माह के लिए अनुमान

'अन्य पूंजी' एफडीआई उद्यम की मूल और अनुषंगी संस्थाओं / शाखाओं के बीच के ऋण सबंधी लेनदेन से संबंधित है।

हो सकता है कि सूचना देने में हुए समय अंतराल के कारण ये आँकड़े भुगतान संतुलन के आंकड़ों से मेल न खाएं।

सारणी सं. 35

1.10 : पत्र-पत्रिकाओं के लिए अभिदान, विदेश में किए गए निवेशों का अनुरक्षण, छात्र ऋण चुकौती और क्रेडिट कार्ड भुगतान जैसी मदें शामिल हैं।

सारणी सं. 36

सूचकांकों में वृद्धि रुपये की मूल्यवृद्धि और विपरीत क्रम का संकेतक है। 6- मुद्राओं वाले सूचकांक के लिए, आधार वर्ष 2021-22 अस्थिर है जिसे प्रत्येक वर्ष अद्यतित किया जाता है। रीर के आंकड़े उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (संयुक्त) पर आधारित है। नीर//रीर सूचकांकों के संकलन के लिए उपयोग की जाने वाली कार्यप्रणाली का ब्यौरा आरबीआई बुलेटिन के दिसंबर 2005, अप्रैल 2014 और जनवरी 2021 के अंक में उपलब्ध है।

सारणी सं. 37

ईसीबी/विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉण्डों (एफसीसीबी) के लिए आवेदनों पर आधारित जिन्हें उस अवधि के दौरान ऋण पंजीकरण संख्या दी गई है।

सारणी सं. 38, 39, 40 और 41

इन सारणियों के संबंध में व्याख्यात्मक टिप्पणियां आरबीआई बुलेटिन 2012 के दिसंबर अंक में उपलब्ध हैं।

सारणी सं. 43

भाग I-ए. भुगतान प्रणाली

1.1.3: प्रतिभूति खंड के अंतर्गत त्रिपक्षीय रेपो का परिचालन 05 नवंबर 2018 से किया गया है।

भाग I-बी भुगतान प्रणाली

4.1.2: 'अन्य' में ई-कॉमर्स लेनदेन और एटीएम के माध्यम से डिजिटल बिल भुगतान आदि शामिल हैं।

4.2.2: 'अन्य' में ई-कॉमर्स लेनदेन, कार्ड से कार्ड अंतरण और एटीएम के माध्यम से डिजिटल बिल भुगतान आदि शामिल हैं।

5: दिसंबर 2010 से उपलब्ध है।

5.1: वॉलेट के माध्यम से माल और सेवाओं की खरीद और निधि अंतरण शामिल है।

5.2.2: ऑनलाइन लेनदेन और अन्य लेनदेन के लिए पीपीआई कार्ड का उपयोग शामिल है।

6.1: तीन ग्रिडों से संबंधित - मुंबई, नई दिल्ली और चेन्नई।

6.2: 'अन्य' में गैर-एमआईसीआर लेनदेन शामिल है जो 21 बैंकों द्वारा प्रबंधित समाशोधन गृह से संबंधित है।

भाग II-ए अन्य भुगतान चैनल

1 : मोबाइल भुगतान -

- इसमें बैंकों के मोबाइल ऐप और यूपीआई ऐप के जरिए किए गए लेनदेन शामिल हैं।
- जुलाई 2017 के बाद के डेटा में मोबाइल के माध्यम से शुरू, संसाधित और अधिकृत किए गए केवल व्यक्तिगत भुगतान और कॉरपोरेट भुगतान शामिल हैं। अन्य कॉरपोरेट भुगतान जो मोबाइल के माध्यम से शुरू, संसाधित और अधिकृत नहीं हैं, को शामिल नहीं किया गया है।

2 : इंटरनेट भुगतान - 'नेटबैंकिंग' के माध्यम से केवल ई-कॉमर्स लेनदेन और बैंक की इंटरनेट बैंकिंग वेबसाइट से किया गया वित्तीय लेनदेन शामिल है।

भाग II-बी. एटीएम

3.3 और 4.2: केवल बैंक द्वारा जारी पीपीआई से किए गए लेनदेन से संबंधित है।

भाग III. भुगतान प्रणाली अवसंरचना

3: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) और व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर्स (डब्ल्यूएलएओ) के एटीएम शामिल हैं। डब्ल्यूएलए को अप्रैल 2014 से शामिल किया गया है।

सारणी सं. 45

(-): शून्य/ नगण्य को दर्शाता है।

बुलेटिन के जून 2023 के संस्करण से टेबल फार्मेट संशोधित किया है।

राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (यूडीएवाई) के अंतर्गत जारी विशेष बॉण्ड शामिल हैं।

वाणिज्यिक बैंकों के अंतर्गत बैंक के प्राथमिक डीलरों को शामिल किया गया है। तथापि, कुल बकाया प्रतिभूतियों में इनका हिस्सा बहुत कम है।

'अन्य' श्रेणी में राज्य सरकारें, डीआईसीजीसी, पीएसयू, ट्रस्ट, केंद्रीय विदेशी बैंक, हिंदू अविभक्त परिवार/व्यक्ति आदि शामिल हैं।

सितंबर 2023 के बाद के आंकड़ों में एक बैंक का एक गैर-बैंक के साथ विलय का प्रभाव शामिल है।

सारणी सं. 46

जीडीपी डेटा वर्ष 2011-12 के आधार पर आधारित है। वर्ष 2023-24 के लिए जीडीपी केंद्रीय बज़ट 2023-24 से ली गई है। डेटा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है।
1 और 2: आंकड़े केंद्र सरकार (एनएसएसएफ की पुन: चुकौती सहित) और राज्य सरकार की निवल चुकौती से संबंधित है।
1.3: राज्य द्वारा स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थानों को दिये गये मुआवजे और कार्य से संबंधित है।
2: यह डेटा केंद्र और राज्य सरकारों की उधार प्राप्तियों सहित केंद्र और राज्य सरकारों के नकदी शेष में हुए घटबढ़ से संबंधित निवल को दर्शाते हैं।
3ए.1.1: आंकड़े भारतीय रिज़र्व बैंक के अभिलेख के अनुसार हैं।
3बी. 1.1: दिनांकित प्रतिभूतियों के माध्यम से उधारियां शामिल हैं।
3बी.1.2: राष्ट्रीय लघु बचत निधि (एनएसएसएफ) की ओर से केंद्र और राज्य सरकारों की विशेष प्रतिभूतियों में किए गए निवल निवेश को दर्शाते हैं।
यह डेटा नए डेटा की उपलब्धता के साथ घटकों में समायोजन के कारण पिछले प्रकाशनों से भिन्न हो सकता है।
3बी. 1.6: केंद्र द्वारा राज्य सरकारों को दिये गये अर्थोपाय अग्रिमों सहित।
3बी. 1.7: खजाना बिल, वित्तीय संस्थानों से ऋण, बीमा और पेंशन निधि, विप्रेषण, नकदी शेष निवेश खाता सहित।

सारणी सं. 47

राज्य सरकारों द्वारा समेकित ऋण शोधन निधि (सीएसएफ), गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ) और नीलामी खज़ाना बिल (एटीबी) के शेषों तथा सरकारी प्रतिभूतियों में किए गए अन्य निवेशों को संपाश्विक के तौर पर रखते हुए विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ) प्राप्त की जाती है।
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा राज्य सरकारों को उनके अल्पकालिक नकदी असंतुलन से निपटने के लिए अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) दिया जाता है।
राज्य सरकारों को उनकी अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) सीमा से अधिक की आवश्यकता को पूरा करने के लिए ओवरड्राफ्ट दिया जाता है।
प्राप्त कुल सहायता (एसडीएफ / डब्ल्यूएमए / ओडी) को उन दिनों की संख्या से भाग देने पर, जिनके लिए माह के दौरान सहायता प्राप्त हुई, औसत राशि प्राप्त होती है।
-: नगण्य।

सारणी सं. 48

समेकित ऋणशोधन निधि (सीएसएफ) और गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ) वे आरक्षित निधियाँ हैं जो कुछ राज्य सरकारों द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक के पास रखी जाती हैं।
नीलामी खज़ाना बिलों (एटीबी) में राज्य सरकारों द्वारा प्राथमिक बाज़ारो में निवेश किए गए 91 दिवसीय, 182 दिवसीय तथा 364 दिनों के खज़ाना बिल शामिल हैं।
--: लागू नहीं (इस योजना का सदस्य नहीं है)।

वर्तमान सांख्यिकी के लिए अवधारणाएं और कार्यप्रणाली आरबीआई मासिक बुलेटिन की वर्तमान सांख्यिकी के लिए व्यापक मार्गदर्शिका में उपलब्ध हैं **(https://rbi.org.in/Scripts/PublicationsViewaspx?id=17618)**

'वर्तमान सांख्यिकी' का समय श्रृंखला डेटा https://data.rbi.org.in पर उपलब्ध है।
विस्तृत व्याख्यात्मक नोट आरबीआई द्वारा जारी प्रासंगिक प्रेस प्रकाशनियों और बैंक के अन्य प्रकाशनों/विज्ञप्तियों जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकी पुस्तिका में उपलब्ध हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक के हाल के प्रकाशन

प्रकाशन का नाम	मूल्य	
	भारत में	**विदेश में**
1. भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन 2024	₹350 एक प्रति ₹250 एक प्रति (रियायती दर*) ₹4,000 (एक वर्ष का सदस्यता शुल्क) ₹3,000 (एक वर्ष रियायती दर*)	15 अमेरिकी डॉलर, एक प्रति 150 अमेरिकी डॉलर (एक वर्ष का सदस्यता शुल्क) (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
2. भारतीय राज्यों से संबंधित सांख्यिकी पुस्तिका 2022-23	₹550 (सामान्य) ₹600 (डाक प्रभार सहित)	24 अमेरिकी डॉलर (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
3. भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकी पुस्तिका 2023-24	₹600 (सामान्य) ₹650 (डाक प्रभार सहित) ₹450 (रियायती) ₹500 (रियायती डाक प्रभार सहित)	50 अमेरिकी डॉलर (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
4. राज्य वित्तः 2023-24 के बजटों का अध्ययन	₹600 एक प्रति (कांउटर पर) ₹650 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	24 अमेरिकी डॉलर, एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
5. मुद्रा और वित्त संबंधी रिपोर्ट 2023-24	₹575 एक प्रति (कांउटर पर) ₹625 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	22 अमेरिकी डॉलर, एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
6. भारतीय रिज़र्व बैंक सामयिक पेपर खंड 44, सं. 1, 2023	₹200 एक प्रति (कांउटर पर) ₹250 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	18 अमेरिकी डॉलर, एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
7. पंचायती राज संस्थाओं का वित्त	₹300 एक प्रति (कांउटर पर) ₹350 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	16 अमेरिकी डॉलर, एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
8. भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति एवं प्रगति संबंधी रिपोर्ट 2022-23	आरबीआई बुलेटिन जनवरी, 2024 के पूरक के रूप में जारी किया गया।	
9. वार्षिक रिपोर्ट 2023-24	आरबीआई बुलेटिन जून, 2024 के पूरक के रूप में जारी किया गया।	
10. वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट-जून 2024	आरबीआई बुलेटिन जुलाई, 2024 के पूरक के रूप में जारी किया गया।	
11. मौद्रिक नीति रिपोर्ट - अप्रैल 2024	आरबीआई बुलेटिन अप्रैल 2024 में शामिल है।	
12. बैंकिंग शब्दावली (अंग्रेजी-हिन्दी)	₹100 एक प्रति (कांउटर पर) ₹150 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	

टिप्पणियां:

1. उपर्युक्त प्रकाशनों में से कई प्रकाशन आरबीआई की वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर उपलब्ध हैं।
2. टाइम सीरीज़ डेटा भारतीय अर्थव्यवस्था के डेटाबेस में उपलब्ध हैं (http://dbie.rbi.org.in) |
3. भारतीय रिज़र्व बैंक का इतिहास 1935-2008 (5 खंड), भारत के प्रमुख पुस्तक भंडारों में उपलब्ध हैं।

* भारत में छात्रों, अध्यापकों / व्याख्याताओं, अकादमिक / शैक्षिक संस्थाओं, सार्वजनिक पुस्तकालयों और पुस्तक विक्रेताओं को रियायत दी जाएगी बशर्ते उन्हें पात्रता प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

सामान्य अनुदेश

1. सभी संचार निम्न को संबोधित किए जाएँ:
   निदेशक, रिपोर्ट और ज्ञान प्रसार प्रभाग,
   आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग (डीआरकेडी, डीईपीआर), भारतीय रिज़र्व बैंक, अमर भवन, तल मंजिल,
   सर पी. एम. रोड, फोर्ट, पोस्ट बॉक्स सं. 1036. मुंबई- 400 001
   टेलीफोन: 022-2260 3000 विस्तार: 4002, ईमेल: spsdepr@rbi.org.in
2. बिक्री के लिए प्रकाशन प्रातः 10:30 बजे से अपराह्न 3:00 बजे तक (सोमवार से शुक्रवार) उपलब्ध हैं।
3. प्रकाशनों को कैश ऑन डिलीवरी के आधार पर नहीं दिया जाएगा।
4. एक बार बेचे गए प्रकाशनों को वापस नहीं लिया जाएगा।
5. प्रकाशन के पिछले अंक आम तौर पर उपलब्ध नहीं होते हैं।
6. जहां रियायती मूल्य का संकेत नहीं दिया गया है, भारत में छात्रों, शिक्षकों, शैक्षिक/ अकादमिक संस्थानों, सार्वजनिक पुस्तकालयों और पुस्तक विक्रेताओं के लिए 25 प्रतिशत की छूट उपलब्ध है, बशर्ते पात्रता का प्रमाण प्रस्तुत किया जाए।
7. सदस्यता शुल्क के भुगतान के लिए एनईएफटी को प्राथमिकता दी जाए और भुगतानकर्ता के नाम, सदस्यता संख्या (यदि कोई हो), खाता संख्या, तारीख और राशि सहित लेनदेन विवरण **spsdepr@rbi.org.in** पर ईमेल किया जाए या डाक द्वारा भेजा जाए।

   ए. एनईएफटी ट्रांसफर के लिए अपेक्षित जानकारी इस प्रकार है:

लाभार्थी का नाम	आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग, आरबीआई
बैंक का नाम	भारतीय रिज़र्व बैंक
शाखा और पता	फोर्ट, मुंबई
बैंक शाखा का आईएफएससी	RBIS0MBPA04
खाता प्रकार	चालू खाता
खाता संख्या	41-8024129-19

   बी. गैर- डिजिटल मोड के माध्यम से सदस्यता के मामले में, कृपया भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई के नाम पर मुंबई में देय डिमांड ड्राफ्ट/ चेक भेजें।

8. 'प्रकाशन प्राप्त न होने' संबंधी शिकायतें दो माह की अवधि के अंदर भेजी जाएं।